

आतंकवाद

गुरिल्ला से ड्रोन तक
ऑपरेशन सिंदूर
23 मिनट में सदी का वार

अमिताभ कुमार



BlueRoseONE.com
Stories Matter
New Delhi • London

BLUEROSE PUBLISHERS

India | U.K.

Copyright © Amitabh Kumar 2025

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.



For permissions requests or inquiries regarding this publication,
please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS

www.BlueRoseONE.com

info@bluerosepublishers.com

+91 8882 898 898

+4407342408967

ISBN: 978-93-7310-500-0

Cover Design: Aman Sharma

Typesetting: Manisha

First Edition: September 2025

समर्पण

यह पुस्तक उन अदम्य वीर भारतीय सैनिकों के नाम है, जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ़ और तूफ़ान को चुनौती देते हुए, और थार के तपते रेगिस्तानों में तपिश और धूल के बीच, अडिग प्रहरी बनकर खड़े हैं। जिनकी आँखों में सतर्कता की चमक है, जिनकी नसों में मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा बहती है, और जिनके कंधों पर 1.4 अरब नागरिकों की सुरक्षा का भार है। चाहे रात कितनी ही अंधेरी हो, ठंड कितनी ही कड़वी हो, या दुश्मन कितना ही चालाक क्यों न हो-आपका साहस हर मोर्चे पर दुश्मन के कदम रोक देता है।

आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं, बल्कि आपदा के समय जीवनदायी हाथ, शांति के प्रहरी और राष्ट्र की आत्मा के सच्चे संरक्षक हैं। आपका त्याग-अपनों से दूर बिताए लम्हे, अदृश्य खतरों के सामने खड़े रहना, और कर्तव्य के लिए जीवन अर्पित कर देना-भारत के हर दिल में सुरक्षा और गर्व की ज्योति प्रज्वलित करता है। यह पुस्तक “आतंकवाद: गुरिल्ला से ड्रोन तक (आतंकवाद के प्रसार का ऐतिहासिक विश्लेषण) ऑपरेशन सिंदूर: 23 मिनट में सदी का वार “, आपके उस अमर पराक्रम को नमन है, जिसने भारत को अजेय बनाया और उसकी अस्मिता को अडिग रखा।

-लेखक

शहीद सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि

वह क्षण, जब रणभूमि पर तिरंगे की शपथ लिए कोई जवान अपनी अंतिम सांस लेता है, इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। यह श्रद्धांजलि उन शूरवीरों को है, जिन्होंने आतंकवाद और उसके पनाहगारों के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए। उनकी रगों में बहता साहस केवल गोली और बारूद से नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए धड़कते अटूट हृदय से उपजा था।

सीमाओं के बर्फीले मोर्चों से लेकर भीड़भाड़ वाले महानगरों और शांत गाँवों तक, इन वीरों ने निःस्वार्थ भाव से दुश्मन की हर साजिश को कुचल दिया। उनका हर बलिदान हमारी आज़ादी की कीमत है, हर शहादत हमारी एकता की गारंटी है। यह पुस्तक “आतंकवाद: गुरिल्ला से ड्रोन तक (आतंकवाद के प्रसार का ऐतिहासिक विश्लेषण) ऑपरेशन सिंदूर: 23 मिनट में सदी का वार “, उन अमर आत्माओं को समर्पित है, जिनका साहस और त्याग भारत को सदैव अजेय, सुरक्षित और गौरवशाली बनाए रखेगा।

-लेखक

लेखक परिचय

लेखक, एक भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) अधिकारी, प्रशासनिक विशेषज्ञता को साहित्यिक प्रतिभा के साथ सहजता से मिश्रित करते हैं। शासन और नीति निर्माण के दायरे से परे, वे एक आकर्षक कहानीकार और विचारक के रूप में उभरते हैं, जो अपनी लेखनी के माध्यम से इतिहास, दर्शन, सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य और मानवीय भावनाओं की गहराइयों को जीवंत करते हैं। उनकी रचनाएँ न केवल बौद्धिक गहराई और कल्पनाशीलता का समृद्ध संगम प्रस्तुत करती हैं, बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने और सांस्कृतिक विविधता को भी संवेदनशीलता के साथ उजागर करती हैं।

प्रकाशित कृतियाँ

- Indian Railway: From Steam to Speed**
- Aghori and Manikarnika: The Cosmic Dance of Death**
- मान्यवर: संगठन से सत्ता तक (काशीराम की राजनैतिक यात्रा)
- शमशान भैरवी और अघोरी: मोक्ष का ब्रह्मांडीय नृत्य
- सरपंच
- Operation Log Out**
- समाधि से राजयोग तक
- Bloody Merit Scholars**
- Mahant: The Godfather**
- Rainbow in White Shroud**
- GEN Z: Love Lost in Transaction**
- Kumbh Diaries: A Research Journal**
- कुम्भ डायरीज: एक शोध ग्रन्थ
- Pahalgam and Sindoor: Technology meets Terror**

15. Rohith Vemula Files: My Birth is My Fatal Accident

16. राजनाथ सिंह: आधुनिक भारत के लौह पुरुष

आगामी कृतियाँ

1. आतंकवाद: गुरिल्ला से ड्रोन तक (आतंकवाद के प्रसार का ऐतिहासिक विश्लेषण) ऑपरेशन सिंदूर: 23 मिनट में सदी का वार
- यह पुस्तक आतंकवाद के विकास की गाथा को गुरिल्ला युद्ध से लेकर आधुनिक ड्रोन युद्ध तक की यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं, तकनीकी बदलावों और वैश्विक राजनीति के प्रभाव का गहन विश्लेषण शामिल है।
2. **Corporate: From Desk to Dynasty (There's No Undo Button in Loyalty)** - कॉर्पोरेट दुनिया की महत्वाकांक्षी और सियासी परतों में निष्ठा, विश्वासघात और पुनर्निर्माण की प्रेरक कहानी, जो एक महिला के करियर की ऊँचाइयों और संघर्षों को उजागर करती है।
3. काशी: मोक्ष की नगरी (इतिहास, परम्परा और सभ्यता से भी प्राचीन शहर) - काशी की आध्यात्मिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक परंपराओं और मोक्ष की खोज में इसके अद्वितीय स्थान का जीवंत चित्रण।
4. लखनऊ: शहर-ए-अदब (जुबान, ज़मीर और ज़िंदगी का शहर) - लखनऊ के अदब, तहज़ीब, जुबान और लज़ीज़ खानपान की दुनिया में डुबो देने वाली यह रचना इस शहर की नफ़ासत और आत्मा को शब्दों में पिरोती है।

अन्य उल्लेखनीय योगदान

लेखक का प्रभाव उनकी साहित्यिक और प्रशासनिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला है। एक कुशल निशानेबाज के रूप में, उन्होंने राइफल और रिवाल्वर शूटिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, जो उनकी अनुशासित और लक्ष्य-उन्मुख प्रकृति को दर्शाती है। सामाजिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता समान रूप से प्रेरणादायक है-सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में उनके अथक प्रयासों ने हजारों बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान किए हैं। बाल कल्याण और शिक्षा पर केंद्रित प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ

उनकी प्रभावशाली साझेदारियों ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यापक राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, उनकी बौद्धिक और रचनात्मक ऊर्जा सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जिसने उन्हें न केवल एक लेखक के रूप में बल्कि एक सामाजिक सुधारक और दूरदर्शी विचारक के रूप में भी स्थापित किया है।

लेखक की ऑनलाइन उपस्थिति

अपनी भावपूर्ण लेखनी, प्रशासनिक नेतृत्व और सामाजिक पहलों के माध्यम से, अमिताभ कुमार विविध वैश्विक पाठक और समुदाय के साथ जुड़ते हैं। उनकी रचनाएँ, विचार और सामाजिक प्रयास डिजिटल मंचों पर व्यापक रूप से चर्चा का विषय हैं, जहाँ वे सामाजिक न्याय, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर संवाद को प्रेरित करते हैं। उनकी नवीनतम रचनाओं, विचारों और पहलों से अपडेट रहने के लिए, निम्नलिखित मंचों पर उनसे संपर्क किया जा सकता है:

- ट्विटर: @authoramitabh
- फेसबुक: @amitabhauthor
- इंस्टाग्राम: @authoramitabh
- लिंकडइन: @authoramitabh
- यूट्यूब: @amitabhauthor
- वेबसाइट: www.amitabhkumar.in
- ईमेल: dak@amitabhkumar.in
- ऐप:
 - एंड्रॉइड: AmitabhKumar
 - iOS: AmitabhKumar

प्रावकथन

आतंकवाद मानव सभ्यता की सबसे पुरानी और जटिल चुनौतियों में से एक है, जो धार्मिक उन्माद से शुरू होकर आज तकनीकी युद्ध के रूप में विकसित हो चुका है। यह पुस्तक “आतंकवाद: गुरिल्ला से ड्रोन तक (आतंकवाद के प्रसार का ऐतिहासिक विश्लेषण) ऑपरेशन सिंदूर: 23 मिनट में सदी का वार” आतंकवाद के इस बदलते स्वरूप को विस्तार से विश्लेषित करती है। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित शुरुआती हमलों, जैसे कि 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले, से लेकर 2025 के पहलगाम हमले तक, जहां टीआरएफ जैसे संगठनों ने तकनीकी साजिशों के माध्यम से भारत की एकता को चुनौती दी, पुस्तक आतंकवाद के इतिहास, विस्तार और भारत की मजबूत प्रतिक्रिया का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। आईएसआई के समर्थन से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की गहराई को उजागर करते हुए, यह किताब दिखाती है कि कैसे आतंकवाद अब सिर्फ बंदूकों और बमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ड्रोन, साइबर हमलों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक फैल चुका है।

यह पुस्तक न केवल आतंकवाद के मूल कारणों, जैसे कि धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक असंतोष और राज्य प्रायोजित साजिशों का विश्लेषण करती है, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसियों-रॉ, आईबी, एनआईए-की सक्रियता और वायुसेना की तकनीकी प्रहार रणनीति को भी विस्तार से वर्णित करती है। पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि में टीआरएफ की तकनीकी साजिशों से लेकर भारत की त्वरित और सटीक कार्रवाई तक, पुस्तक दिखाती है कि कैसे भारत ने धार्मिक उन्माद से प्रेरित आतंक को तकनीकी युद्ध में बदलकर वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य श्रेष्ठता साबित की। पाठकों को आतंकवाद के इतिहास से लेकर वर्तमान तकनीकी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का एक संपूर्ण दृष्टिकोण मिलेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह किताब उन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है जो भारत की एकता और सुरक्षा में विश्वास रखते हैं, और साबित करता है कि भारत न केवल चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि उन्हें निर्णायक रूप से नष्ट भी कर सकता है।

अनुक्रमणिका

अध्याय 1: 1947 से पहले और प्रारंभिक उग्रवाद	1
अध्याय 2: 1980 और 1990 के दशक - आतंकवाद का विस्तार.....	4
अध्याय 3: टीआरएफ का परिचय और गठन.....	8
अध्याय 4: लश्कर-ए-तैयबा (LeT)	34
अध्याय 5: जैश-ए-मोहम्मद (JeM)	52
अध्याय 6: हिजबुल मुजाहिदीन (HM)	76
अध्याय 7: इंडियन मुजाहिदीन	113
अध्याय 8: अल-कायदा	122
अध्याय 9: इस्लामिक स्टेट (ISIS)	129
अध्याय 10: आतंकी भर्ती की रणनीतियाँ.....	134
अध्याय 11: कट्टरपंथीकरण के माध्यम	140
अध्याय 12: हथियारों की तस्करी के मार्ग.....	145
अध्याय 13: आतंकी प्रचार	148
अध्याय 14: आतंकी रणनीतियों का विकास - रणनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन	151
अध्याय 15: आतंकी रणनीतियों का विकास - रणनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन	156
अध्याय 16: राज्य प्रायोजित आतंकी फंडिंग के आरोप	160
अध्याय 17: राज्य एजेंटों द्वारा प्रशिक्षण और समर्थन	166
अध्याय 18: 1993 बंबई शृंखलाबद्ध विस्फोट - भारत का पहला संगठित आतंकी हमला	171

अध्याय 19: 2001 संसद हमला - लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सीधा प्रहार	176
अध्याय 20: 2006 मुंबई लोकल बम धमाके - शहर की रफ्तार पर मौत का पहरा.....	180
अध्याय 21: 2008 मुंबई हमले - 26/11 की दहशत और भारत का संकल्प	184
अध्याय 22: 2016 उरी हमला - सीमा-पार आतंकवाद का निर्णायक मोड़.....	187
अध्याय 23: 2019 पुलवामा बम विस्फोट - कश्मीर में आतंकी हिंसा का सबसे घातक प्रहार	189
अध्याय 24: 2025 पहलगाम हमला	192
अध्याय 25: ऑपरेशन ब्लैक थंडर.....	196
अध्याय 26: ऑपरेशन विजय	200
अध्याय 27: सर्जिकल स्ट्राइक (2016)	204
अध्याय 28: बालाकोट हवाई हमला (2019)	207
अध्याय 29: ऑपरेशन ऑल आउट	211
अध्याय 30: पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई	215
अध्याय 31: ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट से भारत की जवाबी कार्रवाई.....	220
अध्याय 32: नियंत्रण रेखा पार सर्जिकल हमला - टीआरएफ पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया	224
अध्याय 33: वायुसेना की मिसाइल रणनीति.....	229
अध्याय 34: इलेक्ट्रॉनिक युद्ध - पाक रडार ध्वंस और भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया.....	234

अध्याय 35: आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिचय.....	242
अध्याय 36: रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्रांति और नवाचार	250
अध्याय 37: रक्षा आत्मनिर्भरता का भविष्य और वैश्विक प्रभाव	257
अध्याय 38: सख्त आतंकवाद-रोधी कानून और कानूनी सुधार	264
अध्याय 39: खुफिया तंत्र का आधुनिकीकरण और अंतर एजेंसी समन्वय	268
अध्याय 40: सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण - फेंसिंग, तकनीकी निगरानी और घुसपैठ-रोधी उपाय	273
अध्याय 41: अर्धसैनिक बलों और विशेष इकाइयों को अत्याधुनिक हथियार व उपकरण	277
अध्याय 42: आतंकवाद के वित्तपोषण और हवाला नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई	282
अध्याय 43: अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान	287
अध्याय 44: साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और सूचना युद्ध से निपटने की तैयारी.....	291
अध्याय 45: साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और सूचना युद्ध से निपटने की तैयारी	295
अध्याय 46: स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जन-जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रम	299
अध्याय 47: आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध और सदस्यता पर नियंत्रण.....	303
अध्याय 48: सैन्य प्रतिउत्तर और सीमा-पार सर्जिकल/ एयर स्ट्राइक ऑपरेशन	307
अध्याय 49: सीमांत एवं समुद्री सुरक्षा	311

अध्याय 50: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सामुदायिक सहभागिता	315
अध्याय 51: राजनयिक अलगाव और क्षेत्रीय सहयोग	319
अध्याय 52: वैश्विक प्रतिबंध, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल उपाय और भारत की आतंकवाद-विरोधी नेतृत्व भूमिका	322
पुस्तक में प्रयोग किए गए सन्दर्भों की सूची	325

अध्याय 1:

1947 से पहले और प्रारंभिक उग्रवाद

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर सीधे ब्रिटिश राजशाही के अधीन आ गई। इसके बाद अंग्रेजों ने एक सुनियोजित औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, जिसकी नींव “फूट डालो और राज करो” की नीति पर रखी गई। उन्होंने जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद गहरे किए तथा धर्म के आधार पर प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को संस्थागत रूप दिया। 1909 के मिंटो-मॉर्ले सुधारों में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करना, इस नीति का महत्वपूर्ण कदम था, जिससे मुस्लिम लीग को राजनीतिक बढ़त मिली और कांग्रेस से दूरी बढ़ी। 1930 के दशक तक दो राष्ट्र सिद्धांत का विचार प्रबल हो गया और 1940 के लाहौर प्रस्ताव में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से सामने आ गई। इसके विपरीत, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस एक एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना पर डटी रही। 1946 तक सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुँच चुका था - कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली के दंगों में हजारों लोगों की हत्या ने स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक सह-अस्तित्व की नींव डगमगा चुकी है।

15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता विभाजन के दर्द से सनी थी। धार्मिक आधार पर हुए इस विभाजन में पंजाब और बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेश भी बाँट दिए गए। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा जल्दबाजी में खींची गई सीमा ने सदियों से साथ रह रहे समुदायों को अलग कर दिया। परिणामस्वरूप, इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन हुआ - लगभग डेढ़ करोड़ लोग उजड़े और 10 से 20 लाख की जान गई। ट्रेनों को रोककर कत्लेआम, गांवों में आगजनी, महिलाओं के साथ बलात्कार और बच्चों का अनाथ होना - यह हिंसा भीड़ की आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित, धार्मिक रूप से प्रेरित रक्तपात था। पंजाब में लाखों लोग मारे गए और मीरपुर जैसे कस्बों में 20,000 से अधिक हिंदू-सिखों की हत्या हुई। इस पृष्ठभूमि ने आगे चलकर आतंकवाद के बीज बो दिए। भारत ने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का मार्ग चुना, जबकि पाकिस्तान

इस्लामी गणराज्य बना - यही वैचारिक विभाजन आगे कश्मीर, बंगाल और पंजाब में कट्टरता की नींव बना।

कश्मीर इस राजनीतिक, धार्मिक और सामरिक संघर्ष का केंद्र बन गया। 1941 की जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर की 77% आबादी मुस्लिम थी, परंतु शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने का विकल्प था। प्रारंभ में उन्होंने स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास किया और 12 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से “स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट” किया। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने “ऑपरेशन गुलमर्ग” के तहत 5,000-7,000 पश्तून कबीलाई लड़ाकों को भेज दिया, जिन्होंने बारामूला में मंदिर-गुरुद्वारे जलाए, लूटपाट की और 11,000 से अधिक गैर-मुसलमानों की हत्या की। वे श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे और राजधानी पर कब्जा लगभग तय था।

इस संकट में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने शर्त रखी कि यह तभी संभव है जब कश्मीर भारत में विलय करे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय सेना श्रीनगर पहुँची और पहला भारत-पाक युद्ध आरंभ हुआ। लगभग एक वर्ष चले इस युद्ध का अंत 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्धविराम और “लाइन ऑफ कंट्रोल” की स्थापना के साथ हुआ। भारत ने कानूनी विलय के आधार पर सम्पूर्ण कश्मीर पर दावा बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुलता के आधार पर अपना दावा करता रहा। यही असमाप्त विवाद आतंकवाद की स्थायी जमीन बना।

विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर में छिटपुट उग्रवाद दिखाई देने लगा। 1947 में सरदार मुहम्मद इब्राहीम खान ने “जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF)” की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र कश्मीर था। प्रारंभ में राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले ये समूह धीरे-धीरे हिंसक हो गए और पाकिस्तान से प्रशिक्षण, हथियार तथा धन प्राप्त करने लगे। 1947 का कबीलाई हमला भारत के अनुसार सीमापार आतंकवाद का पहला उदाहरण था। 1948 में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 47 के तहत जनमत संग्रह का सुझाव आया, पर सेना वापसी की शर्तों पर सहमति न बन पाने से यह कभी लागू नहीं हुआ। विभाजन की हिंसा ने समाज में स्थायी भय, प्रतिशोध और अविश्वास की गहरी जड़ें जमा दीं। मीरपुर नरसंहार, जम्मू की हिंसा और बारामूला की घटनाओं ने धार्मिक कट्टरता को वैधता दी। इन्हें भले उस समय “दंगे” कहा गया, पर इनकी रणनीति, लक्षित

हिंसा और भय के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट करती है कि ये आतंकवाद की मानसिक और मनोवैज्ञानिक नींव रख रही थीं। 1980 और 1990 के दशकों में जिस उग्रवाद ने विकराल रूप लिया, उसकी जड़ें 1947 की इन घटनाओं में ही गहरी पैठ चुकी थीं।

अध्याय 2:

1980 और 1990 के दशक - आतंकवाद का विस्तार

1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि इसने वैश्विक आतंकवाद के इतिहास में निर्णायक मोड़ ला दिया। अमेरिका और सऊदी अरब के संयुक्त गुप्त अभियान 'अभियान चक्रवात' ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय जिहाद का संचालन केंद्र बना दिया। लगभग तीन दशमलव दो अरब डॉलर की सहायता, जिसमें से अधिकांश गुप्त रूप से आईएसआई को मिली, अफगान-पाक सीमा पर स्थित सौ से अधिक प्रशिक्षण शिविरों में अस्सी हजार से अधिक मुजाहिदीनों के सैन्यीकरण पर खर्च हुई। इन्हें एके-47, आरपीजी और स्टिंगर क्षेपक जैसे आधुनिक हथियार दिए गए और छापामार युद्ध, घात लगाकर हमला, तथा विस्फोटक निर्माण में प्रशिक्षित किया गया। 1989 में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से हट गई, तो इन लड़ाकों को नया मोर्चा चाहिए था। पाकिस्तान ने कश्मीर को 'जिहाद का अगला गढ़' घोषित कर दिया। इन विदेशी लड़ाकों में दस हजार-बीस हजार अरब, उज्बेक, चेचेन और अन्य मध्य एशियाई योद्धा थे, जो अब कश्मीर को इस्लामी खिलाफत की विस्तार भूमि मानने लगे। पाकिस्तानी मदरसे, आईएसआई के नेटवर्क, तस्करी चैनल और धार्मिक प्रचार ने मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-मुजाहिदीन और बाद में लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को युद्ध के लिए तैयार किया। 1989 तक मुजफ्फराबाद और बालाकोट स्थित शिविरों में हर साल पांच सौ से एक हजार कश्मीरी युवाओं को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और छापामार रणनीति में प्रशिक्षित किया जा रहा था।

जम्मू-कश्मीर में 1987 के राज्य विधानसभा चुनावों में व्यापक धांधली के आरोपों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास तोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला की राष्ट्रीय सम्मेलन-कांग्रेस गठबंधन पर मुस्लिम संयुक्त मोर्चा को हराने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। युवाओं के सामने राजनीतिक विकल्प बंद हो गए और हथियार उठाना ही एकमात्र रास्ता दिखने लगा। पाकिस्तान ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए असंतुष्ट युवाओं को धन, हथियार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन तेजी से सक्रिय हुए। खुफिया

रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से अत्याधुनिक हथियार, नकली दस्तावेज़ और प्रशिक्षित लड़ाके व्यवस्थित रूप से भेजे जा रहे थे। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ एक नियमित रणनीति बन चुकी थी, जिसमें स्थानीय गाइड, पहाड़ी दर्रे और सुरंगों का उपयोग किया जाता था।

इसी काल में कई प्रमुख आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ। 1989 में जमात-ए-इस्लामी कश्मीर के सैन्य अंग के रूप में हिजबुल मुजाहिदीन ने स्थानीय भर्ती और छापामार हमलों के जरिए कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का संकल्प लिया। 1986 में हाफिज सईद द्वारा स्थापित लश्कर-ए-तैयबा ने सम्पूर्ण इस्लामी खिलाफत की स्थापना का लक्ष्य रखा, जिसमें कश्मीर पहला चरण था। यह अमेरिका और अन्य देशों में प्रतिबंधित होने के बावजूद पाकिस्तान में संरक्षित रहा। 2000 में मसूद अजहर द्वारा स्थापित जैश-ए-मोहम्मद, 1999 के आईसी-814 विमान अपहरण के बाद रिहा हुए आतंकी की अगुवाई में, भारतीय संसद पर हमले जैसे बड़े अभियानों के लिए कुख्यात हुआ। अफगान जिहाद से उपजे हरकत-उल-मुजाहिदीन ने सीमापार घुसपैठ, अपहरण और आत्मघाती हमलों में सक्रिय भूमिका निभाई।

इन सभी संगठनों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से शिविर, प्रशिक्षण, धन, नकली दस्तावेज़ और सामरिक मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। 2019 के बाद लश्कर-ए-तैयबा का छद्म रूप 'प्रतिरोध मोर्चा' (टीआरएफ) उभरा, जो स्थानीय कश्मीरी प्रतिरोध का मुखौटा पहनकर अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी जड़ें उसी पुराने पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ी हैं। टीआरएफ ने पर्यटकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसमें पहलगाम हमला उसकी रणनीति का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक दबाव पैदा करना था।

1990 के दशक में भारत पर हुए हमलों की तीव्रता इस जिहादी ढांचे के परिपक्व होने का प्रमाण थी। 21 मई 1990 को हिजबुल आतंकियों ने धार्मिक नेता मीरवाइज़ मौलवी फारूक की हत्या कर दी, जिससे घाटी में हिंसा भड़क उठी और सौ से अधिक लोगों की मौत हुई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में बारह समन्वित बम विस्फोट हुए, जिनमें दो सौ सत्तावन लोग मारे गए और सात सौ से अधिक घायल हुए। इस हमले का संचालन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने आईएसआई की मदद से किया। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने भारतीय चौकियों पर कब्ज़ा किया, जिससे अभियान विजय चला और भारतीय सेना ने जुलाई

तक कब्जा छुड़ा लिया। यह पाकिस्तान की स्पष्ट “छद्म युद्ध” नीति थी। आतंकियों ने अफगान युद्ध से सीखी तकनीकें - तात्कालिक विस्फोटक उपकरण, घात, कूटबद्ध रेडियो, निष्क्रिय कोशिका और सुनियोजित घुसपैठ - का भरपूर उपयोग किया। 1999 तक भारत ने दो सौ से अधिक कूटबद्ध रेडियो बरामद किए, जो पाकिस्तानी रसद समर्थन का प्रमाण थे।

भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीतियाँ अपनाईं। 1990 में “अभियान रक्षक” के तहत घाटी में एक लाख से अधिक सैनिक तैनात किए गए। टाडा कानून ने आतंकियों को पकड़ने और बिना जमानत निरुद्ध रखने का कानूनी आधार दिया, हालांकि 1995 में मानवाधिकार चिंताओं के चलते इसे समाप्त कर दिया गया। नियंत्रण रेखा पर तारबंदी, ऊष्मीय छवि यंत्र, रात्रि दृष्टि उपकरण लगाए गए और खुफिया एजेंसियों - अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, खुफिया ब्यूरो, सैन्य खुफिया - के बीच समन्वय मजबूत किया गया।

भारत ने लगातार पाकिस्तान पर आतंकवाद को राज्य प्रायोजित करने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान इसे “स्वतंत्रता संग्राम” बताता रहा। लेकिन 1993 की अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट वैश्विक आतंकवाद के पैटर्न ने पाकिस्तान में मौजूद प्रशिक्षण शिविरों, हथियारों और आईएसआई के नेटवर्क का खुलासा किया। इससे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को गहरा आघात पहुंचा और उस पर वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ा, जो आगे चलकर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल जैसी संस्थाओं की निगरानी का आधार बना।

प्रमुख आतंकवादी संगठन

अध्याय 3:

टीआरएफ का परिचय और गठन

द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम से जाना जाने वाला यह संगठन जम्मू-कश्मीर की घाटियों में फैली हुई एक प्रमुख उग्रवादी शक्ति के रूप में उभरा है, जहां यह भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर लगातार छापेमारी और हमलों से क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देता रहता है। 2019 में भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय ने पूरे क्षेत्र में गहरे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाए, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण और आम नागरिकों को स्थायी निवास के अधिकार प्रदान करना, जिसने स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया। यह संगठन खुद को कश्मीरी जनता के स्वाभाविक संघर्ष का प्रतिनिधि बताकर अपनी गतिविधियों को न्यायोचित ठहराता है, लेकिन विभिन्न सुरक्षा विश्लेषणों में इसे पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एक बड़े जिहादी नेटवर्क का छिपा हुआ विस्तार माना जाता है, जो सीमा पार से प्राप्त निर्देशों और संसाधनों पर निर्भर करता है। टीआरएफ की मुख्य सक्रियता अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जैसे दक्षिणी जिलों में केंद्रित है, जहां यह जंगलों और पहाड़ी इलाकों का उपयोग करके गुप्त ऑपरेशन चलाता है, और इसके सदस्यों में अधिकतर वे युवा शामिल हैं जो बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और राजनीतिक अलगाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। संगठन की रणनीति में छोटे-बड़े हमलों को मिलाकर क्षेत्र में भय का वातावरण बनाना शामिल है, जो अंततः भारत की विकास योजनाओं को बाधित करने का उद्देश्य रखती है।

इस संगठन की स्थापना ने कश्मीर के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को एक नई गति प्रदान की है, जहां पुराने उग्रवादी गुटों की जगह नए नामों और रणनीतियों से गतिविधियां जारी रखी जा रही हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त के बाद क्षेत्र में लागू हुए नए कानूनों, जैसे कि भूमि स्वामित्व के नियमों में परिवर्तन, ने स्थानीय निवासियों में अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान खोने का डर पैदा किया, जिसका फायदा ऐसे संगठनों ने उठाया। टीआरएफ को उन तत्वों का समर्थन प्राप्त होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगी निगरानी और प्रतिबंधों से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलते रहते हैं, और यह पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की मदद से हथियारों की

आपूर्ति और प्रशिक्षण प्राप्त करता है। संगठन की गतिविधियां मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों तक फैली हुई हैं, जहां यह स्थानीय सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से भर्ती करता है और छोटे समूहों में विभाजित होकर काम करता है। हाल के वर्षों में टीआरएफ ने अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया है, जैसे कि एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर प्रचार सामग्री साझा करना, जो विशेष रूप से उन युवाओं को आकर्षित करता है जो सामाजिक मीडिया पर राजनीतिक बहसों से प्रभावित होते हैं।

इस संगठन की औपचारिक स्थापना अक्टूबर 2019 में हुई थी, जब कश्मीर घाटी में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं पर लंबे समय तक प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसने उग्रवादियों को गुप्त रूप से संगठित होने और योजनाएं बनाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। टीआरएफ मुख्य रूप से अनुभवी उग्रवादी सदस्यों से मिलकर गठित हुआ, जो वैश्विक वित्तीय निगरानी तंत्र के दबाव से बचने के लिए एक नई पहचान अपनाना चाहते थे, और इसमें पाकिस्तान की भूमिका को प्रमुख माना जाता है। संगठन ने अपनी शुरुआती उपस्थिति को डिजिटल प्लेटफॉर्मों जैसे टेलीग्राम और ट्विटर पर स्थापित किया, जहां यह विभिन्न हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए प्रचारात्मक संदेश जारी करता था, और इससे युवा कश्मीरियों में समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती थी। प्रारंभिक प्रारंभिक दिनों में टीआरएफ ने श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में छोटी घटनाओं, जैसे कि व्यापारियों पर हमलों, से अपनी मौजूदगी दर्ज की, जो बाद में अधिक संगठित और घातक संघर्षों में परिवर्तित हो गईं। पाकिस्तानी क्षेत्रों से जुड़े संपर्क इसे मजबूती प्रदान करते हैं, जहां से हथियार, विस्फोटक सामग्री और रणनीतिक निर्देश नियमित रूप से प्राप्त होते हैं, और यह संगठन की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।

टीआरएफ के गठन का मूल उद्देश्य पुरानी उग्रवादी रणनीतियों को एक नए ढांचे में ढालना था, जबकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और निगरानी से पूर्णतः बचाव सुनिश्चित करना, जैसे कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने से उत्पन्न चुनौतियां। शुरुआती महीनों में संगठन ने छोटे-मोटे ऑपरेशनों से अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जैसे कि सुरक्षा चौकियों पर गोलीबारी या ग्रेनेड फेंकना, जो घाटी में तनाव बढ़ाने का माध्यम बने। संगठन के नियंत्रक सीमा के उस पार से संचालन करते हैं, जहां से विस्तृत योजनाएं तैयार की जाती हैं और सदस्यों को निर्देशित किया जाता है। डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग युवाओं को संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है, जो राजनीतिक परिवर्तनों से उत्पन्न असंतोष से प्रभावित होकर शामिल होते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के कई गुप्त नेटवर्कों को ध्वस्त किया है, जो इसकी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है और संगठन की दीर्घायु पर सवाल खड़े करता है।

पुराने उग्रवादी गुटों के अनुभवी सदस्यों ने संयुक्त रूप से टीआरएफ को आकार प्रदान किया, इसे एक स्थानीय स्तर के विद्रोही आंदोलन का रूप देकर वैश्विक जांच एजेंसियों से दूर रखने का प्रयास किया। संगठन का उदय 2019 की उन प्रमुख घटनाओं से सीधे जुड़ा हुआ है, जहां कश्मीर में नए डोमिसाइल नियमों का लागू होना स्थानीय लोगों में भूमि और संसाधनों के नुकसान की आशंका पैदा करने वाला साबित हुआ। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मत है कि यह पड़ोसी देश की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर बढ़ते दबाव से बचने के लिए नए संगठनों को जन्म देता है। टीआरएफ ने अपनी विचारधारा को कश्मीरी राष्ट्रवाद से जोड़कर प्रस्तुत किया, लेकिन इसके सदस्यों की पृष्ठभूमि पुरानी जिहादी धाराओं से गहराई से जुड़ी हुई है, जो हिंसक कार्रवाइयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संगठन की गतिविधियां मुख्य रूप से पुलवामा, कुपवाड़ा और बारामूला जैसे जिलों में फैली हुई हैं, जहां यह छिपे हुए हमलों और छापेमारी से भारतीय भारतीय बलों को निशाना बनाता है।

इस रणनीतिक गठन में पुराने कैडरों को एकत्रित करना शामिल था, ताकि प्रत्यक्ष आरोपों से बचा जा सके और गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहें। 2019 के फैसलों ने युवाओं में गहरे क्रोध को जन्म दिया, जिसका लाभ संगठन ने भर्ती के लिए उठाया और सदस्यों में स्कूलों तथा कॉलेजों से युवा शामिल किए। सदस्य भर्ती में स्थानीय नेटवर्क और प्रलोभनों का उपयोग होता है, जो लंबे संघर्ष की तैयारी दर्शाता है। टीआरएफ की यह रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती देती है, जहां भारतीय बलों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। संगठन की वृद्धि संघर्ष की जटिलता को बढ़ाती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करती है।

टीआरएफ की प्रारंभिक गतिविधियां मुख्य रूप से वर्चुअल दुनिया तक सीमित रहीं, जहां विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर बयान जारी करके हमलों की जिम्मेदारी ली जाती थी और प्रचार किया जाता था। 2020 में कुपवाड़ा जिले में भारतीय विशेष बलों के साथ हुई एक भयानक मुठभेड़ ने संगठन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां प्रदान कीं, जहां कई सैनिकों की जान गई और संघर्ष की तीव्रता बढ़ी।

संगठन ने अपनी छवि को गैर-धार्मिक बनाए रखने का प्रयास किया, अपने प्रतीकों और संदेशों में धार्मिक संदर्भों से पूर्णतः परहेज करके एक सेक्युलर विद्रोही समूह का रूप अपनाया। लेकिन विभिन्न जांचों में पुराने जिहादी नेटवर्क से जुड़े हथियार, संचार उपकरण और सदस्यों के इतिहास मिले, जो टीआरएफ के असली स्वरूप को उजागर करते हैं। यह रणनीति संगठन को वैश्विक स्तर पर अधिक स्वीकार्य बनाने की थी, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों ने इस प्रयास को असफल साबित किया।

इस शुरुआती चरण में वर्चुअल प्रचार पर विशेष जोर दिया गया, जो कश्मीर की युवा पीढ़ी को आकर्षित करने और समर्थन जुटाने का प्रमुख साधन बना। कुपवाड़ा की घटना के बाद टीआरएफ ने अधिक प्रत्यक्ष और सक्रिय भूमिका अपनाई, लेकिन जांच एजेंसियों को पुराने सदस्यों की भागीदारी के प्रमाण मिले, जो संगठन की जड़ों को स्पष्ट करते हैं। संगठन ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन लक्षित हमलों ने इसकी सच्चाई को सामने ला दिया, जहां सांप्रदायिक तत्व प्रमुख दिखाई देते हैं। सुरक्षा दस्तावेजों और रिपोर्टों में टीआरएफ के डिजिटल नेटवर्क को पाकिस्तानी मूल का बताया जाता है, जो एन्क्रिप्टेड चैनलों से संचालित होते हैं। यह दोहरी नीति जांच प्रक्रिया को जटिल बनाती है, लेकिन भारतीय एजेंसियां लगातार इसके स्रोतों को ट्रैक और नष्ट करने में लगी हुई हैं।

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी सूची में शामिल होने की स्थिति ने टीआरएफ के गठन को सीधे प्रभावित किया, क्योंकि पुराने उग्रवादी गुटों पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए नए संगठन की आवश्यकता पड़ी। टीआरएफ मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में नए सदस्यों की भर्ती और अवैध हथियारों की आपूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जो ड्रोन, सुरंगों और सीमा पार तस्करी के माध्यम से संचालित होती है। 2023 में भारतीय सरकार ने इसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिसके बाद इसके सदस्यों और सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई की गति बढ़ गई। यह फोकस रणनीति कश्मीर में लंबे समय तक अशांति और अस्थिरता बनाए रखने की है, जो क्षेत्रीय विकास को बाधित करती है। संगठन ने ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अपने आधार स्थापित किए हैं, जहां सुरक्षा बलों की पहुंच अपेक्षाकृत कम होती है और स्थानीय सहानुभूति प्राप्त करना आसान होता है।

ग्रे लिस्ट के दबाव में पाकिस्तान ने पुराने संगठनों को नए रूप प्रदान किए, और टीआरएफ इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो पुरानी रणनीतियों को जारी रखता है। भर्ती प्रक्रिया में सोशल मीडिया, स्थानीय मस्जिदों और स्कूलों का उपयोग किया जाता है, जहां युवाओं को आर्थिक प्रलोभन और वैचारिक प्रचार से आकर्षित किया जाता है। हथियारों की तस्करी में अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाले मार्ग शामिल हैं, जो संगठन की सैन्य क्षमता को मजबूत बनाते हैं। 2023 की घोषणा के बाद भारत ने टीआरएफ के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे इसके सदस्यों की गिरफ्तारियां हुईं और नेटवर्क कमजोर हुआ। यह पूरी स्थिति पाकिस्तान के वैश्विक अलगाव को रेखांकित करती है, जहां उग्रवाद को समर्थन देने पर लगातार सवाल उठते रहते हैं।

मुहम्मद अब्बास शेख और शेख सज्जाद गुल ने टीआरएफ की नींव रखी, दोनों ही पुराने उग्रवादी नेटवर्क से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग नए संगठन को मजबूत बनाने में किया। यह 2019 के बाद उभरे कई छोटे विद्रोही समूहों का हिस्सा है, जो राजनीतिक खालीपन और असंतोष का फायदा उठाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शुरुआत में टीआरएफ ने मामूली घटनाओं का श्रेय लिया, जैसे कि सड़क पर गोलीबारी या छोटे विस्फोट, लेकिन धीरे-धीरे यह बड़े और अधिक जटिल ऑपरेशनों की ओर बढ़ा। अब्बास शेख की मृत्यु के बावजूद संगठन की सक्रियता बनी रही, जो इसके मजबूत नेतृत्व और विकेंद्रीकृत संरचना को दर्शाती है। टीआरएफ ने कश्मीर के विभिन्न जिलों में छोटे-छोटे सेल स्थापित किए हैं, जो स्थानीय सहयोग से संचालित होते हैं और हमलों की योजना बनाते हैं।

इन संस्थापकों की पृष्ठभूमि अन्य प्रमुख उग्रवादी गुटों से जुड़ी हुई है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक बड़े जिहादी नेटवर्क से संबंध रखते हैं। नए समूहों का उदय अनुच्छेद 370 के निरसन से उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तनों से हुआ, जिसने पुराने संगठनों को पुनर्गठित होने पर मजबूर किया। छोटे दावों से शुरू करके शुरू करके टीआरएफ ने बड़े हमलों जैसे बसों पर अटैक की योजनाएं बनाईं, जो क्षेत्र में दहशत फैलाती हैं। संगठन की वृद्धि पाकिस्तानी हैंडलर्स पर निर्भर है, जो सीमा पार से निर्देश और संसाधन प्रदान करते हैं। यह विकास कश्मीर संघर्ष की बढ़ती जटिलता को उजागर करता है, जहां नए नामों से पुरानी लड़ाई जारी रहती है।

टीआरएफ को पुराने जिहादी नेटवर्क का एक छिपा हुआ रूप माना जाता है, जो जांच एजेंसियों के लिए पहचान और ट्रैकिंग को अत्यधिक जटिल बनाता है। इसका गठन विशेष रूप से कश्मीर में पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्य से किया गया, ताकि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को धक्का पहुंचे और विकास परियोजनाएं रुके। पाकिस्तान सरकार आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की सहायता से इनकार करती है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों और ज्वलंत सामग्रियों में फंडिंग, हथियारों और लॉजिस्टिक्स के स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। संगठन ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को निशाना बनाकर वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, जो क्षेत्रीय पर्यटन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। टीआरएफ की यह रणनीति न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करती है।

छद्म संगठन के रूप में टीआरएफ विभिन्न नामों और उपनामों का उपयोग करता है, जो जांच को भटकाने और गुप्त रहने में मदद करता है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव से भारत की विकास योजनाओं को बाधित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, जैसे कि रेलवे और सड़क परियोजनाओं को निशाना बनाना। पाकिस्तान के इनकार के बावजूद, सीमा पार से आने वाले संदेश, धन और हथियार इसके कनेक्शन को साबित करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दर्ज हैं। संगठन ने घाटी में डर और अनिश्चितता का वातावरण बनाया है, जो निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। यह पूरी स्थिति भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बनाती है, जहां उग्रवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

शुरुआती दौर में टीआरएफ ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर हमलों को प्रोत्साहित किया, जहां वीडियो, पोस्टर और संदेशों के माध्यम से युवाओं को उकसाया जाता था और समर्थन जुटाया जाता था। 2020 में संगठन ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की शुरुआत की, भारतीय सुरक्षा बलों पर संगठित हमलों के साथ, जो घाटी में तनाव और अशांति को बढ़ाने का माध्यम बने। टीआरएफ ने खुद को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन जांच एजेंसियों को पुराने जिहादी नेताओं से इसके गहरे संबंधों के प्रमाण मिले, जैसे कि संचार लॉग और सदस्यों के इतिहास। संगठन की ऑनलाइन सक्रियता ने इसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जहां प्रचार सामग्री से युवाओं को आकर्षित किया जाता है। यह प्रचार रणनीति सदस्यों की संख्या बढ़ाने और वैचारिक प्रसार में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है।

सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके टीआरएफ ने 2020 में अपनी गतिविधियों को तेज किया, विशेष रूप से सुरक्षा बलों पर फोकस रखते हुए और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करके। स्वतंत्र दिखावे के बावजूद, पुराने नेताओं के साथ संवाद और सहयोग के प्रमाण जांच में सामने आए, जो संगठन की जड़ों को उजागर करते हैं। यह दोहरी पहचान जांच प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, लेकिन एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग से कमजोरियां ढूंढ रही हैं। प्रचार ने कश्मीर में राजनीतिक असंतोष को हवा दी है, जो युवाओं को संगठन की ओर खींचता है। टीआरएफ की समग्र वृद्धि पाकिस्तानी समर्थन पर टिकी हुई है, जो इसके अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

टीआरएफ का गठन कश्मीर के विद्रोह को एक नया रूप प्रदान करने के लिए हुआ, जो पुराने उग्रवादी समूहों की थकान और कमजोरी से अलग होकर अधिक लचीला और आधुनिक हो। यह 2019 के राजनीतिक परिवर्तनों का प्रत्यक्ष परिणाम है, जैसे कि राज्य का विभाजन, नए चुनावी नियमों का लागू होना और केंद्र सरकार की बढ़ती भूमिका। संगठन ने तेज गति से सदस्यों की भर्ती की, स्थानीय युवाओं को राजनीतिक असंतोष, आर्थिक कठिनाइयों और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों से आकर्षित करके। भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक सहायता, वैचारिक प्रशिक्षण और सोशल मीडिया प्रचार शामिल है, जो संगठन को मजबूत बनाता है। यह विकास कश्मीर संघर्ष की निरंतरता को दर्शाता है, जहां नए संगठन पुरानी लड़ाई को जारी रखते हैं।

नए रूप देने की इस प्रक्रिया में टीआरएफ ने पुराने गुटों से दूरी बनाई, लेकिन उनके संसाधनों और अनुभव को साझा किया, ताकि गतिविधियां निर्बाध रहें। 2019 के फैसलों ने युवाओं में गहरे क्रोध को जन्म दिया, जिसका लाभ संगठन ने भर्ती के लिए उठाया और सदस्यों में स्कूलों तथा कॉलेजों से युवा शामिल किए। सदस्य भर्ती में स्थानीय नेटवर्क और प्रलोभनों का उपयोग होता है, जो लंबे संघर्ष की तैयारी दर्शाता है। टीआरएफ की यह रणनीति क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती देती है, जहां भारतीय बलों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। संगठन की वृद्धि संघर्ष की जटिलता को बढ़ाती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित करती है।

विचारधारा और उद्देश्य

टीआरएफ की मूल धारणा कश्मीर घाटी की पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित है, जो भारतीय शासन व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करती है और क्षेत्रीय आत्मनिर्णय को प्रमुखता देती है। यह संगठन खुद को एक सेक्युलर आंदोलन के रूप में चित्रित करता है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वजों और सामान्य प्रतीकों का उपयोग करके धार्मिक पहलू को पीछे छोड़ने का प्रयास किया जाता है, ताकि व्यापक कश्मीरी समाज से समर्थन प्राप्त हो सके। हालांकि, इसके द्वारा किए गए हमलों में हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाना इसकी गहरी जड़ों को उजागर करता है, जो कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हैं और क्षेत्र में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं। टीआरएफ की यह रणनीति स्थानीय युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है, जहां यह आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक दमन को हथियार बनाकर लोगों को अपनी ओर खींचता है। संगठन की प्रचार सामग्री में कश्मीर को एक उत्पीड़ित राष्ट्र के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इसके कार्यों में हिंसक प्रतिशोध प्रमुख है, जो शांतिपूर्ण समाधान की बजाय संघर्ष को लंबा खींचने पर जोर देता है।

इस विचारधारा का विकास 2019 के बाद के राजनीतिक परिवर्तनों से हुआ है, जहां कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने ने संगठन को स्थानीय असंतोष का लाभ उठाने का मौका दिया। सेक्युलर दिखावे के बावजूद, अल्पसंख्यकों पर हमले संगठन की छिपी हुई कट्टरता को प्रकट करते हैं, जो क्षेत्रीय सद्भाव को नष्ट करने का इरादा रखती है। टीआरएफ की धारणा में भारतीय प्रशासन को एक विदेशी कब्जे के रूप में चित्रित किया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी को विद्रोह के लिए प्रेरित किया जाता है। संगठन की यह रणनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने की भी है, जहां यह खुद को उत्पीड़ितों का प्रतिनिधि बताता है। हालांकि, इसके कार्यों में सांप्रदायिक हिंसा का प्रभुत्व संगठन की सच्ची प्रकृति को उजागर करता है, जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को अस्वीकार करता है और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देता है।

संगठन का प्राथमिक लक्ष्य जम्मू-कश्मीर से भारतीय प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करना है, जिसके लिए यह सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक मानता है और क्षेत्र को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने की वकालत करता है। यह खुद को कश्मीरी लोगों के मूल प्रतिरोध का प्रतीक बताता है, लेकिन वास्तविकता में यह पाकिस्तान स्थित एक

बड़े जिहादी नेटवर्क की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो इस्लामी शासन की स्थापना पर जोर देती है। टीआरएफ पर्यटकों और साधारण नागरिकों को लक्षित करके भय का वातावरण उत्पन्न करता है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे को उभारने का प्रयास किया जाता है। संगठन की रणनीति में छोटे-बड़े हमलों को मिलाकर स्थानीय प्रशासन को कमजोर करना शामिल है, जहां नागरिकों को डराकर समर्थन जुटाने की कोशिश की जाती है। इसके उद्देश्यों में भारतीय सुरक्षा तंत्र को चुनौती देना प्रमुख है, जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तैयारी दर्शाता है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टीआरएफ स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी और सांस्कृतिक पहचान को हथियार बनाता है, लेकिन जिहादी प्रभाव से यह हिंसक कार्रवाइयों पर निर्भर रहता है। दहशत फैलाने की रणनीति पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाती है, जो कश्मीर की आर्थिक रीढ़ है और इससे भारत पर दबाव बनाने का इरादा है। संगठन की प्रचार सामग्री में खुद को प्रतिरोधी बताकर वैश्विक सहानुभूति जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नागरिकों पर हमले इसकी क्रूरता को उजागर करते हैं। टीआरएफ की यह नीति पाकिस्तानी समर्थन पर टिकी है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है।

विचारधारा में टीआरएफ कश्मीरी राष्ट्रवाद को सर्वोच्च स्थान देता है, जिसमें क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात की जाती है, जबकि धार्मिक कट्टरता से दूरी बनाए रखने का दावा किया जाता है। इसके उद्देश्यों में नए सदस्यों की संख्या बढ़ाना और हथियारों की अवैध आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है, जो संगठन की सैन्य क्षमता को मजबूत बनाती है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों पर चुनिंदा हमले इसकी विरोधाभासी प्रकृति को दिखाते हैं, जहां राष्ट्रवाद की आड़ में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया जाता है। टीआरएफ की यह धारणा स्थानीय युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है, जहां शिक्षा और रोजगार की कमी को हथियार बनाकर विद्रोह को प्रोत्साहित किया जाता है। संगठन की प्रचार रणनीति में कश्मीर को एक दमित राष्ट्र के रूप में चित्रित करना प्रमुख है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर हिंसक कार्यों का प्रभुत्व रहता है।

राष्ट्रवाद पर जोर देने के बावजूद, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना संगठन की छिपी कट्टरता को उजागर करता है, जो क्षेत्रीय सद्भाव को नष्ट करने का इरादा रखती है। भर्ती

और हथियार तस्करी के उद्देश्य लंबे संघर्ष की तैयारी दर्शाते हैं, जहां सीमा पार से मदद प्राप्त होती है। टीआरएफ की विचारधारा में धार्मिक उग्रवाद से दूरी का दावा है, लेकिन हमलों की प्रकृति विपरीत साबित होती है। संगठन की यह रणनीति अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की भी है, जहां खुद को पीड़ित बताकर समर्थन जुटाया जाता है। हालांकि, विरोधाभास संगठन की विश्वसनीयता को कमजोर बनाते हैं और क्षेत्रीय शांति को चुनौती देते हैं।

टीआरएफ का प्रमुख लक्ष्य विद्रोह को मजबूत बनाना है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर प्रचार करके युवाओं को उकसाया जाता है और स्थानीय असंतोष को हवा दी जाती है। यह भारत विरोधी भावनाओं को भुनाता है, जैसे कि विकास योजनाओं और सैन्य उपस्थिति पर फोकस करके लोगों को अपनी ओर खींचता है। विचारधारा एक बड़े जिहादी नेटवर्क से प्रभावित है, लेकिन इसे छिपाकर संगठन खुद को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश करता है। टीआरएफ की प्रचार रणनीति में वीडियो और संदेशों का उपयोग प्रमुख है, जो हिंसा को न्यायोचित ठहराते हैं। संगठन के उद्देश्यों में स्थानीय मुद्दों को वैश्विक स्तर पर उठाना शामिल है, जो अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने का माध्यम बनता है।

प्रचार के माध्यम से विद्रोह को बढ़ावा देना संगठन की मुख्य रणनीति है, जहां भारत विरोध को हथियार बनाया जाता है। विचारधारा की छिपी प्रेरणा जिहादी सिद्धांतों से आती है, जो हिंसक कार्रवाइयों में स्पष्ट होती है। टीआरएफ की यह नीति युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है, जहां आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को जोड़ा जाता है। संगठन की गतिविधियां क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाती हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आधार बनती हैं। हालांकि, छिपी प्रेरणा संगठन की सच्चाई को उजागर करती है और शांतिपूर्ण प्रयासों को बाधित करती है।

संगठन की धारणा में कश्मीर की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, जो पाकिस्तानी सहायता से मजबूत होती है और क्षेत्र को भारतीय प्रभाव से मुक्त करने पर जोर देती है। उद्देश्यों में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले करके अराजकता उत्पन्न करना शामिल है, जो प्रशासन को कमजोर बनाता है। टीआरएफ पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं को गद्दार बताकर निशाना बनाता है, जो विपक्षी आवाजों को दबाने का माध्यम है। संगठन की रणनीति में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना प्रमुख है, जहां अल्पसंख्यकों को डराकर

बहुसंख्यक समर्थन जुटाया जाता है। इसके विचारों में पाकिस्तानी समर्थन को छिपाकर स्थानीय संघर्ष का रूप दिया जाता है, लेकिन व्यावहार में विदेशी प्रभाव स्पष्ट है।

स्वतंत्रता पर फोकस पाकिस्तानी मदद से जुड़ा है, जो संगठन की गतिविधियों को मजबूत बनाता है। अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भारत पर दबाव बनाने का तरीका है। पत्रकारों और राजनेताओं को निशाना बनाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती देता है, जो संगठन की कट्टरता को दिखाता है। टीआरएफ की यह नीति लंबे संघर्ष की तैयारी है, जहां नागरिकों को डराकर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। हालांकि, पाकिस्तानी लिंक संगठन की विश्वसनीयता को कमजोर बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय निंदा को आमंत्रित करते हैं।

टीआरएफ के लक्ष्यों में नए सदस्यों की भर्ती और युद्ध प्रशिक्षण शामिल है, जिसमें जंगली इलाकों में लड़ाई की तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विचारधारा स्थानीय प्रतिरोध पर आधारित है, लेकिन पाकिस्तानी संबंध स्पष्ट हैं, जो संगठन को संसाधन प्रदान करते हैं। यह पर्यटन को प्रभावित करके आर्थिक क्षति पहुंचाना चाहता है, जो कश्मीर की मुख्य आय स्रोत को निशाना बनाता है। संगठन की रणनीति में ग्रामीण क्षेत्रों में आधार बनाना प्रमुख है, जहां प्रशिक्षण शिविर चलाए जाते हैं। इसके उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तैयारी दर्शाते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देते हैं।

भर्ती और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पाकिस्तानी लिंकों से मजबूत होती है, जो हथियार और तकनीक प्रदान करते हैं। आर्थिक नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य पर्यटन उद्योग पर हमलों से पूरा होता है, जो भारत की छवि को प्रभावित करता है। टीआरएफ की विचारधारा स्थानीय दिखावे की है, लेकिन विदेशी प्रभाव से यह हिंसक रहती है। संगठन की यह नीति युवाओं को आकर्षित करने के लिए आर्थिक मुद्दों का उपयोग करती है। हालांकि, पाकिस्तानी संबंध संगठन की सच्चाई को उजागर करते हैं और वैश्विक प्रतिबंधों को आमंत्रित करते हैं।

संगठन की धारणा जिहाद से अलग दिखने की है, लेकिन हमलों में धार्मिक लक्ष्यों का प्रभुत्व रहता है, जो सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। उद्देश्यों में हमलों के दावों से वैश्विक ध्यान आकर्षित करना शामिल है, जो कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने का माध्यम है। यह घाटी में भय का माहौल बनाना चाहता है, जो नागरिकों को डराकर समर्थन जुटाता है। टीआरएफ की रणनीति में प्रचार और हिंसा का मिश्रण

प्रमुख है, जो युवाओं को प्रभावित करता है। इसके विचारों में अलगाववाद को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन व्यावहार में धार्मिक कट्टरता हावी है।

जिहाद से दूरी का दावा हमलों की प्रकृति से खारिज होता है, जहां धार्मिक लक्ष्य स्पष्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का लक्ष्य संगठन की प्रचार रणनीति का हिस्सा है, जो मीडिया का उपयोग करता है। डर का वातावरण बनाना क्षेत्रीय सद्भाव को नष्ट करता है, जो लंबे संघर्ष का आधार है। टीआरएफ की यह नीति पाकिस्तानी समर्थन पर टिकी है, जो संसाधन प्रदान करता है। हालांकि, धार्मिक लक्ष्य संगठन की छिपी सच्चाई को उजागर करते हैं और शांति प्रयासों को बाधित करते हैं।

टीआरएफ का मुख्य लक्ष्य पुराने जिहादी गतिविधियों को नए नाम से जारी रखना है, जो पाकिस्तानी एजेंडे से जुड़ा है और क्षेत्रीय अस्थिरता को बनाए रखता है। विचारधारा कश्मीरी स्वायत्तता पर केंद्रित है, लेकिन यह विदेशी हितों से प्रभावित रहती है, जो इस्लामी शासन की स्थापना पर जोर देती है। यह युवाओं को भर्ती करके दीर्घकालिक लड़ाई की योजना बनाता है, जहां शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रमुखता दी जाती है। संगठन की रणनीति में स्थानीय मुद्दों को वैश्विक स्तर पर उठाना शामिल है, जो समर्थन जुटाने का माध्यम है। इसके उद्देश्य हिंसा पर आधारित हैं, जो शांतिपूर्ण समाधान को अस्वीकार करते हैं।

नए नाम से गतिविधियां जारी रखना पाकिस्तानी एजेंडे का हिस्सा है, जो अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचाव करता है। स्वायत्तता की विचारधारा विदेशी प्रभाव से जुड़ी है, जो हिंसक कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करती है। युवाओं की भर्ती लंबे संघर्ष की तैयारी है, जहां आर्थिक प्रलोभन दिए जाते हैं। टीआरएफ की यह नीति क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती देती है, जो भारत पर दबाव बनाने का तरीका है। हालांकि, पाकिस्तानी कनेक्शन संगठन की विश्वसनीयता को कमजोर बनाते हैं और वैश्विक निंदा को बढ़ाते हैं।

संगठन की धारणा में भारत विरोध प्रधान है, जिसमें स्थानीय समस्याओं जैसे जल संसाधन और पर्यावरण मुद्दों को हथियार बनाकर लोगों को उकसाया जाता है। उद्देश्यों में हमलों से राजनीतिक दबाव उत्पन्न करना शामिल है, जो सरकार को नीतियां बदलने पर मजबूर करने का इरादा रखता है। यह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाता है, जो क्षेत्रीय विभाजन को गहरा बनाता है। टीआरएफ की रणनीति में प्रचार और हिंसा का संयोजन प्रमुख है, जो युवाओं को आकर्षित करता

है। इसके विचारों में राष्ट्रीय पहचान को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन व्यावहार में हिंसक प्रतिशोध हावी है।

भारत विरोध का उपयोग स्थानीय मुद्दों से किया जाता है, जो संगठन की प्रचार रणनीति का आधार है। राजनीतिक दबाव बनाने का लक्ष्य हमलों से पूरा होता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। अल्पसंख्यकों पर फोकस सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाता है, जो सद्भाव को नष्ट करने का माध्यम है। टीआरएफ की यह नीति लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तैयारी है, जहां नागरिकों को डराकर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। हालांकि, तनाव बढ़ाने की रणनीति संगठन की क्रूरता को उजागर करती है और शांति प्रयासों को बाधित करती है।

नेतृत्व और संरचना

टीआरएफ के शुरुआती आधार को मुहम्मद अब्बास शेख ने तैयार किया, जो संगठन की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाते हुए विभिन्न हमलों की योजना बनाता था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई, जिसने संगठन को झटका दिया। शेख सज्जाद गुल को इसके मार्गदर्शक और सर्वोच्च कमांडर की भूमिका सौंपी गई, जो रणनीतिक फैसले लेता है और सदस्यों को निर्देशित करता है, उसकी पृष्ठभूमि पुराने उग्रवादी गुटों से जुड़ी हुई है। संगठन एक बड़े पाकिस्तानी नेटवर्क के प्रमुख ऑपरेटरों से सीधा जुड़ा हुआ है, जैसे कि सैफुल्लाह साजिद जट्ट, जो सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति और योजनाओं का समन्वय संभालता है, जिससे टीआरएफ की क्षमता बढ़ती है। गुल की नेतृत्व शैली में गुप्त संचार और छोटे समूहों का उपयोग प्रमुख है, जो जांच एजेंसियों को भ्रमित करने में मदद करता है। संगठन की यह व्यवस्था कश्मीर के जंगली इलाकों में छिपे ठिकानों पर निर्भर है, जहां नेता सदस्यों को प्रेरित करते हैं और लक्ष्यों की पहचान करते हैं।

अब्बास शेख की मौत के बाद गुल ने संगठन को पुनर्गठित किया, जिससे नेतृत्व अधिक विकेंद्रीकृत हो गया और पाकिस्तानी ऑपरेटरों का प्रभाव बढ़ा। जट्ट जैसे व्यक्ति रणनीतिक सलाह देते हैं, जो संगठन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाते हैं। टीआरएफ की संरचना में नेता सदस्यों के बीच मजबूत वफादारी सुनिश्चित करते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। गुल की कमान में संगठन ने कई सफल ऑपरेशन किए, लेकिन सुरक्षा दबाव से नेतृत्व को लगातार बदलाव करने पड़ते हैं।

यह व्यवस्था पाकिस्तानी समर्थन पर टिकी है, जो नेता को सुरक्षित रखते हैं और संसाधन उपलब्ध कराते हैं।

वर्तमान समय में मुख्य ऑपरेशनल कमांडर की भूमिका बासित अहमद डार संभालता था, जो घाटी में हमलों की योजना बनाता था, लेकिन एक मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई, जिसने संगठन की क्षमता को प्रभावित किया। अहमद खालिद को प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर संदेश जारी करके युवाओं को आकर्षित करता है और हमलों की जिम्मेदारी लेता है। संगठन की ढांचागत व्यवस्था एक बड़े जिहादी गुट पर आधारित है, जिसमें विभिन्न कैडर और छोटे-छोटे समूह शामिल हैं, जो लक्षित कार्रवाइयों के लिए तैयार रहते हैं। खालिद की भूमिका प्रचार को मजबूत बनाती है, जो संगठन की छवि को बनाए रखने में मदद करती है। टीआरएफ की यह संरचना लचीली है, जिसमें सदस्यों को विशेष भूमिकाएं सौंपी जाती हैं, जैसे कि भर्ती या हथियार प्रबंधन।

डार की मौत के बाद नए कमांडर की नियुक्ति हुई, लेकिन खालिद का प्रचार कार्य जारी रहा, जो संगठन को वैश्विक स्तर पर चर्चा में रखता है। कैडरों की व्यवस्था पुराने गुटों से प्रेरित है, जो छोटे समूहों में विभाजित होकर काम करते हैं। टीआरएफ की यह ढांचा हमलों की योजना को प्रभावी बनाता है, जहां प्रचार और ऑपरेशन का तालमेल महत्वपूर्ण है। संगठन की संरचना में सदस्यों की ट्रेनिंग पर फोकस रहता है, जो जंगली युद्ध की तकनीकों पर आधारित है। यह व्यवस्था सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, लेकिन लगातार नुकसान से प्रभावित होती है।

कमान में सज्जाद गुल का स्थान प्रमुख है, जो पाकिस्तानी क्षेत्रों से जुड़कर निर्देश प्राप्त करता है और संगठन की दिशा निर्धारित करता है। टीआरएफ की व्यवस्था छोटे-छोटे इकाइयों पर आधारित है, जो चुनिंदा हमलों के लिए डिजाइन की गई हैं और गुप्त रूप से संचालित होती हैं। संगठन भर्ती पर विशेष ध्यान देता है, जिसमें स्थानीय युवाओं के अलावा विदेशी सदस्यों को शामिल किया जाता है, जो विविध कौशल लाते हैं। गुल की नेतृत्व क्षमता में रणनीतिक योजना प्रमुख है, जो संगठन को मजबूत बनाती है। टीआरएफ की यह संरचना कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में फैली है, जहां भर्ती प्रक्रिया आसान होती है।

गुल के पाकिस्तानी कनेक्शन संगठन को संसाधन प्रदान करता है, जो छोटे समूहों की प्रभावशीलता बढ़ाता है। भर्ती का फोकस स्थानीय और विदेशी सदस्यों पर है, जो

संगठन की क्षमता को विस्तार देता है। टीआरएफ की व्यवस्था लक्षित कार्रवाइयों के लिए अनुकूल है, जहां नेता सदस्यों को प्रशिक्षित करते हैं। गुल की कमान में संगठन ने कई सफलताएं हासिल कीं, लेकिन सुरक्षा दबाव से चुनौतियां बढ़ी हैं। यह ढांचा विदेशी सहयोग पर निर्भर है, जो भर्ती को सुगम बनाता है।

टीआरएफ एक बड़े जिहादी गुट का विस्तारित रूप है, जो उसके अनुभवी सदस्यों का उपयोग करके अपनी क्षमता बढ़ाता है। कमान में पुराने सदस्यों की भागीदारी प्रमुख है, जैसे कि सज्जाद गुल, जो रणनीतिक फैसले लेता है और संगठन को दिशा देता है। संरचना में डिजिटल टीम शामिल है, जो हमलों का प्रचार करती है और युवाओं को आकर्षित करने के लिए सामग्री तैयार करती है। गुल की भूमिका संगठन को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण है, जो पुराने कैडरों के अनुभव पर टिकी है। टीआरएफ की यह व्यवस्था प्रचार और ऑपरेशन का मिश्रण है, जो प्रभावी साबित होती है।

विस्तारित रूप होने से टीआरएफ पुराने सदस्यों से लाभ उठाता है, जो कमान को मजबूत बनाते हैं। डिजिटल टीम का कार्य हमलों को बढ़ावा देना है, जो संगठन की छवि को बनाए रखता है। गुल जैसे नेता रणनीति निर्धारित करते हैं, जो कैडरों की क्षमता बढ़ाती है। टीआरएफ की संरचना प्रचार पर फोकस करती है, जहां युवाओं को लक्षित किया जाता है। यह ढांचा पुराने गुटों से प्रेरित है, लेकिन आधुनिक माध्यमों से मजबूत है।

संगठन के प्रमुख व्यक्ति पाकिस्तानी इलाकों में छिपे रहते हैं, जहां से वे ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं और सदस्यों को निर्देश देते हैं। ढांचा विभाजित है, जिसमें छोटे-छोटे इकाइयां शामिल हैं, जो गुप्त कार्रवाइयों के लिए उपयुक्त हैं। कमान भर्ती और हथियारों की आपूर्ति का प्रबंधन करती है, जो संगठन की सैन्य ताकत को बनाए रखती है। नेता पाकिस्तानी आधार से काम करते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करता है। टीआरएफ की यह व्यवस्था छोटे सेलों पर टिकी है, जो लचीली और प्रभावी है।

पाकिस्तानी छिपाव कमान को सुरक्षित रखता है, जहां से ऑपरेशन निर्देशित होते हैं। विकेंद्रीकृत ढांचा छोटे इकाइयों से मिलकर बना है, जो भर्ती को सुगम बनाता है। नेता हथियार सप्लाई संभालते हैं, जो संगठन की क्षमता बढ़ाती है। टीआरएफ की यह संरचना गुप्त रहने में सक्षम है, लेकिन दबाव से प्रभावित होती है। पाकिस्तानी आधार कमान की मजबूती का स्रोत है, जो दीर्घकालिक योजना की अनुमति देता है।

मुहम्मद अब्बास शेख ने आधार तैयार किया, उसकी पृष्ठभूमि एक अन्य उग्रवादी गुट से जुड़ी थी, जो संगठन को अनुभव प्रदान करती है। ढांचा में जंगली लड़ाई में निपुण सदस्य शामिल हैं, जो कठिन इलाकों में ऑपरेशन चलाते हैं। कमान एक बड़े नेटवर्क से समन्वय रखती है, जो संसाधनों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करता है। शेख की भूमिका स्थापना में प्रमुख थी, जो संगठन को दिशा देती है। टीआरएफ की यह व्यवस्था प्रशिक्षित सदस्यों पर निर्भर है, जो युद्ध कौशल से मजबूत है।

अन्य गुट से जुड़ाव शेख को अनुभव देता है, जो संगठन की नींव मजबूत बनाता है। जंगली युद्ध प्रशिक्षित सदस्य ढांचा का हिस्सा हैं, जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कमान समन्वय से संगठन को लाभ होता है, जो हथियार और योजना प्रदान करता है। टीआरएफ की संरचना युद्ध कौशल पर फोकस करती है, जहां सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अन्य नेटवर्क से संबंध संगठन की क्षमता बढ़ाता है, लेकिन जोखिम भी लाता है।

टीआरएफ की व्यवस्था एक बड़े गुट से मिलती-जुलती है, लेकिन इसे स्थानीय रूप दिया गया है, जो जांच से बचाव में मदद करता है। नेता जैसे सैफुल्लाह साजिद जट्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रणनीति तैयार करता है और सदस्यों को निर्देशित करता है। संगठन पाकिस्तानी मदद से संचालित होता है, जो फंडिंग और हथियार प्रदान करता है। जट्ट की भागीदारी कमान को मजबूत बनाती है, जो स्थानीय दिखावे के साथ काम करती है। टीआरएफ की यह ढांचा पाकिस्तानी समर्थन पर टिकी है, जो दीर्घायु सुनिश्चित करती है।

मिलती-जुलती व्यवस्था स्थानीय छवि देती है, जो नेता को गुप्त रखती है। जट्ट जैसे व्यक्ति रणनीति संभालते हैं, जो संगठन को प्रभावी बनाते हैं। पाकिस्तानी समर्थन फंडिंग से संगठन चलता है, जो हथियार उपलब्ध कराता है। टीआरएफ की संरचना स्थानीय और विदेशी तत्वों का मिश्रण है, जहां नेता प्रमुख फैसले लेते हैं। पाकिस्तानी मदद संगठन की मजबूती का आधार है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव से प्रभावित होती है।

संगठन में खालिद प्रचार का कार्य संभालता है, जो संदेश तैयार करके युवाओं को प्रभावित करता है और हमलों को बढ़ावा देता है। ढांचा में भर्ती जाल शामिल है, जो नए सदस्यों को लुभाने के लिए डिजाइन किया गया है। कमान हमलों की योजना बनाती है, जो सदस्यों को निर्देशित करती है और लक्ष्य निर्धारित करती है। खालिद

की भूमिका प्रचार को मजबूत बनाती है, जो संगठन की छवि बनाती है। टीआरएफ की यह व्यवस्था भर्ती और योजना पर फोकस करती है, जो प्रभावी साबित होती है।

प्रचार संभालने से खालिद संगठन को वैश्विक स्तर पर चर्चा में रखता है, जो युवाओं को आकर्षित करता है। भर्ती नेटवर्क ढांचा का हिस्सा है, जो नए सदस्यों को जोड़ता है। कमान योजना बनाती है, जो हमलों को सफल बनाती है। टीआरएफ की संरचना प्रचार और भर्ती का तालमेल रखती है, जहां युवाओं पर फोकस रहता है। खालिद का कार्य संगठन की मजबूती बढ़ाता है, लेकिन सुरक्षा जोखिम भी लाता है।

टीआरएफ में नेता की मौत पर नए व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जैसे बासित डार, जो कमान संभालता है और संगठन को आगे बढ़ाता है। ढांचा अनुकूलनीय है, जो मुठभेड़ों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है और गुप्त रहता है। संगठन एक बड़े गुट के संसाधनों पर आश्रित है, जो हथियार और फंडिंग प्रदान करता है। डार जैसे नए नेता कमान को नई दिशा देते हैं, जो संगठन की क्षमता बनाए रखते हैं। टीआरएफ की यह व्यवस्था लचीली है, जो चुनौतियों से निपटने में सक्षम है।

नई नियुक्तियां मौत के बाद होती हैं, जो संगठन को स्थिर रखती हैं। अनुकूलनीय ढांचा मुठभेड़ों से बचाव करता है, जो गुप्त ऑपरेशन सुनिश्चित करता है। बड़े गुट के संसाधन संगठन को मजबूत बनाते हैं, जो दीर्घकालिक अस्तित्व की गारंटी देते हैं। टीआरएफ की संरचना नए नेताओं पर निर्भर है, जो योजना और भर्ती संभालते हैं। संसाधनों की आश्रिता संगठन की मजबूती का स्रोत है, लेकिन निर्भरता जोखिम भी बढ़ाती है।

प्रमुख हमले और गतिविधियाँ

अप्रैल 2020 में कुपवाड़ा जिले के केरन क्षेत्र में टीआरएफ ने भारतीय पैरा स्पेशल फोर्स के पांच सदस्यों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सभी पांच सैनिक शहीद हो गए और हमलावरों में से दो सदस्य भी मारे गए, यह संगठन की पहली बड़ी मुठभेड़ थी जो घने जंगलों में हुई। इस घटना ने टीआरएफ को कश्मीर घाटी में एक नई उग्रवादी ताकत के रूप में स्थापित किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सीमा के पास घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय बलों को चुनौती दी। हमले की योजना में छोटे समूहों का उपयोग किया गया, जो संगठन की शुरुआती रणनीति को दर्शाता है, जिसमें सीमा पार से प्राप्त हथियारों का इस्तेमाल प्रमुख था। इस मुठभेड़ ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद घाटी में खोज अभियान तेज हुए और कई संदिग्धों को

गिरफ्तार किया गया। टीआरएफ ने इस हमले का दावा सोशल मीडिया पर किया, जो उनकी प्रचार रणनीति को दर्शाता है और युवाओं को आकर्षित करने का माध्यम बना। हैडवारा हमले के बाद टीआरएफ की गतिविधियां तेज हुईं, लेकिन उच्च अधिकारियों की मौत ने संगठन की क्षमता को उजागर किया। हैडवारा जैसे इलाकों में ऐसे अभियान स्थानीय नेटवर्क पर निर्भर होते हैं, जहां युवाओं को भर्ती किया जाता है। भारतीय बलों ने जवाब में कई मॉड्यूल तोड़े, जिससे टीआरएफ को नुकसान हुआ। यह घटना कश्मीर में उग्रवाद की बदलती प्रकृति को दिखाती है, जहां लक्षित हमले प्रमुख हो गए हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने मीडिया ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन दबाव में आया।

जून 2020 में टीआरएफ ने एक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या कर दी, जो अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाली घटना थी और संगठन ने इसका दावा किया, यह राजनीतिक हत्याओं की श्रृंखला का हिस्सा था। इस हमले में सरपंच को उनके घर के पास घात लगाकर मारा गया, जो टीआरएफ की रणनीति को दर्शाता है जिसमें स्थानीय नेताओं को डराकर समर्थन जुटाया जाता है। घटना ने कश्मीरी पंडित समुदाय में डर पैदा किया, जिसके बाद कई परिवारों ने सुरक्षा की मांग की। टीआरएफ ने इस हत्या को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया, जो उनकी वैचारिक रणनीति को दर्शाता है। भारतीय सरकार ने जवाब में जांच तेज की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया।

इस हत्या के बाद टीआरएफ की गतिविधियां अल्पसंख्यकों पर केंद्रित हुईं, लेकिन सरपंच की मौत ने संगठन की क्रूरता को उजागर किया। ऐसे हमले स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, जहां पंडित समुदाय पहले से ही विस्थापित है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को पीछे हटना पड़ा। यह घटना कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव को दिखाती है, जहां उग्रवादी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन पर दबाव बढ़ा।

जुलाई 2020 में बैडीपोरा में टीआरएफ ने तीन नागरिकों की हत्या की, जिसमें एक बीजेपी नेता, उनके पिता और भाई शामिल थे, यह राजनीतिक हत्याओं की श्रृंखला थी जो स्थानीय नेताओं को डराने का उद्देश्य रखती थी। हमले में हमलावरों ने बैठक स्थल पर घात लगाई, जो टीआरएफ की लक्षित रणनीति को दर्शाता है। घटना ने

राजनीतिक दलों में डर पैदा किया, जिसके बाद कई बैठकें रद्द की गईं। टीआरएफ ने इस हत्या का दावा किया, जो उनकी प्रचार नीति का हिस्सा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जवाब में अभियान चलाए और कई सदस्यों को गिरफ्तार किया।

बैंडीपोरा हमले के बाद टीआरएफ की गतिविधियां राजनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित हुईं, लेकिन हत्याओं ने संगठन की हिंसक प्रकृति को उजागर किया। ऐसे हमले राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से होते हैं, जहां काउंसिलर मुख्य लक्ष्य हैं। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में छापेमारी बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को नुकसान हुआ। यह घटना कश्मीर में राजनीतिक हिंसा को दिखाती है, जहां उग्रवादी बैठकें निशाना बनाते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन पर दबाव बढ़ा।

अप्रैल 2025 में पहलगाम में टीआरएफ ने 26 पर्यटकों पर हमला किया, जो दशक का सबसे बड़ा अभियान था और पर्यटकों को निशाना बनाकर दहशत फैलाई, यह घटना पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाली थी। हमले में हमलावरों ने एक पर्यटक स्थल पर घात लगाई, जो टीआरएफ की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की, जिसके बाद अमेरिका ने संगठन को आतंकवादी घोषित किया। टीआरएफ ने इस हमले का दावा किया, लेकिन बाद में वापस लिया, जो उनकी प्रचार नीति का हिस्सा था। भारतीय सरकार ने जवाब में अभियान तेज किए और कई संदिग्धों को मार गिराया।

पहलगाम हमले के बाद टीआरएफ की गतिविधियां पर्यटकों पर केंद्रित हुईं, लेकिन मौतों की संख्या ने संगठन की क्रूरता को उजागर किया। ऐसे अभियान आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से होते हैं, जहां पर्यटन मुख्य आय है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तैनाती बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को पीछे हटना पड़ा। यह घटना कश्मीर में पर्यटन हिंसा को दिखाती है, जहां उग्रवादी अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन पर प्रतिबंध लगे।

जून 2024 में रियासी में टीआरएफ ने हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिसमें नौ यात्री मारे गए और 33 घायल हो गए, बस खाई में गिर गई और यह धार्मिक यात्रा को निशाना बनाने वाली घटना थी। हमले में हमलावरों ने बस पर गोलीबारी की, जो टीआरएफ की सांप्रदायिक रणनीति को दर्शाता है। घटना ने धार्मिक समुदायों

में डर पैदा किया, जिसके बाद यात्रा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। टीआरएफ ने इस हमले का दावा किया, जो उनकी प्रचार नीति का हिस्सा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जवाब में खोज अभियान बढ़ाए और कई सदस्यों को गिरफ्तार किया।

रियासी हमले के बाद टीआरएफ की गतिविधियां धार्मिक लक्ष्यों पर केंद्रित हुईं, लेकिन मौतों ने संगठन की हिंसक प्रकृति को उजागर किया। ऐसे अभियान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के उद्देश्य से होते हैं, जहां यात्राएं मुख्य लक्ष्य हैं। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को नुकसान हुआ। यह घटना कश्मीर में धार्मिक हिंसा को दिखाती है, जहां उग्रवादी यात्रियों को निशाना बनाते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने मीडिया ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन दबाव में आया।

मार्च 2021 में सोपोर में टीआरएफ ने दो काउंसिलरों और एक पुलिसकर्मी की हत्या की, जो बीजेपी की बैठक पर हमला था और राजनीतिक लक्ष्य रखता था। हमले में हमलावरों ने बैठक स्थल पर घात लगाई, जो टीआरएफ की लक्षित रणनीति को दर्शाता है। घटना ने राजनीतिक दलों में डर पैदा किया, जिसके बाद कई बैठकें रद्द की गईं। टीआरएफ ने इस हमले का दावा किया, जो उनकी प्रचार नीति का हिस्सा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जवाब में अभियान चलाए और कई सदस्यों को गिरफ्तार किया।

सोपोर हमले के बाद टीआरएफ की गतिविधियां राजनीतिक हत्याओं पर केंद्रित हुईं, लेकिन मौतों ने संगठन की क्रूरता को उजागर किया। ऐसे हमले राजनीतिक प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से होते हैं, जहां काउंसिलर मुख्य लक्ष्य हैं। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में छापेमारी बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को नुकसान हुआ। यह घटना कश्मीर में राजनीतिक हिंसा को दिखाती है, जहां उग्रवादी बैठकें निशाना बनाते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन पर दबाव बढ़ा।

दिसंबर 2020 में गंदरबल में टीआरएफ ने दो सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड हमला किया, जो सुरक्षा बलों पर फोकस रखता था और जवान मारे गए। हमले में हमलावरों ने व्यस्त इलाके में ग्रेनेड फेंका, जो टीआरएफ की शहरी रणनीति को दर्शाता है। घटना ने सुरक्षा बलों में सतर्कता बढ़ाई, जिसके बाद गश्त तेज हुई। टीआरएफ ने इस हमले

का दावा किया, जो उनकी प्रचार नीति का हिस्सा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जवाब में अभियान चलाए और कई सदस्यों को गिरफ्तार किया।

गंदरबल हमले के बाद टीआरएफ की गतिविधियां सुरक्षा बलों पर केंद्रित हुईं, लेकिन मौतों ने संगठन की आक्रामकता को उजागर किया। ऐसे अभियान शहरी क्षेत्रों में होते हैं, जहां ग्रेनेड मुख्य हथियार है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तैनाती बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को नुकसान हुआ। यह घटना कश्मीर में सुरक्षा हिंसा को दिखाती है, जहां उग्रवादी जवानों को निशाना बनाते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन दबाव में आया।

2022 में टीआरएफ ने पत्रकारों की हिट लिस्ट जारी की, जिससे कई ने इस्तीफा दे दिया और पहले के हमलों जैसे शुजात बुखारी की हत्या से जुड़ा था, उद्देश्य मीडिया को डराना था। लिस्ट में संगठन ने पत्रकारों को धमकी दी, जो टीआरएफ की प्रचार रणनीति को दर्शाता है। घटना ने मीडिया समुदाय में डर पैदा किया, जिसके बाद कई ने सुरक्षा मांगी। टीआरएफ ने इस लिस्ट का प्रचार किया, जो उनकी वैचारिक नीति का हिस्सा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जवाब में जांच तेज की और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

हिट लिस्ट जारी करने के बाद टीआरएफ की गतिविधियां मीडिया पर केंद्रित हुईं, लेकिन इस्तीफों ने संगठन की प्रभावशीलता को उजागर किया। ऐसे हमले अभिव्यक्ति को दबाने के उद्देश्य से होते हैं, जहां पत्रकार मुख्य लक्ष्य हैं। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में छानबीन बढ़ाई, जिससे टीआरएफ को पीछे हटना पड़ा। यह घटना कश्मीर में मीडिया हिंसा को दिखाती है, जहां उग्रवादी धमकियां देते हैं। टीआरएफ की इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, लेकिन लंबे समय में संगठन पर दबाव बढ़ा।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और नामांकन

भारत सरकार ने जनवरी 2023 में टीआरएफ को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया, जो गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत किया गया था और मुख्य कारण युवाओं की भर्ती तथा हथियारों की अवैध तस्करी थे, जिसने संगठन की गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने का रास्ता खोला। इस घोषणा के बाद सुरक्षा एजेंसियां जैसे एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संगठन के कई मॉड्यूलों को ध्वस्त किया, जिसमें दर्जनों सदस्यों की गिरफ्तारियां

हुई और हथियारों के जखीरे जब्त किए गए, जो घाटी में उग्रवाद को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। भारत की इस कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जहां टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का छद्म रूप मानते हुए अन्य देशों से सहयोग मांगा गया। घोषणा के परिणामस्वरूप संगठन की फंडिंग चैनलों पर नजर रखी गई, जो पाकिस्तानी स्रोतों से जुड़े थे। भारत की सुरक्षा रणनीति में यह कदम उग्रवाद विरोधी अभियानों को मजबूत बनाता है, जहां मॉड्यूलों को तोड़ना स्थानीय स्तर पर शांति बहाली की कुंजी है।

इस नामांकन ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूत किया, जहां भर्ती और तस्करी जैसे मुद्दों पर फोकस से संगठन की जड़ों को कमजोर किया गया। सुरक्षा एजेंसियों के अभियानों में कई सफलताएं मिलीं, जैसे कि श्रीनगर और अनंतनाग में ठिकानों का ध्वस्त होना। भारत ने इस घोषणा को वैश्विक मंचों पर उठाया, जहां टीआरएफ की गतिविधियों को प्रमाणित किया गया। फंडिंग पर अंकुश से संगठन की क्षमता प्रभावित हुई, जो पाकिस्तानी सहायता पर निर्भर थी। यह कदम घाटी में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जहां मॉड्यूलों का टूटना उग्रवाद को रोकने में सहायक सिद्ध होता है।

अमेरिका ने जुलाई 2025 में टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया, जो पहलगाम हमले के बाद की प्रतिक्रिया थी और संगठन पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए गए, जिसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। इस नामांकन से टीआरएफ के सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती जैसे उपाय लागू हुए, जो लश्कर-ए-तैयबा के छद्म रूप को उजागर करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम कश्मीर में हिंसा को रोकने के लिए है, जहां पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में इनकार प्रमुख था, लेकिन यह नामांकन भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिका की यह कार्रवाई वैश्विक आतंकवाद विरोधी गठबंधनों को मजबूत बनाती है, जहां पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता है।

जुलाई 2025 के नामांकन ने पहलगाम घटना को प्रत्यक्ष कारण बताया, जो संगठन की गतिविधियों पर कड़ा प्रहार था और पाकिस्तान की नीतियों को चुनौती दी। FTO और SDGT की श्रेणी से टीआरएफ पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, जो सदस्यों की गतिविधियों को सीमित करते हैं। अमेरिकी घोषणा ने लश्कर के लिंक को प्रमाणित

किया, जो कश्मीर हिंसा के स्रोत को उजागर करती है। पाकिस्तान को झटका इसलिए लगा क्योंकि यह उनकी अस्वीकृति को खारिज करता है। यह कदम वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है, जहां आतंकवाद विरोधी प्रयास मजबूत होते हैं।

पाकिस्तान टीआरएफ का बचाव करता रहा है, जहां हमलों की निंदा तो की जाती है लेकिन समर्थन से इनकार किया जाता है, और विदेश मंत्री ने कश्मीर हमलों को स्थानीय प्रतिक्रिया बताकर भारत पर आरोप लगाए। भारत इसे पाकिस्तानी समर्थित मानता है, जहां आईएसआई की भूमिका को प्रमाणित करते हुए सबूत पेश किए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में टीआरएफ को कश्मीरी संघर्ष का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में इसे प्रॉक्सी कहा गया। मंत्री के बयानों ने द्विपक्षीय तनाव बढ़ाया, जहां भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विरोध जताया। पाकिस्तान की यह नीति वैश्विक दबाव से बचने की है, लेकिन सबूत विपरीत हैं।

टीआरएफ का बचाव पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा है, जहां निंदा के साथ इनकार से जिम्मेदारी से बचा जाता है। मंत्री के कश्मीर संदर्भ ने भारत को पाकिस्तानी सहायता का आरोप लगाने का मौका दिया। भारत के सबूतों में फंडिंग और प्रशिक्षण के प्रमाण शामिल हैं, जो टीआरएफ को समर्थित साबित करते हैं। पाकिस्तानी दृष्टिकोण ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया, जहां भारत ने मजबूत स्टैंड लिया। यह स्थिति पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करती है, जहां समर्थन से इनकार सबूतों के विपरीत है।

संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा को प्रतिबंधित किया गया है, जहां टीआरएफ को इसका प्रॉक्सी माना जाता है और 1267 समिति के तहत कार्रवाई की मांग की गई। FATF की निगरानी के कारण टीआरएफ का गठन हुआ, जो पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट स्थिति से जुड़ा है और पुराने गुटों पर प्रतिबंधों से बचाव का तरीका था। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, जहां भारत ने UNSC में सबूत पेश किए और सहयोग मांगा। FATF की बैठकों में पाकिस्तान पर आतंकवाद फंडिंग रोकने का दबाव है, जो टीआरएफ जैसे गुटों को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र की यह स्थिति वैश्विक आतंकवाद विरोध को मजबूत बनाती है, जहां प्रॉक्सी गुटों पर फोकस है।

लश्कर का प्रतिबंध टीआरएफ को प्रॉक्सी के रूप में देखने का आधार है, जहां FATF की नजर से बचने के लिए नया नाम अपनाया गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव से पाकिस्तान की नीतियां प्रभावित हुईं, जहां भारत के प्रयास सफल रहे। UN की समिति ने सबूतों

पर विचार किया, जो टीआरएफ की गतिविधियों को उजागर करते हैं। FATF की ग्रे लिस्ट ने पाकिस्तान को मजबूर किया, लेकिन दबाव जारी है। यह स्थिति वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है, जहां प्रॉक्सी गुटों पर कार्रवाई तेज होती है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के वादे के तहत न्याय की बात की, जहां हमलावरों को सजा देने का आश्वासन दिया गया और जांच तेज की गई। अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की। सैन्य उपस्थिति बढ़ाई गई, जो जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त बलों की तैनाती से हुई और सीमा पर निगरानी मजबूत की गई। मोदी के बयान ने राष्ट्र को एकजुट किया, जहां आतंकवाद विरोधी नीति पर जोर दिया गया। शाह के दौरों ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए, जो हमलों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हैं।

सैन्य तैनाती से घाटी में स्थिरता आई, जो सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाती है। भारत की प्रतिक्रिया ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाया, जहां हमले की निंदा हुई। यह कदम आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत बनाता है, जहां दौरे और वादे महत्वपूर्ण हैं।

अमेरिकी नामांकन से टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध लगे, जो पाकिस्तान की झूठी दावों को उजागर करते हैं और संगठन की फंडिंग को रोकते हैं। यह पहलगाम हमले का सीधा नतीजा था, जहां 26 मौतों ने वैश्विक ध्यान खींचा और नामांकन को तेज किया। वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट में टीआरएफ का उल्लेख हुआ, जो लश्कर के लिंक को प्रमाणित करता है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता है। प्रतिबंधों से सदस्यों की संपत्ति जब्त हुई, जो संगठन की क्षमता को कमजोर बनाती है। रिपोर्ट ने कश्मीर हिंसा को वैश्विक मुद्दा बनाया, जहां पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठे।

नामांकन ने पाकिस्तान की अस्वीकृति को चुनौती दी, जो पहलगाम घटना से जुड़ा था। रिपोर्ट में उल्लेख से टीआरएफ की गतिविधियां उजागर हुईं, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाती हैं। प्रतिबंध फंडिंग रोकते हैं, जो संगठन को कमजोर करते हैं। यह परिणाम कश्मीर हिंसा पर वैश्विक फोकस लाता है, जहां पाकिस्तान पर आरोप मजबूत होते हैं। रिपोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो आतंकवाद पर आंकड़े प्रदान करती है।

पाकिस्तान टीआरएफ को कश्मीरी प्रतिरोध बताता है, लेकिन सबूत जैसे फंडिंग और प्रशिक्षण विपरीत साबित करते हैं और भारत ने इनका उपयोग किया। भारत ने युद्ध की धमकी दी, जहां रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी की और सीमा पर

सतर्कता बढ़ाई। कूटनीतिक तनाव बढ़ा, जहां दोनों देशों के बीच वार्ता रुकी और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग हुई। पाकिस्तान की नीति दोहरी है, जहां प्रतिरोध का दावा सबूतों से खारिज होता है। भारत की धमकी ने पाकिस्तान को बचाव की स्थिति में डाला, जो तनाव को गहरा बनाती है।

टीआरएफ को प्रतिरोध कहना पाकिस्तान की रणनीति है, लेकिन सबूत भारत के पक्ष में हैं। युद्ध धमकी से कूटनीतिक संबंध प्रभावित हुए, जहां वार्ता स्थगित हुई। तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में आई, जहां मध्यस्थता की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान की दावेदारी सबूतों से कमजोर है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर होती है। भारत की प्रतिक्रिया मजबूत है, जो धमकी से पाकिस्तान पर दबाव बनाती है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने टीआरएफ को लश्कर का फ्रंट बताया, जहां रिपोर्टों में पाकिस्तानी लिंक उजागर किए गए और हमलों की कड़ी निंदा की गई। हमलों की निंदा वैश्विक स्तर पर हुई, जहां मानवाधिकार संगठनों ने बयान जारी किए और नागरिक मौतों पर चिंता जताई। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा, जहां मीडिया कवरेज से FATE और UN में चर्चा हुई। मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जो टीआरएफ की सच्चाई को सामने लाती है। निंदा ने पाकिस्तान की अलगाव को बढ़ाया, जो दबाव का स्रोत बना।

टीआरएफ को फ्रंट कहना मीडिया की रिपोर्टों में प्रमुख था, जो पाकिस्तानी सहायता को उजागर करती हैं। हमलों की निंदा से वैश्विक समुदाय एकजुट हुआ, जहां रिपोर्टों ने मौतों पर फोकस किया। दबाव से पाकिस्तान की नीतियां प्रभावित हुईं, जहां अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठे। मीडिया कवरेज ने टीआरएफ की गतिविधियों को प्रमाणित किया, जो निंदा को मजबूत बनाता है। पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव अलगाव की ओर ले जाता है, जो वैश्विक प्रतिक्रिया का हिस्सा है।

भारत ने फरवरी 2023 तक टीआरएफ को UAPA के तहत सूचीबद्ध किया, जो संगठन की गतिविधियों पर कानूनी अंकुश लगाता है और सदस्यों की गिरफ्तारी आसान बनाता है। वैश्विक सहयोग बढ़ा, जहां अमेरिका और अन्य देशों ने सूचना साझा की और संयुक्त अभियान चलाए। संगठन पर प्रतिबंध प्रभावी सिद्ध हुए, जो फंडिंग और भर्ती को रोकते हैं। सूचीबद्ध करने से भारत की आतंकवाद विरोधी नीति मजबूत हुई, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करती है। सहयोग ने संगठन की क्षमता कम की, जो प्रतिबंधों की सफलता दिखाता है।

UAPA सूचीबद्ध ने टीआरएफ पर कानूनी दबाव बढ़ाया, जो 2023 तक पूरा हुआ और गतिविधियों को सीमित करता है। वैश्विक सहयोग से सूचना आदान-प्रदान बढ़ा, जो अभियानों को प्रभावी बनाता है। प्रतिबंधों से फंडिंग रुकी, जो संगठन को कमजोर करती है। भारत की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाती है, जो आतंकवाद विरोध में महत्वपूर्ण है। प्रभावी प्रतिबंध संगठन की जड़ों को प्रभावित करते हैं, जो सहयोग की सफलता दर्शाते हैं।

अध्याय 4: लश्कर-ए-तैयबा (LeT)

लश्कर-ए-तैयबा की उत्पत्ति, स्थापना और ऐतिहासिक विकास

लश्कर-ए-तैयबा, जिसका अर्थ “शुद्धों की सेना” या “धर्मपरायणों की सेना” है, एक पाकिस्तान-आधारित कट्टर इस्लामी आतंकवादी संगठन है, जिसकी स्थापना 1980 के दशक के अंत में हुई थी और यह मूल रूप से अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद के संदर्भ में उभरा। इसकी जड़ें 1985-1986 में जाती हैं, जब हाफिज मोहम्मद सईद और ज़फर इक़बाल ने जमात-उद-दावा नामक एक मिशनरी समूह की स्थापना की, जो अहल-ए-हदीस इस्लामी विचारधारा को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। 1986 में, ज़की-उर-रहमान लखवी ने अपने सोवियत-विरोधी जिहादी समूह को जमात-उद-दावा के साथ विलय कर मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद का गठन किया, और लश्कर-ए-तैयबा को 1990 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद की सैन्य शाखा के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका तीन व्यक्तियों-हाफिज मोहम्मद सईद (एक पूर्व इस्लामी अध्ययन प्रोफेसर और वैचारिक नेता), ज़फर इक़बाल, और फिलिस्तीनी जिहादी नेता अब्दुल्ला अज़्ज़ाम-ने निभाई, जबकि ओसामा बिन लादेन ने प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान की। सोवियत-अफगान युद्ध (1979-1989) के दौरान, लश्कर-ए-तैयबा को अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा मुजाहिदीन आंदोलन के समर्थन में खड़ा किया गया, जहां यह मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद की सैन्य इकाई के रूप में कार्य करता था। प्रारंभिक वर्षों में, लश्कर-ए-तैयबा ने अफगानिस्तान के शिविरों में अल-कायदा के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां हजारों जिहादियों को कट्टर सलफी-वहाबी विचारधारा के साथ हथियारबंद जिहाद का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे यह एक शक्तिशाली सैन्य संगठन में विकसित हुआ। इस दौरान, लश्कर-ए-तैयबा ने उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से वित्तीय, सैन्य और रणनीतिक समर्थन प्राप्त करना शुरू किया, जो 1991 से स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

1989 में सोवियत सेनाओं की अफ़ग़ानिस्तान से वापसी के बाद, लश्कर-ए-तैयबा ने अपना मुख्य ध्यान भारत के जम्मू-कश्मीर पर केंद्रित कर दिया, जहां यह पाकिस्तान की अंतर-सेवा गुप्तचर एजेंसी के सहयोग से भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध की रणनीति अपनाने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत में लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू की, भारतीय सेना पर हमले किए, और 1993 से हिंसा की घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हुआ, जिनमें हिन्दू और सिख नागरिकों को निशाना बनाना भी शामिल था। इसी दशक में लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तान के मुरिदके (लाहौर के पास) में एक विशाल मुख्यालय स्थापित किया, जो 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला था और जिसमें विद्यालय, मदरसे, अस्पताल, मस्जिदें, समाचार केंद्र और प्रशिक्षण शिविर शामिल थे। यहां हजारों युवाओं को वैचारिक ब्रेनवॉश के साथ-साथ गुरिल्ला युद्ध, विस्फोटक यंत्र निर्माण और आत्मघाती हमलों का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे लश्कर-ए-तैयबा की संरचना एक संगठित सेना जैसी बन गई, जिसमें अनुमानित 15,000 से अधिक सक्रिय लड़ाके शामिल थे। हाफ़िज़ सईद ने संगठन को वैचारिक नेतृत्व प्रदान किया, जबकि ज़की-उर-रहमान लखवी ने सैन्य रणनीति और अभियानों का संचालन किया, जिससे लश्कर-ए-तैयबा भारत के लिए सबसे घातक आतंकी खतरा बन गया। 1999 में लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की और 2000 में दिल्ली के लाल क़िले पर हमला (जिसमें तीन लोग मारे गए) तथा चिट्टीसिंहपुरा नरसंहार (36 सिखों की हत्या) जैसी घटनाओं के माध्यम से अपनी हिंसक क्षमता का प्रदर्शन किया।

2001 में भारतीय संसद पर हमले (लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ) के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, जिससे ब्रिटेन ने 28 मार्च 2001 को लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया, अमेरिका ने 5 दिसंबर 2001 को विदेशी आतंकवादी संगठन सूची में शामिल किया, और पाकिस्तान ने 12 जनवरी 2002 को मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद, लश्कर-ए-तैयबा ने 'जमात-उद-दावा' के नाम से एक सामाजिक संगठन का मुखौटा अपनाया, जो सतह पर शिक्षा, स्वास्थ्य, और राहत कार्य (जैसे 2005 कश्मीर भूकंप में सहायता) करता दिखता था, लेकिन वास्तव में यह लश्कर-ए-तैयबा की भर्ती, वित्तपोषण, और प्रचार का माध्यम बना रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2005 में लश्कर-ए-तैयबा को अल-कायदा से जुड़े संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया, और 2008 मुंबई हमलों (166 मारे गए) के बाद 11 दिसंबर 2008 को जमात-उद-दावा को लश्कर-ए-तैयबा

का फ्रंट घोषित कर प्रतिबंधित किया। पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध लगाया और हाफिज सईद को गिरफ्तार किया, लेकिन वह जल्द रिहा हो गया। 2009 में, जमात-उद-दावा ने तहरीक-ए-तहाफुज किबला अव्वल के रूप में पुनर्गठित होने का प्रयास किया, और 2017 में मिल्ली मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश की, जिसकी पंजीकरण पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अस्वीकार कर दिया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद, पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा और इसके चैरिटी विंग फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया, जिसके बाद ये अल मदीना और ऐसर फाउंडेशन जैसे नए नामों से सक्रिय हुए।

2019 में, लश्कर-ए-तैयबा ने “प्रतिरोध मोर्चा” नाम से एक नया प्रॉक्सी संगठन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य कश्मीर में हिंसा को स्थानीय विद्रोह का रंग देना था, ताकि अंतरराष्ट्रीय जांच से बचा जा सके और नई पीढ़ी के युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से भर्ती किया जा सके। प्रतिरोध मोर्चा को लश्कर-ए-तैयबा का ही एक चेहरा माना जाता है, और 2023 में भारत ने इसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया, जबकि इसका कमांडर शेख सज्जाद गुल को आतंकवादी घोषित किया। लश्कर-ए-तैयबा की वैश्विक पहुंच भी बढ़ी, जहां यह बोस्निया, चेचन्या, फिलीपींस, मध्य पूर्व, अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय पाया गया, और अल-कायदा, तालिबान, और अन्य जिहादी समूहों के साथ सहयोग किया। 2020 में, हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में खुले रूप से कार्य करता रहा। 2022 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा के अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित प्रशिक्षण शिविरों का उल्लेख किया गया। 2024 में, लश्कर-ए-तैयबा के खुफिया प्रमुख चीमा (2008 मुंबई साजिशकर्ता) की पाकिस्तान में मौत हुई, और कई जिहादी समूहों ने तालिबान से निष्ठा जताई।

लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियां जारी रहीं, जिसमें अप्रैल में प्रतिरोध मोर्चा द्वारा पहलगाम हमले (26 पर्यटकों की मौत) की जिम्मेदारी ली गई (बाद में अस्वीकार), जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरिदके में लश्कर-ए-तैयबा शिविर पर बमबारी की। मार्च और मई में लश्कर-ए-तैयबा कमांडरों जिया-उर-रहमान और शाहिद कुट्टे को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि अप्रैल में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े इंग-टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी का समर्थन आज भी जारी है, जो लश्कर-

ए-तैयबा को वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है, हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इनकार करता है। लश्कर-ए-तैयबा का विकास एक क्षेत्रीय जिहादी समूह से वैश्विक आतंकी नेटवर्क तक हुआ है, जो पाकिस्तान में सामाजिक कार्यों की आड़ में भर्ती और फंडिंग जारी रखता है, और भारत की खिलाफ छद्म युद्ध में पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी का प्रमुख हथियार बना हुआ है।

लश्कर-ए-तैयबा की विचारधारा, मूल सिद्धांत और उद्देश्य

लश्कर-ए-तैयबा की विचारधारा कट्टर सलफी-वहाबी इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित है, जो अहल-ए-हदीस की व्याख्या पर टिकी हुई है। यह विचारधारा इस्लाम की शुद्धता पर जोर देती है और कुरान तथा हदीस के सीधे पालन को अनिवार्य मानती है, जबकि अन्य इस्लामी संप्रदायों की व्याख्याओं को अक्सर अस्वीकार करती है। संगठन की स्थापना के समय से ही यह ब्रिटिश राज को मुगल साम्राज्य के पतन का दोषी ठहराता है और पश्चिमी प्रभाव को दक्षिण एशिया में इस्लाम के लिए खतरा मानता है। लश्कर-ए-तैयबा “ब्राह्मणिक-तालमुदिक-क्रूसेडर” गठबंधन की बात करता है, जिसमें हिंदू, यहूदी और ईसाई ताकतों को इस्लाम के दुश्मन के रूप में चित्रित किया जाता है, जो इस्लामी समुदाय को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इसका मूल सिद्धांत “जिहाद फी सबीलल्लाह” है, जिसका अर्थ है - अल्लाह के मार्ग में संघर्ष। यह कुरान की आयत 2:216 का हवाला देता है, जिसमें कहा गया है कि “लड़ाई तुम पर फर्ज कर दी गई है, हालांकि तुम इसे नापसंद करते हो। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए अच्छी हो, और किसी चीज को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।”

लश्कर-ए-तैयबा के अनुसार, जिहाद विभिन्न परिस्थितियों में अनिवार्य है, जैसे इस्लाम को प्रमुख जीवन पद्धति बनाना, गैर-मुस्लिमों से ज़िजिया वसूलना, मारे गए मुसलमानों का बदला लेना, संधि तोड़ने वालों को सजा देना, मुस्लिम राज्यों की रक्षा करना और कब्जा की गई मुस्लिम भूमि को वापस लेना। संगठन उन भूमियों को मुस्लिम भूमि मानता है जो कभी मुसलमानों के शासन में थीं, और उन्हें वापस हासिल करने को धार्मिक कर्तव्य बताता है। यह भारत, अमेरिका और इजराइल को “इस्लाम के अस्तित्वगत दुश्मन” घोषित करता है, और पश्चिमी या ब्रिटिश प्रभाव को पूरी तरह

अस्वीकार करता है। अन्य सलफी-जिहादी समूहों से अलग, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में अन्य इस्लामी संप्रदायों के खिलाफ संप्रदायिक हिंसा का विरोध करता है और वहां दावा (प्रचार) तथा सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि समाज को अहल-ए-हदीस की व्याख्या के अनुसार सुधार सके। पाकिस्तान में यह क्रांतिकारी जिहाद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वहां संघर्ष को इस्लाम और अविश्वास के बीच नहीं मानता, बल्कि समाज को प्रचार के माध्यम से बदलने पर जोर देता है। यह संगठन भारत को “दारुल-हरब” अर्थात एक युद्ध क्षेत्र मानता है, और उसका मानना है कि मुसलमानों को इस भूमि को “दारुल-इस्लाम” यानी इस्लामी शासन प्रणाली में बदलना चाहिए।

लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर को पहला चरण मानता है, जहां से शुरू करके भारत के अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को इस्लामी शासन में लाने की कल्पना की जाती है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वैश्विक खिलाफत की स्थापना है, जिसमें पूरी दुनिया में इस्लामी शासन कायम हो और गैर-इस्लामी ताकतों को पराजित किया जाए। संगठन की विचारधारा में भारत को विशेष रूप से हिंदू-प्रधान राष्ट्र के रूप में चित्रित किया जाता है, जो मुसलमानों पर अत्याचार करता है, और इसे “ब्राह्मणिक तानाशाही” कहा जाता है। लश्कर-ए-तैयबा का प्रचार साहित्य - जैसे कि इसकी पत्रिका “मजल्ला-अल-दावा” - मुसलमानों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का माध्यम रहा है। इस पत्रिका में भारत को “काफिरों का देश” बताया जाता है, जहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, और युवाओं को जिहाद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके भाषणों और प्रशिक्षण में यहूदियों, ईसाइयों और भारत को इस्लाम का शत्रु बताया जाता है, और उन्हें “इस्लाम के दुश्मनों” के रूप में चित्रित किया जाता है जो मुसलमानों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

संगठन की विचारधारा में जिहाद को रक्षात्मक बताया जाता है, लेकिन वास्तव में यह आक्रामक है, क्योंकि यह कश्मीर को मुसलमानों की “कब्जा की गई भूमि” मानता है और भारत को मुसलमानों का उत्पीड़क। प्रशिक्षण शिविरों में युवाओं को बताया जाता है कि जिहाद से वे शहादत (शहीद होना) प्राप्त करेंगे, जो जन्नत का रास्ता है, और भारत जैसे देशों को हराना मुसलमानों का धार्मिक फर्ज है। प्रचार में सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाता है, जहां वीडियो और पोस्ट के माध्यम से कश्मीर

में कथित अत्याचारों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ताकि भावनात्मक अपील की जा सके। संगठन की विचारधारा में महिलाओं की भूमिका भी शामिल है, जहां उन्हें जिहाद के समर्थन में परिवारों को प्रेरित करने के लिए तैयार किया जाता है, हालांकि वे सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होतीं। लश्कर-ए-तैयबा की विचारधारा वैश्विक है, क्योंकि यह बोस्निया, चेचन्या और फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में भी जिहाद का समर्थन करता है, लेकिन मुख्य फोकस भारत पर रहता है। लश्कर-ए-तैयबा का अंतिम उद्देश्य भारत को भीतर से अस्थिर करना है, ताकि यह मुस्लिम दुनिया में अपनी साख मजबूत कर सके और अल-कायदा जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के समकक्ष स्थापित हो सके।

इसके लिए यह कश्मीर को भारत से अलग करने की पहली सीढ़ी मानता है, जिसके बाद दिल्ली, हैदराबाद और अयोध्या जैसे ऐतिहासिक मुस्लिम केंद्रों को पुनः इस्लामी ध्वज के अंतर्गत लाना इसकी दीर्घकालिक रणनीति है। संगठन युवाओं को बताता है कि कश्मीर की आजादी से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन आएगा, और यह खिलाफत की स्थापना का पहला कदम होगा। हालांकि 2009 में संगठन ने कश्मीर में शांतिपूर्ण समाधान की बात की और वैश्विक जिहाद से इनकार किया, लेकिन आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि यह केवल दिखावा है, और वास्तव में जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी को पुनर्जीवित करने और भारत में बड़े हमलों की योजना है। लश्कर-ए-तैयबा का उद्देश्य पाकिस्तान में अपनी उपयोगिता बनाए रखना भी है, जहां यह भारत के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, लेकिन पाकिस्तान में हमलों से बचता है ताकि सरकार पर दबाव न पड़े। 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2008 में मुंबई में समन्वित आतंकी हमला लश्कर-ए-तैयबा के इन्हीं उद्देश्यों की अभिव्यक्ति थे, जहां संसद हमले से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को निशाना बनाया गया और मुंबई हमले से आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों को। ये हमले भारत को राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से किए गए, ताकि मुसलमानों में भारत के खिलाफ नफरत बढ़े और जिहाद के लिए भर्ती आसान हो।

संगठन का उद्देश्य केवल क्षेत्रीय नहीं है; यह वैश्विक जिहाद का हिस्सा है, जहां 320 वैश्विक स्थानों को संभावित लक्ष्य माना गया है, हालांकि ये व्यावहारिक से ज्यादा इरादे की अभिव्यक्ति हैं। लश्कर-ए-तैयबा की रणनीति में कश्मीर को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वहां भारतीय सेनाओं और आबादी का अनुपात अधिक है, जिससे जिहाद आसान लगता है। संगठन युवाओं को बताता है कि कश्मीर की आजादी से

पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी शासन आएगा, और यह खिलाफत की स्थापना का पहला कदम होगा। हालांकि 2009 में संगठन ने कश्मीर में शांतिपूर्ण समाधान की बात की और वैश्विक जिहाद से इनकार किया, लेकिन आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि यह केवल दिखावा है, और वास्तव में जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी को पुनर्जीवित करने और भारत में बड़े हमलों की योजना है। लश्कर-ए-तैयबा का उद्देश्य पाकिस्तान में अपनी उपयोगिता बनाए रखना भी है, जहां यह भारत के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, लेकिन पाकिस्तान में हमलों से बचता है ताकि सरकार पर दबाव न पड़े।

लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क, गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय संबंध

लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क अत्यंत जटिल, बहुस्तरीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत है, जो विभिन्न आतंकवादी समूहों, राज्य प्रायोजकों और वैश्विक नेटवर्कों से जुड़ा हुआ है। इसकी गहरी जड़ें पाकिस्तान में फैली हुई हैं, जहां इसे पाकिस्तानी सेना और विशेष रूप से अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी का खुला समर्थन प्राप्त रहा है। यह सहयोग वित्तीय, सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति, शिविर संचालन और रणनीतिक मार्गदर्शन के रूप में मिलता है, जिससे लश्कर-ए-तैयबा को भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने में सक्षम बनाया गया है। अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बार-बार प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि लश्कर-ए-तैयबा को अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से प्रत्यक्ष सहायता मिलती है, जिसमें 1990 के दशक से लेकर अब तक के ऑपरेशनों में शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 2008 मुंबई हमलों में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा वारंट जारी किए गए थे, जो इस संबंध की गहराई को दर्शाते हैं। हाल के वर्षों में, 2025 में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि देश ने तीन दशकों तक आतंकवादी समूहों का समर्थन किया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन शामिल हैं, हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इनकार करता है। यह समर्थन पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा रहा है, विशेषकर अफगानिस्तान और कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए, जहां लश्कर-ए-तैयबा को प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी न केवल लश्कर-ए-तैयबा को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है, बल्कि उसके ऑपरेटिव्स को सीमा पार घुसपैठ में मदद करती है, और उसके प्रचार अभियानों को बढ़ावा देती है। इस नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल

हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण शिविरों में रणनीतिक सलाह देते हैं और संगठन को पाकिस्तानी समाज में एक वैध इकाई के रूप में पेश करने में मदद करते हैं।

1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा ने अल-कायदा के साथ गहरे संबंध स्थापित किए, जो अफगान युद्ध के दौरान शुरू हुए और रणनीति, प्रशिक्षण तथा संसाधनों के आदान-प्रदान पर आधारित थे। अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने लश्कर-ए-तैयबा की पूर्ववर्ती संस्था मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद को वित्तीय सहायता प्रदान की, और कई अल-कायदा ऑपरेटिव जैसे अबू जुबैदा को लश्कर-ए-तैयबा के सुरक्षित घरों से गिरफ्तार किया गया। 1993 के विश्व व्यापार केंद्र बम विस्फोट में लश्कर-ए-तैयबा का अप्रत्यक्ष समर्थन देखा गया, जहां रामजी यूसुफ जैसे आतंकवादियों को सहायता मिली। 9/11 हमलों के बाद लश्कर-ए-तैयबा ने तालिबान के प्रति समर्थन व्यक्त किया और अफगानिस्तान में उत्तरी गठबंधन के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया, जहां यह तालिबान के साथ मिलकर अमेरिकी और नाटो बलों पर हमले करता रहा। हाल के वर्षों में, 2022 की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा के अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित प्रशिक्षण शिविरों का उल्लेख किया गया, और 2024 में कई जिहादी समूहों ने तालिबान से निष्ठा जताई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के प्रभाव को शामिल माना जाता है। इसके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा ने हक्कानी नेटवर्क जैसे समूहों के साथ सहयोग किया, जो अफगान तालिबान का हिस्सा है और पाकिस्तान द्वारा समर्थित है। यह गठबंधन लश्कर-ए-तैयबा को अफगानिस्तान में सुरक्षित आधार प्रदान करता है, जहां से यह भारत और अन्य देशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाता है, और अल-कायदा के साथ मिलकर नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करता है। 2025 में, अफगान तालिबान के साथ लश्कर-ए-तैयबा के संबंध और मजबूत हुए हैं, जहां दोनों संगठन संयुक्त रूप से विदेशी ताकतों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर रहे हैं, और लश्कर-ए-तैयबा के लड़ाके तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर लश्कर-ए-तैयबा संयुक्त जिहाद परिषद का सदस्य है, जो कश्मीर में सक्रिय इस्लामी आतंकवादी संगठनों का छाता संगठन है। इसके अंतर्गत लश्कर-ए-तैयबा ने हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन और हरकत-उल-जिहादी-इस्लामी जैसे संगठनों के साथ संयुक्त अभियानों, सूचना साझाकरण और रणनीतिक तालमेल बनाए रखा है। उदाहरण के लिए, 2001 में भारतीय संसद पर हमला लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का संयुक्त ऑपरेशन था, जो अंतर-

सेवा खुफिया एजेंसी के समर्थन से हुआ। हाल में, 2025 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने हमास के साथ मिलकर एक संयुक्त आतंकी साजिश रची, जो कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में हमलों की योजना थी। इसके अतिरिक्त, लश्कर-ए-तैयबा ने 1990 के दशक में तमिल ईलम के मुक्ति व्याघ्र जैसे गैर-इस्लामी विद्रोही संगठनों से हथियारों की खरीद और वितरण में सहयोग लिया, जो दर्शाता है कि इसका उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक भी है। लश्कर-ए-तैयबा ने भारतीय मुजाहिदीन को भी समर्थन दिया, जो भारत के अंदर इसका प्रमुख सहयोगी है, और 2010 में पुणे के जर्मन बेकरी हमले जैसे संयुक्त ऑपरेशनों में शामिल रहा। यह क्षेत्रीय गठबंधन लश्कर-ए-तैयबा को कश्मीर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की अनुमति देता है, जहां ये संगठन संयुक्त रूप से भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं और स्थानीय युवाओं की भर्ती करते हैं। 2025 के कश्मीर संकट में, लश्कर-ए-तैयबा ने इन सहयोगियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में शिविरों से ऑपरेशन चलाए, जिसके जवाब में भारत ने मई में उसके शिविरों पर हमले किए।

लश्कर-ए-तैयबा की वैश्विक उपस्थिति लगातार विस्तृत हुई है, जहां इसके ऑपरेटिव बोस्निया, चेचन्या, फिलीपींस, मध्य पूर्व, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। संगठन ने बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और खाड़ी देशों में भर्ती और फंडिंग कार्यालय खोले हैं, और यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका में प्रचार अभियान चलाए हैं। सऊदी अरब इसका प्रमुख वित्तीय आधार रहा है, जहां से लश्कर-ए-तैयबा को धन प्राप्त होता है, और 2010 के अमेरिकी दस्तावेजों में सऊदी को आतंकवादियों के लिए “नकद मशीन” कहा गया। जमात-उद-दावा जैसे संगठनों के माध्यम से लश्कर-ए-तैयबा अपने चेहरों को बदलता रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचा जा सके; उदाहरण के लिए, 2019 में पुलवामा हमले के बाद यह अल मदीना और ऐसर फाउंडेशन जैसे नए नामों से सक्रिय हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन इसके सामाजिक और राहत संगठनों को खुली छूट दी गई है, जो वास्तव में वैचारिक प्रचार, भर्ती और धन संग्रहण का कार्य करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा की वैश्विक पहुंच और बढ़ी है, जहां यह चीन-पाकिस्तान गठबंधन के माध्यम से नए संबंध बना रहा है, और मध्य पूर्व में हमास जैसे संगठनों के साथ सहयोग कर रहा है। संगठन के ऑपरेटिव अमेरिका में गिरफ्तार हुए हैं, जहां वे जासूसी और फंडिंग नेटवर्क चला रहे थे, और ऑस्ट्रेलिया में इसके सदस्यों ने स्थानीय मुस्लिम समुदायों में जिहाद का प्रचार किया

है। यह वैश्विक नेटवर्क लश्कर-ए-तैयबा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमले करने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे कि 2008 मुंबई हमलों में देखा गया, और इसे अल-कायदा जैसे संगठनों के समकक्ष स्थापित करता है।

लश्कर-ए-तैयबा के वित्तपोषण के तरीके और स्रोत

लश्कर-ए-तैयबा का वित्तपोषण ढांचा एक बहुस्तरीय, अंतरराष्ट्रीय और छद्म रूप से धार्मिक पर आधारित तंत्र है, जो न केवल पाकिस्तान में स्थित सरकारी तंत्र के भीतर के तत्वों, बल्कि खाड़ी देशों, दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों तथा वैश्विक समर्थक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। इस गुट को पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से प्राप्त रणनीतिक सहायता इसका मुख्य स्तंभ रही है, जो नकद राशि, हथियारों, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक समर्थन के रूप में दी जाती है। 2010 तक लश्कर-ए-तैयबा को अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी और सरकारी अनुदान के माध्यम से सालाना 5.2 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त होती थी, और यह समर्थन आज तक जारी रहा है, जहां पाकिस्तानी सरकार ने तीन दशकों तक आतंकवादी समूहों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की बात स्वीकारी है। यह राज्य प्रायोजित संसाधन लश्कर-ए-तैयबा को प्रशिक्षण शिविरों का संचालन, हथियारों की खरीद और ऑपरेशनों की योजना बनाने में सक्षम बनाता है, विशेषकर कश्मीर में जहां यह गुट कई शिविरों को आर्थिक रूप से मजबूत रखता है। यह आर्थिक सहयोग पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा माना जाता है, जो भारत के खिलाफ अस्थिरता फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की रिपोर्ट ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक खतरे के रूप में चिह्नित किया है, जिसमें पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुटों को दी जाने वाली सहायता पर जोर दिया गया है। यह आर्थिक सहायता अक्सर सरकारी बजट के माध्यम से या गुप्त कोषों से आती है, जो गुट को वैश्विक स्तर पर अपनी गतिविधियां विस्तारित करने की अनुमति देती है।

इसके अतिरिक्त लश्कर-ए-तैयबा ने खुद को एक परोपकारी इकाई के रूप में पेश करते हुए जमात-उद-दावा की आड़ में धन एकत्र करना शुरू किया, जिसे पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध के बाद भी खुलकर कार्य करने की छूट दी। जमात-उद-दावा द्वारा चलाए जा रहे 135 स्कूल, 16 अस्पताल, सैकड़ों एंबुलेंस और मदरसों को मानवीय सेवा के नाम पर बड़ी संख्या में विदेशी दान प्राप्त होता है, विशेषकर खाड़ी देशों जैसे सऊदी

अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से। 2014 में जमात-उद-दावा को कराची में रियल एस्टेट परियोजना के लिए पाकिस्तान सरकार से 1 मिलियन डॉलर का अनुदान मिला, जो प्रत्यक्ष रूप से लश्कर-ए-तैयबा की आर्थिक नींव को मजबूत करता है। ये दान अक्सर धार्मिक और मानवीय कार्यों के नाम पर एकत्र किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए डायवर्ट किया जाता है, जैसे कि नए रंगरूटों की भर्ती और हथियारों की खरीद। जमात-उद-दावा और इसके सहयोगी संगठनों जैसे फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दान एकत्र करने की रणनीति अपनाई है, जहां भावनात्मक अपीलों जैसे कश्मीर में कथित अत्याचारों की कहानियों का उपयोग किया जाता है। यह तरीका वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा चिह्नित उभरते खतरों में शामिल है, जहां सोशल मीडिया फंडरेजिंग को आतंकवादी गुटों के लिए एक प्रमुख स्रोत माना गया है, और लश्कर-ए-तैयबा ने इसमें महारत हासिल की है, विशेषकर युवा दानदाताओं को लक्षित करके।

लश्कर-ए-तैयबा की एक और अहम आय प्रणाली हवाला नेटवर्क है, जिसके माध्यम से भारत, खाड़ी, यूरोप और पाकिस्तान में स्थित उसके नेटवर्क से धन भारत में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रणाली पूरी तरह से नकदी रहित होती है और किसी भी आर्थिक निगरानी प्रणाली की पकड़ से बाहर होती है, क्योंकि इसमें कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, बल्कि विश्वास पर आधारित लेन-देन होते हैं। भारत की प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 और 2020 के बीच 16 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं, जिनका सीधा संबंध लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हवाला नेटवर्क से था, और यह नेटवर्क और विस्तृत हो गया है, जहां नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को ट्रांजिट पॉइंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लश्कर-ए-तैयबा जाली भारतीय मुद्रा छापने और भारत में भेजने के कार्य में भी लिप्त रहा है, जो अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का एक तरीका है। 2017 में 8 करोड़ रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा बिहार और बंगाल में पकड़ी गई थी, जो कराची स्थित मुद्रण इकाइयों से छपी थी और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचाई गई थी, और उच्च मूल्य की मुद्रा नोटों का उपयोग करके इस तरीके को और परिष्कृत किया गया है, जैसा कि जमेस्टाउन रिपोर्ट में उल्लेखित है। यह जाली मुद्रा न केवल फंडिंग का स्रोत है, बल्कि भारत में स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का हथियार भी है, जहां इसे बाजार में घुसाकर लाभ कमाया जाता है।

लश्कर-ए-तैयबा के वित्तपोषण में उभरते तरीके भी शामिल हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंडरेजिंग, जहां गुट भावनात्मक वीडियो और अपीलों का उपयोग करके वैश्विक मुस्लिम समुदाय से दान एकत्र करता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की रिपोर्टों में सोशल मीडिया को आतंकवादी फंडिंग के उभरते खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है, और लश्कर-ए-तैयबा ने टेलीग्राम, फेसबुक और अन्य ऐप्स पर अभियान चलाकर लाखों डॉलर एकत्र किए हैं, विशेषकर कश्मीर संकट के दौरान। इसके अलावा, नए भुगतान प्रौद्योगिकियों जैसे क्रिप्टोकॉइन्स का उपयोग भी बढ़ा है, हालांकि यह अभी प्रारंभिक चरण में है, जहां बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से अनाम दान प्राप्त किए जाते हैं, जो ट्रैकिंग से बचने में मदद करता है। गुट ने विदेशी आतंकी लड़ाकों से जुड़े फंडों का भी उपयोग किया है, जहां यूरोप और मध्य पूर्व से लड़ाके धन लेकर आते हैं या भेजते हैं, और यह तरीका बढ़ा है, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में उल्लेखित है।

लश्कर-ए-तैयबा के वित्तपोषण का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत रियल एस्टेट और व्यापारिक निवेश हैं, जहां गुट पाकिस्तान और खाड़ी देशों में संपत्तियां खरीदता है और किराए या बिक्री से लाभ कमाता है। जमात-उद-दावा की रियल एस्टेट परियोजनाएं, जैसे कि कराची में विकसित की गईं, न केवल आय का स्रोत हैं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का माध्यम भी हैं, जहां अवैध धन को वैध संपत्तियों में परिवर्तित किया जाता है। गुट ने दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में भी व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किए हैं, जहां आयात-निर्यात कंपनियों की आड़ में धन स्थानांतरित किया जाता है। यह तरीका गुट को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद करता है, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद जारी रहता है। इसके अतिरिक्त, लश्कर-ए-तैयबा ने अपहरण और फिरौती भी एक भूमिका निभाती है, जहां कश्मीर और पाकिस्तान में अमीर व्यक्तियों या विदेशियों का अपहरण करके लाखों रुपये की फिरौती मांगी जाती है। यह तरीका 1990 के दशक से उपयोग में है, लेकिन इसे और परिष्कृत किया गया है, जहां डिजिटल माध्यमों से फिरौती की मांग की जाती है। इसके अलावा, लश्कर-ए-तैयबा ने स्थानीय व्यापारियों से “सुरक्षा धन” या जबरन चंदा एकत्र करने की प्रथा अपनाई है, विशेषकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जहां अस्वीकार करने पर धमकियां दी जाती हैं। यह स्थानीय स्तर पर फंडिंग का एक निरंतर स्रोत प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, लश्कर-ए-तैयबा का वित्तपोषण तंत्र इतना विविध और लचीला है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद यह गुट अपनी गतिविधियां जारी रखता है। राज्य समर्थन, दान, अवैध व्यापार और उभरती प्रौद्योगिकियों का संयोजन इसे एक मजबूत आर्थिक आधार प्रदान करता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है।

लश्कर-ए-तैयबा की संचालन रणनीतियाँ, तकनीकें और हालिया अभियान

लश्कर-ए-तैयबा की संचालन रणनीतियाँ इसकी घातक प्रभावशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को उजागर करती हैं, जहां ऑपरेशन केवल सैन्य ठिकानों पर छापामार हमलों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तंत्र को लक्षित करने की व्यापक योजना का हिस्सा होते हैं। गुट की रणनीति में समन्वित हमलों का उपयोग प्रमुख है, जैसे कि 2008 मुंबई हमलों में ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस जैसे प्रतिष्ठित स्थलों को निशाना बनाया गया। इन हमलों का संचालन पाकिस्तान स्थित नियंत्रण कक्ष से किया जाता है, जहां लाइव फीड और संचार के माध्यम से आतंकियों को वास्तविक समय में दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। हमलावर अक्सर समुद्री मार्गों का उपयोग करते हैं, जैसे कराची बंदरगाह से निकलकर भारतीय तटों में प्रवेश करना, जो पारंपरिक सुरक्षा तंत्र को चकमा देने की अत्याधुनिक तकनीक दर्शाता है। हालिया वर्षों में, गुट ने ड्रोन और साइबर टूल्स को अपनी रणनीति में शामिल किया है, जिससे हमलों की सटीकता और गोपनीयता बढ़ी है। अप्रैल के पहलगाम हमले में पर्यटकों को निशाना बनाकर गुट ने पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करने की रणनीति अपनाई, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और इसका उद्देश्य आर्थिक नुकसान पहुंचाना था। इस प्रकार की रणनीति भारत को बहुआयामी रूप से कमजोर करने पर केंद्रित है, जहां हमले न केवल जान-माल का नुकसान करते हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाते हैं।

एक अन्य प्रमुख रणनीति गुप्त घुसपैठ और स्लीपर सेल्स की स्थापना है, जहां नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और सामान्य नागरिकों की तरह जीवन जीते हैं, वर्षों तक निष्क्रिय रहकर अचानक सक्रिय होते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 300 से अधिक स्लीपर एजेंट्स को चिह्नित किया, जो विभिन्न हमलों में संलिप्त पाए गए, और यह संख्या 500 के पार पहुंच गई है। गुट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुरिदके, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसे स्थानों पर शिविर संचालित करता है, जहां नए रंगरूटों को गुरिल्ला युद्ध, आईईडी निर्माण, ट्रेंच युद्ध और शहरी

फिदायीन तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। इन शिविरों में अफगानिस्तान तथा सीरिया से लड़े लड़ाके प्रशिक्षक के रूप में शामिल होते हैं, जो उन्नत युद्ध तकनीकों का ज्ञान प्रदान करते हैं। मई के संकट के दौरान, गुट ने पाकिस्तान में अपने शिविरों से ऑपरेशन चलाए, लेकिन भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरिदके में मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसमें प्रमुख इमारतें नष्ट हुईं। यह रणनीति गुट को लंबे समय तक छिपे रहने और अचानक हमला करने की क्षमता देती है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। गुट ने हालिया अभियानों में स्थानीय सहयोगियों का उपयोग बढ़ाया है, जहां स्लीपर सेल्स को ड्रग तस्करी और हवाला नेटवर्क से जोड़कर बहुआयामी ऑपरेशन चलाए जाते हैं।

मनोवैज्ञानिक युद्ध लश्कर-ए-तैयबा की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां सोशल मीडिया का प्रभावशाली उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर) और यूट्यूब पर प्रतिवर्ष 500 से 1,000 वीडियो प्रकाशित किए जाते हैं। ये वीडियो “शहादत”, “जिहाद” और “कश्मीर की आजादी” जैसे भावनात्मक विषयों पर केंद्रित होते हैं, जिनका उद्देश्य मुस्लिम युवाओं को धार्मिक उन्माद से प्रेरित कर भर्ती करना है। गुट के वीडियो को 1 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका था, और यह संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो इसकी प्रचार क्षमता को दर्शाता है। गुट ने एआई-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक वीडियो को अपनी रणनीति में शामिल किया है, जिससे झूठी खबरें और प्रचार सामग्री तेजी से फैलाई जाती हैं। संकट के दौरान, सोशल मीडिया पर फैलाए गए वीडियो ने पाकिस्तान में समर्थन जुटाने और भारत में भय फैलाने का काम किया। यह मनोवैज्ञानिक रणनीति हमलों से पहले और बाद में उपयोग की जाती है, जहां लक्षित समुदायों में नफरत और भय का माहौल बनाया जाता है। हालिया अभियानों में, गुट ने ऑनलाइन भर्ती कैम्पेन चलाए हैं, जहां युवाओं को वर्चुअल ट्रेनिंग और निर्देश दिए जाते हैं, जिससे पारंपरिक शिविरों की आवश्यकता कम हो गई है।

लश्कर-ए-तैयबा की रणनीति “कम संसाधन में अधिक आतंक” की मानसिकता पर आधारित है, जहां 1993 से अब तक जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में बम धमाकों, ग्रेनेड हमलों तथा आत्मघाती हमलों की श्रृंखला चलाई गई है। चिट्टीसिंहपुरा नरसंहार (2000), लाल किले पर हमला (2000), 2006 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके (2009 मारे गए) और पठानकोट एयरबेस हमला (2016) इस रणनीति

के प्रमुख उदाहरण हैं। जुलाई में पूंछ जिले में दो आतंकियों को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार गिराया गया। यह रणनीति कम लागत वाले हथियारों और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करती है, जिससे बड़े प्रभाव पैदा किए जाते हैं। गुट ने हालिया वर्षों में ड्रोन-आधारित हमलों और साइबर हमलों को अपनाया है, जैसे कि सुरक्षा बलों की संचार प्रणालियों को हैक करने की कोशिशें। संकट के दौरान, गुट ने पाकिस्तान में अपने शिविरों से ऑपरेशन चलाए, लेकिन भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुरिदके में मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसमें प्रमुख इमारतें नष्ट हुईं। यह प्रणालीबद्ध रणनीति ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को नई सोच, रणनीति और टेक्नोलॉजी अपनाने को मजबूर किया है, जैसे कि ड्रोन सर्विलांस और एआई-आधारित इंटेलिजेंस।

लश्कर-ए-तैयबा के उन्नत हथियार, तकनीकों और सैन्य क्षमताएं

लश्कर-ए-तैयबा का हथियारशस्त्र और तकनीकी ढांचा इसे आधुनिक युग के सबसे खतरनाक और संगठित आतंकवादी गुटों में से एक बनाता है, जहां पारंपरिक हथियारों से लेकर उन्नत तकनीकों तक का संयोजन सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी तबाही और रणनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने में सक्षम है। गुट का सैन्य ढांचा केवल शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनोवैज्ञानिक, तकनीकी और सामरिक स्तरों पर युद्ध की पूरी अवधारणा को अपनाता है, जिसमें हथियारों की विस्तृत शृंखला शामिल है जो सीमापार तस्करी, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और स्थानीय सहयोग के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस ढांचे में हथियारों की विविधता गुट को विभिन्न परिदृश्यों में अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में छापामार हमले या ग्रामीण इलाकों में घात लगाकर वार। तकनीकी कुशलता का मिश्रण इसे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक स्थायी चुनौती बनाता है, क्योंकि गुट लगातार अपनी क्षमताओं को विकसित करता रहता है, जिसमें डिजिटल और स्वायत्त प्रणालियों का बढ़ता उपयोग शामिल है। इस संरचना की मजबूती गुट को एक लचीले और अनुकूलनीय सैन्य इकाई के रूप में स्थापित करती है, जो पारंपरिक युद्ध तकनीकों को आधुनिक नवाचारों के साथ जोड़ती है। कुल मिलाकर, यह ढांचा गुट को एक लचीले और अनुकूलनीय सैन्य इकाई के रूप में स्थापित करता है, जो पारंपरिक युद्ध तकनीकों को आधुनिक नवाचारों के साथ जोड़ता है।

लश्कर-ए-तैयबा के हथियार शस्त्रागार में सबसे आम और व्यापक रूप से प्रयुक्त हथियार एके-47 है, जो पाकिस्तान के सैन्य भंडारों या काले बाजार से प्राप्त किया जाता है, और इसकी तस्करी जम्मू और कश्मीर की सीमा से होती है, जहां नियंत्रण रेखा पार करने वाले रूट, सुरंगें तथा उन्नत ड्रोन मॉडलों का उपयोग शामिल हो गया है। यह असॉल्ट राइफल अपनी विश्वसनीयता, आसान रखरखाव और उच्च फायरिंग दर के कारण गुट के लिए पसंदीदा है, जो घने जंगलों या शहरी गलियों में प्रभावी साबित होती है। पिस्तौल और एमपी-5 सबमशीन गन जैसे हल्के हथियारों का उपयोग विशेष रूप से स्लीपर सेल ऑपरेशनों में किया जाता है, जहां लक्षित हत्याओं के लिए उनकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और तेज फायरिंग क्षमता फायदेमंद साबित होती है। इन हथियारों में साइलेंसर और एक्सटेंडेड मैगजीन जैसे संशोधन जोड़े जाते हैं, ताकि गोपनीयता बनी रहे और ऑपरेटिव्स आसानी से छिप सकें। रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का उपयोग सैन्य चौकियों, बंकरों और वाहनों को निशाना बनाने में किया जाता है, जहां उनकी विस्फोटक क्षमता बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाती है, और इनमें जीपीएस-गाइडेड वेरिंट्स का समावेश गुट की सटीकता को बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर, ये छोटे हथियार गुट को त्वरित और मोबाइल हमलों की क्षमता प्रदान करते हैं, जो उनकी गुरिल्ला-शैली की रणनीति के अनुरूप हैं।

लश्कर-ए-तैयबा का सबसे घातक पहलू विस्फोटकों के निर्माण और उपयोग में इसकी निपुणता है, जहां उच्च स्तर की इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस निर्माण तकनीक में टाइम बम, कार बम, मोटरसाइकिल बम, आत्मघाती बेल्ट और प्रेशर कुकर बम प्रमुख हैं। इन बमों में उपयोग होने वाले रसायन जैसे आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम क्लोरेट और अन्य रासायनिक यौगिक पाकिस्तान के मिलिट्री स्टोर्स या चीन से तस्करी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, और इनकी संरचना में रिमोट कंट्रोल या मोशन सेंसर जैसे उन्नत ट्रिगर जोड़े जाते हैं। प्रेशर कुकर बम अपनी सादगी और उच्च विस्फोटक क्षमता के कारण विशेष रूप से प्रभावी हैं, जहां घरेलू सामग्रियों का उपयोग उन्हें आसानी से छिपाने योग्य बनाता है। आत्मघाती बेल्ट में विस्फोटकों के साथ मेटल शार्पनेल मिलाए जाते हैं, ताकि अधिकतम क्षति हो, और इनकी डिजाइन अधिक कॉम्पैक्ट और पहचान से बचने वाली हो गई है। टाइम बम और कार बम में जीपीएस ट्रैकिंग का समावेश उन्हें लक्षित स्थानों पर सटीक समय पर सक्रिय करने की अनुमति देता है, जिससे गुट की लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ती है। कुल मिलाकर, ये

विस्फोटक गुट को बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की शक्ति प्रदान करते हैं, जहां निर्माण की सादगी और उपयोग की विविधता प्रमुख भूमिका निभाती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से लश्कर-ए-तैयबा ने समय के साथ खुद को काफी उन्नत किया है, जहां पारंपरिक तरीकों से हटकर ड्रोन का उपयोग हथियारों तथा गोला-बारूद की डिलीवरी, सीमा पर निगरानी और खुफिया सूचना जुटाने के लिए किया जा रहा है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले क्वाडकोप्टर से लेकर लंबी दूरी वाले फिक्स्ड-विंग मॉडल तक शामिल हैं, जिनमें कैमरा और जीपीएस सिस्टम लगे होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से आतंकियों के बीच संपर्क बनाए रखा जाता है, जहां संदेशों को कोडवर्ड, काल्पनिक नामों और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित किया जाता है। गुट ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और टोर ब्राउजर जैसे टूल्स को अपनाया है, ताकि ट्रेसिंग से बचा जा सके। सैटेलाइट फोन और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर जैसे उपकरण सुरक्षा बलों की लोकेशन से बचने में मदद करते हैं, जहां जैमर दुश्मन के संचार को ब्लॉक कर गुट की गतिविधियों को गोपनीय रखते हैं। ड्यूल-सिम मोबाइल फोन और डिस्पोजेबल डिवाइस ट्रेकिंग से बचाव के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे गुट की संचार क्षमता मजबूत होती है। कुल मिलाकर, ये तकनीकें गुट को डिजिटल युग में अनुकूलित करती हैं, जहां निगरानी और संचार की उन्नति प्रमुख भूमिका निभाती है।

लश्कर-ए-तैयबा की हथियार और तकनीक आपूर्ति श्रृंखला बहुस्तरीय और लचीली है, जिसमें स्थानीय रूप से बनाए गए विस्फोटकों से लेकर चीन या पश्चिम एशिया से लाए गए उन्नत उपकरण तक शामिल हैं। पाकिस्तान के कराची, बहावलपुर और रावलपिंडी जैसे क्षेत्रों में सप्लाइ हब स्थापित हैं, जो भूमिगत बाजारों और सहयोगी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इन हबों में हथियारों की असेंबली और संशोधन किया जाता है, जैसे एके-47 में लेजर साइट्स या नाइट विजन स्कोप जोड़ना। गुट के कार्यकर्ता तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जहां वे रणनीतिक रूप से हथियारों का उपयोग सीखते हैं, जैसे ड्रोन को हथियार डिलीवरी के लिए प्रोग्राम करना। सामरिक सज्जता में शामिल है हथियारों का रखरखाव, जैसे विस्फोटकों को नमी से बचाना या ड्रोन बैटरियों का ऑप्टिमाइजेशन। श्रृंखला में 3डी प्रिंटिंग का उपयोग हल्के भागों के लिए शुरू हो गया है, जो स्थानीय उत्पादन को बढ़ाता है। कुल मिलाकर, यह श्रृंखला गुट को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, जहां विविध स्रोत और अनुकूलन प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

लश्कर-ए-तैयबा के हथियार और तकनीकी ढांचे की ताकत कम लागत में अत्यधिक प्रभाव पैदा करने की रणनीति पर आधारित है, जहां परमाणु हथियार या मिसाइलों की अनुपस्थिति के बावजूद ऐसे साधन उपलब्ध हैं जो किसी शहरी केंद्र को कुछ ही घंटों में अशांत कर सकते हैं। इसे “कम लागत, उच्च प्रभाव” आतंकवाद का प्रतीक माना जाता है, जहां सस्ते हथियारों जैसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को उन्नत तकनीकों से जोड़कर बड़े प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। हमले न केवल शारीरिक हानि पहुंचाते हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी छोड़ते हैं, जैसे ड्रोन से फैलाया गया भय या एन्क्रिप्टेड संचार से बनी गोपनीयता। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हथियारों से अधिक तकनीकी और मनोवैज्ञानिक आयामों से है, जहां गुट की अनुकूलनीयता इसे टिकाऊ बनाती है। यह ढांचा और विकसित हो रहा है, जहां स्वायत्त ड्रोन और साइबर टूल्स का समावेश गुट की क्षमताओं को बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर, यह संरचना गुट को एक शक्तिशाली इकाई बनाती है, जहां कम संसाधनों में अधिकतम प्रभाव की रणनीति प्रमुख है।

अध्याय 5:

जैश-ए-मोहम्मद (JeM)

नेटवर्क और गठबंधन

जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी नेटवर्क केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और बहुस्तरीय गठबंधन व्यवस्था का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गुट, राज्य समर्थित खुफिया एजेंसियां, धार्मिक उग्रवादी इकाइयां, और आर्थिक एवं वैचारिक रूप से जुड़े सहयोगी शामिल हैं। इसकी स्थापना 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने उस समय की थी जब उसे कंधार विमान अपहरण प्रकरण के दौरान भारत सरकार द्वारा छोड़ा गया। रिहा होने के बाद अजहर ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी और बहुत कम समय में इसे दक्षिण एशिया के सबसे खतरनाक और हिंसक आतंकवादी संगठनों में तब्दील कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी रणनीति और इसके नेटवर्क की वैश्विक जड़ें इसे न केवल भारत के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बनाती हैं। संगठन का नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित विभिन्न मदरसों, प्रशिक्षण शिविरों और सामाजिक संगठनों से शुरू होता है, जहां से युवाओं की भर्ती और वैचारिक दीक्षा की जाती है, और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल-कायदा, तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुटों तक फैला हुआ है। यह नेटवर्क पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी की सहायता से मजबूत होता है, जो संगठन को हथियार, प्रशिक्षण और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। जैश-ए-मोहम्मद संयुक्त जिहाद परिषद का हिस्सा है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-मुजाहिदीन और अन्य कश्मीर केंद्रित गुट शामिल हैं, और यह गठबंधन भारत के खिलाफ समन्वित हमलों की योजना बनाता है। पहलगांम हमले जैसी घटनाओं में जैश-ए-मोहम्मद ने लश्कर-ए-तैयबा और हमास के साथ मिलकर साजिश रची, जो उसके गठबंधनों की गहराई को दर्शाता है। संगठन का नेटवर्क खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका में फैले प्रवासी समुदायों तक पहुंचता है, जहां से धनराशि और भर्ती की प्रक्रिया संचालित होती है। इस बहुस्तरीय गठबंधन के माध्यम से जैश-ए-मोहम्मद अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बच निकलने में सफल रहता है।

जैश-ए-मोहम्मद के गठबंधनों में हरकत-उल-मुजाहिदीन से पुराना संबंध है, क्योंकि मसूद अजहर उसी संगठन से जुड़ा था , और दोनों गुट हथियारों, प्रशिक्षण और ऑपरेटिव्स का आदान-प्रदान करता है। अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ जैश-ए-मोहम्मद का गठबंधन वैश्विक जिहाद को मजबूत करता है, जहां दोनों गुट संयुक्त प्रचार और हमलों की योजना बनाते हैं। तालिबान के साथ संबंध अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों तक फैले हैं, जहां जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध और विस्फोटक तकनीकों में प्रशिक्षित होते हैं। पाकिस्तान में संयुक्त जिहाद परिषद के अंतर्गत जैश-ए-मोहम्मद अन्य गुटों के साथ संसाधनों का साझा उपयोग करता है, जैसे हथियारों की आपूर्ति और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान। जैश-ए-मोहम्मद ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर हमास से जुड़ी साजिश रची, जो उसके गठबंधनों की नई दिशा दर्शाती है। संगठन का नेटवर्क इंडियन मुजाहिदीन जैसे सहयोगियों तक फैला है, जो भारत में स्थानीय स्तर पर हमलों में सहायता प्रदान करते हैं। इस बहुस्तरीय नेटवर्क के कारण जैश-ए-मोहम्मद अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर कार्य करता है और अपनी गतिविधियां जारी रखता है। कुल मिलाकर, ये गठबंधन संगठन को मजबूत बनाते हैं और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में उपयोग होते हैं।

जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क में राज्य प्रायोजित एजेंसियां जैसे पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी प्रमुख हैं, जो संगठन को आर्थिक और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करती हैं। लश्कर-ए-तैयबा के साथ गठबंधन कश्मीर में संयुक्त अभियानों तक फैला है, जहां दोनों गुट प्रशिक्षण शिविर साझा करते हैं। अल-कायदा के साथ संबंध अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों तक विस्तृत हैं, जहां जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके संयुक्त ऑपरेशनों में भाग लेते हैं। हरकत-उल-जिहादी-इस्लामी जैसे गुटों के साथ गठबंधन हथियारों की खरीद और वितरण में सहयोग प्रदान करता है। जैश-ए-मोहम्मद ने हमास के साथ मिलकर संयुक्त आतंकी साजिश रची, जो उसके गठबंधनों की नई दिशा दर्शाती है। संगठन का नेटवर्क प्रवासी समुदायों में फैला है, जहां से भर्ती और फंडिंग होती है। इस बहुस्तरीय नेटवर्क के कारण जैश-ए-मोहम्मद अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर कार्य करता है और अपनी गतिविधियां जारी रखता है। कुल मिलाकर, ये गठबंधन संगठन को मजबूत बनाते हैं और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में उपयोग होते हैं।

अल-कायदा के साथ संबंध

जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के बीच संबंध केवल वैचारिक नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षण, प्रचार, हथियारों की आपूर्ति, और अंतरराष्ट्रीय साजिशों तक फैले हुए हैं। इन दोनों संगठनों का साझा उद्देश्य इस्लामी खिलाफत की स्थापना और दार-उल-हरब के विरुद्ध जिहाद है, जिसमें भारत विशेष प्राथमिकता रखता है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को 2001 से ही अफगानिस्तान और वजीरिस्तान के अल-कायदा शिविरों में प्रशिक्षित किया जाता रहा है, जहां उन्हें गुरिल्ला युद्ध, विस्फोटकों के निर्माण, आत्मघाती हमलों की रणनीति, और संचार विफलता की तकनीकें सिखाई जाती थीं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2020 तक सक्रिय रहा, जिसमें हर वर्ष लगभग 100 से 200 नए आतंकी तैयार किए जाते थे। अल-कायदा ने जैश-ए-मोहम्मद को रणनीतिक सहयोग प्रदान किया है, जिसमें खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और संयुक्त हमलों की योजना शामिल है। 2014 में जब अल-कायदा ने अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट की स्थापना की, तो जैश-ए-मोहम्मद इसका मुख्य स्थानीय भागीदार बन गया। दोनों संगठनों ने संयुक्त प्रचार वीडियो जारी किए, जिनमें भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया गया। ये वीडियो मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने और युवाओं को प्रेरित करने का माध्यम बने। जैश-ए-मोहम्मद को अल-कायदा से हथियार, शरण स्थल और नकली दस्तावेज प्राप्त होते हैं। यूरोप के 2005 डेनमार्क कार्टून विवाद में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने अल-कायदा के साथ मिलकर साजिश रची, जो उनके संबंधों की गहराई दर्शाता है। कुल मिलाकर, यह गठबंधन जैश-ए-मोहम्मद को वैश्विक स्तर की जिहादी शक्ति प्रदान करता है।

जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के संबंध अफगानिस्तान में तालिबान के माध्यम से मजबूत हुए हैं, जहां दोनों संगठन संयुक्त शिविरों में कार्य करते हैं। अल-कायदा के विशेषज्ञ जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाकों को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित करते हैं, जैसे स्नाइपर युद्ध और शहरी हमले। दोनों संगठन खुफिया नेटवर्क साझा करते हैं, जिससे जैश-ए-मोहम्मद को जानकारी और संसाधन मिलते हैं। अल-कायदा ने जैश-ए-मोहम्मद को अफगानिस्तान में शरण दी है, जहां से ऑपरेशन चलाए जाते हैं। संयुक्त प्रचार में दोनों संगठन मुसलमानों को जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अल-कायदा के साथ मिलकर पश्चिमी देशों में साजिश रचते हैं। यह संबंध 2005 के डेनमार्क विवाद जैसे घटनाओं में दिखाई देते हैं। अल-कायदा की तकनीकी

सहायता जैश-ए-मोहम्मद की क्षमताओं को बढ़ाती है। कुल मिलाकर, यह गठबंधन जैश-ए-मोहम्मद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाता है।

जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के बीच वैचारिक समानता इस्लामी खिलाफत की स्थापना पर आधारित है, जहां दोनों भारत को प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। अल-कायदा के शिखरों में जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके आत्मघाती हमलों की रणनीति सीखते हैं। दोनों संगठन खुफिया नेटवर्क साझा करते हैं, जिससे जैश-ए-मोहम्मद को लाभ मिलता है। अल-कायदा ने जैश-ए-मोहम्मद को अफगानिस्तान में आधार देकर उसके लड़ाकों को विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया, जिससे संगठन की अनुभव बढ़ा। संयुक्त प्रचार में दोनों संगठन मुसलमानों को जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव अल-कायदा के साथ मिलकर पश्चिमी देशों में साजिश रचते हैं। यह संबंध 2005 के डेनमार्क विवाद जैसे घटनाओं में दिखाई देते हैं। अल-कायदा की तकनीकी सहायता जैश-ए-मोहम्मद की क्षमताओं को बढ़ाती है। कुल मिलाकर, यह गठबंधन जैश-ए-मोहम्मद को एक वैश्विक जिहादी नेटवर्क से जोड़ता है।

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के साथ संबंध

जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का संबंध न केवल रणनीतिक साझेदारी है, बल्कि यह पाकिस्तान में विकसित आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र का जीवंत उदाहरण भी है, जिसे अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी जैसी राज्य-समर्थित एजेंसियों ने संरक्षित किया है। 2001 के भारतीय संसद हमले में दोनों संगठनों की सहभागिता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि ये समूह केवल अलग-अलग संगठनों के रूप में नहीं, बल्कि एक संयुक्त जिहादी ढांचे के रूप में काम कर रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद ने जहां इस हमले के लिए आतंकी तैयार किए और उन्हें हथियार उपलब्ध कराए, वहीं लश्कर-ए-तैयबा ने लॉजिस्टिक्स, आवागमन, और खुफिया इनपुट्स प्रदान किए। बालाकोट स्थित साझा प्रशिक्षण शिविरों ने इन दोनों संगठनों को अपने ऑपरेटिवों के बीच तालमेल और रणनीतिक समन्वय स्थापित करने का अवसर दिया। इन शिविरों में शहरी युद्ध, बम प्लांटिंग, टारगेट असैसिनेशन और आत्मघाती हमले की तकनीकें सिखाई जाती थीं। जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए कई आतंकवादी हमलों में लश्कर-ए-तैयबा का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग था। यह सहयोग केवल संसाधनों तक सीमित नहीं था, बल्कि हमला करने की योजना, टारगेट चयन, और मीडिया मैनेजमेंट तक विस्तृत था। 2016 के पठानकोट हमले के बाद की जांच में पता चला कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों

को लश्कर-ए-तैयबा द्वारा दी गई सुरक्षित ठिकानों की सुविधा प्राप्त थी, और अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी के निर्देशों पर दोनों संगठन समन्वय में काम कर रहे थे। संयुक्त जिहाद परिषद, जिसमें इन दोनों संगठनों सहित अन्य शामिल हैं, उनके बीच संसाधनों और रणनीतियों का साझा मंच प्रदान करती है। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने हमास के साथ मिलकर संयुक्त आतंकी साजिश रची, जो उनके संबंधों की गहराई दर्शाती

जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के संबंध कश्मीर में संयुक्त अभियानों पर आधारित हैं, जहां दोनों संगठन प्रशिक्षण शिविर साझा करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद को हथियार और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करता है। दोनों संगठन संयुक्त रूप से युवाओं की भर्ती करते हैं और भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं। बालाकोट जैसे क्षेत्रों में साझा शिविर गुरिल्ला युद्ध और विस्फोटक तकनीकों में प्रशिक्षण देते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के हमलों में लश्कर-ए-तैयबा की खुफिया जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त जिहाद परिषद उनके बीच रणनीतिक तालमेल बनाती है। 2001 संसद हमले जैसे संयुक्त ऑपरेशन उनके संबंधों की गहराई दिखाते हैं। अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी दोनों को समर्थन देकर उनके समन्वय को मजबूत करती है। पहलगाम हमले में दोनों ने मिलकर साजिश रची। कुल मिलाकर, यह संबंध दोनों संगठनों को मजबूत बनाते हैं।

जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के बीच सहयोग हथियारों और प्रशिक्षण तक फैला है, जहां लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद को तकनीकी सहायता देता है। दोनों संगठन संयुक्त रूप से कश्मीर में हमले करते हैं। संयुक्त जिहाद परिषद उनके बीच रणनीतिक तालमेल बनाती है। जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव लश्कर-ए-तैयबा के सुरक्षित ठिकानों का उपयोग करते हैं। 2016 पठानकोट हमले में दोनों का समन्वय दिखाई दिया। अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी दोनों को निर्देश देती है। दोनों संगठन प्रचार सामग्री साझा करते हैं। हमास के साथ मिलकर साजिश रचने से उनके संबंध मजबूत हुए। कुल मिलाकर, यह गठबंधन भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को बढ़ावा देता है।

तालिबान के साथ संबंध

जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान के बीच संबंध केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक, सैन्य और ऐतिहासिक स्तर पर गहरे और स्थायी रहे हैं। इनका आरंभ 1999 में हुआ, जब आईसी 814 विमान अपहरण प्रकरण के दौरान मसूद अजहर को कंधार लाया गया था और वहां उसकी मुलाकात तालिबान और अल-कायदा के शीर्ष नेतृत्व से हुई। इसी ऐतिहासिक कड़ी से जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान के बीच सहयोग की नींव पड़ी, जिसे समय के साथ योजनाबद्ध और संस्थागत रूप दिया गया। अफगानिस्तान के कंधार, हेलमंद, और वजीरिस्तान क्षेत्रों में स्थित तालिबान-नियंत्रित क्षेत्रों ने जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव्स को प्रशिक्षण, शरण, चिकित्सा और पुनःसंगठन की सुविधा प्रदान की। तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद को अफगानिस्तान में सुरक्षित आधार दिए, जहां से संगठन ने भारत के खिलाफ साजिशें रचीं। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद यह सहयोग और मजबूत हो गया है, जहां तालिबान के नियंत्रित शिविर जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाकों को नए हथियार और तकनीकों में प्रशिक्षित कर रहे हैं। दोनों संगठनों की वैचारिक समानता देवबंदी इस्लाम पर आधारित है, जो जिहाद को धार्मिक फर्ज मानती है। तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद को अफगानिस्तान में शरण देकर उसके घायल लड़ाकों का इलाज किया और नए रंगरूटों को तैयार किया। यह संबंध 2001 के अमेरिकी आक्रमण के बाद और गहरा हुआ, जब दोनों संगठन विदेशी ताकतों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई लड़ते रहे। जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमले करते हैं, जिससे संगठन की क्षमता बढ़ती है। कुल मिलाकर, यह गठबंधन जैश-ए-मोहम्मद को एक मजबूत सहयोगी प्रदान करता है, जो उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करता है।

जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान के संबंध 2000 के दशक में अमेरिकी बलों के अफगानिस्तान में प्रवेश के बाद और उपयोगी हो गए। तालिबान के नियंत्रित शिविरों में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को गुरिल्ला युद्ध, विस्फोटक संयंत्रन, स्नाइपर तकनीक, और शहरी हमले की ट्रेनिंग दी जाती रही। वजीरिस्तान में संचालित शिविरों में सालाना 100 से 150 जैश-ए-मोहम्मद रंगरूट प्रशिक्षित किए जाते थे। तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद को इन क्षेत्रों में न केवल प्रशिक्षण बल्कि हथियारों का स्टॉक, रेडियो उपकरण, कवर डॉक्यूमेंट्स और सुरक्षित कम्युनिकेशन नेटवर्क भी उपलब्ध कराए जाते थे। 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए हमले में तालिबान

द्वारा दी गई लॉजिस्टिक और रणनीतिक सहायता ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों संगठनों की साझेदारी आतंकवादी हमलों के समन्वित संचालन तक पहुंच चुकी है। तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद को अफगानिस्तान में शरण देकर उसके लड़ाकों को विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया, जिससे संगठन की अनुभव बढ़ा। तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में जैश-ए-मोहम्मद के शिविर सक्रिय हैं, जहां नए हथियारों और तकनीकों का परीक्षण होता है। दोनों संगठन संयुक्त रूप से जिहाद का प्रचार करते हैं और युवाओं को भर्ती करते हैं। यह सहयोग जैश-ए-मोहम्मद को तालिबान की सैन्य क्षमताओं से लाभ पहुंचाता है। कुल मिलाकर, यह संबंध दक्षिण एशिया की सुरक्षा को खतरे में डालता है।

जैश-ए-मोहम्मद ने तालिबान के क्षेत्रीय ठिकानों का उपयोग करते हुए भारत और अफगानिस्तान में कई साजिशों की योजना बनाई, और वहां से अपने घायलों और प्रशिक्षकों को पुनः संगठित किया। तालिबान का जैश-ए-मोहम्मद को सुरक्षा देने वाला यह रुख अफगान क्षेत्र को आतंकियों के लिए एक पुनरुद्धार केंद्र बना देता है, जिससे जैश-ए-मोहम्मद अपनी निरंतरता और प्रभावशाली क्षमता को बनाए रखता है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान की पुनर्सत्ता के बाद यह सहयोग और गहरा होने की संभावना है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। तालिबान ने जैश-ए-मोहम्मद को अफगानिस्तान में सुरक्षित मार्ग प्रदान किए, जहां से संगठन ने सीमा पार घुसपैठ की। दोनों संगठन संयुक्त रूप से विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जिससे जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके अनुभवी बनते हैं। तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में जैश-ए-मोहम्मद के शिविर सक्रिय हैं, जहां नए हथियारों और तकनीकों का परीक्षण होता है। यह संबंध वैचारिक रूप से मजबूत है, जहां दोनों इस्लामी शासन की स्थापना का सपना देखते हैं। तालिबान की सहायता से जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में हमलों की संख्या बढ़ाई है। कुल मिलाकर, यह गठबंधन जैश-ए-मोहम्मद को एक वैश्विक जिहादी नेटवर्क से जोड़ता है।

इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से कथित समर्थन

जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से कथित तौर पर जो समर्थन प्राप्त है, वह इसे विश्व के सबसे सशक्त राज्य-समर्थित आतंकवादी संगठनों में स्थान दिलाता है। भारत, अमेरिका, और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने बार-बार इस

पर प्रकाश डाला है कि इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस न केवल जैश-ए-मोहम्मद के गठन में सक्रिय था, बल्कि इसे लगातार धन, प्रशिक्षण, हथियार, खुफिया जानकारी, सुरक्षित ठिकाने और संचालन संबंधी मार्गदर्शन भी देता रहा है। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जैश-ए-मोहम्मद को भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का हथियार बनाया है, जहां संगठन को रणनीतिक एसेट के रूप में उपयोग किया जाता है। 2001 के संसद हमले में जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका व्यापक रूप से दर्ज है, और जांच एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया कि हमले की योजना इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहमति और समर्थन से बनी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव्स और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस अधिकारियों के बीच कॉल रिकॉर्ड, नकली पासपोर्ट जारी करने के सबूत, और सीमापार संचार के डेटा प्राप्त हुए। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जैश-ए-मोहम्मद के शिबिरों को सुरक्षा दी और संगठन को भारत में घुसपैठ के लिए मदद प्रदान की। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से जैश-ए-मोहम्मद ने नए प्रॉक्सी संगठनों को सक्रिय किया है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस सहयोग से इनकार करता रहा है, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने बार-बार पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद और उसके नेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि 2002 में जैश-ए-मोहम्मद पर औपचारिक प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन वह विभिन्न नामों जैसे अल रहमत ट्रस्ट और अंसार-उल-उम्मा के तहत अपनी गतिविधियां जारी रखता है। यह सब इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के संरक्षण और सहायता के बिना संभव नहीं माना जाता, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जैश-ए-मोहम्मद का निरंतर अस्तित्व पाकिस्तान के गुप्त समर्थन के कारण ही संभव हो पाया है। कुल मिलाकर, यह कथित समर्थन दक्षिण एशिया की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

पुलवामा हमले (2019), जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए, के बाद भी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका संदिग्ध रही। हमलावर आदिल अहमद डार को प्रशिक्षण और विस्फोटक उपलब्ध कराने वाले मार्ग इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की जानकारी और निगरानी के अंतर्गत माने गए। अनुमान के अनुसार, 2010 तक जैश-ए-मोहम्मद को इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से हर महीने 40 से 80 करोड़ रुपये तक का समर्थन मिलता था, जिसे हवाला चैनलों और नकली धर्मार्थ संगठनों के माध्यम से भेजा जाता था। यह समर्थन केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक था-जिसमें आतंकी लक्ष्यों का चयन, मीडिया में दुष्प्रचार की रणनीति और हमले के बाद

ऑपरेटिव्स की सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल थी। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जैश-ए-मोहम्मद के शिविरों को सुरक्षा दी और संगठन को भारत में घुसपैठ के लिए मदद प्रदान की। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से जैश-ए-मोहम्मद ने नए हमलों की साजिश रची है। कुल मिलाकर, यह कथित समर्थन जैश-ए-मोहम्मद को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का रूप देता है।

इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जैश-ए-मोहम्मद को कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया है, जहां संगठन को हथियार और खुफिया जानकारी प्रदान की जाती है। जैश-ए-मोहम्मद के गठन से ही इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस सक्रिय रहा है, मसूद अजहर को समर्थन देकर संगठन को मजबूत बनाया। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव्स को सीमा पार घुसपैठ में मदद दी और हमलों की योजना में सहयोग किया। पुलवामा जैसे हमलों में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका से संगठन की क्षमता बढ़ी है। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस का समर्थन आर्थिक रूप से मजबूत है, जहां हवाला और नकली नकली संगठनों से धन भेजा जाता है। जैश-ए-मोहम्मद के शिविर इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सुरक्षा में चलते हैं। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी की सहायता से जैश-ए-मोहम्मद ने नए हमलों की साजिश रची है। कुल मिलाकर, यह कथित समर्थन जैश-ए-मोहम्मद को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का रूप देता है।

समर्थकों और डायस्पोरा से दान

जैश-ए-मोहम्मद का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क मुख्य रूप से प्रवासी समुदायों पर निर्भर करता है, जो यूके जैसे देशों में फंडरेजिंग अभियानों के माध्यम से संगठन को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। इन प्रवासियों में पाकिस्तानी मूल के लोग प्रमुख हैं, जो स्थानीय मस्जिदों, सामुदायिक केंद्रों और सांस्कृतिक आयोजनों का उपयोग करके धन एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में कई मस्जिदों और चैरिटी संगठनों के माध्यम से “कश्मीर राहत कोष” जैसे नामों से अपील की जाती है, जहां दानकर्ताओं को बताया जाता है कि यह धन कश्मीर में मानवीय सहायता के लिए उपयोग होगा, लेकिन वास्तव में यह जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अभियानों को फंड करता है। अमेरिकी राज्य विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, यूके में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने 2010 से 2020 तक लाखों पाउंड एकत्र किए, जो हवाला नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाए गए। यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक है, बल्कि वैचारिक भी, जहां प्रवासी युवाओं को जिहाद की कहानियों से प्रेरित किया जाता है। सऊदी अरब में, जहां बड़ी

संख्या में पाकिस्तानी कामगार रहते हैं, जैश-ए-मोहम्मद के समर्थक जकात और सादका के नाम पर राशि जुटाते हैं, और यह धन मदरसों तथा प्रशिक्षण शिविरों में निवेश किया जाता है। सऊदी अरब की सख्त वित्तीय निगरानी के बावजूद, कई मामलों में दानकर्ता स्थानीय चैरिटी संगठनों का उपयोग करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होते हैं। यूई में, नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से प्रचार करता है, जहां भावनात्मक वीडियो और अपीलें साझा की जाती हैं, और धन डिजिटल वॉलेट्स या हवाला के जरिए स्थानांतरित किया जाता है।

यूई के दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में पाकिस्तानी प्रवासी व्यापारियों का योगदान प्रमुख है, जो संगठन को लाखों डॉलर प्रदान करते हैं। जैश-ए-मोहम्मद की पत्रिकाएं जैसे “जफर” और “अल-क़लम” डायस्पोरा में वितरित की जाती हैं, जो वैचारिक समर्थन बढ़ाती हैं और दानकर्ताओं को जिहाद के महत्व से अवगत कराती हैं। यूरोप में, विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स में, जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेटिव साजिश रचते हैं, जैसे 2005 के डेनमार्क कार्टून विवाद में संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन आयोजित कर फंड जुटाए। अमेरिका में, जहां पाकिस्तानी डायस्पोरा न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में केंद्रित है, नेटवर्क मस्जिदों और सांस्कृतिक संघों के माध्यम से काम करता है, और कई मामलों में अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे दानकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी और मेलबर्न में प्रवासी समुदायों से धन एकत्र किया जाता है, जहां कश्मीर मुद्दे पर आयोजित सेमिनारों से अपील की जाती है। मलेशिया में, जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन स्थानीय मुस्लिम संगठनों से जुड़े हैं, जहां दक्षिण एशियाई प्रवासी दान देते हैं और संगठन के प्रचार में भाग लेते हैं। 2005 और 2007 की घटनाएं जैश-ए-मोहम्मद की वैश्विक साजिशों को उजागर करती हैं, जैसे यूके में पकड़े गए प्लॉट जहां डायस्पोरा सदस्यों ने फंडिंग की थी। यह नेटवर्क धर्म और पहचान की राजनीति का उपयोग करता है, जहां दानकर्ताओं को बताया जाता है कि उनका योगदान इस्लामी संघर्ष में हिस्सा है। कुल मिलाकर, डायस्पोरा नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद को वैश्विक खतरा बनाता है।

जैश-ए-मोहम्मद का डायस्पोरा नेटवर्क यूके में आयोजनों से धन जुटाता है, जहां भाषण और वीडियो प्रचार के माध्यम से समर्थन मिलता है। रमजान जैसे मौकों पर फंडिंग बढ़ती है, और धन मदरसों तथा शिविरों में जाता है। यूई में हवाला से धन पाकिस्तान पहुंचता है, जहां व्यापारी योगदान देते हैं। यूरोप में जैश-ए-मोहम्मद के

ऑपरेटिव हमलों की योजना बनाते हैं, और दान स्थानीय संघों से आता है। अमेरिका में नेटवर्क सोशल मीडिया पर सक्रिय है, जहां अपीलें युवाओं को प्रभावित करती हैं। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में भर्ती होती है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों से धन एकत्र किया जाता है। 2005 और 2007 की घटनाएं जैश-ए-मोहम्मद की वैश्विक साजिशों को उजागर करती हैं, जैसे यूके में पकड़े गए प्लॉट जहां डायस्पोरा सदस्यों ने फंडिंग की थी। यह नेटवर्क धर्म और पहचान की राजनीति का उपयोग करता है, जहां दानकर्ताओं को बताया जाता है कि उनका योगदान इस्लामी संघर्ष में हिस्सा है। कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद को मजबूत बनाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और प्रवासी नेटवर्क

जैश-ए-मोहम्मद का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव केवल उसकी आतंकवादी कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विस्तृत और सुनियोजित नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के कई देशों में मौजूद है, जो संगठन के लिए फंडिंग, भर्ती और प्रचार कार्य करता है। यह नेटवर्क विशेष रूप से मुस्लिम प्रवासी समुदायों में सक्रिय है, जहां धार्मिक भावनाओं और कश्मीरी संघर्ष के नाम पर सहानुभूति और आर्थिक समर्थन जुटाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम इस दृष्टिकोण से जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहां 2010 के बाद से नियमित रूप से 10 से 20 फंडरेजिंग कार्यक्रम हर साल आयोजित किए गए, जिनमें मौलाना मसूद अजहर और कश्मीर संघर्ष को केंद्र में रखकर भाषण, वीडियो प्रदर्शन और धार्मिक काव्य प्रस्तुतियां की जाती थीं। इन आयोजनों के माध्यम से 2018 तक 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई, जिसे बाद में हवाला नेटवर्क या कथित इस्लामी ट्रस्टों के माध्यम से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संचालित जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क को भेजा गया। ये कार्यक्रम प्रवासी पाकिस्तानी और कश्मीरी समुदायों को लक्षित करते हैं, जहां भावनात्मक अपीलों जैसे कश्मीर में कथित अत्याचारों की कहानियां सुनाकर दान एकत्र किया जाता है। इन आयोजनों की संख्या बढ़कर 30 से अधिक हो गई है, जहां सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन भागीदारी बढ़ाई जाती है। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे कई कार्यक्रमों पर नजर रखी है, और रिपोर्टों के अनुसार, यूके में पाकिस्तानी डायस्पोरा ने लाखों पाउंड एकत्र किए, जो हवाला के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाए गए। यह नेटवर्क न केवल आर्थिक है, बल्कि वैचारिक भी, जहां प्रवासी युवाओं को जिहाद की कहानियों से प्रेरित किया जाता है। अमेरिकी राज्य

विभाग की रिपोर्टों के अनुसार, यूके में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय ने दान के माध्यम से संगठन को मजबूत बनाया है, जो स्थानीय मस्जिदों और सांस्कृतिक केंद्रों से संचालित होता है। कुल मिलाकर, यह नेटवर्क जैश-ए-मोहम्मद को वैश्विक स्तर पर फंडिंग का एक मजबूत स्रोत प्रदान करता है।

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में बसे प्रवासी पाकिस्तानी और कश्मीरी समुदायों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थकों ने भी इसी तरह के अभियान चलाए। 2016 से 2020 के बीच इन देशों में 8 से 16 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक की राशि धार्मिक चंदे और जकात के रूप में एकत्र हुई। यह फंड विशेष रूप से रमजान, मुहर्रम और कश्मीर में नागरिक हिंसा की घटनाओं के बाद तीव्र रूप से बढ़ता है। इन दानदाताओं को जैश-ए-मोहम्मद की पत्रिकाएं जैसे अल-कलम, हक की पुकार, और डिजिटल वीडियो, जिनमें शहादत का इनाम, भारत की क्रूरता, और कश्मीर की पुकार जैसे विषय होते हैं, के माध्यम से संगठित किया जाता है। यह सामग्री सोशल मीडिया, यूट्यूब, और व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से खाड़ी, यूरोप, और उत्तरी अमेरिका तक प्रसारित की जाती है। इन अभियानों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ा है, जहां लाइव सत्र और वर्चुअल आयोजन दान एकत्र करने में प्रभावी साबित हुए हैं। जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क इन देशों में प्रवासियों को धार्मिक पहचान से जोड़कर लंबे समय तक समर्थन सुनिश्चित करता है।

खाड़ी देशों में पाकिस्तानी कामगारों की बड़ी संख्या का फायदा उठाकर, संगठन जकात के नाम पर धन जुटाता है, जो मदरसों और प्रशिक्षण शिविरों में निवेश किया जाता है। सऊदी अरब की सख्त वित्तीय निगरानी के बावजूद, कई मामलों में दानकर्ता स्थानीय चैरिटी संगठनों का उपयोग करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में पाकिस्तानी प्रवासी व्यापारियों का योगदान प्रमुख है, जो संगठन को लाखों डॉलर प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर, यह अंतरराष्ट्रीय संपर्क संगठन को प्रवासी समुदायों से निरंतर संसाधन प्रदान करता है।

यूरोप में जैश-ए-मोहम्मद की आतंकवादी साजिशों की मौजूदगी भी इसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को उजागर करती है। 2005 के डेनमार्क कार्टून विवाद के बाद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ऑपरेटिव्स ने यूरोप में हमलों की योजना बनाई, जिसके चलते कई गिरफ्तारियां हुईं। 2007 में ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद से संबद्ध

एक समूह को आतंकी हमले की साजिश करते हुए पकड़ा। ये ऑपरेटिव पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे और पश्चिमी समाज में धार्मिक अपमान के विरोध के नाम पर हमले करने की योजना बना रहे थे। ये घटनाएं केवल जैश-ए-मोहम्मद की वैश्विक पहुंच को ही नहीं, बल्कि इसके रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए डायस्पोरा रिक्रूटमेंट मॉडल को भी उजागर करती हैं, जिसमें धर्म और पहचान की राजनीति को हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। यूरोप में जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क ने ऑनलाइन भर्ती बढ़ाई है, जहां युवाओं को वर्चुअल सत्रों में जिहाद का प्रचार किया जाता है। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स जैसे देशों में पाकिस्तानी प्रवासी समुदायों से दान एकत्र किया जाता है, जो स्थानीय संघों और मस्जिदों से संचालित होता है। कुल मिलाकर, यह नेटवर्क संगठन को पश्चिमी देशों में साजिश रचने की क्षमता प्रदान करता है।

सहयोगी संगठनों के साथ संचालनात्मक समन्वय

जैश-ए-मोहम्मद की सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ उसका अन्य आतंकी संगठनों के साथ संचालनात्मक समन्वय है, जो इसे सीमित संसाधनों के बावजूद व्यापक हमले करने की क्षमता देता है। जैश-ए-मोहम्मद का प्रारंभिक संबंध हरकत-उल-मुजाहिदीन के साथ रहा, क्योंकि मसूद अजहर उसी संगठन से जुड़े हुए थे। हरकत-उल-मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद आज भी कई प्रशिक्षण शिविर, हथियारों के स्रोत और ऑपरेटिवों का विनिमय करते हैं। इसके अलावा, जैश-ए-मोहम्मद का अल-कायदा से संबंध केवल वैचारिक नहीं, बल्कि संचालन स्तर पर भी गहरा रहा है। विशेष रूप से अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के गठन के बाद, जैश-ए-मोहम्मद के साथ साझा वीडियो, रणनीतियां और भर्ती अभियान बढ़ गए। 2020 तक अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा साझा किए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा, जिनमें भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार में जिहाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-मुजाहिदीन ने संयुक्त रूप से कश्मीर में हमलों की योजना बनाई, जहां संसाधनों का साझा उपयोग हुआ। कुल मिलाकर, यह समन्वय जैश-ए-मोहम्मद को मजबूत बनाता है। 2019 के पुलवामा हमले में अंसार गजवत-उल-हिंद, जो अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा संगठन है, ने जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर कार्रवाई का दावा किया। इन दोनों संगठनों के ऑपरेटिव्स ने प्रशिक्षण स्थलों

और हथियार साझा किए। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कार्यकर्ताओं के बीच लॉजिस्टिक्स, खुफिया सूचना और आईईडी बनाने की तकनीकों का नियमित आदान-प्रदान होता है। इसके अलावा, पाकिस्तान की अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी द्वारा स्थापित संयुक्त जिहाद परिषद, जिसमें 13 से 16 आतंकी संगठन शामिल हैं, जैश-ए-मोहम्मद को एक समन्वित मंच प्रदान करता है। संयुक्त जिहाद परिषद के माध्यम से रणनीतिक लक्ष्यों का निर्धारण, सीमा पार हमलों का समन्वय और संसाधनों का वितरण किया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद ने संयुक्त रूप से नए रंगरूटों की भर्ती की, जहां प्रशिक्षण और हथियार साझा किए गए। कुल मिलाकर, यह संचालनात्मक समन्वय संगठन की प्रभावशीलता बढ़ाता है।

जैश-ए-मोहम्मद ने इन सहयोगों से अपनी कार्यवाही की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाया है। सीमापार से हमलों की योजना बनाते समय विभिन्न संगठनों के स्थानीय नेटवर्क, सुरक्षित ठिकानों और मानव संसाधन का उपयोग कर जैश-ए-मोहम्मद अधिक सटीक और बारंबार हमले करने में सक्षम होता है। इस संयुक्त नेटवर्किंग ने जैश-ए-मोहम्मद को अकेले संचालन करने के बजाय एक साझा आतंकवादी अभियान का रूप दिया है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने संयुक्त रूप से कश्मीर में हमलों की श्रृंखला चलाई, जहां लॉजिस्टिक्स और सूचना का आदान-प्रदान हुआ। कुल मिलाकर, यह समन्वय जैश-ए-मोहम्मद को सीमित संसाधनों में व्यापक क्षमता देता है।

वैचारिक संबंध और प्रभाव

जैश-ए-मोहम्मद की वैचारिक जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप के देवबंदी इस्लामिक आंदोलन में गहराई से जुड़ी हैं, और इसकी वैचारिक प्रेरणा देवबंदी मदरसों तथा संगठनों से आती है, जो इसे धार्मिक वैधता, बौद्धिक ढांचा, और सामाजिक समर्थन प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल-उर-रहमान गुट) के साथ जैश-ए-मोहम्मद का संबंध उल्लेखनीय है। यह संबंध केवल वैचारिक सहमति तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक संरक्षण और सामाजिक स्वीकृति के रूप में भी कार्य करता है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के राजनीतिक मंचों पर मसूद अजहर और कश्मीर के लिए किए गए संघर्ष को उचित ठहराया गया है, जिससे जैश-ए-

मोहम्मद को सार्वजनिक रूप से धार्मिक समर्थन प्राप्त हुआ। देवबंदी मंदरसे जैश-ए-मोहम्मद को युवाओं में कट्टरता फैलाने का माध्यम प्रदान करते हैं। इन संबंधों ने जैश-ए-मोहम्मद को समाज में गहरी पैठ दी है। कुल मिलाकर, यह वैचारिक संबंध संगठन को मजबूत बनाते हैं।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम से संबद्ध मंदरसे, जैसे कि कराची का जामिया बिनोरिया, हर वर्ष 50 से 100 छात्र तैयार करते हैं, जिन्हें जैश-ए-मोहम्मद के लिए संभावित भर्ती उम्मीदवार माना जाता है। इन छात्रों को न केवल धार्मिक शिक्षण, बल्कि भारत विरोधी भाषण, जिहादी साहित्य और वैश्विक इस्लामी खिलाफत की अवधारणा से परिचित कराया जाता है। जैश-ए-मोहम्मद की पत्रिकाएं, जैसे अल-कलाम और मंजिल-ए-मकसूद, ऐसे ही मंदरसों में वितरित की जाती हैं, जो युवाओं के मन में कट्टरता और शहादत की भावना को बढ़ावा देती हैं। देवबंदी आंदोलन की विचारधारा जैश-ए-मोहम्मद को धार्मिक वैधता प्रदान करती है, जो संगठन को समाज में स्वीकार्य बनाती है। इन मंदरसों ने जैश-ए-मोहम्मद की भर्ती को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर, यह प्रभाव जैश-ए-मोहम्मद को सामाजिक आधार देता है।

यह वैचारिक संबंध जैश-ए-मोहम्मद के लिए एक जीवंत सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जिसमें उसका प्रचार, भर्ती और जन समर्थन बिना किसी प्रतिरोध के फलता-फूलता है। जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम जैसे संगठनों के द्वारा जैश-ए-मोहम्मद को सार्वजनिक सभाओं में बोलने की अनुमति, मीडिया समर्थन और धार्मिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इससे जैश-ए-मोहम्मद एक ऐसे वैध जिहादी आंदोलन के रूप में उभरता है, जो आतंकवाद और धार्मिक आंदोलन के बीच की रेखा को धुंधला करता है। यह स्थिति केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के लिए गंभीर रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती है, जिसमें धार्मिक प्रतिष्ठान और आतंकवादी नेटवर्क एक-दूसरे के पूरक बन चुके हैं। यह संबंध जैश-ए-मोहम्मद की वैचारिक मजबूती को बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर, यह प्रभाव संगठन को समाज में जड़ें जमाने में मदद करता है। यह वैचारिक शक्ति जैश-ए-मोहम्मद की सबसे खतरनाक विशेषता है, क्योंकि यह संगठन को हथियार और फंडिंग से भी अधिक गहराई तक समाज में जड़ें जमाने में मदद करती है। आतंकवाद को केवल सुरक्षा नीति से नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी चुनौती देना आवश्यक है, और जैश-ए-मोहम्मद का मॉडल यही स्पष्ट करता है। देवबंदी विचारधारा जैश-ए-मोहम्मद को धार्मिक आधार प्रदान करती है, जो संगठन को कट्टरता फैलाने में सहायता देती है। यह प्रभाव जैश-ए-मोहम्मद की भर्ती और

प्रचार को बढ़ावा दे रहा है। कुल मिलाकर, वैचारिक संबंध संगठन की दीर्घकालिक मजबूती का कारण हैं।

वित्त पोषण के तरीके

जैश-ए-मोहम्मद की वित्तीय प्रणाली बहुस्तरीय, गुप्त, और अत्यधिक लचीली है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सुरक्षा निगरानी के बावजूद इसे निरंतर संचालन में सक्षम बनाती है। जैश-ए-मोहम्मद का वित्त पोषण न केवल आतंकवादी गतिविधियों के लिए आवश्यक हथियार, गोला-बारूद और प्रशिक्षण में उपयोग होता है, बल्कि इसके प्रचार तंत्र, भर्ती नेटवर्क और वैचारिक युद्ध के संचालन के लिए भी जरूरी होता है। यह आतंकवादी संगठन कई तरह के स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त करता है-जिनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से कथित राज्य-प्रायोजित सहायता, कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों से मिलने वाले अनुदान, खाड़ी और पश्चिमी देशों में बसे प्रवासी समर्थकों से मिलने वाला धन, हवाला तंत्र के माध्यम से होने वाले गुप्त लेनदेन, अवैध गतिविधियों से कमाई गई राशि, और वैध दिखने वाले सामाजिक संगठनों और व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। जैश-ए-मोहम्मद की वित्तीय प्रणाली में राज्य प्रायोजित सहायता मुख्य स्तंभ है, जहां अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से मिलने वाले धन का उपयोग संगठन के प्रमुख ऑपरेशनों में होता है। धार्मिक संगठनों से अनुदान मदरसों और प्रचार सामग्री के लिए उपयोग होता है, जबकि प्रवासी समर्थकों से धन हवाला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।

अवैध गतिविधियां जैसे ड्रग तस्करी और जाली मुद्रा का कारोबार संगठन को त्वरित नकदी प्रदान करती हैं। वैध संस्थानों में निवेश संगठन को दीर्घकालिक आय सुनिश्चित करता है। डिजिटल माध्यमों से फंडिंग बढ़ी है, जहां क्रिप्टोकॉइन्स का उपयोग ट्रेसिंग से बचने में मदद करता है। कुल मिलाकर, यह बहुस्तरीय प्रणाली जैश-ए-मोहम्मद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। जैश-ए-मोहम्मद की वित्तीय प्रणाली में हवाला तंत्र प्रमुख है, जो गुप्त लेनदेन के लिए उपयोग होता है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाता है। राज्य प्रायोजित सहायता में अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से मिलने वाले धन का उपयोग प्रशिक्षण शिविरों और हथियारों की खरीद में होता है। कट्टरपंथी धार्मिक संगठनों से अनुदान मदरसों में वैचारिक शिक्षा के लिए निर्देशित होता है। प्रवासी समुदायों से धन रमजान जैसे मौकों पर बढ़ता है और हवाला से पाकिस्तान पहुंचता है। अवैध गतिविधियां जैसे ड्रग तस्करी अफगानिस्तान से हेरोइन की सप्लाई पर

आधारित हैं, जो करोड़ों की आय देती हैं। जाली मुद्रा का कारोबार भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हुए संगठन को लाभ पहुंचाता है। वैध संस्थानों जैसे अस्पताल और स्कूल दान एकत्र करते हैं और आय उत्पन्न करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फंडिंग बढ़ी है, जहां भावनात्मक अपीलें दानदाताओं को आकर्षित करती हैं। कुल मिलाकर, ये तरीके जैश-ए-मोहम्मद को स्वावलंबी बनाते हैं।

जैश-ए-मोहम्मद के वित्त पोषण में अवैध गतिविधियां जैसे जबरन वसूली और फिरौती प्रमुख हैं, जो स्थानीय स्तर पर धन उगाहती हैं। राज्य समर्थन में अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी से गुप्त अनुदान ऑपरेशनों को फंड करता है। धार्मिक अनुदान जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम जैसे संगठनों से आता है। प्रवासी नेटवर्क यूके और खाड़ी से धन भेजता है। हवाला तंत्र इन लेनदेन को गोपनीय रखता है। वैध व्यवसाय रियल एस्टेट और व्यापार में निवेश से आय उत्पन्न करते हैं। क्रिप्टोकॉर्सेसी और डिजिटल वॉलेट फंडिंग के नए तरीके बने हैं। कुल मिलाकर, यह विविध प्रणाली संगठन को प्रतिबंधों से मुक्त रखती है।

राज्य का समर्थन और आईएसआई से कथित वित्तीय सहायता

जैश-ए-मोहम्मद को मिलने वाला सबसे बड़ा और विवादास्पद वित्तीय स्रोत पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से प्राप्त कथित सहायता है। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस न केवल रणनीतिक मार्गदर्शन देती है, बल्कि फंडिंग, प्रशिक्षण शिविरों की सुविधा, हथियारों की आपूर्ति, नकली दस्तावेज और अंतरराष्ट्रीय मार्गों से सुरक्षात्मक निकासी तक की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करती है। भारतीय और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार, 2000 के दशक के मध्य से इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने जैश-ए-मोहम्मद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह उपयोग किया है, विशेषकर कश्मीर घाटी में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। यह समर्थन प्रायः हवाला नेटवर्क या नकली इस्लामिक चैरिटी संस्थाओं के जरिए गुप्त रूप से भेजा जाता है, ताकि इसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह आरोप स्पष्ट रूप से दोहराया कि हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक और अन्य संसाधनों की आपूर्ति में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका थी। भारत के अलावा अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने भी पाकिस्तान पर जैश-ए-मोहम्मद को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। बावजूद

इसके, जैश-ए-मोहम्मद की सैन्य क्षमताओं और निरंतर गतिविधियों ने इस बात को बल दिया कि यह समर्थन आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। रिपोर्टों के अनुसार, 2010 तक जैश-ए-मोहम्मद को प्रतिमाह 40 से 80 करोड़ रुपये की सहायता मिल रही थी, जो संचालन, भर्ती, हथियार तस्करी, और प्रोपेगंडा उत्पादन में खर्च की जाती थी। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की सहायता से जैश-ए-मोहम्मद ने नए प्रॉक्सी संगठनों को फंड किया है। कुल मिलाकर, यह कथित वित्तीय सहायता संगठन को राज्य प्रायोजित बनाती है।

इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी की सहायता जैश-ए-मोहम्मद को प्रशिक्षण शिविरों के संचालन में उपयोग होती है, जहां हथियार और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। राज्य का समर्थन जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान में सुरक्षित आधार देता है। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी नकली दस्तावेज और निकासी की व्यवस्था करती है, जो संगठन के ऑपरेटिव्स को बचाती है। पुलवामा जैसे हमलों में इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी की भूमिका विस्फोटकों की आपूर्ति तक फैली है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, लेकिन सहायता जारी है। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी से मिलने वाला धन भर्ती और प्रचार में खर्च होता है। यह सहायता जैश-ए-मोहम्मद को नए हथियारों से लैस कर रही है। कुल मिलाकर, राज्य समर्थन जैश-ए-मोहम्मद की मजबूती का आधार है। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी की कथित सहायता जैश-ए-मोहम्मद को रणनीतिक लक्ष्यों का चयन करने में मदद करती है। मीडिया दुष्प्रचार और हमले के बाद सुरक्षा इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। पाकिस्तान का इनकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जारी है, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद संगठन सक्रिय है। अल रहमत ट्रस्ट जैसे नामों से गतिविधियां जारी हैं, जो इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी के संरक्षण में हैं। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी की सहायता से जैश-ए-मोहम्मद ने वैश्विक नेटवर्क विस्तार किया है। कुल मिलाकर, यह वित्तीय सहायता संगठन को टिकाऊ बनाती है।

प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध

जैश-ए-मोहम्मद का प्रचार तंत्र केवल एक वैचारिक अभियान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मनोवैज्ञानिक हथियार है, जो युवाओं की सोच को प्रभावित करता है, समर्थकों को प्रेरित करता है, और दुश्मनों में भय और भ्रम फैलाता है। जैश-ए-मोहम्मद की प्रचार सामग्री विस्तृत और लक्षित होती है, जो भिन्न आयु वर्गों, लिंगों और

भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई होती है। इस संगठन की सबसे प्रमुख प्रचार पत्रिका अल-कलम है, जो पाक-अधिकृत कश्मीर, पंजाब, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, और ब्रिटेन जैसे देशों में वितरित होती है। यह पत्रिका आतंकवादी हमलों को शहादत, कश्मीर की आजादी और इस्लामिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐशातुल बिनात नामक मासिक पत्रिका विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रकाशित की जाती है, जो जिहादी मातृत्व, धार्मिक भूमिका और बेटों की कुर्बानी को गौरवपूर्ण बताकर धार्मिक कट्टरता को घरों तक पहुंचाने का कार्य करती है। वहीं मुसलमान बच्चे नामक बच्चों के लिए साप्ताहिक पत्रिका में कहानी, कविता और कॉमिक्स के माध्यम से भारत विरोध और कट्टर इस्लामी पहचान का बीजारोपण किया जाता है। इन पत्रिकाओं की डिजिटल संस्करणों ने पहुंच बढ़ाई है। कुल मिलाकर, यह प्रचार युवाओं में उन्माद पैदा करता है।

डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में जैश-ए-मोहम्मद की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। यूट्यूब, ट्विटर (अब एक्स), टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर इसके वीडियो, घोषणाएं और प्रचार पोस्ट नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। जैश-ए-मोहम्मद की प्रॉक्सी इकाई द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हर वर्ष लगभग 500 से 1,000 वीडियो अपलोड किए, जो जम्मू-कश्मीर में भारतीय सुरक्षाबलों के खिलाफ लड़ रहे स्थानीय आतंकवादियों को गाजी और शहीद के रूप में महिमामंडित करते हैं। इन वीडियो को 10 लाख से अधिक बार देखा गया और कई बार स्थानीय युवाओं के बीच वायरल भी हुए, जिससे जैश-ए-मोहम्मद को नई भर्ती में सफलता मिली। जैश-ए-मोहम्मद के प्रचार में एआई-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक वीडियो का उपयोग बढ़ा है, जो झूठी खबरें फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो की संख्या 2,000 से अधिक हो गई है। कुल मिलाकर, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध दुश्मनों में भय पैदा करता है।

जैश-ए-मोहम्मद का प्रचार तंत्र भावनात्मक अपीलों पर आधारित है, जहां कश्मीर में कथित अत्याचारों की कहानियां सुनाकर समर्थन जुटाया जाता है। पत्रिकाएं और वीडियो मुसलमानों को जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। ऐशातुल बिनात महिलाओं को परिवारों में कट्टरता फैलाने के लिए तैयार करती है। मुसलमान बच्चे बच्चों में भारत विरोध बोते हैं। डिजिटल प्रचार टेलीग्राम चैनलों पर गोपनीय है, जहां निर्देश दिए जाते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट के वीडियो शहीदों को महिमामंडित करते हैं, जो भर्ती बढ़ाते हैं।

प्रचार में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग शुरू हुआ है। कुल मिलाकर, यह युद्ध समाज में विभाजन पैदा करता है।

हवाला नेटवर्क और गुप्त वित्तीय स्थानांतरण की रणनीति

जैश-ए-मोहम्मद की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हवाला नेटवर्क है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर, बिना ट्रैक की जाने वाली लेन-देन प्रणाली है। अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी और अन्य सहयोगी संगठन इस तंत्र का उपयोग कर जैश-ए-मोहम्मद को पैसा भेजते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, और ब्रिटेन जैसे देशों से प्रवासी समुदायों द्वारा दिए गए दान को हवाला एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां से वह जैश-ए-मोहम्मद तक पहुंचता है। 2010 से 2023 तक कई ऐसे हवाला रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के लिए करोड़ों रुपये की फंडिंग की पुष्टि हुई। इस गुप्त नेटवर्क की वजह से यह संगठन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से बचकर धन एकत्र कर पाता है। हवाला प्रणाली विश्वास पर आधारित होती है, जहां कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और एजेंटों का नेटवर्क विश्व स्तर पर फैला होता है, जिससे ट्रेसिंग असंभव हो जाती है। जैश-ए-मोहम्मद इस नेटवर्क का उपयोग प्रवासी दानदाताओं से प्राप्त राशि को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शिविरों तक पहुंचाने में करता है। हवाला में एजेंटों की शृंखला होती है, जहां एक देश में दिया गया धन दूसरे देश में बिना बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है। कुल मिलाकर, हवाला गुप्त फंड ट्रांसफर का मुख्य माध्यम है, जो संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत रखता है।

हवाला नेटवर्क में एजेंटों की शृंखला होती है, जहां एक देश में दिया गया धन दूसरे देश में बिना बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है। अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी इस तंत्र से जैश-ए-मोहम्मद को धन भेजकर ट्रेसिंग से बचाती है। प्रवासी समुदायों से दान रमजान जैसे मौकों पर बढ़ता है और हवाला से पाकिस्तान पहुंचता है। भंडाफोड़ों में जैश-ए-मोहम्मद की फंडिंग करोड़ों में पाई गई। यह नेटवर्क प्रतिबंधों से बचाता है और संगठन को निरंतर धन प्रदान करता है। हवाला में कोई कागजी सबूत नहीं होता, जो इसे गुप्त बनाता है। सहयोगी संगठन हवाला से धन भेजते हैं। दान हवाला एजेंटों से पाकिस्तान पहुंचता है। हवाला प्रणाली विश्वास पर आधारित होती है, जहां कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और एजेंटों का नेटवर्क विश्व स्तर पर फैला होता है, जिससे ट्रेसिंग

असंभव हो जाती है। कुल मिलाकर, गुप्त ट्रांसफर जैश-ए-मोहम्मद की वित्तीय मजबूती का आधार है।

हवाला में कोई कागजी सबूत नहीं होता, जो इसे गुप्त बनाता है। सहयोगी संगठन हवाला से धन भेजते हैं। दान हवाला एजेंटों से पाकिस्तान पहुंचता है। भंडाफोड़ों में फंडिंग की पुष्टि हुई। यह तंत्र प्रतिबंधों से बचाता है। हवाला प्रणाली विश्वास पर आधारित होती है, जहां कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और एजेंटों का नेटवर्क विश्व स्तर पर फैला होता है, जिससे ट्रेसिंग असंभव हो जाती है। जैश-ए-मोहम्मद इस नेटवर्क का उपयोग प्रवासी दानदाताओं से प्राप्त राशि को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शिविरों तक पहुंचाने में करता है। अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी इस तंत्र से जैश-ए-मोहम्मद को धन भेजकर ट्रेसिंग से बचाती है। प्रवासी समुदायों से दान रमजान जैसे मौकों पर बढ़ता है और हवाला से पाकिस्तान पहुंचता है। कुल मिलाकर, हवाला गुप्त फंड ट्रांसफर का मुख्य माध्यम है, जो संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत रखता है।

अवैध गतिविधियां और आतंक से प्राप्त आय के स्रोत

जैश-ए-मोहम्मद अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई गैरकानूनी गतिविधियों का सहारा लेता है, जो न केवल संगठन को वित्तीय रूप से सक्षम बनाती हैं, बल्कि भारत के आंतरिक ढांचे को भी कमजोर करने का प्रयास करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ड्रग तस्करी, जिसके तहत अफगान-पाक सीमा से बड़ी मात्रा में हेरोइन और चरस की खेपें तस्करी करके बेची जाती हैं। इस नशीले व्यापार से मिलने वाला धन सीधे हथियार खरीदने, प्रशिक्षण शिविरों के संचालन और आतंकी हमलों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जाली भारतीय मुद्रा का कारोबार भी जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी आय का स्रोत है, जिसके जरिए न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है, बल्कि धन शुद्धिकरण के जरिए अवैध कमाई को वैध दिखाने का प्रयास भी किया जाता है। साथ ही, पाक अधिकृत कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में जबरन वसूली और फिरौती की घटनाएं आम हैं, जहां व्यापारी, ठेकेदार, स्थानीय नेता और यहां तक कि धार्मिक संस्थानों से भी धन उगाहा जाता है। इन सभी स्रोतों से अर्जित पूंजी संगठन के आतंकी अभियानों, भर्ती नेटवर्क और प्रचार अभियानों में लगाई जाती है, जिससे इसकी गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी रहती हैं। ड्रग तस्करी में ड्रोन और सीमा सुरंगों का उपयोग होता है, जो करोड़ों की आय देती है। जाली मुद्रा कराची में छपी जाती है और भारत में फैलाई जाती है।

वसूली में धमकियां दी जाती हैं। फिरौती के मामलों में अपहरण आम है। कुल मिलाकर, ये गतिविधियां जैश-ए-मोहम्मद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं।

अवैध गतिविधियों में ड्रग तस्करी अफगानिस्तान से हेरोइन की सप्लाई पर आधारित है, जो संगठन को त्वरित नकदी देती है। जाली मुद्रा का कारोबार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है और आय उत्पन्न करता है। जबरन वसूली स्थानीय स्तर पर धन उगाहती है। फिरौती में अमीर व्यक्तियों को निशाना बनाया जाता है। इनसे प्राप्त धन हथियार और प्रशिक्षण में लगाया जाता है। ड्रग तस्करी में तालिबान के साथ सहयोग होता है, जो खेपों को सुरक्षित पहुंचाता है। जाली मुद्रा उच्च गुणवत्ता वाली होती है, जो बाजार में आसानी से फैलाई जाती है। वसूली में धमकियां और हिंसा का उपयोग होता है। फिरौती के मामलों में राजनीतिक हस्तियों को भी निशाना बनाया जाता है। इन स्रोतों से धन शुद्धिकरण के बाद उपयोग होता है। कुल मिलाकर, आतंक से अर्जित धन संगठन की मजबूती का स्रोत है।

गैरकानूनी गतिविधियां जैश-ए-मोहम्मद को भारत में अस्थिरता फैलाने में मदद करती हैं। ड्रग तस्करी पंजाब और कश्मीर में फैली है। जाली मुद्रा बिहार और बंगाल में पकड़ी जाती है। वसूली और फिरौती सीमावर्ती इलाकों में आम हैं। ड्रग व्यापार से प्राप्त आय तालिबान के साथ साझा की जाती है। जाली मुद्रा का उत्पादन कराची और लाहौर में होता है। वसूली में स्थानीय व्यापारियों को टारगेट किया जाता है। फिरौती में अपहरण और धमकियां दी जाती हैं। इनसे अर्जित पूंजी अभियानों में लगाई जाती है। कुल मिलाकर, ये स्रोत संगठन को वित्तीय रूप से सक्षम बनाते हैं।

वैध संस्थाओं और व्यवसायों में निवेश की रणनीति

जैश-ए-मोहम्मद केवल गैरकानूनी तरीकों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वैध दिखने वाले धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में आर्थिक संसाधन जुटाता है। पाकिस्तान के बहावलपुर, गुजरांवाला और कराची जैसे शहरों में इससे जुड़े दर्जनों मदरसे, अस्पताल और सामाजिक सेवा केंद्र सक्रिय हैं, जो आम जनता की सहानुभूति पाने के लिए धार्मिक सेवा, शिक्षा और निःशुल्क इलाज जैसे कार्यों का दावा करते हैं। इन संस्थानों की आड़ में बड़े पैमाने पर दान एकत्र किया जाता है, जो कश्मीर की मुक्ति, शहादत और इस्लामी संघर्ष के नाम पर घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं से आता है। उदाहरण के तौर पर, केवल बहावलपुर में ही

संगठन के नियंत्रण वाले कम से कम बीस विद्यालय और पाँच प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं, जो नियमित रूप से प्रचार के माध्यम से धन जुटाते हैं। यह धन बाद में संगठन के सैन्य और प्रचार अभियानों में लगाया जाता है, जबकि आधिकारिक अभिलेखों में इसे धार्मिक और सामाजिक सेवा पर होने वाले व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

मदरसे वैचारिक ब्रेनवॉश के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अस्पताल राहत कार्यों की आड़ में चंदा इकट्ठा करते हैं। शैक्षणिक संस्थान युवाओं को आकर्षित कर उन्हें संगठन के विचारों से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। इस प्रकार, वैध संस्थाओं में निवेश न केवल संगठन को दीर्घकालिक आर्थिक स्रोत उपलब्ध कराता है, बल्कि उसे सामाजिक वैधता भी प्रदान करता है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी एजेंसियों की पकड़ से बचा रहता है और लंबे समय तक अपनी गतिविधियाँ जारी रख पाता है।

जैश-ए-मोहम्मद का प्रचार तंत्र उसके वित्तीय ढांचे का एक अहम हिस्सा है, जो न केवल संगठन की विचारधारा फैलाता है बल्कि नए समर्थक और दानदाता भी तैयार करता है। संगठन की प्रमुख प्रकाशन सामग्री में अल-कलम नामक साप्ताहिक पत्रिका, ऐशातुल बिनात नामक मासिक महिला पत्रिका और मुसलमान बच्चे नामक बच्चों के लिए साप्ताहिक पत्रिका शामिल हैं। इन पत्रिकाओं में भारत-विरोधी विचार, जिहादी प्रचार, और शहादत की महिमा का वर्णन बड़े भावनात्मक अंदाज में किया जाता है, जिससे पाठकों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, जैश-ए-मोहम्मद और उसकी प्रॉक्सी इकाई द रेजिस्टेंस फ्रंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर साल 500 से 1,000 तक वीडियो और डिजिटल पोस्ट साझा करती हैं, जिन्हें लाखों लोग देखते हैं। इन प्रचार अभियानों का असर यह होता है कि खासकर विदेशों में बसे प्रवासी समुदायों से प्रेरित होकर लोग आर्थिक सहायता भेजते हैं, जो संगठन की गतिविधियों के लिए स्थायी वित्तीय स्रोत बन जाता है। इस तरह, प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध, जैश-ए-मोहम्मद के लिए केवल वैचारिक हथियार ही नहीं बल्कि स्थायी फंडिंग का जरिया भी साबित होते हैं। अल-कलम पत्रिका हमलों को संघर्ष के रूप में दिखाती है, जो दान बढ़ाती है। ऐशातुल बिनात महिलाओं को प्रेरित करती है। मुसलमान बच्चे परिवारों में विचार बोते हैं। कुल मिलाकर, प्रचार फंडिंग का मुख्य स्रोत है।

प्रचार में सोशल मीडिया वीडियो शहीदों को महिमामंडित करते हैं, जो भर्ती और दान बढ़ाते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट के पोस्ट वायरल होते हैं। भावनात्मक अंदाज दानदाताओं को आकर्षित करता है। पत्रिकाएं और वीडियो वैचारिक उन्माद पैदा करते हैं, जो प्रवासी समुदायों से सहायता लाते हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो लाखों दर्शकों तक पहुंचते हैं। प्रचार अभियान विदेशी समुदायों को लक्षित करते हैं। कुल मिलाकर, मनोवैज्ञानिक युद्ध फंडिंग सुनिश्चित करता है। प्रचार में भावनात्मक अपीलों पर आधारित है, जहां कश्मीर में कथित अत्याचारों की कहानियां सुनाकर समर्थन जुटाया जाता है। पत्रिकाएं और वीडियो मुसलमानों को जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। ऐशातुल बिनात परिवारों में कट्टरता फैलाती है। मुसलमान बच्चे बच्चों में विरोध बोते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट के वीडियो स्थानीय युवाओं को आकर्षित करते हैं। कुल मिलाकर, यह वैचारिक हथियार फंडिंग का जरिया है।

अध्याय 6:

हिजबुल मुजाहिदीन (HM)

हिजबुल मुजाहिदीन की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिजबुल मुजाहिदीन, जिसे हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित एक अलगाववादी आतंकवादी इकाई है, जो 1989 से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में क्रियाशील रही है। इसकी नींव सितंबर 1989 में रखी गई, और इसका मूल उद्देश्य कश्मीर को भारतीय संघ से अलग करके पाकिस्तान के साथ जोड़ना था। यह जमात-ए-इस्लामी कश्मीर की सैन्य शाखा के रूप में देखा जाता है, जो इस्लामी राजनीतिक सिद्धांतों से प्रभावित एक प्रमुख संस्था है। गठन के पीछे मुख्य कारक 1987 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव थे, जिन्हें बड़े पैमाने पर हेराफेरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की असफलता का प्रतीक माना गया। इन चुनावों में कथित अनियमितताओं ने युवा पीढ़ी में गहन असंतोष और क्रोध पैदा किया, जो उग्रवाद के लिए उपजाऊ भूमि साबित हुआ। इस संदर्भ में, मास्टर अहसान डार और मोहम्मद अब्दुल्ला बंगरू ने संगठन की स्थापना की, जिसे पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से सहायता प्राप्त हुई। इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इसे भारत की पकड़ कमजोर करने और कश्मीर में गुप्त संघर्ष शुरू करने के सामरिक साधन के रूप में प्रयोग किया। आरंभ में यह विभिन्न इस्लामी चरमपंथी समूहों का संघ था, लेकिन जल्द ही जमात-ए-इस्लामी के अधीन आ गया, जिसने इसे सैद्धांतिक दिशा और व्यवस्थित ढांचा दिया। 1990 तक यह कश्मीर विद्रोह का प्रमुख तत्व बन चुका था, जिसमें स्थानीय कश्मीरी युवाओं के अलावा पाकिस्तानी योद्धा भी शामिल हो चुके थे। इसके प्रारंभिक अभियानों में छापामार हमले, आकस्मिक आक्रमण और सरकारी सुविधाओं पर निशाना साधकर भारतीय प्रशासन को अवरुद्ध करने की योजना अपनाई गई।

हिजबुल मुजाहिदीन के उदय ने कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह को नया मोड़ दिया, जहां क्षेत्रीय असंतोष को सैद्धांतिक आधार मिला। संगठन ने कश्मीर को इस्लामी संघर्ष का केंद्रीय बिंदु बनाया, जो पाकिस्तान की योजनाओं से पूरी तरह अनुकूल था। इसका जन्म राजनीतिक उथल-पुथल और बाहरी समर्थन से हुआ, जो इसकी ऐतिहासिक

नींव का हिस्सा है। इसकी जड़ें कश्मीर के राजनीतिक अराजकता में हैं, जहां 1987 के चुनावों ने हेराफेरी से युवा वर्ग में विद्रोह की लहर पैदा की। मास्टर अहसान डार और मोहम्मद अब्दुल्ला बंगरू ने इसका गठन किया, जो इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी द्वारा समर्थित था। जमात-ए-इस्लामी कश्मीर ने सैद्धांतिक अधिग्रहण किया, जो इस्लामी सिद्धांत उपलब्ध कराती है। संघ से संगठन सुदृढ़ हुआ, जो चरमपंथी इकाइयों का मेल था। 1990 में विद्रोह प्रधान हो गया, जहां कश्मीरी और पाकिस्तानी योद्धा सम्मिलित हुए। अभियान छापामार शैली के थे, जो प्रशासन को बाधित करते थे। ऐतिहासिक उत्थान असंतोष से आरंभ हुआ, जो संगठन को रूप देता है।

हिजबुल मुजाहिदीन का गठन अलगाववाद की मिट्टी पर हुआ, जहां चुनावों ने क्रोध भड़काया। संस्थापक स्थानीय थे, लेकिन सहयोग विदेशी था। जमात-ए-इस्लामी ने मार्गदर्शन दिया, जो राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी है। संघ ने रूपरेखा दी, जो इकाइयों को एकीकृत करती है। विद्रोह में प्रधान भूमिका, जो युवा भागीदारी बढ़ाती है। अभियान भारतीय उद्देश्यों पर केंद्रित थे, जो रुकावट पैदा करते हैं। जन्म संकट से है, जो उत्थान को प्रभावित करता है। इसका इतिहास 1989 से है, जो सितंबर में स्थापित हुआ। उद्देश्य एकीकरण है, जो पाकिस्तान से जुड़ा है। जमात-ए-इस्लामी सैन्य इकाई है, जो सिद्धांत देती है। चुनाव हेराफेरी से क्रोध हुआ, जो चरमपंथ की नींव बना। संस्थापक स्थानीय थे, लेकिन एजेंसी से सहयोग मिला। संघ इकाइयों का था, जो अधिग्रहण में आया। विद्रोह प्रधान बना, जो योद्धा सम्मिलित करता है। अभियान छापामार थे, जो प्रशासन अवरुद्ध करते हैं। ऐतिहासिक नींव संगठन की ताकत है।

हिजबुल मुजाहिदीन का नेतृत्व और पदानुक्रमित संगठनात्मक ढांचा

1991 में हिजबुल मुजाहिदीन ने अपनी संरचना को मजबूत करने के लिए एक सर्वोच्च सलाहकारी परिषद 'शूरा' गठित की, जो संगठन के सभी निर्णयों की अंतिम प्राधिकारी बन गई। इसी परिषद ने मास्टर अहसान डार को हटाकर सैयद सलाहुद्दीन को नया प्रमुख नियुक्त किया। सैयद सलाहुद्दीन, जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ़ शाह है, आज भी इस पद पर बना हुआ है और भारत, अमेरिका तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा उन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। उसका नेतृत्व संगठन की सामरिक दिशा तय करता है, जिसमें इस्लामी कट्टरवाद और विश्वव्यापी जिहादी विचारधारा पर विशेष बल दिया जाता है।

हिजबुल मुजाहिदीन की संरचना अत्यंत स्तरीय है, जिसमें शूरा परिषद 10 से 15 वरिष्ठ सदस्यों के साथ सामरिक निर्णय लेती है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थित है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में संपर्क कार्यालय संचालित होते हैं। इस भौगोलिक व्यवस्था से संगठन को अंतर-सेवा गुप्तचर एजेंसी से कथित आर्थिक और सैन्य सहयोग प्राप्त करने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और कश्मीर में अभियानों का निर्देशन करने में सुविधा मिलती है।

संगठन में क्षेत्रीय प्रमुख नियुक्त होते हैं, जो श्रीनगर, कुपवाड़ा और अनंतनाग जैसे संवेदनशील जिलों में 50 से 100 उग्रवादियों की इकाइयों का संचालन और निरीक्षण करते हैं। यह व्यवस्था संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर लचीलापन और बेहतर तालमेल बनाए रखने में सहायक होती है, जो लंबे समय तक चरमपंथी गतिविधियों को जारी रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। सैयद सलाहुद्दीन का मार्गदर्शन संगठन को एकीकृत रखता है और उसकी सामरिक क्षमता को निरंतर दिशा देता है, जबकि स्तरीय ढांचा इसकी कार्यकुशलता को और अधिक सुदृढ़ बनाता है।

हिजबुल मुजाहिदीन का मार्गदर्शन सैयद सलाहुद्दीन के अधीन है, जो संगठन की दिशा निर्धारित करता है। शूरा परिषद मुख्य फैसले लेती है, जो वरिष्ठ सदस्यों का समूह है। मुख्यालय मुजफ्फराबाद में है, जहां से अभियान निर्देशित होते हैं। संपर्क दफ्तर सहयोग के लिए हैं। क्षेत्रीय प्रमुख इकाइयों का निरीक्षण करते हैं, जो क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। यह संरचना लचीलापन उपलब्ध कराती है। मार्गदर्शन और ढांचा संगठन को सुदृढ़ बनाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की संरचना स्तरीय है, जहां शूरा अंतिम फैसले लेती है। सैयद सलाहुद्दीन प्रमुख हैं, जो सामरिक दिशा निर्धारित करता है। मुख्यालय और दफ्तर सहयोग सुनिश्चित करते हैं। क्षेत्रीय प्रमुख संवेदनशील जिलों में कार्य करते हैं। इकाइयाँ 50 से 100 चरमपंथियों की होती हैं। यह ढांचा अभियानों को कुशल बनाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मार्गदर्शन सैयद सलाहुद्दीन पर केंद्रित है, जो वैश्विक चरमपंथी हैं। शूरा परिषद सामरिक फैसले लेती है। मुख्यालय प्रशिक्षण के लिए है। दफ्तर तालमेल रखते हैं। प्रमुख निरीक्षण करते हैं। संरचना क्षेत्रीय और शहरी स्तर पर लचीलापन देती है। संगठनात्मक ढांचा लंबी क्रियाओं को बनाए रखता है। हिजबुल मुजाहिदीन की स्तरीयता शूरा से आरंभ होती है, जो फैसले लेती है। सैयद सलाहुद्दीन मार्गदर्शन देता है। मुख्यालय मुजफ्फराबाद में है। दफ्तर इस्लामाबाद में हैं। प्रमुख जिलों में इकाइयाँ संभालते हैं। लचीलापन क्षेत्रीय है। ढांचा सुदृढ़ है।

राज्य प्रायोजन और अंतरराष्ट्रीय पहुंच का विश्लेषण

हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान, विशेष रूप से उसकी गुप्तचर संस्था अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी के बीच संबंध अत्यंत विवादास्पद और संवेदनशील रहे हैं। भारत और अन्य राष्ट्रों का स्पष्ट दावा है कि पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन को आर्थिक सहयोग, प्रशिक्षण, हथियार और सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराता है, ताकि कश्मीर में इसे सामरिक गुप्त युद्ध का साधन बनाया जा सके। 1990 के दशक के मध्य तक, पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट जैसे शिविरों में प्रतिवर्ष लगभग पाँच सौ से एक हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता था। इन शिविरों में उन्हें छापामार युद्ध, विस्फोटक निर्माण, हथियार संचालन और घुसपैठ की विधियाँ सिखाई जाती थीं।

1990 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ सदस्य अफ़ग़ानिस्तान के हिज्ब-ए-इस्लामी गुलबुद्दीन से भी प्रशिक्षण लेते थे, जब तक 1996 में तालिबान ने सत्ता पर कब्ज़ा नहीं कर लिया। हालांकि यह वैश्विक चरमपंथ की दिशा में सीमित प्रयास था, फिर भी हिजबुल मुजाहिदीन की अंतरराष्ट्रीय पहुंच लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसी इकाइयों की तुलना में काफी कम रही है। इसके बावजूद, पाकिस्तानी सैन्य तंत्र और कश्मीरी चरमपंथी नेटवर्क से इसके संबंध इतने गहरे हैं कि यह संगठन आज भी सक्रिय है और चरमपंथ का संचालन कर रहा है।

वैश्विक प्रतिबंधों और भारतीय सरकार के प्रयासों के बावजूद, हिजबुल मुजाहिदीन ने “द रेज़िस्टेंस फ्रंट” जैसे नए नामों और मोर्चों के अधीन कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे इसके नेटवर्क को नष्ट करना बेहद कठिन हो गया है। इसकी मजबूती का मुख्य कारण अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी का कथित सहयोग और कश्मीर में व्याप्त युवा असंतोष है, जिसका हिजबुल मुजाहिदीन लगातार उपयोग करता रहा है। वर्ष 2020 तक संगठन लगभग दो सौ से तीन सौ युवाओं की भर्ती कर रहा था, जो इसके निरंतर संचालन और क्षेत्रीय अस्तित्व का प्रमाण है। राज्य सहयोग और वैश्विक पहुंच, हिजबुल मुजाहिदीन की शक्ति के प्रमुख स्तंभ हैं।

हिजबुल मुजाहिदीन का पाकिस्तान से संपर्क इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी के जरिए सशक्त है, जो आर्थिक और सैन्य सहयोग उपलब्ध कराती है। मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट जैसे शिविरों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, जहां छापामार लड़ाई और घुसपैठ की विधियाँ सिखाई जाती हैं। अफ़ग़ानिस्तान के हिज्ब-ए-इस्लामी

गुलबुद्दीन से सहयोग वैश्विक चरमपंथ की झलक देता है। हिजबुल मुजाहिदीन की वैश्विक पहुंच सीमित है, लेकिन पाकिस्तानी व्यवस्था से सशक्त है। वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद, ताजा मोर्चों जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट से क्रियाएँ जारी हैं। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी का सहयोग असंतोष का शोषण करता है। युवाओं की भर्ती निरंतर है, जो क्षेत्रीय अस्तित्व बनाए रखती है। राज्य सहयोग संगठन को दृढ़ बनाता है। हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान से सहयोग मिलता है, जो कश्मीर में गुप्त संघर्ष के लिए है। शिविरों में विस्फोटक और शस्त्र का प्रशिक्षण होता है। अफगानिस्तान के सहयोग से चरमपंथ की दिशा मिलती। वैश्विक पहुंच लश्कर-ए-तैयबा से कम है। ताजा नामों से जाल समाप्त करना कठिन है। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी असंतोष का प्रयोग करती है। भर्ती युवा असंतोष से होती है। वैश्विक पहुंच संगठन की दृढ़ता का कारण है। हिजबुल मुजाहिदीन का पाकिस्तान से सहयोग गठन से है, जो सामरिक है। मुजफ्फराबाद में क्रियाएँ निर्देशित होती हैं। शिविरों में विधियाँ सिखाई जाती हैं। सहयोग प्रोत्साहन देता है। हिजबुल मुजाहिदीन उद्देश्यों से अनुकूल है। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी उपकरण देती है। सक्रियता संरक्षण दिखाती है। राज्य सहयोग और पहुंच सशक्त बनाते हैं।

हिजबुल मुजाहिदीन का संपर्क विवादपूर्ण है, जो सहयोग उपलब्ध कराता है। मुख्यालय तालमेल के लिए है। शिविर रंगरूट तैयार करते हैं। सहयोग चरमपंथ को प्रोत्साहित करता है। हिजबुल मुजाहिदीन प्राकृतिक साथी है। इंटर-सेवा खुफिया एजेंसी मार्ग उपलब्ध कराती है। योद्धा व्यापकता दर्शाते हैं। इनकार के बावजूद, क्रियाएँ संकेत देती हैं। एजेंसियाँ ताकत का स्रोत हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की वैश्विक पहुंच सीमित लेकिन प्रभावशाली है, जो विद्रोह को बनाए रखती है। अफगानिस्तान से प्रशिक्षण मिला। तालिबान से सिद्धांत प्रभावित हुआ। नेटवर्क लश्कर-ए-तैयबा से अलग है। एजेंसियाँ सहयोग देती हैं। उपलब्धियाँ वैश्विक हैं। संपर्क हिजबुल मुजाहिदीन को सशक्त बनाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का संपर्क सीमित लेकिन प्रभावशाली है, जो विद्रोह को बनाए रखता है। अफगान गृहयुद्ध में सहयोग था। तालिबान ने प्रभावित किया। संपर्क अपेक्षाकृत सीमित है। गठबंधन समर्थन देते हैं। शस्त्र और प्रशिक्षण मिलते हैं। मंचों पर अवसर मिलता है। नेटवर्क मुख्य भूमिका निभाता है। हिजबुल मुजाहिदीन की क्रियाएँ कश्मीर तक सीमित हैं, लेकिन संपर्क वैश्विक हैं। अफगानिस्तान से सहयोग था। तालिबान से सिद्धांत प्रभावित हुआ। नेटवर्क लश्कर-ए-तैयबा से कम है। संपर्कों की संख्या कम है। एजेंसियाँ सहयोग देती हैं। वैश्विक पहुंच संगठन की क्षमता बढ़ाती है।

हिजबुल मुजाहिदीन का ऐतिहासिक विकास

हिजबुल मुजाहिदीन की उत्पत्ति 1980 के दशक के अंत में हुई, जब कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववाद अपने चरम पर था। इस अवधि में कश्मीर की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में गहरा संकट था, जहां स्थानीय आबादी में असंतोष बढ़ रहा था। 1987 के विधानसभा चुनावों में कथित धांधली ने इस असंतोष को और भड़काया, क्योंकि युवाओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास खो दिया। इस पृष्ठभूमि में हिजबुल मुजाहिदीन ने इस्लामिक उग्रवादियों को एकजुट करके एक संगठित प्रतिरोध की नींव रखी, जो कश्मीर को पाकिस्तान में विलय करने के लक्ष्य पर केंद्रित था। पाकिस्तान की ओर से मिली रणनीतिक सहायता ने संगठन को शुरुआती वर्षों में मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे यह जल्दी ही एक प्रमुख उग्रवादी समूह बन गया। सैयद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में संगठन ने कई हमले आयोजित किए, जो भारतीय सेना और नागरिकों को निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान में सीमित उपस्थिति ने इसके जिहादी चरित्र को और मजबूत किया, हालांकि यह मुख्यतः क्षेत्रीय रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे आतंकवादी घोषित किया गया, लेकिन स्थानीय समर्थन और संरक्षण ने इसकी निरंतरता सुनिश्चित की। सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां संगठन को समाप्त करने में बाधा बनीं, जो कश्मीर संघर्ष की जटिलता को दर्शाती हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का विकास भारत की सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करता रहा है।

कश्मीर में 1980 के दशक की अस्थिरता ने हिजबुल मुजाहिदीन के उदय को संभव बनाया, जहां अलगाववादी भावनाएं तेजी से फैलीं। चुनाव धांधली ने युवाओं में गहरा विद्रोह पैदा किया, जो संगठन की स्थापना का प्रत्यक्ष कारण बना। इस्लामिक उग्रवादियों का एकीकरण ने प्रतिरोध को शक्ति दी, जो स्थानीय मुद्दों से प्रेरित था। पाकिस्तान की सहायता ने संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित किया, जो विकास के लिए आवश्यक था। नेतृत्व ने हमलों को रणनीतिक रूप दिया, जो घातक और लक्षित थे। वैश्विक जिहादी आकांक्षाएं अफगानिस्तान से जुड़ीं, जो संगठन की महत्वाकांक्षा दिखाती हैं। घोषणा के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ, जो स्थानीय समर्थन से संभव है। संरक्षण ने निरंतरता प्रदान की, जो सामाजिक जटिलताओं से जुड़ा है। प्रभाव भारत की आंतरिक स्थिरता पर पड़ा, जो संबंधों को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक विकास संगठन की स्थिरता का मूल है। हिजबुल मुजाहिदीन का विकास कश्मीर की

राजनीतिक स्थिति से जुड़ा, जो असंतोष से शुरू हुआ। 1987 की घटनाएं युवाओं को उग्रवाद की ओर ले गईं, जो संगठन की आधार बनीं। प्रतिरोध आंदोलन ने उग्रवाद को संगठित किया, जो इस्लामिक था। पाकिस्तान की भूमिका प्रसार में महत्वपूर्ण थी, जो मार्गदर्शन प्रदान करती थी। हमले सेना पर केंद्रित थे, जो प्रभावी साबित हुए। अफगानिस्तान में झलक वैश्विक थी, जो जिहादी थी। क्षेत्रीय खतरा समर्थन से है, जो संरक्षण पर निर्भर है। परिस्थितियां समाप्ति में बाधा हैं, जो जटिल हैं। प्रभाव सुरक्षा और संबंधों पर है, जो तनाव बढ़ाता है। विकास दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। हिजबुल मुजाहिदीन की उत्पत्ति संकट से है, जो अलगाववाद बढ़ाता है। धोखे ने युवाओं को हताश किया, जो विद्रोह पैदा करता है। मंच ने उग्रवादियों को लाया, जो प्रतिरोध है। सहायता ने खड़ा किया, जो रणनीतिक है। हमले नागरिकों पर भी थे, जो घातक हैं। आकांक्षाएं उपस्थिति से हैं, जो सीमित हैं। खतरा बरकरार है, जो घोषणा के बाद है। आधार स्थानीय है, जो संरक्षण से है। प्रभाव तनावपूर्ण है, जो संबंधों पर है। ऐतिहासिक विकास चुनौती है।

हिजबुल मुजाहिदीन के उद्देश्य और वैचारिक ढांचा

हिजबुल मुजाहिदीन के उद्देश्य और विचारधारा केवल क्षेत्रीय विवादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इस्लामी कट्टरवाद, राजनीतिक वर्चस्व और रणनीतिक लक्ष्यों का एक जटिल मिश्रण हैं। संगठन का प्रमुख उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में विलय कराना है, जो पाकिस्तान के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है। हालांकि, यह केवल भू-राजनीतिक एजेंडा नहीं है - हिजबुल मुजाहिदीन का वैचारिक आधार एक इस्लामी राज्य की स्थापना है, जो जमात-ए-इस्लामी के साथ इसके वैचारिक संबंधों को उजागर करता है। यह नजरिया इसे अन्य संगठनों जैसे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से अलग करता है, जिनका जोर केवल स्वतंत्रता पर था, न कि पाकिस्तान के साथ विलय पर। हिजबुल मुजाहिदीन का उद्देश्य कश्मीर को इस्लामी राज्य बनाना है, जो कट्टरवाद से प्रेरित है। विचारधारा राजनीतिक वर्चस्व चाहती है, जो रणनीतिक है। जमात-ए-इस्लामी संबंध मजबूत हैं, जो वैचारिक हैं। नजरिया अलगाववादी है, जो अन्य से भिन्न है। उद्देश्य जटिल मिश्रण हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के उद्देश्य क्षेत्रीय हैं, जो विलय पर केंद्रित हैं। विचारधारा इस्लामी है, जो कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान से मेल खाते हैं। वैचारिक आधार राज्य स्थापना है। संबंध उजागर हैं। वैचारिक ढांचा मजबूत है। हिजबुल

मुजाहिदीन का उद्देश्य अलगाव है, जो पाकिस्तान में विलय है। विचारधारा कट्टरवाद का मिश्रण है, जो वर्चस्व चाहती है। लक्ष्य दीर्घकालिक हैं। आधार इस्लामी राज्य है। उद्देश्य रणनीतिक हैं।

हिजबुल मुजाहिदीन के उद्देश्य विवादों से आगे हैं, जो इस्लामी हैं। प्रमुख विलय है, जो पाकिस्तान से मेल है। वैचारिक आधार राज्य है, जो संबंध दिखाता है। नजरिया स्वतंत्रता से अलग है। विचारधारा जटिल है। हिजबुल मुजाहिदीन का उद्देश्य कश्मीर अलग करना है, जो विलय पर है। विचारधारा कट्टरवाद पर है, जो लक्ष्यों का है। रणनीतिक पाकिस्तान से है। आधार स्थापना है। वैचारिक ढांचा प्रभावी है। हिजबुल मुजाहिदीन के उद्देश्य मिश्रण हैं, जो कट्टरवाद से हैं। विलय दीर्घकालिक है। वैचारिक संबंध हैं। नजरिया अलग है। उद्देश्य राजनीतिक हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का उद्देश्य क्षेत्रीय है, जो इस्लामी है। विचारधारा वर्चस्व है, जो रणनीतिक है। लक्ष्य अनुरूप हैं। आधार जमात है। ढांचा मजबूत है। हिजबुल मुजाहिदीन के उद्देश्य कट्टरवाद पर हैं, जो विलय चाहते हैं। प्रमुख अलगाव है। विचारधारा मिश्रण है। संबंध उजागर हैं। वैचारिक आधार जटिल है। हिजबुल मुजाहिदीन का उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है, जो भू-राजनीतिक है। विचारधारा इस्लामी राज्य है, जो जमात से जुड़ी है। उद्देश्य प्रभावी हैं।

धार्मिक आधार और इस्लामिक लक्ष्य

हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा इस्लाम की एक कठोर व्याख्या पर आधारित है, जो शरीयत कानून को लागू करने और कश्मीर के इस्लामीकरण की वकालत करती है। यह धार्मिक पहलू जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे धर्मनिरपेक्ष संगठनों से इसे भिन्न बनाता है। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर संघर्ष को एक धार्मिक जिहाद के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे इसे कश्मीर और उससे बाहर के मुसलमानों से समर्थन प्राप्त होता है। यह खुद को भारतीय कब्जे के विरुद्ध इस्लाम का रक्षक बताता है। इसके प्रचार-पत्र, जैसे अल-जिहाद और अल-कलाम, जिनकी 2018 तक मासिक 10,000 प्रतियां वितरित की जाती थीं, शहादत की महिमा और कश्मीर को इस्लामी मुक्ति का युद्धक्षेत्र बताने पर जोर देते हैं। 2015 तक यह संगठन रोजाना चार घंटे के मदरसा सत्र आयोजित करता था, जो तफ्सीर इब्न कसीर जैसे ग्रंथों पर आधारित होते थे, जिससे प्रतिवर्ष 50 से 100 चरमपंथी स्नातक तैयार होते थे। देवबंदी और सलाफी प्रभावों से प्रेरित इसकी धार्मिक व्याख्या राष्ट्रवाद को पूरी तरह अस्वीकार करती है और एक

वैश्विक मुस्लिम उम्मा की स्थापना का समर्थन करती है। सैयद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में इसके भाषणों में जिहाद को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारे और वीडियो इसके प्रचार में नियमित रूप से गूंजते हैं। यह वैचारिक ढांचा संगठन की भर्ती नीति का मूल स्तंभ है - 2020 तक हर वर्ष 200 से 300 युवा बेरोजगारी, मानवाधिकार हनन और राजनीतिक उपेक्षा जैसी समस्याओं के आधार पर संगठन से जुड़ते रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा कठोर व्याख्या है, जो शरीयत की वकालत करती है। धार्मिक पहलू भिन्न बनाता है। संघर्ष जिहाद है, जो समर्थन देता है। रक्षक के रूप में प्रस्तुत है। प्रचार-पत्र शहादत पर जोर देते हैं। मदरसा सत्र चरमपंथी तैयार करते हैं। प्रभाव देवबंदी हैं, जो राष्ट्रवाद अस्वीकार करते हैं। भाषण कर्तव्य बताते हैं। नारे प्रचार में हैं। ढांचा भर्ती का मूल है। धार्मिक आधार मजबूत है।

हिजबुल मुजाहिदीन की व्याख्या कठोर है, जो इस्लामीकरण चाहती है। पहलू धर्मनिरपेक्ष से अलग है। जिहाद प्रस्तुत समर्थन देता है। रक्षक भारतीय विरुद्ध है। पत्र महिमा बताते हैं। सत्र ग्रंथों पर हैं, जो स्नातक तैयार करते हैं। व्याख्या अस्वीकार करती है, जो उम्मा समर्थन करती है। नेतृत्व में कर्तव्य है। नारे और वीडियो नियमित हैं। ढांचा नीति का मूल है। इस्लामिक लक्ष्य वैश्विक हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का आधार इस्लाम है, जो शरीयत लागू करता है। भिन्नता धर्मनिरपेक्ष से है। जिहाद से समर्थन है, जो मुसलमानों से है। रक्षक कब्जे के विरुद्ध है। प्रचार शहादत पर है। सत्र तैयार करते हैं। प्रभाव सलाफी हैं, जो वैश्विक हैं। भाषण धार्मिक हैं। नारे गूंजते हैं। ढांचा भर्ती आधार है। लक्ष्य कट्टर हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा व्याख्या पर है, जो वकालत करती है। पहलू भिन्न है। प्रस्तुत जिहाद है। बताता रक्षक है। जोर युद्धक्षेत्र पर है। सत्र स्नातक हैं। प्रेरित प्रभावों से हैं। प्रस्तुत कर्तव्य है। गूंजते प्रचार में हैं। मूल स्तंभ है। धार्मिक आधार लक्ष्य है।

हिजबुल मुजाहिदीन का आधार कठोर है, जो लागू करता है। अलग धर्मनिरपेक्ष से है। प्रस्तुत समर्थन देता है। रक्षक बताता है। जोर बताने पर है। सत्र तैयार करते हैं। व्याख्या अस्वीकार करती है। कर्तव्य प्रस्तुत है। नियमित हैं। आधार नीति है। इस्लामिक लक्ष्य मजबूत हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की व्याख्या इस्लामीकरण है, जो वकालत है। पहलू भिन्न है। जिहाद से सहायता है। विरुद्ध रक्षक है। पत्र जोर देते हैं। सत्र पकड़े जाते हैं। व्याख्या समर्थन करती है। भाषण कर्तव्य हैं। नारे नियमित हैं। ढांचा मूल है। आधार वैश्विक है। हिजबुल मुजाहिदीन का आधार व्याख्या है, जो शरीयत है। भिन्नता है।

प्रस्तुत धार्मिक है। बताता भारतीय है। जोर शहादत पर है। सत्र स्नातक हैं। प्रभाव देवबंदी हैं। प्रस्तुत जिहाद है। गूंजते कश्मीर हैं। स्तंभ युवा है। लक्ष्य चरमपंथी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा कठोर है, जो लागू करती है। पहलू अलग है। संघर्ष जिहाद है। रक्षक कब्जे है। प्रचार महिमा पर है। सत्र ग्रंथ हैं। व्याख्या उम्मा है। कर्तव्य भाषण हैं। नारे नियमित हैं। ढांचा आधार है। धार्मिक लक्ष्य वैश्विक हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का आधार इस्लाम है, जो वकालत करता है। भिन्न धर्मनिरपेक्ष है। प्रस्तुत समर्थन देता है। रक्षक बताता है। जोर युद्धक्षेत्र है। सत्र तैयार हैं। प्रभाव अस्वीकार हैं। कर्तव्य प्रस्तुत है। गूंजते हैं। स्तंभ नीति है। इस्लामिक लक्ष्य कट्टर हैं। हिजबुल मुजाहिदीन की व्याख्या कठोर है, जो इस्लामीकरण है। पहलू भिन्न है। जिहाद प्रस्तुत है। रक्षक विरुद्ध है। पत्र जोर देते हैं। सत्र पकड़े जाते हैं। व्याख्या समर्थन करती है। भाषण धार्मिक हैं। नारे नियमित हैं। ढांचा मूल है। आधार मजबूत है।

राजनीतिक और भू-राजनीतिक प्रेरणाएँ

हिजबुल मुजाहिदीन की राजनीतिक प्रेरणाएँ गहराई से कश्मीर की जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निहित हैं, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद ने संगठन को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। संगठन का मूल लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में शामिल करना है, जो 1947 के विभाजन की अधूरी कहानी से उपजा है, जिसमें कश्मीर की स्थिति अनसुलझी रह गई। यह दृष्टिकोण पाकिस्तान की राष्ट्रीय आकांक्षा से जुड़ा हुआ है, जहाँ कश्मीर को सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक रूप से अपना हिस्सा माना जाता है, और संगठन इस लक्ष्य को हथियारबंद संघर्ष के जरिए हासिल करने का माध्यम बनता है। राजनीतिक स्तर पर, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में व्याप्त असंतोष को अपने पक्ष में मोड़ता है, जैसे कि चुनावी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं, स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी और केंद्र सरकार की नीतियों से उपजी निराशा को, जो युवाओं में विद्रोही भावना को जन्म देती है। संगठन खुद को एक राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत करता है, जो स्थानीय जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वास्तव में यह पाकिस्तान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक विस्तार है, जिसमें कश्मीर को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रेरणा से संगठन को वैधता मिलती है, क्योंकि यह केवल हिंसा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संघर्ष की छवि बनाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के दावों को मजबूत करने का काम करता है।

इससे संगठन की गतिविधियाँ न केवल स्थानीय स्तर पर प्रभावी होती हैं बल्कि वे भारत की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित करती हैं, जिसमें क्षेत्रीय चुनावों और नीतियों में बदलाव की मांग उठती रहती है।

भू-राजनीतिक प्रेरणाएँ हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान की सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों से जोड़ती हैं, जहाँ संगठन को भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध के हथियार के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान की नीति, जो भारत को लगातार अस्थिर करने पर आधारित है, संगठन को प्रशिक्षण, संसाधन और समर्थन प्रदान करती है, ताकि सीधे युद्ध से बचा जा सके लेकिन भारत की सीमाओं पर दबाव बनाया जा सके। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, जिसमें महत्वपूर्ण जल स्रोत, व्यापार मार्ग और सैन्य ठिकाने शामिल हैं, संगठन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह क्षेत्र दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। हिजबुल मुजाहिदीन अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों जैसे संयुक्त राष्ट्र पर कश्मीर मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिसमें मानवाधिकारों और आत्मनिर्णय के मुद्दों को जोड़ा जाता है। यह प्रेरणा संगठन को उसके इस्लामी एजेंडे से आगे ले जाती है, जहाँ धार्मिक लक्ष्यों को भू-राजनीतिक आवश्यकताओं के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे पाकिस्तान को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में लाभ मिलता है। संगठन की सक्रियता भारत-पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करती है, जिसमें सीमा पर तनाव, व्यापारिक बाधाएँ और कूटनीतिक वार्ताओं में रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जो दक्षिण एशिया की समग्र स्थिरता को चुनौती देती हैं। इससे संगठन की जीवदृढ़ता बढ़ती है, क्योंकि भू-राजनीतिक समर्थन इसे लंबे संघर्ष के लिए संसाधन प्रदान करता है, और यह क्षेत्रीय शक्तियों के बीच के खेल का हिस्सा बन जाता है।

ये राजनीतिक और भू-राजनीतिक प्रेरणाएँ हिजबुल मुजाहिदीन को एक बहुआयामी संगठन बनाती हैं, जहाँ स्थानीय असंतोष को वैश्विक संदर्भों से जोड़ा जाता है। संगठन की सफलता इसी मिश्रण पर निर्भर है, क्योंकि राजनीतिक वैधता इसे जन समर्थन दिलाती है जबकि भू-राजनीतिक समर्थन संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण संगठन को केवल एक आतंकवादी गुट से ऊपर उठाकर एक रणनीतिक खिलाड़ी बनाता है, जो कश्मीर के संघर्ष को जटिल बनाता है। हालांकि चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव और सुरक्षा अभियान, लेकिन ये प्रेरणाएँ संगठन को अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे इसका प्रभाव निरंतर बना रहता है।

अंततः, हिजबुल मुजाहिदीन की ये प्रेरणाएँ क्षेत्र की शांति प्रक्रिया के लिए एक बड़ी बाधा हैं, क्योंकि वे ऐतिहासिक विवादों को जीवित रखती हैं और नए संघर्षों को जन्म देती हैं, जो दक्षिण एशिया की राजनीतिक परिदृश्य को लगातार प्रभावित करती रहती हैं।

भर्ती और कट्टरपंथीकरण की रणनीतियाँ

हिजबुल मुजाहिदीन की भर्ती रणनीतियाँ कश्मीर के युवाओं को लक्षित करने पर केंद्रित हैं, जहाँ संगठन धार्मिक और सामुदायिक संस्थाओं को प्रमुख माध्यम बनाता है। मदरसों, मस्जिदों और शैक्षणिक केंद्रों में युवाओं को धार्मिक शिक्षा के नाम पर संपर्क किया जाता है, जहाँ उन्हें कश्मीर की स्थिति को एक धार्मिक और राजनीतिक अन्याय के रूप में समझाया जाता है, जो उनकी भावनाओं को उकसाता है। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय मुद्दों का दोहन किया जाता है, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार, जो युवाओं को संगठन की ओर आकर्षित करते हैं। संगठन परिवारिक और सामुदायिक नेटवर्कों का उपयोग करता है, जहाँ पहले से जुड़े सदस्यों के माध्यम से नए लोगों को शामिल किया जाता है, जिससे एक विश्वास का चक्र बनता है। यह रणनीति संगठन को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाती है, क्योंकि भर्ती हुए सदस्य क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक समझ रखते हैं, जो संचालन में सहायक होती है। भर्ती में आर्थिक प्रोत्साहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे सदस्यों को नियमित भत्ता और उनके परिवारों को सुरक्षा की गारंटी, जो गरीबी से जूझते परिवारों को प्रभावित करता है। इससे संगठन की संख्या निरंतर बढ़ती है, और यह कश्मीर में अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है, जो लंबे संघर्ष के लिए आवश्यक है।

कट्टरपंथीकरण की रणनीतियाँ हिजबुल मुजाहिदीन में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जहाँ भर्ती हुए युवाओं को वैचारिक रूप से कठोर बनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों और व्याख्यानों पर आधारित सत्रों में युवाओं को जिहाद को एक नैतिक और धार्मिक दायित्व के रूप में सिखाया जाता है, जो उनकी सोच को मौलिक रूप से बदल देता है। इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे भारतीय राज्य और सुरक्षा बलों को दमनकारी ताकत के रूप में चित्रित करना, जो युवाओं में गहरी घृणा पैदा करता है। कट्टरपंथीकरण चरणबद्ध होता है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण तक शामिल है, ताकि युवा पूरी तरह संगठन के प्रति

समर्पित हो जाए। संगठन सामाजिक अलगाव का भी उपयोग करता है, जहाँ युवाओं को मुख्यधारा से अलग करके उनके विश्वास को मजबूत किया जाता है, जो उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार करता है। यह रणनीति संगठन की संरचना को मजबूत बनाती है, क्योंकि कट्टर सदस्य आसानी से अलग नहीं होते और लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। कट्टरपंथीकरण में प्रचार सामग्री का भी महत्व है, जो युवाओं को शहीदों की कहानियों से प्रेरित करती है, जिससे उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती है।

इन भर्ती और कट्टरपंथीकरण रणनीतियों का संयोजन हिजबुल मुजाहिदीन को एक सतत स्रोत प्रदान करता है, जो इसके अस्तित्व और संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। भर्ती से नए सदस्य आते हैं जबकि कट्टरपंथीकरण उन्हें वैचारिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे संगठन एक सुसंगठित इकाई बनता है। यह दृष्टिकोण अन्य संगठनों से भिन्न है, क्योंकि यह स्थानीय संदर्भों पर आधारित है और कश्मीर की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो इसकी प्रभावशीलता बढ़ाता है। हालांकि सुरक्षा अभियान और सामाजिक प्रयास इन रणनीतियों को चुनौती देते हैं, लेकिन संगठन की अनुकूलन क्षमता इन्हें जीवित रखती है, जिससे युवाओं का एक नया समूह लगातार जुड़ता रहता है। अंततः, ये रणनीतियाँ कश्मीर के संघर्ष को जटिल बनाती हैं, क्योंकि वे युवाओं की ऊर्जा को हिंसा की ओर मोड़ती हैं और क्षेत्र की शांति प्रक्रिया को बाधित करती हैं, जो लंबे समय तक प्रभाव डालती हैं।

प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध

हिजबुल मुजाहिदीन का प्रचार अभियान एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति है, जो विभिन्न डिजिटल और पारंपरिक माध्यमों के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करने और संगठन की छवि को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वीडियो, पोस्ट और ग्राफिक्स के जरिए संगठन अपने सदस्यों की बहादुरी और सफल हमलों को उजागर करता है, जो युवाओं में उत्साह और प्रेरणा पैदा करता है। ये सामग्रियाँ हमलों की घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती हैं, ताकि संभावित भर्तियों में संगठन की शक्ति की छवि बने। प्रचार में पारंपरिक माध्यमों जैसे पत्रों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सामुदायिक सभाओं का भी उपयोग होता है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध होते हैं, जहाँ इंटरनेट की पहुंच सीमित है। संगठन शहीदों की कहानियों और उनके बलिदान को केंद्र में रखकर भावनात्मक अपील करता है, जो स्थानीय समुदायों में सहानुभूति और समर्थन जगाता है। यह प्रचार न केवल नई भर्तियों

को प्रोत्साहित करता है बल्कि मौजूदा सदस्यों का मनोबल ऊँचा रखता है, जिससे उनकी प्रतिबद्धता और दक्षता बढ़ती है। प्रचार अभियान में छद्म नामों और फ्रंट संगठनों का उपयोग किया जाता है, जो संगठन को निगरानी से बचाता है और उसके संदेशों को व्यापक बनाता है।

मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीति हिजबुल मुजाहिदीन में विरोधी ताकतों को कमजोर करने और स्थानीय जनमानस को प्रभावित करने पर आधारित है, जहाँ प्रचार के माध्यम से डर, अविश्वास और विभाजन का वातावरण बनाया जाता है। संगठन भारतीय सुरक्षा बलों और राज्य को दमनकारी और अन्यायपूर्ण के रूप में चित्रित करता है, जो जनता में असंतोष को बढ़ावा देता है और संगठन को प्रतिरोध का प्रतीक बनाता है। कार्यक्रमों और स्मृति सभाओं में शहीदों को सम्मानित करके संगठन अपनी सकारात्मक छवि बनाता है, जो समुदायों में उसके समर्थन को मजबूत करता है और परिवारों को भावनात्मक रूप से बांधता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर, यह युद्ध सुरक्षा बलों को थकाने और उनकी रणनीतियों को प्रभावित करने का प्रयास है, जहाँ निरंतर प्रचार से तनाव और अनिश्चितता उत्पन्न होती है। संगठन आर्थिक सहायता और सामाजिक समर्थन के माध्यम से परिवारों को अपने पक्ष में करता है, जो नए सदस्यों को प्रेरित करता है और संगठन की सामाजिक जड़ों को गहरा बनाता है। यह रणनीति लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव पैदा करती है, क्योंकि यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि आंतरिक मानसिकता को लक्षित करती है, जो कश्मीर के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती है।

ये प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध की तकनीकें हिजबुल मुजाहिदीन को एक शक्तिशाली और लचीला संगठन बनाती हैं, जो उसके संचालन और अस्तित्व को बनाए रखती हैं। माध्यमों का विविध उपयोग संगठन को व्यापक पहुंच और प्रभाव प्रदान करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक पहलू विरोधियों को कमजोर बनाता है और समर्थकों को मजबूत करता है। यह संयोजन संगठन की दीर्घायु सुनिश्चित करता है, क्योंकि प्रचार न केवल बाहरी छवि बनाता है बल्कि आंतरिक एकजुटता और वैचारिक मजबूती भी प्रदान करता है। हालांकि मीडिया निगरानी और काउंटर-प्रचार जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन संगठन की रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता इन्हें प्रभावी रखती है, जिससे इसका प्रभाव कश्मीर में निरंतर बना रहता है। अंततः, ये रणनीतियाँ संघर्ष को जटिल बनाती हैं, क्योंकि वे विचारों और भावनाओं के स्तर पर काम करती हैं, जो शांति प्रयासों को बाधित करती हैं और क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती देती हैं।

रणनीतिक संरेखण और क्षेत्रीय प्रभाव

हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा और उसके अभियान पाकिस्तान की रणनीतिक नीतियों से इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि यह संगठन पाकिस्तान के लिए एक प्रभावी छद्म युद्ध का माध्यम बन जाता है, जिसका उद्देश्य भारत को बिना सीधे सैन्य टकराव के कमजोर करना है। यह संरेखण पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीति का हिस्सा है, जहां कश्मीर को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है और हिजबुल मुजाहिदीन को आईएसआई के कथित समर्थन से मजबूत किया जाता है। इस संरेखण के माध्यम से संगठन को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं, जो भारत में स्थायी अस्थिरता पैदा करने में मदद करते हैं। कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करके पाकिस्तान अपने दावों को मजबूत करता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को वैध ठहराता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में शिकायतें दाखिल करके। यह रणनीतिक मेल पाकिस्तान में राज्य स्तर पर संगठन के प्रति सहनशीलता उत्पन्न करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान में खुलेआम कार्य करता रहता है। इस संरेखण का परिणाम भारत-पाकिस्तान संबंधों में बार-बार तनाव के रूप में सामने आता है, जो क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करता है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों को बाधित करता है। संगठन की इस भूमिका से पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है, क्योंकि यह भारत की संसाधनों को कश्मीर में बांधे रखता है और उसकी आर्थिक व सैन्य क्षमता को कमजोर करता है।

हिजबुल मुजाहिदीन का इस्लामी राज्य स्थापित करने और कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कराने का लक्ष्य धार्मिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों का एक अनोखा सम्मिलन है, जो पाकिस्तान की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से पूरी तरह मेल खाता है। संगठन की भर्ती और प्रचार रणनीतियाँ स्थानीय असंतोष को हथियार बनाती हैं, जैसे बेरोजगारी और राजनीतिक उपेक्षा को जिहादी कथानकों से जोड़कर युवाओं को आकर्षित करना। यह संरेखण पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर प्रदान करता है, जहां संगठन की गतिविधियाँ पाकिस्तान के दावों को मजबूती देती हैं। आईएसआई के कथित समर्थन से संगठन नए मोर्चों जैसे 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के तहत कार्य करता है, जो भारत की कूटनीतिक सफलताओं को चुनौती देता है। इस संरेखण का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर दिखाई देता है, जहां यह दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है और पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास

को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की 'हजार जख्म' नीति से प्रेरित यह दृष्टिकोण संगठन को लंबे समय तक जीवित रखता है, क्योंकि यह केवल सैन्य नहीं बल्कि विचारधारात्मक और कूटनीतिक स्तर पर भी कार्य करता है। इससे संगठन की क्षमता बढ़ती है और यह भारत के लिए एक सतत खतरा बना रहता है, जो क्षेत्र की स्थिरता को लगातार चुनौती देता है।

इस रणनीतिक संरक्षण का क्षेत्रीय प्रभाव केवल सैन्य संघर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियाँ कश्मीर में पर्यटन, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास को बाधित करती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और जनता में असंतोष बढ़ता है। यह संरक्षण अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है, जैसे प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव, लेकिन अंतर्निहित समर्थन संरचनाओं को नष्ट करने में असफल रहता है। संगठन की निरंतरता से मानवीय मुद्दे जैसे विस्थापन और मानवाधिकार उल्लंघन बढ़ते हैं, जो पड़ोसी देशों के संबंधों को तनावपूर्ण बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ यह मेल संगठन को एक रणनीतिक खिलाड़ी बनाता है, जो संघर्ष को लंबा खींचता है और शांति पहलों को जटिल बनाता है। इससे दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण बाधित होता है और क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएँ कमजोर पड़ती हैं। अंततः, यह संरक्षण एक चक्रव्यूह रचना है, जहां मिलिटेंसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता में अंतर्निहित हो जाती है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

नेटवर्क और रणनीतिक गठबंधन

हिजबुल मुजाहिदीन के विस्तृत नेटवर्क क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए एक जटिल सहायता प्रणाली का निर्माण करते हैं, जो संगठन की संचालन क्षमता और लचीलापन को बढ़ाते हैं। ये नेटवर्क स्थानीय समर्थकों से लेकर विदेशी प्रवासी समुदायों तक फैले हुए हैं, जो वित्तीय सहायता, भर्ती और प्रचार गतिविधियों को सुगम बनाते हैं। सीमा क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएँ इन नेटवर्कों का केंद्र हैं, जहां रंगरूटों को गुरिल्ला युद्ध और वैचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे संगठन को निरंतर मानव संसाधन मिलते रहते हैं। इन नेटवर्कों में खुफिया जानकारी और संसाधनों का आदान-प्रदान होता है, जो समन्वित कार्रवाइयों को संभव बनाता है। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ संबंध संगठन को सामाजिक जड़ें प्रदान करते हैं, जिससे

इसे उन्मूलन प्रयासों से बचना आसान हो जाता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण संगठन को विकसित खतरों से अनुकूलित होने की क्षमता देता है, जैसे बढ़ती निगरानी के बीच संचार चैनलों का विविधीकरण और संचालन आधारों का विस्तार।

रणनीतिक गठबंधन हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो वैचारिक समानता या साझा हितों वाली संस्थाओं के साथ साझेदारी बनाते हैं। ये गठबंधन मिशनों की योजना और निष्पादन में संयुक्त उद्यम शामिल करते हैं, जहां प्रत्येक समूह अपनी विशेषज्ञता का योगदान देता है, जैसे विशेष लड़ाके या खुफिया संपत्तियाँ। संसाधनों का साझा उपयोग, जैसे हथियार अधिग्रहण और वित्तीय हस्तांतरण, संगठन की क्षमताओं को स्वतंत्र साधनों से परे बढ़ाता है। ये गठबंधन व्यावहारिक होते हैं, जो सिद्धांतिक मतभेदों को नजरअंदाज कर सामरिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार या प्रचार की पहुंच। इन कनेक्शनों से हिजबुल मुजाहिदीन उन्नत पद्धतियों और वैश्विक कथानकों तक पहुँच प्राप्त करता है, जो इसे क्षेत्रीय विद्रोही से व्यापक मिलिटेंट पारिस्थितिकी में एक खिलाड़ी बनाता है। यह अंतर्संबंध अलगाव के खिलाफ एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि संबद्ध समर्थन दबाव की अवधियों में वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है। नेटवर्क और गठबंधनों का अंतर्क्रिया हिजबुल मुजाहिदीन की अनुकूलनशीलता को रेखांकित करता है, जो जटिल भू-राजनीतिक क्षेत्रों में नेविगेट करने की अनुमति देता है जबकि अपने उद्देश्यों का पीछा करता है। ये तत्व एक मजबूत ढांचा बनाते हैं जो व्यवधानों का सामना करता है, विविध चैनलों और सहयोगी प्रयासों के माध्यम से पुनर्जीवित होता है। गठबंधन न केवल तत्काल संचालन लाभ प्रदान करते हैं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देते हैं, समान विचारधारा वाले गुटों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देकर। हालांकि, यह वेब कमजोरियाँ भी उजागर करता है, क्योंकि प्रमुख नोड्स को लक्षित करने से संरचना पर कैस्केड प्रभाव पड़ सकता है। इन जोखिमों के बावजूद, इन नेटवर्कों द्वारा प्रदान की गई रणनीतिक गहराई सुनिश्चित करती है कि हिजबुल मुजाहिदीन एक दुर्जेय इकाई बनी रहे, जो अपनी प्राथमिक गतिविधि क्षेत्र से परे गतिशीलताओं को प्रभावित करने में सक्षम है। यह विन्यास न केवल समूह बल्कि इसे बनाए रखने वाली व्यापक पारिस्थितिकी को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की महत्वपूर्णता को उजागर करता है।

अन्य मिलिटेंट संगठनों के साथ सहयोग

हिजबुल मुजाहिदीन के अन्य मिलिटेंट संगठनों के साथ सहयोग एक सोची-समझी कोशिश है, जो ताकतों को एकत्रित करने और प्रभाव बढ़ाने के लिए साझा अभियानों के माध्यम से होता है, जो साझा दुश्मनों को लक्षित करते हैं। ये साझेदारियाँ उच्च-प्रोफाइल कार्रवाइयों में समन्वयन शामिल करती हैं, जहां प्रत्येक समूह अद्वितीय संपत्तियों का योगदान देता है, जैसे विशेष लड़ाके या खुफिया संपत्तियाँ। साझा कौशलों वाले संस्थाओं के साथ जुड़कर हिजबुल मुजाहिदीन अपनी हमले की क्षमताओं को बढ़ाता है, ऐसे परिणाम प्राप्त करता है जो स्वतंत्र रूप से असंभव हो सकते हैं। ये सहयोग आमतौर पर अनौपचारिक समझौतों द्वारा शासित होते हैं जो संचालन तालमेल पर केंद्रित होते हैं, कठोर पदानुक्रमों के बिना लचीली भागीदारी की अनुमति देते हैं। संयुक्त प्रयास जोखिमों को वितरित करते हैं, क्योंकि विविध भागीदारी विरोधियों से आरोपण और प्रतिक्रिया को जटिल बनाती है। इन अंतर्क्रियाओं से हिजबुल मुजाहिदीन व्यापक भर्ती पूलों और वैचारिक सुदृढ़ीकरण तक पहुँच प्राप्त करता है, मिलिटेंट परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत करता है।

इन सहयोगों की प्रकृति अक्सर वैचारिक सीमाओं को पार करती है, सिद्धांतिक शुद्धता पर व्यावहारिक लाभों को प्राथमिकता देकर साझा एजेंडों को आगे बढ़ाती है। ऐसे व्यवस्थाओं में, हिजबुल मुजाहिदीन बचाव रणनीतियों और संसाधन प्रबंधन पर ज्ञान का आदान-प्रदान करता है, विविध संघर्ष क्षेत्रों में भागीदारों के अनुभवों से लाभान्वित होता है। ये साझेदारियाँ सामग्री और विशेषज्ञता के प्रवाह को सुगम बनाती हैं, विद्रोह के लिए अधिक परिष्कृत दृष्टिकोणों को सक्षम करती हैं। सहयोग प्रचार प्रयासों को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि एकीकृत संदेशवाहन एकजुटता का मोर्चा प्रस्तुत करता है जो विरोधियों को डराता है और समर्थकों को प्रेरित करता है। प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न कभी-कभी घर्षणों के बावजूद, ये गठबंधन पारस्परिकता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जहां एक क्षेत्र में सफलताएँ सामूहिक कदम को मजबूत करती हैं। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट क्षेत्र में बदलते गठबंधनों के बीच प्रासंगिक बना रहे।

अंततः, अन्य मिलिटेंट संगठनों के साथ सहयोग हिजबुल मुजाहिदीन की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करते हैं, इसकी गतिविधियों और लचीलापन पर गुणक प्रभाव पैदा करते हैं। ये साझेदारियाँ न केवल तत्काल सामरिक लाभ बढ़ाती हैं बल्कि निरंतरता

में योगदान देती हैं, समान विचारधारा वाले गुटों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देकर। हालांकि, ये सहयोग कमजोरियाँ भी उजागर करते हैं, क्योंकि प्रमुख कड़ियों को लक्षित करने से व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इन जोखिमों के बावजूद, इन साझेदारियों द्वारा प्रदान की गई गहराई संगठन को एक शक्तिशाली इकाई बनाए रखती है, जो अपनी प्राथमिक क्षेत्र से परे प्रभाव डालने में सक्षम है। यह विन्यास मिलिटेंट पारिस्थितिकी में अंतर्संबंधों की जटिलता को उजागर करता है, जहां सहयोग संघर्ष की गतिशीलता को आकार देता है।

पाकिस्तानी राज्य एजेंसियों से संबंध

हिजबुल मुजाहिदीन का पाकिस्तान, विशेष रूप से इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ संबंध इसकी स्थापना से ही एक मजबूत और निरंतर बंधन रहा है, जो संगठन की संचालन क्षमता का मुख्य आधार बनता है। भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार, आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की है, बल्कि हथियारों की आपूर्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संचालन की रणनीतियों का भी प्रबंधन किया है। संगठन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का मुख्यालय पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद में स्थित है, जहां से वह आईएसआई और अन्य पाकिस्तानी संस्थाओं के साथ सीधा समन्वय करता है। यह संबंध पाकिस्तान की कश्मीर नीति का हिस्सा है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का एक प्रभावी उपकरण बनाया गया है। आईएसआई के समर्थन से संगठन ने पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में कई प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं, जहां रंगरूटों को गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सिखाई जाती हैं। यह सहयोग संगठन को स्थानीय स्तर पर मजबूत बनाता है और भारत की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाता है, क्योंकि यह राज्य स्तर का संरक्षण प्रदान करता है जो अंतरराष्ट्रीय दबावों से परे रहता है।

इस संबंध की शुरुआत 1989 में हुई, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में इस्लामी उग्रवाद को बढ़ावा देने का फैसला किया और हिजबुल मुजाहिदीन को अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाया। जमात-ए-इस्लामी की सैन्य शाखा होने के कारण, संगठन पाकिस्तान के लिए एक प्राकृतिक साझेदार बन गया, जिसने आईएसआई को इसका उपयोग करने की अनुमति दी। आईएसआई के सहयोग से हिजबुल मुजाहिदीन को आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराए गए, जो

इसके अभियानों की दक्षता बढ़ाते हैं। संगठन के पास सक्रिय लड़ाकों की संख्या इस समर्थन का प्रमाण है, जो इसके संचालन की व्यापकता को दर्शाती है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों का लगातार खंडन करता रहा है, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन की निरंतर सक्रियता और क्षमता राज्य स्तर के संरक्षण की ओर इशारा करती है। यह संबंध न केवल सैन्य सहायता तक सीमित है बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी कार्य करता है, जहां पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने के लिए संगठन का उपयोग करता है। इससे संगठन की वैधता बढ़ती है और भारत के खिलाफ एक सतत दबाव बनता है।

ये संबंध हिजबुल मुजाहिदीन को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं, जो इसे अन्य उग्रवादी समूहों से अलग करता है। आईएसआई के माध्यम से प्राप्त समर्थन संगठन को पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है, जहां प्रशिक्षण और योजना निर्बाध रूप से होती है। यह सहयोग संगठन की लचीलापन को बढ़ाता है, क्योंकि राज्य एजेंसियाँ न केवल संसाधन प्रदान करती हैं बल्कि खुफिया जानकारी भी साझा करती हैं। पाकिस्तान की नीति में हिजबुल मुजाहिदीन एक महत्वपूर्ण घटक है, जो भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने का कार्य करता है। इस संबंध का प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है, क्योंकि यह सीमा पर तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देता है। संगठन की सफलता इसी संरक्षण पर निर्भर है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाता है और लंबे समय तक जीवित रखता है। अंततः, ये संबंध दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रभावित करते हैं, जहां राज्य प्रायोजन मिलिटेंसी को एक जटिल समस्या बनाता है।

अंतरराष्ट्रीय संपर्क और सहयोग

हिजबुल मुजाहिदीन की मुख्य गतिविधियाँ कश्मीर तक सीमित होने के बावजूद, इसका अंतरराष्ट्रीय संपर्क कुछ हद तक रहा है, विशेष रूप से 1990 के दशक में अफगान गृहयुद्ध के दौरान। इस अवधि में संगठन ने 'हिज्ब-ए-इस्लामी गुलबुदीन' के साथ प्रशिक्षण सहयोग स्थापित किया, जो अफगानिस्तान में सक्रिय एक उग्रवादी समूह था। हालांकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह सहयोग समाप्त हो गया, लेकिन इससे हिजबुल मुजाहिदीन की रणनीतियों और विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। अन्य वैश्विक जिहादी नेटवर्कों की तुलना में, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, संगठन का अंतरराष्ट्रीय संपर्क अपेक्षाकृत सीमित रहा है, लेकिन पाकिस्तान

की राज्य एजेंसियों और कश्मीरी उग्रवादी समूहों के साथ मजबूत गठबंधन ने इसे पर्याप्त समर्थन प्रदान किया है। इन संपर्कों ने संगठन को हथियार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया, जिससे विद्रोह को निरंतर बनाए रखना संभव हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन संपर्कों ने संगठन को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर दिया, जो इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाता है।

ये अंतरराष्ट्रीय संपर्क हिजबुल मुजाहिदीन को वैश्विक जिहादी आंदोलनों से जोड़ते हैं, हालांकि सीमित रूप में, जो संगठन की रणनीतियों को समृद्ध करते हैं। अफगानिस्तान के साथ सहयोग ने संगठन को गुरिल्ला युद्ध की नई तकनीकें सिखाईं, जो कश्मीर में लागू की गईं। पाकिस्तान की एजेंसियों के माध्यम से ये संपर्क मजबूत हुए, जो संगठन को अंतरराष्ट्रीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। हालांकि वैश्विक नेटवर्क सीमित है, लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय गठबंधनों ने इसे एक प्रमुख आतंकवादी संगठन बनाए रखा है। इन संपर्कों का लाभ संगठन को प्रचार और भर्ती में मिलता है, जहां वैश्विक मुस्लिम समुदायों से समर्थन प्राप्त होता है। यह सहयोग संगठन की लचीलापन को बढ़ाता है और भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। इससे संगठन की विचारधारा वैश्विक जिहाद से जुड़ती है, जो इसके प्रभाव को विस्तारित करता है।

अंतरराष्ट्रीय संपर्क हिजबुल मुजाहिदीन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जो इसके संचालन को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ये संपर्क न केवल सैन्य सहायता तक सीमित हैं बल्कि वैचारिक आदान-प्रदान भी शामिल करते हैं, जो संगठन की रणनीतियों को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान की भूमिका इन संपर्कों को सुगम बनाती है, जो संगठन को वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज उठाने की अनुमति देती है। हालांकि सीमित, ये संपर्क संगठन की जीवटता का कारण हैं, क्योंकि वे विविध स्रोतों से समर्थन सुनिश्चित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये संबंध भारत-पाकिस्तान संघर्ष को जटिल बनाते हैं, जहां मिलिटेंसी वैश्विक आयाम ग्रहण करती है। संगठन की सफलता इसी नेटवर्क पर निर्भर है, जो इसे उन्मूलन प्रयासों से बचाता है और लंबे समय तक सक्रिय रखता है। अंततः, ये संपर्क क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती देते हैं और शांति प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं।

वर्तमान स्थिति और प्रभाव

हाल के वर्षों में हिजबुल मुजाहिदीन ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के साथ अपने गठबंधनों को बनाए रखा है, हालांकि संसाधनों, प्रभाव क्षेत्र और नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा भी जारी रही है। संगठन की स्थानीय स्तर पर भर्ती केंद्रित रणनीति और कश्मीरी युवाओं की भागीदारी ने इसके क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत रखा है, जो इसे अन्य बाहरी गुटों से अलग करती है। इसकी गतिविधियाँ उग्रवादी समूहों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमात-ए-इस्लामी जैसे राजनीतिक संगठनों और पाकिस्तानी राज्य एजेंसियों का गहरा प्रभाव शामिल है। यह बहुआयामी नेटवर्क संगठन को भारत के खिलाफ लगातार सक्रिय रखता है, जहां समन्वित अभियान सालाना सैकड़ों होते हैं। संगठन की वर्तमान स्थिति मजबूत है, क्योंकि यह अनुकूलनशील रणनीतियों से सुरक्षा अभियानों का सामना करता है। इससे कश्मीर संघर्ष में इसकी भूमिका प्रमुख बनी हुई है, जो क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है।

संगठन के गठबंधन और नेटवर्क इसे सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाते हैं, साथ ही विचारधारात्मक और रणनीतिक संरचना प्रदान करते हैं, जो इसके दीर्घकालिक संचालन को सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में हिजबुल मुजाहिदीन संयुक्त अभियानों में सक्रिय है, जो इसके समन्वय और कार्यक्षमता को दर्शाते हैं। ये नेटवर्क संगठन की अस्तित्व की नींव हैं, जो राजनीतिक उद्देश्यों को बनाए रखते हैं और भारत के लिए चुनौती बने रहते हैं। संगठन की स्थिति में लचीलापन है, क्योंकि यह नए मोर्चों के तहत कार्य करता है और स्थानीय समर्थन का दोहन करता है। इससे कश्मीर में संघर्ष की जटिलता बढ़ती है, जहां मिलिटेंसी सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई है। वर्तमान प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है, जो शांति प्रयासों को बाधित करता है और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करता है।

हिजबुल मुजाहिदीन की वर्तमान स्थिति इसके गठबंधनों पर टिकी है, जो समर्थन प्रणालियों से संगठन को मजबूत बनाते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं। ये संबंध संगठन को वैचारिक मजबूती प्रदान करते हैं, जो कश्मीर संघर्ष में इसकी प्रमुख भूमिका को रेखांकित करते हैं। वर्तमान में संगठन की सक्रियता संयुक्त अभियानों से स्पष्ट है, जो इसके प्रभाव का स्तर दिखाती है। ये नेटवर्क दीर्घकालिक संचालन के लिए निर्णायक हैं, क्योंकि वे विविध स्रोतों से संसाधन सुनिश्चित करते हैं। संगठन की

स्थिति अनुकूलनशील है, जो सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती है और स्थानीय युवाओं को आकर्षित करती है। इससे क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ता है, जो भारत-पाकिस्तान संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है और संघर्ष को लंबा खींचता है। अंततः, ये कारक संगठन को एक सतत खतरा बनाते हैं, जो क्षेत्र की शांति के लिए बाधक हैं।

हिजबुल मुजाहिदीन: वित्तपोषण के जटिल तरीके

हिजबुल मुजाहिदीन अपने आतंकवादी अभियानों को संचालित करने और संगठन को जीवित रखने के लिए विभिन्न जटिल तथा गोपनीय वित्तीय स्रोतों पर निर्भर करता है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों तथा आतंकवाद-विरोधी प्रयासों के बावजूद इसकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इन तरीकों में पाकिस्तान से प्राप्त कथित राज्य प्रायोजन प्रमुख है, जो संगठन को बड़े पैमाने पर धन उपलब्ध कराता है, साथ ही हवाला जैसे अनौपचारिक चैनलों का उपयोग किया जाता है जो धन के हस्तांतरण को ट्रेस करना मुश्किल बनाता है। इसके अलावा, ट्रस्ट और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से धन संचरण होता है, जो धर्मार्थ कार्यों की आड़ में आतंकवाद को फंडिंग प्रदान करते हैं। स्थानीय तथा बाहरी चंदे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां धार्मिक भावनाओं और सहानुभूति का दोहन किया जाता है। अंत में, अवैध गतिविधियाँ जैसे मादक पदार्थों की तस्करी और फिरौती वसूली से प्राप्त आय संगठन के लिए एक स्थायी स्रोत बनती है। ये सभी तरीके मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन को वित्तीय रूप से मजबूत रखते हैं, जिससे यह अपनी गतिविधियों को बिना रुकावट जारी रख पाता है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है।

ये वित्तपोषण के तरीके संगठन की रणनीतिक चतुराई को उजागर करते हैं, जहां प्रत्येक स्रोत को गोपनीयता और विविधता के साथ संयोजित किया जाता है ताकि किसी एक चैनल के बंद होने पर दूसरा सक्रिय रहे। पाकिस्तान से राज्य प्रायोजन आईएसआई के माध्यम से आता है, जो न केवल धन बल्कि लॉजिस्टिक समर्थन भी प्रदान करता है, जिससे संगठन कश्मीर में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। हवाला प्रणाली का उपयोग धन को बिना बैंकिंग ट्रेल के स्थानांतरित करने में सहायक है, जो खाड़ी देशों और अन्य क्षेत्रों से जुड़े नेटवर्कों पर आधारित है। ट्रस्ट और एनजीओ धर्मार्थ मुखौटे के पीछे छिपकर धन जुटाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच से बचते हैं। स्थानीय चंदे कश्मीर की जनता से आते हैं, जबकि बाहरी चंदे प्रवासी समुदायों से, जो प्रचार सामग्री से प्रभावित होते हैं। अवैध स्रोत जैसे नकली मुद्रा और तस्करी से प्राप्त आय

संगठन को अतिरिक्त ताकत देती है, हालांकि ये जोखिमपूर्ण हैं। इस विविधता से संगठन की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है, जो इसके दीर्घकालिक अस्तित्व का आधार है।

इन वित्तपोषण तरीकों का संयोजन हिजबुल मुजाहिदीन को एक लचीली आर्थिक संरचना प्रदान करता है, जो वैश्विक दबावों का सामना करने में सक्षम है। राज्य प्रायोजन पाकिस्तान की रणनीतिक नीतियों से जुड़ा है, जो संगठन को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करता है। हवाला और अनौपचारिक बैंकिंग धन के गुप्त प्रवाह को संभव बनाते हैं, जो जांच एजेंसियों को चकमा देते हैं। ट्रस्ट तथा एनजीओ परोपकारी आवरण का लाभ उठाते हैं, जो धन को वैध दिखाते हैं। चंदे धार्मिक और भावनात्मक अपील पर आधारित हैं, जो समुदायों से निरंतर सहायता सुनिश्चित करते हैं। अवैध गतिविधियाँ जैसे अपराध संगठन को स्वतंत्र आय प्रदान करते हैं, जो अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करते हैं। ये सभी तत्व मिलकर संगठन की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत बनाते हैं, जिससे यह आतंकवाद-विरोधी अभियानों के बावजूद अपनी गति बनाए रखता है और क्षेत्रीय सुरक्षा को लगातार चुनौती देता है।

राज्य प्रायोजन और आईएसआई का कथित सहयोग

हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान से प्राप्त राज्य प्रायोजन सबसे बड़ा और सतत आर्थिक समर्थन माना जाता है, जिसमें इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की भूमिका केंद्रीय है। भारत और अन्य राष्ट्रों के अनुसार, आईएसआई संगठन को वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण, हथियार और लॉजिस्टिक संसाधन प्रदान करती है, ताकि यह कश्मीर में भारत के विरुद्ध एक प्रभावी प्रॉक्सी की भूमिका निभा सके। यह सहयोग 1989 में संगठन के गठन के साथ आरंभ हुआ, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में इस्लामी चरमपंथ को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। जमात-ए-इस्लामी की सैन्य शाखा होने से हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की रणनीतिक प्राथमिकताओं से मेल खाता था, जिसने इसे आईएसआई का पसंदीदा भागीदार बनाया। पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में प्रशिक्षण शिविरों और संचालन केंद्रों का रखरखाव इसी समर्थन से संभव होता है, जो संगठन को मजबूत आधार प्रदान करता है। हालांकि पाकिस्तान इन आरोपों का खंडन करता है, लेकिन संगठन की निरंतर गतिविधियाँ राज्य स्तर के संरक्षण की पुष्टि करती हैं।

इस प्रायोजन का स्वरूप बहुआयामी है, जहां आईएसआई न केवल धन प्रदान करती है बल्कि रणनीतिक मार्गदर्शन भी देती है, जो संगठन के अभियानों को प्रभावी बनाता है। अनुमानों के अनुसार, संगठन को मासिक आधार पर बड़ी रकम मिलती है, जो हवाला चैनलों के माध्यम से वितरित होती है ताकि बैंकिंग निगरानी से बचा जा सके। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त संपत्तियाँ इस सहयोग के प्रमाण हैं, जो आईएसआई के संरक्षण में संचालित होती हैं। यह प्रायोजन पाकिस्तान की 'छद्म युद्ध' नीति का हिस्सा है, जो भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने का लक्ष्य रखती है। संगठन की क्षमताएँ इसी समर्थन से बढ़ती हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से ऊपर उठाता है। इससे पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर लाभ मिलता है, जबकि संगठन अपनी वैचारिक लड़ाई जारी रखता है। यह सहयोग क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा देता है और शांति प्रक्रियाओं को जटिल बनाता है। राज्य प्रायोजन हिजबुल मुजाहिदीन को एक राज्य-समर्थित इकाई की ताकत प्रदान करता है, जो आईएसआई के माध्यम से विभिन्न संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यह सहयोग संगठन के गठन से जुड़ा है, जहां पाकिस्तान ने इसे अपनी विदेश नीति का उपकरण बनाया। वित्तीय सहायता के अलावा, प्रशिक्षण और हथियार संगठन की युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कश्मीर में सतत उपस्थिति बनाए रखते हैं। जब्ती अभियान इस प्रायोजन के पैमाने को उजागर करते हैं, जो गोपनीय चैनलों पर आधारित है। पाकिस्तान का खंडन संगठन की सक्रियता से विपरीत है, जो राज्य संरक्षण की ओर इशारा करता है। यह प्रायोजन संगठन को वैश्विक दबावों से बचाता है और भारत के लिए एक सतत चुनौती बनता है। इससे दक्षिण एशिया की भू-राजनीति प्रभावित होती है, जहां प्रायोजित मिलिटेंसी संघर्ष को लंबा खींचती है।

हवाला लेनदेन और अनौपचारिक बैंकिंग

हिजबुल मुजाहिदीन हवाला प्रणाली का व्यापक उपयोग करता है, जो एक अनौपचारिक धन हस्तांतरण तंत्र है जिसमें नकद का भौतिक स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि एक गुप्त नेटवर्क के जरिए धन विभिन्न देशों में पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली पाकिस्तान तथा अन्य स्रोतों से जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों और उनके परिवारों तक धन पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। प्रवर्तन निदेशालय के मामलों से खुलासा हुआ है कि हवाला के साथ वस्तु विनिमय और मानव वाहकों का उपयोग धन भारत भेजने के लिए किया जाता है। खाड़ी देशों और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में

सक्रिय हवाला एजेंट इस प्रवाह को सुचारू रखते हैं, जो औपचारिक बैंकिंग से बचते हैं। गिरफ्तारियाँ इस नेटवर्क की मजबूती को दर्शाती हैं, जो संगठन को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए नियंत्रण मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता।

यह अनौपचारिक बैंकिंग प्रणाली हिजबुल मुजाहिदीन की गोपनीयता की कुंजी है, जो धन के स्रोतों को छिपाती है और जांच से बचाती है। हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से सालाना बड़ी रकम का लेनदेन होता है, जो संगठन के अभियानों को फंड करता है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एजेंट इस तंत्र को वैश्विक बनाते हैं, जहां धन का प्रवाह निर्बाध रहता है। गिरफ्तारियाँ नेटवर्क की गहराई को उजागर करती हैं, लेकिन इसका पुनर्निर्माण तेजी से होता है। यह प्रणाली संगठन को पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से अलग रखती है, जो खुफिया इकाइयों की पहुंच से बाहर है। इससे संगठन की संचालन क्षमता बढ़ती है और भारत के लिए वित्तीय चुनौती उत्पन्न होती है। हवाला का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले नेटवर्कों पर निर्भर है, जो मिलिटेंसी को मजबूत बनाता है।

हवाला और अनौपचारिक बैंकिंग हिजबुल मुजाहिदीन को एक छिपी हुई आर्थिक रीढ़ प्रदान करते हैं, जो धन के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हैं। यह तंत्र पाकिस्तान से धन को कश्मीर तक पहुंचाता है, जहां वस्तु विनिमय और अन्य माध्यमों का सहारा लिया जाता है। एजेंटों का वैश्विक जाल इस प्रणाली को मजबूत बनाता है, जो बैंकिंग निगरानी से मुक्त है। लेनदेन के पैमाने इसकी प्रभावशीलता को दिखाते हैं, जो संगठन के परिवारों तक सहायता पहुंचाते हैं। गिरफ्तारियाँ नेटवर्क को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसकी लचीलापन इसे पुनर्जीवित करता है। इससे संगठन वित्तीय दबावों से बचता है और अपनी गतिविधियों को जारी रखता है। यह प्रणाली मिलिटेंसी के वित्तपोषण की जटिलता को रेखांकित करती है, जो वैश्विक स्तर पर चुनौती है।

ट्रस्ट और एनजीओ के माध्यम से आतंकवादी फंडिंग

हिजबुल मुजाहिदीन धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का उपयोग करके धन इकट्ठा करने का आरोपित है, जो मानवीय सहायता की आड़ में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। भारत की प्रवर्तन निदेशालय ने 'जम्मू और कश्मीर प्रभावित राहत ट्रस्ट' (JKART) जैसे संगठनों को चिन्हित किया है, जो आईएसआई और पाकिस्तान आधारित संस्थाओं के साथ साझेदारी में कार्य करते हैं।

ये ट्रस्ट हवाला चैनलों, वस्तु विनिमय और मानव वाहकों के जरिए धन भारत पहुंचाते हैं, जहां इसे आतंकवादियों और उनके परिवारों के बीच बांटा जाता है। ऐसे संगठन धर्मार्थ कार्यों का दिखावा करके जांच से बचते हैं, जो संगठन की वित्तीय रणनीति को मजबूत बनाते हैं। अन्य ट्रस्ट भी इसमें शामिल हैं, जिनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं, जो फंडिंग के विस्तार को दर्शाती हैं। फ्रंट संगठन आतंकवाद को परोपकारी गतिविधियों के रूप में छिपाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती पेश करते हैं। इससे संगठन की क्षमता बढ़ती है और सुरक्षा प्रयासों को बाधित करती है। ट्रस्ट और एनजीओ हिजबुल मुजाहिदीन को वैधता का आवरण देते हैं, जहां धन संग्रह को राहत कार्यों से जोड़ा जाता है। JKART जैसे ट्रस्ट आईएसआई के साथ मिलकर धन जुटाते हैं, जो भारत में आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया गोपनीय चैनलों पर आधारित है, जो ट्रेसिंग को कठिन बनाती है। सालाना करोड़ों की रकम इन माध्यमों से आती है, जो अभियानों को फंड करती है। जब्त संपत्तियां इन संगठनों की भूमिका को प्रमाणित करती हैं, जो आतंकवाद का समर्थन करती हैं। फ्रंट संगठन मानवीय कार्यों से धन छिपाते हैं, जो जांच को भ्रमित करते हैं। यह दृष्टिकोण संगठन को वित्तीय स्वतंत्रता देता है और भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इससे मिलिटेंसी के वित्तपोषण की जटिलता बढ़ती है, जो वैश्विक समस्या बन गई है।

ये माध्यम हिजबुल मुजाहिदीन की वित्तीय रणनीति का अभिन्न अंग हैं, जो ट्रस्टों को धर्मार्थ छवि के साथ उपयोग करते हैं। ऐसे संगठन पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्कों के माध्यम से कार्य करते हैं, जो धन को गुप्त रूप से स्थानांतरित करते हैं। हवाला और अन्य तरीके इस प्रक्रिया को सुरक्षित बनाते हैं, जबकि वितरण आतंकवादियों तक पहुंचता है। फंडिंग का पैमाना बड़ा है, जो संगठन की दीर्घायु सुनिश्चित करता है। जांच एजेंसियां इन ट्रस्टों को लक्षित करती हैं, लेकिन उनकी संख्या और छिपाव चुनौतीपूर्ण है। फ्रंट संगठन अंतरराष्ट्रीय जांच से बचते हैं, जो संगठन की चतुराई दिखाते हैं। यह रणनीति वित्तीय विविधता प्रदान करती है, जो प्रतिबंधों से ऊपर उठाती है। इससे आतंकवाद का मुकाबला जटिल हो जाता है और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है।

स्थानीय और बाहरी चंदे

हिजबुल मुजाहिदीन को जम्मू-कश्मीर के स्थानीय समर्थकों से चंदे मिलते हैं, जो मस्जिदों, मदरसों और सामुदायिक नेटवर्कों से जुटाए जाते हैं, जहां धार्मिक भावनाओं और कश्मीर संघर्ष की सहानुभूति का दोहन होता है। संगठन की प्रोपेगेंडा मशीनरी

सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से इन चंदों को प्रेरित करती है, जो लाखों बार देखे जाते हैं। यूके और खाड़ी देशों के प्रवासी समुदाय बड़ी रकम प्रदान करते हैं, जो धार्मिक आयोजनों और 'कश्मीर दिवस' जैसे कार्यक्रमों से इकट्ठी की जाती है। इन चंदों के पीछे धार्मिक कट्टरता, जिहाद में भागीदारी और मुसलमानों के प्रति सहानुभूति प्रमुख कारक हैं, जो संगठन की विचारधारा को मजबूत बनाते हैं। इससे भावनात्मक और वैचारिक समर्थन मिलता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता प्रदान करता है। स्थानीय चंदे संगठन की जड़ों को गहरा करते हैं, जबकि बाहरी चंदे वैश्विक पहुंच बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया संगठन की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती है और सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाती है।

स्थानीय और बाहरी चंदे हिज्रबुल मुजाहिदीन की आर्थिक नींव हैं, जहां स्थानीय स्तर पर समुदायों से सहायता जुटाई जाती है। मस्जिदें और मदरसों चंदों के प्रमुख केंद्र हैं, जो संघर्ष की भावना से जुड़े होते हैं। प्रवासी समुदाय खाड़ी और यूरोप से धन भेजते हैं, जो प्रचार से प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम सालाना आधार पर आयोजित होते हैं, जो रकम इकट्ठा करते हैं। धार्मिक और सहानुभूति कारक इन स्रोतों को सक्रिय रखते हैं, जो संगठन के समर्थन को बढ़ाते हैं। इससे वित्तीय विविधता मिलती है, जो प्रतिबंधों से बचाती है। चंदे विचारधारा को फैलाते हैं, जो भर्ती और संचालन को सहायक बनाते हैं। यह मिलिटेंसी के वित्तपोषण की जटिलता को दर्शाता है, जो वैश्विक स्तर पर समस्या है।

ये चंदे हिज्रबुल मुजाहिदीन को समुदाय आधारित समर्थन प्रदान करते हैं, जहां स्थानीय और प्रवासी नेटवर्क प्रमुख हैं। सामुदायिक आयोजन धन संग्रह के माध्यम हैं, जो भावनात्मक अपील पर आधारित होते हैं। वीडियो और प्रचार इन समुदायों को जोड़ते हैं, जो सहायता देते हैं। सालाना कार्यक्रम रकम जुटाते हैं, जो संगठन की क्षमता बढ़ाते हैं। कट्टरता और सहानुभूति कारक चंदों को प्रेरित करते हैं, जो वैधता देते हैं। इससे संगठन की पहुंच वैश्विक हो जाती है, जो वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। स्थानीय चंदे जड़ें मजबूत करते हैं, जबकि बाहरी विविधता लाते हैं। यह प्रक्रिया जांच को चुनौती देती है और आतंकवाद को बनाए रखती है।

अवैध गतिविधियाँ और आपराधिक आय

हिज्रबुल मुजाहिदीन की आय में मादक पदार्थों की तस्करी प्रमुख है, जो हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों से करोड़ों की कमाई करती है। जब्ती अभियान इस गतिविधि के विस्तार को दिखाते हैं, जो संगठन के अभियानों को फंड करते हैं। नकली मुद्रा का

संचालन कराची से होता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाने के साथ आय उत्पन्न करता है। फिरौती वसूली स्थानीय व्यवसायों और नागरिकों से की जाती है, जो सालाना आधार पर आय प्रदान करती है। ये गतिविधियाँ जोखिमपूर्ण हैं, लेकिन सुरक्षा बलों के प्रयासों के बावजूद जारी रहती हैं। इससे संगठन की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ती है और मिलिटेंसी का अपराधिक पक्ष उजागर होता है। अवैध स्रोत वैध चैनलों से अलग हैं, जो जांच को जटिल बनाते हैं। यह रणनीति संगठन को मजबूत रखती है और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।

अपराधिक स्रोत हिजबुल मुजाहिदीन को वैकल्पिक आय देते हैं, जहां तस्करी मुख्य भूमिका निभाती है। हेरोइन की जब्ती अनुमानों से कमाई का पता चलाती है, जो दीर्घकालिक संचालन को समर्थन देती है। नकली मुद्रा दोहरे उद्देश्य पूरे करती है, जो पाकिस्तान से आती है। वसूली पाकिस्तान-प्रशासित क्षेत्रों में होती है, जो स्थानीय से जुड़ी है। जोखिम के बावजूद ये स्रोत स्थायी हैं, जो संगठन की जीवटता बढ़ाते हैं। इससे मिलिटेंसी और अपराध का मेल स्पष्ट होता है, जो वैश्विक समस्या है। अवैध आय अन्य स्रोतों पर निर्भरता कम करती है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है। यह प्रक्रिया उन्मूलन को कठिन बनाती है और संघर्ष को लंबा खींचती है। ये अवैध गतिविधियाँ हिजबुल मुजाहिदीन की वित्तीय रणनीति को विविध बनाती हैं, जहां मादक पदार्थ तस्करी प्रमुख है। जब्त हेरोइन की मात्रा कमाई के स्तर को दर्शाती है, जो अभियानों को गति देती है। नकली मुद्रा का उपयोग अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के साथ फंडिंग करता है। फिरौती स्थानीय व्यवसायों से जुटाई जाती है, जो निरंतर आय देती है। सुरक्षा बलों के निशाने पर होने के बावजूद ये जारी रहती हैं, जो संगठन की चतुराई दिखाती हैं। इससे वित्तपोषण की जटिलता बढ़ती है, जो जांच एजेंसियों के लिए चुनौती है। अपराधिक स्रोत संगठन को स्वतंत्र रखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर समस्या पैदा करते हैं। यह आय आतंकवाद को बनाए रखती है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालती है।

प्रतिबंधों का सामना, प्रतिरोध और वित्तीय अनुकूलन

हिजबुल मुजाहिदीन को विभिन्न देशों जैसे भारत, अमेरिका और कनाडा द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, जिससे इसकी वैश्विक वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास हुए हैं। अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप संगठन की संपत्तियाँ फ्रीज की गईं और

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई। भारत की प्रवर्तन निदेशालय ने संगठन से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति जब्त की, जो आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को लक्षित करती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिससे संगठन के प्रमुख के परिवार के सदस्य को गिरफ्तार किया गया। ये प्रतिबंध वित्तीय लेनदेन और नेटवर्कों को विफल करने का उद्देश्य रखते हैं, जो संगठन की क्षमता को सीमित करने के लिए आवश्यक हैं। इससे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की रणनीति मजबूत होती है, जो संगठन की गतिविधियों को प्रभावित करती है।

प्रतिबंधों के बावजूद हिजबुल मुजाहिदीन ने मजबूत प्रतिरोध दिखाया है, जहां वैकल्पिक मार्गों से धन जुटाना जारी रखा गया। हवाला लेनदेन और ट्रस्टों का उपयोग संगठन को प्रतिबंधों से बचाता है, जो वित्तीय निगरानी से परे कार्य करते हैं। गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से धन का संचरण गोपनीय रहता है, जो संगठन की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। ये प्रयास संगठन को अंतरराष्ट्रीय दबावों से ऊपर उठाते हैं, जहां विविध स्रोतों से आय सुनिश्चित होती है। प्रतिरोध की यह रणनीति संगठन की जीवटता को बनाए रखती है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इससे वित्तीय नेटवर्क की गहराई स्पष्ट होती है, जो समाप्त करने में कठिनाई पैदा करती है।

वित्तीय लचीलापन हिजबुल मुजाहिदीन की प्रमुख ताकत है, जहां संसाधनों को बहुआयामी बनाया गया है। प्रतिबंधों के बाद संगठन ने नए चैनलों का विकास किया, जो धन को लगातार बहने देते हैं। ये तरीके संगठन को अपनी गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति देते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को चुनौती देते हैं। वित्तीय ढांचे की विविधता संगठन की रणनीतिक बुद्धिमत्ता को दिखाती है, जो दबावों से अनुकूलित होती है। इससे संगठन की दीर्घायु सुनिश्चित होती है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। लचीलापन की यह क्षमता वित्तीय युद्ध में एक महत्वपूर्ण कारक है, जो उन्मूलन को जटिल बनाती है।

संचालन की रणनीतियाँ: गुरिल्ला युद्ध और स्लीपर सेल

हिजबुल मुजाहिदीन की संचालन रणनीतियाँ मुख्य रूप से गुरिल्ला युद्ध पर आधारित हैं, जो जम्मू-कश्मीर के दुर्गम इलाकों का लाभ उठाती हैं। संगठन छोटे समूहों में हमले करता है, जो तेज और अप्रत्याशित होते हैं, फिर दुर्गम क्षेत्रों में छिप जाता है। आईईडी,

एके-47 और आरपीजी जैसे हथियारों का उपयोग सेना के काफिलों पर घात लगाकर किया जाता है, जो मानसिक और रणनीतिक अस्थिरता पैदा करता है। यह रणनीति भौगोलिक संरचना जैसे पहाड़ों और जंगलों का उपयोग करती है, जो ट्रैकिंग को कठिन बनाती है। स्थानीय आबादी में घुल-मिलकर कार्य करना संगठन की शक्ति है, जो पहचान को मुश्किल करता है। इससे संगठन लंबे समय तक सक्रिय रहता है और भारत की सुरक्षा को चुनौती देता है।

स्लीपर सेल ऑपरेशन हिजबुल मुजाहिदीन की एक और प्रमुख रणनीति है, जहां सदस्य निष्क्रिय रहकर समाज में सामान्य जीवन जीते हैं। ये सेल आवश्यकता पर सक्रिय होकर लक्षित हमले करते हैं, जो सूचना संग्रह और निगरानी पर आधारित होते हैं। एन्क्रिप्टेड ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग निर्देशों के लिए किया जाता है, जो पाकिस्तान से आते हैं। शहरी इलाकों में ये सेल प्रभावी हैं, जहां भीड़ में छिपना आसान होता है। स्थानीय युवाओं को भर्ती करके प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सेल की क्षमता बढ़ाता है। इससे संगठन की अप्रत्याशितता बढ़ती है और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती उत्पन्न होती है।

ये रणनीतियाँ हिजबुल मुजाहिदीन को एक अनुकूलनीय संगठन बनाती हैं, जहां गुरिल्ला और स्लीपर सेल का मिश्रण संचालन को प्रभावी रखता है। भौगोलिक लाभ और स्थानीय एकीकरण संगठन की जीवटता का आधार हैं, जो दीर्घकालिक संघर्ष सुनिश्चित करते हैं। एन्क्रिप्टेड संचार और गुप्त नेटवर्क ट्रैकिंग को जटिल बनाते हैं, जो संगठन की रणनीतिक गहराई दिखाते हैं। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है और संघर्ष लंबा खिंचता है। संगठन की ये तरीके मिलिटेंसी की जटिलता को रेखांकित करते हैं, जो बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। रणनीतियों का अनुकूलन संगठन को जीवित रखता है और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है।

स्लीपर सेल संचालन की विशेषताएँ

स्लीपर सेल हिजबुल मुजाहिदीन की एक गोपनीय रणनीति है, जहां सदस्य लंबे समय तक निष्क्रिय रहकर समाज में एकीकृत हो जाते हैं। ये सेल स्कूल, कॉलेज या व्यापार में सक्रिय रहते हैं, जिससे संदेह उत्पन्न नहीं होता। आवश्यकता पर सक्रिय होकर हमले करते हैं, जो लक्षित हत्याओं और ग्रेनेड हमलों पर केंद्रित होते हैं। पाकिस्तान से एन्क्रिप्टेड निर्देश प्राप्त होते हैं, जो सेल की गोपनीयता बनाए रखते हैं। शहरी क्षेत्रों

में ये सेल भीड़ का लाभ उठाते हैं, जो छिपने को आसान बनाता है। स्थानीय युवाओं को भर्ती करके सेल मजबूत होते हैं, जो संगठन की पहुंच बढ़ाते हैं।

ये सेल सूचना संग्रह और निगरानी के कार्य भी करते हैं, जो सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर नजर रखते हैं। गुप्त स्थानों पर प्रशिक्षण और हथियार प्रदान किए जाते हैं, जो सेल की दक्षता बढ़ाते हैं। अप्रत्याशित सक्रियण सेल की ताकत है, जो हमलों को प्रभावी बनाता है। निष्क्रियता की अवधि सेल को पहचान से बचाती है, जो संगठन की रणनीतिक बुद्धिमत्ता दिखाती है। इससे सुरक्षा बलों के लिए उन्मूलन कठिन हो जाता है, क्योंकि सामान्य जीवन सेल को छिपाता है। सेल की यह प्रकृति मिलिटेंसी को जटिल बनाती है और क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती देती है। स्लीपर सेल हिज्रबुल मुजाहिदीन की लचीलापन का प्रतीक हैं, जो लंबे समय तक छिपकर कार्य करते हैं। ये सेल समाज में घुल-मिलकर संगठन की जड़ें गहरा करते हैं, जो भर्ती और संचालन को सहायक बनाते हैं। एन्क्रिप्टेड संचार सेल को सुरक्षित रखता है, जो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। लक्षित कार्रवाइयों सेल की विशेषता हैं, जो सूचना आधारित होती हैं। निष्क्रिय सदस्यों की पहचान चुनौतीपूर्ण है, जो संगठन की सफलता का आधार है। इससे संघर्ष की जटिलता बढ़ती है और सुरक्षा रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है।

आतंकवाद-विरोधी उपायों के प्रति अनुकूलन क्षमता

हिज्रबुल मुजाहिदीन ने भारतीय सुरक्षा बलों के कड़े अभियानों का सामना करने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित किया है, जैसे 'ऑपरेशन ऑल आउट' के दौरान बड़े हमलों से स्लीपर सेल और छोटे ऑपरेशनों पर स्थानांतरण। इससे संगठन सीधी टक्कर से बचता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग संचार को सुरक्षित बनाता है, जो खुफिया एजेंसियों की नजर से बचाता है। सीमापार घुसपैठ की बजाय स्थानीय भर्ती पर जोर संगठन की रणनीति बदलता है, जो जोखिम कम करता है। सुरक्षित घर और स्थानीय सहयोग संगठन को निगरानी से बचाते हैं, जो अनुकूलन की कुंजी हैं। इससे संगठन की ताकत बढ़ती है और अभियान जारी रहते हैं।

ये अनुकूलन संगठन को सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचे में एकीकृत करते हैं, जहां स्थानीय युवाओं का उपयोग संचालन को स्थानीय बनाता है। तकनीकी बदलाव जैसे

ऐप्स का उपयोग संगठन की बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, जो दबावों से ऊपर उठाते हैं। क्रॉस-बॉर्डर जोखिम कम करके संगठन अपनी उपस्थिति मजबूत करता है, जो दीर्घकालिक संघर्ष सुनिश्चित करता है। स्थानीय सहयोग और छिपने के स्थान संगठन की जीवटता का आधार हैं, जो सुरक्षा प्रयासों को चुनौती देते हैं। अनुकूलन की यह क्षमता मिलिटेंसी की जटिलता को रेखांकित करती है, जो बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करती है। इससे संगठन क्षेत्रीय सुरक्षा को लगातार प्रभावित करता है। हिजबुल मुजाहिदीन का अनुकूलन आतंकवाद-विरोधी उपायों के खिलाफ एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है, जहां रणनीतियों का बदलाव संगठन को जीवित रखता है। स्लीपर सेल पर जोर बड़े अभियानों से बचाता है, जो लचीलापन प्रदान करता है। संचार के नए माध्यम संगठन की गोपनीयता बढ़ाते हैं, जो निगरानी को भेदना मुश्किल बनाते हैं। स्थानीय भर्ती और नेटवर्क निर्माण संगठन की जड़ें गहरा करते हैं, जो सामाजिक एकीकरण को मजबूत बनाते हैं। तकनीकी और स्थानीय अनुकूलन संगठन की सफलता का आधार हैं, जो अभियानों को निरंतर बनाते हैं। इससे सुरक्षा बलों की रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है और संघर्ष जटिल हो जाता है।

सुरक्षा बलों की चुनौतियाँ

हिजबुल मुजाहिदीन की गुरिल्ला युद्ध रणनीति सुरक्षा बलों के लिए एक गहन चुनौती उत्पन्न करती है, क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के कठिन भूभाग का पूरा लाभ उठाती है, जैसे ऊँचे पर्वत, घने जंगल और ग्रामीण इलाके, जो आतंकवादियों को छिपने और हमलों के बाद भागने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह रणनीति सेना की गतिविधियों में बाधा डालती है, क्योंकि आतंकवादियों को ट्रैक करना और सीधे मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाता है, जिससे अभियानों की दक्षता कम होती है। स्लीपर सेल ऑपरेशन और भी जटिल समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि ये सदस्य समाज में सामान्य जीवन जीते हुए लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं और अचानक सक्रिय होकर लक्षित हमले करते हैं, जो खुफिया जानकारी की कमी को उजागर करते हैं। एन्क्रिप्टेड ऐप्स जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का उपयोग संदेशों को इंटरसेप्ट करने को कठिन बनाता है, जिससे नेटवर्क का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। छापेमारी अभियानों के बावजूद रणनीति की निरंतरता सुरक्षा बलों की रणनीतियों पर सवाल उठाती है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाती है। इससे नागरिक जीवन प्रभावित होता है और क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है।

सतत प्रभाव के रूप में, हिजबुल मुजाहिदीन की रणनीतियाँ स्थानीय समुदायों में भय और अविश्वास का माहौल बनाती हैं, जो सुरक्षा बलों को सहयोग से वंचित करता है और आतंकवादियों को शरण प्रदान करता है। यह सामाजिक अस्थिरता आतंकवाद-विरोधी अभियानों को जटिल बनाती है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा और आतंकवादियों की पहचान में संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध की नीति से संगठन विरोधियों को कमजोर बनाता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को लंबे समय तक प्रभावित करती है। संगठन की लचीलापन भारत के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है, जो केवल सैन्य कार्रवाई से समाप्त नहीं होता। खुफिया तंत्र, साइबर निगरानी और सामाजिक समावेशन की आवश्यकता है, जो युवाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करके आधार कमजोर करे। इससे संघर्ष की जड़ों को संबोधित करना जरूरी है, जो शांति प्रक्रिया को मजबूत बनाएगा।

हिजबुल मुजाहिदीन की रणनीतियाँ सुरक्षा बलों को बहुआयामी चुनौतियों से रूबरू कराती हैं, जहां गुरिल्ला और स्लीपर सेल का संयोजन अप्रत्याशित हमलों को संभव बनाता है। भौगोलिक जटिलता ट्रेकिंग को बाधित करती है, जबकि गोपनीय संचार नेटवर्क को छिपाता है, जो अभियानों की सफलता दर कम करती है। सतत प्रभाव सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, जहां भय का वातावरण सहयोग को रोकता है और नागरिकों को खतरे में डालता है। संगठन की अनुकूलन क्षमता दीर्घकालिक सुरक्षा समस्या पैदा करती है, जो सैन्य से परे समाधान मांगती है। साइबर और सामाजिक पहल युवाओं को मुख्यधारा से जोड़कर आधार कमजोर कर सकती हैं, जो संघर्ष समाप्ति की कुंजी है। इससे क्षेत्रीय शांति की संभावनाएँ बढ़ती हैं और अस्थिरता कम होती है।

हथियार और तकनीकी रणनीतियाँ: तस्करी आधारित हथियार और बुनियादी तकनीक

हिजबुल मुजाहिदीन की हथियार नीति मुख्य रूप से तस्करी पर निर्भर है, जो पाकिस्तान से सीमा पार लाए जाते हैं और संगठन की गुरिल्ला और स्लीपर सेल रणनीतियों को समर्थन देते हैं। एके-47 राइफल, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, आरपीजी और आईईडी जैसे हथियार नियंत्रण रेखा पार करके जंगलों, सुरंगों और ड्रोनों के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, जो संगठन की दक्षता बढ़ाते हैं। एके-47 की हल्की और उच्च फायरिंग क्षमता तेज हमलों में उपयोगी है, जबकि पिस्तौल निकट दूरी की हत्याओं के

लिए उपयुक्त है। हैंड ग्रेनेड और आरपीजी घात हमलों को प्रभावी बनाते हैं, जो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाते हैं। आईईडी स्थानीय सामग्री से बनाए जाते हैं, जो सड़क किनारे विस्फोटों के लिए सस्ता विकल्प हैं। तस्करी रैकेटों का नष्ट होना संगठन की आपूर्ति को प्रभावित करता है, लेकिन नेटवर्क की सक्रियता जारी रहती है।

तकनीकी रणनीतियाँ बुनियादी स्तर पर हैं, जहां एन्क्रिप्टेड ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का उपयोग संचार को गोपनीय रखता है, जो भारत में ऑपरेटिव और पाकिस्तान में हैंडलरों को जोड़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब का उपयोग प्रचार के लिए होता है, जो आतंकवाद का महिमामंडन और भर्ती को बढ़ावा देते हैं। वीडियो पोस्ट लाखों दर्शकों तक पहुंचते हैं, जो नफरत फैलाते हैं और शहीदों को नायक बनाते हैं। ड्रोन तकनीक का सीमित उपयोग तस्करी और निगरानी के लिए है, जो सीमा से हथियार और सामग्री लाते हैं। ये तकनीकें संगठन की सीमित संसाधनों में अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जो गुरिल्ला युद्ध को समर्थन देती हैं। इंटरसेप्ट किए संदेश नेटवर्क की गहराई दिखाते हैं, जो संगठन की अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करते हैं। हथियार और तकनीक की निर्भरता हिजबुल मुजाहिदीन को एक पारंपरिक मिलिटेंट बनाती है, जहां तस्करी हथियारों का मुख्य स्रोत है। एके-47 की खेपें संगठन के भंडार को मजबूत बनाती हैं, जो तेज भागने में सहायक हैं। पिस्तौल और ग्रेनेड लक्षित और घात हमलों के लिए हैं, जो ग्रेनेड हमलों की संख्या से स्पष्ट है। आईईडी की स्थानीय निर्माण क्षमता लागत कम करती है और प्रभाव बढ़ाती है, जो काफिलों को निशाना बनाते हैं। ड्रोन का उपयोग तस्करी को आधुनिक बनाता है, जो जब्ती अभियानों से बचने में मदद करता है। तकनीकी स्तर पर एन्क्रिप्टेड संचार और सोशल मीडिया प्रचार संगठन की पहुंच बढ़ाते हैं, जो युवाओं को आकर्षित करते हैं। ये रणनीतियाँ सीमित संसाधनों में संगठन की सामरिक उपस्थिति बनाए रखती हैं, जो कश्मीर में निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।

मूलभूत तकनीकी उपयोग

हिजबुल मुजाहिदीन अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद सरल तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग करता है, जो गुरिल्ला युद्ध और स्लीपर सेल रणनीतियों को मजबूत बनाते हैं। एन्क्रिप्टेड मोबाइल एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम भारत में ऑपरेटिवों और पाकिस्तान में हैंडलरों के बीच गुप्त संवाद स्थापित करते हैं, जो रणनीतियों को सुरक्षित रखते हैं। सालाना दर्जनों एन्क्रिप्टेड संदेशों को इंटरसेप्ट करने

के बावजूद ये ऐप्स कोडवर्ड और बिचौलियों से सूचनाएँ साझा करने में सक्षम हैं, जो संगठन की गोपनीयता बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब आतंकवाद का महिमामंडन करते हैं, युवाओं को भर्ती करने और भारतीय राज्य की छवि खराब करने में उपयोगी हैं। सैकड़ों वीडियो पोस्ट सालाना करोड़ों दर्शकों तक पहुँचते हैं, जो नफरत फैलाते और शहीदों को नायक बनाते हैं। ड्रोन तकनीक का सीमित उपयोग हथियार तस्करी से टोही तक विस्तारित है, जो सीमा पार सामग्री लाने में सहायक है। ये तकनीकें संगठन की अनुकूलन क्षमता को दर्शाती हैं, जो सीमित संसाधनों में अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

मूलभूत तकनीक हिज़बुल मुजाहिदीन को गोपनीय संचालन प्रदान करती है, जहाँ एन्क्रिप्टेड ऐप्स संवाद को निगरानी से बचाते हैं और रणनीतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग प्रचार के लिए है, जो वीडियो से भावनाओं को भड़काता है और भर्ती को बढ़ावा देता है। ड्रोनों का बढ़ता उपयोग निगरानी को मजबूत करता है, जो हथियारों के अलावा नकली मुद्रा और नशीले पदार्थ लाने में मदद करता है। इंटरसेप्ट संदेश संगठन की तकनीकी गहराई दिखाते हैं, जो बिचौलियों से सूचनाएँ छिपाते हैं। ये उपकरण गुरिल्ला रणनीतियों को सहायक बनाते हैं, जो संगठन की जीवटता बढ़ाते हैं। तकनीकें सरल होने से आसानी से अपनाई जाती हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हैं। इससे मिलिटेंसी की पहुंच बढ़ती है और प्रभाव विस्तारित होता है। हिज़बुल मुजाहिदीन की तकनीक बुनियादी है लेकिन प्रभावी, जहाँ ऐप्स गुप्त संवाद सुनिश्चित करते हैं और मीडिया प्रचार को फैलाते हैं। वीडियो पोस्ट शहीदों को महिमामंडित करते हैं, जो युवाओं को जिहाद की ओर आकर्षित करते हैं। ड्रोन टोही और तस्करी को आधुनिक बनाते हैं, जो जब्ती से बचने में सहायक हैं। संदेशों का इंटरसेप्ट संगठन की चतुराई दिखाता है, जो कोडवर्ड से रणनीतियाँ साझा करते हैं। ये तरीके स्लीपर सेल को मजबूत बनाते हैं, जो गोपनीयता पर आधारित हैं। तकनीकें सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करती हैं, जो संगठन की अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करती हैं। इससे सुरक्षा को जटिल चुनौती मिलती है और उन्मूलन मुश्किल होता है।

तकनीकी सीमाएँ और चुनौतियाँ

हिजबुल मुजाहिदीन की तकनीकी निर्भरता इसकी रणनीतिक क्षमता को सीमित करती है, क्योंकि बाहरी स्रोतों से हथियार और गोला-बारूद पर आश्रित होना आपूर्ति श्रृंखला को कमजोर बनाता है। यदि भारतीय सुरक्षा बल इन मार्गों को बंद कर दें, तो संगठन की युद्ध क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो इसके अभियानों को बाधित करेगा। अत्याधुनिक साइबर हमलों, बड़े समन्वित आतंकी हमलों और सैटेलाइट निगरानी जैसी क्षमताओं का अभाव इसे अन्य संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद से पीछे रखता है, जो अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं। फिर भी, स्थानीय समुदायों का समर्थन, जमीनी शोषण और कश्मीर के भौगोलिक लाभ से संगठन अपनी सीमाओं की भरपाई करता है, जो इसकी जीवदृढ़ता को बनाए रखते हैं। थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन जैसी तकनीकों से सुरक्षा बल आतंकवादियों को पकड़ते हैं, जो संगठन की कमजोरियों को उजागर करती हैं। स्थानीय नागरिकों में डर का वातावरण संगठन के पक्ष में या खिलाफ कार्य करता है, जो सहायता में बाधा बनता है।

सीमाएँ हिजबुल मुजाहिदीन को उन्नत संगठनों से अलग करती हैं, जहाँ तस्करी आपूर्ति पर टिकी है और बाधा पड़ने पर क्षमता कम होती है। साइबर और सैटेलाइट क्षमताओं का अभाव बड़े हमलों को सीमित करता है, जो रणनीति को प्रभावित करता है। स्थानीय समर्थन और भूभाग से भरपाई होती है, जो जमीनी लड़ाई में ताकत देता है। सुरक्षा एजेंसियों की उन्नत तकनीकें जैसे ड्रोन सर्विलांस संगठन की कमजोरियों का फायदा उठाती हैं, जो आतंकवादियों को पकड़ने में सफल रहती हैं। नागरिकों में संदेह सहायता को रोकता है, जो चुनौती बढ़ाता है। आपूर्ति श्रृंखला का नष्ट होना और तकनीकी संसाधनों का निष्क्रियकरण मुख्य चुनौती है, जो सामाजिक आधार को कम करके आतंकवाद समाप्त कर सकता है। तकनीकी चुनौतियाँ संगठन की क्षमता को बाधित करती हैं, जहाँ बाहरी निर्भरता युद्ध को प्रभावित करती है। उन्नत क्षमताओं का अभाव इसे पीछे रखता है, लेकिन स्थानीय लाभ से संतुलन बनता है। सुरक्षा बलों की तकनीकें जैसे कम्युनिकेशन जैमर संगठन को कमजोर करती हैं, जो पकड़ने में सहायक हैं। डर का वातावरण सहायता में बाधा है, जो दोनों पक्षों को प्रभावित करता है। आपूर्ति का नष्ट होना और संसाधनों का निष्क्रियकरण प्रमुख है, जो कश्मीर में समर्थन कम करके आधार समाप्त कर सकता है। इससे मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होती है।

अध्याय 7: इंडियन मुजाहिदीन

इंडियन मुजाहिदीन की उत्पत्ति

इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का उद्भव 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब भारत में इस्लामी चरमपंथी विचारधारा ने एक नई संगठित रूपरेखा ग्रहण की। यह संगठन मुख्य रूप से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कट्टरपंथी सदस्यों से निकला, जिसकी स्थापना 1977 में छात्रों के बीच इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह अधिक उग्र हो गया। सिमी को 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि 11 सितंबर के हमलों के बाद इसे आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप लगा। सिमी के असंतुष्ट सदस्यों ने, जो भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए हिंसक जिहाद का समर्थन करते थे, आईएम का गठन किया। प्रमुख संस्थापकों में कर्नाटक के भटकल बंधु रियाज भटकल और इकबाल भटकल शामिल हैं, जिनके अलावा यासिन भटकल, अब्दुल सुबहान कुैशी (तौकीर) और अन्य युवा कार्यकर्ता थे। ये सदस्य वैश्विक जिहादी संगठनों जैसे अल-कायदा से प्रेरित थे और पाकिस्तान स्थित समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) तथा जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से समर्थन प्राप्त करते थे। पाकिस्तान की आईएसआई से भी इनकी कड़ियाँ जुड़ीं, जो प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराती थी। आईएम ने अपनी पहली दावेदारी 2007 में उत्तर प्रदेश के अदालती परिसरों में हुए धमाकों के साथ की, लेकिन इसे पहले की घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना था, जिसमें मुसलमानों के कथित उत्पीड़न का बदला लेने के लिए शहरी केंद्रों पर हमले शामिल थे। 2008 में जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों ने सैकड़ों लोगों की जान ली, जो आईएम की पहुंच और योजना क्षमता को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में मॉड्यूल स्थापित करके संगठन ने शिक्षित युवा मुसलमानों को भर्ती किया, जो सांप्रदायिक भेदभाव से निराश थे। भारतीय अधिकारियों ने 2013 में यासिन भटकल जैसी प्रमुख गिरफ्तारियों से संगठन को कमजोर किया, लेकिन इसके छिटपुट गुट अभी भी मौजूद हैं।

संगठन की स्थापना एक वैचारिक आधार पर हुई, जहां जिहाद को आवश्यक माध्यम माना जाता है। इसके प्रचार अभियानों में भारत को मुसलमानों के उत्पीड़क के रूप में दर्शाया जाता है, और ऐतिहासिक घटनाओं जैसे 1947 का बंटवारा, 1992 का बाबरी मस्जिद ध्वंस तथा 2002 के गुजरात दंगों को साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है। यह हिंसा को बचाव की कार्रवाई के रूप में वैध ठहराता है, जो युवाओं में प्रतिशोध की भावना जगाती है। संगठन के घोषणा-पत्र और वीडियो में शहादत को सर्वोच्च मूल्य बताया जाता है, जबकि आतंकवादियों को वीर योद्धाओं की संज्ञा दी जाती है। यह दृष्टिकोण शहरी मुसलमानों को आकर्षित करता है, जो सरकारी नीतियों से निराश होते हैं। 2010 तक संगठन ने सालाना दर्जनों युवाओं को इस विचारधारा से जोड़ा, जो सामाजिक असंतोष का फायदा उठाती थी। वैश्विक जिहादी आंदोलनों जैसे अल-कायदा और आईएसआईएस से प्रेरणा लेते हुए, यह एक मुस्लिम खिलाफत की स्थापना की हिमायत करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करे। इसके ऑनलाइन मंच और पत्रिकाएं शहादत की प्रशंसा करती हैं, जो सदस्यों को नायकों के रूप में प्रस्तुत करती हैं।

इसके लक्ष्य धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तरों पर विस्तृत हैं। धार्मिक दृष्टि से, यह शुद्ध इस्लाम का प्रसार करता है और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का विरोध करता है, जो पश्चिमी प्रभावों को अस्वीकार करती है। राजनीतिक रूप से, यह आर्थिक केंद्रों को लक्षित करके भारत को कमजोर बनाना चाहता है, जो सांप्रदायिक विद्वेष को उकसाता है। सामाजिक-आर्थिक आयाम में, यह मुसलमानों के बीच निर्धनता, भेदभाव और राज्य की अनदेखी का उपयोग करता है, जो युवाओं को विद्रोह की ओर धकेलता है। 2015 तक मुंबई के स्लम इलाकों से भर्ती का बड़ा हिस्सा आता था, जो आर्थिक असमानता पर आधारित था। 2008 के जयपुर विस्फोट जैसे हमले हिंदू-प्रधान स्थानों को चुनकर सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देते थे। संगठन ने सालाना कई हमलों की योजना बनाई, जो भारत की स्थिरता को हिलाने का इरादा रखते थे। रणनीतिक स्तर पर, यह डर उत्पन्न करके मुसलमानों की वैश्विक पीड़ा की कथा को फैलाता है, जो अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास है। 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोटों से आर्थिक नुकसान हुआ, जो विकास को बाधित करता था। सरकारी प्रतिक्रियाओं को उत्पीड़न के रूप में चित्रित करके, यह समुदाय में अलगाव की भावना को मजबूत करता है।

संगठन वैश्विक इस्लामी आंदोलन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, जो अल-कायदा और आईएसआईएस की प्रचार तकनीकों से जुड़ता है। सोशल मीडिया के जरिए असंतुष्ट युवाओं को लक्षित किया जाता है, जो ऑनलाइन कट्टरवाद की ओर ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मदरसों को भर्ती स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां वजीफे हवाला से दिए जाते हैं। 2013 में आंतरिक विवादों से नए गुट बने, जो एकता को प्रभावित करते हैं लेकिन खतरे को कम नहीं करते। स्लीपर सेल और कठोर दर्शन से संगठन जीवित रहता है, जो युवाओं को जिहाद की ओर आकर्षित करता है। विचारधारा शुद्धता पर जोर देती है, जो धर्मनिरपेक्षता को खारिज करती है। राजनीतिक लक्ष्य आर्थिक केंद्रों को कमजोर बनाते हैं, जो सांप्रदायिकता को भड़काते हैं। सामाजिक स्तर पर, यह असमानता का शोषण करता है, जो भर्ती को बढ़ावा देता है। हमलों का उद्देश्य डर फैलाना है, जो मुसलमानों की कहानी को प्रसारित करता है। इससे संगठन की रणनीति बहुआयामी बनती है, जो भारत की स्थिरता को चुनौती देती है।

इंडियन मुजाहिदीन के नेटवर्क और साझेदारियाँ

इंडियन मुजाहिदीन का गठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कट्टर गुटों से हुआ, जिसे प्रतिबंधित करने के बाद संगठन ने पाकिस्तान स्थित समूहों से मजबूत रिश्ते विकसित किए। लश्कर-ए-तैयबा के साथ सहयोग ने बम निर्माण और शहरी लड़ाई में विशेषज्ञता प्रदान की, जबकि जैश-ए-मोहम्मद ने हमलों की योजना में योगदान दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन कड़ियों की पुष्टि की, जहां प्रमुख सदस्यों ने पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकातें कीं। प्रशिक्षण शिविरों में ऑपरेटिवों को युद्ध तकनीकों का ज्ञान दिया गया, जो संगठन की क्षमता को बढ़ाता रहा। अल-कायदा से विचारधारात्मक जुड़ाव ने वैश्विक जिहाद की दिशा दी, जबकि आईएसआईएस के प्रभाव ने प्रचार को तेज किया। आंतरिक कलह से नए समूह उभरे, जो अल-कायदा से जुड़े। प्रवासी समुदायों ने वित्तीय सहायता प्रदान की, जो विदेशी नेटवर्क को मजबूत बनाती है। ये साझेदारियाँ संगठन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देती हैं, जो स्थानीय और वैश्विक तत्वों का मिश्रण हैं।

संगठन के नेटवर्क में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का योगदान प्रमुख है, जो वित्त और लॉजिस्टिक समर्थन देती है। लश्कर-ए-तैयबा के साथ साझा अभियानों ने मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में विनाश फैलाया, जहां दोनों संगठनों ने सुरक्षित पनाहगहों का साझा इस्तेमाल किया। जैश-ए-मोहम्मद ने हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित की, जो संगठन की ताकत बढ़ाती है। अल-कायदा के साथ वैचारिक गठजोड़ ने खिलाफत की अवधारणा को अपनाया, जो युवाओं को आकर्षित करता है। आईएसआईएस से प्रेरित प्रचार ने वीडियो के माध्यम से प्रभाव फैलाया, जो लाखों तक पहुंचा। नए गुटों का उदय आंतरिक असहमति से हुआ, जो अल-कायदा से प्रेरित हैं। यूके और सऊदी अरब के प्रवासियों ने चंदे के जरिए सहयोग दिया, जो हवाला से संगठन तक पहुंचते हैं। ये गठबंधन संगठन को बहुस्तरीय बनाते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रहते हैं।

इंडियन मुजाहिदीन की साझेदारियाँ स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट से विकसित हुईं, जो पाकिस्तानी समूहों से जुड़ीं। लश्कर-ए-तैयबा ने प्रशिक्षण शिविर उपलब्ध कराए, जहां ऑपरेटिवों को तकनीकें सिखाई गईं। जैश-ए-मोहम्मद के साथ समन्वय ने हमलों की दक्षता बढ़ाई, जो संयुक्त प्रयासों से सफल हुए। अल-कायदा का प्रभाव विचारधारात्मक रहा, जो जिहाद की वैश्विक दृष्टि प्रदान करता है। आईएसआईएस से प्रभावित होकर संगठन ने ऑनलाइन अभियान चलाए, जो प्रचार को प्रभावी बनाते

हैं। नए गुटों का उदय आंतरिक असहमति से हुआ, जो अल-कायदा से प्रेरित हैं। यूएई और सऊदी अरब के समुदायों ने वित्तीय योगदान दिया, जो मस्जिदों से इकट्ठा होता है। ये नेटवर्क संगठन को बहुस्तरीय बनाते हैं, जो स्थानीय से वैश्विक तक फैले हैं।

भारतीय मुजाहिदीन के धन संग्रह के स्रोत और तरीके

भारतीय मुजाहिदीन शहरी आतंक को बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी गुप्तचर सेवा से कथित सहायता प्राप्त करता है, जो संगठन को नियमित आर्थिक संसाधन प्रदान करती है। हवाला तंत्र से मासिक धनराशि का हस्तांतरण इस तरह किया जाता है कि जांच एजेंसियों की निगाह से बचा रहे, जिससे अभियानों की निरंतरता सुनिश्चित होती है। विदेशों में बसे भारतीय समुदायों से प्राप्त चंदा धार्मिक आयोजनों के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो संगठन की अंतरराष्ट्रीय अपील को दर्शाता है।

नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार इसका एक प्रमुख आय स्रोत है, जो बार-बार की ज़ब्तों के बाद भी जारी रहता है। नकली मुद्रा का उत्पादन आर्थिक अस्थिरता पैदा करने के साथ-साथ संगठन के लिए आमदनी भी लाता है। वैध प्रतीत होने वाले व्यापारों में लगाई गई पूंजी स्थायी लाभ देती है, जो प्रतिबंधों के प्रभाव को कम कर देती है। इन विविध तरीकों से संगठन बहुआयामी स्वरूप ग्रहण करता है और अलग-अलग स्तरों पर अपनी गतिविधियाँ जारी रख पाता है।

संगठन की आर्थिक व्यवस्था में गुप्तचर सहयोग महत्वपूर्ण है, जो प्रशिक्षण के अलावा धन की व्यवस्था करता है। हवाला संचालकों का जाल सालाना करोड़ों का व्यवहार करता है, जो गिरफ्तारियों से प्रभावित होता है लेकिन पुनः स्थापित हो जाता है। दान प्राप्ति मस्जिद कार्यक्रमों से होती है, जो भावनाओं का दोहन करती है। ड्रग व्यापार से प्राप्त मुनाफा संचालन को तेज करता है, जो हेरोइन जैसी वस्तुओं से आता है। जाली मुद्रा का कारखाना पाकिस्तान से चलता है, जो रैकेट से जुड़ा है। व्यापारिक लगाव अनाज क्षेत्र में केंद्रित है, जो वार्षिक लाभ पैदा करता है। ये तकनीकें जांच को भ्रमित करती हैं, जो वैश्विक कमियों का लाभ उठाती हैं। वित्तीय स्रोत इंडियन मुजाहिदीन को टिकाऊ रखते हैं, जहां एजेंसी समर्थन मूलभूत है। हवाला चैनल मुस्लिम बहुल इलाकों से जुड़े हैं, जो संचालकों से धन स्थानांतरित करते हैं। चंदा संग्रह धार्मिक आयोजनों से है, जो दाताओं की उदारता पर निर्भर है। नशीले पदार्थ व्यापार आय का बड़ा हिस्सा है, जो नशीली वस्तुओं से कमाया जाता है। नकली नोट कारखाना कराची केंद्रित है,

जो अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाता है। वैध निवेश संपत्ति में हैं, जो प्रतिबंधित स्थिति में भी जारी रहते हैं। ये प्रक्रियाएँ वैश्विक कमजोरियों का शोषण करती हैं, जो संगठन को मजबूत रखती हैं।

इंडियन मुजाहिदीन की क्रियान्वयन युक्तियाँ

इंडियन मुजाहिदीन की क्रियान्वयन युक्तियाँ मुख्य रूप से गोपनीयता और आश्चर्यजनक हमलों पर केंद्रित हैं, जिनका लक्ष्य भारत के प्रमुख शहरों में अराजकता उत्पन्न करना है। संगठन छोटे समूहों में विभाजित होकर कार्य करता है, जहां प्रत्येक इकाई स्वतंत्र रूप से योजना बनाती है ताकि पकड़े जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित न हो। ऐसी युक्तियाँ 2000 के दशक में विकसित हुईं, जब संगठन ने दिल्ली और मुंबई जैसे घनी आबादी वाले स्थानों को चुना, जहां हमलों से अधिकतम प्रभाव पड़ता है। इन युक्तियों का आधार स्थानीय संसाधनों का उपयोग और न्यूनतम जोखिम है, जिससे संगठन लंबे समय तक सक्रिय रहता है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ये युक्तियाँ विदेशी सहयोगियों से सीखी गई हैं, जो योजना की जटिलता बढ़ाती हैं। कुल मिलाकर, ये युक्तियाँ संगठन को लचीला और अप्रत्याशित बनाती हैं, जिससे प्रतिकार कठिन हो जाता है।

संगठन की प्रमुख युक्ति स्लीपर सेल मॉडल है, जिसमें सदस्य सामान्य जीवन जीते हुए वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं और आवश्यकता पर सक्रिय होते हैं। यह मॉडल छोटे-छोटे दलों पर आधारित है, जहां प्रत्येक दल में सीमित सदस्य होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर भर्ती और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उदाहरणस्वरूप, विभिन्न शहरों में छिपे सेल समय-समय पर सक्रिय होकर हमलों की तैयारी करते हैं, जैसे कि प्रमुख बाजारों या परिवहन केंद्रों पर। इस युक्ति से संगठन खुफिया एजेंसियों से बचता है, क्योंकि सदस्यों की दैनिक गतिविधियाँ संदेहास्पद नहीं लगतीं। हाल के वर्षों में, कई ऐसे सेल उजागर हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि यह युक्ति अब भी प्रभावी है। इन सेलों की सक्रियता घटनाओं के आधार पर होती है, जो संगठन की दीर्घकालिक योजना को मजबूत बनाती है। क्रियान्वयन में संचार की युक्तियाँ अत्यंत सुरक्षित हैं, जहां एन्क्रिप्टेड अनुप्रयोगों और कोडेड संदेशों का प्रयोग प्रमुख है। सदस्य योजना बनाने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, जो ट्रैकिंग को मुश्किल बनाते हैं। ऐसी युक्तियाँ हमलों से पहले और बाद में दावा करने के लिए ईमेल का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि अहमदाबाद धमाकों में चेतावनी भेजना। संचार नेटवर्क स्थानीय सिम

कार्डों और सार्वजनिक फोन बूथों पर निर्भर है, जो पहचान छिपाने में सहायक है। यह युक्ति संगठन को समन्वित रखती है, भले ही नेता विदेश में हों। हालिया जांचों से पता चला है कि ये तरीके विकसित होकर अधिक डिजिटल हो गए हैं, जो क्रियान्वयन की गति बढ़ाते हैं।

सहयोगी संगठनों के साथ समन्वय संगठन की युक्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से संसाधन साझा किए जाते हैं। यह समन्वय प्रशिक्षण शिविरों में होता है, जहां सदस्य संयुक्त अभ्यास करते हैं ताकि हमलों की प्रभावशीलता बढ़े। उदाहरण के तौर पर, पाकिस्तान स्थित शिविरों में सीखी गई युक्तियाँ भारतीय शहरों में लागू की जाती हैं। ऐसी साझेदारियाँ संगठन को लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करती हैं, जो क्रियान्वयन को सुगम बनाती हैं। जांच एजेंसियों ने कई मामलों में इस समन्वय को उजागर किया है, जो दर्शाता है कि बिना इनके संगठन की क्षमता सीमित होती। यह युक्ति संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत बनाती है, जिससे वैश्विक जिहादी नेटवर्क का लाभ मिलता है। प्रचार और भर्ती की युक्तियाँ सोशल मीडिया पर आधारित हैं, जहां वीडियो और संदेशों से युवाओं को आकर्षित किया जाता है। संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी क्रियाओं का प्रचार करता है, जो हमलों के बाद समर्थन जुटाने में मदद करता है। ऐसी युक्तियाँ लक्षित संदेशों से होती हैं, जो स्थानीय शिकायतों को उजागर करती हैं। प्रचार सामग्री में हमलों की सफलता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, जो नई भर्ती को प्रेरित करती है। हाल के वर्षों में, हजारों वीडियो प्रसारित हुए हैं, जो क्रियान्वयन का हिस्सा बन गए हैं। यह युक्ति संगठन को विचारधारा फैलाने और समर्थकों को सक्रिय रखने में सक्षम बनाती है, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। विकास और वर्तमान स्थिति में युक्तियाँ गुटबाजी से प्रभावित हुई हैं, जहां नए उपसमूह उभरकर अलग रास्ते अपनाते हैं। संगठन की मूल युक्तियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन गिरफ्तारियों से प्रभावित होकर अधिक छिपी हुई हो गई हैं। उदाहरणस्वरूप, नेता जेल में होने पर भी सेल सक्रिय रहते हैं, जो दर्शन को मजबूत बनाती है। हालिया वर्षों में, क्रियान्वयन कम हुए हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। सुरक्षा उपायों से युक्तियाँ बदल रही हैं, जैसे कि अधिक डिजिटल निर्भरता। यह विकास संगठन को अनुकूलित रखता है, जिससे भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ती हैं।

इंडियन मुजाहिदीन के शस्त्र और प्रविधियाँ

इंडियन मुजाहिदीन के शस्त्र मुख्यतः घरेलू सामग्रियों से बने विस्फोटक उपकरणों पर निर्भर हैं, जो संगठन की सीमित संसाधनों में भी उच्च प्रभाव पैदा करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जैसे सुलभ रसायनों से तैयार आईईडी इनके प्रमुख हथियार हैं, जिन्हें साइकिलों या बैगों में छिपाकर रखा जाता है। ये उपकरण सस्ते होने के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जा सकते हैं, जिससे तस्करी की जरूरत कम हो जाती है। विभिन्न शहरों में पकड़े गए मामलों से पता चलता है कि संगठन इनकी निर्माण प्रक्रिया में कुशल है। कुल मिलाकर, ऐसे शस्त्र संगठन को गुप्त और प्रभावी बनाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बढ़ती है। संगठन अन्य घातक शस्त्रों की तस्करी भी करता है, जैसे कि आरडीएक्स जो सैन्य स्तर का विस्फोटक है और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से प्राप्त होता है। छोटे हथियार जैसे पिस्तौल और रिवाल्वर लक्षित हमलों में उपयोग होते हैं, जो पुलिस या व्यक्तियों पर केंद्रित होते हैं। ग्रेनेड भीड़ वाले स्थानों पर आतंक फैलाने के लिए फेंके जाते हैं, जिससे अराजकता बढ़ती है। इन शस्त्रों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित सहयोगी समूहों से होती है, जो तस्करी चैनलों का संचालन करते हैं। स्थानीय कार्यशालाओं में निर्माण से संगठन स्वावलंबी बनता है, जिससे उसकी क्षमता बनी रहती है। प्रविधियाँ संचार और प्रचार पर आधारित हैं, जहां एन्क्रिप्टेड अनुप्रयोगों और कोडेड संदेशों का प्रयोग प्रमुख है। ये ऐप्स ट्रैकिंग से बचाते हैं और गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके युवाओं को प्रेरित किया जाता है, जहां हमलों की सफलता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। ऐसी प्रविधियाँ संगठन को वैश्विक स्तर पर जोड़ती हैं, जिससे विचारधारा का प्रसार आसान होता है। हालिया वर्षों में, डिजिटल माध्यमों की भूमिका बढ़ी है, जो प्रचार को प्रभावी बनाती है।

टाइमर आधारित आईईडी प्रविधि संगठन की तकनीकी कुशलता का उदाहरण है, जहां विस्फोट पूर्व निर्धारित समय पर होता है। डिजिटल घड़ियाँ और बैटरी सर्किट्स से बने ये उपकरण साधारण वस्तुओं जैसे कुकर में छिपाए जाते हैं, जिससे पता लगाना कठिन होता है। हमलावर सुरक्षित दूरी पर रहता है, जबकि क्षति अधिकतम होती है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए मामलों से स्पष्ट है कि ये प्रविधियाँ विकसित हो रही हैं। कुल मिलाकर, ऐसी तकनीकें संगठन को चपल और खतरनाक बनाती हैं, जिससे प्रतिरोध चुनौतीपूर्ण होता है। प्रशिक्षण प्रविधियाँ विदेशी शिविरों पर निर्भर हैं, जहां

सदस्यों को विस्फोटक निर्माण और शहरी युद्ध के तरीके सिखाए जाते हैं। पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों में स्थित ये शिविर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ऑनलाइन प्रचार का ज्ञान प्रदान करते हैं। युवाओं को साइबर सुरक्षा से बचने के गुर बताए जाते हैं, जो संचालन को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे प्रशिक्षण संगठन की क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे सदस्य कुशल बनते हैं। जांचों से पता चला है कि ये प्रविधियाँ वर्षों से चली आ रही हैं, जो निरंतरता दर्शाती हैं। संगठन की समग्र प्रविधियाँ बहुस्तरीय हैं, जहाँ शस्त्र और तकनीक का संयोजन मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है। ये तरीके भारत की स्थिरता को लक्षित करते हैं, जिससे आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से प्राप्त ज्ञान संगठन को अनुकूलित रखता है, जो नए रूपों में उभरता है। कुल मिलाकर, ऐसी प्रणाली एक संगठित ढांचा बनाती है, जिसमें विनाश और प्रचार का मिश्रण होता है। हालिया विकास से स्पष्ट है कि ये प्रविधियाँ सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती देती रहती हैं।

अध्याय 8:

अल-कायदा

उद्गम और दक्षिण एशिया में ए-क्यू-आई-एस का क्षेत्रीय प्रभाव

अल-कायदा की स्थापना 1988 में ओसामा बिन लादेन द्वारा सोवियत-अफगान युद्ध के दौरान की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य सोवियत सेनाओं के विरुद्ध लड़ने वाले मुजाहिदीन गुटों को एकजुट करना था। यह संगठन बाद में एक वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क के रूप में उभरा, जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए भयावह आतंकी हमलों के माध्यम से विश्वभर में अपनी पहचान कायम की। इन हमलों के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध की शुरुआत की। अल-कायदा की विचारधारा एक कट्टरपंथी इस्लामी राज्य - खलीफा की स्थापना और मुस्लिम भूमि से पश्चिमी प्रभावों को पूरी तरह हटाने पर आधारित है। इस संगठन ने अपने वैश्विक जिहादी मिशन के विस्तार के उद्देश्य से 2014 में अयमान अल-जवाहिरी के नेतृत्व में “अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट” (ए-क्यू-आई-एस) की स्थापना की।

ए-क्यू-आई-एस का गठन विशेष रूप से दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र के रूप में किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सरकारों को इस्लामी राज्य में बदलना है। पाकिस्तान को यह संगठन भारत के विरुद्ध जिहाद के लिए एक द्वार के रूप में देखता है। ए-क्यू-आई-एस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान-नियंत्रित क्षेत्रों, जैसे वज्जीरिस्तान और हेलमंद, में अपने प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं, जो इसे सुरक्षा बलों से बचने और रणनीतिक योजना तैयार करने का आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी विशेषकर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यह संगठन भारत-पाकिस्तान विवाद का लाभ उठाकर अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। ए-क्यू-आई-एस ने भारत में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कई हमले किए हैं। 2016 के पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले में सात सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी, जबकि 2018 में जम्मू-कश्मीर में एयरबेस पर हमले में दो सैनिक शहीद हुए थे। 2020 तक ऐसे लगभग दस से पंद्रह हमलों की पुष्टि की जा चुकी है। ए-क्यू-आई-एस तालिबान और इस्लामिक स्टेट - खुरासान प्रांत (आई-एस-के-पी) जैसे अन्य कट्टरपंथी गुटों के साथ भी सहयोग करता है, हालांकि यह संगठन अपनी स्वतंत्र

पहचान बनाए रखता है। कई बार यह गुट क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। 2023 तक कश्मीर में ए-क्यू-आई-एस के दो सौ से तीन सौ ऑपरेटिव सक्रिय थे।

बांग्लादेश में इसकी सीमित उपस्थिति देखी गई है, जहाँ 2015 में कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था जो स्थानीय हमलों की योजना बना रहे थे। म्यांमार में अभी तक ए-क्यू-आई-एस की कोई प्रमुख गतिविधि सामने नहीं आई है, लेकिन रोहिंग्या संकट को यह संगठन प्रचार और भर्ती के एक औजार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। ए-क्यू-आई-एस का प्रमुख नेतृत्व दस से पंद्रह वरिष्ठ सदस्यों की एक शूरा परिषद के अधीन है। इसने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के युवाओं को भर्ती किया है, जो सरकारों से निराश और कट्टरपंथी विचारधारा की ओर झुके हुए होते हैं। 2020 तक हर साल एक सौ से दो सौ नए भर्ती किए जाने की जानकारी है। ए-क्यू-आई-एस अपने प्रचार और वैचारिक विस्तार के लिए सोशल मीडिया, वीडियो संदेशों, और मस्जिद नेटवर्कों का उपयोग करता है। 2024 तक इसने सालाना पाँच सौ से एक हजार वीडियो ऑनलाइन साझा किए, जिन्हें कुल मिलाकर दस लाख से अधिक बार देखा गया। 2018 तक इसके ऐसे दस से पंद्रह केंद्र चिन्हित किए गए थे जहाँ इन वीडियो को व्यापक रूप से वितरित किया जाता था। यह प्रचार न केवल ए-क्यू-आई-एस की विचारधारा को फैलाता है, बल्कि भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में असंतोष को बढ़ाता है, जिससे संगठन दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है।

लक्ष्य और विचारधारा

अल-कायदा की कट्टरपंथी वैचारिक नींव उसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन द्वारा 1988 में रखी गई थी, जिसे अयमान अल-जवाहिरी ने 2014 में ए-क्यू-आई-एस के माध्यम से दक्षिण एशिया में विस्तार दिया। ए-क्यू-आई-एस का प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण एशिया में इस्लामी राज्य की स्थापना करना है, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से हासिल किया जाए। यह संगठन भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ढांचे को इस्लामी मूल्यों के लिए खतरा मानता है और इसे मुस्लिमों के दमन का प्रतीक बताता है। ए-क्यू-आई-एस की विचारधारा सख्त सलाफी-जिहादी चिंतन पर आधारित है, जो सय्यद कुतुब और अब्दुल्ला अज़्जाम जैसे कट्टरपंथी विचारकों के लेखन से प्रेरित है। यह विचारधारा मुस्लिम समाज को “शुद्ध” इस्लामी शासन के अधीन लाने के लिए

वैश्विक जिहाद की वकालत करती है। दक्षिण एशिया में ए-क्यू-आई-एस भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है, खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को “इस्लामी मुक्ति संग्राम” के युद्धक्षेत्र के रूप में प्रचारित करके। 2002 के गुजरात दंगों, जिसमें एक हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे, उनमें से अधिकांश मुस्लिम थे - ऐसे घटनाओं को ए-क्यू-आई-एस मुस्लिम उत्पीड़न के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने का माहौल बनाया जाता है। 2020 तक संगठन हर वर्ष लगभग एक सौ से दो सौ युवाओं की भर्ती करता रहा है।

ए-क्यू-आई-एस का प्रचार तंत्र सोशल मीडिया और मस्जिद नेटवर्कों के माध्यम से सक्रिय है। इसके प्रचार वीडियो शहीदों को जन्नत का वादा करते हैं, जिहाद को सबसे बड़ा कर्तव्य बताते हैं, और भारत के खिलाफ युद्ध को धर्म का हिस्सा बताकर युवाओं को उकसाते हैं। 2024 तक सालाना पाँच सौ से एक हज़ार वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किए गए, जिनकी कुल दर्शक संख्या दस लाख से अधिक थी। ए-क्यू-आई-एस अपने इन प्रचार वीडियो को भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फैला रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, जहाँ स्थानीय मस्जिदों और मदरसों के माध्यम से इनका वितरण होता है। 2016 तक ऐसे दस से पंद्रह मस्जिद नेटवर्कों की पहचान की गई थी जहाँ से प्रचार सामग्री नियमित रूप से फैलाई जाती थी। ए-क्यू-आई-एस की भर्ती रणनीति शहीदों को नायक के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। जिहादी बनने वाले को हर महीने चार हज़ार से आठ हज़ार रुपये तक की सहायता दी जाती है, जबकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को चार लाख से आठ लाख रुपये तक की राशि हवाला नेटवर्क के माध्यम से भेजी जाती है। 2022 तक ए-क्यू-आई-एस ने लगभग दो सौ से तीन सौ शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी।

कट्टरपंथी बनाने की प्रक्रिया में ए-क्यू-आई-एस हर दिन चार घंटे की मदरसा शिक्षा का आयोजन करता है, जिसमें “तप्सीर इब्न कसीर” जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। 2015 तक सालाना पचास से एक सौ युवाओं को इस प्रकार के धार्मिक चरमपंथ की ओर धकेला गया। संगठन स्थानीय शिकायतों, जैसे बेरोज़गारी, भेदभाव और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का भी लाभ उठाकर अपनी विचारधारा की ओर युवाओं को आकर्षित करता है। ए-क्यू-आई-एस की विचारधारा केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और स्थानीय असंतोष का खतरनाक मिश्रण है। पश्चिमी

देशों की सैन्य हस्तक्षेप, विशेष रूप से इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई को ए-क्यू-आई-एस अपने प्रचार का मुख्य आधार बनाता है। 2016 के पठानकोट हमले को ए-क्यू-आई-एस ने पश्चिमी हस्तक्षेप का बदला बताया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संगठन वैश्विक मुस्लिम पीड़ाओं को स्थानीय जिहाद में परिवर्तित करने की योजना पर काम करता है।

नेटवर्क और गठबंधन

अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (ए-क्यू-आई-एस), जिसकी स्थापना 2014 में अयमान अल-जवाहिरी ने की थी, ने दक्षिण एशिया में अपने आतंकवादी अभियानों को सशक्त और विस्तृत करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ गहरे गठबंधन बना लिए हैं। ए-क्यू-आई-एस का पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ मजबूत समन्वय है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से भारत के कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी हमलों के लिए किया गया। 2016 का पठानकोट हमला, जिसमें सात भारतीय सुरक्षा कर्मी मारे गए, लश्कर-ए-तैयबा के साथ समन्वयित एक संयुक्त अभियान था। इसमें दोनों संगठनों ने सुरक्षित पनाहगाहों और रसद सहायता का साझा इस्तेमाल किया। 2019 तक भारत में ए-क्यू-आई-एस द्वारा किए गए कुल हमलों में से पचास से साठ प्रतिशत हमले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के सहयोग से किए गए थे।

तालिबान के साथ ए-क्यू-आई-एस के संबंध भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों, जैसे वज्जीरिस्तान और हेलमंद, में प्रशिक्षण शिविर और शरण प्रदान करते हैं। 2015 तक ए-क्यू-आई-एस हर वर्ष एक सौ से डेढ़ सौ आतंकवादियों को इन ठिकानों पर प्रशिक्षण देता रहा। इन शिविरों में दोनों संगठनों का साझा हथियार भंडार, जैसे दो सौ एके-सैंतालीस रायफल और पचास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, रखा गया था। यह आधारभूत संरचना अमेरिकी आक्रमण के बाद ए-क्यू-आई-एस की पुनः सक्रियता में सहायक बनी। वैश्विक स्तर पर ए-क्यू-आई-एस, अल-कायदा के केंद्रीय नेतृत्व के अधीन रहते हुए, अर्ध-स्वायत्त रूप से कार्य करता है। 2023 तक ए-क्यू-आई-एस ने अल-कायदा के वैश्विक नेटवर्क के साथ समन्वय करते हुए कम से कम दस से पंद्रह अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिशों को अंजाम देने की योजना बनाई थी, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया।

ए-क्यू-आई-एस का अल-कायदा की अन्य शाखाओं जैसे अरब प्रायद्वीप में अल-कायदा (ए-क्यू-ए-पी), इस्लामिक मघरेब में अल-कायदा (ए-क्यू-आई-एम), और अल-शबाब (पूर्वी अफ्रीका) के साथ भी संबंध है, जिससे उसका अंतरराष्ट्रीय विस्तार और विचारधारा को मजबूती मिलती है। 2023 तक ए-क्यू-आई-एस के दक्षिण एशिया में लगभग दो सौ से तीन सौ सक्रिय आतंकवादी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस नेटवर्क को तकनीकी रूप से भी उन्नत किया गया है। ए-क्यू-आई-एस सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम का प्रयोग करते हुए सालाना पाँच सौ से एक हजार वीडियो अपलोड करता है, जिन्हें 2024 तक कुल मिलाकर दस लाख से अधिक बार देखा गया। एक विशेष वीडियो, जो 2016 में एक विफल आतंकी साजिश पर आधारित था, उसे अकेले ही पाँच लाख बार देखा गया। ये प्रचार सामग्री भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फैलाई जाती है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में, जहाँ स्थानीय मस्जिदों और मदरसों के माध्यम से वितरण होता है। 2016 तक ऐसे दस से पंद्रह मस्जिद नेटवर्कों की पहचान की गई थी।

ए-क्यू-आई-एस अपने आतंकी नेटवर्क के भीतर सुरक्षित संवाद के लिए एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों का उपयोग करता है। 2023 तक दो सौ से तीन सौ एन्क्रिप्टेड संदेशों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। इसकी वित्तीय व्यवस्था भी जटिल है-यह दान, हवाला लेन-देन और नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों पर आधारित है। 2020 तक ए-क्यू-आई-एस ने हर वर्ष चालीस करोड़ से अस्सी करोड़ रुपये की रकम जुटाई। 2016 में चालीस करोड़ रुपये की हेरोइन और 2017 में कराची स्थित प्रिंटिंग प्रेस से आठ करोड़ रुपये मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी। ए-क्यू-आई-एस का यह बहुआयामी नेटवर्क इसे भारतीय सुरक्षा के लिए एक सतत और गंभीर खतरा बनाता है, जो कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्रों का रणनीतिक लाभ उठाकर अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है।

वित्त पोषण के तरीके

ए-क्यू-आई-एस की आतंकी गतिविधियों के संचालन के लिए उसका वित्तीय तंत्र अत्यंत विविध और लचीला है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और वित्तीय निगरानी से बचते हुए अपनी पूंजी जुटाने में सक्षम रहा है। इसकी फंडिंग का प्रमुख हिस्सा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों और इस्लामी संगठनों द्वारा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी देशों से आता है, जिन्हें मानवीय सहायता या धार्मिक चंदा

कहकर इकट्ठा किया जाता है। इन फंडों को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रखते हुए हवाला नेटवर्क के माध्यम से ए-क्यू-आई-एस तक पहुँचाया जाता है। 2023 तक हर साल इस माध्यम से आठ करोड़ रुपये तक की रकम भेजी जाती थी, भले ही भारत सरकार ने एक सौ से दो सौ हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार कर लिया हो। इसके अलावा, ए-क्यू-आई-एस ने विभिन्न धर्मार्थ संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों को छद्म आवरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिनके माध्यम से 2019 तक हर वर्ष सोलह करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई गई। 2018 में भारतीय एजेंसियों ने कई ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की पहचान की, जो असल में ए-क्यू-आई-एस के वित्तीय नेटवर्क का हिस्सा थे।

अवैध गतिविधियाँ, जैसे नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्रा व्यापार, और सीमा पार से आने वाली तस्करी, ए-क्यू-आई-एस की आय का एक और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 2020 तक नशीली दवाओं के व्यापार से अकेले चालीस करोड़ रुपये से अस्सी करोड़ रुपये तक की वार्षिक आमदनी होती थी। 2016 में चालीस करोड़ रुपये की हेरोइन और 2017 में कराची स्थित प्रिंटिंग प्रेस से आठ करोड़ रुपये मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ए-क्यू-आई-एस ने अपने वित्तीय नेटवर्क को आधुनिक बना लिया है। इसने पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम कर के क्रिप्टोकॉर्सेसी, ऑनलाइन जन-धन संग्रहण और स्थानीय वस्तु विनिमय (बार्टर प्रणाली) जैसे विकल्पों का प्रयोग शुरू किया। इससे न केवल ए-क्यू-आई-एस के वित्तीय लेन-देन गुप्त बने रहते हैं, बल्कि यह वैश्विक प्रतिबंधों की निगरानी से भी बचने में सफल रहता है। भारत ने 2022 तक चालीस करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की और एफ-ए-टी-एफ (वित्तीय कार्रवाई कार्यबल) के दबाव में कई संदिग्ध खातों को फ्रीज किया, फिर भी ए-क्यू-आई-एस की विविध और बहुस्तरीय वित्तीय रणनीति इसे संचालित रहने में समर्थ बनाती है।

संचालन रणनीतियाँ और तकनीकें

1988 में अल-कायदा की स्थापना से लेकर 2014 में ए-क्यू-आई-एस के गठन तक, इस संगठन ने आतंकवाद की रणनीतियों को समय के अनुसार बदला और परिष्कृत किया है। ए-क्यू-आई-एस विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, और भारत में कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, अपने आतंकवादी एजेंडे को लागू करने के लिए स्लीपर सेल, आत्मघाती हमलों और साइबर हमलों का उपयोग करता है। ए-क्यू-आई-एस की

स्लीपर सेल रणनीति बेहद खतरनाक है - इनमें पाँच से दस सदस्यों के छोटे समूह होते हैं जो सामान्य नागरिकों की तरह समाज में घुलमिल कर रहते हैं और आदेश मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं। 2016 में कश्मीर में ए-क्यू-आई-एस की एक स्लीपर सेल की साजिश को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया था। 2023 तक बीस से तीस सक्रिय स्लीपर सेल की पहचान की जा चुकी थी।

आत्मघाती हमले अल-कायदा की सबसे प्रमुख रणनीति रही है। हालांकि 2019 का पुलवामा हमला ए-क्यू-आई-एस द्वारा नहीं, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किया गया था, लेकिन ए-क्यू-आई-एस ने कई ऐसे आत्मघाती हमले किए हैं जिनका उद्देश्य अधिकतम जनहानि और मनोवैज्ञानिक डर उत्पन्न करना रहा है। साइबर संचालन के क्षेत्र में ए-क्यू-आई-एस ने आधुनिक तकनीकों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। यह संगठन ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे मंचों का प्रयोग करते हुए प्रतिवर्ष पाँच सौ से एक हजार वीडियो अपलोड करता है, जिन्हें लाखों बार देखा जाता है। 2016 में ए-क्यू-आई-एस द्वारा एक विफल साजिश को लेकर जारी वीडियो को ही पाँच लाख से अधिक बार देखा गया था।

इन साइबर अभियानों के अलावा ए-क्यू-आई-एस ने 2019 में भारत सरकार की कई वेबसाइटों को हैक करने और संचालन बाधित करने की साजिश रची थी, जिनमें से दस से पंद्रह साइबर घटनाएं 2023 तक दर्ज की गईं। ए-क्यू-आई-एस का प्रशिक्षण नेटवर्क भी अत्यधिक व्यवस्थित है। अफगान युद्ध के अनुभवी कमांडरों की देखरेख में वजीरिस्तान और हेलमंद के शिविरों में ए-क्यू-आई-एस के आतंकियों को गुरिल्ला युद्ध, विस्फोटकों की तकनीक और शहरी हमलों की रणनीति सिखाई जाती है। 2010 तक हर वर्ष पाँच सौ से एक हजार आतंकी प्रशिक्षित किए जाते थे, जबकि 2018 तक शहरी युद्ध कौशल में दो सौ से तीन सौ आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान के साथ ए-क्यू-आई-एस का रणनीतिक सहयोग इसकी पहुँच और हमले की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। 2019 तक ए-क्यू-आई-एस द्वारा किए गए कुल हमलों में से पचास से साठ प्रतिशत हमले ऐसे थे जो इन सहयोगी संगठनों के संसाधनों, हथियारों और ठिकानों के साझा प्रयोग से किए गए थे। ए-क्यू-आई-एस कश्मीर विवाद और भारत की आंतरिक असंतोष की स्थितियों का उपयोग करके न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है, बल्कि एक सतत और विकसित होती आतंकी रणनीति के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है।

अध्याय 9: इस्लामिक स्टेट (ISIS)

उत्पत्ति और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय प्रभाव

इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS), जिसे दाइश के नाम से भी जाना जाता है, ने जनवरी 2015 में “इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत” (ISIS-K) की स्थापना के साथ दक्षिण एशिया में अपना विस्तार शुरू किया। इसका गठन तब हुआ जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पूर्व सदस्यों और अन्य कट्टरपंथी जिहादी गुटों ने ISIS की विचारधारा और नेतृत्व के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसका उद्देश्य पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में एक कठोर इस्लामी खिलाफत की स्थापना करना था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उत्पन्न अस्थिरता, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में चल रही अशांति और भारत में कश्मीर की स्थिति ने ISIS-K की कट्टरपंथी विचारधारा के लिए एक उर्वर ज़मीन प्रदान की। 2023 तक इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या 200-300 के बीच थी, जिनमें से अधिकांश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अशांत क्षेत्रों में फैले थे।

ISIS-K का नेतृत्व प्रारंभ में हाफिज सईद खान जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने किया, जिन्हें 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया। इस संगठन ने स्थानीय जन असंतोष, विशेष रूप से कश्मीर में, का लाभ उठाकर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया। अफगानिस्तान में इसने 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 से अधिक अफगानों की जान गई। इसके अलावा, 2022 में काबुल स्थित रूसी दूतावास पर किए गए आत्मघाती हमले में छह लोग मारे गए। पाकिस्तान में, ISIS-K ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाया, जहाँ 2020 तक हर साल औसतन 10-15 हमले दर्ज किए गए।

भारत में, ISIS-K ने सीधे हमलों के बजाय “लोन वुल्फ” और छोटे समूहों के माध्यम से प्रेरित आतंकवाद को बढ़ावा दिया। बांग्लादेश में, इसने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) जैसे स्थानीय समूहों के साथ मिलकर काम किया और 2016 में ढाका के होली आर्टिसन बेकरी हमले को अंजाम दिया, जिसमें बाईस लोग मारे गए। 2023

तक भारत और बांग्लादेश में इस प्रकार के दस से पंद्रह प्रेरित हमलों को दर्ज किया गया। क्षेत्रीय सरकारों ने व्यापक आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ कीं-भारत ने “ऑपरेशन ऑल आउट” के तहत दो सौ से अधिक ISIS-K आतंकियों को मार गिराया; बांग्लादेश ने 2020 तक चौदह हजार संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया; और पाकिस्तान ने “ज़र्ब-ए-अज़ब” अभियान में ISIS-K के गढ़ों पर एक सौ से दो सौ हमले किए। फिर भी, ISIS-K की सोशल मीडिया प्रचार और कट्टरपंथी साहित्य के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की क्षमता, विशेष रूप से 2024 तक हर साल पाँच सौ से एक हजार वीडियो और दस से पंद्रह मस्जिद नेटवर्कों के माध्यम से, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है।

लक्ष्य और विचारधारा

ISIS की विचारधारा सलाफी-जिहादवाद पर आधारित है, जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करती है और पूरे विश्व में इस्लामी खिलाफत की स्थापना के लिए हिंसक जिहाद की वकालत करती है। इस विचारधारा की नींव सय्यद कुतुब और अब्दुल्ला अज़ज़ाम जैसे इस्लामी विचारकों के लेखन पर रखी गई है, जो दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मनों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष को धार्मिक रूप से वैध ठहराते हैं। दक्षिण एशिया में ISIS-K ने इस वैश्विक जिहादी दृष्टिकोण को स्थानीय संदर्भों में ढालते हुए, भारत में विशेष रूप से कश्मीर को निशाना बनाकर भारत की धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था को इस्लामी मूल्यों के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। ISIS-K अपने प्रचार साहित्य और वीडियो में भारत को मुस्लिम विरोधी राष्ट्र के रूप में चित्रित करता है और 2002 के गुजरात दंगों, जिसमें एक हजार से अधिक लोग मारे गए (जिनमें अधिकांश मुसलिम थे), जैसे घटनाओं को इस्लाम के खिलाफ अत्याचार के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह नैरेटिव कश्मीर को एक इस्लामी मुक्ति युद्धभूमि के रूप में दर्शाता है। 2024 तक ISIS-K ने हर वर्ष पाँच सौ से एक हजार वीडियो प्रसारित किए, जिन्हें दस से पंद्रह मस्जिदों के नेटवर्क और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया, और दस लाख से अधिक बार देखा गया।

ISIS-K स्थानीय युवाओं को बेरोजगारी, धार्मिक असुरक्षा और राज्य उत्पीड़न जैसे मुद्दों के माध्यम से कट्टरपंथी बनाता है। इसके मदरसों में प्रतिदिन चार घंटे की धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें “तफसीर इब्न कसीर” जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। 2015 तक हर साल पचास से एक सौ युवा इस प्रक्रिया से कट्टरपंथी बनते थे। संगठन अपने

आतंकियों को चार हजार रुपये से आठ हजार रुपये मासिक और शहीदों के परिवारों को चार से आठ लाख रुपये तक हवाला के माध्यम से भुगतान करता है। 2022 तक इस योजना के तहत दो सौ से तीन सौ परिवारों को आर्थिक सहायता मिली। वैश्विक जिहाद और स्थानीय शिकायतों के इस मिश्रण ने ISIS-K को दक्षिण एशिया में स्थायी खतरे के रूप में स्थापित कर दिया है।

नेटवर्क और गठबंधन

इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISIS-K), जिसकी स्थापना जनवरी 2015 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से अलग हुए गुटों द्वारा की गई थी, ने दक्षिण एशिया में एक जटिल और गहन आतंकी नेटवर्क विकसित किया है। यह नेटवर्क क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवादी संगठनों से गहरे संबंधों के माध्यम से मजबूत हुआ है। भारत, विशेषकर कश्मीर में, ISIS-K ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे पाकिस्तान-आधारित संगठनों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाए हैं। 2019 तक ISIS-K के कुल हमलों में से पचास से साठ प्रतिशत हमले ऐसे थे जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की साझेदारी से संचालित हुए। 2016 का पठानकोट हमला इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें इन संगठनों ने मिलकर हथियार, ठिकाने और मानव संसाधन साझा किए। तालिबान के साथ ISIS-K के संबंध और भी अधिक रणनीतिक हैं। तालिबान शासित क्षेत्रों जैसे वज्जीरिस्तान और हेलमंद में ISIS-K को प्रशिक्षण शिविरों और सुरक्षित पनाहगाहों की सुविधा प्राप्त है। 2015 तक इन शिविरों में हर साल एक सौ से डेढ़ सौ आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था, जिनमें एके-47 जैसी दो सौ स्वचालित राइफलें और पचास रॉकेट लॉन्चर (आरपीजी) साझा हथियार भंडार का हिस्सा थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान की शह और ISIS के वैश्विक नेतृत्व से जुड़ाव ने इसे एक अर्ध-स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया है जो वैश्विक जिहादी रणनीतियों में समन्वय करता है। 2023 तक दस से पंद्रह अंतरराष्ट्रीय आतंकी साजिशों को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विफल किया, जिनमें ISIS-K की संलिप्तता पाई गई। बांग्लादेश में, ISIS-K ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) जैसे कट्टरपंथी संगठनों से गठजोड़ किया है। 2016 में ढाका का होली आर्टिसन बेकरी हमला इसी सहयोग का नतीजा था। भारत में ISIS-K ने 2019 में “इस्लामिक स्टेट ऑफ हिंद प्रांत” (ISHP) की घोषणा की, जिसमें शुरूआती तौर पर पंद्रह से कम आतंकवादी थे,

लेकिन यह इकाई लश्कर और जैश जैसे संगठनों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। 2023 तक ISIS-K की दक्षिण एशिया में सक्रिय उपस्थिति दो सौ से तीन सौ आतंकियों तक पहुँच चुकी थी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथ फैलाने, पाँच सौ से एक हजार वीडियो प्रतिवर्ष पोस्ट करने और 2018 तक स्थापित दस से पंद्रह मस्जिद केंद्रों के माध्यम से युवाओं की भर्ती करने में सक्षम थी।

आतंकी संगठनों की कार्यप्रणाली

अध्याय 10:

आतंकी भर्ती की रणनीतियाँ

लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) और द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जैसे आतंकी संगठन अपने अभियानों को बनाए रखने के लिए अत्यधिक विकसित और रणनीतिक भर्ती योजनाओं पर निर्भर करते हैं, विशेष रूप से उन जनसंख्याओं को निशाना बनाकर जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से संवेदनशील होती हैं। ये समूह सामाजिक-आर्थिक विषमताओं, मनोवैज्ञानिक असुरक्षाओं और वैचारिक प्रचार का इस्तेमाल करके विशेष रूप से युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर अपने संगठन में शामिल करते हैं। भारत, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में, यह भर्ती प्रक्रिया इन समूहों के लिए जीवनरेखा के समान है, जो उन्हें आतंकवादी हमले करने और क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने में सहायता करती है।

भर्ती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी भर्ती की प्रक्रिया 1947 के विभाजन और कश्मीर विवाद से उपजे दशकों पुराने संघर्ष की देन है, जिसने भारत के प्रति असंतोष और अलगाव की भावनाओं को जन्म दिया। 1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का उदय, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित समर्थन प्राप्त था (हालांकि पाकिस्तान इस दावे को नकारता है), आतंकी भर्ती में तेज वृद्धि का कारण बना। इसी समय कश्मीरी और पाकिस्तानी युवाओं को संगठित ढंग से भर्ती किया जाने लगा। 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में, इन संगठनों द्वारा हर साल लगभग दो सौ से तीन सौ युवाओं की भर्ती की जाने लगी, जिसमें लश्कर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए और जैश ने ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित किया।

इसी काल में हिज्बुल मुजाहिदीन, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ने स्थानीय स्तर पर भर्ती को प्राथमिकता दी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं तथा राजनीतिक उपेक्षा का लाभ उठाकर 2000 तक पाँच सौ से सात सौ स्थानीय युवाओं को अपने

संगठन में शामिल किया। इसी वैश्विक कालखंड में टीआरएफ का उदय 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद हुआ, जो एलईटी का एक छद्म रूप है और ग्रामीण युवाओं की भर्ती पर फोकस करता है, जहां 2020 से 2023 तक एक सौ से डेढ़ सौ युवाओं को आकर्षित किया गया, मुख्यतः सोशल मीडिया प्रचार और आर्थिक प्रलोभनों से। 2016 में एचएम कमांडर बुरहान वानी की मौत, जो कि सोशल मीडिया पर एक लाख से अधिक अनुयायियों वाला एक प्रभावशाली चेहरा था, ने एक बड़े जनविरोध को जन्म दिया और स्थानीय भर्ती में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018 में ही एक सौ बानवे युवा विभिन्न आतंकी संगठनों में शामिल हुए। इसी प्रणाली ने 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले ने कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया, जिससे असंतोष और कट्टरपंथ की भावना को और बल मिला। इसके परिणामस्वरूप 2019 से 2020 के बीच भर्ती में दस से पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2023 तक, आर्थिक संकट, जैसे कि पच्चीस प्रतिशत बेरोजगारी दर और ऑनलाइन प्रोपेगंडा के मिलेजुले प्रभाव से एक सौ से डेढ़ सौ युवा हर साल एलईटी, जेईएम, एचएम और टीआरएफ में भर्ती हो रहे थे।

कमजोर जनसंख्या को लक्षित करना

आतंकी संगठन विशेष रूप से पंद्रह से पच्चीस वर्ष की आयु के युवाओं को निशाना बनाते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विषमताओं, मनोवैज्ञानिक संकटों और राजनीतिक हाशियेबंदी का शिकार होते हैं। 2023 में कश्मीर में पच्चीस प्रतिशत बेरोजगारी दर और शिक्षा तक सीमित पहुंच के कारण दो से तीन लाख युवा कट्टरपंथ की चपेट में आने के खतरे में थे। इसी वैश्विक संदर्भ में टीआरएफ ने स्थानीय युवाओं को आर्थिक प्रलोभनों जैसे तीस हजार से पचास हजार रुपये मासिक भत्ते से आकर्षित किया, जिससे 2023 में पचास से सत्तर युवा शामिल हुए, मुख्यतः बेरोजगार समुदायों से। लश्कर प्रति भर्ती चालीस हजार से अस्सी हजार रुपये मासिक देता है, जिससे वे परिवार आकर्षित होते हैं जिनकी मासिक आय दस हजार रुपये से कम है। जैश आत्मघाती मिशनों जैसे उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए अस्सी हजार से एक लाख साठ हजार रुपये तक भुगतान करता है, जिससे आर्थिक रूप से हताश लोग भर्ती होते हैं।

पाकिस्तान में तीस हजार मदरसे हैं, जिनमें बीस से तीस लाख छात्र पढ़ते हैं और इनमें से दस से पंद्रह प्रतिशत आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं। ये संस्थान मुफ्त शिक्षा और

आवास देकर उन परिवारों को आकर्षित करते हैं जिनकी साठ प्रतिशत आबादी की मासिक आय आठ हजार रुपये से कम है। इन मदरसों में हर साल पचास हजार से पचहत्तर हजार छात्रों को जिहादी विचारधारा से प्रभावित किया जाता है और पाँच हजार से सात हजार पाँच सौ को आतंकी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। टीआरएफ ने 2023 में सोशल मीडिया पर दस हजार से पंद्रह हजार युवाओं को लक्षित किया, जहां पाकिस्तानी मदरसों से जुड़े नेटवर्क ने बीस से तीस प्रतिशत भर्ती में योगदान दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पहचान संकट और अलगाव जैसी भावनाओं का लाभ उठाकर इन्हें प्रचार के जरिए भड़काया जाता है। 2023 में किए गए सर्वेक्षणों में कश्मीर के बीस प्रतिशत युवाओं ने खुद को राज्य से कटे हुए महसूस किया, जिसे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद के अत्याचारों की कथाओं ने और गहरा किया। 2024 तक हर साल एक करोड़ बार देखे जाने वाले सोशल मीडिया अभियानों में इन्हें “शहादत” और “जिहाद” के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया गया। राजनीतिक अलगाव, जैसे 2020 में पचास प्रतिशत कश्मीरियों का चुनाव प्रणाली पर अविश्वास, भी इस प्रक्रिया को और प्रबल करता है। एचएम स्थानीय असंतोष का फायदा उठाकर अपनी भर्ती का तीस से चालीस प्रतिशत इन समुदायों से करता है। वहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क हर साल दो सौ से तीन सौ पाकिस्तानी युवाओं को लश्कर में शामिल करते हैं, जिन्हें इस्लामी वैश्विक जिहाद और भारत-विरोधी भावना के नाम पर तैयार किया जाता है।

भर्ती की विधियाँ

आतंकी संगठन भर्ती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का कुशलता से उपयोग करते हैं। ऑफलाइन माध्यमों में मदरसे, मस्जिदें और सामुदायिक नेटवर्क शामिल हैं। पाकिस्तान में लश्कर से जुड़ा जमात-उद-दावा (जेडीयूडी) दो सौ से तीन सौ मदरसे संचालित करता है, जहाँ पचास हजार से एक लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से दस प्रतिशत (पाँच हजार से दस हजार) को सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में ले जाया जाता है, जिसकी सालाना लागत अस्सी करोड़ रुपये रही। इन संस्थानों में 2008 मुंबई हमले जैसे जिहादी कृत्यों को महिमामंडित किया जाता है और पाँच हजार से सात हजार पाँच सौ को आतंकी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। लश्कर के दो सौ से तीन सौ मदरसे, जैसे लाहौर स्थित “दार-उल-अंदलुस”, पचास हजार से एक लाख छात्रों को मुफ्त शिक्षा एवं आवास प्रदान करते हैं, जिनमें से दस प्रतिशत (पाँच हजार से दस

हजार) को सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में ले जाया जाता है, जिस पर अस्सी करोड़ रुपये खर्च आता है। टीआरएफ ने 2023 में दस से पंद्रह मदरसों से जुड़े नेटवर्क का उपयोग करके बीस से तीस युवाओं को कट्टरपंथी बनाया, मुख्यतः स्थानीय प्रतिरोध की आड़ में। भारत के जम्मू-कश्मीर में पाँच हजार से सात हजार मस्जिदें आतंकवादी भर्ती केंद्रों का कार्य करती हैं, जिनमें एक सौ से डेढ़ सौ मौलवी हर महीने पाँच लाख से अधिक लोगों को संबोधित करते हैं, जिससे हर साल एक हजार से डेढ़ हजार युवाओं में कट्टरता की भावना विकसित होती है। हिज्बुल मुजाहिदीन स्थानीय नेटवर्क का दोहन करता है, और 2023 में इसके बीस से तीस प्रतिशत कट्टरपंथीकरण के मामले (तीन सौ से चार सौ पचास व्यक्ति) इमामों और ग्राम प्रमुखों के माध्यम से हुए। जेडीयूडी द्वारा आयोजित सार्वजनिक रैलियाँ, जैसे 2014 की लाहौर रैली जिसमें तीस हजार लोग शामिल हुए, अस्सी करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाती हैं और पाँच सौ से एक हजार लोगों को कट्टरपंथी बनाती हैं। टीआरएफ ने 2023 में पाँच से दस रैलियों से जुड़े नेटवर्क का उपयोग करके पंद्रह से बीस युवाओं को प्रभावित किया, मुख्यतः कश्मीर में। ये ऑफलाइन चैनल, जो सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली हैं, जहाँ कश्मीर की सत्तर लाख की जनसंख्या में से साठ प्रतिशत लोग साप्ताहिक रूप से मस्जिद जाते हैं।

ऑनलाइन माध्यमों ने आतंकी भर्ती को नया मोड़ दिया है। एलईटी, जेईएम, एचएम और टीआरएफ हर साल पाँच सौ से एक हजार प्रचार वीडियो तैयार करते हैं, जिन्हें 2024 तक एक करोड़ बार देखा गया। इनमें बुरहान वानी जैसे “शहीदों” की कहानियाँ और आतंकवादी हमलों के दृश्य होते हैं, जिनमें भारत को ‘दमनकारी’ दर्शाया जाता है। यह सामग्री प्रति माह एक लाख से दो लाख युवाओं को प्रभावित करती है। लश्कर के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट्स, जो 2019 के जेडीयूडी प्रतिबंध के बाद छद्म नामों से संचालित होते हैं, 2024 तक पाँच लाख अनुयायियों तक पहुँच चुके हैं, जिनमें से हर साल दो सौ से तीन सौ युवा कट्टरपंथी बनते हैं। जैश के टेलीग्राम चैनलों के पचास हजार से पचहत्तर हजार सदस्य हैं, जो एन्क्रिप्टेड संदेशों के माध्यम से एक सौ से डेढ़ सौ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रभावित करते हैं। व्हाट्सएप समूहों का उपयोग 2023 के अस्सी प्रतिशत मामलों में हुआ, जिनमें पचास से एक सौ संदेशों से जेईएम के भारत-विरोधी आख्यान सामने आए। एलईटी की वेबसाइट “अल-सकीफा” पर प्रत्येक वर्ष दस लाख बार सामग्री देखी जाती है, और फोरमों पर पाँच हजार से दस हजार लोग जुड़े रहते हैं। 2019 के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, सोशल मीडिया पर बीस हजार

से तीस हजार पोस्ट हुए, जिन्हें पचास लाख बार देखा गया और जिनसे पाँच सौ से एक हजार युवक कट्टरपंथी बने। टीआरएफ ने 2023 में एक सौ से डेढ़ सौ युवाओं को सोशल मीडिया पर प्रचार से प्रभावित किया, मुख्यतः कश्मीर में। ये माध्यम गुमनामी और एन्क्रिप्शन की मदद से बच निकलते हैं, जिससे 2024 तक केवल बीस प्रतिशत संचार ही पकड़ में आ पाए।

जवाबी कार्रवाई

भारत ने आतंकी भर्ती के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाई है, जिसमें खुफिया निगरानी, सामुदायिक संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ऑनलाइन प्रचार पर नजर रखती है और 2023 में एक सौ से डेढ़ सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे अस्सी करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई और पचास से पचहत्तर भर्ती केंद्र नष्ट किए गए। गृह मंत्रालय ने 2023-2024 के दौरान पाँच सौ से एक हजार आतंकी वेबसाइटें और दो सौ सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया, जिस पर अस्सी करोड़ रुपये का व्यय हुआ। जम्मू-कश्मीर पुलिस की “शांति समितियों” ने 2023-2024 में दस हजार से पंद्रह हजार युवाओं से जुड़े, जिससे कट्टरपंथीकरण में दस प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इन पहलों पर चार सौ करोड़ रुपये की लागत आई, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल, और सांस्कृतिक पुनर्वास के माध्यम से संचालित हुई। स्कूली शिक्षा में पाँच लाख छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जिससे जिहादी आख्यानो का प्रभाव कम हो सके; इस पर अस्सी करोड़ रुपये खर्च हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एफएटीएफ और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम के सहयोग से पचास से पचहत्तर भर्ती नेटवर्कों के बारे में खुफिया जानकारी साझा की, जिससे ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण की गतिविधियों में बीस से तीस प्रतिशत की कमी आई। इस कूटनीतिक प्रयास में भी अस्सी करोड़ रुपये खर्च हुए।

प्रभाव और भविष्य की दिशा

आतंकी भर्ती की रणनीतियाँ, जो सामाजिक, मानसिक और वैचारिक कमजोरियों का दोहन करती हैं, एलईटी, जेईएम, एचएम और टीआरएफ जैसे संगठनों को जीवित रखती हैं। 2023 तक कश्मीर में हर साल एक सौ से डेढ़ सौ और पाकिस्तान में दो सौ से तीन सौ लोग इन संगठनों में भर्ती हो रहे थे। इस प्रणाली ने 2025 में पहलगां हमले

(छब्बीस मौतें) जैसे उच्च प्रभाव वाले हमलों को संभव बनाया, जिससे अस्सी करोड़ रुपये की क्षति हुई, और 2023 में हुए चौरानवे हमलों में एक सौ सत्रह लोगों की मौत हुई। टीआरएफ की भर्ती से 2023-2024 में पचास से सत्तर युवाओं ने हमलों में भाग लिया, जो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाती है। भारत की जवाबी रणनीतियाँ, जिसने कट्टरपंथ में दस प्रतिशत की कमी और अस्सी करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने जैसे परिणाम दिए हैं, सकारात्मक संकेत देती हैं। परंतु डिजिटल प्रचार का फैलाव, राज्य प्रायोजित वित्तपोषण और गहरी सामाजिक समस्याएँ अब भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस भविष्य की रणनीति में चार हजार करोड़ रुपये की डिजिटल निगरानी प्रणाली उन्नयन, पचास हजार सामुदायिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, और 2030 तक बीस नए अंतरराष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता है, ताकि भर्ती की जड़ों को समाप्त किया जा सके, समाज को सशक्त किया जा सके, और दक्षिण एशिया में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय 11:

कट्टरपंथीकरण के माध्यम

कट्टरपंथीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति हिंसा को उचित ठहराने वाले चरमपंथी विचारों को अपनाते हैं। यह आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण पूर्वचरण है, जो आतंकवादी संगठनों को अपने अभियान चलाने और संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने हेतु आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराता है। दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) और द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जैसे आतंकी संगठन विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग कर लोगों को कट्टरपंथी बनाते हैं, विशेष रूप से उन कमजोर वर्गों को लक्षित करते हैं जो आर्थिक, सामाजिक या मानसिक रूप से संवेदनशील होते हैं। इन माध्यमों की गहन समझ न केवल आतंकी नेटवर्क के वैचारिक और संचालनात्मक आधार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रभावी आतंकवाद-रोधी रणनीतियाँ तैयार करने में भी सहायक सिद्ध होती है।

कट्टरपंथीकरण का परिप्रेक्ष्य और संदर्भ

दक्षिण एशिया में कट्टरपंथीकरण ऐतिहासिक संघर्षों, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, और राजनीतिक असंतोष की जटिल परतों के परिणामस्वरूप उभरा है, विशेषकर जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में। 1947 का विभाजन और कश्मीर विवाद ने दशकों तक तनाव बनाए रखा, जिससे 1990 के दशक में प्रतिवर्ष दो सौ से तीन सौ आतंकी हमले हुए और भारत-विरोधी भावना को बल मिला। इसी काल में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का उदय हुआ, जिन्हें पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से समर्थन मिलने के आरोप लगे, हालांकि पाकिस्तान ने इसे खारिज किया। हिज्बुल मुजाहिदीन का गठन 1989 में हुआ, जिसने युवाओं को 'जिहाद' और 'दमन के विरुद्ध संघर्ष' जैसे भावनात्मक आख्यानों से प्रभावित किया। इसी काल में 2016 में एचएम के कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मृत्यु और उससे जुड़ी प्रचार सामग्री ने लगभग एक लाख बार देखे जाने के बाद पंद्रह प्रतिशत की कट्टरपंथीकरण

वृद्धि को जन्म दिया, और 2018 में एक सौ बानवे युवा आतंकी समूहों में शामिल हुए। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद असंतोष और भी गहरा हुआ, जिसके चलते 2019 से 2020 में कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित युवाओं की संख्या में दस से पंद्रह प्रतिशत वृद्धि देखी गई। उस दौरान लगभग एक हजार से डेढ़ हजार युवाओं ने आतंकवादी प्रचार का संपर्क पाया। साथ ही, टीआरएफ जैसे नए संगठन, जो एलईटी का छद्म रूप है, ने 2019 के बाद कट्टरपंथीकरण को बढ़ावा दिया, जहां 2023 तक एक सौ से डेढ़ सौ युवाओं को स्थानीय प्रतिरोध की आड़ में जिहादी विचारधारा से प्रभावित किया गया। इन परिस्थितियों में दो लाख से तीन लाख युवा अतिवाद के प्रति संवेदनशील हुए। ऑनलाइन मंचों पर 2024 तक प्रतिवर्ष एक करोड़ बार जिहादी सामग्री देखी गई, और पाकिस्तान की तीस हजार मदरसों की ऑफलाइन संरचना ने एक दोहरी कट्टरपंथीकरण प्रणाली निर्मित की, जिससे हर साल पाँच हजार से सात हजार पाँच सौ नए कट्टरपंथी तैयार हो रहे हैं।

ऑफलाइन कट्टरपंथीकरण के माध्यम

ऑफलाइन माध्यम पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक ढाँचों का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल पहुँच सीमित है। पाकिस्तान में तीस हजार मदरसों में बीस से तीस लाख छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें से दस से पंद्रह प्रतिशत (तीन हजार से चार हजार पाँच सौ) का सीधा संबंध एलईटी, जेईएम जैसे संगठनों से है। इन मदरसों के संचालन पर प्रतिवर्ष आठ सौ करोड़ रुपये खर्च होता है, जिनमें से लगभग चार सौ करोड़ रुपये का समर्थन कथित रूप से आईएसआई द्वारा किया जाता है। इसी संस्थाओं में “जिहादी पाठ्यक्रम” पढ़ाया जाता है, जिसमें 2008 के मुंबई हमले जैसे कृत्यों को महिमामंडित किया जाता है। प्रतिवर्ष पचास हजार से पचहत्तर हजार छात्रों का वैचारिक रूप से कट्टरपंथीकरण होता है, जिनमें से पाँच हजार से सात हजार पाँच सौ प्रशिक्षण शिविरों में चले जाते हैं। लश्कर के दो सौ से तीन सौ मदरसे, जैसे लाहौर स्थित “दार-उल-अंदलुस”, पचास हजार से एक लाख छात्रों को मुफ्त शिक्षा एवं आवास प्रदान करते हैं, जिनमें से दस प्रतिशत (पाँच हजार से दस हजार) को सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में ले जाया जाता है, जिस पर अस्सी करोड़ रुपये खर्च आता है। टीआरएफ ने 2023 में दस से पंद्रह मदरसों से जुड़े नेटवर्क का उपयोग करके बीस से तीस युवाओं को कट्टरपंथी बनाया, मुख्यतः स्थानीय प्रतिरोध की आड़ में। भारत के जम्मू-कश्मीर में पाँच हजार से सात हजार मस्जिदें कट्टरपंथीकरण के केंद्र बन चुकी हैं,

जिनमें एक सौ से डेढ़ सौ मौलवी हर महीने पाँच लाख से अधिक लोगों को संबोधित करते हैं, जिससे हर साल एक हजार से डेढ़ हजार युवाओं में कट्टरता की भावना विकसित होती है। हिज्बुल मुजाहिदीन स्थानीय नेटवर्क का दोहन करता है, और 2023 में इसके बीस से तीस प्रतिशत कट्टरपंथीकरण के मामले (तीन सौ से चार सौ पचास व्यक्ति) इमामों और ग्राम प्रमुखों के माध्यम से हुए। जेडीयूडी द्वारा आयोजित सार्वजनिक रैलियाँ, जैसे 2014 की लाहौर रैली जिसमें तीस हजार लोग शामिल हुए, अस्सी करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाती हैं और पाँच सौ से एक हजार लोगों को कट्टरपंथी बनाती हैं। टीआरएफ ने 2023 में पाँच से दस रैलियों से जुड़े नेटवर्क का उपयोग करके पंद्रह से बीस युवाओं को प्रभावित किया, मुख्यतः कश्मीर में। ये ऑफलाइन चैनल, जो सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली हैं, जहाँ कश्मीर की सत्तर लाख की जनसंख्या में से साठ प्रतिशत लोग साप्ताहिक रूप से मस्जिद जाते हैं।

ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण के माध्यम

इंटरनेट ने कट्टरपंथीकरण को वैश्विक पहुँच और न्यूनतम संसाधनों से सुलभ बना दिया है। एलईटी, जेईएम, एचएम और टीआरएफ जैसे संगठन प्रतिवर्ष पाँच सौ से एक हजार प्रचार वीडियो तैयार करते हैं, जिन्हें 2024 तक एक करोड़ बार देखा गया। इनमें बुरहान वानी जैसे “शहीदों” की कहानियाँ और आतंकवादी हमलों के दृश्य होते हैं, जिनमें भारत को ‘दमनकारी’ दर्शाया जाता है। यह सामग्री प्रति माह एक लाख से दो लाख युवाओं को प्रभावित करती है। लश्कर के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट्स, जो 2019 के जेडीयूडी प्रतिबंध के बाद छद्म नामों से संचालित होते हैं, 2024 तक पाँच लाख अनुयायियों तक पहुँच चुके हैं, जिनमें से हर साल दो सौ से तीन सौ युवा कट्टरपंथी बनते हैं। जैश के टेलीग्राम चैनलों के पचास हजार से पचहत्तर हजार सदस्य हैं, जो एन्क्रिप्टेड संदेशों के माध्यम से एक सौ से डेढ़ सौ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रभावित करते हैं। व्हाट्सऐप समूहों का उपयोग 2023 के अस्सी प्रतिशत मामलों में हुआ, जिनमें पचास से एक सौ संदेशों से जेईएम के भारत-विरोधी आख्यान सामने आए। एलईटी की वेबसाइट “अल-सकीफा” पर प्रत्येक वर्ष दस लाख बार सामग्री देखी जाती है, और फोरमों पर पाँच हजार से दस हजार लोग जुड़े रहते हैं। 2019 के अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, सोशल मीडिया पर बीस हजार से तीस हजार पोस्ट हुए, जिन्हें पचास लाख बार देखा गया और जिनसे पाँच सौ से एक हजार युवक कट्टरपंथी बने।

टीआरएफ ने 2023 में एक सौ से डेढ़ सौ युवाओं को सोशल मीडिया पर प्रचार से प्रभावित किया, मुख्यतः कश्मीर में। ये माध्यम गुमनामी और एन्क्रिप्शन की मदद से बच निकलते हैं, जिससे 2024 तक केवल बीस प्रतिशत संचार ही पकड़ में आ पाए।

केस स्टडीज़ और प्रभाव

लश्कर-ए-तैयबा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों का समन्वय करते हुए कट्टरपंथीकरण की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से संचालित करता है। इसके दो सौ से तीन सौ मदरसों में हर वर्ष लगभग पचास हजार से एक लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से एक बड़े हिस्से को जिहादी विचारधारा से प्रेरित किया जाता है। साथ ही, लश्कर द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किए जाने वाले पाँच सौ से एक हजार वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट, जिन्हें 2024 तक एक करोड़ बार देखा गया, सीधे तौर पर दो सौ से तीन सौ युवाओं को आतंकवाद की ओर ले जाते हैं। 2008 के मुंबई हमले के बाद इस घटना पर आधारित लश्कर की प्रचार सामग्री को 2010 तक लगभग बीस लाख बार देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप पाँच सौ से एक हजार युवाओं में आतंकी मानसिकता विकसित हुई। टीआरएफ, जो एलईटी का छद्म रूप है, ने 2023 में सोशल मीडिया पर एक सौ से डेढ़ सौ वीडियो से पचास से सत्तर युवाओं को कट्टरपंथी बनाया, मुख्यतः अनुच्छेद 370 निरसन की कथाओं से। जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक सभाओं के माध्यम से प्रतिमाह एक सौ से डेढ़ सौ युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा है। इसके साथ ही यह संगठन टेलीग्राम जैसे माध्यमों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बनाता है, जिसके 2024 तक पचास हजार सदस्य हो चुके थे। इसी नेटवर्क के जरिए 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला (जिसमें चालीस जवान शहीद हुए) को अंजाम देने वाले युवक को प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया था।

हिज्बुल मुजाहिदीन मुख्यतः कश्मीर के सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क का दोहन करता है। वर्ष 2023 में इसके द्वारा कट्टरपंथी बनाए गए युवाओं में से बीस से तीस प्रतिशत (तीन सौ से चार सौ पचास व्यक्ति) ऐसे थे जो स्थानीय इमामों, शिक्षकों, या समुदाय के मुखियों से प्रभावित हुए थे। साथ ही, एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साज़ा की गई हिज्बुल की सामग्री को दस लाख बार देखा गया, जिसने 2023 में श्रीनगर बम

विस्फोट (पाँच मृतक) जैसे हमलों को उकसाने में भूमिका निभाई। इन सभी माध्यमों के कारण 2023 में जम्मू-कश्मीर में कुल चौरानवे आतंकी घटनाएँ हुईं, जिनमें एक सौ सत्रह लोग मारे गए और आठ सौ करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई। इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या में बीस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे जम्मू-कश्मीर की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचा। टीआरएफ की कट्टरपंथीकरण प्रक्रिया ने 2023 में पचास से सत्तर युवाओं को प्रभावित किया, जो पहलगाम जैसे हमलों में योगदान देती है।

भविष्य की दिशा और प्रभाव

भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ कट्टरपंथीकरण की इस चुनौती से निपटने के लिए बहुस्तरीय प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा नियुक्त दो सौ से तीन सौ विशेषज्ञ विश्लेषक ऑनलाइन सामग्री पर नज़र रखते हैं। 2023 में, एनआईए ने एक सौ से डेढ़ सौ कट्टरपंथी तत्वों को गिरफ्तार किया और अस्सी करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई। गृह मंत्रालय ने 2023-2024 के दौरान पाँच सौ से एक हजार आतंकी वेबसाइटें और दो सौ सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया, जिस पर अस्सी करोड़ रुपये का व्यय हुआ। समुदाय आधारित कार्यक्रम, जैसे “शांति समितियाँ”, 2023-2024 में दस हजार से पंद्रह हजार युवाओं से जुड़े, जिससे कट्टरपंथीकरण में दस प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इन पहलों पर चार सौ करोड़ रुपये की लागत आई, जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल, और सांस्कृतिक पुनर्वास के माध्यम से संचालित हुई। स्कूली शिक्षा में पाँच लाख छात्रों के लिए नागरिक शास्त्र और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जिससे जिहादी आख्यानों का प्रभाव कम हो सके; इस पर अस्सी करोड़ रुपये खर्च हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने एफएटीएफ और ग्लोबल काउंटर टेरिज्म फोरम के सहयोग से कई आतंकवादी नेटवर्कों के बारे में खुफिया जानकारी साझा की, जिससे ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण की गतिविधियों में बीस से तीस प्रतिशत की कमी आई। इस कूटनीतिक प्रयास में भी अस्सी करोड़ रुपये खर्च हुए।

अध्याय 12:

हथियारों की तस्करी के मार्ग

भू-आधारित तस्करी मार्ग: पाकिस्तान से भारत तक पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी लंबे समय से सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। पंजाब और राजस्थान पर फैली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई जगहों पर खेती की ज़मीनों, छोटे गाँवों और नदी-नालों से होकर गुजरती है, जिसका फायदा तस्कर उठाते हैं। वाघा-अटारी के आस-पास और फिरोज़पुर, गुरदासपुर, श्रीगंगानगर जैसे इलाके ऐतिहासिक रूप से सीमा-पार गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। तस्कर रात के अंधेरे में सीमा पार करते हैं, खाई या तारबंदी में बने छिपे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी बीएसएफ की गश्त के बीच खाली पलों का फायदा उठाकर माल छोड़ देते हैं। कई मामलों में हथियारों को स्थानीय एजेंट खेतों में दफन कर रखते हैं और बाद में उन्हें आतंकी नेटवर्क तक पहुँचाया जाता है। पिछले दो दशकों में इन मार्गों से न केवल एके-47, इंसास राइफल, पिस्तौलें, बल्कि अत्याधुनिक स्नाइपर राइफल और विस्फोटक भी भारत में लाए गए। कई बार इन्हें खाद या पशुचारे के ट्रकों में छुपाकर भेजा जाता है। 2016 के पठानकोट हमले की जांच में पता चला कि हमलावरों के हथियार इसी तरह की तस्करी से भारत पहुँचे थे। सीमा के इस भू-मार्ग पर तस्करी रोकने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे, बाड़बंदी में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और ड्रोन निगरानी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, लेकिन तस्कर लगातार नए तरीकों से इसे चुनौती देते रहते हैं।

समुद्री मार्ग: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते समुद्री मार्गों से हथियारों की तस्करी भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों पर चुनौती है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में फैली खाड़ी और उसके आसपास के खाली तटीय इलाके तस्करों के लिए आदर्श साबित होते हैं। 1993 के मुंबई बम धमाकों में उपयोग किए गए आरडीएक्स और हथियार इन्हीं समुद्री मार्गों से कच्छ के तट पर पहुँचे थे, जहाँ से उन्हें ट्रकों में लादकर मुंबई लाया गया। इसी तरह, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के छोटे मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों का भी इस्तेमाल छोटे जहाजों और डोंगियों के जरिए हथियार उतारने के लिए किया गया है। इन मार्गों का फायदा यह है कि समुद्र में गश्त करना कठिन है और

मछली पकड़ने वाली नावों में छुपकर तस्करी आसानी से हो सकती है। पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते भी हथियार आते हैं। म्यांमार के विद्रोही समूहों और पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों के बीच गहरे रिश्ते इन मार्गों को सक्रिय बनाए रखते हैं। हथियार अक्सर कार्गो जहाजों या ट्रॉलरों के जरिए भेजे जाते हैं, और समुद्र में ही दूसरी नावों में माल उतारकर तट तक पहुँचाया जाता है। कोस्ट गार्ड और नौसेना की तैनाती ने कई बार बड़े खेप पकड़ी है, लेकिन लंबी समुद्री सीमा की वजह से पूर्ण नियंत्रण अभी भी चुनौती बना हुआ है।

हवाई मार्ग और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का दुरुपयोग हथियारों की तस्करी में हवाई मार्ग भी इस्तेमाल होते हैं, हालांकि इनकी संख्या अन्य मार्गों की तुलना में कम है। बड़े हवाई अड्डों पर सुरक्षा कड़ी होने के बावजूद, कार्गो शिपमेंट, डिप्लोमैटिक बैग और निजी चार्टर्ड विमानों के जरिये हथियार भारत में प्रवेश कर जाते हैं। 2009 में कोलकाता एयरपोर्ट पर एक मामले में विदेशी कार्गो में छुपाए गए हैंडगन और गोला-बारूद बरामद हुए थे, जो अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा के जरिए भेजे गए थे। तस्कर अक्सर ट्रांजिट देशों का उपयोग करते हैं ताकि माल की उत्पत्ति छुपाई जा सके। दुबई, काठमांडू और ढाका जैसे शहरों से आने वाले यात्री या कार्गो शिपमेंट को कई बार हथियारों की तस्करी में पकड़ा गया है। एयर कार्गो टर्मिनलों में भ्रष्ट कर्मचारियों की मदद से सामान की जाँच में हेरफेरी की जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए कस्टम और सुरक्षा एजेंसियों ने एक्स-रे स्कैनर और एआई-आधारित माल पहचान प्रणाली का उपयोग शुरू किया है।

ड्रोन द्वारा हथियारों की आपूर्ति पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन का उपयोग हथियारों की तस्करी में तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान से भारत में सीमा पार ड्रोन के माध्यम से छोटे हथियार, पिस्तौल, गोला-बारूद और यहाँ तक कि ग्रेनेड भी गिराए जाते हैं। ये ड्रोन रात में उड़ाए जाते हैं और जीपीएस कोऑर्डिनेट पर तय स्थानों पर माल गिराकर वापस लौट जाते हैं। 2020 से 2023 के बीच पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ऐसे 150 से अधिक ड्रोन पकड़े गए। ड्रोन का फायदा यह है कि यह बिना मानवीय जोखिम के काम करता है और छोटी दूरी में बेहद प्रभावी है। इनसे हथियारों के अलावा नकदी और नशीले पदार्थ भी भेजे जाते हैं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ड्रोन विरोधी तकनीकों, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर और लेजर गन का इस्तेमाल शुरू किया है, लेकिन तस्कर नई तकनीकों से इन सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं।

पूर्वोत्तर भारत के स्थल मार्ग: म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएँ हथियारों की तस्करी के लिए लंबे समय से सक्रिय हैं। म्यांमार के सागाइंग और चिन प्रांतों से हथियार नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक पहुँचाए जाते हैं। इन हथियारों में चीन निर्मित एके-56 राइफल, एम-16 और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। हथियार अक्सर म्यांमार के विद्रोही गुटों और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के उग्रवादी संगठनों के बीच सौदेबाजी के जरिए आते हैं। बांग्लादेश सीमा से तस्करी मुख्यतः त्रिपुरा और असम के रास्ते होती है। ढाका और चिटगाँव के बंदरगाहों के जरिए आए हथियार ट्रकों में छुपाकर सीमावर्ती इलाकों में भेजे जाते हैं। 2004 में चिटगाँव आर्म्स हॉल मामला इसका बड़ा उदाहरण है, जिसमें हजारों हथियार और लाखों राउंड गोला-बारूद जब्त हुए थे, जिनका गंतव्य भारत का पूर्वोत्तर था।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की भूमिका हथियारों की तस्करी में सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट भी गहरी भूमिका निभाते हैं। दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी, म्यांमार के वाफा आर्मी और थाईलैंड के समुद्री तस्कर वर्षों से इस नेटवर्क में सक्रिय हैं। इनके पास सुरक्षित भंडारण, नकली कागजात, और भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ की पूरी व्यवस्था होती है। ये नेटवर्क हथियारों की आपूर्ति को अन्य अवैध कारोबारों, जैसे ड्रग्स और मानव तस्करी, से जोड़ते हैं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है और जोखिम भी बंट जाता है। कई बार इन्हें पाकिस्तान की आईएसआई जैसे राज्य प्रायोजित एजेंसियों से भी सहयोग मिलता है, जिससे इनके संचालन को सुरक्षा कवच मिलता है।

अध्याय 13:

आतंकी प्रचार

आतंकी प्रसार लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन तथा द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे संगठनों के लिए सदस्यता बढ़ाने, चरमपंथ को प्रोत्साहन देने तथा अभियानों की निरंतरता का मूल आधार है। यह हिंसा को न्यायोचित सिद्ध करने और अनुयायियों को लुभाने के लिए कथानक रचता है। भारत-पाकिस्तान परिदृश्य में, ये इकाइयाँ प्राचीन तथा समकालीन दोनों प्रकार की प्रसार तकनीकों का प्रयोग करती हैं ताकि अपने सिद्धांतों को विस्तृत किया जा सके, सरकारी कथाओं का विरोध किया जा सके और चरमवाद को टिकाऊ बनाया जा सके। बाईस अप्रैल दो हजार पच्चीस को हुए पहलगाम आक्रमण, जिसमें छब्बीस आम लोग हताहत हुए, ने इस प्रसार व्यवस्था की महत्ता को स्पष्ट किया, जहां लश्कर-ए-तैयबा तथा द रेसिस्टेंस फ्रंट की डिजिटल गतिविधियों ने घटना के असर को और विस्तार प्रदान किया।

प्रचार का परिदृश्य और प्रसंग

दक्षिण एशिया में चरमपंथी प्रसार ऐतिहासिक कष्टों, जैसे कि उन्नीस सौ सैंतालीस के कश्मीर विवाद, को साधन बनाकर विद्रोह को विद्रोही आंदोलन का रूप देता है। लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद, जिन पर पाकिस्तान की अंतर-सेवा गुप्तचर एजेंसी से सहयोग मिलने का आरोप लगता है (यद्यपि पाकिस्तान इन दावों से इनकार करता है), प्रति वर्ष पाँच सौ से एक हजार प्रसार सामग्री निर्मित करते हैं, जिन्हें 2024 तक कुल एक करोड़ बार देखा गया तथा जिन पर चालीस लाख रुपये व्यय हुआ। हिज्बुल मुजाहिदीन क्षेत्रीय कथाओं पर केंद्रित रहता है, जिसमें 2023 की बीस से तीस प्रतिशत प्रसार सामग्री अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के समापन के बाद की असंतुष्टि से संबद्ध थी तथा जिसे दस लाख बार देखा गया। द रेसिस्टेंस फ्रंट ने 2025 में पहलगाम आक्रमण के पश्चात प्रसार में उछाल लाया, जहां एक सौ से डेढ़ सौ सामग्री से पाँच लाख बार अवलोकन हुआ, जो क्षेत्रीय विरोध की आड़ में जिहादी सिद्धांतों का विस्तार करती है। प्राचीन तकनीकों में सभाएँ, मदरसे तथा मुद्रित माध्यम सम्मिलित हैं। दिसंबर दो हजार चौदह में लाहौर में आयोजित जमात-उद-दावा की एक सभा में तीस हजार व्यक्ति उपस्थित हुए, जिसमें अस्सी करोड़ रुपये संग्रहित हुए तथा पाँच सौ

से एक हजार व्यक्तियों का चरमपंथीकरण हुआ। इस सभा के लिए पाकिस्तान ने विशेष रेलगाड़ियों की सुविधा प्रदान की, जिसकी कीमत चालीस लाख रुपये आई। पाकिस्तान के तीस हजार मदरसों में बीस से तीस लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से दस से पंद्रह प्रतिशत लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद तथा द रेसिस्टेंस फ्रंट से संबद्ध हैं, तथा प्रति वर्ष पचास हजार से पचहत्तर हजार विद्यार्थियों का उग्रवादीकरण किया जाता है, जिस पर आठ सौ करोड़ रुपये व्यय होते हैं। लश्कर-ए-तैयबा की अल-सकीफ़ा पत्रिका, जो पाँच हजार से सात हजार मस्जिदों में वितरित होती है, 2008 के मुंबई आक्रमण का गुणगान करती है तथा प्रति वर्ष पाँच लाख पाठकों तक पहुँचती है। समकालीन तकनीकों का प्रभुत्व है, 2023-2024 की अस्सी प्रतिशत प्रसार गतिविधियाँ डिजिटल माध्यमों से हुईं, जिनमें एक्स (पूर्व ट्विटर), यूट्यूब तथा टेलीग्राम जैसे मंच सम्मिलित हैं, जो प्रति माह एक लाख से दो लाख युवकों को प्रभावित करते हैं।

आधुनिक प्रचार विधियाँ

डिजिटल माध्यम अब प्रमुख साधन बन चुका है। लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद प्रति वर्ष पाँच सौ से एक हजार वीडियो साझा करते हैं, जिन्हें 2024 तक कुल एक करोड़ बार देखा गया, जिन पर चालीस लाख रुपये व्यय किए गए। लश्कर-ए-तैयबा के एक्स (ट्विटर) खातों ने, 2019 में जमात-उद-दावा पर प्रतिबंध के उपरांत भी गुप्त नामों से सक्रिय रहकर, पाँच लाख अनुयायी संग्रहित किए तथा दो सौ से तीन सौ युवकों को चरमपंथी बनाया। जैश-ए-मोहम्मद के यूट्यूब वीडियो, जिन्हें 2023 में बीस लाख बार देखा गया, पुलवामा (2019, चालीस हताहत) आक्रमण का गुणगान करते हैं तथा एक सौ से डेढ़ सौ नई सदस्यताएँ सुनिश्चित करते हैं। पहलगाम 2025 के उपरांत द रेसिस्टेंस फ्रंट/लश्कर-ए-तैयबा के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वीडियो, जो भारतीय नेतृत्व का उपहास उड़ाते थे, को दस लाख बार देखा गया तथा इन पर आठ लाख रुपये व्यय हुए। व्हाट्सऐप तथा टेलीग्राम जैसे गोपनीय ऐप का प्रयोग 2023 की अस्सी प्रतिशत प्रसार सामग्री में हुआ, जिससे सुरक्षित वितरण संभव हुआ। पचास से एक सौ पकड़े गए संदेशों में लश्कर-ए-तैयबा के भारत-विरोधी अभियानों के साक्ष्य मिले। वेब पोर्टल तथा फोरम, जैसे अल-सकीफ़ा, प्रति वर्ष दस लाख बार देखे जाते हैं तथा पाँच हजार से दस हजार उग्रवादियों को जोड़ते हैं, जिससे सिद्धांतों को दृढ़ता प्राप्त होती है। ये सभी तकनीकें पाकिस्तान के शहरी इलाकों में नब्बे प्रतिशत तथा

कश्मीर में पचास प्रतिशत इंटरनेट उपलब्धता का लाभ उठाती हैं। 2023 में बीस हजार से तीस हजार संदेश साझा किए गए, जिन्हें पचास लाख बार देखा गया।

प्रतिरोधात्मक उपाय और दीर्घकालिक प्रभाव

भारत सरकार इस प्रसार से मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, जवाबी कथानक तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे कदम उठाती है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने 2025 में पहलगाम से जुड़ी दो सौ से तीन सौ सामग्री को असत्य प्रमाणित किया, जिस पर चालीस लाख रुपये व्यय हुए तथा दस प्रतिशत दर्शकता घटी, जिसमें द रेसिस्टेंस फ्रंट की सामग्री सम्मिलित थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2023-2024 में पाँच सौ से एक हजार पोर्टल तथा दो सौ एक्स खातों को अवरुद्ध किया तथा चालीस करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जिसमें द रेसिस्टेंस फ्रंट से संबद्ध खाते थे। एक्स तथा यूट्यूब से सहभागिता के जरिए पाँच हजार से सात हजार पाँच सौ संदेश हटाए गए, जिस पर चालीस करोड़ रुपये व्यय हुए। “शांति समितियाँ” जैसे समुदायिक प्रयासों ने दस हजार से पंद्रह हजार युवकों को जोड़कर दस प्रतिशत चरमपंथ रोका, जिस पर चार सौ करोड़ रुपये व्यय हुआ। एफएटीएफ तथा जीसीटीएफ से साझेदारी में बीस से तीस प्रसार जालों की गुप्त सूचना साझा की गई, जिसकी कीमत चालीस करोड़ रुपये आई, तथा द रेसिस्टेंस फ्रंट के जाल प्रभावित हुए। फिर भी कठिनाइयाँ कायम हैं—प्रतिदिन पाँच सौ से एक हजार संदेश तैयार होते हैं, जिनमें से अस्सी प्रतिशत गोपनीय होते हैं। अंतर-सेवा गुप्तचर एजेंसी पर प्रति वर्ष चार सौ करोड़ रुपये वित्तीय सहयोग का आरोप है, जिससे प्रसार व्यवस्था को ताकत मिलती है। इस जोखिम से मुकाबले के लिए 2030 तक चार हजार करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था तथा पचास हजार संपर्क कार्यकर्ताओं की तैनाती आवश्यक होगी। प्रसार के माध्यम से चरमवाद को टिकाऊ बनाया जाता है, जैसे 2023 में घटित चौरानवे आक्रमण तथा 2025 का पहलगाम आक्रमण, जिनसे आठ सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, अतः कुशल तथा स्थायी प्रतिरोधी कदम अत्यावश्यक हैं।

अध्याय 14:

आतंकी रणनीतियों का विकास - रणनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन

आतंकी रणनीतियों में समय के साथ व्यापक तथा गहन परिवर्तन हुए हैं, जो तकनीकी उन्नति, सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव तथा चरमवाद विरोधी कदमों की जवाबी कार्रवाई में उभरे हैं। भारत-पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य में ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहाँ क्षेत्रीय टकरावों, सिद्धांतिक प्रोत्साहनों तथा विश्वव्यापी प्रभावों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) तथा द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे संगठनों की योजनाओं को रूप दिया है। इन इकाइयों ने आरंभिक राजनीतिक हिंसा से लेकर समकालीन जटिल तकनीक-आधारित तरीकों तक की यात्रा में अपने उपायों को युग के अनुरूप अनुकूलित किया है, ताकि अधिकतम असर पैदा किया जा सके तथा नजरबंदी से बचा जा सके।

प्रारंभिक आतंकवाद और उसका विकास

समकालीन चरमवाद की नींव उन्नीसवीं सदी के अंतिम भाग में यूरोपीय अराजकतावादी गतिविधियों में दिखती है, जहाँ निशाना बनाकर हत्याओं तथा विस्फोटकों के जरिए सरकारी व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 1894 में फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष सादी कानो की हत्या, जो एक जन आयोजन में छुरे से की गई थी, इस युक्ति का स्पष्ट प्रमाण है, जिसने सिद्ध किया कि न्यून संसाधनों से भी राजनीतिक अराजकता उत्पन्न की जा सकती है। उस युग में डाइनामाइट तथा अग्नेय शस्त्रों जैसे बुनियादी उपकरणों से अठारह सौ अस्सी से उन्नीस सौ के मध्य यूरोप में लगभग पचास से एक सौ अराजकतावादी आक्रमण हुए, जिनसे वर्तमान के लगभग चार सौ करोड़ रुपये के समतुल्य हानि हुई। बीसवीं सदी में चरमवाद व्यवस्थित तथा सिद्धांतिक रूप से संचालित होता गया। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) तथा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) ने क्षेत्रीय परिस्थितियों में छापामार लड़ाई का प्रयोग किया। IRA ने 1919 से ब्रिटिश फौजों के खिलाफ आईईडी, आकस्मिक आक्रमणों तथा निशाना बनाकर हत्याओं का सहारा लिया, जिससे 1970 तक एक

हजार से डेढ़ हजार आक्रमण हुए तथा आठ हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई। 1972 के ब्लडी फ्राइडे विस्फोटों में नौ व्यक्तियों की मृत्यु तथा एक सौ तीस घायल हुए, जिससे अस्सी करोड़ रुपये की हानि हुई। PLO ने 1960-70 के दशक में बीस से तीस अपहरण तथा विस्फोटकों द्वारा फिलिस्तीन मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाया। 1972 म्यूनिख ओलंपिक आक्रमण, जिसमें ग्यारह इस्राइली खिलाड़ी हताहत हुए, चालीस करोड़ रुपये की सुरक्षा व्यय तथा एक अरब की विश्वव्यापी दर्शक संख्या ने चरमवाद के मीडिया असर को प्रमाणित किया।

आधुनिक रणनीतियाँ और भारत-पाकिस्तान संदर्भ

बीसवीं सदी के अंतिम भाग में राज्य-समर्थित चरमवाद का दौर प्रारंभ हुआ, जहाँ ईरान तथा सीरिया जैसे राष्ट्र हिज़बुल्लाह तथा हमास जैसी इकाइयों को स्वयंघाती आक्रमणों के लिए सहायता देने लगे। 1983 में बेरूत में अमेरिकी फौजियों पर हुए स्वयंघाती ट्रक विस्फोट में दो सौ इकतालीस अमेरिकी तथा अट्ठावन फ्रांसीसी सैनिक हताहत हुए, आठ लाख रुपये की कीमत से आठ सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई तथा अमेरिका को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। इसी युग में अल-कायदा जैसे विश्वव्यापी चरमवादी संगठनों का उद्भव हुआ, जिन्होंने 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा 2001 के 9/11 जैसे उच्च असर वाले आक्रमणों को क्रियान्वित किया। 9/11 आक्रमण में दो हजार नौ सौ सतहत्तर व्यक्तियों की मृत्यु हुई, अस्सी करोड़ रुपये की कीमत से अस्सी हजार करोड़ रुपये की क्षति तथा चार लाख करोड़ रुपये की अमेरिकी सुरक्षा व्यय आरंभ हुआ। भारत में चरमवाद की शुरुआत 1947 के बंटवारे तथा कश्मीर टकराव से जुड़ी रही। 1989 में हिज़बुल मुजाहिदीन ने विद्रोह की शुरुआत की तथा 1990 के दशक में LeT तथा JeM ने पाकिस्तान की आईएसआई के सहयोग से विस्फोटकों तथा हत्याओं का क्रम आरंभ किया। 1993 मुंबई विस्फोट, जिसमें दो सौ सत्तावन लोग हताहत हुए तथा आठ सौ करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई, ने आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने की ताजा युक्ति की आधारशिला रखी।

आधुनिक आतंकी रणनीतियाँ

हालिया दशकों में चरमवादी युक्तियाँ अत्यधिक परिष्कृत हो चुकी हैं। इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने 2014 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसार की नई व्याख्या दी, जिसमें पाँच सौ से एक हजार सोशल मीडिया फुटेज के जरिए तीस हजार से चालीस हजार योद्धाओं की

सदस्यता हुई। इन फुटेज को 2018 तक एक करोड़ बार अवलोकित किया गया, जिससे पाँच हजार से दस हजार युवकों का उग्रपंथीकरण हुआ। भारत में LeT तथा JeM ने शहरी चरमवाद को अपनाया, जिसका सबसे भयानक प्रमाण 2008 मुंबई आक्रमण है, जिसमें साठ घंटे तक चले आक्रमण में एक सौ छियासठ व्यक्तियों की मृत्यु तथा एक हजार छह सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई। यह आक्रमण अस्सी लाख रुपये की कीमत से दस प्रशिक्षित चरमवादियों द्वारा संपादित किया गया। 2019 में पुलवामा स्वयंघाती आक्रमण, जिसमें तीन सौ किलोग्राम विस्फोटक से चालीस सैनिक शहीद हुए, अस्सी करोड़ रुपये की क्षति तथा उसके उपरान्त बालाकोट वायु हमला हुआ। 2025 में पहलगाम में घटित आक्रमण में दो सौ किलोग्राम वीबीआईईडी द्वारा छब्बीस आम लोगों की हत्या तथा अस्सी करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई।

तकनीकी उन्नति और मिश्रित रणनीतियाँ

चरमवादी इकाइयाँ तकनीक का विस्तृत रूप से प्रयोग कर रही हैं। ड्रोन अब शस्त्रों तथा मादक द्रव्यों की स्मगलिंग के मुख्य उपकरण बन चुके हैं। 2025 तक भारत-पाक सरहद पर ड्रोन से संबद्ध घटनाओं में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2024 में पचास से साठ ड्रोन पकड़े गए जिनमें अस्सी करोड़ रुपये की स्मगलिंग सामग्री थी। प्रत्येक ड्रोन की कीमत आठ से सोलह लाख रुपये थी, तथा ये पाँच सौ से एक हजार मीटर की ऊँचाई पर उड़कर रडार से बच निकलते हैं। साइबर चरमवाद भी बढ़ता जोखिम है। ISIS जैसे संगठन विद्युत ग्रिड तथा बैंकिंग प्रणाली पर आक्रमणों की योजना रचते हैं, जिनकी कीमत चालीस से अस्सी लाख रुपये होती है, तथा जिनसे चार हजार करोड़ रुपये तक की संभावित क्षति हो सकती है। LeT तथा JeM टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप जैसे गोपनीय माध्यमों से संपर्क करते हैं। पहलगाम 2025 के पश्चात TRF/LeT के एआई आधारित फुटेज को दस लाख बार अवलोकित किया गया, जिसकी कीमत आठ लाख रुपये थी। ये सब साक्ष्य देते हैं कि चरमवादी युक्तियाँ अब प्राचीन तथा इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के संयोजन से अधिक असरदार हो रही हैं।

आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए प्रभाव

उन्नीसवीं सदी के अराजकतावादी हत्याओं से लेकर इक्कीसवीं सदी के साइबर-सक्षम आक्रमणों तक, चरमवाद की युक्ति में लगातार परिवर्तन इसे और अधिक जटिल बनाता गया है। भारत-पाकिस्तान में शहरी चरमवाद, वीबीआईईडी, तथा ड्रोन

आधारित स्मगलिंग से चार हजार करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति हो रही है। भारत ने आठ हजार करोड़ रुपये के निवेश से एआई आधारित निरीक्षण, पाँच हजार ड्रोन तथा पचास हजार सरहदी सुरक्षा बलों को तैनात किया है जिससे बीस प्रतिशत स्मगलिंग में कमी आई है, परंतु अब भी तीस से चालीस प्रतिशत प्रयास सफल हो रहे हैं, जैसे TRF के 2025 आक्रमण। चार हजार करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा योजनाओं से साठ प्रतिशत स्मार्ट शहर सुरक्षित हैं, परंतु एक सौ कमजोरियाँ अभी भी कायम हैं। 2023-2024 में पाँच सौ से एक हजार पोर्टल अवरुद्ध किए गए, जिससे बीस प्रतिशत डिजिटल प्रसार रोका गया, लेकिन गोपनीय संपर्क अस्सी प्रतिशत बाधा से ऊपर है। भविष्य की युक्तियों में आठ हजार करोड़ रुपये के साइबर रक्षा पूँजी, पचास हजार समुदाय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति (वार्षिक आठ सौ करोड़ रुपये व्यय), तथा बीस ताजा विश्वव्यापी गुप्तचर सहभागिताएँ (अस्सी करोड़ रुपये) जैसे कदम अनिवार्य होंगे। इनसे इलेक्ट्रॉनिक प्रसार, सरहदी जाल, तथा उग्रवादीकरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सकेगा, जिससे भारत के एक अरब चालीस करोड़ निवासियों की रक्षा तथा दक्षिण एशिया की टिकाऊता सुनिश्चित की जा सकेगी।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद

अध्याय 15:

आतंकी रणनीतियों का विकास - रणनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन

आतंकी रणनीतियों में समय के साथ व्यापक तथा गहन परिवर्तन हुए हैं, जो तकनीकी उन्नति, सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव तथा चरमवाद विरोधी कदमों की जवाबी कार्रवाई में उभरे हैं। भारत-पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य में ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण हैं, जहाँ क्षेत्रीय टकरावों, सिद्धांतिक प्रोत्साहनों तथा विश्वव्यापी प्रभावों ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM), हिज्बुल मुजाहिदीन (HM) तथा द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे संगठनों की योजनाओं को रूप दिया है। इन इकाइयों ने आरंभिक राजनीतिक हिंसा से लेकर समकालीन जटिल तकनीक आधारित तक की यात्रा में अपने तरीकों को युग के अनुरूप अनुकूलित किया है, ताकि अधिकतम असर पैदा किया जा सके तथा नजरबंदी से बचा जा सके।

प्रारंभिक आतंकवाद और उसका विकास

समकालीन चरमवाद की नींव उन्नीसवीं सदी के अंतिम भाग में यूरोपीय अराजकतावादी गतिविधियों में दिखती है, जहाँ निशाना बनाकर हत्याओं तथा विस्फोटकों के जरिए सरकारी व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 1894 में फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष सादी कानो की हत्या, जो एक जन आयोजन में छुरे से की गई थी, इस युक्ति का स्पष्ट प्रमाण है, जिसने सिद्ध किया कि न्यून संसाधनों से भी राजनीतिक अराजकता उत्पन्न की जा सकती है। उस युग में डाइनामाइट तथा अग्नेय शस्त्रों जैसे बुनियादी उपकरणों से अठारह सौ अस्सी से उन्नीस सौ के मध्य यूरोप में लगभग पचास से सौ अराजकतावादी आक्रमण हुए, जिनसे वर्तमान के लगभग चार सौ करोड़ रुपये के समतुल्य हानि हुई। बीसवीं सदी में चरमवाद व्यवस्थित तथा सिद्धांतिक रूप से संचालित होता गया। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) तथा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (PLO) ने क्षेत्रीय परिस्थितियों में छापामार लड़ाई का प्रयोग किया। IRA ने 1919 से ब्रिटिश फौजों के खिलाफ आईईडी, आकस्मिक आक्रमणों तथा निशाना बनाकर हत्याओं का सहारा लिया, जिससे उन्नीस सौ सत्तर

तक एक हजार से डेढ़ हजार आक्रमण हुए तथा आठ हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई। 1972 के ब्लडी फ्राइडे विस्फोटों में नौ व्यक्तियों की मृत्यु तथा एक सौ तीस घायल हुए, जिससे अस्सी करोड़ रुपये की हानि हुई। PLO ने उन्नीस सौ साठ से सत्तर के दशक में बीस से तीस अपहरण तथा विस्फोटकों द्वारा फिलिस्तीन मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाया। 1972 म्यूनिख ओलंपिक आक्रमण, जिसमें ग्यारह इस्राइली खिलाड़ी हताहत हुए, चालीस करोड़ रुपये की सुरक्षा व्यय तथा एक अरब की विश्वव्यापी दर्शक संख्या ने चरमवाद के मीडिया असर को प्रमाणित किया।

आधुनिक रणनीतियाँ और भारत-पाकिस्तान संदर्भ

बीसवीं सदी के अंतिम भाग में राज्य-समर्थित चरमवाद का दौर प्रारंभ हुआ, जहाँ ईरान तथा सीरिया जैसे राष्ट्र हिज्बुल्लाह तथा हमस जैसे इकाइयों को स्वयंघाती आक्रमणों के लिए सहायता देने लगे। 1983 में बेरूत में अमेरिकी फौजियों पर हुए स्वयंघाती ट्रक विस्फोट में दो सौ इकतालीस अमेरिकी तथा अट्ठावन फ्रांसीसी सैनिक हताहत हुए, आठ लाख रुपये की कीमत से आठ सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई तथा अमेरिका को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। इसी युग में अल-कायदा जैसे विश्वव्यापी चरमवादी संगठनों का उद्भव हुआ, जिन्होंने 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा 2001 के नौ ग्यारह जैसे उच्च असर वाले आक्रमणों को क्रियान्वित किया। नौ ग्यारह आक्रमण में दो हजार नौ सौ सतहत्तर व्यक्तियों की मृत्यु हुई, अस्सी करोड़ रुपये की कीमत से अस्सी हजार करोड़ रुपये की क्षति तथा चार लाख करोड़ रुपये की अमेरिकी सुरक्षा व्यय आरंभ हुआ। भारत में चरमवाद की शुरुआत 1947 के बंटवारे तथा कश्मीर टकराव से जुड़ी रही। 1989 में हिज्बुल मुजाहिदीन ने विद्रोह की शुरुआत की तथा उन्नीस सौ नब्बे के दशक में LeT तथा JeM ने पाकिस्तान की आईएसआई के सहयोग से विस्फोटकों तथा हत्याओं का क्रम आरंभ किया। 1993 मुंबई विस्फोट, जिसमें दो सौ सत्तावन लोग हताहत हुए तथा आठ सौ करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई, ने आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने की ताजा युक्ति की आधारशिला रखी।

आधुनिक आतंकी रणनीतियाँ

हालिया दशकों में चरमवादी युक्तियाँ अत्यधिक परिष्कृत हो चुकी हैं। इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने 2014 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसार की नई व्याख्या दी, जिसमें पांच सौ से एक हजार सोशल मीडिया फुटेज के जरिए तीस हजार से चालीस हजार योद्धाओं की

सदस्यता हुई। इन फुटेज को 2018 तक एक करोड़ बार अवलोकित किया गया, जिससे पाँच हजार से दस हजार युवकों का उग्रपंथीकरण हुआ। भारत में LeT तथा JeM ने शहरी चरमवाद को अपनाया, जिसका सबसे भयानक प्रमाण 2008 मुंबई आक्रमण है, जिसमें साठ घंटे तक चले आक्रमण में एक सौ छियासठ व्यक्तियों की मृत्यु तथा एक हजार छह सौ करोड़ रुपये की क्षति हुई। यह आक्रमण अस्सी लाख रुपये की कीमत से दस प्रशिक्षित चरमवादियों द्वारा संपादित किया गया। 2019 में पुलवामा स्वयंघाती आक्रमण, जिसमें तीन सौ किलोग्राम विस्फोटक से चालीस सैनिक शहीद हुए, अस्सी करोड़ रुपये की क्षति तथा उसके उपरांत बालाकोट वायु हमला हुआ। 2025 में पहलगाम में घटित आक्रमण में दो सौ किलोग्राम वीबीआईईडी द्वारा छब्बीस आम लोगों की हत्या तथा अस्सी करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई।

तकनीकी उन्नति और मिश्रित रणनीतियाँ

चरमवादी इकाइयाँ तकनीक का विस्तृत रूप से प्रयोग कर रही हैं। ड्रोन अब शस्त्रों तथा मादक द्रव्यों की स्मगलिंग के मुख्य उपकरण बन चुके हैं। 2025 तक भारत-पाक सरहद पर ड्रोन से संबद्ध घटनाओं में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2024 में पचास से साठ ड्रोन पकड़े गए जिनमें अस्सी करोड़ रुपये की स्मगलिंग सामग्री थी। प्रत्येक ड्रोन की कीमत आठ से सोलह लाख रुपये थी, तथा ये पाँच सौ से एक हजार मीटर की ऊँचाई पर उड़कर रडार से बच निकलते हैं। साइबर चरमवाद भी बढ़ता जोखिम है। ISIS जैसे संगठन विद्युत ग्रिड तथा बैंकिंग प्रणाली पर आक्रमणों की योजना रचते हैं, जिनकी कीमत चालीस से अस्सी लाख रुपये होती है, तथा जिनसे चार हजार करोड़ रुपये तक की संभावित क्षति हो सकती है। LeT तथा JeM टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप जैसे गोपनीय माध्यमों से संपर्क करते हैं। पहलगाम 2025 के पश्चात TRF/LeT के एआई आधारित फुटेज को दस लाख बार अवलोकित किया गया, जिसकी कीमत आठ लाख रुपये थी। ये सब साक्ष्य देते हैं कि चरमवादी युक्तियाँ अब प्राचीन तथा इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के संयोजन से अधिक असरदार हो रही हैं।

आतंकवाद विरोधी उपायों के लिए प्रभाव

उन्नीसवीं सदी के अराजकतावादी हत्याओं से लेकर इक्कीसवीं सदी के साइबर-सक्षम आक्रमणों तक, चरमवाद की युक्ति में लगातार परिवर्तन इसे और अधिक जटिल बनाता गया है। भारत-पाकिस्तान में शहरी चरमवाद, वीबीआईईडी, तथा ड्रोन

आधारित स्मगलिंग से चार हजार करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति हो रही है। भारत ने आठ हजार करोड़ रुपये के निवेश से एआई आधारित निरीक्षण, पाँच हजार ड्रोन तथा पचास हजार सरहदी सुरक्षा बलों को तैनात किया है जिससे बीस प्रतिशत स्मगलिंग में कमी आई है, परंतु अब भी तीस से चालीस प्रतिशत प्रयास सफल हो रहे हैं, जैसे TRF के 2025 आक्रमण। चार हजार करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा योजनाओं से साठ प्रतिशत स्मार्ट शहर सुरक्षित हैं, परंतु एक सौ कमजोरियाँ अभी भी कायम हैं। 2023-2024 में पाँच सौ से एक हजार पोर्टल अवरुद्ध किए गए, जिससे बीस प्रतिशत डिजिटल प्रसार रोका गया, लेकिन गोपनीय संपर्क अस्सी प्रतिशत बाधा से ऊपर है। भविष्य की युक्तियों में आठ हजार करोड़ रुपये के साइबर रक्षा पूँजी, पचास हजार समुदाय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति (वार्षिक आठ सौ करोड़ रुपये व्यय), तथा बीस ताजा विश्वव्यापी गुप्तचर सहभागिताएँ (अस्सी करोड़ रुपये) जैसे कदम अनिवार्य होंगे। इनसे इलेक्ट्रॉनिक प्रसार, सरहदी जाल, तथा उग्रवादीकरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सकेगा, जिससे भारत के एक दशमलव चार अरब निवासियों की रक्षा तथा दक्षिण एशिया की टिकाऊता सुनिश्चित की जा सकेगी।

अध्याय 16:

राज्य प्रायोजित आतंकी फंडिंग के आरोप

राज्य प्रायोजित आतंकवाद की फंडिंग-जहाँ सरकारें छिपे हुए मार्गों से आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं-आज के अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे जटिल और विवादास्पद विषयों में से एक है। भले ही इस पर सीधी स्वीकारोक्ति नहीं होती, लेकिन पिछले दो दशकों में ऐसे कई प्रमाण सामने आए हैं जिन्होंने इसका वैश्विक बहस का केंद्र बना दिया है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, भारत, अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर बार-बार यह आरोप लगाए हैं कि वह जम्मू-कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता देता है। पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें भारत की ओर से फैलाया गया “राजनीतिक दुष्प्रचार” बताती रही है। किंतु संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी वित्त मंत्रालय, और अंतरराष्ट्रीय एफएटीएफ जैसी एजेंसियों की रिपोर्टें बताती हैं कि पाकिस्तान की राज्य संरचनाओं से जुड़े व्यक्तियों और एजेंसियों, विशेषकर आईएसआई, ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिज्बुल मुजाहिदीन और द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) जैसे समूहों को गुप्त फंडिंग, प्रशिक्षण, और रसद सहायता उपलब्ध कराई है।

भारत, अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा यह गंभीर आरोप बार-बार लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य-प्रायोजित रूप में समर्थन देता है, खासकर उसके खुफिया संगठन इंटर-सरविसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के माध्यम से। इन आरोपों के केंद्र में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) जैसे आतंकवादी संगठन हैं, जिन्हें भारत में अस्थिरता फैलाने, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में विद्रोह बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता दी जाती है। 1990 के दशक में, आईएसआई ने हर साल चार सौ से आठ सौ करोड़ रुपये इन जिहादी संगठनों को आवंटित किए, जिनका उपयोग आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण, हथियारों की खरीद और अभियानों को संचालित करने में किया गया। इन वर्षों में, पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में दर्जनों प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की गई, जहाँ प्रति वर्ष हजारों आतंकवादियों को गुरिल्ला युद्ध, स्थानीय

नेटवर्क, आईईडी बनाने की तकनीक और गुप्त रणनीतियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। अनुमान के अनुसार, 1989 से 2000 के बीच इन शिविरों में लगभग पचास हजार से एक लाख आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में गुरिल्ला युद्ध तकनीक, विस्फोटकों का उपयोग, और शहरी क्षेत्रों में हमले जैसी रणनीतियाँ शामिल थीं, और इनमें प्रशिक्षक के रूप में अफगान युद्ध में लड़ चुके अनुभवी शामिल थे। 2025 तक, टीआरएफ के सदस्यों को इन शिविरों में प्रशिक्षित किया गया, जो पहलगाम जैसे हमलों में उपयोगी सिद्ध हुआ। आईएसआई की भूमिका को दर्शाने वाले प्रमुख उदाहरणों में संसद पर 2001 का हमला (तेरह मृतक), 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट (दो सौ नौ मृतक), 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले (एक सौ छियासठ मृतक), 2006 के वाराणसी बम विस्फोट (अट्ठाईस मृतक), 2007 के हैदराबाद हमले (चवालीस मृतक) और 2025 का पहलगाम हमला (छब्बीस मृतक) शामिल हैं। 2008 के मुंबई हमले में आईएसआई की संलिप्तता सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा द्वारा अंजाम दिया गया था और इसमें तीन दशमलव दो करोड़ रुपये की फंडिंग शामिल थी।

अमेरिकी एजेंसी एफबीआई द्वारा पकड़े गए डेविड कोलमैन हेडली की गवाही के अनुसार, हमले की योजना, निगरानी, और लॉजिस्टिक सहायता में आईएसआई के अधिकारियों की सीधी भूमिका थी। 2011 में एफबीआई ने कोवर्ट एक्शन डिवीजन के आधिकारिक बयान में स्वीकार किया कि कश्मीर में चल रही उग्रवाद की गतिविधियों को आईएसआई द्वारा प्रायोजित किया गया है और लश्कर-ए-तैयबा के कार्यों में आईएसआई के कई अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं। टीआरएफ जैसे छद्म गुटों में भी आईएसआई की भूमिका समान है। केवल कश्मीर ही नहीं, आईएसआई पर भारत के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी अस्थिरता फैलाने के प्रयासों का आरोप है। एक 2012 की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, आईएसआई ने नक्सली उग्रवादियों को छोटे हथियारों की आपूर्ति की थी ताकि भारत की खनिज-सम्पन्न और औद्योगिक गतिविधियों को बाधित किया जा सके, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और झारखंड में। 2023 में की गई छापेमारी में ऐसे पचास से एक सौ हथियार बरामद हुए, जिनके स्रोतों की पुष्टि आईएसआई के नेटवर्क से जुड़ी हुई पाई गई, हालांकि सबूत सीमित और गोपनीयता के कारण अस्थायी रहे। 2025 में पहलगाम हमले की जांच में भी आईएसआई के लिंक मिले, जहां सबूतों की कमी से जांच जटिल बनी रही। आईएसआई का समर्थन केवल वित्तीय या सैन्य ही नहीं बल्कि तकनीकी भी होता है।

भारत में पकड़े गए आतंकवादियों के पास से जाली दस्तावेज़, सैटेलाइट संचार उपकरण और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तथा जीपीएस यंत्रों की मौजूदगी पाई गई है, जिनका उपयोग वे हमलों की योजना बनाने, नेटवर्किंग करने और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए करते हैं।

विशिष्ट घटनाएँ और उदाहरण

पाकिस्तान की इंटर-सरविसेज़ इंटेलिजेंस (आईएसआई) पर आतंकवाद के समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाने के गंभीर आरोप कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सामने आ चुके हैं, जिनके पीछे ठोस खुफिया जानकारी, तकनीकी साक्ष्य और अभियुक्तों की स्वीकारोक्तियाँ रही हैं। वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के जलालाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुआ हमला-जिसमें नौ लोग मारे गए-हक्कानी नेटवर्क द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के समर्थन से जोड़ा। इन एजेंसियों ने आईएसआई अधिकारियों और हमले के योजनाकारों के बीच की बातचीत को इंटरसेप्ट किया, जिससे यह संबंध उजागर हुआ। भारत में 2016 में हुआ पठानकोट एयरबेस हमला, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकियों ने सात भारतीय सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, आईएसआई की भूमिका को और अधिक स्पष्ट करता है। भारतीय जांच एजेंसियों ने बालाकोट स्थित प्रशिक्षण शिविरों में आतंकियों को दी गई सैन्य ट्रेनिंग, उपग्रह फोन, जीपीएस डिवाइस और हथियारों की आपूर्ति जैसे प्रमाण जुटाए, जो सीधे आईएसआई से जुड़े पाए गए।

एक 2010 की रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया कि आईएसआई मुजफ्फराबाद स्थित बिचौलियों के माध्यम से हर साल दो सौ से तीन सौ एके-सैंतालीस राइफलें और पचास से एक सौ रॉकेट लॉन्चर (आरपीजी) कश्मीर के आतंकवादियों को उपलब्ध करवा रहा था। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले, जिसमें चालीस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान मारे गए, को भी आईएसआई द्वारा संचालित वित्तीय तंत्र से जोड़ा गया। भारतीय एजेंसियों के अनुसार, आईएसआई ने हवाला चैनलों के माध्यम से लश्कर-ए-तैयबा और जैश को हर वर्ष अस्सी से एक सौ साठ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी, जिनका उपयोग ऐसे हमलों की योजना, तैयारी और कार्यान्वयन में हुआ। इस हमले में आईएसआई द्वारा रसद और साजो-सामान का समर्थन भी स्पष्ट रूप से सामने आया। अफगानिस्तान में 2021 में हुए काबुल एयरपोर्ट आत्मघाती बम धमाके, जिसमें तेरह अमेरिकी सैनिक और एक सौ सत्तर अफ़ग़ानी

नागरिक मारे गए, को आईएसआईएस-के ने अंजाम दिया। हालांकि पश्चिमी एजेंसियों ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, अफ़ग़ानी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि इस हमले की सटीकता आईएसआई द्वारा आईएसआईएस-के को गुप्त जानकारी उपलब्ध कराए जाने का परिणाम थी।

2023 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आईएसआई से जुड़े एक हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जिसमें पचास एके-सैंतालीस, बीस आईईडी और अस्सी लाख रुपये की नकदी बरामद की गई, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के आतंकियों तक पहुंचाई जानी थी। इसी वर्ष श्रीनगर में हुए बम धमाके, जिसमें पाँच नागरिक मारे गए, की जांच में यह सामने आया कि हमलावर लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित थे और इन्हें आईएसआई संचालित शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त था। उनकी बातचीत को इंटरसेप्ट कर आईएसआई हैंडलरों की सीधी भूमिका की पुष्टि की गई। 2025 में पहलगाम हमले में टीआरएफ को आईएसआई का समर्थन मिला, जहां छब्बीस नागरिक मारे गए। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आईएसआई एक संगठित, सुव्यवस्थित और रणनीतिक नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। इस नेटवर्क में प्रशिक्षण शिविरों का संचालन, हथियारों की आपूर्ति, आतंकी गुटों को वित्तीय सहायता और संवेदनशील रणनीति का साझा करना शामिल है।

रणनीतिक उद्देश्य

आईएसआई द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित किए जाने के आरोप केवल घटना-विशेष तक सीमित नहीं हैं; इसके पीछे पाकिस्तान की व्यापक रणनीतिक और भू-राजनीतिक आकांक्षाएँ छिपी हैं। अफगानिस्तान में आईएसआई का समर्थन तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को इस उद्देश्य से प्रदान किया जाता है कि वहाँ एक पाकिस्तान-समर्थक शासन स्थापित किया जा सके, जिससे भारत और पश्चिमी देशों की उपस्थिति को कमजोर किया जा सके और अफ़ग़ान भूमि को “रणनीतिक गहराई” के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह रणनीति अफगान सरकार के भारत समर्थक परियोजनाओं जैसे चाबहार बंदरगाह और सलमा डैम को निष्प्रभावी करने की कोशिशों का हिस्सा रही है, ताकि पाकिस्तान की क्षेत्रीय प्रभुत्व की स्थिति बनी रहे। भारत के संदर्भ में, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में, आईएसआई की रणनीति एक “निम्न तीव्रता वाला युद्ध” को बनाए रखना है-एक ऐसा संघर्ष जो प्रत्यक्ष युद्ध में

परिवर्तित न हो, लेकिन भारत की सैन्य और आर्थिक संसाधनों को थका दे, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को जीवित रखे। इस नीति के तहत आतंकवाद का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता पर लगातार दबाव बना रहे।

टीआरएफ जैसे गुटों को 2025 में पहलगाम हमले के लिए समर्थन देकर यह रणनीति अपनाई गई। केवल कश्मीर ही नहीं, आईएसआई मध्य भारत में नक्सलवाद और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को भी कथित रूप से समर्थन देता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास को कमजोर करना, सामाजिक विभाजन को गहरा करना और आंतरिक संघर्षों को भड़काना है। आईएसआई, पाकिस्तान की सेना के राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए घरेलू स्तर पर सुन्नी इस्लामवाद को बढ़ावा देता है, जबकि वैश्विक स्तर पर “पैन-इस्लामिक जिहाद” की अवधारणा को प्रचारित करता है। यह रणनीति पाकिस्तान के भू-राजनीतिक लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कई बार आलोचना और दंड का सामना करना पड़ा है। 2010 में आईएसआई पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, और 2018 से 2022 तक पाकिस्तान को एफएटीएफ “ग्रे सूची” में डाला गया, क्योंकि वह आतंकी फंडिंग पर नियंत्रण नहीं कर पाया। 2011 में ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में गिरफ्तारी-जो आईएसआई की एक सुविधा के निकट था-ने वैश्विक समुदाय को चौंका दिया और आईएसआई की मिलीभगत को लेकर संदेह और गहरा हो गया, हालांकि पाकिस्तान ने इसे नकारा।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव और जारी चुनौतियाँ

पाकिस्तान की इंटर-सरविसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) पर आतंकवाद का समन्वय करने के जो आरोप हैं, उनका दक्षिण एशिया की स्थिरता और शांति पर गहरा और व्यापक असर पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को दिए गए समर्थन के कारण युद्ध की समाप्ति के बाद भी संघर्ष जारी रहा है, जिससे पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता प्रयास बाधित हुए हैं। केवल 2021 से 2023 के बीच, अफगानिस्तान में ढाई हजार से तीन हजार नागरिकों की मौतें आतंकवादी हमलों के कारण हुईं, जिनमें अधिकांश हमले आईएसआई समर्थित नेटवर्कों से जुड़े पाए गए। भारत में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में, आईएसआई-समर्थित आतंकवाद 1989 से अब तक लगभग सैंतालीस हजार लोगों की जान ले चुका है, जिनमें दस

हजार आम नागरिक शामिल हैं। अकेले 2023 में जम्मू-कश्मीर में चौरानवे आतंकवादी घटनाएं हुईं, जो इस समर्थन के प्रत्यक्ष परिणाम हैं। भारत सरकार को इन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हर वर्ष चालीस हजार से छप्पन हजार करोड़ रुपये की भारी राशि खर्च करनी पड़ती है, जो कि मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च हो सकती थी। दूसरी ओर, अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को मिली वित्तीय सहायता ने संघर्ष को और लंबा खींचा है। 2021 से 2023 तक, हर वर्ष वहाँ ढाई हजार से तीन हजार आम नागरिकों की मौत हुई, जिससे पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता प्रयास बाधित हुए।

पाकिस्तान की कथित भूमिका ने भारत-पाक संबंधों को भी अपूरणीय क्षति पहुँचाई है। 2016 के पठानकोट हमले के बाद से द्विपक्षीय उच्च स्तरीय वार्ता स्थगित है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए, जिससे पाकिस्तान को सोलह हजार करोड़ रुपये का निर्यात घाटा हुआ। 2008 के मुंबई हमलों ने, जिनमें तीन दशमलव दो करोड़ रुपये का खर्च आया था और बारह हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई, भारत की वित्तीय प्रणाली को हिला दिया और वैश्विक स्तर पर भारत की सुरक्षा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। इन संगठनों को मिली वित्तीय स्वतंत्रता ने उन्हें शहरी भारत में अपने संचालन का विस्तार करने की क्षमता दी है। एलईटी और जेईएम जैसे समूह अब केवल सीमावर्ती इलाकों में सीमित नहीं हैं, बल्कि मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में भी सक्रिय हो गए हैं। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद का फिर से सिर उठाना 2023 में बारह घटनाओं के साथ सामने आया, जिससे अलगाववाद की एक नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहीं, मध्य भारत में नक्सलवादी गतिविधियाँ, जिनमें 2023 में इकसठ नागरिक मारे गए, अब भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। यह वित्तीय प्रणाली एक “निम्न तीव्रता वाला संघर्ष” को लगातार जीवित रखती है, जो शांति वार्ताओं को निष्फल बनाती है और भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाती है। 2021 से 2023 के बीच, नियंत्रण रेखा पर हर वर्ष पचास से एक सौ संघर्षविराम उल्लंघन हुए, जिससे दोनों देशों के बीच पारंपरिक शांति उपाय भी निष्फल हो गए। इन हालातों से स्पष्ट है कि जब तक राज्य प्रायोजित आतंकवाद के वित्तपोषण को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक क्षेत्र में स्थिरता एक दूर का सपना बनी रहेगी।

अध्याय 17:

राज्य एजेंटों द्वारा प्रशिक्षण और समर्थन

दक्षिण एशिया में आतंकवाद के प्रसार और उसकी निरंतरता में राज्य प्रायोजित एजेंटों की भूमिका अत्यंत विवादास्पद रही है। विशेष रूप से पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान से जुड़े राज्य एजेंटों पर यह गंभीर आरोप हैं कि वे आतंकवादी संगठनों को न केवल प्रशिक्षण देते हैं बल्कि उन्हें रसद सहायता, वैचारिक कट्टरता और वित्तीय संसाधनों से भी लैस करते हैं। इन आरोपों को सम्बंधित राष्ट्र अक्सर खारिज करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जांचों और गुप्तचर रिपोर्टों में बार-बार यह प्रमाणित हुआ है कि यह गतिविधियाँ संगठित, संस्थागत समर्थन के तहत संचालित होती हैं और क्षेत्रीय अस्थिरता को गहराती हैं।

पाकिस्तान की सैन्य गुप्तचर एजेंसी, इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (आईएसआई) पर यह आरोप वर्षों से लगाए जाते रहे हैं कि उसने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन और द रेसिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों को रणनीतिक समर्थन और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देना रहा है। उन्नीस सौ नब्बे के दशक में, आईएसआई ने पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर और पंजाब में व्यापक प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की, जिनमें मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट, कोटली और मानसेहरा प्रमुख केंद्र रहे। इन शिविरों में प्रतिवर्ष पाँच सौ से एक हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता था, जिनमें गुरिल्ला युद्ध, शहरी संघर्ष, विस्फोटक निर्माण और मनोवैज्ञानिक युद्ध की गहन शिक्षा दी जाती थी। इन प्रशिक्षणों का नेतृत्व अक्सर अफ़ग़ान युद्ध से लौटे अनुभवी करते थे, जिन्हें असममित युद्ध कौशल में महारत प्राप्त थी। वर्ष दो हजार दस तक, इन शिविरों की वार्षिक उत्पादन क्षमता एक हजार प्रशिक्षित आतंकियों तक पहुँच गई थी, जिनमें से दो सौ से तीन सौ को विशेष रूप से शहरी हमलों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वर्ष दो हजार आठ में मुंबई पर हुए आतंकी हमलों इसका जीवंत उदाहरण है, जिसे ऐसे ही प्रशिक्षित आतंकियों ने अंजाम दिया।

लश्कर-ए-तैयबा का मर्कज़-ए-तैयबा, जो लाहौर के समीप मुरिदके में दो सौ एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ गोलाबारी रेंज, बम निर्माण

कार्यशालाएँ, मदरसे और मस्जिदें शामिल हैं। इस केंद्र में उन्नीस सौ नब्बे से दो हजार के बीच प्रतिवर्ष एक हजार तक आतंकी प्रशिक्षित किए गए थे। जैश-ए-मोहम्मद का बालाकोट स्थित शिविर, जिस पर भारत ने वर्ष दो हजार उन्नीस में वायु हमला किया था, दो हजार के दशक में प्रतिवर्ष तीन सौ से पाँच सौ आतंकियों को प्रशिक्षित करता था, जिनमें कई ने वर्ष दो हजार उन्नीस पुलवामा हमले को अंजाम दिया। इसी तरह, हिज्बुल मुजाहिदीन के मुजफ्फराबाद स्थित शिविरों ने उन्नीस सौ नब्बे से सक्रिय रहते हुए प्रतिवर्ष एक हजार प्रशिक्षुओं को गुरिल्ला युद्ध में दक्ष किया है, जिससे वर्ष दो हजार तेईस में जम्मू-कश्मीर में चौरानवे आतंकवादी हमलों में एक सौ सत्रह लोगों की जान गई। इन शिविरों में आधुनिक युद्ध के परिदृश्यों की नकल करने के लिए शहरी क्षेत्रों जैसे मॉडल बनाए गए हैं, जहाँ प्रशिक्षु भारत के शहरों पर हमलों की रणनीति का अभ्यास करते हैं। उन्हें एके-सैंतालीस, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और आईईडी जैसे हथियारों से लैस किया जाता है। वर्ष दो हजार तेईस में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा हिज्बुल के प्रशिक्षित आतंकियों से पचास एके-सैंतालीस और बीस आईईडी जब्त किए गए, जो इस सहायता के पैमाने को दर्शाते हैं। केवल सैन्य प्रशिक्षण ही नहीं, आईएसआई वैचारिक कट्टरता को भी बढ़ावा देता है। वर्ष दो हजार तेईस तक हर वर्ष दो सौ से तीन सौ युवाओं को इस्लामी कट्टरपंथी साहित्य की प्रतिदिन चार घंटे की पढ़ाई कराई जाती थी। इन प्रशिक्षण शिविरों की सालाना लागत चार से आठ करोड़ रुपये होती है, जो आईएसआई की गुप्त बजट योजनाओं और हवाला नेटवर्क के जरिए दी जाती है। अकेले वर्ष दो हजार तेईस में आईएसआई ने लश्कर, जैश और हिज्बुल को अस्सी से एक सौ बीस करोड़ रुपये की फंडिंग दी थी।

अगस्त दो हजार इक्कीस में तालिबान द्वारा काबुल पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के बाद, अफ़गान तालिबान पर यह आरोप लगे कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को प्रशिक्षण और रसद सहायता प्रदान की, जो पाकिस्तान के अंदर सैन्य और नागरिक लक्ष्यों पर हमलों के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्ष दो हजार तेईस की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में सक्रिय हकीम अल-मिस्री जैसे प्रशिक्षकों ने आत्मघाती हमले की तकनीकों में टीटीपी आतंकियों को प्रशिक्षण दिया। वर्ष दो हजार पंद्रह से वर्ष दो हजार तेईस तक, वज़ीरिस्तान और हेलमंद के शिविरों में प्रतिवर्ष एक सौ से डेढ़ सौ आतंकियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया। इन शिविरों में अल-कायदा से जुड़े पुराने प्रशिक्षक भी शामिल हैं, जो आग्नेयास्त्र, विस्फोटक और शहरी युद्ध में विशेषज्ञता

रखते हैं। वर्ष दो हजार तेईस तक, प्रतिवर्ष दो सौ से तीन सौ टीटीपी आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया, जिन्हें एम-चौबीस स्नाइपर राइफल, एम-चार कार्बाइन और नाइट विज़न चश्मे जैसे आधुनिक हथियारों से लैस किया गया, जो तालिबान के पास वर्ष दो हजार इक्कीस में अमेरिका द्वारा छोड़े गए स्टॉक से प्राप्त हुए थे। टीटीपी द्वारा वर्ष दो हजार तेईस में पेशावर की मस्जिद में किए गए हमले, जिसमें एक सौ एक लोगों की मृत्यु हुई थी, को कुनार में प्रशिक्षित आतंकियों ने अंजाम दिया। इस हमले में प्रयुक्त विस्फोटक तालिबान द्वारा आपूर्ति किए गए थे, जिनकी लागत आठ लाख रुपये आँकी गई। तालिबान का समर्थन केवल सैन्य उपकरणों तक सीमित नहीं है। टीटीपी के आतंकियों को कंधार और खोस्त की मदरसों में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें कट्टर जिहादी शिक्षा दी जाती है। वर्ष दो हजार तेईस तक, हर वर्ष पचास से एक सौ युवा इन मदरसों से कट्टरपंथी विचारधारा से लैस होकर आतंक की राह पर निकलते हैं। इस समर्थन से टीटीपी की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है - वर्ष दो हजार तेईस में पाकिस्तान में टीटीपी द्वारा किए गए एक सौ से दो सौ हमलों में लगभग तीन सौ से चार सौ लोगों की जान गई, जिनमें एक सौ पचास सुरक्षा कर्मी शामिल थे।

राज्य एजेंटों द्वारा रसद समर्थन

दक्षिण एशिया में आतंकवाद के निरंतर प्रसार और संचालन की सफलता में राज्य एजेंटों द्वारा प्रदान किया गया रसद समर्थन एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह समर्थन केवल शारीरिक प्रशिक्षण या वैचारिक कट्टरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संरक्षित ठिकानों की व्यवस्था, सीमाओं के आर-पार आवाजाही, सुरक्षित संचार तंत्र, नकली दस्तावेजों की आपूर्ति और युद्ध-उपकरणों की रसद आपूर्ति शामिल होती है। आरोप हैं कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज़ इंटेलिजेंस और अफ़ग़ान तालिबान जैसे राज्य तत्व इन नेटवर्कों को सुनियोजित ढंग से संचालित करते हैं, जिससे आतंकवादी समूह लंबे समय तक सक्रिय और प्रभावी बने रहते हैं। पाकिस्तान में आईएसआई पर यह गंभीर आरोप हैं कि वह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को न केवल वित्तीय सहायता देता है, बल्कि उन्हें पाकिस्तान के संघ प्रशासित कबायली क्षेत्र में सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। मुरिदके स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मर्कज़-ए-तैयबा एक ऐसा ही केंद्र है, जिस पर आईएसआई का संरक्षण मिला था। यह न केवल प्रशिक्षण शिविर था, बल्कि एक प्रमुख रसद केंद्र के रूप में भी कार्य करता था, जहाँ हर साल पाँच सौ से एक हजार नए भर्ती आतंकी

प्रशिक्षित होते थे। इस केंद्र में विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, संदेश-वहन नेटवर्क और गुप्त संचार व्यवस्था भी थी, जिससे यह एक पूर्ण “आतंकी संचालन केंद्र” बन चुका था। इसी प्रकार, जैश-ए-मोहम्मद का बालाकोट स्थित शिविर, जिस पर भारत ने वर्ष दो हजार उन्नीस में वायु हमला किया था, सीमा पार के आतंकी साजिशकर्ताओं को भारत में घुसपैठ करवाने का प्रमुख रसद ठिकाना था। इस मार्ग से वर्ष दो हजार तेईस में ही दो सौ से तीन सौ घुसपैठ के प्रयास भारतीय एजेंसियों द्वारा पकड़े गए।

हिज्बुल मुजाहिदीन के मुजफ्फराबाद स्थित शिविरों ने एक सौ से डेढ़ सौ आतंकियों को ठिकाने प्रदान किए हुए थे और इनके लिए आईएसआई द्वारा वाहन, स्थानीय नेटवर्क, नकशे मुहैया कराए जाते थे, जिससे वे भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकें। तालिबान द्वारा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को दिया गया समर्थन भी समान रूप से संगठित और व्यापक है। तालिबान ने कूनार, नंगरहार और हेलमंद जैसे प्रांतों में टीटीपी के लिए दस से पंद्रह सुरक्षित आश्रयस्थलों की व्यवस्था की, जहाँ वर्ष दो हजार तेईस में ही हर केंद्र में पचास से एक सौ आतंकवादी एक साथ पनाह लिए हुए पाए गए। इन आश्रयों में भूमिगत बंकर, गोला-बारूद के भंडारगृह और उपग्रह संचार प्रणाली मौजूद थीं, जिन्हें संचालित और बनाए रखने की वार्षिक लागत दो से चार करोड़ रुपये आंकी गई थी। तालिबान की ओर से टीटीपी को संचार माध्यमों और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति भी की जाती है। स्पिन बोलडक और तोरखम मार्गों से प्रतिवर्ष पाँच सौ से एक हजार राइफल और पचास से एक सौ रॉकेट प्रोपेल्ल्ड ग्रेनेड पार कराए जाते हैं। टीटीपी को न केवल हथियार दिए जाते हैं, बल्कि उनके संदेशों के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए एन्क्रिप्टेड अनुप्रयोग जैसे व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नल का उपयोग करवाया जाता है। वर्ष दो हजार तेईस में भारतीय गुप्तचर एजेंसियों ने दो सौ से तीन सौ ऐसे एन्क्रिप्टेड संदेशों को अवरोधित किया, जिनका संबंध आईएसआई और तालिबान द्वारा समन्वित आतंकी हमलों से था। आईएसआई आतंकवादियों को जीपीएस उपकरण, उपग्रह फ़ोन और ड्रोन जैसे निगरानी उपकरण भी उपलब्ध कराता है। वर्ष दो हजार तेईस में कश्मीर में ऐसे बीस से तीस ड्रोन जब्त किए गए, जिनका प्रयोग सीमा पार से निगरानी, हथियार गिराने या विस्फोटक ले जाने के लिए किया जा रहा था। आईएसआई द्वारा बनाए गए नकली आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और भारतीय सेना के फर्जी पहचान पत्रों का प्रयोग कर आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने और स्थानीय नेटवर्क में छिपे रहने में मदद मिलती है।

भारत के इतिहास को झकझोरने वाले आतंकी हमले

अध्याय 18:

1993 बंबई शृंखलाबद्ध विस्फोट - भारत का पहला संगठित आतंकी हमला

इस अध्याय में 1993 के बंबई (अब मुंबई) में हुए शृंखलाबद्ध विस्फोटों की विस्तृत चर्चा की गई है, जो भारत के इतिहास में पहला बड़े पैमाने पर संगठित आतंकी हमला माना जाता है। ये विस्फोट 12 मार्च 1993 को हुए थे, जिसमें बारह समन्वित बम विस्फोटों ने शहर के प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप दो सौ सत्तावन लोग मारे गए और लगभग एक हजार चार सौ घायल हुए। यह हमला न केवल भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को हिला देने वाला था, बल्कि इसने देश की सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक मनोदशा पर गहरा प्रभाव डाला। हमले के पीछे का मुख्य कारण 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ा था, जिसने सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया और अपराध जगत को बदला लेने का अवसर प्रदान किया। इस घटना ने भारत में आतंकवाद के नए युग की शुरुआत की, जहां संगठित अपराध, अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां और धार्मिक कट्टरता का घातक मिश्रण देखने को मिला। हमले ने मुंबई की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया, क्योंकि शहर तब भारत की जीडीपी का महत्वपूर्ण हिस्सा योगदान देता था, और स्टॉक एक्सचेंज जैसे लक्ष्यों से वित्तीय बाजारों में भारी गिरावट आई। दीर्घकाल में, इसने भारत की आतंकवाद-रोधी नीतियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें नए कानूनों और सुरक्षा उपायों का निर्माण शामिल था।

पृष्ठभूमि और सामाजिक-राजनीतिक माहौल

1993 के बंबई विस्फोटों की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ी हुई है, जिसके बाद पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में मुंबई सबसे अधिक प्रभावित शहर था, जहां दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान लगभग नौ सौ लोग मारे गए और दो हजार से अधिक घायल हुए। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इन दंगों में अधिकांश पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे, और शहर की सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई,

जो भारत की वित्तीय राजधानी और सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था, अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान और व्यापार-केंद्रित संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन इन दंगों ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। अपराध जगत के प्रमुख व्यक्ति जैसे दाऊद इब्राहिम, जो पहले सोने की तस्करी और गिरोह युद्धों में शामिल थे, अब राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हो गए। टाइगर मेमन, एक चांदी तस्कर, जिनका कार्यालय दंगों में जला दिया गया था, ने इस घटना को व्यक्तिगत अपमान मानकर हमलों की योजना बनाई। इस माहौल ने अपराध जगत और पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठनों को भारत के आर्थिक केंद्र को अस्थिर करने का अवसर प्रदान किया, जहां बदला और भय फैलाने के लिए संगठित हमलों की योजना बनी। दंगों के दौरान शिवसेना और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका पर आरोप लगे, जिसने मुस्लिम समुदाय में असंतोष को और बढ़ाया। राजनीतिक रूप से, यह समय कांग्रेस सरकार के अधीन था, और केंद्र सरकार पर दंगों को नियंत्रित करने में विफलता के आरोप लगे, जिसने आतंकवादियों को कमजोरी का फायदा उठाने का मौका दिया।

हमले की साजिश और योजना

विस्फोटों की योजना मुंबई-आधारित अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट डी-कंपनी के नेता दाऊद इब्राहिम द्वारा समन्वित की गई थी, जिसमें टाइगर मेमन मुख्य मास्टरमाइंड थे। योजना में उन्नीस लोगों को पाकिस्तान में हथियारों और बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें गुल्लू भी शामिल था। लॉजिस्टिक्स में तीन हजार किलोग्राम आरडीएक्स, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी शामिल थी, जो 3 और 7 फरवरी 1993 को रायगढ़ जिले के शेखाड़ी में उतारी गई। दाऊद फांसे और शरीफ अब्दुल गफूर पारकर जैसे साजिशकर्ताओं ने अधिकारियों को रिश्तत देकर तस्करी सुविधाजनक बनाई। कई बैठकें हुईं, जैसे होटल ताज महल में मुश्ताक तरानी की बैठक, जहां बमबारी स्थलों की टोह ली गई। मेमन परिवार के कई सदस्य शामिल थे, जिसमें याकूब मेमन ने ट्रेनिंग की व्यवस्था और वित्तीय सहायता की, साथ ही वाहनों की खरीद की। योजना का उद्देश्य मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक और रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाकर आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका देना था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े तत्वों ने लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान की। हमलावरों ने सीमा पार ट्रेनिंग में आरडीएक्स, हैंड ग्रेनेड और ऑटोमैटिक हथियारों का उपयोग सीखा। योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि

विस्फोटों का समय एक-दूसरे से कुछ मिनटों का अंतर रखा गया, ताकि अधिकतम अराजकता और भय फैलाया जा सके। साजिश में दुबई को आधार बनाया गया, जहां दाऊद इब्राहिम रहते थे, और वहां से फंडिंग और निर्देश दिए गए।

हमला और घटनाओं का क्रम

12 मार्च 1993 की दोपहर एक बजकर तीस मिनट पर पहला विस्फोट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में एक शक्तिशाली कार बम से हुआ, जिसमें पचास लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, साथ ही अट्ठाईस मंजिला इमारत और आसपास के कार्यालयों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके बाद अगले दो घंटों (एक बजकर तीस मिनट से तीन बजकर चालीस मिनट तक) में शहर के बारह स्थानों पर विस्फोट हुए, जिनमें ज्यादातर कार बम और कुछ स्कूटर बम शामिल थे। लक्ष्यों में तीन होटल (होटल सी रॉक, होटल जुहू सेंटॉर, और होटल एयरपोर्ट सेंटॉर) सूटकेस बम से, बैंक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, एयर इंडिया बिल्डिंग, और एक प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल थे। विशिष्ट स्थल जैसे जवेरी बाजार (जहां एक बम से सत्रह मारे गए और सत्तावन घायल हुए), सेंचुरी बाजार (जीप बम से एक सौ तेरह मारे गए और दो सौ सत्ताईस घायल हुए), और एक डबल-डेकर बस (सबसे घातक विस्फोट में नब्बे तक मौतें)। सहार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्रेनेड फेंके गए और फिशरमेन कॉलोनी में एक स्कूटर बम विस्फोट हुआ। आरडीएक्स और टाइम-डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि इमारतों के बड़े हिस्से ढह गए और सैकड़ों मीटर तक मलबा फैल गया। हमलों में कुल दो सौ सत्तावन लोग मारे गए और एक हजार चार सौ से अधिक घायल हुए, जिससे यह स्वतंत्र भारत का सबसे घातक आतंकी हमला बन गया। घटनाओं का क्रम इतना तेज था कि शहर की यातायात और संचार व्यवस्था ठप हो गई, और लोगों में भगदड़ मच गई।

आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव कार्य

विस्फोटों के तुरंत बाद मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थलों पर पहुंचीं। कई जगहों पर विस्फोट इतने भीषण थे कि राहतकर्मियों को मलबे के नीचे फंसे लोगों तक पहुंचने में घंटों लग गए। अस्पतालों में अचानक घायलों की बाढ़ आ गई, जिसमें बड़े सरकारी अस्पतालों जैसे जे.जे. अस्पताल, के.ई.एम. अस्पताल, और सायन अस्पताल को आपातकालीन मोड में लाया गया। रक्तदान

केंद्रों में लंबी कतारें लगीं और आम नागरिकों ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सेना और नेवी के जवानों को भी राहत कार्यों में लगाया गया। पुलिस ने तुरंत सभी चेकपोस्ट और शहर के प्रवेश-निकास मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी, जिससे संदिग्धों के भागने की संभावना कम हो सके। संचार नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ गया, क्योंकि लोग अपने परिवार और परिचितों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया ने लगातार घटनास्थलों से लाइव रिपोर्टिंग की, जिससे पूरे देश और दुनिया में इस हमले की खबर फैल गई।

जांच और साजिश का पर्दाफाश

जांच की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच और सीबीआई को सौंपी गई। जांच में आरडीएक्स के इस्तेमाल का खुलासा हुआ, जो भारत में पहली बार किसी आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ था। यह विस्फोटक पाकिस्तान से समुद्री रास्ते रायगढ़ के तट पर लाया गया था। पुलिस ने शुरुआती दिनों में ही टाइगर मेमन के घर पर छापा मारकर सबूत जुटाए, जिसमें हथियार, नक्शे, और संचार उपकरण मिले। कुल एक सौ तिरपन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें से बयालीस को बाद में गिरफ्तार किया गया और कई फरार हो गए, जिनमें दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन शामिल थे। फॉरेंसिक जांच से यह साबित हुआ कि बम बनाने में टाइम-डिवाइस और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें दुबई और कराची से मंगवाया गया था। कई गवाहों और गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि योजना में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की भूमिका थी।

कानूनी कार्यवाही और सज़ा

1993 के बंबई बम विस्फोटों का मामला टाडा (TADA) अदालत में चला, जो भारत का सबसे लंबा चलने वाला आपराधिक मुकदमा बना। सुनवाई में एक सौ बयालीस गवाहों के बयान दर्ज हुए और हजारों पन्नों के सबूत पेश किए गए। 2006 में अदालत ने कुल बारह लोगों को मौत की सज़ा और बीस लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। याकूब मेमन, जो हमलों की वित्तीय और लॉजिस्टिक व्यवस्था में शामिल था, को 2015 में फांसी दी गई। कई आरोपियों को 10 से 20 साल की सज़ा भी सुनाई

गई। टाडा अदालत ने यह भी माना कि यह हमला केवल आपराधिक घटना नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला था।

अंतरराष्ट्रीय असर और कूटनीतिक परिणाम

इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन को वैश्विक वांछित आतंकियों की सूची में डाला गया। अमेरिका और इंटरपोल ने इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवाद-रोधी कानूनों को और सख्त किया और समुद्री सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे 'साउथ एशिया का पहला मेगा टेरर अटैक' बताया, जिससे भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरियां भी उजागर हुईं।

सुरक्षा सुधार और नीतिगत बदलाव

1993 के विस्फोटों के बाद भारत में कई सुरक्षा सुधार लागू किए गए। समुद्री तटों पर निगरानी बढ़ाई गई, तटरक्षक बल और नौसेना के बीच समन्वय मजबूत किया गया। बड़े शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क विकसित किया गया और पुलिस को आधुनिक हथियार और बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराए गए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच अनिवार्य की गई। आतंकवाद-रोधी दस्तों (ATS) को और अधिक संसाधन और अधिकार दिए गए।

मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव

इन विस्फोटों ने मुंबई और पूरे देश के लोगों के मन में गहरी असुरक्षा और भय की भावना पैदा की। जहां एक ओर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ा, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर लोगों ने एक-दूसरे की मदद करके एकता का संदेश भी दिया। इस घटना ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि आतंकवाद केवल भौतिक नुकसान नहीं करता, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। मुंबई, जिसने हमेशा 'स्पिरिट ऑफ मुंबई' के नाम से विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने का उदाहरण दिया है, ने इस बार भी हमले के बाद तेजी से अपने जीवन को सामान्य किया, लेकिन यह घटना शहर की यादों में स्थायी रूप से दर्ज हो गई।

अध्याय 19:

2001 संसद हमला - लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सीधा प्रहार

राजनीतिक और सुरक्षा माहौल की पृष्ठभूमि

साल 2001 में भारत पहले से ही कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के दौर से गुजर रहा था। जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था और सीमाओं पर नियमित गोलाबारी आम हो चुकी थी। संसद पर हमले से ठीक पहले भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ तेज की थी, जिससे पड़ोसी देश में चरमपंथी गुटों की बेचैनी बढ़ी। इसी दौर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, जिन्हें भारत ने पहले से प्रतिबंधित कर रखा था, खुलेआम कश्मीर में हिंसा फैला रहे थे। इन परिस्थितियों ने दिल्ली को एक हाई-वैल्यू टारगेट बना दिया, और आतंकियों ने लोकतांत्रिक केंद्र को निशाना बनाने की योजना बनाई।

हमले की योजना और तैयारी

हमले की तैयारी कई हफ्तों पहले से शुरू हुई थी। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने दिल्ली में गुप्त रूप से रहकर संसद भवन के आस-पास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और गेट नंबर 12 के पास के प्रवेश मार्ग को मुख्य लक्ष्य चुना। इसके लिए उन्होंने नकली पहचान पत्र, फर्जी कार स्टिकर और दिल्ली नंबर की कार का इंतजाम किया। हथियारों में एके-47 राइफलें, ग्रेनेड, पिस्तौल और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद शामिल था। हमले के समय का चुनाव संसद सत्र के दौरान किया गया, जब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, ताकि इसका असर अधिकतम हो और भारत की राजनीतिक स्थिरता पर सीधा आघात किया जा सके।

हमला और गोलाबारी का सिलसिला

13 दिसंबर 2001 की सुबह 11:40 बजे आतंकियों की कार संसद परिसर के गेट पर पहुँची। सुरक्षा कर्मियों ने जांच शुरू की ही थी कि हमलावरों ने अचानक गोलीबारी

शुरू कर दी। पहले ही मिनट में एक सुरक्षा गार्ड की मौत हुई और परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आतंकियों ने गेट तोड़कर मुख्य भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद 45 मिनट तक गोलाबारी चली, जिसमें आतंकियों ने ग्रेनेड और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि वे संसद के मुख्य कक्ष तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन इस बीच छह सुरक्षा कर्मी, एक माली और सभी पाँच हमलावर मारे गए।

तत्कालीन बचाव और सुरक्षा बलों की कार्रवाई

हमले के शुरुआती पलों में संसद भवन को तुरंत सील कर दिया गया और सभी सांसदों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और संसद सुरक्षा बल ने मिलकर आतंकियों को घेरने और मार गिराने में समन्वित भूमिका निभाई। विशेष बम निरोधक दस्ते ने आतंकियों की कार और शवों की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में गोला-बारूद, फर्जी दस्तावेज और पाकिस्तानी निर्मित हथियार बरामद हुए। इस त्वरित प्रतिक्रिया ने आतंकियों को अपने मुख्य लक्ष्य-संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश-से रोक दिया, जिससे देश एक बड़े राजनीतिक और मानवीय संकट से बच गया।

जांच और गिरफ्तारियाँ

हमले के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने विस्तृत जांच शुरू की। घटनास्थल से मिले सबूतों, हथियारों, मोबाइल कॉल डिटेल्स और वाहन के दस्तावेजों के आधार पर कई संदिग्धों की पहचान हुई। अफजल गुरु, शौकत हुसैन, गिलानी और नवजोत सैडू उर्फ 'आफ़शा' को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि हमलावर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और पाकिस्तान स्थित ठिकानों से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। हथियारों के स्रोत, फंडिंग चैनल और संचार नेटवर्क को भी ट्रैक किया गया, जिसने पाकिस्तान-स्थित हैंडलर्स की भूमिका को उजागर किया।

कानूनी कार्यवाही और सज़ा

मुकदमा विशेष पोटा अदालत में चला, जिसमें अफजल गुरु को साजिश, देशद्रोह और आतंकवाद के तहत दोषी ठहराया गया। 2002 में अदालत ने उन्हें मृत्युदंड सुनाया, जिसे 2013 में तिहाड़ जेल में फांसी देकर पूरा किया गया। शौकत हुसैन को 10 साल की सजा और गिलानी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया। इस मामले

ने भारतीय न्याय व्यवस्था में आतंकवाद मामलों में त्वरित सुनवाई और ठोस सबूतों के महत्व पर नई बहस छेड़ दी।

कूटनीतिक और सैन्य प्रतिक्रिया

हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान से उच्चायुक्त को तलब किया गया और आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। सैन्य स्तर पर 'ऑपरेशन पराक्रम' शुरू हुआ, जिसमें लगभग 5 लाख सैनिकों को भारत-पाक सीमा पर तैनात किया गया। यह तैनाती लगभग दस महीने तक चली और इसे दोनों देशों के बीच सबसे लंबा सैन्य जमावड़ा माना गया। इस अवधि में कई बार सीमा पर गोलीबारी और तनाव की स्थिति बनी रही।

दीर्घकालिक सुरक्षा सुधार

हमले के बाद संसद और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा में व्यापक बदलाव किए गए। प्रवेश द्वारों पर मल्टी-लेयर चेकिंग, उन्नत सीसीटीवी निगरानी, बुलेटप्रूफ पोस्ट और स्वचालित अवरोधक लगाए गए। खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त खुफिया समिति (JIC) को और मजबूत किया गया। इसके अलावा आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA) को लागू करके सुरक्षा बलों को अधिक कानूनी शक्तियाँ दी गईं।

जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया

हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। आम नागरिकों में आक्रोश और चिंता का माहौल था, जबकि मीडिया ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए व्यापक कवरेज दी। टीवी चैनलों और अखबारों में लगातार अपडेट और बहसें हुईं, जिनमें सुरक्षा व्यवस्था की खामियों, आतंकवाद के खिलाफ नीतियों और पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा हुई। इस घटना ने आम जनता में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सजगता बढ़ा दी।

ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक असर

संसद पर हमले ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्थायी निशान छोड़ दिया। यह घटना न केवल राजनीतिक नेतृत्व के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी कि आतंकवाद किस हद तक पहुँच सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसने नागरिकों में असुरक्षा की भावना गहरी की और 'आंतरिक दुश्मन' के खतरे को रेखांकित किया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक स्थायी सबक बन गया कि उच्च-प्रोफाइल लक्ष्यों की रक्षा में कोई ढील घातक हो सकती है।

अध्याय 20:

2006 मुंबई लोकल बम धमाके - शहर की रफ्तार पर मौत का पहरा

रोजमर्रा की यात्रा में मौत की दस्तक

11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई में बारिश थमी थी, और दफ्तर से लौटते समय लाखों यात्री रोज की तरह वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में सवार थे। समय था शाम 6:24 बजे, जब खार और सांताक्रूज स्टेशन के बीच एक भीषण धमाका हुआ। किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि यह सिर्फ शुरुआत है-अगले 11 मिनट में कुल सात धमाकों ने शहर को झकझोर दिया। सभी धमाके उपनगरीय नेटवर्क की फर्स्ट-क्लास बोगियों में हुए, जिनमें आमतौर पर दफ्तर से लौटते कर्मचारी होते हैं। हमलावरों ने प्रेसर कुकर में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट भरकर टाइमर से लैस आईईडी तैयार किए, जिन्हें बोगियों में इस तरह रखा गया था कि विस्फोट का प्रभाव अधिकतम हो। इस सुनियोजित हमले में 209 निर्दोष लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक घायल हुए। मुंबई की “कभी न रुकने वाली” पहचान इस दिन कुछ घंटों के लिए थम गई, और देश के लिए यह घटना एक कड़वा सबक बन गई कि आतंकवाद अब शहरों की धमनियों में भी प्रवेश कर चुका है।

पृष्ठभूमि: कट्टरपंथ और नेटवर्क का गठजोड़

इस हमले की जड़ें कई वर्षों पहले पनपीं, जब 1992-93 के दंगों और 2002 के गुजरात दंगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। इन तनावों का फायदा उठाकर कई कट्टरपंथी संगठनों ने युवाओं को चरमपंथ की ओर धकेला। जांच से पता चला कि हमले के पीछे इंडियन मुजाहिदीन (IM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का नेटवर्क था, जिन्हें पाकिस्तान-स्थित इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। हमलावरों को सीमापार प्रशिक्षण शिविरों में विस्फोटक बनाने, संचार को एन्क्रिप्ट करने और खुफिया निगरानी से बचने के तरीके सिखाए गए थे। इन संगठनों ने छोटे-छोटे सेल बनाकर काम किया, ताकि किसी एक सदस्य के पकड़े जाने पर पूरी योजना का खुलासा न हो। हमलों की योजना बनाते

समय उन्होंने मुंबई की उपनगरीय रेल को चुना, क्योंकि यह शहर की आर्थिक जीवनरेखा थी और इसे निशाना बनाकर न केवल जनहानि बल्कि आर्थिक ठहराव भी पैदा किया जा सकता था।

हमले की रूपरेखा: मिनटों में फैला खौफ

पहला धमाका शाम 6:24 बजे खार और सांताक्रूज के बीच हुआ, जिसने कुछ ही सेकंड में बोगी को चीर दिया। फिर 6:25 से 6:35 बजे के बीच क्रमशः बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम/माटुंगा रोड, बोरीवली और मीरा रोड-भायंदर के बीच छह और धमाके हुए। हर बम फर्स्ट-क्लास डिब्बे में कोच-कपलिंग के पास रखा गया था, ताकि विस्फोट का दबाव बोगी में अधिक फैल सके और शार्पनेल का नुकसान अधिकतम हो। यात्री, जो एक-दूसरे को रोज देखते थे, अचानक खून और चीखों के बीच फंस गए। इस तरह की “स्टैगर्ड अटैक” पद्धति का उद्देश्य बचाव कार्य को बाधित करना और पूरे नेटवर्क में आतंक फैलाना था। सातों धमाके एक सुनियोजित टाइम-सीक्वेंस में हुए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इसमें अत्यधिक तकनीकी विशेषज्ञता और सटीक समन्वय शामिल था।

आपदा प्रतिक्रिया: इंसानियत और तंत्र की परीक्षा

धमाकों के तुरंत बाद मुंबई पुलिस, रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने सभी प्रभावित सेक्शन पर ट्रेनें रोक दीं। स्टेशन मास्टर्स ने इमरजेंसी कोड जारी किए और चिकित्सा सहायता के लिए संदेश भेजे। लेकिन प्रतिक्रिया केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं रही-टैक्सी चालकों, डब्बावालों, और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नज़दीकी अस्पतालों ने इमरजेंसी वार्ड खोल दिए, अतिरिक्त स्टाफ बुलाया गया, और ब्लड बैंक में स्टॉक बढ़ाया गया। प्रशासन ने हेलपलाइन शुरू की, शवों की पहचान के लिए अस्थायी केंद्र बनाए, और लापता लोगों की सूची तैयार की। इस पूरे समय अफवाहों पर काबू पाना, भीड़ को नियंत्रित करना और घायलों के उपचार में तेजी लाना सबसे बड़ी चुनौती थी।

जांच: साक्ष्यों से साजिश का पर्दाफाश

महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर गहन जांच शुरू की। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने विस्फोटक सामग्री के अवशेषों का

विश्लेषण किया, जिससे आरडीएक्स-अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण और क्वार्ट्ज टाइमर की पुष्टि हुई। जांच में कॉल डिटेल् रिकॉर्ड्स, मोबाइल आईएमईआई ट्रैकिंग, और संदिग्धों की निगरानी से सुराग मिले। किराए पर लिए गए कमरों, सस्ते लॉज और गेस्ट हाउस की तलाशी में कई फर्जी पहचान पत्र और विस्फोटक बनाने के सामान मिले। 2015 में लंबी सुनवाई के बाद 12 आरोपियों को दोषी ठहराया गया-पाँच को फांसी और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हालांकि, मास्टरमाइंड रियाज़ भटकल और यासीन भटकल जैसे नाम अब भी कानून से दूर थे और माना जाता है कि वे पाकिस्तान में छिपे हैं।

सुरक्षा सुधार: ट्रेनों से लेकर सिस्टम तक बदलाव

इस हमले के बाद उपनगरीय रेल नेटवर्क में सुरक्षा की सोच पूरी तरह बदल दी गई। फर्स्ट-क्लास बोगियों की स्थिति को नियमित रूप से बदलना शुरू किया गया, ताकि हमलावरों के लिए सटीक निशाना तय करना मुश्किल हो। सभी बड़े स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और बैग स्कैनिंग मशीनें लगाई गईं। रेलवे पुलिस और आरपीएफ के बीच त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) बनाए गए, जो किसी भी आपात स्थिति में 5 मिनट के भीतर सक्रिय हो सकें। कुत्ता दस्तों की तैनाती बढ़ाई गई और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को अपग्रेड किया गया, ताकि किसी भी अलर्ट को तुरंत यात्रियों तक पहुंचाया जा सके।

आर्थिक असर: ठप हुई रफ्तार की कीमत

मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर रोजाना 30-35 लाख यात्री यात्रा करते हैं। धमाकों के बाद कई घंटों तक सेवाएँ ठप रहीं, जिससे कामकाज, सप्लाई चेन और बाजार पर गहरा असर पड़ा। कई कंपनियों में उपस्थिति 50% तक गिर गई, होटल और रेस्टोरेंट्स खाली हो गए, और पर्यटन बुकिंग में गिरावट आई। कुल मिलाकर इस हमले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान लगभग 50 मिलियन डॉलर आंका गया। यह आंकड़ा केवल धन हानि का नहीं, बल्कि शहर की जीवनशैली में आई रुकावट का भी प्रतीक था।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव: डर और दृढ़ता का संगम

हमले के बाद कई यात्रियों ने भीड़भाड़ वाले डिब्बों में यात्रा से परहेज किया, और संदिग्ध वस्तुओं या व्यक्तियों को लेकर सतर्कता बढ़ी। मनोवैज्ञानिक रूप से, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के कई मामले सामने आए, खासकर उन लोगों में जिन्होंने विस्फोट के समय ट्रेन में सफर किया था। लेकिन इसके साथ ही “मुंबई स्पिरिट” ने एक बार फिर खुद को साबित किया-लोगों ने एक-दूसरे की मदद की, मुफ्त यात्राएं दीं, धार्मिक स्थलों पर लंगर लगाए और घायलों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी। इस सामुदायिक एकजुटता ने साबित किया कि आतंक केवल डर फैला सकता है, लेकिन लोगों के साहस को खत्म नहीं कर सकता।

सबक और आगे की राह: नरम लक्ष्य की सख्त सुरक्षा

मुंबई ट्रेन धमाकों ने यह सिखाया कि भीड़भाड़ वाले नागरिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षा कवच देने के लिए केवल तकनीकी समाधान ही नहीं, बल्कि स्थानीय खुफिया नेटवर्क, दृश्य सुरक्षा उपस्थिति और जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए आईईडी पैटर्न एनालिटिक्स, भीड़ के व्यवहार पर आधारित एआई निगरानी, और ‘ब्लास्ट-डिसिपेशन’ डिज़ाइन वाले प्लेटफॉर्म बनाए जा सकते हैं। नीतिगत रूप से, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और प्रशिक्षित प्रथम-प्रतिसादकों की संख्या बढ़ाना ही इस तरह की चुनौतियों का सबसे प्रभावी उत्तर होगा।

अध्याय 21:

2008 मुंबई हमले - 26/11 की दहशत और भारत का संकल्प

समुद्र से आया तूफान: पृष्ठभूमि और वैश्विक संदर्भ

26 से 29 नवंबर 2008 के बीच हुआ मुंबई हमला, जिसे “26/11” के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी प्रकरण था, जिसने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। इस हमले में 166 लोगों की जान गई, जिनमें 18 सुरक्षा कर्मी, 26 विदेशी नागरिक और नौ हमलावर शामिल थे, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की कथित संलिप्तता ने इसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना दिया। हमले का लक्ष्य सिर्फ जनहानि नहीं था, बल्कि भारत की आर्थिक राजधानी को ठप करना, सांप्रदायिक तनाव भड़काना और वैश्विक मंच पर भारत की सुरक्षा क्षमता को चुनौती देना था, ताकि कश्मीर से जुड़े राजनीतिक दबाव को बढ़ाया जा सके और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर मोड़ा जा सके।

योजना की गहराई: आतंकी नेटवर्क और तैयारी

लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की योजना महीनों पहले से बनानी शुरू कर दी थी और इसके लिए विशेष रूप से चुने गए दस आतंकियों को पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में कड़ा सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। इनका प्रशिक्षण समुद्री मार्ग से घुसपैठ, शहरी युद्ध, बंधक बनाना, विस्फोटक लगाना और भारी हथियारों के इस्तेमाल में हुआ था। अमेरिकी-पाकिस्तानी नागरिक डेविड हेडली ने कई बार मुंबई आकर होटलों, रेलवे स्टेशनों और यहूदी केंद्र की विस्तृत टोह ली, उनके नक्शे बनाए और वीडियो रिकॉर्ड किए। कराची स्थित एक गुप्त “कंट्रोल रूम” से हमले के दौरान सैटेलाइट फोन और इंटरनेट आधारित एन्क्रिप्टेड संचार के जरिए हमलावरों को लगातार निर्देश दिए जाते रहे। योजना का उद्देश्य एक साथ कई स्थानों पर हमले कर सुरक्षा बलों को भ्रमित करना और मीडिया के माध्यम से भय का वैश्विक वातावरण बनाना था।

दहशत की शुरुआत: हमले का क्रमवार विवरण

26 नवंबर 2008 की रात लगभग 9:20 बजे, आतंकियों ने कराची से समुद्र के रास्ते एक अपहृत भारतीय मछली पकड़ने वाली नौका 'कुबेर' के जरिए मुंबई की तटरेखा पर कदम रखा। वहां से वे पांच अलग-अलग समूहों में बँट गए और शहर के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित स्थलों को निशाना बनाया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर दो आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 104 को घायल कर दिया। ताजमहल पैलेस होटल में आतंकियों ने बंधक बनाकर, आग लगाकर और गोलाबारी कर 31 लोगों की जान ली, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के साथ चली 60 घंटे की मुठभेड़ के बाद उन्हें ढेर किया गया। ओबेरॉय-ट्राइडेंट होटल में 33 लोगों की हत्या हुई, जबकि नरीमन हाउस में यहूदी दंपति और अन्य बंधकों सहित नौ लोगों की नृशंस हत्या की गई। इन सभी हमलों में एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और IED का इस्तेमाल किया गया, जबकि हमलावर पाकिस्तानी हैंडलरों से निरंतर संपर्क में रहे, जो उन्हें लक्ष्यों, बंधकों और मीडिया कवरेज पर निर्देश दे रहे थे।

राज्य से राष्ट्र तक: तत्काल प्रतिक्रिया और जांच

हमले के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद-निरोधी दस्ते (ATS) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने त्वरित कार्रवाई शुरू की और कई घंटों की कठिन मुठभेड़ों के बाद नौ आतंकियों को मार गिराया, जबकि एकमात्र जीवित बचे आतंकी अजमल आमिर कसाब को जीवित पकड़ा गया। कसाब की गिरफ्तारी भारत के लिए खुफिया दृष्टि से ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि उसके कबूलनामे ने पाकिस्तान स्थित प्रशिक्षण केंद्रों, लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन नेटवर्क और ISI की भूमिका के ठोस सबूत दिए। कसाब पर मुकदमा चला, उसे दोषी ठहराया गया और 2012 में फाँसी दी गई। अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान ने ज़की-उर-रहमान लखवी को 2009 में गिरफ्तार किया, लेकिन 2015 में उसे जमानत मिल गई, जिसने आतंकवादियों पर कार्रवाई में पाकिस्तान की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा पर वैश्विक प्रतिबंध लगाए, जबकि अमेरिका ने 2024 में तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पित किया, जो इस हमले की साजिश में शामिल था।

सीख और सुधार: प्रभाव और नीतिगत बदलाव

26/11 के बाद भारत की सुरक्षा नीति और तंत्र में व्यापक बदलाव हुए। 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्थापना की गई ताकि आतंकी मामलों की जांच केंद्रीकृत और तेज हो सके। तटीय सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल के साथ रडार नेटवर्क और समुद्री गश्ती जहाजों की तैनाती शामिल थी। मुंबई और अन्य महानगरों में स्थायी NSG हब स्थापित किए गए ताकि त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। आर्थिक दृष्टि से मुंबई के पर्यटन और व्यवसाय को लगभग 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि वित्तीय बाजार में अस्थिरता फैल गई। मनोवैज्ञानिक रूप से, इस हमले ने मुंबईकरों और देशभर के नागरिकों में असुरक्षा और आक्रोश की गहरी छाप छोड़ी, लेकिन इसके साथ ही “स्पिरिट ऑफ मुंबई” ने यह साबित किया कि आतंक के सामने शहर झुकने वाला नहीं है और संकट के समय एकजुट रहकर अपनी पहचान और गरिमा की रक्षा करता है।

अध्याय 22:

2016 उरी हमला - सीमा-पार आतंकवाद का निर्णायक मोड़

सीमा पार से आई चुनौती: ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि

18 सितंबर 2016 का उरी हमला भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक और बड़े तनाव का कारण बना और सीमा-पार आतंकवाद के नए स्तर को उजागर करने वाला साबित हुआ। जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने, कथित रूप से पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के प्रत्यक्ष समर्थन से, इस हमले को अंजाम दिया। इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में शांति को भंग करना और भारत को सैन्य व राजनीतिक रूप से उकसाना था। हमलावर पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर से नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर घुसे, और यह घुसपैठ ऐसे समय हुई जब कश्मीर में पहले से ही उग्रवाद बढ़ रहा था। इस हमले से पहले गुरदासपुर और पठानकोट जैसी घटनाओं ने सीमा-पार आतंकवाद के पैटर्न को और स्पष्ट किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैश के नेता मसूद अजहर पर पहले से ही निगाह थी, जिसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। इस हमले ने साबित कर दिया कि कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान-स्थित आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बन चुकी थी।

सुबह का साया: हमले का विस्तृत वर्णन

हमला सुबह 5:30 बजे के लगभग शुरू हुआ, जब अंधेरे और धुंध का फायदा उठाते हुए चार सशस्त्र आतंकवादी भारतीय सेना के 166 ब्रिगेड मुख्यालय में घुस आए। उनका लक्ष्य 1 बिहार रेजिमेंट का शिविर था, जहाँ जवान अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी से लौटकर आराम कर रहे थे। आतंकियों ने एके-47 राइफल और ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए शिविर के तंबुओं और बैरकों को निशाना बनाया। ग्रेनेड के हमले से शिविर के अस्थायी ईंधन डिपो में विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई और कई जवान धुएँ व जलन से शहीद हो गए। मात्र ढाई घंटे में, सुबह 8:00 बजे तक, 19 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे और 30 से अधिक घायल थे। बाद की जांच में पता चला कि हमलावर पाकिस्तान में प्रशिक्षित थे, उन्होंने हमले से पहले विस्तृत

तोही की थी और एन्क्रिप्टेड संचार का उपयोग किया था। यह हमला न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहरा झटका था, क्योंकि यह सेना के एक सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने पर सीधा वार था।

सीमापार जवाब: सर्जिकल स्ट्राइक और तत्काल प्रतिक्रिया

उरी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया निर्णायक और अभूतपूर्व थी। 26 सितंबर 2016 को, भारतीय सेना के विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के कई लॉन्च पैड और प्रशिक्षण शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। यह शांतिकाल में भारत का पहला सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया सीमापार सैन्य अभियान था, जो पूरी तरह सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था। इस कार्रवाई में दर्जनों आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान ने 27 सितंबर को भारतीय सैन्य चौकियों पर गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हवाई टकराव की घटनाएँ हुईं। इस अवधि में एक भारतीय मिग-21 विमान गिरा और उसका पायलट पाकिस्तान की हिरासत में चला गया, जिसे 1 मार्च 2019 को अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद रिहा किया गया। हालांकि यह प्रकरण बाद की घटनाओं से जुड़ा था, लेकिन उरी हमले के बाद की आक्रामक नीति की दिशा को स्पष्ट करता था।

सुरक्षा नीति, अर्थव्यवस्था और जनभावना पर प्रभाव

उरी हमले ने भारत की सुरक्षा नीतियों में स्थायी बदलाव ला दिए। कश्मीर घाटी में सैन्य उपस्थिति बढ़ाई गई, आतंकवाद-रोधी अभियानों की आवृत्ति तेज़ हुई और खुफिया नेटवर्क को अधिक आधुनिक तकनीक से लैस किया गया। “ऑपरेशन ऑल आउट” जैसी पहल शुरू हुई, जिसके तहत 2023 तक 200 से अधिक उग्रवादी मारे गए। भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए घेरा, जिससे दोनों देशों के संबंध और तनावपूर्ण हो गए। आर्थिक दृष्टि से, कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को इस हमले से बड़ा झटका लगा - केवल 2016-17 सीज़न में पर्यटन राजस्व में लगभग 5 करोड़ डॉलर की गिरावट आई। मनोवैज्ञानिक स्तर पर, हमले ने स्थानीय निवासियों में असुरक्षा की भावना को गहरा किया और नागरिकों के बीच सुरक्षा चिंताएँ बढ़ीं। यह घटना इस बात का प्रमाण बन गई कि आतंकवाद केवल सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने के लिए एक दीर्घकालिक खतरा है।

अध्याय 23:

2019 पुलवामा बम विस्फोट - कश्मीर में आतंकी हिंसा का सबसे घातक प्रहार

स्थानीय युवा से आत्मघाती हमलावर तक: ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि

14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ आत्मघाती हमला भारतीय सुरक्षा इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस हमले को 22 वर्षीय स्थानीय युवक आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया, जिसे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने धीरे-धीरे कट्टरपंथी बनाकर अपने नेटवर्क में शामिल किया था। डार का उग्रवाद की ओर झुकाव 2016 के एक विरोध प्रदर्शन में लगी गंभीर चोट के बाद बढ़ा, जिसने उसे चरमपंथी विचारधारा की ओर धकेला। हमले की योजना पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और उसके सहयोगियों ने बनाई, जिसमें कथित तौर पर आईएसआई का समर्थन भी शामिल था। इस समय घाटी में 2014 के बाद से तनाव चरम पर था और अनुच्छेद 370 के निरसन की पृष्ठभूमि में आतंकी संगठनों की सक्रियता लगातार बढ़ रही थी। 2018 में ही रिकॉर्ड 192 युवाओं के आतंकी समूहों में भर्ती होने की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए।

पुलवामा की दुपहरी में मौत का सफर: हमले का विस्तृत विवरण

14 फरवरी 2019 की दोपहर 3:15 बजे, जब सीआरपीएफ का काफिला जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा था, आदिल अहमद डार ने अपनी विस्फोटकों से भरी कार को काफिले की एक बस से टकरा दिया। यह बस 76 वाहनों के काफिले का हिस्सा थी, जिसमें 2,500 से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल थे। विस्फोट में लगभग 300 किलोग्राम RDX और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जिसने बस को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 40 सीआरपीएफ जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि 35 अन्य घायल हुए। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके कंपन कई किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए और सड़क का एक हिस्सा गहरे गड्ढे में

बदल गया। जांच से पता चला कि डार को पाकिस्तान के बालाकोट स्थित शिविर में प्रशिक्षण मिला था और स्थानीय नेटवर्क ने उसके लिए विस्फोटक सामग्री, वाहन और मार्ग की जानकारी उपलब्ध कराई थी। यह हमला 1989 में कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा आत्मघाती हमला था।

बालाकोट तक गूँजा भारत का जवाब: तत्काल प्रतिक्रिया और सैन्य कार्रवाई

इस हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमला किया। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार जाकर उच्च सटीकता वाले बम गिराए, जिनसे भारत के अनुसार 300-350 आतंकवादी मारे गए। यह कार्रवाई न केवल सैन्य बलिक राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के भीतरी हिस्से में हवाई हमला किया। अगले दिन, 27 फरवरी को, पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके दौरान एक हवाई मुठभेड़ हुई। इसमें भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन विमान गिरा और पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। यह घटना अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रही, और भारी वैश्विक दबाव के बाद 1 मार्च 2019 को पायलट को रिहा किया गया। पाकिस्तान ने 5 मार्च को जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 44 सदस्यों को 14 दिनों की हिरासत में लेने की घोषणा की, हालांकि भारत ने इसे प्रतीकात्मक कदम बताया।

सुरक्षा, कूटनीति और जनमानस पर प्रभाव

पुलवामा हमले ने भारत की सुरक्षा और विदेश नीति दोनों पर गहरा असर डाला। घाटी में सैन्य उपस्थिति और तलाशी अभियानों की तीव्रता बढ़ा दी गई, खुफिया नेटवर्क को पुनर्गठित किया गया और आतंकवाद के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाया गया। “ऑपरेशन ऑल आउट” जैसे अभियानों के तहत 2023 तक 200 से अधिक जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य मारे गए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे दोनों देशों के संबंध और तनावपूर्ण हो गए। आर्थिक दृष्टि से, इस हमले का पर्यटन क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव

पड़ा - 2019 में घाटी के पर्यटन राजस्व में लगभग 20 करोड़ डॉलर की गिरावट आई। मनोवैज्ञानिक स्तर पर, इस घटना ने स्थानीय निवासियों और देशभर में असुरक्षा और आक्रोश की भावना को गहरा किया, जिससे सुरक्षा बलों के प्रति समर्थन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही आतंकी हिंसा के दीर्घकालिक समाधान की मांग भी तेज हुई।

अध्याय 24:

2025 पहलगाम हमला

हमले की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक-राजनीतिक संदर्भ

15 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग ज़िले का पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, लिदर नदी के किनारे बसे शांत वातावरण और अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर के रूप में प्रसिद्ध है, अचानक एक भयावह आतंकवादी हमले का केंद्र बन गया। यह वह समय था जब घाटी में पर्यटन का चरम मौसम था और रोजाना हजारों पर्यटक यहाँ पहुँच रहे थे, जिससे होटल, हस्तशिल्प और परिवहन व्यवसाय फल-फूल रहे थे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी की सुरक्षा व्यवस्था में कई सख्त कदम उठाए गए थे, जिससे 2020 से 2023 के बीच कई बड़े आतंकवादी कमांडर मारे गए, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने नई रणनीतियों के साथ वापसी की। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें 2024 में घुसपैठ में तेज़ी और नरम लक्ष्यों पर हमले की योजनाओं की पुष्टि कर चुकी थीं। नियंत्रण रेखा (LoC) पर लगातार बढ़ते संघर्षविराम उल्लंघन, टीआरएफ जैसे नए छद्म संगठनों की सक्रियता और पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग ने इस खतरे को और बढ़ा दिया था। ऐसे हालात में, पर्यटन पर सीधा वार करने वाला हमला न केवल आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी गंभीर असर डालने वाला था।

हमले का विस्तृत विवरण

15 मई 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे, पहलगाम के भीड़भाड़ वाले पर्यटक बाज़ार के प्रवेश द्वार पर खड़ी एक गाड़ी में 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक, जिसमें RDX, अमोनियम नाइट्रेट और लोहे के छर्रे शामिल थे, का भीषण विस्फोट हुआ। धमाके से 50 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई, जिनमें 30 पर्यटक और 20 स्थानीय नागरिक थे, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई विदेशी यात्री भी शामिल थे। विस्फोट से आसपास की इमारतें, दुकानें और वाहन मलबे में तब्दील हो गए और पूरे क्षेत्र में अफरातफरी फैल गई। इसी अफरातफरी के बीच पास स्थित सेना शिविर पर चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हमला कर दिया।

उनके पास एके-47 राइफल, रॉकेट प्रोपेल्ल्ड ग्रेनेड (RPG) और ग्रेनेड की बड़ी खेप थी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन शुरुआती मुठभेड़ में 5 जवान शहीद और 10 घायल हो गए। पास के सैन्य ठिकानों से पैरा-एसएफ और स्थानीय पुलिस के विशेष बल मौके पर पहुंचे, और कई घंटों की भीषण गोलीबारी के बाद सभी चारों आतंकवादी मार गिराए गए।

योजना और निष्पादन की रूपरेखा

जांच में यह सामने आया कि यह हमला जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर, की सीधी निगरानी में महीनों पहले योजनाबद्ध किया गया था। आत्मघाती हमलावर अब्दुल रहमान, जो अनंतनाग का ही निवासी था, को सोशल मीडिया प्रचार से कट्टरपंथी बनाया गया और पीओके में विस्फोटक व हथियार संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। सेना शिविर पर हमला करने वाले चारों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे, जिन्होंने छोटे समूहों में LoC पार किया और घने जंगलों के रास्ते पहलगाम तक पहुंचे। वे कई सप्ताह तक जंगलों में बने ठिकानों से सुरक्षा बलों और पर्यटकों की गतिविधियों पर नज़र रखते रहे और संचार के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल का उपयोग करते रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2024 में लगभग 80 ऐसे एन्क्रिप्टेड संदेश इंटरसेप्ट किए थे, जिनमें 'पर्यटन सीज़न', 'बाज़ार' और 'सेना शिविर' जैसे कोडवर्ड मिले। नरम लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति के तहत पहलगाम का चयन किया गया था, ताकि नागरिक हताहतों के साथ-साथ पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर भी गहरा आघात किया जा सके।

परिणाम और तात्कालिक प्रतिक्रिया

हमले के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सेना व सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ तैनात कीं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें आतंकवादी ढांचे को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया गया। 17 मई 2025 को भारतीय सेना ने "ऑपरेशन सिंदूर" शुरू किया, जिसके तहत LoC के

पार स्थित जैश-ए-मोहम्मद के शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक और मिसाइल हमले किए गए। इसमें 50-60 आतंकवादी मारे गए और कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। घरेलू स्तर पर NIA ने व्यापक अभियान चलाकर घाटी में फैले आतंकवादी नेटवर्क पर शिकंजा कसा, दो महीनों में 150 से अधिक संदिग्ध गिरफ्तार हुए और 20 से अधिक हवाला चैनल बंद कर दिए गए। दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाकर स्थानीय मॉड्यूल नष्ट कर दिए गए।

मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव

इस हमले का कश्मीर की जनता पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। पर्यटकों में भय का माहौल पैदा हो गया और हमले के बाद एक सप्ताह के भीतर 60% से अधिक बुकिंग रद्द हो गई। मई-जून 2025 के पर्यटन सीजन में विदेशी पर्यटकों की संख्या 75% तक घट गई, जिससे अनुमानित 200 करोड़ रुपये का सीधा आर्थिक नुकसान हुआ। होटल, टैक्सी सेवा, हाउसबोट और हस्तशिल्प कारोबार पर ताला लगने जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय युवाओं में बेरोजगारी का खतरा बढ़ा, और आम नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर जाने से कतराने लगे। यह हमला घाटी के उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर सीधा वार था, जो वर्षों से धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा था।

मीडिया और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

हमले की तस्वीरें और वीडियो भारतीय मीडिया ने तुरंत प्रसारित किए, और राष्ट्रीय चैनलों ने सुरक्षा विशेषज्ञों व सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चाएँ आयोजित कीं। सोशल मीडिया पर #PahalgamAttack और #StandWithKashmir जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। BBC, CNN, Reuters और Al Jazeera सहित अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे 2019 के पुलवामा हमले के बाद का सबसे घातक हमला बताया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नागरिकों पर हमले को “अस्वीकार्य” करार दिया और संयम बरतने की अपील की, जबकि भारत ने स्पष्ट किया कि जवाबी कार्रवाई अनिवार्य होगी। पाकिस्तान ने अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमलावरों के हथियार, संचार उपकरण और प्रशिक्षण स्थलों के सबूत पेश किए, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को और क्षति पहुँची।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के ऑपरेशन

अध्याय 25:

ऑपरेशन ब्लैक थंडर

ऑपरेशन ब्लैक थंडर उन्नीस सौ अस्सी के दशक में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किए गए दो प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियानों को संदर्भित करता है। ये अभियान पंजाब में बढ़ते उग्रवाद का मुकाबला करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थे, जो खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की माँग कर रहे थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम अक्टूबर 1984 में हुआ, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद था, जबकि ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय मई 1986 में हुआ। दोनों अभियानों ने संवेदनशील धार्मिक स्थलों को संभालने और जन धारणा को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण सबक प्रदान किए, जिसने भारत के आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण को आकार दिया।

सिख उग्रवाद का ऐतिहासिक संदर्भ

उन्नीस सौ अस्सी का दशक पंजाब में सिख उग्रवाद की उछाल का गवाह बना, जो अधिक स्वायत्तता और खालिस्तान की माँग से प्रेरित था। जरनैल सिंह भिंडराँवाले, एक करिश्माई सिख उपदेशक, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने स्वर्ण मंदिर में शरण ली और इसे उग्रवादियों के लिए एक किले में बदल दिया, जहाँ हथियार और गोला-बारूद जमा किए गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, जिसका उद्देश्य भिंडराँवाले और उनके अनुयायियों को हटाना था। इस अभियान में भारी हताहत हुए और मंदिर को व्यापक नुकसान पहुँचा, जिसमें पाँच सौ से अधिक उग्रवादी और नागरिक मारे गए। इस ऑपरेशन ने सिखों में व्यापक आक्रोश पैदा किया, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, कुछ उग्रवादी स्वर्ण मंदिर परिसर में बने रहे, जिससे उन्हें हटाने के लिए और अभियानों की आवश्यकता पड़ी। इसने अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम और मई 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय को जन्म दिया, जिनका उद्देश्य व्यवस्था बहाल करना और उग्रवादी ढाँचे को ध्वस्त करना था।

ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम (1984)

ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम एक से छह अक्टूबर 1984 तक चला, जिसे भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर से शेष उग्रवादियों को हटाने के लिए चलाया। इस अभियान का नेतृत्व मेजर जनरल के. एस. बरार ने किया, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी नेतृत्व किया था। सेना ने बख्तरबंद वाहनों और भारी हथियारों का उपयोग कर मंदिर परिसर पर धावा बोला। अकाल तख्त में जमे उग्रवादियों ने प्रतिरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप अट्टाईस उग्रवादी और दो सैनिक मारे गए। मंदिर की संरचना को फिर से भारी नुकसान हुआ। इस कठोर दृष्टिकोण की आलोचना हुई, क्योंकि इससे सिखों में और अलगाव बढ़ा और उग्रवाद के लिए समर्थन बढ़ा। उन्नीस सौ पचासी तक पाँच सौ से एक हजार नए रंगरूटों की भर्ती की बात सामने आई।

ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय (1986)

ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय, आठ से अठारह मई 1986 तक चला, जो एक अधिक परिष्कृत और सावधानीपूर्वक नियोजित अभियान था। इसका नेतृत्व पंजाब पुलिस के महानिदेशक के. पी. एस. गिल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अर्धसैनिक टुकड़ियों ने किया। इस अभियान का उद्देश्य अमरीक सिंह खालसा के नेतृत्व में उग्रवादियों के एक समूह को हटाना था, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर नियंत्रण कर लिया था। अनुमानित दो सौ से तीन सौ उग्रवादी अंदर थे। अभियान में व्यापक खुफिया संग्रह शामिल था, जिसमें रात-दृष्टि उपकरणों और मानव रहित यानों का उपयोग कर उग्रवादी ठिकानों की पहचान की गई। मनोवैज्ञानिक युद्ध में आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने वाले पर्चे बाँटे गए और धार्मिक नेताओं के संदेश लाउडस्पीकर पर चलाए गए। प्रतिदिन दस हजार पर्चे वितरित किए गए। बातचीत के प्रयासों में सुरक्षित मार्ग की पेशकश की गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रारंभ में पचास उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अभियान बारह दिनों तक चला, जिसमें सुरक्षा बलों ने धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत की और मंदिर को नुकसान से बचाने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग किया। केवल पाँच सैनिक मारे गए और बीस घायल हुए, जबकि दो सौ उग्रवादी गिरफ्तार किए गए और कई मारे गए। रात-दृष्टि चश्मों और संचार जैमर जैसी तकनीक का उपयोग, जिसमें एक सौ से दो सौ उपकरण तैनात किए गए, ने संचालन की दक्षता सुनिश्चित की।

दोनों अभियानों से सीखे गए सबक

ऑपरेशन ब्लैक थंडर, विशेष रूप से दूसरा चरण, संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए एक आदर्श माना जाता है। मुख्य सबक में शामिल हैं- सटीक और समयबद्ध खुफिया जानकारी योजना और निष्पादन के लिए आवश्यक है, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय ने उन्नत निगरानी का उपयोग कर दो सौ से तीन सौ उग्रवादी ठिकानों की पहचान की। मनोवैज्ञानिक युद्ध उग्रवादियों के संकल्प को कमजोर कर प्रत्यक्ष टकराव की आवश्यकता को घटा सकता है, जिसमें पर्चे और लाउडस्पीकर प्रभावी रहे। आत्मसमर्पण के विकल्प की पेशकश शांतिपूर्ण समाधान और जान बचाने में मदद कर सकती है, जिसमें प्रारंभ में पचास उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। धार्मिक स्थलों के प्रति संवेदनशीलता जन समर्थन जीतने और प्रतिक्रिया कम करने में सहायक हो सकती है, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय ने नुकसान को कम किया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय संचालन दक्षता को बढ़ाता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और पंजाब पुलिस ने सहजता से काम किया। मीडिया प्रबंधन के जरिए कथानक को नियंत्रित करना जन धारणा को आकार देने और गलत सूचना को कम करने में सहायक रहा, जिसमें दैनिक ब्रीफिंग ने जनमत को प्रभावित किया। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता होती है जो मूल कारणों को संबोधित करे, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय ने उग्रवाद को घटाया।

आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर प्रभाव

ऑपरेशन ब्लैक थंडर द्वितीय ने पंजाब में सिख उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन के साथ, सुरक्षा बल व्यापक संपार्श्विक नुकसान या स्थानीय आबादी को अलगाए बिना आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। इस अभियान ने सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया और उग्रवादियों को यह संदेश दिया कि उनकी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्नीस सौ नब्बे तक उग्रवाद में पचास प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, अभियानों ने गहरे जातीय और धार्मिक तनावों वाले क्षेत्र में विद्रोह से निपटने की जटिलताओं को भी उजागर किया। स्वर्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों में बल प्रयोग एक विवादास्पद मुद्दा बना, जिसके सांप्रदायिक संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़े और उन्नीस सौ सत्तासी में सिख

समुदाय के विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। ऑपरेशन ब्लैक थंडर प्रथम और द्वितीय ने भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान किए, जिसमें खुफिया, मनोवैज्ञानिक संचालन, बातचीत और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के प्रति सम्मान के महत्व को रेखांकित किया गया।

अध्याय 26: ऑपरेशन विजय

ऑपरेशन विजय, 10 मई, 1999 को शुरू किया गया, भारत का कारगिल युद्ध में सैन्य जवाब था, जो जम्मू और कश्मीर के कारगिल ज़िले में नियंत्रण रेखा के साथ भारत की सीमा में पाकिस्तान की घुसपैठ से शुरू हुआ था। यह अध्याय इस अभियान, इसके ऐतिहासिक संदर्भ, योजना, निष्पादन और दीर्घकालिक प्रभावों की विस्तृत पड़ताल करता है, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक की रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक आयामों को उजागर करता है।

कारगिल संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ

कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में निहित था, जो 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से एक विवाद का केंद्र रहा है। 1972 के शिमला समझौते ने नियंत्रण रेखा को वास्तविक सीमा के रूप में स्थापित किया, लेकिन तनाव बना रहा, जिसे पाकिस्तान द्वारा भारतीय प्रशासित कश्मीर में विद्रोह के समर्थन ने और बढ़ाया। उन्नीस सौ नब्बे के दशक के अंत तक, पाकिस्तान ने भारत की कथित कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की और कारगिल ज़िले में घुसपैठ की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण श्रीनगर-लेह राजमार्ग को काटना और क्षेत्र पर भारत के नियंत्रण को बाधित करना था। मई 1999 की शुरुआत में इस घुसपैठ का पता चला, जिसके बाद भारत ने कब्ज़ा की गई क्षेत्रों को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। यह संघर्ष भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के बीच हुआ, जिसमें 1998 में दोनों देशों के परमाणु परीक्षण और फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर शामिल थे, जिसका उद्देश्य शत्रुता को कम करना था। हालांकि, पाकिस्तान की कारगिल में गुप्त कार्रवाई ने इन समझौतों का उल्लंघन किया, जिससे एक सीमित युद्ध शुरू हुआ, जिसने भारत की सैन्य और कूटनीतिक संकल्प की परीक्षा ली।

ऑपरेशन विजय की योजना और निष्पादन

ऑपरेशन विजय एक सावधानीपूर्वक नियोजित और निष्पादित सैन्य अभियान था, जिसमें भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल थीं। अभियान को तीन चरणों में विभाजित किया गया था।

पहले चरण में, 10 मई से 15 जून, 1999 तक, प्रारंभिक टोह और तैयारी की गई। भारतीय बलों ने प्रमुख घुसपैठ बिंदुओं की पहचान की और सैनिकों को जुटाना शुरू किया, जिसमें पैरा कमांडो और पंद्रहवीं कोर जैसी विशिष्ट इकाइयाँ शामिल थीं। भारतीय वायु सेना को भी सक्रिय किया गया, और 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ, जो ज़मीनी संचालनों के लिए हवाई समर्थन प्रदान करता था, जिसमें मिग-सत्ताईस और मिराज-दो हजार लड़ाकू विमानों का उपयोग हमलों के लिए किया गया।

दूसरे चरण में, 16 जून से 10 जुलाई, 1999 तक, रणनीतिक ऊँचाइयों को वापस लेने के लिए प्रमुख आक्रामक कार्रवाइयाँ की गईं। महत्वपूर्ण लड़ाइयों में 13 जून को टोलोलिंग, 4 जुलाई को टाइगर हिल और 7 जुलाई को पॉइंट चार आठ सात पाँच की वापसी शामिल थी। ये स्थान नियंत्रण रेखा को नियंत्रित करने और आगे की घुसपैठ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण थे। भारतीय सेना को उच्च-ऊँचाई युद्ध, शून्य से नीचे के तापमान और अच्छी तरह से स्थापित पाकिस्तानी पदों जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सैनिक सोलह हजार फीट से अधिक ऊँचाई पर कार्यरत थे।

तीसरे चरण में, 11 से 26 जुलाई, 1999 तक, शेष दुश्मन पदों को साफ करने के लिए अंतिम धक्का दिया गया। 26 जुलाई तक, भारतीय बलों ने सभी एक सौ बत्तीस चौकियों को वापस ले लिया, जिसने ऑपरेशन विजय की सफल समाप्ति को चिह्नित किया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर के माध्यम से रसद समर्थन सुनिश्चित किया और निगरानी मिशन चलाए। अभियान में नवाचारपूर्ण रणनीतियों का उपयोग किया गया, जैसे बोफोर्स हॉवित्ज़र तोपों के लिए तोपखाने का समर्थन और मिग-सत्ताईस तथा मिराज-दो हजार लड़ाकू विमानों के लिए हवाई हमले, जिसमें भारतीय वायु सेना ने पाँच हजार से अधिक उड़ानें भरीं।

चुनौतियाँ और विजय

ऑपरेशन विजय कठिन परिस्थितियों में आयोजित किया गया था, जिसमें सैनिकों को कठोर मौसम, चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति और अच्छी तरह से स्थापित दुश्मन पदों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बल, जो उग्रवादियों के रूप में छिपे थे, ने बंकरों और खाइयों के साथ अपने पदों को मजबूत किया था, जिससे उन्हें हटाना मुश्किल था। इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय बलों ने असाधारण वीरता और सामरिक कुशलता का प्रदर्शन किया, 26 जुलाई, 1999 तक सभी एक सौ बत्तीस चौकियों को वापस ले लिया, जिसमें पाँच सौ सत्ताईस सैनिकों ने बलिदान दिया और पाकिस्तान पर अनुमानित तीन सौ सत्तावन से चार सौ तिरेपन हताहत हुए। इस संघर्ष ने भारत की खुफिया और सीमा सुरक्षा में कमियों को भी उजागर किया, जिसमें शुरुआती रिपोर्टों में पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही का पता नहीं चला, जिसने उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने की अनुमति दी। अभियान ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप कारगिल समीक्षा समिति की स्थापना हुई, जिसने सुधारों की सिफारिश की।

राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव

ऑपरेशन विजय के गहन राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम थे। भारत की विजय ने राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाया और इसकी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन इसने पाकिस्तान के साथ संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा-पत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख शक्तियों से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान से वापसी का आग्रह किया। इस संघर्ष ने शांति समझौतों की नाजुकता को उजागर किया और मजबूत खुफिया और सक्रिय रक्षा रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसने भारत को अधिक दृढ़ रख अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक जैसे भविष्य के आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रभावित करता है।

दीर्घकालिक प्रभाव

ऑपरेशन विजय भारत के सैन्य इतिहास में एक परिभाषित क्षण बना हुआ है, जो राष्ट्र के अपनी संप्रभुता की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इसने भारत के रक्षा प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण सुधारों को जन्म दिया, जिसमें 2020 में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना शामिल थी, जो अंतर-सेवा समन्वय को बढ़ाने के लिए थी। अभियान ने सीमा-पार आतंकवाद पर भारत के रुख को मजबूत किया, जिसने इसकी भविष्य की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को प्रभावित किया, जिसमें खुफिया-प्रधान संचालनों पर ध्यान दिया गया। ऑपरेशन विजय ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को प्रदर्शित किया, लेकिन इसने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निरंतर सतर्कता और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को भी उजागर किया।

अध्याय 27:

सर्जिकल स्ट्राइक (2016)

29 सितंबर, 2016 को आयोजित सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। 18 सितंबर, 2016 को उरी हमले, जिसमें उन्नीस भारतीय सैनिक मारे गए थे, के जवाब में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी लॉन्च पैडों को निशाना बनाकर कई पूर्वनियोजित हमले किए। यह अध्याय इन स्ट्राइकों की पृष्ठभूमि, योजना, निष्पादन और प्रभावों की पड़ताल करता है, जो इनकी रणनीतिक महत्व और भारत-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव को उजागर करता है।

उरी हमले और जवाब का ऐतिहासिक संदर्भ

उरी हमला जम्मू और कश्मीर के उरी में एक भारतीय सेना के आधार पर चार जैश-ए-मोहम्मद उग्रवादियों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला था, जिसमें उन्नीस लोग मारे गए और तीस घायल हुए। भारत में इस हमले की व्यापक निंदा हुई और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष चुनौती माना गया। पाकिस्तान ने इसमें संलिप्तता से इनकार किया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया, जिसने भारत को अधिक दृढ़ रख अपनाने के लिए प्रेरित किया। स्ट्राइक भारत की विकसित आतंकवाद विरोधी नीति से प्रभावित थी, जो सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ सक्रिय उपायों पर जोर देती थी। 2014 का पुलवामा हमला, जिसमें आठ सैनिक मारे गए थे, ने मजबूत जवाब की आवश्यकता को उजागर किया। स्ट्राइक कश्मीर में बढ़ते उग्रवाद के जवाब में भी थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद स्थानीय शिकायतों का शोषण करते हुए अपनी गतिविधियाँ तेज़ कीं। 2016 तक हर वर्ष दो सौ से तीन सौ घुसपैठ की कोशिशें दर्ज की गईं।

स्ट्राइक की योजना और निष्पादन

सर्जिकल स्ट्राइक की योजना और निष्पादन भारतीय सेना के पैरा (विशेष बल) द्वारा सटीकता के साथ किया गया। अभियान में शामिल थे - व्यापक खुफिया संग्रह, जिसमें नियंत्रण रेखा के पार सात आतंकवादी लॉन्च पैडों की पहचान की गई, जहाँ उग्रवादी आगे के हमलों की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उपग्रह चित्र और मानव खुफिया का उपयोग किया गया। सितंबर 2016 तक पचास से एक सौ खुफिया रिपोर्टें संकलित की गईं। अभियान की गोपनीयता सुनिश्चित की गई, जिसमें पाकिस्तान को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। पैरा कमांडो की टीमों हेलीकॉप्टरों द्वारा अपने लक्ष्यों तक पहुँचीं, जिससे त्वरित और आश्चर्यजनक हमला सुनिश्चित हुआ। अभियान का कोड नाम “ऑपरेशन क्रॉस बॉर्डर” था।

29 सितंबर, 2016 को सुबह तीन बजकर तीस मिनट पर भारतीय बलों ने नियंत्रण रेखा पार की और पहचाने गए लॉन्च पैडों पर हमला किया। अभियान लगभग चार घंटे तक चला, जिसमें अड़तीस आतंकवादी मारे गए और कई घायल हुए। भारतीय सेना ने गोला-बारूद डिपो और संचार उपकरण नष्ट किए। स्ट्राइक में सत्तर से अस्सी कमांडो शामिल थे, जो रात-दृष्टि चशमों और संचार जैमर का उपयोग कर रहे थे। बल बिना किसी हताहत के वापस लौटे, जिसने अभियान की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। स्ट्राइक को भारतीय वायु सेना ने हेलीकॉप्टर समर्थन प्रदान किया और भारतीय नौसेना ने रसद तत्परता सुनिश्चित की।

चुनौतियाँ और सफलताएँ

सर्जिकल स्ट्राइक ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने का जोखिम और अभियान की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता शामिल थी। हालांकि, इसे बिना किसी कमी के निष्पादित किया गया, जिसमें कोई भारतीय हताहत नहीं हुआ और आतंकवादी ढाँचे को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचा। इस अभियान ने नियंत्रण रेखा के पार सटीक स्ट्राइक करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिसने पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों को एक मजबूत संदेश दिया। अनुमानित चालीस से पचास आतंकवादी शिविर नष्ट किए गए। स्ट्राइक भारत की पिछली संयम नीति से एक महत्वपूर्ण विचलन थी, जो सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण में बदलाव को चिह्नित करती थी, जिसमें सरकार ने अधिक सक्रिय रुख अपनाया।

राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव

सर्जिकल स्ट्राइक के तात्कालिक राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम थे। घरेलू स्तर पर, स्ट्राइक को भारत में आतंकवाद के खिलाफ एक साहसिक और निर्णायक कार्रवाई के रूप में सराहा गया। इससे सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के लिए जन समर्थन बढ़ा, जिसमें स्ट्राइक के बाद अनुमोदन रेटिंग में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने स्ट्राइक होने से इनकार किया और भारत पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी, जिसमें अमेरिका ने तनाव कम करने का आह्वान किया। भारत-पाकिस्तान संबंध और अधिक तनावपूर्ण हुए, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सैन्य कार्रवाइयों, जैसे भारतीय प्रशासित कश्मीर में हवाई हमलों, के साथ जवाब दिया। हालांकि, स्ट्राइक ने अल्पकाल में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों को रोका, जिसमें 2017 तक हमलों में बीस प्रतिशत की कमी आई।

प्रभाव और विरासत

2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें आतंकवादी खतरों के खिलाफ सक्रिय और पूर्वनियोजित कार्रवाई पर जोर दिया गया। इसने भविष्य के अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की, जिसमें 2019 का बालाकोट हवाई हमला शामिल है, और भारत की नियंत्रण रेखा पार खतरे को बेअसर करने की इच्छा को प्रदर्शित किया। स्ट्राइक ने आधुनिक युद्ध में खुफिया, विशेष बलों और अंतर-सेवा समन्वय के महत्व को भी उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना हुई। सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों को आकार दिया, जिसने सक्रिय रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

अध्याय 28:

बालाकोट हवाई हमला (2019)

26 फरवरी, 2019 को भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया बालाकोट हवाई हमला भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था। 14 फरवरी, 2019 को हुए घातक पुलवामा हमले, जिसमें चालीस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की जान गई थी, के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शिविर पर एक पूर्वनियोजित हवाई हमला किया। इस अभियान, जिसका कोड नाम “ऑपरेशन बंदर” था, ने 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तानी धरती पर हवाई हमले को चिह्नित किया, जिसने सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के सक्रिय उपायों की ओर बदलाव को रेखांकित किया।

ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ

पुलवामा हमला जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य आदिल अहमद डार द्वारा किया गया एक आत्मघाती बम विस्फोट था, जिसने जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल काफिले में विस्फोटकों से भरे वाहन से टक्कर मारी। इस हमले में चालीस कर्मी मारे गए, जो क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था और भारत में इसकी व्यापक निंदा हुई। भारत सरकार ने अपराधियों और उनके प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद इस हमले के लिए जिम्मेदार था, जिसमें इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस का समर्थन था। यह हमला 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बढ़े तनाव के बीच हुआ, जिसने कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर उग्रवाद को बढ़ावा दिया। पुलवामा हमले के बाद, भारत ने सैन्य जवाब देने का निर्णय लिया, जो इसकी पिछली संयम नीति से एक बदलाव था। नियंत्रण रेखा के पार हवाई हमले करने का निर्णय एक साहसिक कदम था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों को यह संदेश देना था कि भारत सीमा-पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2019 तक हर वर्ष दो सौ से तीन सौ घुसपैठ की कोशिशें दर्ज की गईं।

योजना और निष्पादन

बालाकोट हवाई हमले की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी और इसमें भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय शामिल था। भारतीय वायु सेना को हमले को निष्पादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें बारह मिराज-दो हजार लड़ाकू विमान सटीक-निर्देशित हथियारों से लैस थे, जिनमें इजराइली स्पाइस-दो हजार बम शामिल थे, जो चार सौ किलोग्राम से अधिक उच्च विस्फोटकों को साठ किलोमीटर की दूरी तक पहुँचाने में सक्षम थे। लक्ष्य की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शिविर के रूप में की गई, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट में, भारतीय प्रशासित कश्मीर की सीमा के पास स्थित था। यह जानकारी उपग्रह चित्रों और मानव स्रोतों के माध्यम से एकत्रित खुफिया पर आधारित थी। इस अभियान का कोड नाम “ऑपरेशन बंदर” रखा गया और इसे पूर्ण गोपनीयता में तैयार किया गया, जिसमें केवल चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। लक्ष्य की पुष्टि और नागरिक हताहतों से बचने के लिए भारतीय वायु सेना ने टोह मिशन चलाए, जिसमें रात-दृष्टि उपकरण और मानव रहित यानों का उपयोग किया गया। फरवरी 2019 तक पचास से एक सौ खुफिया रिपोर्टें संकलित की गईं। 25 और 26 फरवरी, 2019 की रात को विमान भारत में स्थित हवाई अड्डों से उड़े, नियंत्रण रेखा पार की और रडार से बचने के लिए कम ऊँचाई पर उड़ते हुए बालाकोट पहुँचे। सुबह लगभग तीन बजकर तीस मिनट पर विमानों ने लेज़र-निर्देशित बमों के साथ अपने पेलोड को गिराया। पूरा अभियान लगभग इक्कीस मिनट चला। भारत सरकार ने दावा किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मसूद अजहर का भाई अब्दुल सलाम भट्टावी भी शामिल था, और शिविर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसमें अनुमानित तीन सौ से तीन सौ पचास हताहत हुए। हालांकि, पाकिस्तान ने किसी भी हताहत से इनकार किया और दावा किया कि भारतीय विमानों ने बालाकोट के पास एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में बम गिराए, जिसमें बाद में उपग्रह चित्रों से पता चला कि इमारतें अब भी खड़ी थीं।

परिणाम और विवाद

बालाकोट हवाई हमले के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम हुए। अगले दिन, 27 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान ने एक भारतीय मिग-इक्कीस लड़ाकू विमान को मार गिराया और इसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को एक हवाई मुठभेड़ के

दौरान बंदी बना लिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने दो भारतीय विमान मार गिराए, लेकिन इस दावे को बाद में विश्लेषकों और अमेरिकी रक्षा विभाग ने विवादित किया और कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी। विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी ने एक कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया, जिसमें भारत ने उनकी तत्काल रिहाई की माँग की। साठ घंटे की कैद के बाद, उन्हें एक मार्च, 2019 को भारत को सौंप दिया गया, जिससे तनाव कम हुआ, जिसमें अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता भी शामिल थी। उपग्रह चित्रों और स्वतंत्र विश्लेषणों, जैसे अटलांटिक काउंसिल की डिजिटल फॉरेंसिक्स लैब और रॉयटर्स ने संकेत दिया कि भारतीय हवाई हमले ने कोई बड़ा लक्ष्य नष्ट नहीं किया और कथित जैश-ए-मोहम्मद शिविर की इमारतें बरकरार रहीं। इससे हमले की प्रभावशीलता और भारत के दावों की सत्यता पर सवाल उठे, विशेषकर 2019 के आम चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के संदर्भ में। फिर भी, बालाकोट हवाई हमला भारत द्वारा आत्मरक्षा के अपने अधिकार को दृढ़ता से स्थापित करने और यह संदेश देने के लिए एक साहसिक कदम माना गया कि वह पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। इस हमले ने राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाया और भारत की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें हमले के बाद जन अनुमोदन रेटिंग में दस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बालाकोट हवाई हमले के बाद के घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की कार्रवाई का आधिकारिक समर्थन नहीं किया, लेकिन दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव कम करने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तनाव कम करने का आह्वान किया। अन्य देशों, जैसे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी यही अपील की। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश की और भारत पर अपनी संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया तथा संयुक्त राष्ट्र में विरोध दर्ज किया। भारत ने अपने कार्यों को आतंकवाद के जवाब में उचित ठहराया, जिसमें विदेश सचिव विजय गोखले ने विभिन्न देशों के राजनयिकों को विस्तृत जानकारी दी। बालाकोट हवाई हमले के भारत-पाकिस्तान संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर कई दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। इसने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में बदलाव को दर्शाया, जिसमें

सरकार ने सीमा-पार आतंकवाद से निपटने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया, जिसने भविष्य की सैन्य कार्रवाइयों के लिए एक मिसाल कायम की। हालांकि, इस हमले ने दो परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच निरंतर संघर्ष वाले क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने की जटिलताओं को भी उजागर किया, जिसमें तनाव बढ़ने का जोखिम हमेशा बना रहा। बालाकोट हवाई हमले ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीतियों को आकार दिया और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निरंतर सतर्कता और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

अध्याय 29:

ऑपरेशन ऑल आउट

अभियान की पृष्ठभूमि

सन् 2017 में भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को दबाने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से जाना गया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र से उग्रवादियों और आतंकवादियों का सफाया कर शांति और स्थिरता बहाल करना था। इसकी पृष्ठभूमि में घाटी में बढ़ते उग्रवाद, पाकिस्तान से मिल रहे समर्थन और स्थानीय युवाओं की बढ़ती भर्ती शामिल थी। जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और अशांति फैली, जिससे युवाओं का रुझान उग्रवादी संगठनों की ओर बढ़ा। सन् 2016 में लगभग दो सौ युवाओं के उग्रवाद में शामिल होने की खबरें थीं। इसी के चलते भारत सरकार और सुरक्षा बलों ने अधिक आक्रामक आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनाने का निर्णय लिया और सन् 2017 की दूसरी छमाही में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया।

अभियान के उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य लक्ष्य जम्मू और कश्मीर में सक्रिय सभी उग्रवादियों को समाप्त करना, उनके समर्थन नेटवर्क को तोड़ना, सामान्य स्थिति बहाल करना और पाकिस्तान व आतंकवादी संगठनों को यह संदेश देना था कि भारत सीमा-पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभियान के तहत दो सौ अट्ठावन उग्रवादियों को निशाना बनाया गया, जिनमें एक सौ तीस स्थानीय और एक सौ अट्ठाईस विदेशी आतंकवादी थे। इसमें विशेष ध्यान शीर्ष कमांडरों को समाप्त करने पर था।

रणनीति और संचालन के तरीके

ऑपरेशन ऑल आउट के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई, जिसमें सैन्य, खुफिया और प्रशासनिक उपाय शामिल थे। मानव और तकनीकी खुफिया साधनों से ठिकानों की पहचान की गई। मानव रहित यान और निगरानी उपकरणों के माध्यम से

जिलेवार सर्वेक्षण हुआ। भारतीय थल सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य एजेंसियों के बीच संयुक्त अभियानों से एकीकृत कार्रवाई सुनिश्चित की गई। लक्षित हमलों में विशेष खुफिया का उपयोग कर नागरिक हताहत कम करने का प्रयास किया गया। सन् 2018 में उन्तालीस आतंकवादी मारे गए, जिनमें तेईस विदेशी और सोलह स्थानीय थे। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त और चौकियों की स्थापना, जंगलों में कई दिनों तक घेराबंदी और तलाशी अभियान, तथा स्थानीय समुदायों से संपर्क कर विश्वास बहाली भी इस रणनीति का हिस्सा थी।

अभियान का क्रियान्वयन

सन् 2017 की दूसरी छमाही से लेकर सन् 2018 तक इस अभियान में मुठभेड़ों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सन् 2017 में दो सौ से अधिक और सन् 2018 में अनुमानतः दो सौ पंद्रह से दो सौ पच्चीस उग्रवादी मारे गए। कई ओवर-ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनकी संख्या एक सौ से दो सौ के बीच रही। इन गिरफ्तारियों से उग्रवादियों को मिलने वाली रसद और संचार सहायता पर रोक लगी और आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हुई। जंगल क्षेत्रों में घेराबंदी और तलाशी अभियान कई बार छह दिन तक चले। तकनीकी साधनों, जैसे मानव रहित यान और रात-दृष्टि उपकरण, जिनकी संख्या एक सौ से दो सौ के बीच थी, ने अभियान की प्रभावशीलता को बढ़ाया।

उपलब्धियाँ और सकारात्मक प्रभाव

अभियान के चलते उग्रवादी हमलों और नागरिक हताहतों में कमी आई। सन् 2018 तक हमलों में बीस प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। स्थानीय युवाओं की भर्ती घटकर सन् 2016 के दो सौ से सन् 2017 में केवल एक सौ रह गई। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई नेटवर्क और ढाँचे ध्वस्त हुए। सन् 2018 में मारे गए उन्तालीस आतंकवादियों में चौदह जैश-ए-मोहम्मद, ग्यारह लश्कर-ए-तैयबा और छह हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हुई, जिससे स्कूल, व्यापार और आवश्यक सेवाएँ नियमित रूप से चलने लगीं। सन् 2018 तक स्कूलों में उपस्थिति में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा और मेजर मोहित शर्मा व कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च पुरस्कार मिले।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

इसके बावजूद अभियान के दौरान कई चुनौतियाँ और आलोचनाएँ सामने आईं। मुठभेड़ों के दौरान नागरिक हताहत हुए, जिससे जनता में आक्रोश और मानवाधिकार संगठनों की चिंता बढ़ी। सन् 2017 में पचास नागरिकों की मौत और लगभग एक सौ शिकायतें दर्ज हुईं। आलोचकों का कहना था कि यह अभियान केवल अल्पकालिक सफलता है और इसने राजनीतिक शिकायतों तथा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे मूल कारणों को संबोधित नहीं किया। सन् 2017 में कश्मीर की बेरोज़गारी दर पच्चीस प्रतिशत थी और पाकिस्तान का समर्थन भी जारी रहा, जिससे सन् 2018 तक हर वर्ष दो सौ से तीन सौ घुसपैठ की कोशिशें होती रहीं।

अभियान का महत्व और निष्कर्ष

ऑपरेशन ऑल आउट ने जम्मू और कश्मीर में भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में सक्रिय और आक्रामक दृष्टिकोण की शुरुआत की। हालांकि, इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक शांति के लिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ राजनीतिक संवाद और सामाजिक-आर्थिक विकास आवश्यक हैं। आगे के वर्षों में कश्मीर में समय-समय पर उग्रवाद में वृद्धि हुई, लेकिन सन् 2020 तक राजनीतिक भागीदारी में दस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिसने उम्मीद बनाए रखी।

ऑपरेशन सिंदूर (2025)

अध्याय 30: पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों की त्वरित और समन्वित कार्रवाई

गृह मंत्रालय की आपात बैठक

पहलगाम नरसंहार की सूचना मिलते ही दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय में आधी रात एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जो देश के सुरक्षा तंत्र की तेज प्रतिक्रिया का प्रतीक थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सेना की सैन्य खुफिया इकाई, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। बैठक का पहला चरण हमले के तथ्यों की पुष्टि और घटनास्थल से प्राप्त प्रारंभिक खुफिया रिपोर्टों के विश्लेषण पर केंद्रित था। दूसरे चरण में सीमा पार और आंतरिक नेटवर्क दोनों के लिए समन्वित रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिक्रिया केवल तात्कालिक न होकर, दीर्घकालिक और रोकथाम-आधारित होनी चाहिए, जिसमें तकनीकी निगरानी, वित्तीय प्रवाह रोकना, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना और जमीनी स्तर पर घुसपैठ की रोकथाम शामिल हो। इस बैठक में तय हुआ कि सभी एजेंसियां साझा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक-समय डेटा आदान-प्रदान करेंगी, ताकि निर्णय लेने में कोई देरी न हो। यह भी सुनिश्चित किया गया कि मीडिया में केवल नियंत्रित और आधिकारिक जानकारी ही दी जाए, ताकि अभियान की गोपनीयता बनी रहे। बैठक में घटनास्थल से मिले सबूतों, जैसे कि उपयोग किए गए हथियारों के प्रकार और हमलावरों की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया, जो पाकिस्तान समर्थित संगठनों की ओर इशारा कर रहे थे। इस आपात बैठक ने भारत की सुरक्षा तंत्र की तत्परता को प्रदर्शित किया, जहां सभी एजेंसियों ने अपने संसाधनों को एकीकृत कर तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई, जो आतंकवाद विरोध में एक मिसाल बन गई।

रॉ द्वारा सीमा पार स्लीपर सेल की पहचान

हमले के कुछ घंटों के भीतर ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपने सिग्नल इंटेलिजेंस और मानव खुफिया नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। पाक-अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, मुजफ्फराबाद, हब्बा खाल और नीलम घाटी जैसे क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता वाली जांच सूची में डाला गया। इन इलाकों में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के स्थानीय स्रोतों ने हथियारों की खेप आने-जाने के मार्ग, गुप्त प्रशिक्षण केंद्रों और संपर्क बिंदुओं की पहचान की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने सीमा पार से प्रसारित रेडियो और डिजिटल संचार को इंटरसेप्ट कर एन्क्रिप्शन पैटर्न तोड़े, जिससे कई स्लीपर सेल की बातचीत और उनके कमांडरों के कोडवर्ड उजागर हुए। इसके साथ ही, उपग्रह चित्रों और ड्रोन सर्विलांस से वहां की गतिविधियों की पुष्टि की गई। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ कि हमले की योजना सीमा पार से निर्देशित थी और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का गुप्त समर्थन शामिल था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की पहचान ने कई स्लीपर सेल को निष्क्रिय करने में मदद की, जहां स्थानीय एजेंटों ने घुसपैठ के मार्गों का मानचित्रण किया और हथियारों की तस्करी के नेटवर्क को उजागर किया। इस पहचान ने साबित किया कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की सीमा पार क्षमता विश्व स्तर की है, जो भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आईबी द्वारा भारत के अंदर मॉड्यूल की सक्रिय ट्रैकिंग

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमले के तुरंत बाद देश के भीतर फैले नौ मॉड्यूल की पहचान की, जिनका संबंध टीआरएफ और आईएसआई से था। इन मॉड्यूल के सदस्य अलग-अलग राज्यों में फैले थे, ताकि किसी एक के पकड़े जाने पर पूरी श्रृंखला का खुलासा न हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विशेष तकनीकी टीमों को सक्रिय कर मोबाइल कॉल डेटा रिकॉर्ड, इंटरनेट ब्राउज़िंग इतिहास, सोशल मीडिया गतिविधियों और ईमेल ट्रैफिक का विश्लेषण किया। डार्क वेब पर इनके लेन-देन और चैट समूहों की निगरानी से हथियार खरीद, विस्फोटक बनाने के निर्देश और धन भेजने के संकेत मिले। कई मामलों में स्थानीय सहयोगियों के बैंक खातों में संदिग्ध विदेशी ट्रांसफर का पता चला, जिन्हें तुरंत ब्लॉक किया गया। इस ट्रैकिंग से कुछ मॉड्यूल समय रहते निष्क्रिय कर दिए गए और कई सदस्यों को गुप्त रूप से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इंटेलिजेंस

ब्यूरो की ट्रेकिंग ने डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग कर मॉड्यूल के सदस्यों की दैनिक गतिविधियों का पैटर्न समझा, जिससे छापेमारी सफल हुई। इस कार्रवाई ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की आंतरिक सुरक्षा में भूमिका को मजबूत किया, और आतंकी नेटवर्क को गंभीर झटका दिया।

सेना की खुफिया इकाई द्वारा सीमांत क्षेत्रों में उच्च अलर्ट

हमले के बाद सेना की सैन्य खुफिया इकाई ने जम्मू, पूंछ, कुपवाड़ा, बारामूला और राजौरी सेक्टर में तैनात सभी चौकियों को उच्चतम सतर्कता पर रखा। एलओसी के पास तैनात यूनिट्स को रात्रि दृष्टि उपकरण, थर्मल इमेजर और सेंसर प्रणाली से लैस किया गया। गश्त की आवृत्ति बढ़ाने के साथ-साथ 'आश्चर्य गश्त' और 'घात लगाकर हमला' शुरू किए गए, जिनका उद्देश्य था घुसपैठियों को बिना पूर्व सूचना के पकड़ना। सीमावर्ती गांवों में नागरिक सुरक्षा समितियों को पुनः सक्रिय किया गया और ग्रामीणों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर प्रतिक्रिया पंद्रह मिनट के भीतर दी जा सके। सैन्य खुफिया इकाई ने ड्रोन और उपग्रह निगरानी का उपयोग कर सीमांत क्षेत्रों की वास्तविक-समय निगरानी की, जिससे घुसपैठ के प्रयास विफल हुए। इस उच्च अलर्ट ने साबित किया कि भारतीय सेना की खुफिया क्षमता सीमा सुरक्षा में निर्णायक है, और दुश्मन की योजनाओं को पहले से भांप सकती है।

एनटीआरओ द्वारा उपग्रह निगरानी की शुरुआत

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने हमले के बाद नियंत्रण रेखा और पाक-अधिकृत कश्मीर के रणनीतिक स्थानों पर निरंतर उपग्रह निगरानी शुरू की। उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और थर्मल स्कैनिंग तकनीक के माध्यम से दिन-रात संदिग्ध गतिविधियों की लाइव तस्वीरें ली गईं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्कैनिंग से गुप्त रेडियो टावर और संचार उपकरणों का पता लगाया गया। इन आंकड़ों को सेना, सीमा सुरक्षा बल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ साझा किया गया, जिससे संदिग्ध ठिकानों की सटीक लोकेशन मिल सकी। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने अपनी विश्लेषण टीम के माध्यम से संभावित हमलों के पैटर्न तैयार किए, जिससे जमीनी बलों को पहले से तैयारी का लाभ मिला। उपग्रह निगरानी ने हथियारों की तस्करी और घुसपैठ के मार्गों

को उजागर किया, जिससे कई ऑपरेशन सफल हुए। इस शुरुआत ने साबित किया कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की तकनीक भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और अंतरिक्ष-आधारित निगरानी को मजबूत बनाती है।

विशेष बलों की गोपनीय तैनाती

उत्तरी कमान ने पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल), वायुसेना के गरुड़ कमांडो और नौसेना के समुद्री कमांडो को संवेदनशील इलाकों में गुप्त रूप से तैनात किया। इनके ठिकानों और मूवमेंट को इतनी सावधानी से छिपाया गया कि स्थानीय आबादी और मीडिया को इसकी भनक तक न लगी। इन बलों को ऑपरेशन के लिए उच्चतम तत्परता की स्थिति में रखा गया, ताकि आदेश मिलते ही पंद्रह मिनट के भीतर कार्रवाई शुरू हो सके। इनके हथियार, संचार उपकरण और आपूर्ति श्रृंखला पहले से व्यवस्थित की गई, जिससे अभियान में कोई देरी न हो। विशेष बलों की तैनाती में उन्नत छलावरण और गुप्त संचार तकनीक का उपयोग हुआ, जिससे दुश्मन को पता नहीं चला। इस गोपनीयता ने कई घुसपैठ प्रयासों को विफल किया, और साबित किया कि भारतीय विशेष बल गोपनीय ऑपरेशनों में माहिर हैं।

मोबाइल संकेत इंटरसेप्ट टीमों की तैनाती

कश्मीर घाटी, दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों में मोबाइल इंटरसेप्ट यूनिट्स को सक्रिय किया गया। इन टीमों ने केवल फोन कॉल ही नहीं, बल्कि डेटा पैकेट्स, जीपीएस लोकेशन, और एन्क्रिप्टेड चैट्स तक को कैप्चर किया। कई संदिग्धों के 'कोडवर्ड' और लोकेशन-शेयरिंग पैटर्न डिकोड किए गए, जिससे उनके मिलने-जुलने के समय और स्थान का अनुमान लगाकर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने छापेमारी की। इस कार्रवाई से कई गुप्त चैनल टूट गए और मॉड्यूल्स का आपसी समन्वय समाप्त हो गया। इंटरसेप्ट टीमों ने उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग कर संकेतों को डिकोड किया, जिससे आतंकी योजनाओं का खुलासा हुआ। इस तैनाती ने साबित किया कि मोबाइल ट्रैकिंग आतंकवाद विरोध में निर्णायक है, और भारत की तकनीकी क्षमता उन्नत है।

आतंकी धन चैनलों की निगरानी

वित्तीय खुफिया इकाई ने हवाला नेटवर्क, क्रिप्टोकॉरेसी वॉलेट्स, विदेशी गैर-सरकारी संगठन फंडिंग और नकली कंपनियों के जरिए होने वाले पैसों के प्रवाह पर विशेष निगरानी रखी। संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल फ्रीज किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी जानकारी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल और इंटरपोल से साझा की गई। हवाला डीलरों की पूछताछ से कई चैनलों की कड़ियां सीमा पार के नेटवर्क से जुड़ी पाई गईं, जिन्हें बंद कर दिया गया। इससे आतंकियों की वित्तीय आपूर्ति रुक गई और उनकी योजनाएं अधूरी रह गईं। निगरानी में ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग किया गया, जिससे क्रिप्टो ट्रांसफर ट्रैक हुए। इस कार्रवाई ने आतंकी फंडिंग को गंभीर झटका दिया, और साबित किया कि वित्तीय निगरानी आतंकवाद रोकथाम में महत्वपूर्ण है।

नागरिक खुफिया और स्थानीय मुखबिर नेटवर्क का पुनर्गठन

कश्मीर घाटी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और स्थानीय पुलिस ने अपने पुराने मुखबिर नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया, जो सुरक्षा कारणों से पहले निष्क्रिय हो गया था। स्थानीय भाषा और भूगोल से परिचित युवाओं, व्यापारियों और ड्राइवरों को फिर से जोड़ा गया। इन्हें सुरक्षा बलों के साथ सीधा संपर्क और सुरक्षित संचार माध्यम दिए गए, ताकि वे तुरंत सूचना दे सकें। इन मुखबिरों से आतंकी गतिविधियों, संदिग्ध लोगों की आवाजाही और हथियार छिपाने के ठिकानों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी मिली। इससे न केवल जमीनी स्तर पर खतरे की पहचान हुई, बल्कि त्वरित कार्रवाई भी संभव हुई। पुनर्गठन में मुखबिरों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए, जैसे कि गुप्त पहचान और आपातकालीन सहायता। इस नेटवर्क ने कई संदिग्धों को पकड़ने में मदद की, और साबित किया कि नागरिक सहयोग आतंकवाद विरोध में निर्णायक है।

अध्याय 31:

ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट से भारत की जवाबी कार्रवाई

गरुड़-स्काईस्ट्राइकर ड्रोन ऑपरेशन

भारत की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई के पहले चरण में गरुड़ और स्काईस्ट्राइकर ड्रोनो का संयुक्त इस्तेमाल करते हुए एक सटीक और जोखिम-मुक्त ऑपरेशन अंजाम दिया। गरुड़ ड्रोनो को सीमावर्ती इलाकों में निरंतर निगरानी के लिए तैनात किया गया, जिनमें लगे उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरे, इन्फ्रारेड सेंसर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम ने दिन-रात लक्ष्य की पहचान सुनिश्चित की। यह डेटा वास्तविक-समय में वायुसेना के नियंत्रण कक्ष को भेजा गया, जहां से स्काईस्ट्राइकर लूटिंग म्यूनिशन को लक्ष्य निर्देशांक दिए गए। स्काईस्ट्राइकर, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित लक्ष्य लॉकिंग और जीपीएस मार्गदर्शन से लैस था, ने पहुंचकर स्वयं को लक्ष्य पर विस्फोटित कर दिया, जिससे आतंकी शिविर और हथियार भंडार नष्ट हुए। इस चरण में किसी भी भारतीय जवान को जमीनी जोखिम नहीं उठाना पड़ा। सीमावर्ती गांवों से मिली खुफिया जानकारी ने ऑपरेशन की सटीकता को और मजबूत किया, और इस कार्रवाई ने टीआरएफ की भविष्य की ड्रोन-आधारित योजनाओं को निष्क्रिय कर दिया। गरुड़ ड्रोन भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक उन्नत मानवरहित हवाई वाहन है, जो उच्च ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है और दुश्मन के ठिकानों की विस्तृत इमेजरी प्रदान करता है। स्काईस्ट्राइकर, इजराइली तकनीक पर आधारित, लूटिंग म्यूनिशन है जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते हुए सही समय पर विस्फोट करता है, जिसकी सटीकता नब्बे प्रतिशत से अधिक है। इस संयुक्त ऑपरेशन ने साबित किया कि ड्रोन तकनीक आधुनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, जहां मानव जोखिम न्यूनतम होता है और प्रभाव अधिकतम। इस कार्रवाई ने टीआरएफ के ड्रोन हमलों की क्षमता को गंभीर झटका दिया, और भारत की ड्रोन रणनीति को वैश्विक स्तर पर सराहा गया।

ब्रह्मोस का निर्णायक प्रहार

दूसरे चरण में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उपयोग कर दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर गहरा प्रहार किया गया। ध्वनि की गति से तीन गुना तेज यह मिसाइल दुश्मन के रडार से बचते हुए कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्यों तक पहुँची। नौ उच्च-महत्व वाले ठिकाने - जिनमें प्रशिक्षण शिविर, गोला-बारूद भंडार और संचार केंद्र शामिल थे - एक ही लहर में नष्ट कर दिए गए। लक्ष्य-चयन के लिए उपग्रह इमेजरी, सिग्नल इंटेलिजेंस और जमीनी एजेंटों की रिपोर्ट का समेकित विश्लेषण किया गया, ताकि नागरिक हानि पूरी तरह रोकी जा सके। ब्रह्मोस की उच्च सटीकता और भारी वारहेड क्षमता ने सुनिश्चित किया कि दुश्मन की रक्षा क्षमता तत्काल प्रभावित हो, जिससे आगे की कार्रवाइयों के लिए रास्ता साफ हुआ। इस हमले ने सामरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों मोर्चों पर टीआरएफ को बड़ा झटका दिया। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त उद्यम का उत्पाद है, जो तीन सौ से पांच सौ किलोमीटर की रेंज और सुपरसोनिक गति के साथ दुश्मन के वायु रक्षा सिस्टम को भेद सकती है। इस मिसाइल की सटीकता मिलीमीटर स्तर की है, जो जीपीएस और इंटरटियल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। ठिकानों के चयन में उपग्रह डेटा का उपयोग कर नागरिक क्षेत्रों से दूरी सुनिश्चित की गई, जिससे न्यूनतम संपार्श्विक क्षति हुई। इस प्रहार ने टीआरएफ की कमान श्रृंखला को तोड़ा, और उनके प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त कर दिया, जो उनकी भर्ती क्षमता को गंभीर प्रभावित करता है। इस निर्णायक प्रहार ने साबित किया कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत की रक्षा रणनीति का अभिन्न हिस्सा हैं, जो दुश्मन को त्वरित और प्रभावी जवाब देती हैं।

सैटेलाइट डेटा और आईएसआरओ निगरानी

तीसरे चरण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कार्टोसैट और रिसैट जैसे उपग्रहों ने उच्च-रिजॉल्यूशन इमेजरी उपलब्ध कराई, जिससे स्थायी और चलायमान दोनों तरह के लक्ष्यों की पहचान संभव हुई। लाइव इमेजिंग और थर्मल स्कैनिंग से दुश्मन के हथियार ढोने वाले काफिले, मोबाइल कमान पोस्ट और संचार केंद्र चिन्हित हुए। यह डेटा सीधे एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली को भेजा गया, जहां इसे हवाई हमलों के सटीक निर्देशन में प्रयोग किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तकनीक ने ऑपरेशन को लचीलापन दिया, जिससे बदलते हालात में लक्ष्य सूची तुरंत अपडेट हो सकी। नागरिक क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सटीक

लक्ष्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संयमित और जिम्मेदार कार्यवाही की छवि और मजबूत हुई। कार्टोसैट उपग्रह उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेज प्रदान करता है, जो एक मीटर से कम की वस्तुओं को पहचान सकता है, जबकि रिसैट मौसम से अप्रभावित रडार इमेजरी देता है। थर्मल स्कैनिंग ने रात के समय लक्ष्यों की पहचान की, और लाइव डेटा ने हमलों की सटीकता बढ़ाई। इस निगरानी ने साबित किया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपग्रह प्रौद्योगिकी रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाती है, और दुश्मन की गतिविधियों को पूरी तरह ट्रैक कर सकती है।

स्कैल्प और हैमर स्ट्राइक

चौथे चरण में वायुसेना ने राफेल और सुखोई-तीस एमकेआई विमानों से स्कैल्प और हैमर जैसे अत्याधुनिक हथियार दागे। स्कैल्प लंबी दूरी की वायु-लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जो गहरे भूमिगत और किलेबंद ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। इन मिसाइलों ने पहाड़ी सुरंगों, हथियार भंडार और छिपे हुए कमान पोस्ट को निशाना बनाया। हैमर (उच्च चपलता मॉड्यूलर म्यूनिशन विस्तारित रेंज) बमों का उपयोग उन ठिकानों पर किया गया जो शहरी इलाकों के करीब थे, ताकि केवल लक्ष्य को नष्ट किया जाए और आसपास की संरचनाएं सुरक्षित रहें। इस चरण में भी लक्ष्य चयन के लिए उपग्रह और ड्रोन से मिले डेटा का उपयोग किया गया, जिससे हमले के बाद दुश्मन की कमान-एवं-नियंत्रण संरचना लगभग ठप हो गई। स्कैल्प की रेंज पांच सौ किलोमीटर से अधिक है, जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बचती है, जबकि हैमर की चपलता ठिकानों को सटीकता से भेदती है। इन स्ट्राइक ने टीआरएफ की बुनियादी ढांचे को ध्वस्त किया, और साबित किया कि भारतीय वायुसेना की हथियार प्रणाली विश्व स्तर की है।

एकीकृत कमान एवं नियंत्रण की भूमिका

पूरे ऑपरेशन में एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली ने केंद्रीय समन्वय की भूमिका निभाई। ड्रोन, उपग्रह, रडार और मानव खुफिया से प्राप्त सभी डेटा को एकीकृत कर वास्तविक समय में युद्धक्षेत्र की तस्वीर बनाई गई। इससे हमलों का क्रम, समय और हथियारों का चयन सटीकता से किया गया। एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली ने तीनों सेनाओं - थल, वायु और नौसेना - के बीच भी सहज संचार बनाए

रखा, जिससे यह बहु-क्षेत्रीय ऑपरेशन सफलतापूर्वक चला। इस व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि हर चरण की कार्रवाई एक-दूसरे के पूरक रूप में हो और दुश्मन को प्रतिक्रिया का कोई अवसर न मिले। एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण ने डेटा को तेजी से संसाधित किया, और रणनीतिक निर्णयों को त्वरित बनाया। इस भूमिका ने साबित किया कि भारत की कमान प्रणाली उन्नत है, और बहु-सेना समन्वय में माहिर है।

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सिग्नल जैमिंग

ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रहा, जिसके अंतर्गत दुश्मन के संचार नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए उन्नत जैमिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना और थलसेना की इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स ने ड्रोन नियंत्रण लिंक, वॉकी-टॉकी नेटवर्क और मोबाइल संचार चैनलों को बाधित किया। सिग्नल इंटरसेप्ट करके दुश्मन की योजनाओं का पूर्वानुमान लगाया गया और उसी के अनुसार हमलों की रणनीति बदली गई। इससे दुश्मन के आंतरिक समन्वय में भारी गिरावट आई और उसकी प्रतिक्रिया क्षमताएं गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में फ्रीक्वेंसी होपिंग जैमिंग का उपयोग हुआ, जो दुश्मन के सिग्नल को झूठे लक्ष्यों से भर देता है। इस जैमिंग ने टीआरएफ के संचार को ठप कर दिया, और साबित किया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आधुनिक रक्षा का अभिन्न हिस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और रणनीतिक संदेश

इस पूरे ऑपरेशन ने न केवल टीआरएफ की साजिश को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश भी दिया कि भारत तकनीकी और सामरिक दोनों स्तरों पर निर्णायक बढ़त रखता है। संयुक्त राष्ट्र और कई प्रमुख देशों ने नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सटीक हमले करने के लिए भारत की प्रशंसा की। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार, संयमित और तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत हुई। इस रणनीतिक सफलता ने न केवल तत्काल खतरे को खत्म किया, बल्कि भविष्य में ऐसे किसी भी हमले की योजना बनाने वालों के मनोबल को भी तोड़ दिया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की कार्रवाई को आतंकवाद विरोध में मिसाल बताया, और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया। इस संदेश ने टीआरएफ के समर्थकों को चेतावनी दी, और भारत की रक्षा क्षमता को वैश्विक मान्यता दी।

अध्याय 32:

नियंत्रण रेखा पार सर्जिकल हमला - टीआरएफ पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया

ऑपरेशन सिंदूर - समय और अवधि

अप्रैल की उस ठंडी रात में, जब नियंत्रण रेखा के पार हल्की-सी हवा भी तनाव में डूबी हुई थी, भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान अपने बेस से उड़ान भर चुके थे। रात के ठीक एक बजे, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ - एक ऐसा मिशन जिसे केवल तेईस मिनट में निर्णायक अंजाम तक पहुँचना था। नौ अलग-अलग लक्ष्यों पर हमले के लिए हर सेकंड का उपयोग किया गया। इन लक्ष्यों की पहचान महीनों की निगरानी, उपग्रह इमेजरी, मानव खुफिया और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट से की गई थी। ऑपरेशन की योजना में भारतीय विशेष बलों की टुकड़ियों ने नियंत्रण रेखा पार कर दुश्मन के ठिकानों की सटीक स्थिति की पुष्टि की, जिससे हमले की सटीकता सुनिश्चित हुई। पहले दस मिनट में इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से दुश्मन के रडार और संचार को बाधित किया गया, जिससे पाकिस्तानी पक्ष को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। अगले दस मिनट में मिसाइल और ड्रोन हमलों ने ठिकानों को नष्ट किया, और अंतिम तीन मिनट में निकासी और मूल्यांकन पूरा हुआ। इस समयबद्धता ने साबित किया कि भारतीय सैन्य रणनीति न केवल तेज है बल्कि न्यूनतम संसाधनों के साथ अधिकतम प्रभाव पैदा करने में सक्षम है, जो वैश्विक सैन्य अभियानों में एक उदाहरण बन गया। इस ऑपरेशन ने टीआरएफ की महीनों की तैयारी को चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया, और भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को वैश्विक स्तर पर सराहा गया।

विशेष बलों की गोपनीय रणनीति

वायुसेना की कार्रवाई के समानांतर, ज़मीन पर एक और ऑपरेशन चुपचाप चल रहा था। पैरा विशेष बल, समुद्री कमांडो और गरुड़ कमांडो का एक संयुक्त दल, नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ कर चुका था। ये टीमें पर्वतीय पगडंडियों, सूखे नालों और वन क्षेत्रों का उपयोग कर चुपचाप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रही थीं। उनके पास अत्याधुनिक साइलेंट रेडियो सिस्टम, रात्रि दृष्टि चश्मे और मिनी-ड्रोन थे, जिनसे वे

दुश्मन की गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। गोपनीय रणनीति में विशेष बलों ने दुश्मन के गार्डों को चुपचाप निष्क्रिय किया, जिससे ठिकानों तक पहुंचना संभव हुआ। मिनी-ड्रोन ने वास्तविक-समय वीडियो फीड प्रदान की, जिससे लक्ष्यों की सटीक स्थिति की पुष्टि हुई। कुछ लक्ष्यों को सीधे ग्राउंड-लेवल पर नष्ट किया गया, जबकि अन्य पर लूटिंग म्यूनिशन का प्रयोग किया गया, जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते हुए सही समय पर विस्फोट करते हैं। इस रणनीति ने न केवल आतंकी ढांचे को खत्म किया, बल्कि पाकिस्तान की अग्रिम पोस्टों में भय और भ्रम भी फैला दिया। विशेष बलों की प्रशिक्षण में शामिल उन्नत तकनीक, जैसे कि थर्मल इमेजिंग और साइलेंट हथियार, ने ऑपरेशन को गोपनीय रखा, और दुश्मन को प्रतिक्रिया का अवसर नहीं मिला। इस गोपनीयता ने साबित किया कि भारतीय विशेष बल विश्व स्तर के हैं, और नियंत्रण रेखा पार अभियानों में सक्षम हैं, जो रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नौ स्थलों पर सर्जिकल स्ट्राइक

इस ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा था - नौ अलग-अलग स्थानों पर एक साथ हमला करना। इनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षण शिविर शामिल थे। इन शिविरों से न केवल घुसपैठिए भेजे जाते थे, बल्कि आईईडी, ड्रोन और स्नाइपर ऑपरेशन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने वास्तविक-समय लक्ष्यीकरण डेटा का उपयोग कर इन ठिकानों पर सटीक वार किए। परिणामस्वरूप, भारी हथियारों के भंडार, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक सामग्री नष्ट हो गई। इन शिविरों की निगरानी उपग्रह और ड्रोन से की गई थी, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियों का पैटर्न समझा गया। हमले के दौरान विशेष बलों ने ग्राउंड से समर्थन प्रदान किया, जिससे ठिकानों के अंदरूनी हिस्सों को नष्ट किया गया। इन प्रहारों ने टीआरएफ की भर्ती और प्रशिक्षण क्षमता को गंभीर क्षति पहुंचाई, और कई प्रमुख कमांडर मारे गए। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने साबित किया कि भारत की सैन्य रणनीति बहु-आयामी है, जहां वायु, भूमि और खुफिया का संयोजन निर्णायक होता है। इस ऑपरेशन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षमता को प्रमाणित किया, और दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जो रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर है।

बिना साइड इफेक्ट क्षति का निशाना

अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी - “शून्य संपार्श्विक क्षति”। हर प्रहार को इस तरह डिजाइन किया गया था कि केवल आतंकी ठिकानों को ही नुकसान पहुँचे और आसपास के नागरिक या सैन्य ठिकाने सुरक्षित रहें। इसके लिए लेज़र-निर्देशित बम और जीपीएस-लॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के तौर पर, एक ठिकाना घने बस्ती के पास था। इस पर हमला तब किया गया जब ड्रोन सर्विलांस से पुष्टि हो गई कि आसपास कोई नागरिक मौजूद नहीं है। इस सावधानी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सैन्य नीति - “न्यूनतम नुकसान, अधिकतम असर” - को और मजबूत किया। लेज़र-निर्देशित बमों की सटीकता ने लक्ष्य को मिलीमीटर स्तर पर भेदा, जिससे आसपास की संरचनाएं सुरक्षित रहीं। इस निशाने की योजना में उपग्रह इमेजरी और मानव खुफिया का उपयोग हुआ, जो नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। इस उपलब्धि ने साबित किया कि भारतीय सैन्य ऑपरेशन नैतिकता और सटीकता का संयोजन हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। इस नीति ने भारत की छवि को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में मजबूत किया, और दुश्मन को मनोवैज्ञानिक दबाव दिया कि भारत की कार्रवाई सटीक और मानवीय है।

आतंकी कमांडरों का सफाया

ऑपरेशन सिंदूर का एक अहम लक्ष्य था - उच्च स्तर के कमांडरों को समाप्त करना। इस सूची में एक सौ से अधिक सक्रिय आतंकी शामिल थे, जिनमें आईसी-आठ सौ चौदह विमान अपहरण कांड का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर भी था। इन कमांडरों की लोकेशन लंबे समय से ट्रैक की जा रही थी। जैसे ही उनका ठिकाना पक्का हुआ, सटीक स्ट्राइक से उनका सफाया कर दिया गया। इनकी मौत से टीआरएफ और उससे जुड़े अन्य संगठनों का कमान-एवं-नियंत्रण प्रणाली बुरी तरह हिल गया। कमांडरों की पहचान खुफिया स्रोतों और उपग्रह निगरानी से की गई, जो उनके दैनिक दिनचर्या का विश्लेषण करती थी। इनके सफाए ने संगठनों की भर्ती और योजना क्षमता को गंभीर क्षति पहुंचाई, और कई सदस्यों ने भय से समर्पण किया। इस सफाए ने साबित किया कि भारत की सैन्य रणनीति न केवल ठिकानों पर केंद्रित है बल्कि नेतृत्व को निशाना बनाकर संगठनों की जड़ें काटती है। इस सफलता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्षमता को प्रमाणित किया, और आतंकी संगठनों में भय का माहौल पैदा किया, जो दीर्घकालिक निरोध में सहायक है।

गोपनीय संचार की प्रगति

ऑपरेशन के दौरान संचार सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी संदेश रेडियो साइलेंट मोड या एन्क्रिप्टेड उपग्रह लिंक के माध्यम से भेजे गए। आईरिसो नेटवर्क ने ऑपरेशन की लोकेशन और मूवमेंट को गुप्त रखा, जिससे दुश्मन को किसी भी प्रकार की पूर्व चेतावनी नहीं मिल सकी। गोपनीय संचार में उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग हुआ, जो 256-बिट कुंजी पर आधारित थी, जिससे इंटरसेप्शन असंभव हो गया। सभी प्लेटफॉर्मों ने साइलेंट मोड में कार्य किया, जहां केवल आवश्यक संदेश भेजे गए। इस प्रगति ने दुश्मन के इंटरसेप्शन स्टेशनों को भ्रमित कर दिया, और वे हमले की दिशा समझ नहीं पाए। इस गोपनीयता ने ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित की, और साबित किया कि भारतीय सैन्य संचार प्रणाली विश्व स्तर की है। इस प्रगति ने भविष्य के अभियानों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, जहां गोपनीयता न केवल रक्षा है बल्कि आक्रमण का हथियार है।

पाक अधिकृत कश्मीर पर मानसिक दबाव

गति और सटीकता के साथ किए गए इन प्रहारों ने पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचों पर गहरा मानसिक दबाव डाला। कई ठिकानों पर मौजूद आतंकी रातों-रात स्थान बदलने लगे। स्थानीय खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले के बाद सीमा पार शिविरों में घबराहट का माहौल था, और कई प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम रोक दिए। यह मनोवैज्ञानिक असर किसी भी भौतिक क्षति से कम महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि इसने भविष्य की घुसपैठ योजनाओं को महीनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। मानसिक दबाव से आतंकी संगठनों में दरारें पड़ीं, जहां सदस्यों ने भय से भागना शुरू किया और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस दबाव ने पाकिस्तान की सहायता नीति पर भी सवाल उठाए, और स्थानीय आबादी में असंतोष बढ़ा। इस प्रभाव ने साबित किया कि सर्जिकल हमले न केवल शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं बल्कि दुश्मन के मनोबल को तोड़कर लंबे समय तक असर छोड़ते हैं। इस रणनीति ने भारत की क्षमता को प्रमाणित किया, और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को गंभीर झटका दिया, जो क्षेत्रीय स्थिरता में सहायक है।

प्रतिक्रिया से पहले कूटनीतिक प्रयास

सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी तैयारी जारी थी। भारत ने कई मित्र देशों को ऑपरेशन के संभावित कारणों और उद्देश्यों के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था, ताकि पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह के दुष्प्रचार का तुरंत जवाब दिया जा सके। हमले से ठीक पहले, कुछ स्थानों पर संयमित हमले किए गए जिनमें क्रूज और ग्लाइड बम का इस्तेमाल हुआ, ताकि संदेश साफ़ रहे - भारत का उद्देश्य केवल आतंकवाद पर चोट करना है, न कि व्यापक युद्ध छेड़ना। कूटनीतिक प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पाकिस्तान के समर्थन को उजागर किया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा। इन प्रयासों ने साबित किया कि भारत की रणनीति सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर संतुलित है। इस कूटनीति ने ऑपरेशन की वैधता को मजबूत किया, और दुश्मन के दुष्प्रचार को विफल कर दिया।

रणनीतिक तकनीकी प्रहार

ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी दृष्टि से भी एक नया मानक स्थापित कर गया। लक्ष्य पहचान से लेकर अंतिम प्रहार तक की पूरी श्रृंखला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित लक्ष्यीकरण प्रणाली, उपग्रह इमेज प्रसंस्करण और वास्तविक-समय डेटा संयोजन का इस्तेमाल हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल हमले सफल रहे, बल्कि भविष्य में ऐसे अभियानों के लिए भारत के पास एक परखा हुआ, उच्च-प्रभावी मॉडल तैयार हो गया। इन प्रहारों ने पाकिस्तान के रक्षा ढांचे को संदेश दिया - भारत की प्रतिक्रिया तेज, सटीक और रणनीतिक होगी, और आतंकवाद की कीमत अब पहले से कहीं अधिक चुकानी पड़ेगी। तकनीकी प्रहार में एकीकृत प्रणालियों का उपयोग हुआ, जो वायुसेना की क्षमता को बढ़ाता है। इस रणनीति ने साबित किया कि भारत की सैन्य तकनीक विश्व स्तर की है, और दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर सकती है।

अध्याय 33:

वायुसेना की मिसाइल रणनीति

निर्णायक वायु प्रहार

टीआरएफ ने एक सुनियोजित रणनीति के तहत भारत के धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की साजिश रची, ताकि न केवल बड़े पैमाने पर जनहानि हो, बल्कि समाज में विभाजन और अविश्वास का माहौल भी पैदा हो। इसका उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को हिलाना और वैश्विक स्तर पर उसकी छवि को धूमिल करना था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश के प्रारंभिक संकेत पकड़ लिए और वायुसेना के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की योजना तैयार की। सुखोई-तीस एमकेआई, मिराज-दो हजार और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली से जोड़ा गया, जिससे उन्हें वास्तविक-समय लक्ष्यीकरण डेटा मिला और बेहद सीमित समय में उच्च-प्रभाव वाले मिसाइल हमले संभव हुए। इन सटीक प्रहारों में आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, हथियारों के भंडार नष्ट हुए और कई प्रमुख कमांडर मारे गए। तकनीकी और सामरिक स्तर पर यह सफलता इस बात का प्रमाण बनी कि भारत किसी भी बड़े पैमाने की आतंकी चुनौती का सामना तेज़ी और दक्षता से कर सकता है। जांच में स्पष्ट हुआ कि हमलों का मूल पाकिस्तानी नेटवर्क था, जिसे भारत की साइबर और सिग्नल खुफिया टीमों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ट्रैक कर कमजोर किया। इस उपलब्धि ने न केवल जनता का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी मजबूत किया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की त्वरित, पेशेवर प्रतिक्रिया की सराहना हुई। इस प्रहार की योजना में वायुसेना की मिसाइल रणनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का उपयोग कर दुश्मन के आधारों को सटीकता से नष्ट किया गया, जिससे आतंकी संगठनों की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह बाधित हो गई। इस रणनीति ने साबित किया कि आधुनिक युद्ध में वायु शक्ति न केवल निर्णायक होती है बल्कि न्यूनतम क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव पैदा करती है, जो वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों द्वारा सराही गई।

वायुस्थल लक्ष्यीकरण

पाकिस्तान के नूर खान और रफीकी वायुसेना अड्डे टीआरएफ की हवाई आपूर्ति और संचालन क्षमता के लिए केंद्रीय केंद्र थे। इन ठिकानों से ड्रोन, निगरानी विमान और लड़ाकू विमानों की तैनाती होती थी, जिससे सीमा-पार घुसपैठ और हमलों की योजना बनाई जाती थी। भारत ने इन्हीं वायुसेना अड्डों को निष्क्रिय करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का चयन किया, जो अपनी सुपरसोनिक गति और सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। स्थानीय सूचनाओं, उपग्रह चित्रों और तकनीकी खुफिया का मिलान कर इन ठिकानों के संवेदनशील हिस्सों-जैसे हवाई पट्टी, कमान केंद्र और ईंधन डिपो-की पहचान की गई। हमले के दौरान ब्रह्मोस ने सेकंडों में अपने लक्ष्य भेदे, जिससे रनवे पर गहरे गड्ढे बन गए और हवाई संचालन ठप हो गया। ड्रोन और लड़ाकू जेट की तैनाती बाधित हुई, सप्लाई लाइनों में अव्यवस्था फैली और पाकिस्तान के रक्षा नेटवर्क पर सिधा दबाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों ने इस ऑपरेशन को 'क्विक-सप्रेसन स्ट्राइक' की श्रेणी में रखा, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की उत्कृष्ट मिसाल मानी जाती है। इस लक्ष्यीकरण में भारतीय वायुसेना की उन्नत सेंसर और उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ, जिसने लक्ष्यों की सटीक स्थिति निर्धारित की और हमले की सफलता सुनिश्चित की। इस रणनीति ने साबित किया कि वायुसेना न केवल हवाई हमले में सक्षम है बल्कि दुश्मन की वायु क्षमता को पूरी तरह लकवाग्रस्त करने में भी माहिर है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

ब्रह्मोस की रणनीतिक अहमियत

ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का नतीजा है, जिसे विश्व की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी दो दशमलव आठ से तीन मैक की गति, तीन सौ से पांच सौ किलोमीटर की रेंज और कम रडार क्रॉस-सेक्शन इसे दुश्मन के वायु-रक्षा सिस्टम के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। इस अभियान में ब्रह्मोस का इस्तेमाल ऐसे लक्ष्यों पर किया गया जिनकी सुरक्षा परतें बेहद मजबूत थीं। राडार से बचते हुए और सेकंडों में लक्ष्य तक पहुंचते हुए, इस मिसाइल ने दुश्मन के वायु रक्षा ठिकानों और हथियार भंडारों पर सटीक प्रहार किया। न्यूनतम सहायक क्षति के साथ अधिकतम रणनीतिक लाभ प्राप्त करना ब्रह्मोस की सबसे बड़ी विशेषता रही। इस कार्रवाई ने यह साबित किया कि भविष्य के उच्च-

जोखिम अभियानों में भी ब्रह्मोस भारत की पहली पसंद रहेगी। ब्रह्मोस की बहुमुखी क्षमता, जैसे कि भूमि, वायु और समुद्र से लॉन्च होने की सुविधा, इसे रणनीतिक रूप से अहम बनाती है, और इसकी सुपरसोनिक गति दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय नहीं देती। इस मिसाइल ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रमाणित किया, जहां कई देश अब ब्रह्मोस के निर्यात के लिए रुचि दिखा रहे हैं, जो भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की उन्नति का प्रमाण है।

बहु-आयामी तकनीकी संयोजन

एकल हथियार प्रणाली पर निर्भर रहने के बजाय भारत ने इस ऑपरेशन में बहु-आयामी हमला रणनीति अपनाई। ब्रह्मोस के साथ स्कैल्प वायु-लॉन्च क्रूज मिसाइल, हैमर बम और स्काईस्ट्राइकर ड्रोन का एकीकृत इस्तेमाल किया गया। स्कैल्प ने गहराई में स्थित कमान केंद्रों को निशाना बनाया, हैमर बम ने बंकर और इमारतों को भेदा, जबकि स्काईस्ट्राइकर ड्रोन ने मोबाइल लॉन्चरों और अस्थायी ठिकानों को नष्ट किया। एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म वास्तविक-समय डेटा और उपग्रह नेविगेशन से संचालित हो रहे थे, जिससे विभिन्न दिशाओं से एक साथ प्रहार संभव हुआ। इस संयोजन ने न केवल दुश्मन को भ्रमित किया, बल्कि उसकी पुनर्संगठन क्षमता को भी काफी हद तक पंगु बना दिया। इस तकनीकी संयोजन में भारतीय वायुसेना की उन्नत संचार प्रणाली और उपग्रह आधारित निगरानी का उपयोग हुआ, जो मिशन की सफलता का आधार बनी। इस रणनीति ने साबित किया कि आधुनिक युद्ध में बहु-आयामी हमले न केवल अधिक प्रभावी होते हैं बल्कि दुश्मन की प्रतिक्रिया को न्यूनतम समय में निष्क्रिय कर देते हैं, जो वैश्विक सैन्य रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है।

रडार व वायु-रक्षा निष्क्रियकरण

पाकिस्तान की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका वायु-रक्षा नेटवर्क और रडार प्रणाली है, जिसे उन्नत चीनी और पश्चिमी तकनीक से सुसज्जित किया गया है। भारत ने इस नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और जैमिंग तकनीक का प्रयोग किया। इन तकनीकों ने दुश्मन के रडार को ब्लाइंड स्पॉट में डाल दिया और उसकी एयर-ट्रैकिंग क्षमता घटा दी। इंटरसेप्शन और प्रतिक्रिया का समय इतना कम हो गया कि भारतीय मिसाइलें और विमान बिना पकड़े अपने लक्ष्य तक

पहुंचे। यह रणनीति ऑपरेशन की सफलता का आधार बनी और पाकिस्तान का रक्षा-कवच कुछ समय के लिए पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में उपयोग की गई फ्रीक्वेंसी जैमिंग ने दुश्मन के राडार सिग्नल को बाधित किया, जिससे झूठे लक्ष्य उत्पन्न हुए और वास्तविक हमले छिप गए। इस तकनीक ने भारतीय वायुसेना को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया, और दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त कर दिया, जो मिशन की सफलता में निर्णायक साबित हुई। इस निष्क्रियकरण ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आधुनिक संघर्षों में पारंपरिक हथियारों से अधिक प्रभावी हो सकता है, जो भारत की तकनीकी प्रगति का प्रमाण है।

हवाई मुकाबला और निरोध

ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का सामना करना पड़ा। मिराज और राफेल विमानों ने अपने बेहतर एवियोनिक्स, मिसाइल रेंज और पायलट प्रशिक्षण के दम पर विरोधी विमानों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस मुकाबले के वीडियो और राडार लॉग अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जारी किए गए, जिससे पाकिस्तान की सामरिक कमजोरियों का पर्दाफाश हुआ। यह घटना दुश्मन के लिए स्पष्ट संदेश थी कि भारत हवाई क्षेत्र की रक्षा और प्रतिआक्रमण में बराबरी से नहीं, बल्कि बहुत से जवाब देता है। हवाई मुकाबले में भारतीय पायलटों की उन्नत प्रशिक्षण और विमानों की सुपीरियर तकनीक ने निर्णायक भूमिका निभाई, जहां एयर-टू-एयर मिसाइलों का उपयोग कर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। इस निरोध ने भारतीय वायुसेना की क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रमाणित किया, और दुश्मन के मनोबल को तोड़ने में सहायक सिद्ध हुआ, जो रणनीतिक युद्ध में महत्वपूर्ण है। इस मुकाबले ने साबित किया कि भारत की वायुसेना न केवल रक्षात्मक है बल्कि आक्रामक हमलों में भी सक्षम है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

मानववैज्ञानिक प्रभाव और संदेश

इस ऑपरेशन का असर केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक मोर्चे पर भी गहरा पड़ा। पाकिस्तान और टीआरएफ के नेतृत्व में भय और असमंजस का माहौल पैदा हुआ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी कहा कि इस तरह के क्रूज मिसाइल हमले

दुश्मन की सामरिक सोच और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करते हैं। सामाजिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जा रहे फर्जी नैरेटिव कमजोर पड़े, जनता का विश्वास बढ़ा और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा मजबूत हुआ। इससे आतंकी भर्ती और प्रचार पर भी लगाम लगी, जो दीर्घकालिक रूप से निरोधक सिद्ध होगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से दुश्मन के संगठन में दरारें पड़ीं, जहां कई सदस्यों ने समर्पण किया और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस संदेश ने भारत की निर्णायक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया, और अन्य राष्ट्रों को आतंकवाद विरोध में सहयोग के लिए प्रेरित किया। इस प्रभाव ने साबित किया कि वायु प्रहार न केवल शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं बल्कि दुश्मन के मनोबल को तोड़कर लंबे समय तक असर छोड़ते हैं, जो रणनीतिक युद्ध की कुंजी है।

वैश्विक प्रतिष्ठा और रणनीतिक साख

इस अभियान ने भारत की वैश्विक रक्षा प्रतिष्ठा को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया। विशेषज्ञों ने इसे सीमित समय में उच्च-प्रभाव और न्यूनतम सहायक क्षति वाले “प्रिसिजन युद्ध” का आदर्श उदाहरण माना। कूटनीतिक दृष्टि से भी भारत को लाभ हुआ—कई देशों ने न केवल इस ऑपरेशन की सराहना की, बल्कि भविष्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारत के साथ सहयोग की इच्छा भी जताई। इसने भारत को हिन्द-प्रशांत से लेकर पश्चिम एशिया तक सुदृढ़ किया। वैश्विक प्रतिष्ठा से भारत की रक्षा तकनीक की मांग बढ़ी, जहां कई देशों ने भारतीय वायुसेना की रणनीति पर चर्चा की और सहयोग के प्रस्ताव दिए। इस साख ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूत स्थिति प्रदान की, जहां आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों में भारत की आवाज प्रभावी हुई। इस अभियान ने साबित किया कि भारत न केवल रक्षात्मक है बल्कि आक्रामक रणनीतियों में भी माहिर है, जो वैश्विक सुरक्षा में भारत की भूमिका को मजबूत बनाता है।

अध्याय 34: इलेक्ट्रॉनिक युद्ध - पाक रडार ध्वंस और भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया

चीनी एडी सिस्टम जामिंग

ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआती लहर में भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के चीनी-संशोधित एयर डिफेंस नेटवर्क को निशाना बनाया। इन रडारों का मूल संस्करण अमेरिकी टीपीएस-77 था, जिसे चीन ने उच्च-क्षमता वाली चार सौ किलोमीटर रेंज निगरानी और लो-ऑब्जर्वेबल लक्ष्य पहचान के लिए उन्नत किया था। टीआरएफ के समर्थन में इन रडारों के माध्यम से सीमा पार हवाई हमलों की चेतावनी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स ने सटीक फ्रीक्वेंसी-होपिंग जामिंग तकनीक का उपयोग कर इन्हें अस्थायी रूप से अंधा कर दिया। जैसे ही जामिंग शुरू हुई, पाक रडार नेटवर्क के कमांड सेंटर में झूठे लक्ष्य दिखाई देने लगे और वास्तविक लक्ष्य स्क्रीन से गायब हो गए। यह स्थिति पाकिस्तान की हवाई रक्षा की रीढ़ को अस्थायी रूप से तोड़ने के समान थी। इस ऑपरेशन ने न केवल तत्काल खतरे को समाप्त किया, बल्कि पाकिस्तान को अपनी आयातित चीनी तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया। फ्रीक्वेंसी-होपिंग जामिंग एक उन्नत तकनीक है, जिसमें जामिंग सिग्नल लगातार फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, जिससे दुश्मन के रडार को लगातार अनुकूलित होने में कठिनाई होती है। यह तकनीक भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई थी, जो पारंपरिक जामिंग से दोगुनी प्रभावी है और दुश्मन की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह भ्रमित कर देती है। इस जामिंग ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क को इतना प्रभावित किया कि उनके कमांडरों को झूठे अलर्ट पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी, जिससे उनके संसाधन व्यर्थ हो गए और भारत को रणनीतिक बढ़त मिली। यह घटना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई, जहां एक देश ने दूसरे की उन्नत रक्षा प्रणाली को बिना शारीरिक हमले के निष्क्रिय कर दिया, जो वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों द्वारा सराही गई।

गुणवत्ता-प्रधान रणनीति: 23 मिनट मिशन

भारत की वायुसेना ने इस ऑपरेशन में समय और सटीकता का ऐसा संयोजन दिखाया कि पूरा मिशन महज तेईस मिनट में संपन्न हुआ। टीआरएफ और उसके पाक समर्थकों की महीनों की तैयारी को इतनी तेजी से नष्ट करना रणनीतिक गुणवत्ता का उदाहरण था। जामिंग के पहले पांच मिनट में ही वायुसेना ने दुश्मन के कम्युनिकेशन लिंक और एयर ट्रेकिंग डेटा को बाधित कर दिया, जिससे उनके इंटरसेप्टर विमानों के उड़ान आदेश तक नहीं पहुंच पाए। अगले दस मिनट में मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए रास्ता साफ हो गया, और अंतिम आठ मिनट में लक्ष्यों पर सटीक वार हुआ। इस तेज और मौन हमले ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्षमता को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। अंतरराष्ट्रीय सैन्य विश्लेषकों ने इस मिशन को 'क्विक-सप्रेसन स्ट्राइक' की श्रेणी में रखा, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की उत्कृष्ट मिसाल मानी जाती है। इस मिशन की योजना में भारतीय वायुसेना ने उन्नत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया, जो वास्तविक-समय डेटा विश्लेषण और स्वचालित निर्णय लेने में सक्षम है। पहले पांच मिनट की जामिंग ने दुश्मन के रडार को झूठे सिग्नल से भर दिया, जिससे उनके ऑपरेटरों को भ्रमित कर दिया गया और वास्तविक हमले का पता नहीं चला। अगले चरण में, मिसाइल लॉन्च के लिए सुखोई और राफेल विमानों का उपयोग किया गया, जो अपनी उच्च गति और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। अंतिम चरण में, लक्ष्यों पर हमला इतना सटीक था कि न्यूनतम सहायक क्षति हुई, जो गुणवत्ता प्रधान रणनीति का प्रमाण है। इस मिशन ने साबित किया कि भारतीय वायुसेना की रणनीति न केवल तेज है बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, जो वैश्विक स्तर पर सराही गई।

क्वांटम जामिंग प्रभाव

भारत ने इस मिशन में पहली बार क्वांटम जामिंग तकनीक का प्रयोग किया, जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से कहीं आगे है। क्वांटम स्तर पर सिग्नल में हस्तक्षेप कर यह तकनीक रडार की वेव-फॉर्म को अस्थिर कर देती है, जिससे वह लक्ष्य की दूरी, गति और दिशा का सही अनुमान नहीं लगा पाता। पाकिस्तानी टीपीएस-77 रडार, जिन्हें पारंपरिक जामिंग से सुरक्षित माना जाता था, इस तकनीक के सामने पूरी

तरह विफल हो गए। भारतीय विशेषज्ञों ने इन रडारों के लिए उपयोग की जा रही विशेष फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल का पहले ही अध्ययन कर लिया था, जिससे जामिंग की तीव्रता और अवधि का सटीक निर्धारण किया जा सका। नतीजतन, दुश्मन की वायु चेतावनी प्रणाली ने वास्तविक लक्ष्यों को न देखकर झूठे इको सिग्नल पर प्रतिक्रिया दी। इस तकनीकी छलांग ने भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में अग्रणी स्थान पर ला खड़ा किया। क्वांटम जामिंग क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां क्वांटम बिट्स का उपयोग कर सिग्नल को अप्रत्याशित रूप से विकृत किया जाता है, जो पारंपरिक रडार के लिए असंभव होता है। इस तकनीक ने पाकिस्तानी रडार को इतना प्रभावित किया कि कंट्रोल सिस्टम में ओवरलोड हो गया, और झूठे लक्ष्यों की बाढ़ आ गई, जिससे ऑपरेटरों को वास्तविक खतरे का पता नहीं चला। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इस तकनीक को वर्षों की मेहनत से विकसित किया, जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का संयोजन है। इस जामिंग ने साबित किया कि भारत की तकनीक न केवल रक्षात्मक है बल्कि आक्रामक रूप से दुश्मन की प्रणाली को पंगु बनाने में सक्षम है, जो वैश्विक सैन्य रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ती है। इस प्रभाव ने पाकिस्तान को अपनी रक्षा तकनीक पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया, और भारत की निर्णायक क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली।

एलओसी पर जीपीएस जामिंग

नियंत्रण रेखा पर भारत ने उच्च-शक्ति वाले जामरों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के जीपीएस और वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली सिग्नल को बाधित कर दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पाकिस्तानी सटीक-मार्गदर्शित मिसाइलों और ड्रोन का नेविगेशन बिगड़ जाए। जामिंग के बाद कई ड्रोन लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही दिशा भटक गए और कुछ मिसाइलें निर्धारित मार्ग से भटककर सुरक्षित क्षेत्रों में निष्क्रिय हो गईं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और थलसेना ने इस मौके का लाभ उठाकर सीमांत क्षेत्रों की निगरानी और गश्त को और सघन कर दिया। इस तकनीकी कार्रवाई ने साबित किया कि भारत न केवल हवाई क्षेत्र में बल्कि अंतरिक्ष-आधारित नेविगेशन प्रणालियों पर भी नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता रखता है। जीपीएस जामिंग एक उन्नत तकनीक है, जहां उच्च-शक्ति वाले सिग्नल दुश्मन के जीपीएस रिसीवर को

ओवरलोड कर देते हैं, जिससे स्थान निर्धारण असंभव हो जाता है। इस जामिंग ने पाकिस्तानी ड्रोन को इतना प्रभावित किया कि वे अपने निर्धारित मार्ग से भटक गए और कई मामलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। भारतीय सीमा बलों ने इस अवसर का उपयोग कर सीमा पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए और गश्त बढ़ाई, जिससे घुसपैठ के प्रयास पूरी तरह विफल हो गए। इस तकनीक ने साबित किया कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता अंतरिक्ष तक विस्तारित है, जो वैश्विक स्तर पर दुश्मन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस जामिंग की सफलता ने भारत को रणनीतिक ऊपरी हाथ दिया, और दुश्मन की नेविगेशन निर्भरता को उजागर कर दिया, जो भविष्य के अभियानों में उपयोगी सिद्ध होगी।

सम्युक्ता और डी-4एस सिस्टम की भूमिका

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 'सम्युक्ता' इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ने इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह प्रणाली एक मोबाइल, बहु-फ्रीक्वेंसी जामिंग प्लेटफॉर्म है, जो संचार और रडार दोनों को बाधित करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसे अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर पाकिस्तानी सेना की संचार लाइनों को लक्ष्य बनाया गया। डी-4एस (रक्षात्मक दमन प्रणाली) यूनिट्स ने सक्रिय हस्तक्षेप कर दुश्मन की लंबी दूरी की संचार लिंक को बाधित किया। इससे पाकिस्तान के ग्राउंड नियंत्रण केंद्र और अग्रिम अड्डों के बीच का तालमेल टूट गया। इस दोहरी-परत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हमले ने दुश्मन को युद्धक्षेत्र में पूरी तरह अलग-थलग कर दिया और भारतीय बलों को निर्णायक बढ़त दिलाई। सम्युक्ता प्रणाली की क्षमता में बहु-फ्रीक्वेंसी जामिंग शामिल है, जो दुश्मन के संचार को विभिन्न बैंड्स पर बाधित करती है, जिससे उनका नेटवर्क पूरी तरह पंगु हो जाता है। डी-4एस प्रणाली विशेष रूप से रक्षात्मक दमन के लिए डिज़ाइन की गई है, जो दुश्मन की लंबी दूरी की लिंक को लक्षित करती है और उन्हें निष्क्रिय कर देती है। इस संयोजन ने पाकिस्तानी सेना के कमांडरों को अलग-थलग कर दिया, जिससे उनके आदेश सैनिकों तक नहीं पहुंच पाए और ऑपरेशन में अव्यवस्था फैल गई। इस भूमिका ने साबित किया कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां विश्व स्तर की हैं, और दुश्मन के संचार नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने में सक्षम हैं, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की सफलता का प्रमाण है।

आकाशतीर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित C4ISR प्रणाली

‘आकाशतीर’ एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम कमान, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, खुफिया, निगरानी एवं टोह प्रणाली है, जिसे इस मिशन में वायु रक्षा प्रबंधन के लिए उपयोग किया गया। एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली नेटवर्क से जुड़कर इसने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए पूर्व चेतावनी जारी की और इंटरसेप्टर प्रणाली को स्वचालित रूप से सक्रिय किया। आकाशतीर ने सौ प्रतिशत इंटरसेप्ट दर हासिल की, यानी कोई भी दुश्मन का ड्रोन या मिसाइल भारतीय सीमा में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर पाया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिथ्म ने संभावित खतरों के मार्ग और गति का सटीक अनुमान लगाया, जिससे प्रतिक्रिया समय कुछ सेकंड तक सीमित हो गया। इस प्रणाली ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि भारत की वायु रक्षा अब पूरी तरह नेटवर्क-केंद्रित और भविष्य-दर्शी हो चुकी है। आकाशतीर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली वास्तविक-समय डेटा विश्लेषण करती है, जो दुश्मन के हमलों के पैटर्न को पहचानती है और स्वचालित रूप से काउंटर उपाय सक्रिय करती है। इसने दुश्मन के ड्रोन हमलों को पूरी तरह रोका, और इंटरसेप्टर मिसाइलों को सटीक निर्देश देकर सौ प्रतिशत सफलता हासिल की। इस प्रणाली की भूमिका ने भारत की वायु रक्षा को अभेद्य बनाया, और पाकिस्तान को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। आकाशतीर ने साबित किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता युद्ध के मैदान में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, जो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की उन्नति का प्रमाण है।

दुश्मन तकनीक का हस्तगत डेटा

मिशन के दौरान और बाद में भारतीय तकनीकी टीमों ने पाकिस्तानी हमलों में इस्तेमाल हुए उपकरणों और हथियारों के अवशेष एकत्र किए। इनमें चीनी पीएल-पंद्रह एयर-टू-एयर मिसाइल के टुकड़े, तुर्की-निर्मित ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई वाहन प्रणाली शामिल थे। इनका फॉरेंसिक विश्लेषण कर यह पुष्टि हुई कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमताएं विदेशी तकनीक पर अत्यधिक निर्भर हैं। मिसाइलों के मार्गदर्शन प्रणाली और ड्रोन के प्रोसेसर चिप्स से मिली जानकारी ने भारत को दुश्मन की आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी खामियों और कमजोरियों की विस्तृत समझ दी। यह डेटा भविष्य में काउंटर-प्रौद्योगिकी विकास के लिए भी उपयोगी साबित होगा, जिससे अगली बार दुश्मन की किसी भी तकनीक को और तेजी से निष्क्रिय किया जा सकेगा। फॉरेंसिक विश्लेषण में

पाया गया कि चीनी मिसाइलों में इस्तेमाल हुए घटक कम गुणवत्ता के थे, जिससे उनकी सटीकता प्रभावित हुई। भारतीय टीमों ने इन अवशेषों से दुश्मन की तकनीकी निर्भरता को उजागर किया, जो पाकिस्तान की सप्लाई चेन की कमजोर कड़ियों को दर्शाता है। इस डेटा का उपयोग कर भारत ने अपनी रक्षा प्रणालियों को और मजबूत किया, और भविष्य के अभियानों में इन कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बनाई। इस हस्तगत डेटा ने साबित किया कि भारत न केवल हमला करने में सक्षम है बल्कि दुश्मन की तकनीक को विश्लेषित कर आगे की रणनीति बनाने में भी माहिर है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की गहराई को दर्शाता है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: पैसिव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध

भारत की इस निर्णायक कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने पैसिव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपाय अपनाने की कोशिश की, जिनमें अंतरिक्ष-आधारित सिग्नल परावर्तन और फ्रीक्वेंसी-शिफ्टिंग शामिल थे। उनका उद्देश्य था भारतीय विमानों और मिसाइलों के सेंसर को भ्रमित करना। हालांकि, भारतीय काउंटर-इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टीमों ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। पैसिव तकनीक पर आधारित पाकिस्तान की रणनीति पुराने ढर्रे की थी, जबकि भारत की प्रतिक्रिया पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एकीकृत और डेटा-चालित थी। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के सभी प्रतिउत्तर प्रयास नाकाम रहे और उनकी कमजोरी और उजागर हो गई। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में पाकिस्तान ने सिग्नल परावर्तन का उपयोग कर भारतीय सेंसर को झूठे लक्ष्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीमों ने उन्नत एंटी-जैमिंग तकनीक से इसे निष्फल कर दिया। फ्रीक्वेंसी-शिफ्टिंग ने भी कोई असर नहीं दिखाया, क्योंकि भारतीय प्रणालियां स्वचालित रूप से फ्रीक्वेंसी बदलती हैं। इस प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान की तकनीकी पिछड़ापन को उजागर किया, और भारत की उन्नत क्षमता को प्रमाणित किया। इस घटना ने साबित किया कि पाकिस्तान की रणनीति अप्रभावी है, और भारत की काउंटर तकनीक न केवल रक्षात्मक है बल्कि आक्रामक रूप से दुश्मन को पीछे धकेलती है।

रणनीतिक संदेश: भारतीय तकनीकी प्रभुत्व

ऑपरेशन सिंदूर के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध चरण ने पाकिस्तान और उसके समर्थक नेटवर्क को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत तकनीकी और सामरिक दोनों मोर्चों पर निर्णायक

बढ़त रखता है। वैश्विक मंच पर भारत की छवि एक जिम्मेदार लेकिन कठोर प्रतिक्रिया देने वाली सैन्य शक्ति के रूप में और मजबूत हुई। इस अभियान ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति केवल हथियार उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी प्रणालियों के विकास और उनके वास्तविक समय उपयोग में भी अग्रणी है। पाकिस्तान के लिए यह एक चेतावनी थी कि भविष्य के किसी भी आक्रामक प्रयास को तकनीकी रूप से प्रारंभिक चरण में ही कुचल दिया जाएगा। इस संदेश ने पाकिस्तान के नेतृत्व में भय पैदा किया, और उनके समर्थकों को भारत की क्षमता का एहसास कराया। भारत की निर्णायक प्रतिक्रिया ने वैश्विक सैन्य समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, और कई देशों ने भारतीय तकनीक की सराहना की। इस प्रभुत्व ने साबित किया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विश्व नेता बन रहा है, जो रक्षा नीति की सफलता का प्रमाण है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियाँ

अध्याय 35:

आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिचय

आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जब कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया। रक्षा क्षेत्र में यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लंबे समय से आयातित हथियारों पर निर्भर रहा है, और स्वदेशीकरण से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। अभियान के तहत रक्षा मंत्रालय ने कई नीतियां लागू की हैं, जैसे कि आयात प्रतिबंध और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन, जिससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिला है। यह अभियान 'भारत में बनाओ' का विस्तार है, जो रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है, और इससे लाखों रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अभियान ने रक्षा क्षेत्र को एक नए दौर में प्रवेश कराया है, जहां स्वदेशी तकनीक का विकास प्राथमिकता है, और यह भारत को वैश्विक स्तर पर रक्षा उत्पादक के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, यह अभियान राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि अब भारत अपने रक्षा उपकरणों का निर्माण खुद कर रहा है, जो विदेशी निर्भरता से मुक्ति का प्रतीक है। अभियान की सफलता से रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, और ₹ पैंतीस हजार करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान रक्षा क्षेत्र में तकनीकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जहां पहले सत्तर प्रतिशत से अधिक उपकरण विदेशी स्रोतों से आते थे। अब सरकार ने एक सौ एक रक्षा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया है, जिससे स्वदेशी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को मजबूती मिली है। यह अभियान न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है बल्कि राष्ट्रीय गौरव को भी मजबूत करता है, क्योंकि अब भारत अपने हथियारों का निर्माण खुद कर रहा है। परिणामस्वरूप, रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है और ₹ पैंतीस हजार करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगा। अभियान ने रक्षा क्षेत्र को एक नए दौर में प्रवेश कराया है, जहां स्वदेशी

तकनीक का विकास प्राथमिकता है, और यह भारत को वैश्विक स्तर पर रक्षा उत्पादक के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, यह अभियान राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि अब भारत अपने रक्षा उपकरणों का निर्माण खुद कर रहा है, जो विदेशी निर्भरता से मुक्ति का प्रतीक है। अभियान की सफलता से रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, और ₹ पैंतीस हजार करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाएगा।

रक्षा क्षेत्र में आयात निर्भरता की समस्या

रक्षा क्षेत्र में आयात निर्भरता लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, जहां रूस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से हथियार खरीदने पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य इस निर्भरता को तीस प्रतिशत तक कम करना है, जिससे राष्ट्रीय बजट पर बोझ कम होगा और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नीति के तहत, सरकार ने रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी है, और कई आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे न केवल आर्थिक बचत होती है बल्कि आपातकालीन स्थितियों में रक्षा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होती है, क्योंकि विदेशी स्रोतों पर निर्भरता से युद्ध के समय जोखिम बढ़ जाता है। अभियान ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे स्थानीय कंपनियां मजबूत हुई हैं। यह उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादन से तकनीकी गोपनीयता बनी रहती है और विदेशी दबाव कम होता है। आयात पर ₹ दो लाख करोड़ की बचत होने की उम्मीद है, जो अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए उपयोगी होगी।

आयात निर्भरता कम करने से रक्षा क्षेत्र में स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, जहां पहले विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने से स्वदेशी अनुसंधान प्रभावित होता था। अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 जैसी नीतियां स्वदेशी कंपनियों को अनुबंध देने को अनिवार्य बनाती हैं, जिससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां मजबूत हुई हैं। यह उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादन से तकनीकी गोपनीयता बनी रहती है और विदेशी दबाव कम होता है। परिणामस्वरूप, आयात पर ₹ दो लाख करोड़ की बचत होने की उम्मीद है, जो अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए उपयोगी होगी। अभियान ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता दी जाए, जिससे स्थानीय कंपनियां मजबूत हुई

हैं। यह उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादन से तकनीकी गोपनीयता बनी रहती है और विदेशी दबाव कम होता है। आयात पर ₹ दो लाख करोड़ की बचत होने की उम्मीद है, जो अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए उपयोगी होगी।

रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन

आत्मनिर्भरता अभियान रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर लाखों रोजगार सृजित करता है, जहां छोटे और मध्यम उद्योगों को शामिल किया गया है। रक्षा कॉरिडोर जैसे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित परियोजनाएं पाँच लाख से अधिक नौकरियां पैदा कर रही हैं, और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन से युवा उद्यमियों को अवसर मिल रहे हैं। नवाचार रक्षा चुनौतियाँ योजना के तहत एक सौ से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई है, जिससे इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है। यह सृजन न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है, जहां रक्षा उत्पादन इकाइयां स्थापित हो रही हैं। अभियान से कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है और 2030 तक एक करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। यह रोजगार सृजन से सामाजिक स्थिरता बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी कम होने से युवाओं में असंतोष घटता है और वे उत्पादक कार्यों में लगते हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान भी हो रहा है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है।

रोजगार सृजन से सामाजिक स्थिरता बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी कम होने से युवाओं में असंतोष घटता है और वे उत्पादक कार्यों में लगते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है और 2030 तक एक करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। यह अभियान महिलाओं को भी शामिल कर रहा है, जहां बीस प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिससे लिंग समानता को बढ़ावा मिलता है। परिणामस्वरूप, आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान भी हो रहा है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। अभियान से कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है और 2030 तक एक करोड़ नौकरियां सृजित होने की संभावना है। यह अभियान महिलाओं को भी शामिल कर रहा है, जहां बीस प्रतिशत रोजगार महिलाओं

के लिए आरक्षित हैं, जिससे लिंग समानता को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक उत्थान भी हो रहा है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का योगदान

आत्मनिर्भर भारत अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, क्योंकि विदेशी हथियारों पर निर्भरता से युद्ध के समय आपूर्ति बाधित हो सकती है। स्वदेशी उत्पादन से भारत अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा कर सकता है, जैसे कि तेजस जेट और अर्जुन टैंक, जो स्थानीय स्तर पर निर्मित हैं। यह नीति सैन्य बलों को समय पर उपकरण उपलब्ध कराती है, जिससे तैयारियां मजबूत होती हैं और दुश्मन के दबाव से मुक्ति मिलती है। अभियान से रक्षा अनुसंधान बढ़ा है, जहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक हजार से अधिक पेटेंट प्राप्त किए हैं, जो सुरक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत बनाते हैं। विदेशी निर्भरता कम होने से जोखिम घटता है, क्योंकि आयात पर प्रतिबंध से स्थानीय उद्योग मजबूत होते हैं और गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहती है। यह अभियान साइबर सुरक्षा को भी शामिल करता है, जहां स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से हैकिंग के खतरे कम होते हैं। भारत की सैन्य क्षमता बढ़ी है, और पचास प्रतिशत उपकरण स्वदेशी होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा। यह नीति वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता से सैन्य सहायता की आवश्यकता कम होती है।

विदेशी निर्भरता कम होने से जोखिम घटता है, क्योंकि आयात पर प्रतिबंध से स्थानीय उद्योग मजबूत होते हैं और गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहती है। यह अभियान साइबर सुरक्षा को भी शामिल करता है, जहां स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से हैकिंग के खतरे कम होते होते हैं। परिणामस्वरूप, भारत की सैन्य क्षमता बढ़ी है, और पचास प्रतिशत उपकरण स्वदेशी होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा। यह नीति वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता से सैन्य सहायता की आवश्यकता कम होती है। अभियान से रक्षा अनुसंधान बढ़ा है, जहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक हजार से अधिक पेटेंट प्राप्त किए हैं, जो सुरक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत बनाते हैं। विदेशी निर्भरता कम होने से जोखिम घटता है, क्योंकि आयात पर प्रतिबंध से स्थानीय उद्योग मजबूत होते हैं और गोपनीय जानकारी सुरक्षित रहती है। यह अभियान साइबर सुरक्षा को भी शामिल करता है, जहां स्वदेशी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से हैकिंग के खतरे कम होते हैं। भारत की सैन्य

क्षमता बढ़ी है, और पचास प्रतिशत उपकरण स्वदेशी होने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रमुख फोकस क्षेत्र हथियार निर्माण हैं, जहां पिनाका रॉकेट और एके-दो सौ तीन राइफल जैसे उत्पाद स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे हैं। यह क्षेत्र आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां हथियारों का चालीस प्रतिशत आयात होता है, और स्वदेशी उत्पादन से लागत बीस प्रतिशत तक कम हो सकती है। सरकार ने एक सौ एक हथियारों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे स्थानीय कंपनियां जैसे आयुध कारखाना बोर्ड को बढ़ावा मिला है। यह फोकस सैन्य बलों को उन्नत हथियार प्रदान करता है, जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अभियान से हथियार उत्पादन में नवाचार बढ़ा है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र रोजगार सृजन भी करता है, जहां दो लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। भारत हथियार निर्यात में प्रमुख बन रहा है, जो आर्थिक लाभ प्रदान करता है।

विमान और ड्रोन निर्माण भी प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां तेजस फाइटर जेट और रुस्तम ड्रोन स्वदेशी नवाचार के उदाहरण हैं। ड्रोन तकनीक से निगरानी और हमले की क्षमता बढ़ी है, और पाँच हजार ड्रोन शामिल करने की योजना है। यह फोकस वायु सेना को मजबूत बनाता है, जहां पहले अस्सी प्रतिशत विमान आयातित थे, और अब स्वदेशी उत्पादन से मरम्मत और रखरखाव आसान हो गया है। अभियान से विमान उत्पादन में तकनीकी विकास हुआ है, जहां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक सौ तेईस तेजस जेट के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। यह क्षेत्र सुरक्षा को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी विमान से गोपनीयता बनी रहती है। परिणामस्वरूप, भारत विमान निर्यात में प्रवेश कर रहा है, जो वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाएगा।

आयात प्रतिबंध का महत्व

सरकार द्वारा एक सौ एक रक्षा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो 2020 में घोषित किया गया था। यह प्रतिबंध हथियारों, गोला-बारूद और उपकरणों पर लागू है, जिससे स्वदेशी कंपनियां मजबूत हुई हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ी है। प्रतिबंध से ₹ एक लाख करोड़ की बचत होने की उम्मीद है, जो स्थानीय उद्योगों में निवेश के लिए उपयोगी होगा। यह नीति रक्षा मंत्रालय द्वारा

लागू की गई है, जो स्वदेशी उत्पादकों को प्राथमिकता देती है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, जहां स्थानीय कंपनियां उन्नत तकनीक विकसित कर रही हैं। यह प्रतिबंध ड्रोन, मिसाइल और टैंक जैसे क्षेत्रों में लागू है, जिससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं सक्रिय हुई हैं। परिणामस्वरूप, रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, और ₹ पैंतीस हजार करोड़ का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।

स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से रोजगार बढ़ा है, जहां दो लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। यह प्रतिबंध ड्रोन, मिसाइल और टैंक जैसे क्षेत्रों में लागू है, जिससे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाएं सक्रिय हुई हैं। परिणामस्वरूप, रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, और ₹ पैंतीस हजार करोड़ का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह नीति रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई है, जो स्वदेशी उत्पादकों को प्राथमिकता देती है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, जहां स्थानीय कंपनियां उन्नत तकनीक विकसित कर रही हैं। यह प्रतिबंध हथियारों, गोला-बारूद और उपकरणों पर लागू है, जिससे स्वदेशी कंपनियां मजबूत हुई हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ी है। प्रतिबंध से ₹ एक लाख करोड़ की बचत होने की उम्मीद है, जो स्थानीय उद्योगों में निवेश के लिए उपयोगी होगा।

रक्षा निर्यात को बढ़ावा

रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां ₹ पैंतीस हजार करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में निर्यात ₹ पंद्रह हजार करोड़ है, और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उत्पादों से वृद्धि हो रही है। सरकार ने निर्यात प्रचार योजना शुरू की है, जो विदेशी बाजारों में भारतीय हथियारों को प्रमोट करती है। यह लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा आएगी। अभियान से रक्षा उद्योग मजबूत होगा, जहां दो सौ से अधिक कंपनियां शामिल हैं। ब्रह्मोस और तेजस जैसे उत्पाद वियतनाम और फिलीपींस को निर्यात हो रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह लक्ष्य रोजगार सृजन भी करेगा, जहां एक लाख नौकरियां पैदा होंगी। कुल मिलाकर, यह लक्ष्य भारत को रक्षा निर्यात में प्रमुख देश बनाएगा, जो आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाएगा।

निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने से रक्षा उद्योग मजबूत होगा, जहां दो सौ से अधिक कंपनियां शामिल हैं। ब्रह्मोस और तेजस जैसे उत्पाद वियतनाम और फिलीपींस को निर्यात हो रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। यह लक्ष्य रोजगार सृजन भी करेगा, जहां एक लाख नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने निर्यात प्रचार योजना शुरू की है, जो विदेशी बाजारों में भारतीय हथियारों को प्रमोट करती है। यह लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा आएगी। अभियान से रक्षा उद्योग मजबूत होगा, जहां दो सौ से अधिक कंपनियां शामिल हैं। ब्रह्मोस और तेजस जैसे उत्पाद वियतनाम और फिलीपींस को निर्यात हो रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है।

लागत बचत और आर्थिक लाभ

आत्मनिर्भरता से रक्षा आयात पर ₹ दो लाख करोड़ की वार्षिक बचत हो सकती है, जहां वर्तमान में ₹ तीन लाख करोड़ से अधिक है। स्वदेशी उत्पादन से लागत तीस प्रतिशत तक कम होती है, क्योंकि आयात शुल्क और परिवहन व्यय बचता है। यह बचत शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए उपयोगी होगी। अभियान से रक्षा बजट का बेहतर उपयोग हो रहा है, जो विकास को गति देगा। स्वदेशी हथियारों से रखरखाव आसान होता है, जिससे लंबे समय में और बचत होती है। यह बचत आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की बचत होती है। परिणामस्वरूप, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, और रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। लागत बचत से रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, जहां ₹ एक लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड उपलब्ध हुआ है। स्वदेशी हथियारों से रखरखाव आसान होता है, जिससे लंबे समय में और बचत होती है। यह बचत आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की बचत होती है। परिणामस्वरूप, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, और रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभियान से रक्षा बजट का बेहतर उपयोग हो रहा है, जो विकास को गति देगा। स्वदेशी उत्पादन से लागत तीस प्रतिशत तक कम होती है, क्योंकि आयात शुल्क और परिवहन व्यय बचता है। यह बचत शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए उपयोगी होगी।

भारत में बनाओ का विस्तार

आत्मनिर्भर भारत अभियान 'भारत में बनाओ' का विस्तार है, जो रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देता है। नवाचार रक्षा चुनौतियाँ योजना से एक सौ से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, जिससे नवाचार बढ़ा है। यह अभियान युवा उद्यमियों को अवसर देता है, जहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक पर फोकस है। 'भारत में बनाओ' से रक्षा उत्पादन बढ़ा है, जो आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाता है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन से रोजगार बढ़ा है, जहां पचास हजार युवा शामिल हुए हैं। सरकार ने रक्षा स्टार्टअप्स के लिए ₹ पाँच सौ करोड़ का फंड बनाया है, जिससे तकनीकी विकास हुआ है। यह अभियान वैश्विक स्तर पर भारत को रक्षा उत्पादक बनाता है, जहां निर्यात बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन से रोजगार बढ़ा है, जहां पचास हजार युवा शामिल हुए हैं। सरकार ने रक्षा स्टार्टअप्स के लिए ₹ पाँच सौ करोड़ का फंड बनाया है, जिससे तकनीकी विकास हुआ है। यह अभियान वैश्विक स्तर पर भारत को रक्षा उत्पादक बनाता है, जहां निर्यात बढ़ रहा है। 'भारत में बनाओ' से रक्षा उत्पादन बढ़ा है, जो आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाता है। नवाचार रक्षा चुनौतियाँ योजना से एक सौ से अधिक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है, जिससे नवाचार बढ़ा है। यह अभियान युवा उद्यमियों को अवसर देता है, जहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक पर फोकस है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति विकसित हुई है, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।

अध्याय 36:

रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्रांति और नवाचार

तेजस फाइटर जेट

तेजस लड़ाकू विमान भारत की स्वदेशी तकनीकी प्रगति का प्रमुख उदाहरण है, जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह विमान पूरी तरह स्वदेशी है, जिसमें साठ प्रतिशत से अधिक कंपोनेंट भारत में निर्मित हैं, और यह भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तेजस की डिजाइन उन्नत वायुगतिकी पर आधारित है, जो इसे हल्का और चुस्त बनाती है, और यह बहु-भूमिका लड़ाकू के रूप में कार्य करता है। सरकार ने एक सौ तेईस तेजस विमान के ऑर्डर दिए हैं, जिसकी कुल मूल्य अड़तालीस हजार करोड़ रुपये है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह विमान मिसाइल और रडार सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन के खिलाफ प्रभावी हमला करने में सक्षम है। तेजस का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ है, जहां एक हजार से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है। परिणामस्वरूप, तेजस निर्यात के लिए भी तैयार है, जो वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। अड़तालीस हजार करोड़ रुपये मूल्य के एक सौ तेईस ऑर्डर से तेजस विमान भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उत्पादन से पचास हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। यह विमान स्वदेशी इंजन और एवियोनिक्स से लैस है, जो विदेशी निर्भरता कम करता है और लागत बचत करता है। तेजस की क्षमता आठ जी तक है, जो इसे आधुनिक युद्ध में उपयोगी बनाती है, और यह बहु-भूमिका मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। अभियान से तेजस का उत्पादन बढ़ा है, और पचास से अधिक विमान वायु सेना में शामिल हो चुके हैं। यह विमान रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है, जहां वियतनाम और अर्जेंटीना जैसे देश रुचि दिखा रहे हैं। तेजस का विकास 1983 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। परिणामस्वरूप, तेजस ने भारत को लड़ाकू विमान उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल किया है।

अर्जुन टैंक: एमके-एकए संस्करण

अर्जुन टैंक भारत की स्वदेशी रक्षा प्रगति का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के सहयोग से निर्मित है। एमके-एकए संस्करण उन्नत क्षमता वाला है, जिसमें लेजर निर्देशित मिसाइल और स्वचालित ट्रांसमिशन शामिल हैं, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त बनाते हैं। सरकार ने एक सौ अठारह यूनिट्स के ऑर्डर दिए हैं, जो भारतीय सेना की टैंक क्षमता को मजबूत करेंगे। अर्जुन का डिजाइन भारी कवच और उच्च गतिशीलता पर आधारित है, जो दुश्मन के हमलों से बचाव करता है। यह टैंक स्वदेशी इंजन से लैस है, जो विदेशी निर्भरता कम करता है और लागत बचत करता है। अर्जुन का विकास 1970 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। अर्जुन टैंक निर्यात के लिए भी तैयार है, जो वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एक सौ अठारह यूनिट्स के साथ अर्जुन एमके-एकए संस्करण भारतीय सेना को उन्नत क्षमता प्रदान करता है, जहां एक सौ बीस मिलीमीटर बंदूक और थर्मल इमेजिंग से लक्ष्य सटीकता बढ़ी है। यह टैंक स्वदेशी कंपोनेंट से बना है, जो सत्तर प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से बीस हजार रोजगार सृजित हुए हैं। अर्जुन की गतिशीलता सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जो रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में उपयोगी है। अभियान से अर्जुन का उत्पादन बढ़ा है, और पचास से अधिक टैंक सेना में शामिल हो चुके हैं। यह टैंक रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है, जहां मध्य पूर्व देश रुचि दिखा रहे हैं। अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ है, जहां पांच सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

पिनाका रॉकेट: बहु-बैरल सिस्टम

पिनाका रॉकेट भारत की रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी प्रगति है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और बहु-बैरल प्रक्षेपक सिस्टम पर आधारित है। यह रॉकेट दुश्मन के ठिकानों पर तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है, जिसमें उन्नत निर्देशन सिस्टम शामिल है। पिनाका की सीमा पचहत्तर किलोमीटर तक बढ़ाई गई है, जो पहले चालीस किलोमीटर थी, और यह सेना की तोपखाने क्षमता को मजबूत बनाता है। सरकार ने पिनाका के कई रेजिमेंट ऑर्डर किए हैं, जो

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह रॉकेट बहुवारहेड से लैस है, जो क्षेत्रीय हमलों में प्रभावी है। पिनाका का विकास 1980 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। पचहत्तर किलोमीटर सीमा वाले पिनाका रॉकेट भारत की सेना को मजबूत बनाता है, जहां बहु-बैरल सिस्टम से बारह रॉकेट चौवालीस सेकंड में दागे जा सकते हैं। यह रॉकेट स्वदेशी कंपोनेंट से बना है, जो अस्सी प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से तीस हजार रोजगार सृजित हुए हैं। पिनाका की सटीकता एक प्रतिशत से कम त्रुटि वाली है, जो इसे आधुनिक युद्ध में उपयोगी बनाती है। अभियान से पिनाका का उत्पादन बढ़ा है, और दस से अधिक रेजिमेंट सेना में शामिल हो चुके हैं। यह रॉकेट रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है, जहां आर्मेनिया और फिलीपींस जैसे देश रुचि दिखा रहे हैं। पिनाका का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ है, जहां आठ सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

ड्रोन विकास: रुस्तम-दो का नवाचार

ड्रोन विकास भारत की रक्षा प्रगति का प्रमुख क्षेत्र है, जहां रुस्तम-दो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और निगरानी तथा हमलों के लिए आदर्श है। यह ड्रोन स्वदेशी है, जिसमें उन्नत सेंसर और लंबी उड़ान क्षमता शामिल है, जो बीस घंटे तक उड़ सकता है। रुस्तम-दो की डिजाइन मानवरहित हवाई वाहन तकनीक पर आधारित है, जो इसे बहुमुखी बनाती है, और यह सेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सरकार ने रुस्तम-दो के कई यूनिट्स ऑर्डर दिए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह ड्रोन कैमरा और मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन की निगरानी में सक्षम है। रुस्तम का विकास 2009 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। रुस्तम-दो ड्रोन भारत की सेना को उन्नत निगरानी प्रदान करता है, जहां तीन सौ किलोमीटर की रेंज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम से लक्ष्य पहचान आसान होती है। यह ड्रोन स्वदेशी कंपोनेंट से बना है, जो नब्बे प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से चालीस हजार रोजगार सृजित हुए हैं। रुस्तम की ऊंचाई तीस हजार फुट तक है, जो इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोगी बनाती है। अभियान से ड्रोन उत्पादन बढ़ा है, और एक सौ से अधिक ड्रोन सेना में शामिल हो चुके हैं। यह ड्रोन

रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है, जहां मध्य पूर्व देश रुचि दिखा रहे हैं। रूस्म का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ है, जहां छह सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

मिसाइल सिस्टम: ब्रह्मोस

मिसाइल सिस्टम में ब्रह्मोस भारत-रूस संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जो अतिध्वनिक गति वाली मिसाइल है और चार सौ किलोमीटर तक की रेंज रखती है। यह मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित है, जिसमें उन्नत निर्देशन सिस्टम शामिल है, जो सटीक हमला करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की डिजाइन क्रूज मिसाइल पर आधारित है, जो इसे बहुमुखी बनाती है, और यह थल, जल और वायु से प्रक्षेपित की जा सकती है। सरकार ने ब्रह्मोस के कई संस्करण ऑर्डर दिए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह मिसाइल मैक तीन की गति से उड़ती है, जो दुश्मन के रडार से बचाव करती है। ब्रह्मोस का विकास 1998 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। परिणामस्वरूप, ब्रह्मोस निर्यात के लिए भी तैयार है, जो वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर, ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा क्षेत्र में तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो भविष्य के नवाचारों का आधार बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सेना को अतिध्वनिक हमला क्षमता प्रदान करती है, जहां दो सौ नब्बे किलोमीटर की रेंज और सटीक लक्ष्यीकरण से दुश्मन के ठिकाने नष्ट होते हैं। यह मिसाइल स्वदेशी कंपोनेंट से बनी है, जो पचास प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से तीस हजार रोजगार सृजित हुए हैं। ब्रह्मोस की गति मैक तीन है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाती है। अभियान से ब्रह्मोस का उत्पादन बढ़ा है, और दो सौ से अधिक मिसाइल सेना में शामिल हो चुकी हैं। यह मिसाइल रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करती है, जहां फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश रुचि दिखा रहे हैं। ब्रह्मोस का विकास भारत-रूस संयुक्त उद्यम से हुआ है, जहां पांच सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

अग्नि मिसाइल

अग्नि मिसाइल भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रगति का प्रतीक है, जहां अग्नि-पांच पांच हजार किलोमीटर की रेंज रखती है और परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है, जिसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम शामिल है, जो सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करता है। अग्नि-पांच की डिजाइन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित है, जो इसे लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयुक्त बनाती है। सरकार ने अग्नि श्रृंखला के कई संस्करण ऑर्डर दिए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह मिसाइल ठोस ईंधन से संचालित है, जो त्वरित प्रक्षेपण की अनुमति देती है। अग्नि का विकास 1983 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। पांच हजार किलोमीटर रेंज वाली अग्नि-पांच मिसाइल भारत की सेना को परमाणु निरोध प्रदान करती है, जहां बहु स्वतंत्र पुनः प्रवेश वाहन तकनीक से कई लक्ष्यों पर हमला संभव है। यह मिसाइल स्वदेशी कंपोनेंट से बनी है, जो अस्सी प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से पच्चीस हजार रोजगार सृजित हुए हैं। अग्नि की सटीकता दस मीटर से कम है, जो इसे आधुनिक युद्ध में उपयोगी बनाती है। अभियान से अग्नि का उत्पादन बढ़ा है, और पचास से अधिक मिसाइल सेना में शामिल हो चुकी हैं। यह मिसाइल रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करती है, जहां एशियाई देश रुचि दिखा रहे हैं। अग्नि का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ है, जहां सात सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

आईएनएस विक्रांत

आईएनएस विक्रांत भारत की स्वदेशी नौसेना प्रगति का प्रमुख उदाहरण है, जो कोचिन जहाज निर्माण द्वारा विकसित किया गया है और तेईस हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्मित है। यह विमानवाहक पूरी तरह स्वदेशी है, जिसमें छिहत्तर प्रतिशत कंपोनेंट भारत में निर्मित हैं, और यह भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विक्रांत की डिजाइन शॉर्ट टेक ऑफ लेकिन अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम पर आधारित है, जो इसे तीस विमान ले जाने में सक्षम बनाती है, और यह बहु-भूमिका जहाज के रूप में कार्य करता है। सरकार ने विक्रांत को कमीशन किया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह पोत मिसाइल और रडार

से लैस है, जो दुश्मन के खिलाफ प्रभावी बचाव करता है। विक्रांत का विकास 2009 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। तेईस हजार करोड़ रुपये लागत वाला आईएनएस विक्रांत भारत की नौसेना को मजबूत बनाता है, जहां चालीस हजार टन का विस्थापन और अट्ठाईस गांठ की गति से समुद्री नियंत्रण संभव है। यह पोत स्वदेशी कंपोनेंट से बना है, जो छिहत्तर प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से साठ हजार रोजगार सृजित हुए हैं। विक्रांत की क्षमता तीस विमान ले जाने की है, जो इसे आधुनिक युद्ध में उपयोगी बनाती है। अभियान से विक्रांत का उत्पादन बढ़ा है, और यह पूरी तरह संचालन योग्य हो चुका है। यह पोत रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है, जहां दक्षिण एशियाई देश रुचि दिखा रहे हैं। विक्रांत का विकास कोचिन जहाज निर्माण के सहयोग से हुआ है, जहां एक हजार से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

रोहिणी रडार सिस्टम

रोहिणी रडार सिस्टम भारत की रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और वायु रक्षा में उपयोग होता है। यह रडार स्वदेशी है, जिसमें तीन आयामी ट्रैकिंग सिस्टम शामिल है, जो एक सौ पचास किलोमीटर तक की निगरानी करता है। रोहिणी की डिजाइन सक्रिय चरणबद्ध सरणी तकनीक पर आधारित है, जो इसे बहुमुखी बनाती है, और यह वायु सेना की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सरकार ने रोहिणी के कई यूनिट्स ऑर्डर दिए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। यह रडार बहु लक्ष्यों को ट्रैक करता है, जो दुश्मन के हमलों से बचाव करता है। रोहिणी का विकास 2000 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। रोहिणी रडार भारत की वायु सेना को उन्नत निगरानी प्रदान करता है, जहां तीन सौ साठ डिग्री कवरेज और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता से लक्ष्य पहचान आसान होती है। यह रडार स्वदेशी कंपोनेंट से बना है, जो पचासी प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से पंद्रह हजार रोजगार सृजित हुए हैं। रोहिणी की सटीकता निर्यात के प्रतिशत है, जो इसे आधुनिक युद्ध में उपयोगी बनाती है। अभियान से रोहिणी का उत्पादन बढ़ा है, और एक सौ से अधिक रडार सेना में शामिल हो चुके हैं। यह रडार रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करता है, जहां यूरोपीय देश रुचि दिखा रहे हैं। रोहिणी का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के

सहयोग से हुआ है, जहां चार सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है।

AI और साइबर सुरक्षा: रक्षा में AI लैब का विकास, 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा भारत की रक्षा नवाचार का प्रमुख क्षेत्र है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्थापित किए गए हैं और एक सौ से अधिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यह तकनीक स्वदेशी है, जिसमें मशीन लर्निंग और गहन लर्निंग शामिल हैं, जो साइबर हमलों से बचाव करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की डिजाइन पूर्वानुमान विश्लेषण पर आधारित है, जो इसे खतरे की पहले पहचान करने में सक्षम बनाती है। सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब के लिए फंडिंग बढ़ाई है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह तकनीक साइबर रक्षा सिस्टम से लैस है, जो दुश्मन के साइबर हमलों से बचाव करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब का विकास 2018 से शुरू हुआ था, जो दशकों की मेहनत का परिणाम है, और अब यह भारत की रक्षा तकनीक का गौरव है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर सुरक्षा निर्यात के लिए भी तैयार है, जो वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर रक्षा क्षेत्र में तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो भविष्य के नवाचारों का आधार बनेगा। एक सौ से अधिक प्रोजेक्ट्स वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब भारत की सेना को साइबर सुरक्षा प्रदान करते हैं, जहां स्वचालित खतरा पहचान से हमले रोके जाते हैं। यह तकनीक स्वदेशी कंपोनेंट से बनी है, जो नब्बे प्रतिशत से अधिक स्थानीय है, और उत्पादन से दस हजार रोजगार सृजित हुए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता निन्यानबे प्रतिशत सटीकता वाली है, जो इसे आधुनिक साइबर युद्ध में उपयोगी बनाती है। अभियान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास बढ़ा है, और पचास से अधिक प्रोजेक्ट्स संचालन योग्य हो चुके हैं। यह तकनीक रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहित करती है, जहां अमेरिका और यूरोप रुचि दिखा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से हुआ है, जहां तीन सौ से अधिक इंजीनियर शामिल थे, और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भारत को साइबर सुरक्षा उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रमाण है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

अध्याय 37:

रक्षा आत्मनिर्भरता का भविष्य और वैश्विक प्रभाव

निर्यात लक्ष्य 2027: एक लाख करोड़ रुपये

रक्षा निर्यात को 2027 तक एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो वर्तमान पंद्रह हजार करोड़ रुपये से कई गुना वृद्धि का संकेत है। यह लक्ष्य ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस जेट जैसे उत्पादों पर आधारित है, जो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं। सरकार ने निर्यात प्रचार योजना शुरू की है, जो प्रदर्शनी और द्विपक्षीय समझौतों से बाजार विस्तार कर रही है। यह लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा आएगी और रक्षा उद्योग मजबूत होगा। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह लक्ष्य सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि निर्यात से राजस्व बढ़ता है और निवेश आकर्षित होता है। एक लाख करोड़ रुपये निर्यात लक्ष्य से भारत वैश्विक बाजार में मजबूत हिस्सेदारी प्राप्त करेगा, जहां एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है। यह लक्ष्य स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देता है, जहां नवाचार रक्षा चुनौतियाँ योजना से नवीन उत्पाद विकसित हो रहे हैं। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का मध्य लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह लक्ष्य युवा उद्यमियों को अवसर देता है, जहां एक लाख नौकरियां सृजित होंगी। परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादों से वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से रोजगार सृजन हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

स्वदेशी हथियारों को पचहत्तर प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करने का प्रमुख उद्देश्य है, जो वर्तमान साठ प्रतिशत से वृद्धि का संकेत देता है। यह लक्ष्य तेजस और अर्जुन जैसे उत्पादों पर आधारित है, जो स्थानीय निर्माण से बने हैं। सरकार ने एक सौ एक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है, जो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह लक्ष्य आर्थिक बचत करेगा, क्योंकि आयात पर पचास हजार करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसी संस्थाएं सक्रिय हो रही हैं। यह लक्ष्य सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि स्वदेशी हथियारों से आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है, जो वैश्विक स्तर पर लाभदायक है। पचहत्तर प्रतिशत स्वदेशी हथियार लक्ष्य से आयात पर पचास हजार करोड़ रुपये की बचत होगी, जो अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए उपयोगी है। यह लक्ष्य स्थानीय उद्योगों को मजबूत बनाता है, जहां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और आयुध कारखाना बोर्ड जैसी कंपनियां विस्तार कर रही हैं। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह लक्ष्य युवा इंजीनियरों को अवसर देता है, जहां दो लाख नौकरियां सृजित होंगी। परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी हथियारों से सुरक्षा मजबूत होती है। अभियान से रोजगार सृजन हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

रोजगार सृजन की क्षमता: पांच लाख नौकरियां

रोजगार सृजन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रमुख लाभ है, जहां पांच लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जो युवाओं को सशक्त बनाएगी। यह सृजन स्टार्टअप्स और कॉरिडोर से आएगा, जहां नवाचार रक्षा चुनौतियाँ योजना से युवा उद्यमी शामिल हो रहे हैं। सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में कौशल विकसित करते हैं। यह सृजन आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि बेरोजगारी कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं। यह सृजन सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि कुशल श्रमिक से रक्षा क्षमता बढ़ती है। पांच लाख नौकरियां सृजित होने से युवा सशक्तिकरण होगा, जहां रक्षा कॉरिडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर बढ़ेंगे। यह सृजन महिलाओं को भी शामिल करेगा, जहां तीस प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह सृजन युवा इंजीनियरों को अवसर देता है, जहां एक लाख युवा प्रशिक्षित होंगे। परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह सृजन राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादों से सुरक्षा मजबूत होती है। अभियान से सामाजिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

वैश्विक साझेदारियां: क्वाड का सहयोग

वैश्विक साझेदारियां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) से ब्रह्मोस निर्यात बढ़ा है। यह साझेदारी तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देती है, जो भारत की क्षमता मजबूत बनाती है। सरकार ने क्वाड के माध्यम से संयुक्त अभ्यास शुरू किए हैं, जो रक्षा सहयोग को गहरा करते हैं। यह साझेदारी आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि निर्यात से राजस्व बढ़ता है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर साझेदारी कर रही हैं। यह साझेदारी सुरक्षा को मजबूत करती है, क्योंकि संयुक्त प्रयास से खतरे कम होते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर प्रभावी बन रहा है, जो सामरिक लाभ प्रदान करता है। यह साझेदारी आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दीर्घकालिक सहयोग सुनिश्चित करती है। क्वाड से ब्रह्मोस निर्यात में वृद्धि हुई है, जहां फिलीपींस जैसे देशों को आपूर्ति हो रही है। यह साझेदारी तकनीकी आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है, और दस हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह साझेदारी युवा इंजीनियरों को अवसर देती है, जहां संयुक्त प्रोजेक्ट्स से कौशल विकास होता है। परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह साझेदारी राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देती है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादों से वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से सामरिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है। यह साझेदारी रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का मूल आधार है, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।

तकनीकी निर्यात की संभावना: ड्रोन और मिसाइल अफ्रीका-एशिया को

तकनीकी निर्यात रक्षा क्षेत्र में भविष्य की संभावना है, जहां ड्रोन और मिसाइल अफ्रीका और एशिया को निर्यात किए जा रहे हैं। यह निर्यात भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, जो रूस्म ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उत्पादों पर आधारित है। सरकार ने निर्यात प्रचार योजना से बाजार विस्तार किया है, जो प्रदर्शनी और समझौतों से सहायता करती है। यह निर्यात आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि राजस्व से निवेश बढ़ेगा। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यह निर्यात सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि वैश्विक मान्यता से गठबंधन बढ़ते हैं। भारत तकनीकी निर्यात में प्रमुख बन

रहा है, जो सामरिक लाभ प्रदान करता है। ड्रोन और मिसाइल निर्यात से अफ्रीका-एशिया में बाजार खुला है, जहां रुस्तम और पिनाका जैसे उत्पाद मांग में हैं। यह निर्यात तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है, और बीस हजार करोड़ रुपये का राजस्व होने की संभावना है। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह निर्यात युवा उद्यमियों को अवसर देता है, जहां स्टार्टअप्स वैश्विक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह निर्यात राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादों से वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से सामरिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

रक्षा स्टार्टअप का उज्ज्वल भविष्य: एक हजार से अधिक स्टार्टअप, दस हजार करोड़ रुपये का निवेश

रक्षा स्टार्टअप भविष्य की संभावना हैं, जहां एक हजार से अधिक स्टार्टअप दस हजार करोड़ रुपये के निवेश से विकसित हो रहे हैं। यह विकास नवाचार रक्षा चुनौतियाँ योजना से प्रेरित है, जो नवाचार को बढ़ावा देती है। सरकार ने स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रदान की है, जो ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि स्टार्टअप्स से रोजगार सृजन होता है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय स्तर पर तकनीक विकसित हो रही है। यह निवेश सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि नई तकनीक से क्षमता बढ़ती है। भारत स्टार्टअप केंद्र बन रहा है, जो वैश्विक स्तर पर लाभदायक है। यह निवेश आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो युवा उद्यमिता को सशक्त बनाता है। दस हजार करोड़ रुपये निवेश से एक हजार से अधिक रक्षा स्टार्टअप विकसित हो रहे हैं, जहां ड्रोन और साइबर तकनीक पर फोकस है। यह निवेश स्टार्टअप्स को बाजार पहुंच प्रदान करता है, और पचास हजार युवा शामिल हुए हैं। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह निवेश युवा इंजीनियरों को अवसर देता है, जहां नवाचार केंद्र स्थापित हो रहे हैं। भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह निवेश राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादों से वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से सामाजिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

साइबर रक्षा का नेतृत्व: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम

साइबर रक्षा में भारत वैश्विक नेता बन रहा है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम से खतरे रोके जा रहे हैं। यह नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता लैब से आया है, जो एक सौ से अधिक प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। सरकार ने साइबर सुरक्षा पर फोकस किया है, जो स्मार्ट शहर और रक्षा नेटवर्क को सुरक्षित बनाता है। यह सिस्टम आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि साइबर हमलों से बचत होती है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय स्तर पर तकनीक विकसित हो रही है। यह नेतृत्व सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से खतरे की पहले पहचान होती है। परिणामस्वरूप, भारत साइबर रक्षा में प्रमुख बन रहा है, जो वैश्विक स्तर पर लाभदायक है। कुल मिलाकर, यह नेतृत्व आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम से साइबर रक्षा मजबूत हुई है, जहां निन्यानबे प्रतिशत खतरे रोके जा रहे हैं। यह सिस्टम स्थानीय तकनीक से विकसित है, और बीस हजार विशेषज्ञ शामिल हैं। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह नेतृत्व युवा इंजीनियरों को अवसर देता है, जहां साइबर लैब स्थापित हो रहे हैं। भारत वैश्विक साइबर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्वदेशी तकनीक से वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से सामरिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है। यह नेतृत्व रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का मूल आधार है, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक होगा।

पर्यावरण अनुकूल उत्पादन: हरित रक्षा निर्माण की दिशा में सस्टेनेबल प्रयास

पर्यावरण अनुकूल रक्षा उत्पादन भविष्य की संभावना है, जहां हरित निर्माण से सस्टेनेबल विकास सुनिश्चित होता है। यह प्रयास कार्बन उत्सर्जन कम करता है, जो रक्षा फैक्टरियों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। सरकार ने हरित नीतियां लागू की हैं, जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देती हैं। यह प्रयास आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि हरित तकनीक से लागत बचत होती है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय स्तर पर सस्टेनेबल उत्पादन हो रहा है। यह प्रयास

सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि पर्यावरण अनुकूल उत्पाद लंबे समय तक उपयोगी रहते हैं। भारत हरित रक्षा में प्रमुख बन रहा है, जो वैश्विक स्तर पर लाभदायक है। यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सस्टेनेबल विकास सुनिश्चित करता है। हरित रक्षा उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण होता है, जहां सौर ऊर्जा से पचास प्रतिशत बिजली बचत हो रही है। यह प्रयास स्थानीय तकनीक से विकसित है, और दस हजार विशेषज्ञ शामिल हैं। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह प्रयास युवा इंजीनियरों को अवसर देता है, जहां हरित लैब स्थापित हो रहे हैं। भारत वैश्विक हरित बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह प्रयास राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि सस्टेनेबल उत्पादों से वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से सामाजिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

वैश्विक प्रभाव में वृद्धि: आतंकवाद-रोधी नेतृत्व और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका वैश्विक प्रभाव रक्षा क्षेत्र में भारत की भविष्य की संभावना है, जहां आतंकवाद-रोधी में नेता बनकर संयुक्त राष्ट्र में भूमिका बढ़ी है। यह प्रभाव क्वाड और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों से आया है, जो रक्षा सहयोग को गहरा करते हैं। सरकार ने वैश्विक साझेदारियां बढ़ाई हैं, जो निर्यात और तकनीक साझा करती हैं। यह प्रभाव आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि वैश्विक मान्यता से निवेश आकर्षित होता है। अभियान से रक्षा क्षेत्र में नवाचार बढ़ा है, और स्थानीय स्तर पर तकनीक विकसित हो रही है। यह प्रभाव सुरक्षा को मजबूत करता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से खतरे कम होते हैं। भारत वैश्विक नेता बन रहा है, जो सामरिक लाभ प्रदान करता है। यह प्रभाव आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दीर्घकालिक वैश्विक भूमिका सुनिश्चित करता है।

आतंकवाद-रोधी में नेतृत्व से भारत संयुक्त राष्ट्र में मजबूत हुआ है, जहां काउंटर टेररिज्म कमिटी की अध्यक्षता से प्रतिबंध बढ़े हैं। यह प्रभाव वैश्विक साझेदारियों से आया है, और बीस हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। अभियान से रक्षा निर्यात बढ़ा है, और पैंतीस हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है। यह प्रभाव युवा राजनयिकों को अवसर देता है, जहां संयुक्त अभ्यास हो रहे हैं। भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जो आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है। यह प्रभाव राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है, क्योंकि वैश्विक मान्यता मिलती है। अभियान से सामरिक उत्थान हुआ है, और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ा है।

भारत की आतंक-रोधी प्रमुख रणनीतियाँ

अध्याय 38:

सख्त आतंकवाद-रोधी कानून और कानूनी सुधार

आतंकवाद विरोधी कानूनों का ऐतिहासिक विकास

भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों की नींव 1960 के दशक में पड़ी जब देश विभाजन के बाद की अस्थिरता और सीमा विवादों से जूझ रहा था, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। 1967 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित हुआ, जो संगठनों को अवैध घोषित करने और उनके सदस्यों पर कार्रवाई का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत शुरुआती वर्षों में तीन सौ से अधिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद के बढ़ते मामलों के कारण 1985 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लागू किया गया, जो विशेष अदालतों और विस्तारित हिरासत की व्यवस्था लेकर आया, जिससे 1990 तक पंद्रह हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए। ये कानून कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय अलगाववादी समूहों को लक्षित करते थे, जहां घुसपैठ की घटनाएं सालाना पांच सौ से अधिक पहुंच गई थीं। इन प्रारंभिक प्रयासों ने पुलिस को मजबूत जांच शक्तियां प्रदान कीं, जिससे आतंकी घटनाओं में बीस प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, हालांकि इनकी कठोरता ने नागरिक अधिकारों पर बहस छेड़ दी। कुल मिलाकर, ये ऐतिहासिक कदम देश की सुरक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे, जो वैश्विक आतंकवाद के बढ़ते खतरे से प्रेरित थे।

2000 के दशक में मुंबई हमलों जैसे बड़े घटनाक्रमों ने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया, जब 2002 में आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पेश किया गया, जो गुप्तचर जानकारी को सबूत मानने की अनुमति देता था। इस अधिनियम के तहत 2004 तक एक हजार दो सौ से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीतिक असहमति दबाने में देखा गया, जिससे 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर आतंकवाद की परिभाषा विस्तृत की गई, जिसने 2010 तक चार हजार मामलों में जांच तेज की। इन बदलावों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया, जहां संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों से प्रभावित होकर भारत ने सीमा पार आतंकवाद पर फोकस किया। विकास की इस प्रक्रिया में

कानूनों ने आतंकी फंडिंग को ट्रैक करने के लिए वित्तीय निगरानी को शामिल किया, जिससे अवैध धन प्रवाह में पैंतीस प्रतिशत की कमी आई। अंत में, ये क्रमिक परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सतत प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समय के साथ अधिक परिष्कृत हो गए हैं।

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के मुख्य प्रावधान गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने का प्रावधान प्रमुख है, जो केंद्र सरकार को ऐसे समूहों की संपत्ति जब्त करने और उनके सदस्यों को दस वर्ष तक की सजा देने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत पचास से अधिक संगठनों को अवैध घोषित किया गया, जिससे उनकी गतिविधियां चालीस प्रतिशत कम हुईं। विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना से अपील प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई, जहां औसतन दो सौ मामलों की सालाना सुनवाई होती है। ये नियम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रचार पर अंकुश लगाते हैं, जिसमें सामाजिक मीडिया सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति शामिल है। कार्यान्वयन में पुलिस को एक सौ अस्सी दिनों तक की हिरासत मिलती है, जो जांच के लिए पर्याप्त समय प्रदान करती है, जिससे सबूत संग्रह में सुधार हुआ। कुल रूप से, ये प्रावधान सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जो आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने में सहायक हैं।

अधिनियम में आतंकवाद की परिभाषा में बम विस्फोट, अपहरण और साजिश शामिल हैं, जो अदालतों को तेज फैसले लेने की अनुमति देती है, जहां छह हजार से अधिक आरोप पत्र दाखिल हुए। वित्तीय सहायता रोकने के लिए बैंक खातों को फ्रीज करने का विकल्प दिया गया है, जिसके चलते पांच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जब्त की गई। ये नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र की सूची से प्रभावित होकर विदेशी संगठनों पर भी कार्रवाई होती है। सुनवाई में गवाह सुरक्षा की व्यवस्था से गवाहों की संख्या पच्चीस प्रतिशत बढ़ी, जो मामलों की मजबूती बढ़ाती है। अधिनियम की इन विशेषताओं ने आतंकी नेटवर्क को तोड़ने में मदद की, जहां सालाना तीन सौ से अधिक साजिशें नाकाम हुईं। अंततः, ये मुख्य तत्व कानूनी ढांचे की रीढ़ हैं, जो राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करते हैं।

आतंकवाद रोकथाम अधिनियम और उसके उत्तराधिकारी आतंकवाद रोकथाम अधिनियम ने 2002 में विशेष अदालतों और गुप्तचर सबूतों को मान्यता देकर सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त किया, जिसके तहत 2004 तक आठ सौ से अधिक मामले दर्ज

हुए। इस कानून ने आतंकी फंडिंग पर नजर रखने के लिए वित्तीय जांच को अनिवार्य बनाया, जिससे अवैध लेनदेन में तीस प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, इसका कार्यान्वयन राजनीतिक दुरुपयोग से प्रभावित रहा, जहां विपक्षी नेताओं पर एक सौ पचास से ज्यादा मामले बने। उत्तराधिकारी के रूप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के संशोधनों ने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, जो 2008 के मुंबई हमलों के बाद मजबूत हुए। इन बदलावों ने हिरासत अवधि को बढ़ाकर जांच की गुणवत्ता सुधारी, जहां 2010 तक दो हजार पांच सौ गिरफ्तारियां दर्ज की गईं। कुल मिलाकर, ये कानून आतंकवाद से मुकाबले की एक महत्वपूर्ण कड़ी बने, जो समय के साथ विकसित हुए। उत्तराधिकारी संशोधनों ने 2019 में आतंकवाद की परिभाषा को और विस्तृत किया, जिसमें साइबर आतंकवाद को शामिल कर पांच सौ से अधिक डिजिटल मामलों की जांच हुई। इन प्रावधानों ने अंतर-राज्यीय समन्वय को बढ़ावा दिया, जहां विभिन्न एजेंसियां एक हजार से ज्यादा संयुक्त अभियानों में शामिल हुईं। कानून ने संपत्ति जब्ती को आसान बनाया, जिससे तीन सौ करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त हुईं। हालांकि, कम दोषसिद्धि दर ने इनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए, जहां औसतन पांच प्रतिशत मामलों में सजा हुई। ये विकास राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका को मजबूत करते हैं, जो पांच नब्बे प्रतिशत दोषसिद्धि दर हासिल कर चुकी है। अंत में, ये उत्तराधिकारी कदम पुराने कानूनों की कमियों से सीखकर अधिक प्रभावी बने हैं, जो सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा हैं।

हालिया संशोधन और उनके प्रभाव

2019 के संशोधनों ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा, जिससे एक सौ से अधिक व्यक्ति इस श्रेणी में आए। इन बदलावों ने जांच एजेंसियों को अधिक स्वायत्तता दी, जहां सालाना चार सौ मामलों में तेज कार्रवाई हुई। प्रभाव के रूप में आतंकी घटनाओं में पंद्रह प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, खासकर कश्मीर घाटी में जहां घुसपैठ दो सौ से नीचे आई। संशोधनों ने वित्तीय ट्रैकिंग को मजबूत किया, जिससे हवाला नेटवर्क पर दो सौ पचास छापे मारे गए। हालांकि, इनकी कठोरता ने गिरफ्तारियों में वृद्धि की, जहां तीन हजार से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। कुल रूप से, ये हालिया परिवर्तन आतंकवाद से निपटने में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। संशोधनों के प्रभाव में दोषसिद्धि दर में सुधार देखा गया, जहां

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों में पांच नब्बे प्रतिशत सफलता मिली, जो वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च है। इन बदलावों ने साइबर निगरानी को शामिल कर तीन सौ से अधिक ऑनलाइन साजिशें रोकीं। कानूनी प्रक्रिया में तेजी आई, जहां सुनवाई का समय बारह महीनों से घटकर छह महीने हो गया। हालांकि, कम कुल दोषसिद्धि दर तीन प्रतिशत के आसपास बनी रही, जो जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है। ये संशोधन अंतरराष्ट्रीय दबाव से प्रभावित हुए, जहां वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के मानकों को अपनाया गया। अंततः, ये कदम कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाते हैं, जो उभरते खतरों से मुकाबला करने में सक्षम हैं।

अध्याय 39:

खुफिया तंत्र का आधुनिकीकरण और अंतर-एजेंसी समन्वय

भारतीय खुफिया एजेंसियों का अवलोकन और विकास

भारतीय खुफिया तंत्र की संरचना में अनुसंधान और विश्लेषण अनुभाग बाहरी खतरों पर केंद्रित है, जो 1968 में स्थापित हुई और अब दस हजार से अधिक कर्मचारियों के साथ कार्य करती है, मुख्य रूप से सीमा पार गतिविधियों की निगरानी करती है। खुफिया ब्यूरो आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करता है, जो 1887 से चला आ रहा है और पच्चीस हजार से ज्यादा अधिकारियों के साथ देश भर में फैला हुआ है, जहां यह स्थानीय स्तर पर सूचनाएं एकत्र करता है। संयुक्त खुफिया समिति विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करती है, जो 1948 में बनी और अब सालाना पांच हजार से अधिक रिपोर्ट तैयार करती है। ये एजेंसियां कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हैं, जहां 1,200 से ज्यादा ऑपरेशनों में योगदान दिया गया। विकास के क्रम में 2008 के मुंबई हमलों के बाद इनकी क्षमता बढ़ाई गई, जिससे बजट पंद्रह हजार करोड़ रुपये पहुंच गया। कुल रूप से, ये संस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला हैं, जो समय के साथ अधिक व्यापक हो गई हैं।

विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2009 में बनी, जो एक हजार पांच सौ से अधिक मामलों की जांच कर चुकी है और पांच नब्बे प्रतिशत दोषसिद्धि दर हासिल की है। रक्षा खुफिया एजेंसी सैन्य खुफिया पर ध्यान देती है, जो 2002 से कार्यरत है और तीन हजार से ज्यादा सैनिकों के साथ सीमा क्षेत्रों में तैनात है। ये एजेंसियां डिजिटल युग में अनुकूलित हुई हैं, जहां दो हजार से अधिक साइबर संबंधित जांचें पूरी हुईं। केंद्रीय स्तर पर बहु एजेंसी केंद्र 2001 में स्थापित हुआ, जो दैनिक पांच सौ से ज्यादा सूचनाएं साझा करता है। इनका विकास वैश्विक सहयोग से प्रभावित हुआ, जहां छब्बीस देशों के साथ समझौते हैं। अंत में, ये क्रमिक बदलाव खुफिया तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जो उभरते खतरों से मुकाबला करते हैं।

प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण

आधुनिकीकरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रमुख है, जहां नेटरा सिस्टम एन्क्रिप्टेड संचार की निगरानी करता है और एक हजार से अधिक खतरे पहचाने गए। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम डिजिटल रिकॉर्ड रखता है, जो पचास हजार से ज्यादा पुलिस स्टेशनों को जोड़ता है और जांच समय को पचास प्रतिशत कम करता है। राष्ट्रीय स्वचालित चेहरा पहचान सिस्टम चेहरे की पहचान से आठ सौ से अधिक संदिग्धों को पकड़ा। ये तकनीकें ड्रोन डिटेक्शन के लिए इंद्राजाल जैसी प्रणालियों में शामिल हैं, जो सीमा पर तीन सौ से ज्यादा ड्रोन हमलों को रोकें। बजट में पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित हैं, जो मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने पर खर्च होते हैं। कुल मिलाकर, ये एकीकरण खुफिया संग्रह को अधिक सटीक बनाते हैं, जो खतरे की पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं।

प्रौद्योगिकी में बड़ा डेटा विश्लेषण का योगदान महत्वपूर्ण है, जहां सामाजिक मीडिया मॉनिटरिंग से दो हजार पांच सौ रेडिकल सामग्री को ब्लॉक किया गया। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड डेटा एकीकरण करता है, जो दस से अधिक डेटाबेस को जोड़ता है और दैनिक एक मिलियन रिकॉर्ड प्रोसेस करता है। सिम्फनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरण वित्तीय लेनदेन की जांच करते हैं, जो चार सौ करोड़ रुपये के अवैध फंड को जब्त करने में सहायक रहे। ये प्रणालियां भाषा विविधता को संभालती हैं, जहां उर्दू और बंगाली स्क्रिप्ट के लिए विशेष एल्गोरिदम विकसित किए गए। आधुनिकीकरण से ऑपरेशनल दक्षता तीस प्रतिशत बढ़ी। अंततः, ये प्रयास खुफिया तंत्र को डिजिटल युग के अनुरूप बनाते हैं, जो सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं।

अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र

समन्वय तंत्र में बहु एजेंसी केंद्र केंद्रीय भूमिका निभाता है, जो 2001 से कार्यरत है और राज्य स्तर पर राज्य बहु एजेंसी केंद्र के साथ जुड़ा है, जहां दैनिक तीन सौ से अधिक सूचनाएं आदान-प्रदान होती हैं। आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबला सेल 2011 में बनी, जो विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर पांच सौ से ज्यादा मामलों में कार्रवाई की। फेक इंडियन करेंसी नोट समन्वय केंद्र अवैध मुद्रा पर नजर रखता है, जो दो सौ छापों में शामिल रहा। ये तंत्र पांच बहुपक्षीय मंचों के साथ जुड़े हैं, जहां ब्रिक्स और क्वाड जैसे समूहों में सूचना साझा होती है। समन्वय से घुसपैठ की घटनाएं

पच्चीस प्रतिशत घटी। कुल रूप से, ये व्यवस्थाएं एजेंसियों को एकीकृत करती हैं, जो सामूहिक प्रयासों को मजबूत बनाती हैं।

तंत्र में टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल राष्ट्रीय जांच एजेंसी में कार्य करता है, जो एक सौ पचास मामलों की जांच पूरी कर चुका है। रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद सैन्य और नागरिक एजेंसियों के बीच पुल का काम करती है, जो एक सौ संयुक्त अभियानों में शामिल रही। ये व्यवस्थाएं क्षेत्रीय कार्यबल बनाती हैं, जो सीमा प्रबंधन में चार सौ से अधिक अधिकारियों को शामिल करती हैं। समन्वय से साइबर खतरे बीस प्रतिशत कम हुए। ये तंत्र वैश्विक समझौतों से मजबूत होते हैं, जहां ट्यूनीशिया के साथ स्टैंड-अलोन डायलॉग शामिल है। अंत में, ये तंत्र एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जो सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में प्रभावी हैं।

प्रमुख उपलब्धियां और आंकड़े

उपलब्धियों में अखनूर मुठभेड़ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम वाहनों का उपयोग प्रमुख है, जहां तीन आतंकवादियों को बिना सैनिक हानि के निष्क्रिय किया गया। नेटग्रिड ने दो मिलियन रिकॉर्ड एकत्र कर तीन सौ साजिशें रोकीं। चेहरा पहचान से एक हजार दो सौ संदिग्ध पकड़े गए, जो जांच दक्षता को चालीस प्रतिशत बढ़ाया। ये सफलताएं छब्बीस देशों के साथ समझौतों से समर्थित हैं, जहां पचास संयुक्त अभियान हुए। आंकड़ों में आतंकी घटनाएं पंद्रह प्रतिशत घटीं। कुल मिलाकर, ये परिणाम खुफिया तंत्र की क्षमता को दर्शाते हैं, जो निरंतर सुधार से प्राप्त हुए हैं। आंकड़ों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का शून्य दशमलव सात प्रतिशत खर्च शामिल है, जो तीन हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा। स्काईनेट खुफिया ने पांच सौ ड्रोन हमलों को रोका, जो सीमा सुरक्षा में योगदान देता है। उपलब्धियों में सामाजिक मीडिया मॉनिटरिंग से तीन हजार रेडिकल खाते बंद हुए। ये परिणाम पांच बहुपक्षीय मंचों से प्राप्त सहयोग से मजबूत हैं, जहां दो सौ सूचना आदान-प्रदान हुए। सफलताओं से दोषसिद्धि दर पांच नब्बे प्रतिशत पहुंची, जो पूर्व वर्षों से दोगुनी है। अंततः, ये आंकड़े और उपलब्धियां तंत्र की प्रभावकारिता को प्रमाणित करते हैं, जो सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाते हैं।

5. खुफिया साझाकरण में चुनौतियां

साझाकरण में डेटा साइलो प्रमुख बाधा हैं, जहां विभिन्न एजेंसियां तीस प्रतिशत सूचनाएं साझा नहीं करतीं। भाषा विविधता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडरेशन प्रभावित होता है, जहां गैर-लैटिन स्क्रिप्ट में चालीस प्रतिशत सामग्री का पता नहीं लगता। फॉरेंसिक क्षमता की कमी से जांच में देरी होती है, जो दो सौ मामलों में देखी गई। ये चुनौतियां नौकरशाही से बढ़ती हैं, जहां अनुमोदन प्रक्रिया साठ दिनों तक लंबी हो जाती है। निवेश की कमी से प्रशिक्षण सीमित रहता है, जो दस हजार अधिकारियों की आवश्यकता के मुकाबले पांच हजार तक पहुंचा। कुल रूप से, ये बाधाएं साझाकरण को कमजोर करती हैं, जो समग्र सुरक्षा पर असर डालती हैं। चुनौतियों में साइबर रेडिकलाइजेशन शामिल है, जहां एक हजार पांच सौ ऑनलाइन मामले बढ़े लेकिन बीस प्रतिशत ही सुलझे। डेटा गोपनीयता नियमों से साझाकरण बाधित होता है, जो एजेंसियों के बीच विश्वास कम करता है। मानव संसाधन की कमी से विश्लेषण प्रभावित होता है, जहां पंद्रह प्रतिशत पद खाली रहे। ये मुद्दे औपनिवेशिक विरासत से जुड़े हैं, जो केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। चुनौतियां निवेश बढ़ाने से हल हो सकती हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए। अंत में, ये अवरोध खुफिया साझाकरण की दक्षता को सीमित करते हैं, जो सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

भविष्य की दिशा और सुधार सुझाव

भविष्य में एकीकृत राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षा में शामिल कर पांच हजार विशेषज्ञ तैयार करेगा। सुधारों में क्षेत्रीय कार्यबल बनाना शामिल है, जो दस क्षेत्रों में तैनात होंगी और एक हजार से अधिक पैटर्न पहचानेंगी। डेटा एकीकरण को मजबूत कर साइलो हटाए जाएंगे, जो साझाकरण को अस्सी प्रतिशत तक बढ़ाएगा। ये दिशाएं वैश्विक मानकों से मेल खाती हैं, जहां क्वाड जैसे मंचों से सहयोग बढ़ेगा। सुधार से बजट बीस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो प्रौद्योगिकी विकास पर केंद्रित होगा। कुल रूप से, ये योजनाएं तंत्र को अधिक अनुकूल बनाएंगी, जो उभरते खतरों से मुकाबला करेंगी। सुझावों में प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाना है, जहां पंद्रह हजार अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेनिंग दी जाए। भविष्य में साइबर खतरा पूर्वानुमान पर फोकस होगा, जो घटनाओं को पैंतीस प्रतिशत कम करेगा। भाषा मॉडल विकसित कर मॉडरेशन सुधारना आवश्यक है, जो पचास प्रतिशत

अधिक सामग्री कवर करेगा। ये दिशाएं रक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना एजेंसी को मजबूत करेंगी, जो दो सौ प्रोजेक्ट्स संचालित करेगी। सुधारों से दोषसिद्धि दर अठ्ठानवे प्रतिशत तक पहुंच सकती है। अंततः, ये प्रस्ताव खुफिया तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय 40:

सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण - फेंसिंग, तकनीकी निगरानी और घुसपैठ-रोधी उपाय

भारतीय सीमाओं का अवलोकन और चुनौतियां

भारत की सीमाएं कुल पंद्रह हजार एक सौ छह किलोमीटर लंबी हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ तीन हजार तीन सौ तेईस किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ चार हजार छियानबे किलोमीटर और चीन के साथ तीन हजार चार सौ अठासी किलोमीटर की सीमा शामिल है, जो विविध भूभाग जैसे रेगिस्तान, पहाड़ और नदियों से गुजरती है। इन सीमाओं पर सालाना पांच सौ से अधिक घुसपैठ की कोशिशें दर्ज होती हैं, मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में जहां एक सौ पचास घटनाएं सामने आईं। सीमा सुरक्षा बल इन क्षेत्रों में दो लाख पैसठ हजार से अधिक जवानों को तैनात करता है, जो मौसमी चुनौतियों जैसे बर्फबारी और बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बांग्लादेश सीमा पर मवेशी तस्करी की एक हजार दो सौ वार्षिक घटनाएं सुरक्षा को जटिल बनाती हैं, जबकि म्यांमार सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी तीन सौ टन से अधिक पहुंच गई है। ये चुनौतियां बहुपक्षीय हैं, जहां अवैध प्रवासन की दर दस प्रतिशत सालाना बढ़ रही है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कुल रूप से, ये सीमाएं राष्ट्रीय अखंडता की कुंजी हैं, जो बहुमुखी खतरे पैदा करती हैं।

चुनौतियों में भौगोलिक विविधता प्रमुख है, जहां हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई पांच हजार मीटर से अधिक होने से निगरानी कठिन हो जाती है, और दो सौ से ज्यादा सुरंगों की खोज हुई। पाकिस्तान सीमा पर भूमि माइन की एक हजार घटनाएं सालाना रिपोर्ट होती हैं, जो जवानों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। पूर्वोत्तर सीमाओं पर जंगली इलाके अवैध हथियारों की तस्करी को बढ़ावा देते हैं, जहां पांच सौ से अधिक जत्तियां हुईं। ये मुद्दे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, जहां बाढ़ से बीस प्रतिशत सीमा पोस्ट प्रभावित होते हैं। चुनौतियां मानव तस्करी से जुड़ी हैं, जहां महिलाओं और बच्चों की आठ सौ वार्षिक घटनाएं दर्ज होती हैं। अंत में, ये अवरोध सीमा प्रबंधन को जटिल बनाते हैं, जो एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करते हैं।

सीमा फेंसिंग परियोजनाओं का विकास

फेंसिंग परियोजनाओं की शुरुआत 1980 के दशक में हुई, जब पाकिस्तान सीमा पर दो हजार किलोमीटर की बाड़ लगाई गई, जो अब पांच नब्बे प्रतिशत पूरी हो चुकी है और तीन हजार दो सौ किलोमीटर तक पहुंच गई। बांग्लादेश सीमा पर तीन हजार किलोमीटर की फेंसिंग पूरी हुई, जिसमें स्मार्ट बाड़ प्रणाली शामिल है जो गति सेंसर से लैस है। इन परियोजनाओं का बजट दस हजार करोड़ रुपये है, जो बहु-स्तरीय बाड़ों का निर्माण करती है, जहां पांच मीटर ऊंची जालियां और कंटीले तार लगाए जाते हैं। विकास में सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें शामिल हैं, जो एक हजार पांच सौ किलोमीटर क्षेत्र को रोशन करती हैं। ये प्रयास घुसपैठ को साठ प्रतिशत कम करने में सफल रहे, जहां एक सौ से कम घटनाएं बाड़ वाले क्षेत्रों में हुईं। कुल रूप से, ये परियोजनाएं सीमा को अभेद्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, जो तकनीकी उन्नति से प्रेरित हैं।

विकास की प्रक्रिया में म्यांमार सीमा पर एक हजार किलोमीटर की फेंसिंग पूरी होने वाली है, जिसमें ड्रोन-सक्षम गेट शामिल हैं जो स्वचालित रूप से खुलते-बंद होते हैं। चीन सीमा पर चुनौतीपूर्ण इलाकों में पांच सौ किलोमीटर की डिजिटल फेंसिंग स्थापित की गई, जो इंफ्रारेड सेंसर से जुड़ी है। परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ी, जहां दो हजार ग्रामीणों को रोजगार मिला। ये प्रयास पर्यावरण-अनुकूल हैं, जहां तीस प्रतिशत सामग्री पुनर्चक्रित है। विकास से तस्करी में चालीस प्रतिशत कमी आई, जहां दो सौ टन से कम माल जब्त हुआ। अंततः, ये क्रमिक कदम फेंसिंग को मजबूत बनाते हैं, जो सीमा सुरक्षा की आधारभूत संरचना हैं।

तकनीकी निगरानी प्रणालियों का एकीकरण

निगरानी प्रणालियों में बंद सर्किट टेलीविजन कैमरों का उपयोग प्रमुख है, जहां पाकिस्तान सीमा पर पांच हजार से अधिक कैमरे लगाए गए, जो चौबीस घंटे वास्तविक-समय फुटेज प्रदान करते हैं। एकीकरण में थर्मल इमेजिंग शामिल है, जो रात के समय दो किलोमीटर दूर तक पता लगाती है और तीन सौ घुसपैठियों को पकड़ा। उपग्रह इमेजरी से एक हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी होती है, जो मौसम परिवर्तनों को ट्रैक करती है। ये प्रणालियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हैं, जो असामान्य गतिविधियों को नब्बे प्रतिशत सटीकता से पहचानती हैं। एकीकरण से

ऑपरेशनल लागत पच्चीस प्रतिशत घटी, जहां आठ हजार करोड़ रुपये है। कुल रूप से, ये सिस्टम निगरानी को उन्नत बनाते हैं, जो खतरे की तत्काल पहचान करते हैं।

एकीकरण की प्रक्रिया में रडार सिस्टम शामिल हैं, जो बांग्लादेश सीमा पर दो सौ यूनिट तैनात हैं और पांच किलोमीटर रेंज में गति ट्रैक करते हैं। भूमि सेंसर एक हजार पांच सौ किलोमीटर क्षेत्र में कंपन पता लगाते हैं, जो एक सौ पचास अलर्ट उत्पन्न किए। ये प्रणालियां क्लाउड-आधारित डेटा भंडारण से जुड़ी हैं, जो दस टेराबाइट डेटा सालाना संग्रहीत करती हैं। एकीकरण से मानव संसाधन की बचत हुई, जहां बीस प्रतिशत कम जवान तैनात करने पड़े। ये प्रयास स्मार्ट शहर मॉडल से प्रेरित हैं, जहां पांच सौ अतिरिक्त सेंसर लगाए जाएंगे। अंत में, ये व्यवस्थाएं तकनीकी निगरानी को एकीकृत करती हैं, जो सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं।

घुसपैठ-रोधी उपायों की रणनीतियां

घुसपैठ-रोधी रणनीतियां में गश्ती इकाइयां प्रमुख हैं, जहां पचास हजार से अधिक वाहन तैनात हैं और दैनिक एक हजार किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हैं। उपायों में सुरंग डिटेक्शन शामिल है, जो सोनार तकनीक से एक सौ मीटर गहराई तक पता लगाती है और पचास सुरंगें नष्ट कीं। रणनीतियां स्थानीय खुफिया नेटवर्क पर आधारित हैं, जहां पांच हजार मुखबिरो से सूचनाएं एकत्र होती हैं। ये तरीके ड्रोन गश्त से जुड़े हैं, जो पांच सौ यूनिट के साथ दो हजार घंटे उड़ान भरते हैं। रणनीतियों से घुसपैठ दर पचास प्रतिशत घटी, जहां एक सौ से कम प्रयास सफल हुए। कुल रूप से, ये उपाय घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हैं, जो बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाते हैं। रणनीतियों की संरचना में संयुक्त अभ्यास शामिल हैं, जहां सेना और स्थानीय पुलिस दो सौ सेशन आयोजित कर चुके हैं। उपायों में बायोमेट्रिक जांच चौकियां हैं, जो एक हजार स्थानों पर लगी हैं और पांच मिलियन लोगों की जांच करती हैं। ये तरीके वाहन स्कैनर से जुड़े हैं, जो तीन सौ टन सामग्री सालाना स्कैन करते हैं। रणनीतियां जल क्षेत्रों पर फोकस करती हैं, जहां नाव गश्त पांच सौ किलोमीटर नदियों को कवर करती है। इनसे तस्करी पैतीस प्रतिशत कम हुई, जहां एक सौ पचास छापे सफल रहे। अंततः, ये विधियां घुसपैठ-रोधी प्रयासों को मजबूत बनाती हैं, जो सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं।

प्रमुख उपलब्धियां और आंकड़े

उपलब्धियों में पाकिस्तान सीमा पर तीन हजार किलोमीटर फेंसिंग पूरी होना प्रमुख है, जो घुसपैठ को सत्तर प्रतिशत घटा चुकी है। आंकड़ों में दो सौ जब्तियां शामिल हैं, जहां पांच सौ हथियार और एक हजार किलोग्राम नशीले पदार्थ पकड़े गए। निगरानी से चार सौ अलर्ट उत्पन्न हुए, जो एक सौ पचास संदिग्धों को पकड़ने में सहायक रहे। ये परिणाम दस हजार करोड़ रुपये के निवेश से प्राप्त हुए, जो पंद्रह प्रतिशत बढ़ा। उपलब्धियां पूर्वोत्तर सीमाओं पर दिखीं, जहां तीन सौ तस्करी मार्ग बंद हुए। कुल मिलाकर, ये सफलताएं सीमा सुरक्षा की क्षमता को दर्शाती हैं, जो निरंतर प्रयासों से आई हैं। आंकड़ों में बांग्लादेश सीमा पर चार हजार किलोमीटर फेंसिंग से अवैध प्रवासन चालीस प्रतिशत कम हुआ, जहां पांच हजार लोग लौटाए गए। उपलब्धियों में ड्रोन से एक हजार घंटे की निगरानी शामिल है, जो दो सौ खतरे रोके। ये परिणाम दो हजार सेंसरों से प्राप्त हुए, जो पांच सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हैं। उपलब्धियां चीन सीमा पर सुरंग नष्ट करने में हैं, जहां तीस संरचनाएं ध्वस्त की गईं। आंकड़े बारह हजार करोड़ रुपये दिखाते हैं, जो उन्नति का संकेत है। अंत में, ये आंकड़े और उपलब्धियां प्रगति को प्रमाणित करते हैं, जो सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाते हैं।

भविष्य की दिशा और सुधार सुझाव

भविष्य की दिशा में स्मार्ट फेंसिंग का विस्तार है, जो पांच हजार किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेंसर लगाएगा और घुसपैठ को अस्सी प्रतिशत कम करेगा। सुधारों में ड्रोन बेड़े बढ़ाना शामिल है, जहां एक हजार अतिरिक्त यूनिट तैनात होंगी और तीन हजार घंटे उड़ान बढ़ेंगी। दिशाएं उपग्रह निगरानी को मजबूत करेंगी, जो दो हजार वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। ये योजनाएं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री पर फोकस करेंगी, जहां पचास प्रतिशत फेंसिंग सौर ऊर्जा से चलेगी। सुधार से बजट पंद्रह हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। कुल रूप से, ये दिशाएं सीमा सुरक्षा को आधुनिक बनाएंगी, जो नए खतरे से मुकाबला करेंगी। सुझावों में संयुक्त प्रशिक्षण बढ़ाना है, जहां पांच हजार जवानों को विशेष कोर्स दिए जाएंगे और दक्षता तीस प्रतिशत बढ़ेगी। भविष्य में बायोमेट्रिक सिस्टम अपग्रेड होगा, जो दस मिलियन जांच सालाना संभालेगा। दिशाएं रडार नेटवर्क विस्तार पर हैं, जो तीन सौ यूनिट अतिरिक्त लगाएंगी। ये प्रस्ताव स्थानीय भागीदारी बढ़ाएंगे, जहां तीन हजार ग्रामीणों को शामिल किया जाएगा। सुधारों से घुसपैठ दर नब्बे प्रतिशत कम हो सकती है। अंततः, ये सुझाव सुरक्षा उपायों को उन्नत बनाते हैं, जो राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करेंगे।

अध्याय 41:

अर्धसैनिक बलों और विशेष इकाइयों को अत्याधुनिक हथियार व उपकरण

अर्धसैनिक बलों की संरचना और भूमिका

भारत के अर्धसैनिक बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं, जो कुल मिलाकर दस लाख से अधिक जवानों की ताकत रखते हैं और आंतरिक सुरक्षा से लेकर सीमा प्रबंधन तक के कार्य संभालते हैं। इन बलों की भूमिका और विस्तारित हो गई है, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकेले तीन लाख से ज्यादा सदस्यों के साथ दंगों और उग्रवाद नियंत्रण में सक्रिय है, जबकि सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर दो लाख पैसठ हजार जवानों के साथ तैनात है। इनकी संरचना बहु-स्तरीय है, जिसमें विशेष दस्ते जैसे त्वरित कार्रवाई बल शामिल हैं, जो सालाना पांच सौ से अधिक अभियानों में भाग लेते हैं। भूमिका में नागरिक सहायता भी आती है, जहां प्राकृतिक आपदाओं में एक लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। ये बल सेना के पूरक हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में चालीस प्रतिशत योगदान देते हैं। कुल रूप से, ये संरचनाएं विविध चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई हैं, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी रहती हैं।

विशेष इकाइयों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका काउंटर-टेररिज्म पर केंद्रित है, जहां दस हजार से अधिक कमांडो विभिन्न शहरों में तैनात हैं और बंधक बचाव अभियानों में विशेषज्ञ हैं। इनकी संरचना में ब्लैक कैट कमांडो शामिल हैं, जो दो सौ से ज्यादा अभ्यासों में भाग ले चुके हैं। भूमिका में महत्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षा भी आती है, जहां पांच हजार से अधिक प्रमुख व्यक्तियों की रक्षा की जाती है। इन बलों की तैनाती शहरी क्षेत्रों में बढ़ी है, जहां अपराध दर पंद्रह प्रतिशत कम करने में योगदान दिया गया। संरचना में असम राइफल्स जैसे क्षेत्रीय बल शामिल हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों में साठ हजार जवानों के साथ उग्रवाद नियंत्रित करते हैं। अंत में, ये इकाइयां राष्ट्रीय ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो बहुमुखी कार्यों से सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

आधुनिक हथियारों का अधिग्रहण

आधुनिक हथियारों में एके-दो सौ तीन असॉल्ट राइफल्स का अधिग्रहण प्रमुख है, जहां छह लाख से अधिक इकाइयां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल को वितरित की गईं, जो रूसी तकनीक पर आधारित हैं और छह सौ मीटर रेंज प्रदान करती हैं। अधिग्रहण में यूग्रा राइफल शामिल है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित है और पचास हजार यूनिट्स का परीक्षण पूरा हुआ, जिसमें सात दशमलव छह दो मिलीमीटर कैलिबर से उच्च सटीकता मिलती है। ये हथियार स्वदेशी उत्पादन पर फोकस करते हैं, जहां अमेठी फैक्ट्री सालाना एक लाख राइफल्स बनाती है। अधिग्रहण से पुरानी इंसास राइफल्स को प्रतिस्थापित किया गया, जो तीस प्रतिशत अधिक प्रभावी साबित हुईं। ये प्रयास भारत में बनाओ से प्रेरित हैं, जहां सत्तर प्रतिशत घटक स्थानीय हैं। कुल रूप से, ये अधिग्रहण बलों की मारक क्षमता बढ़ाते हैं, जो अभियानों में निर्णायक साबित होते हैं।

हथियारों में एस-चार सौ वायु रक्षा सिस्टम का एकीकरण हुआ है, जहां पांच रेजिमेंट्स सीमा सुरक्षा बल में तैनात हैं और चार सौ किलोमीटर रेंज में ड्रोन हमलों को रोकते हैं। अधिग्रहण में लेजर हथियार शामिल हैं, जो एक सौ यूनिट्स का परीक्षण किया गया और दो किलोमीटर दूरी से लक्ष्य नष्ट करते हैं। ये सिस्टम स्मार्ट बमों से जुड़े हैं, जहां ब्रह्मोस मिसाइल्स की दो सौ यूनिट्स विशेष इकाइयों को दी गईं। अधिग्रहण प्रक्रिया में दस हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से चालीस प्रतिशत कम निर्भरता दिखाता है। ये हथियार बहु-उपयोगी हैं, जहां रात्रि दृष्टि स्कोप एक लाख जवानों को प्रदान किए गए। अंततः, ये कदम हथियार प्रणालियों को उन्नत बनाते हैं, जो सुरक्षा चुनौतियों से मुकाबला करते हैं।

विशेष इकाइयों के लिए उन्नत उपकरण

विशेष इकाइयों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए ड्रोन-रोधी उपकरण प्रमुख हैं, जहां पांच सौ यूनिट्स तैनात हैं और पांच किलोमीटर रेंज में मानवरहित हवाई वाहन को निष्क्रिय करते हैं। उन्नत उपकरणों में शरीर कवच शामिल है, जो दस हजार सेट्स प्रदान किए गए और नौ मिलीमीटर गोलियों से सुरक्षा देते हैं। ये उपकरण हेलमेट-माउंटेड कैमरों से जुड़े हैं, जहां दो हजार यूनिट्स वितरित हुए और वास्तविक-समय वीडियो ट्रांसमिशन प्रदान करते हैं। विशेष इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुसार, ये

उपकरण हल्के वजन के हैं, जहां प्रत्येक सेट पांच किलोग्राम से कम है। उन्नति से अभियान सफलता पच्चीस प्रतिशत बढ़ी, जहां बंधक बचाव में एक सौ से अधिक मिशन पूरे हुए। कुल रूप से, ये उपकरण कमांडो की क्षमता बढ़ाते हैं, जो उच्च जोखिम वाले कार्यों में उपयोगी हैं। उपकरणों में त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों का उपयोग हुआ है, जहां तीन सौ से अधिक वाहन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में शामिल हैं और एक सौ किलोमीटर प्रति घंटा गति से पहुंचते हैं। उन्नत सिस्टम में थर्मल इमेजर्स शामिल हैं, जो एक हजार पांच सौ यूनिट्स प्रदान किए गए और रात के अभियानों में तीन किलोमीटर दूरी से लक्ष्य पहचानते हैं। ये उपकरण रोबोटिक डिवाइस से जुड़े हैं, जहां दो सौ बॉट्स बम डिफ्यूज करने में सक्षम हैं। विशेष इकाइयों के लिए, ये उपकरण मॉड्यूलर हैं, जहां अनुकूलन से दक्षता पैंतीस प्रतिशत बढ़ी। ये प्रयास अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हैं, जहां पचास प्रतिशत उपकरण आयातित हैं। अंत में, ये उन्नयन विशेष दस्तों को मजबूत बनाते हैं, जो काउंटर-टेरिज्म में प्रभावी रहते हैं।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए सिमुलेशन केंद्र प्रमुख हैं, जहां दस केंद्र स्थापित हैं और सालाना बीस हजार जवानों को आभासी ट्रेनिंग देते हैं। क्षमता निर्माण में शूटिंग रेंज शामिल हैं, जो पांच सौ से अधिक स्थानों पर हैं और जीवंत फायर अभ्यास प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम ड्रोन अभियान पर फोकस करते हैं, जहां पांच हजार जवानों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण से अभियान त्रुटियां बीस प्रतिशत कम हुईं, जहां सिमुलेटेड परिदृश्यों में नब्बे प्रतिशत सफलता मिली। क्षमता में अंतर-बल अभ्यास शामिल हैं, जहां एक हजार संयुक्त सेशन सालाना होते हैं। कुल रूप से, ये प्रयास जवानों की कौशल को बढ़ाते हैं, जो वास्तविक स्थितियों में उपयोगी साबित होते हैं। क्षमता निर्माण में विशेष इकाइयों के लिए विदेशी सहयोग प्रमुख है, जहां दो हजार कमांडो अमेरिकी और इजरायली विशेषज्ञों से ट्रेनिंग ले चुके हैं। प्रशिक्षण में साइबर युद्ध मॉड्यूल शामिल हैं, जो एक हजार पांच सौ सदस्यों को कवर करते हैं और हैकिंग रोकथाम सिखाते हैं। ये कार्यक्रम फिटनेस मानकों पर आधारित हैं, जहां वार्षिक टेस्ट में पांच नब्बे प्रतिशत पास दर है। निर्माण से नेतृत्व कौशल बढ़े, जहां पांच सौ अधिकारियों को उन्नत कोर्स दिए गए। प्रशिक्षण बजट दो हजार करोड़ रुपये है, जो पंद्रह प्रतिशत बढ़ा। अंततः, ये कदम क्षमता को मजबूत बनाते हैं, जो बलों की तैयारियों को बढ़ावा देते हैं।

बजट और वित्तीय आवंटन बजट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए पैंतीस हजार एक सौ सैंतालीस करोड़ रुपये आवंटित हैं, जो हथियार खरीद पर दस हजार करोड़ रुपये खर्च करता है और वेतन पर साठ प्रतिशत जाता है। वित्तीय आवंटन में सीमा सुरक्षा बल को अट्ठाईस हजार दो सौ इकतीस करोड़ रुपये मिले, जो उपकरण उन्नयन पर आठ हजार करोड़ रुपये निर्दिष्ट हैं। ये राशियां आधुनिकीकरण योजना-चार से जुड़ी हैं, जहां कुल एक हजार पांच सौ तेईस करोड़ रुपये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए मंजूर हुए। आवंटन से स्वदेशी हथियारों पर फोकस बढ़ा, जहां सत्तर प्रतिशत बजट स्थानीय उत्पादन पर है। वित्तीय संरचना में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को चौदह हजार करोड़ रुपये दिए गए, जो औद्योगिक सुरक्षा पर केंद्रित हैं। कुल रूप से, ये आवंटन संसाधनों को सुनिश्चित करते हैं, जो अभियान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वित्तीय आवंटन में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए दो हजार करोड़ रुपये शामिल हैं, जो पांच सौ करोड़ रुपये खर्च करता है। बजट में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को नौ हजार करोड़ रुपये मिले, जो हिमालयी क्षेत्रों में तैनाती पर फोकस करते हैं। ये राशियां पूर्व वर्षों से दस प्रतिशत बढ़ीं, जहां कुल गृह मंत्रालय बजट एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये है। आवंटन से प्रशिक्षण पर एक हजार करोड़ रुपये निर्दिष्ट हैं, जो क्षमता निर्माण में योगदान देते हैं। वित्तीय योजना में सशस्त्र सीमा बल को सात हजार करोड़ रुपये दिए गए, जो पूर्वोत्तर सुरक्षा पर केंद्रित हैं। अंत में, ये बजट रणनीतियां वित्तीय संसाधनों को अनुकूलित करती हैं, जो बलों की प्रभावशीलता बढ़ाती हैं।

भविष्य की योजनाएं और चुनौतियां

भविष्य की योजनाओं में उन्नत बहु भूमिका लड़ाकू विमान का एकीकरण है, जो मंजूर हुआ और विशेष इकाइयों के लिए एक सौ यूनिट्स का लक्ष्य रखता है, जिसमें स्टेल्थ तकनीक शामिल है। चुनौतियों में बजट की कमी प्रमुख है, जहां अनुमानित जरूरतों से बीस प्रतिशत कम आवंटन हुआ। योजनाएं लेजर-आधारित हथियारों पर फोकस करती हैं, जो पांच सौ यूनिट्स तैनात करने का लक्ष्य रखती हैं। भविष्य में ड्रोन बेड़े विस्तार होगा, जहां एक हजार अतिरिक्त यूनिट्स शामिल होंगी। चुनौतियां आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी हैं, जहां तीस प्रतिशत उपकरण देरी से पहुंचते हैं। कुल रूप से, ये योजनाएं विकास की दिशा दिखाती हैं, जो चुनौतियों से निपटने का प्रयास करती हैं। चुनौतियों में तकनीकी प्रशिक्षण की कमी शामिल है, जहां पंद्रह प्रतिशत जवान उन्नत उपकरणों से अपरिचित हैं। योजनाओं में साइबर रक्षा उपकरणों का अधिग्रहण है, जो

दो हजार यूनिट्स का लक्ष्य रखता है। भविष्य में रोबोटिक सिस्टम बढ़ेंगे, जहां तीन सौ बॉम्ब्स बम डिटेक्शन के लिए होंगे। चुनौतियां राजनीतिक हस्तक्षेप से बढ़ती हैं, जहां दस प्रतिशत बजट कटौती हुई। योजनाएं स्वदेशी उत्पादन पर जोर देती हैं, जहां अस्सी प्रतिशत लक्ष्य है। अंततः, ये दिशाएं भविष्य को आकार देती हैं, जो चुनौतियों को अवसरों में बदलती हैं।

अध्याय 42:

आतंकवाद के वित्तपोषण और हवाला नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई

आतंकवादी वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत

आतंकवादी वित्तपोषण के स्रोतों में विदेशी दान मुख्य हैं, जहां खाड़ी देशों से पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हवाला चैनलों से भारत पहुंची, मुख्य रूप से जिहादी समूहों को समर्थन देने के लिए। इन स्रोतों में अपहरण और फिरौती शामिल हैं, जहां पूर्वोत्तर राज्यों में सालाना तीन सौ से अधिक मामलों से एक हजार करोड़ रुपये इकट्ठा होते हैं, जो उग्रवादी गुटों की आय का चालीस प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। दान के रूप में आने वाली राशि धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी होती है, जहां दो हजार से ज्यादा फर्जी गैर सरकारी संगठनों की जांच में आठ सौ करोड़ रुपये की अनियमितता पाई गई। ये स्रोत ड्रग तस्करी से जुड़े हैं, जहां अफगानिस्तान से आने वाली हेरोइन की पांच सौ टन सालाना व्यापार से दस हजार करोड़ रुपये की कमाई होती है। वित्तपोषण की विविधता से संगठन स्वतंत्र रहते हैं, जहां तीस प्रतिशत आय स्थानीय जबरन वसूली से आती है। कुल रूप से, ये स्रोत आतंकवाद को जीवित रखने की रीढ़ हैं, जो बहु-स्तरीय नेटवर्क से संचालित होते हैं।

स्रोतों में जाली मुद्रा का उत्पादन प्रमुख है, जहां पाकिस्तान आधारित प्रेस से तीन हजार करोड़ रुपये मूल्य की नकली नोट भारत में फैलाई गईं, जो बाजार में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं। इनमें ऑनलाइन क्राउडफंडिंग शामिल है, जहां सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक हजार पांच सौ अभियानों से पांच सौ करोड़ रुपये जुटाए गए, मुख्य रूप से विदेशी डायस्पोरा से। वित्तपोषण में संपत्ति निवेश का योगदान है, जहां रियल एस्टेट में दो हजार करोड़ रुपये की खरीदारी दर्ज हुई, जो आय को छिपाने का माध्यम बनती है। ये स्रोत कर चोरी से जुड़े हैं, जहां चार सौ से अधिक मामलों में एक हजार दो सौ करोड़ रुपये की हानि हुई। विविधता से ट्रेकिंग कठिन होती है, जहां बीस प्रतिशत आय क्रिप्टोकॉर्सेसी से आती है। अंत में, ये माध्यम वित्तीय प्रवाह को जटिल बनाते हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती पैदा करते हैं।

हवाला नेटवर्क की कार्यप्रणाली

हवाला नेटवर्क की कार्यप्रणाली में अनौपचारिक ट्रांसफर प्रमुख है, जहां पचास हजार से अधिक ऑपरेटर भारत में सक्रिय हैं और सालाना बीस हजार करोड़ रुपये का लेनदेन करते हैं, मुख्य रूप से दुबई और सिंगापुर से जुड़े चैनलों से। ये नेटवर्क पासवर्ड-आधारित सिस्टम पर चलते हैं, जहां भेजने वाला व्यक्ति एक कोड देता है और प्राप्तकर्ता उसी से राशि लेता है, बिना बैंकिंग रिकॉर्ड के। कार्यप्रणाली में स्थानीय एजेंटों की भूमिका है, जहां मुंबई और दिल्ली में दस हजार से ज्यादा दुकानें कवर के रूप में काम करती हैं, जो पांच प्रतिशत कमीशन लेती हैं। नेटवर्क में क्रिप्टोकॉइन्स की एकीकरण हुआ है, जहां दो हजार ट्रांजेक्शन बिटकॉइन से पूरे हुए। ये सिस्टम गोपनीयता पर आधारित हैं, जहां कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। कुल रूप से, ये विधियां वित्तीय लेनदेन को अदृश्य बनाती हैं, जो ट्रेसिंग को मुश्किल करती हैं।

कार्यप्रणाली में बहु-देशीय कनेक्शन शामिल हैं, जहां पाकिस्तान से आठ हजार करोड़ रुपये सालाना हवाला से आते हैं, मुख्य रूप से आतंकवादी गुटों को सपोर्ट करने के लिए। नेटवर्क में मोबाइल ऐप्स का उपयोग होता है, जहां पांच हजार से अधिक यूजर्स रजिस्टर्ड हैं और इंस्टेंट ट्रांसफर प्रदान करते हैं। ये सिस्टम ट्रस्ट-बेस्ड हैं, जहां पार्टनर नेटवर्क बीस देशों में फैला है और बैलेंस सेटलमेंट महीने के अंत में होता है। कार्यप्रणाली में फर्जी व्यापार बिलों का योगदान है, जहां तीन हजार करोड़ रुपये की ओवर-इनवॉइसिंग पकड़ी गई। नेटवर्क की लचीलापन से रिकवरी तेज होती है, जहां छापे के बाद दस प्रतिशत ऑपरेटर नए स्थान पर शिफ्ट होते हैं। अंत में, ये तंत्र हवाला को मजबूत बनाते हैं, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली को बायपास करते हैं।

कानूनी ढांचा और प्रवर्तन

कानूनी ढांचे में धन शोधन निवारण अधिनियम प्रमुख है, जहां दस हजार से अधिक मामलों में पंद्रह हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई, मुख्य रूप से आतंकवादी फंडिंग से जुड़े। प्रवर्तन में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं, जहां वित्तीय सहायता को अपराध मानकर सात वर्ष की सजा दी जाती है और पांच हजार आरोपित गिरफ्तार हुए। ढांचा में वित्तीय खुफिया इकाई की भूमिका है, जहां सालाना दो लाख संदिग्ध ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होते हैं। कानूनी उपायों में बैंकिंग नियम सख्त हुए हैं, जहां दस लाख रुपये से अधिक नकद जमा पर जांच अनिवार्य है।

प्रवर्तन से हवाला मामलों में तीस प्रतिशत कमी आई, जहां एक हजार छापे मारे गए। कुल रूप से, ये नियम वित्तीय अपराधों को नियंत्रित करते हैं, जो जांच को मजबूत बनाते हैं। प्रवर्तन में प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता प्रमुख है, जहां चार हजार जांचें पूरी हुईं और आठ हजार करोड़ रुपये जब्त किए गए, मुख्य रूप से हवाला से जुड़े। ढांचा में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों का पालन शामिल है, जहां भारत की रेटिंग सुधरी और नब्बे प्रतिशत अनुपालन हासिल हुआ। कानूनी प्रक्रियाओं में विशेष अदालतें हैं, जहां पांच सौ मामलों की सुनवाई छह महीनों में पूरी होती है। प्रवर्तन में डिजिटल ट्रैकिंग शामिल है, जहां एक हजार पांच सौ ऐप्स की मॉनिटरिंग से चार सौ करोड़ रुपये पकड़े गए। ढांचा से दोषसिद्धि दर पच्चीस प्रतिशत पहुंची, जो पूर्व वर्षों से दोगुनी है। अंत में, ये उपाय कानूनी प्रवर्तन को प्रभावी बनाते हैं, जो वित्तीय अपराधों को दबाते हैं।

जांच एजेंसियों की भूमिका और समन्वय

जांच एजेंसियों में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका प्रमुख है, जहां चार हजार से अधिक अधिकारी तैनात हैं और हवाला नेटवर्क पर दो हजार छापे मार चुके हैं, मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में। समन्वय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी शामिल है, जहां आतंकवादी मामलों में एक हजार पांच सौ संयुक्त अभियान हुए और पांच सौ करोड़ रुपये जब्त किए गए। एजेंसियों की भूमिका में खुफिया ब्यूरो से सूचना साझाकरण है, जहां दैनिक तीन सौ रिपोर्ट्स आदान-प्रदान होती हैं। जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो की भागीदारी है, जहां आठ सौ मामलों में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच की गई। समन्वय से सफलता दर चालीस प्रतिशत बढ़ी, जहां तीन सौ गिरफ्तारियां हुईं। कुल रूप से, ये एजेंसियां वित्तीय जांच को एकीकृत करती हैं, जो अपराध नेटवर्क को तोड़ती हैं। समन्वय में वित्तीय खुफिया इकाई की केंद्रीय भूमिका है, जहां पांच लाख संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जांच हुई और एक हजार दो सौ करोड़ रुपये फ्रीज किए गए। एजेंसियों में सीमा शुल्क विभाग शामिल है, जहां सीमा पर तीन हजार छापों से आठ सौ करोड़ रुपये की तस्करी रोकी गई। भूमिका में राज्य पुलिस की सहायता है, जहां बीस राज्यों में एक हजार संयुक्त कार्यबल बने। जांच में डीआरआई की भागीदारी है, जहां ड्रग संबंधित पांच सौ मामलों में चार सौ करोड़ रुपये पकड़े गए। समन्वय से जानकारी प्रवाह तेज हुआ, जहां दो हजार संयुक्त मीटिंग्स हुईं। अंत में, ये प्रयास एजेंसियों को मजबूत बनाते हैं, जो वित्तीय अपराधों से मुकाबला करते हैं।

प्रमुख उपलब्धियां और आंकड़े

उपलब्धियों में हवाला नेटवर्क पर तीन हजार छापे प्रमुख हैं, जहां दस हजार करोड़ रुपये जब्त किए गए और दो हजार ऑपरेटर गिरफ्तार हुए, मुख्य रूप से उत्तर भारत में। आंकड़ों में धन शोधन मामलों में पांच हजार जांचें शामिल हैं, जहां आठ हजार करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच हुई। उपलब्धियां फर्जी गैर सरकारी संगठनों पर कार्रवाई में हैं, जहां एक हजार पांच सौ संस्थाएं बंद की गईं और छह सौ करोड़ रुपये जब्त हुए। ये परिणाम क्रिप्टो ट्रेडिंग से आए, जहां चार सौ करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति फ्रीज की गई। आंकड़े दोषसिद्धि में बीस प्रतिशत वृद्धि दिखाते हैं, जहां तीन सौ सजाएं हुईं। कुल रूप से, ये सफलताएं वित्तीय नियंत्रण को दर्शाती हैं, जो आतंकवाद को कमजोर बनाती हैं।

आंकड़ों में विदेशी फंडिंग में तीस प्रतिशत कमी शामिल है, जहां चार हजार करोड़ रुपये रोके गए, मुख्य रूप से खाड़ी से आने वाले। उपलब्धियां जाली मुद्रा पर कार्रवाई में हैं, जहां दो हजार करोड़ रुपये मूल्य की नोट्स जब्त की गईं। ये परिणाम संयुक्त अभियानों से प्राप्त हुए, जहां एक हजार छापों में पांच सौ गिरफ्तारियां हुईं। उपलब्धियां ड्रग तस्करी रोकने में हैं, जहां तीन सौ टन सामग्री पकड़ी गई और पांच हजार करोड़ रुपये की हानि रोकी गई। आंकड़े गैर सरकारी संगठन जांच में दो हजार मामलों की जांच दिखाते हैं, जहां सात सौ करोड़ रुपये जब्त हुए। अंत में, ये आंकड़े उपलब्धियों को प्रमाणित करते हैं, जो वित्तीय कार्रवाई की प्रभावशीलता दिखाते हैं।

भविष्य की चुनौतियां और सुधार सुझाव

भविष्य की चुनौतियों में डिजिटल वॉलेट्स का बढ़ता उपयोग प्रमुख है, जहां दस हजार से अधिक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन आतंकवाद से जुड़े पाए गए, लेकिन ट्रेडिंग में पचास प्रतिशत कमी है। सुधार सुझावों में ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करना शामिल है, जो पांच हजार ट्रांजेक्शन दैनिक ट्रैक करेगा। चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय सहयोग की कमी से हैं, जहां तीस प्रतिशत फंड विदेशी बैंकों से आते हैं। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन पर फोकस होगा, जो एक लाख रिपोर्ट्स सालाना प्रोसेस करेगा। सुधार से बजट दो हजार करोड़ रुपये बढ़ सकता है। कुल रूप से, ये चुनौतियां विकास को प्रभावित करती हैं, जो सुधारों से हल हो सकती हैं। सुधारों में एजेंसी समन्वय बढ़ाना है, जहां बीस संयुक्त प्लेटफार्म बनेंगे और जांच समय

चालीस प्रतिशत कम होगा। चुनौतियों में स्थानीय हवाला ऑपरेटरों की संख्या शामिल है, जहां साठ हजार से अधिक सक्रिय हैं। भविष्य में कानूनी संशोधन होंगे, जहां क्रिप्टो पर दस प्रतिशत टैक्स लगाएंगे। सुधार में प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जहां पांच हजार अधिकारियों को विशेष कोर्स दिए जाएंगे। चुनौतियां वैश्विक महामारी से बढ़ीं, जहां ऑनलाइन फंडिंग पच्चीस प्रतिशत बढ़ी। अंत में, ये सुझाव भविष्य को मजबूत बनाते हैं, जो चुनौतियों को कम करने का प्रयास करते हैं।

अध्याय 43:

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियान

भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां

भारत ने आतंकवाद विरोधी समझौतों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है, जहां पचास से अधिक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियां हस्ताक्षरित हो चुकी हैं, मुख्य रूप से प्रत्यर्पण और सूचना साझाकरण पर केंद्रित। इनमें अमेरिका के साथ 2002 से चला आ रहा काउंटर-टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप शामिल है, जो अब तक बीस बैठकें आयोजित कर चुका है और पांच सौ से अधिक आतंकवादी मामलों में सहायता प्रदान कर चुका है। समझौतों में यूरोपीय संघ के साथ 2020 का संयुक्त बयान प्रमुख है, जो आतंकवादी फंडिंग पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की जांचों में सहयोग करता है। ये संधियां एशियन देशों के साथ भी विस्तारित हैं, जहां आसियान-भारत संयुक्त घोषणा से तीन सौ से ज्यादा संयुक्त वर्कशॉप आयोजित हुए। समझौतों से प्रत्यर्पण दर पच्चीस प्रतिशत बढ़ी, जहां एक सौ पचास से अधिक संदिग्धों को सौंपा गया। कुल रूप से, ये दस्तावेज वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत बनाते हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयासों को बढ़ावा देते हैं।

संधियों में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क के तहत दस नए समझौते शामिल हैं, जहां भारत ने आतंकवादी संगठनों की सूची में दो सौ नाम जोड़े और पांच हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज कीं। इनमें क्वाड देशों के साथ विदेश मंत्रियों का बैठक समझौता प्रमुख है, जो साइबर आतंकवाद पर चार सौ से अधिक संयुक्त अभ्यासों का आधार बना। समझौतों में ब्रिक्स प्लेटफॉर्म से जुड़े पंद्रह दस्तावेज हैं, जो वित्तीय ट्रैकिंग में दो हजार मामलों की जांच कर चुके हैं। ये संधियां मध्य पूर्व देशों के साथ भी हैं, जहां तीन सौ करोड़ रुपये की दान राशि पर नजर रखी गई। संधियों से वैश्विक सहयोग में भारत की हिस्सेदारी तीस प्रतिशत बढ़ी, जहां एक सौ से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है। अंत में, ये समझौते अंतरराष्ट्रीय ढांचे को मजबूत बनाते हैं, जो आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को लक्षित करते हैं।

बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका

बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रमुख है, जहां पंद्रह प्रस्तावों का समर्थन किया गया और आतंकवाद विरोधी समिति में पांच सौ रिपोर्ट्स योगदान दिए गए। इनमें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का सदस्य बनकर आतंकवादी फंडिंग जोखिमों पर दो सौ से अधिक सिफारिशें दी गईं। मंचों में क्वाड समूह की बैठकें शामिल हैं, जहां दसवीं बैठक से तीन सौ करोड़ रुपये की संयुक्त फंडिंग आतंकवाद विरोधी प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित हुई। भारत की सक्रियता ब्रिक्स में दिखी, जहां चार सौ से अधिक साझा दस्तावेज तैयार हुए। भूमिका से वैश्विक आतंकवाद घटनाओं में दस प्रतिशत कमी आई, जहां भारत ने एक सौ देशों के साथ सूचना साझा की। कुल रूप से, ये प्रयास बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाते हैं, जो वैश्विक शांति में योगदान देते हैं। मंचों में आसियान के साथ भारत की भागीदारी प्रमुख है, जहां बीस संयुक्त घोषणाएं जारी हुईं और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद लड़ाई में पांच सौ से अधिक प्रशिक्षण सेशन आयोजित हुए। इनमें जी-बीस शिखर सम्मेलनों शामिल हैं, जहां आतंकवाद फंडिंग पर एक हजार करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता ली गई। भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम में दिखी, जहां तीन सौ से अधिक मामलों में सहयोग किया गया। मंचों से प्रत्यर्पण समझौतों में एक सौ पचास से अधिक सफलताएं मिलीं। भूमिका ने क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाई, जहां दक्षिण एशिया में आतंकवाद घटनाएं बीस प्रतिशत घटीं। अंत में, ये योगदान भारत को वैश्विक नेता बनाते हैं, जो बहुपक्षीय प्रयासों को दिशा देते हैं।

द्विपक्षीय सहयोग के उदाहरण

द्विपक्षीय सहयोग में भारत-अमेरिका समझौता प्रमुख है, जहां पांच संयुक्त कार्यसमूह बैठकें हुईं और चार सौ से अधिक आतंकवादी संदिग्धों की जानकारी साझा की गई। उदाहरण में भारत-फ्रांस सहयोग शामिल है, जहां दो सौ करोड़ रुपये की संयुक्त फंडिंग से काउंटर-टेरिज्म केंद्र स्थापित हुए। ये सहयोग इजरायल के साथ हैं, जहां तीन सौ से अधिक तकनीकी हस्तांतरण आतंकवाद विरोधी उपकरणों के लिए हुए। द्विपक्षीय प्रयासों से प्रत्यर्पण मामलों में एक सौ से अधिक सफलताएं मिलीं। सहयोग ने साइबर क्षेत्र में पांच सौ से अधिक संयुक्त जांचें कीं। कुल रूप से, ये उदाहरण द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाते हैं, जो व्यावहारिक कार्रवाइयों पर केंद्रित हैं। उदाहरणों में भारत-यूके समझौता है, जहां एक सौ पचास से अधिक संयुक्त अभ्यासों से आतंकवाद फंडिंग

पर तीन सौ करोड़ रुपये रोके गए। द्विपक्षीय सहयोग ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जहां क्वाड ढांचे से दो सौ से अधिक सूचना आदान-प्रदान हुए। ये प्रयास सऊदी अरब के साथ हैं, जहां चार सौ करोड़ रुपये की दान राशि पर नजर रखी गई। सहयोग से सीमा पार आतंकवाद में पंद्रह प्रतिशत कमी आई। उदाहरणों में रूस के साथ समझौते शामिल हैं, जहां एक सौ से अधिक संयुक्त वर्कशॉप आयोजित हुए। अंत में, ये मामले द्विपक्षीय सहयोग की विविधता दिखाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं।

संयुक्त अभियानों और सफलताओं के आंकड़े

संयुक्त अभियानों में भारत-अमेरिका की ऑपरेशन से दो सौ से अधिक आतंकवादी संदिग्ध पकड़े गए, जहां साझा खुफिया से पांच सौ करोड़ रुपये की फंडिंग रोकी गई। सफलताओं में संयुक्त राष्ट्र के साथ तीन सौ से अधिक मिशनों की हिस्सेदारी है, जहां एक सौ पचास आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगे। अभियानों से प्रत्यर्पण में एक सौ से अधिक मामले सफल हुए, जहां दो हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं। आंकड़ों में क्वाड अभियानों से चार सौ से अधिक साइबर हमले रोके गए। सफलताएं आसियान संयुक्त अभियानों में हैं, जहां पांच सौ से अधिक ट्रेनिंग सेशन से क्षमता बढ़ी। कुल रूप से, ये अभियान वैश्विक सहयोग की सफलता दर्शाते हैं, जो आतंकवाद को कमजोर बनाते हैं। आंकड़ों में भारत-ईयू अभियानों से तीन सौ से अधिक संयुक्त जांचें हुईं, जहां एक हजार करोड़ रुपये की अवैध राशि पकड़ी गई। सफलताओं में ब्रिक्स मिशनों से दो सौ आतंकवादी नेटवर्क तोड़े गए। अभियानों से दोषसिद्धि में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि हुई, जहां एक सौ पचास सजाएं अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आईं। आंकड़े वित्तीय कार्रवाई कार्यबल रिपोर्ट से जुड़े हैं, जहां पांच सौ जोखिमों की पहचान हुई। सफलताएं मध्य पूर्व अभियानों में हैं, जहां चार सौ करोड़ रुपये की दान राशि ब्लॉक की गई। अंत में, ये परिणाम संयुक्त प्रयासों की प्रभावकारिता दिखाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर सुरक्षा बढ़ाते हैं।

चुनौतियां और बाधाएं

चुनौतियों में राजनीतिक मतभेद प्रमुख हैं, जहां बीस प्रतिशत समझौते क्रियान्वयन में देरी से प्रभावित हुए, मुख्य रूप से पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से। बाधाओं में सूचना साझाकरण की कमी शामिल है, जहां तीस प्रतिशत मामलों में गोपनीयता नियमों से ट्रेकिंग बाधित हुई। चुनौतियां वित्तीय संसाधनों से जुड़ी हैं, जहां विकासशील देशों के

साथ सहयोग में पांच सौ करोड़ रुपये की कमी दर्ज हुई। बाधाएं साइबर क्षेत्र में हैं, जहां चालीस प्रतिशत हमलों का पता नहीं लगता। चुनौतियां कानूनी असमानताओं से बढ़ती हैं, जहां एक सौ से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध अस्वीकृत हुए। कुल रूप से, ये मुद्दे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जटिल बनाते हैं, जो एकजुटता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। बाधाओं में सांस्कृतिक अंतर शामिल हैं, जहां पंद्रह प्रतिशत संयुक्त अभियानों में संचार समस्याओं से असफलता मिली। चुनौतियां वैश्विक महामारी से प्रभावित हैं, जहां पच्चीस प्रतिशत बैठकें आभासी हो गईं और प्रभाव कम हुआ। बाधाएं फंडिंग असमानता से हैं, जहां भारत ने एक हजार करोड़ रुपये योगदान दिए लेकिन प्राप्ति छह सौ करोड़ रुपये रही। चुनौतियां तकनीकी असंगतता से जुड़ी हैं, जहां दो सौ से अधिक सिस्टम एकीकरण में विफल रहे। बाधाएं भू-राजनीतिक तनाव से बढ़ती हैं, जहां दस प्रतिशत समझौते रद्द हुए। अंत में, ये अवरोध सहयोग की राह में रुकावटें हैं, जो सुधार की मांग करते हैं।

भविष्य की रणनीतियां और सुधार सुझाव

भविष्य की रणनीतियों में डिजिटल प्लेटफार्मों का विकास प्रमुख है, जहां पचास संयुक्त ऑनलाइन फोरम बनेंगे और सूचना साझाकरण चालीस प्रतिशत बढ़ेगा। सुधार सुझावों में कानूनी सामंजस्य बढ़ाना शामिल है, जहां एक सौ से अधिक देशों के साथ एकीकृत प्रत्यर्पण ढांचे का लक्ष्य है। रणनीतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता ट्रेकिंग पर फोकस करेंगी, जो पांच सौ से अधिक फंडिंग चैनलों की निगरानी करेगा। भविष्य में बहुपक्षीय फंडिंग बढ़ेगी, जहां दो हजार करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता ली जाएगी। सुधार से सहयोग दर तीस प्रतिशत बढ़ सकती है, जहां दो सौ नए समझौते हस्ताक्षरित होंगे। कुल रूप से, ये रणनीतियां वैश्विक सहयोग को मजबूत बनाएंगी, जो आतंकवाद विरोध में नई दिशा देंगी। सुझावों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार है, जहां एक हजार संयुक्त वर्कशॉप आयोजित होंगे और क्षमता पच्चीस प्रतिशत बढ़ेगी। भविष्य की योजनाओं में साइबर फोकस शामिल है, जहां तीन सौ से अधिक संयुक्त सिमुलेशन अभ्यास होंगे। रणनीतियां क्षेत्रीय मंचों पर जोर देंगी, जहां दक्षिण एशिया में पांच सौ करोड़ रुपये की फंडिंग आएगी। सुधार में राजनीतिक संवाद बढ़ाना है, जहां पचास उच्च-स्तरीय बैठकें सालाना होंगी। योजनाएं वित्तीय ट्रांसपेरेंसी पर केंद्रित होंगी, जहां एक हजार जांचें डिजिटल होंगी। अंत में, ये प्रस्ताव भविष्य को आकार देंगे, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अधिक प्रभावी बनाएंगे।

अध्याय 44:

साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और सूचना युद्ध से निपटने की तैयारी

साइबर सुरक्षा का राष्ट्रीय ढांचा

भारत की साइबर सुरक्षा नीति 2013 में शुरू हुई और इसमें कई संशोधन हो चुके हैं, जहां राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र दस लाख से अधिक साइबर घटनाओं की निगरानी करता है, मुख्य रूप से आतंकवादी हमलों से जुड़े। ढांचे में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम शामिल है, जो सालाना पांच लाख अलर्ट जारी करती है और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करती है, जैसे कि बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र जहां तीन लाख से अधिक हमले रोके गए। नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, जहां पांच सौ से अधिक कंपनियां सरकारी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं और साझा डेटा से खतरे की पहचान करती हैं। ढांचा बहु-एजेंसी मॉडल पर आधारित है, जहां गृह मंत्रालय दो हजार से अधिक विशेषज्ञों को निर्देशित करता है। विकास से साइबर हमलों में पंद्रह प्रतिशत कमी आई, जहां तीन सौ उनहत्तर मिलियन मालवेयर पहचान दर्ज हुए। कुल रूप से, ये तत्व राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को एकीकृत करते हैं, जो डिजिटल खतरे से मुकाबला करने की आधारभूत व्यवस्था हैं।

ढांचे का विकास 2020 की महामारी के बाद तेज हुआ, जहां राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र ने पचास से अधिक क्षेत्रों को कवर किया और बहतर प्रतिशत संगठनों ने जोखिम वृद्धि रिपोर्ट की। नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ा है, जहां स्वचालित खतरा पहचान सिस्टम चार लाख से अधिक फिशिंग प्रयासों को ब्लॉक करते हैं। विकास में राज्य स्तर के साइबर सेल शामिल हैं, जहां अट्वाइस राज्यों में एक हजार से अधिक इकाइयां तैनात हैं। ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाता है, जहां वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की सिफारिशों से नब्बे प्रतिशत अनुपालन हासिल हुआ। विकास से तैयारियां मजबूत हुईं, जहां चौबीस प्रतिशत संगठन हमलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अंत में, ये प्रगति साइबर ढांचे को गतिशील बनाती हैं, जो उभरते डिजिटल खतरे से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

डिजिटल निगरानी के उपकरण और प्रणालियां

डिजिटल निगरानी में केंद्रीकृत निगरानी सिस्टम प्रमुख है, जहां एक करोड़ से अधिक संचार लाइनों की निगरानी होती है, मुख्य रूप से आतंकवादी संदेशों को ट्रैक करने के लिए। उपकरणों में नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण उपकरण शामिल हैं, जो पांच पेटाबाइट डेटा प्रोसेस करते हैं और दो लाख संदिग्ध कॉल्स की जांच की। प्रणालियां सामाजिक मीडिया स्कैनर से जुड़ी हैं, जहां फेसबुक और ट्विटर पर तीन करोड़ पोस्ट्स सालाना स्कैन होते हैं। निगरानी में चेहरा पहचान सिस्टम का उपयोग है, जो पचास लाख चेहरों की डेटाबेस से मेल खाता है। उपकरणों से आतंकवादी साजिशें बीस प्रतिशत पहले पता लगती हैं, जहां एक सौ पचास घटनाएं रोकी गईं। कुल रूप से, ये सिस्टम डिजिटल क्षेत्र को कवर करते हैं, जो निगरानी को सटीक बनाते हैं। प्रणालियों में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क शामिल है, जहां दो करोड़ रिकॉर्ड्स संग्रहीत करता है और आतंकवादी प्रोफाइल्स से एक लाख मैच उत्पन्न करता है। उपकरणों में आवाज पहचान सॉफ्टवेयर है, जहां दस भाषाओं में काम करता है और पांच हजार कॉल्स से सबूत निकाले। निगरानी में जीपीएस ट्रैकर्स का योगदान है, जहां तीन लाख वाहनों पर लगे हैं और सीमा क्षेत्रों में गतिविधियां ट्रैक करते हैं। प्रणालियां क्लाउड-आधारित हैं, जहां एक टेराबाइट डेटा दैनिक प्रोसेस करती हैं। विकास से निगरानी दक्षता पैंतीस प्रतिशत बढ़ी, जहां चार सौ साइबर अलर्ट जारी हुए। अंत में, ये उपकरण डिजिटल निगरानी को बहुमुखी बनाते हैं, जो आतंकवाद विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सूचना युद्ध से निपटने की रणनीतियां

सूचना युद्ध की रणनीतियों में फर्जी समाचार काउंटर यूनिट प्रमुख है, जहां पांच लाख से अधिक गलत सूचनाओं को ब्लॉक किया गया, मुख्य रूप से आतंकवादी प्रचार से जुड़ी। रणनीतियों में मीडिया निगरानी केंद्र शामिल हैं, जो दस हजार चैनलों की निगरानी करता है और दो हजार फर्जी वीडियो हटाए। युद्ध से निपटने में सार्वजनिक जागरूकता अभियान हैं, जहां एक करोड़ लोगों तक पहुंचा गया। रणनीतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तथ्य जांच पर आधारित हैं, जहां नब्बे प्रतिशत सटीकता से झूठी खबरें पहचानती हैं। निपटने से प्रचार प्रभाव पच्चीस प्रतिशत कम हुआ, जहां तीन सौ अभियान चलाए गए। कुल रूप से, ये तरीके डिजिटल क्षेत्र डेटा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जो युद्ध की चुनौतियों से मुकाबला करते हैं। रणनीतियों में सामाजिक मीडिया

नियमन ढांचा है, जहां तीन करोड़ यूजर्स की पोस्ट्स स्कैन हुईं और एक लाख खाते निलंबित किए गए। युद्ध निपटने में क्रॉस-प्लेटफॉर्म समन्वय शामिल है, जहां गूगल और फेसबुक के साथ पांच सौ समझौते करता है। रणनीतियां सामग्री मॉडरेशन उपकरणों पर फोकस करती हैं, जो पांच भाषाओं में काम करते हैं और चार लाख पोस्ट्स हटाईं। निपटने में समुदाय रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो दो लाख शिकायतें सालाना प्रोसेस करता है। रणनीतियों से जनमत प्रभाव बीस प्रतिशत नियंत्रित हुआ, जहां एक सौ पचास कैंपेन सफल रहे। अंत में, ये विधियां सूचना युद्ध को कमजोर बनाती हैं, जो प्रचार के खिलाफ प्रभावी ढाल प्रदान करती हैं।

प्रमुख साइबर घटनाएं और प्रतिक्रियाएं

प्रमुख घटनाओं में रूसी साइबर हमला प्रमुख है, जहां यूक्रेन संबंधित चार हजार तीन सौ पंद्रह घटनाओं में भारत ने सत्तर प्रतिशत वृद्धि देखी, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना पर। प्रतिक्रियाओं में तत्काल पैचिंग शामिल है, जहां दो लाख सिस्टम अपडेट किए गए और तीन सौ हमले रोके गए। घटनाओं में आईएस से जुड़े एक हजार आठ सौ पांच मौतों वाले हमले हैं, जहां साइबर प्रचार पांच सौ से अधिक साइट्स पर फैला। प्रतिक्रियाएं ब्लॉकिंग से हुईं, जहां एक हजार डोमेन बंद किए गए। घटनाओं से सबक लेते हुए, चार लाख से अधिक सुरक्षा अलर्ट जारी हुए। कुल रूप से, ये मामले साइबर चुनौतियों को उजागर करते हैं, जो प्रतिक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं। प्रतिक्रियाओं में राष्ट्रीय साइबर घटना प्रतिक्रिया टीम की सक्रियता है, जहां तीन लाख से अधिक हमलों पर कार्रवाई हुई और पांच नब्बे प्रतिशत रिकवरी रेट हासिल हुआ। घटनाओं में चीनी हैकिंग प्रयास शामिल हैं, जहां दो हजार से अधिक सरकारी साइट्स प्रभावित हुईं। प्रतिक्रियाएं फायरवॉल उन्नयन से हुईं, जहां एक लाख डिवाइस सुरक्षित किए गए। घटनाओं से डेटा चोरी बीस प्रतिशत बढ़ी, जहां पांच सौ मिलियन रिकॉर्ड्स लीक हुए। प्रतिक्रियाएं बैकअप सिस्टम से हुईं, जो अस्सी प्रतिशत डेटा बहाल किया। अंत में, ये उदाहरण प्रतिक्रियाओं की दक्षता दिखाते हैं, जो साइबर घटनाओं से सीखते हैं।

उपलब्धियां और सांख्यिकीय आंकड़े

उपलब्धियों में साइबर हमलों में चार प्रतिशत कमी प्रमुख है, जहां तीन सौ उनहत्तर मिलियन मालवेयर पहचान से सत्तर प्रतिशत रोके गए, मुख्य रूप से आतंकवादी स्रोतों

से। आंकड़ों में फिशिंग हमलों में पचास प्रतिशत वृद्धि रिपोर्ट हुई, लेकिन चार लाख प्रयास ब्लॉक किए गए। उपलब्धियां साइबर तैयारियों में हैं, जहां चौबीस प्रतिशत संगठन पूरी तरह सक्षम हैं। आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर चार हजार तीन सौ पंद्रह घटनाओं की वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन अस्सी प्रतिशत प्रतिक्रिया समय एक घंटे से कम रहा। उपलब्धियां सूचना युद्ध में पांच लाख फर्जी समाचार ब्लॉक करने में हैं। कुल रूप से, ये परिणाम साइबर प्रयासों की सफलता दर्शाते हैं, जो डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। आंकड़ों में आतंकवादी मौतों में आईएस के एक हजार आठ सौ पांच मामले शामिल हैं, जहां साइबर निगरानी से बाईस देशों में पांच सौ साजिशें रोकी गईं। उपलब्धियां डिजिटल ट्रेकिंग में हैं, जहां दो लाख संदिग्धों की निगरानी से एक सौ पचास गिरफ्तारियां हुईं। आंकड़े सूचना युद्ध में बहत्तर प्रतिशत जोखिम वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन तीन लाख प्रचार सामग्री हटाई गई। उपलब्धियां राष्ट्रीय साइबर नीति से हैं, जहां नब्बे प्रतिशत अनुपालन हासिल हुआ। आंकड़े चार लाख से अधिक साइबर अलर्ट जारी होने में हैं। अंत में, ये सांख्यिकी उपलब्धियों को प्रमाणित करते हैं, जो तैयारी की प्रभावकारिता दिखाते हैं।

भविष्य की चुनौतियां और सुधार प्रस्ताव

भविष्य की चुनौतियों में साइबर जोखिमों में बहत्तर प्रतिशत वृद्धि प्रमुख है, जहां फिशिंग और फ्रॉड हमले सत्तर प्रतिशत बढ़े, लेकिन तैयारियां केवल चौबीस प्रतिशत संगठनों तक सीमित हैं। सुधार प्रस्तावों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण बढ़ाना शामिल है, जहां पांच लाख सिस्टम अपग्रेड से जोखिम तीस प्रतिशत कम होंगे। चुनौतियां राज्य-प्रायोजित हमलों से हैं, जहां भारत का साइबर कार्यक्रम जासूसी और काउंटरटेरिज्म पर केंद्रित है। भविष्य में ब्लॉकचेन सुरक्षा पर फोकस होगा, जहां एक लाख ट्रांजेक्शन सुरक्षित करेगा। सुधार से बजट तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ सकता है। कुल रूप से, ये मुद्दे साइबर क्षेत्र को जटिल बनाते हैं, जो नवीन सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। प्रस्तावों में अंतर-एजेंसी समन्वय मजबूत करना है, जहां बीस संयुक्त प्लेटफॉर्म बनेंगे और जांच समय चालीस प्रतिशत कम होगा। चुनौतियों में सूचना युद्ध में फर्जी समाचार का प्रसार शामिल है, जहां पांच लाख से अधिक मामले रिपोर्ट हुए। भविष्य में तथ्य-जांच सिस्टम विकसित होंगे, जो दस लाख पोस्ट्स दैनिक स्कैन करेंगे। सुधार में प्रशिक्षण बढ़ाना है, जहां पांच हजार विशेषज्ञ तैयार होंगे। चुनौतियां डेटा गोपनीयता से जुड़ी हैं, जहां तीस प्रतिशत नियम असंगत हैं। अंत में, ये प्रस्ताव साइबर तैयारी को मजबूत बनाते हैं, जो भविष्य के खतरे से मुकाबला करेंगे।

अध्याय 45:

साइबर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और सूचना युद्ध से निपटने की तैयारी

साइबर सुरक्षा का राष्ट्रीय ढांचा

भारत की साइबर सुरक्षा नीति 2013 में शुरू हुई और इसमें कई संशोधन हो चुके हैं, जहां राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र दस लाख से अधिक साइबर घटनाओं की निगरानी करता है, मुख्य रूप से आतंकवादी हमलों से जुड़े। ढांचे में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम शामिल है, जो सालाना पांच लाख अलर्ट जारी करती है और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करती है, जैसे कि बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र जहां तीन लाख से अधिक हमले रोके गए। नीति में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, जहां पांच सौ से अधिक कंपनियां सरकारी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं और साझा डेटा से खतरे की पहचान करती हैं। ढांचा बहु-एजेंसी मॉडल पर आधारित है, जहां गृह मंत्रालय दो हजार से अधिक विशेषज्ञों को निर्देशित करता है। विकास से साइबर हमलों में पंद्रह प्रतिशत कमी आई, जहां तीन सौ उनहत्तर मिलियन मालवेयर पहचान दर्ज हुए। कुल रूप से, ये तत्व राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को एकीकृत करते हैं, जो डिजिटल खतरे से मुकाबला करने की आधारभूत व्यवस्था हैं। ढांचे का विकास 2020 की महामारी के बाद तेज हुआ, जहां राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र ने पचास से अधिक क्षेत्रों को कवर किया और बहत्तर प्रतिशत संगठनों ने जोखिम वृद्धि रिपोर्ट की। नीति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बढ़ा है, जहां स्वचालित खतरा पहचान सिस्टम चार लाख से अधिक फिशिंग प्रयासों को ब्लॉक करते हैं। विकास में राज्य स्तर के साइबर सेल शामिल हैं, जहां अट्ठाईस राज्यों में एक हजार से अधिक इकाइयां तैनात हैं। ढांचा अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाता है, जहां वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की सिफारिशों से नब्बे प्रतिशत अनुपालन हासिल हुआ। विकास से तैयारियां मजबूत हुईं, जहां चौबीस प्रतिशत संगठन हमलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अंत में, ये प्रगति साइबर ढांचे को गतिशील बनाती हैं, जो उभरते डिजिटल खतरे से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

डिजिटल निगरानी के उपकरण और प्रणालियां डिजिटल निगरानी में केंद्रीकृत निगरानी सिस्टम प्रमुख है, जहां एक करोड़ से अधिक संचार लाइनों की निगरानी होती है, मुख्य रूप से आतंकवादी संदेशों को ट्रैक करने के लिए। उपकरणों में नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण उपकरण शामिल हैं, जो पांच पेटाबाइट डेटा प्रोसेस करते हैं और दो लाख संदिग्ध कॉल्स की जांच की। प्रणालियां सामाजिक मीडिया स्कैनर से जुड़ी हैं, जहां फेसबुक और ट्विटर पर तीन करोड़ पोस्ट्स सालाना स्कैन होते हैं। निगरानी में चेहरा पहचान सिस्टम का उपयोग है, जो पचास लाख चेहरों की डेटाबेस से मेल खाता है। उपकरणों से आतंकवादी साजिशें बीस प्रतिशत पहले पता लगीं, जहां एक सौ पचास घटनाएं रोकी गईं। कुल रूप से, ये सिस्टम डिजिटल क्षेत्र को कवर करते हैं, जो निगरानी को सटीक बनाते हैं। प्रणालियों में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क शामिल है, जहां दो करोड़ रिकॉर्ड्स संग्रहीत करता है और आतंकवादी प्रोफाइल्स से एक लाख मैच उत्पन्न करता है। उपकरणों में आवाज पहचान सॉफ्टवेयर है, जहां दस भाषाओं में काम करता है और पांच हजार कॉल्स से सबूत निकाले। निगरानी में जीपीएस ट्रैकर्स का योगदान है, जहां तीन लाख वाहनों पर लगे हैं और सीमा क्षेत्रों में गतिविधियां ट्रैक करते हैं। प्रणालियां क्लाउड-आधारित हैं, जहां एक टेराबाइट डेटा दैनिक प्रोसेस करती हैं। विकास से निगरानी दक्षता पैंतीस प्रतिशत बढ़ी, जहां चार सौ साइबर अलर्ट जारी हुए। अंत में, ये उपकरण डिजिटल निगरानी को बहुमुखी बनाते हैं, जो आतंकवाद विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सूचना युद्ध से निपटने की रणनीतियां

सूचना युद्ध की रणनीतियों में फर्जी समाचार काउंटर यूनिट प्रमुख है, जहां पांच लाख से अधिक गलत सूचनाओं को ब्लॉक किया गया, मुख्य रूप से आतंकवादी प्रचार से जुड़ी। रणनीतियों में मीडिया निगरानी केंद्र शामिल हैं, जो दस हजार चैनलों की निगरानी करता है और दो हजार फर्जी वीडियो हटाए। युद्ध से निपटने में सार्वजनिक जागरूकता अभियान हैं, जहां एक करोड़ लोगों तक पहुंचा गया। रणनीतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तथ्य जांच पर आधारित हैं, जहां नब्बे प्रतिशत सटीकता से झूठी खबरें पहचानती हैं। निपटने से प्रचार प्रभाव पच्चीस प्रतिशत कम हुआ, जहां तीन सौ अभियान चलाए गए। कुल रूप से, ये तरीके डिजिटल क्षेत्र डेटा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, जो युद्ध की चुनौतियों से मुकाबला करते हैं। रणनीतियों में सामाजिक मीडिया नियमन ढांचा है, जहां तीन करोड़ यूजर्स की पोस्ट्स स्कैन हुईं और एक लाख खाते

निलंबित किए गए। युद्ध निपटने में क्रॉस-प्लेटफॉर्म समन्वय शामिल है, जहां गूगल और फेसबुक के साथ पांच सौ समझौते करता है। रणनीतियां सामग्री मॉडरेशन उपकरणों पर फोकस करती हैं, जो पांच भाषाओं में काम करते हैं और चार लाख पोस्ट्स हटाईं। निपटने में समुदाय रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो दो लाख शिकायतें सालाना प्रोसेस करता है। रणनीतियों से जनमत प्रभाव बीस प्रतिशत नियंत्रित हुआ, जहां एक सौ पचास कैपेन सफल रहे। अंत में, ये विधियां सूचना युद्ध को कमजोर बनाती हैं, जो प्रचार के खिलाफ प्रभावी ढाल प्रदान करती हैं।

प्रमुख साइबर घटनाएं और प्रतिक्रियाएं

प्रमुख घटनाओं में रूसी साइबर हमला प्रमुख है, जहां यूक्रेन संबंधित चार हजार तीन सौ पंद्रह घटनाओं में भारत ने सत्तर प्रतिशत वृद्धि देखी, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना पर। प्रतिक्रियाओं में तत्काल पैचिंग शामिल है, जहां दो लाख सिस्टम अपडेट किए गए और तीन सौ हमले रोके गए। घटनाओं में आईएस से जुड़े एक हजार आठ सौ पांच मौतों वाले हमले हैं, जहां साइबर प्रचार पांच सौ से अधिक साइट्स पर फैला। प्रतिक्रियाएं ब्लॉकिंग से हुईं, जहां एक हजार डोमेन बंद किए गए। घटनाओं से सबक लेते हुए, चार लाख से अधिक सुरक्षा अलर्ट जारी हुए। कुल रूप से, ये मामले साइबर चुनौतियों को उजागर करते हैं, जो प्रतिक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं। प्रतिक्रियाओं में राष्ट्रीय साइबर घटना प्रतिक्रिया टीम की सक्रियता है, जहां तीन लाख से अधिक हमलों पर कार्रवाई हुई और पांच नब्बे प्रतिशत रिकवरी रेट हासिल हुआ। घटनाओं में चीनी हैकिंग प्रयास शामिल हैं, जहां दो हजार से अधिक सरकारी साइट्स प्रभावित हुईं। प्रतिक्रियाएं फायरवॉल उन्नयन से हुईं, जहां एक लाख डिवाइस सुरक्षित किए गए। घटनाओं से डेटा चोरी बीस प्रतिशत बढ़ी, जहां पांच सौ मिलियन रिकॉर्ड्स लीक हुए। प्रतिक्रियाएं बैकअप सिस्टम से हुईं, जो अस्सी प्रतिशत डेटा बहाल किया। अंत में, ये उदाहरण प्रतिक्रियाओं की दक्षता दिखाते हैं, जो साइबर घटनाओं से सीखते हैं।

उपलब्धियां और सांख्यिकीय आंकड़े

उपलब्धियों में साइबर हमलों में चार प्रतिशत कमी प्रमुख है, जहां तीन सौ उनहत्तर मिलियन मालवेयर पहचान से सत्तर प्रतिशत रोके गए, मुख्य रूप से आतंकवादी स्रोतों से। आंकड़ों में फिशिंग हमलों में पचास प्रतिशत वृद्धि रिपोर्ट हुई, लेकिन चार लाख

प्रयास ब्लॉक किए गए। उपलब्धियां साइबर तैयारियों में हैं, जहां चौबीस प्रतिशत संगठन पूरी तरह सक्षम हैं। आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर चार हजार तीन सौ पंद्रह घटनाओं की वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन अस्सी प्रतिशत प्रतिक्रिया समय एक घंटे से कम रहा। उपलब्धियां सूचना युद्ध में पांच लाख फर्जी समाचार ब्लॉक करने में हैं। कुल रूप से, ये परिणाम साइबर प्रयासों की सफलता दर्शाते हैं, जो डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। आंकड़ों में आतंकवादी मौतों में आईएस के एक हजार आठ सौ पांच मामले शामिल हैं, जहां साइबर निगरानी से बाईस देशों में पांच सौ साजिशें रोकी गईं। उपलब्धियां डिजिटल ट्रैकिंग में हैं, जहां दो लाख संदिग्धों की निगरानी से एक सौ पचास गिरफ्तारियां हुईं। आंकड़े सूचना युद्ध में बहतर प्रतिशत जोखिम वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन तीन लाख प्रचार सामग्री हटाई गई। उपलब्धियां राष्ट्रीय साइबर नीति से हैं, जहां नब्बे प्रतिशत अनुपालन हासिल हुआ। आंकड़े चार लाख से अधिक साइबर अलर्ट जारी होने में हैं। अंत में, ये सांख्यिकी उपलब्धियों को प्रमाणित करते हैं, जो तैयारी की प्रभावकारिता दिखाते हैं।

भविष्य की चुनौतियां और सुधार प्रस्ताव

भविष्य की चुनौतियों में साइबर जोखिमों में बहतर प्रतिशत वृद्धि प्रमुख है, जहां फिशिंग और फ्रॉड हमले सत्तर प्रतिशत बढ़े, लेकिन तैयारियां केवल चौबीस प्रतिशत संगठनों तक सीमित हैं। सुधार प्रस्तावों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एकीकरण बढ़ाना शामिल है, जहां पांच लाख सिस्टम अपग्रेड से जोखिम तीस प्रतिशत कम होंगे। चुनौतियां राज्य-प्रायोजित हमलों से हैं, जहां भारत का साइबर कार्यक्रम जासूसी और काउंटरटेरिज्म पर केंद्रित है। भविष्य में ब्लॉकचेन सुरक्षा पर फोकस होगा, जहां एक लाख ट्रांजेक्शन सुरक्षित करेगा। सुधार से बजट तीन हजार करोड़ रुपये बढ़ सकता है। कुल रूप से, ये मुद्दे साइबर क्षेत्र को जटिल बनाते हैं, जो नवीन सुधारों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। प्रस्तावों में अंतर-एजेंसी समन्वय मजबूत करना है, जहां बीस संयुक्त प्लेटफॉर्म बनेंगे और जांच समय चालीस प्रतिशत कम होगा। चुनौतियों में सूचना युद्ध में फर्जी समाचार का प्रसार शामिल है, जहां पांच लाख से अधिक मामले रिपोर्ट हुए। भविष्य में तथ्य-जांच सिस्टम विकसित होंगे, जो दस लाख पोस्ट्स दैनिक स्कैन करेंगे। सुधार में प्रशिक्षण बढ़ाना है, जहां पांच हजार विशेषज्ञ तैयार होंगे। चुनौतियां डेटा गोपनीयता से जुड़ी हैं, जहां तीस प्रतिशत नियम असंगत हैं। अंत में, ये प्रस्ताव साइबर तैयारी को मजबूत बनाते हैं, जो भविष्य के खतरे से मुकाबला करेंगे।

अध्याय 46:

स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जन-जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रम

स्थानीय समुदायों की भागीदारी के मॉडल

स्थानीय समुदायों की भागीदारी में ग्राम सभाओं का उपयोग प्रमुख है, जहां दो लाख से अधिक गांवों में आतंकवाद विरोधी मीटिंग्स आयोजित हुईं, मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पचास प्रतिशत समुदायों ने संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग की। इन मॉडलों में युवा क्लबों की भूमिका है, जहां एक करोड़ से ज्यादा युवा सदस्यों ने सतर्कता अभियान चलाए और पांच हजार से अधिक टिप्स पुलिस को दिए। भागीदारी शहरी क्षेत्रों में फैली, जहां अपार्टमेंट एसोसिएशनों ने तीन लाख से अधिक निगरानी समितियां बनाईं। मॉडल महिलाओं पर केंद्रित हैं, जहां चालीस प्रतिशत समितियां महिला-प्रधान हैं और घरेलू स्तर पर जागरूकता फैलाई। भागीदारी से रिपोर्टिंग दर तीस प्रतिशत बढ़ी, जहां दस हजार से अधिक घटनाएं रोकी गईं। कुल रूप से, ये मॉडल समुदायों को सक्रिय बनाते हैं, जो आधार स्तर पर सुरक्षा बढ़ाते हैं। मॉडलों का विकास 2020 के बाद तेज हुआ, जहां पंचायती राज संस्थाओं ने एक लाख से अधिक रिजॉल्यूशन पास किए और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। भागीदारी में धार्मिक नेताओं की भूमिका बढ़ी, जहां मस्जिद और मंदिर समितियों ने दो लाख से अधिक संयुक्त सभाएं आयोजित कीं। विकास में स्कूलों का योगदान है, जहां पांच लाख छात्रों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मॉडल आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हैं, जहां तीन हजार जनजातीय परिषदों ने सतर्कता नेटवर्क बनाए। विकास से समुदाय विश्वास पच्चीस प्रतिशत बढ़ा, जहां चार हजार से अधिक स्थानीय इनपुट्स से जांच हुई। अंत में, ये प्रगति भागीदारी को गहरा बनाती हैं, जो लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

जन-जागरूकता अभियानों की संरचना

जन-जागरूकता अभियानों में डिजिटल कैंपेन प्रमुख हैं, जहां सामाजिक मीडिया पर पांच करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचा गया, मुख्य रूप से युवाओं को लक्षित कर

जहां एक करोड़ वीडियो दृश्य से संदेश फैले। संरचना में रेडियो और टीवी स्पॉट शामिल हैं, जहां दस लाख से अधिक प्रसारण हुए और सत्तर प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया। अभियान स्कूल वर्कशॉप्स पर आधारित हैं, जहां दो लाख से अधिक सेशन आयोजित हुए और छात्रों को संकेत पहचानना सिखाया। संरचना में पोस्टर और बैनर ड्राइव है, जहां तीन करोड़ से अधिक सामग्री वितरित हुई। अभियानों से जागरूकता स्तर चालीस प्रतिशत बढ़ा, जहां आठ हजार से अधिक रिपोर्ट्स आईं। कुल रूप से, ये ढांचे जागरूकता को व्यापक बनाते हैं, जो रोकथाम में सहायक होते हैं। संरचना का विकास 2022 के बाद तेज हुआ, जहां मोबाइल ऐप्स ने एक करोड़ डाउनलोड्स हासिल किए और वास्तविक-समय अलर्ट प्रदान किए। अभियानों में थिएटर और नुककड़ नाटक शामिल हैं, जहां पांच लाख से अधिक प्रदर्शन हुए और स्थानीय भाषाओं में संदेश दिए। विकास में कॉर्पोरेट भागीदारी है, जहां पांच सौ कंपनियों ने दो करोड़ रुपये दान किए। संरचना बहुभाषी है, जहां बाईस भाषाओं में सामग्री तैयार हुई। विकास से प्रभाव पैतीस प्रतिशत बढ़ा, जहां छह हजार से अधिक स्थानीय इवेंट्स सफल रहे। अंत में, ये प्रगति अभियानों को प्रभावी बनाती हैं, जो जनमानस में बदलाव लाती हैं।

पुनर्वास कार्यक्रमों की रूपरेखा

पुनर्वास कार्यक्रमों में आत्मसमर्पित उग्रवादियों के लिए कौशल ट्रेनिंग प्रमुख है, जहां दस हजार से अधिक पूर्व सदस्यों को रोजगार दिया गया, मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में जहां साठ प्रतिशत सफलतापूर्वक मुख्यधारा में लौटे। रूपरेखा में मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग शामिल है, जहां पांच लाख सेशन हुए और तनाव प्रबंधन सिखाया। कार्यक्रम परिवार पुनर्मिलन पर केंद्रित हैं, जहां दो हजार से अधिक परिवारों को सहायता मिली। रूपरेखा में आर्थिक पैकेज है, जहां एक लाख से अधिक लाभार्थियों को पांच हजार करोड़ रुपये दिए गए। कार्यक्रमों से पुनर्वास दर पचास प्रतिशत बढ़ी, जहां तीन हजार समर्पण हुए। कुल रूप से, ये ढांचे पूर्व आतंकवादियों को नया जीवन देते हैं, जो समाज में एकीकरण सुनिश्चित करते हैं। रूपरेखा का विकास 2019 के बाद तेज हुआ, जहां विशेष केंद्रों ने एक लाख से अधिक लोगों को कवर किया और व्यावसायिक कोर्स प्रदान किए। कार्यक्रमों में कम्युनिटी रिहैब केंद्र शामिल हैं, जहां तीन हजार से अधिक सुविधाएं सक्रिय हैं और स्थानीय सहयोग से चलती हैं। विकास में शिक्षा ग्रांट्स हैं, जहां चार हजार बच्चों को छात्रवृत्ति मिली। रूपरेखा स्वास्थ्य

देखभाल पर फोकस करती है, जहां दो लाख से अधिक मेडिकल चेकअप्स हुए। विकास से सफलता पैतालीस प्रतिशत बढ़ी, जहां चार हजार पूर्व सदस्यों ने व्यवसाय शुरू किए। अंत में, ये प्रगति पुनर्वास को व्यावहारिक बनाती हैं, जो दीर्घकालिक शांति में योगदान देती हैं।

भागीदारी और जागरूकता के प्रभाव

भागीदारी के प्रभाव में स्थानीय रिपोर्टिंग का बढ़ता स्तर प्रमुख है, जहां पंद्रह हजार से अधिक टिप्स से पांच हजार जांचें शुरू हुईं, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जहां सत्तर प्रतिशत समुदाय सक्रिय हुए। जागरूकता से अपराध दर बीस प्रतिशत घटी, जहां शहरी इलाकों में तीन लाख से अधिक लोग जागरूक हुए। प्रभाव में विश्वास निर्माण है, जहां पुलिस-समुदाय मीटिंग्स से चालीस प्रतिशत बेहतर संबंध बने। भागीदारी से साजिशें पच्चीस प्रतिशत पहले रोकी गईं, जहां दो हजार घटनाएं टलीं। जागरूकता से युवा रेडिकलाइजेशन तीस प्रतिशत कम हुआ, जहां एक करोड़ से अधिक संदेश फैले। कुल रूप से, ये प्रभाव समुदायों को मजबूत बनाते हैं, जो आतंकवाद विरोध में सहायक होते हैं। जागरूकता के प्रभाव में मीडिया कवरेज का योगदान है, जहां पांच हजार से अधिक कहानियों से दो करोड़ लोगों तक पहुंचा। भागीदारी से आर्थिक लाभ हुआ, जहां पुनर्वास से एक हजार से अधिक व्यवसाय शुरू हुए। प्रभाव में सामाजिक एकता बढ़ी, जहां बहु-धार्मिक इवेंट्स से चार लाख लोग जुड़े। जागरूकता से रिपोर्टिंग पैतीस प्रतिशत बढ़ी, जहां छह हजार स्थानीय इनपुट्स आए। भागीदारी से महिलाओं की भूमिका पच्चीस प्रतिशत बढ़ी, जहां तीन लाख से अधिक महिलाएं सक्रिय हुईं। अंत में, ये परिणाम प्रभाव को मापने योग्य बनाते हैं, जो कार्यक्रमों की सफलता दिखाते हैं।

पुनर्वास कार्यक्रमों की चुनौतियां

पुनर्वास की चुनौतियों में पूर्व सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार प्रमुख है, जहां चालीस प्रतिशत लाभार्थियों ने अस्वीकृति रिपोर्ट की, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दो हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। चुनौतियां फंडिंग की कमी से हैं, जहां पांच हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले तीन हजार करोड़ उपलब्ध हुए। कार्यक्रमों में ट्रस्ट की कमी है, जहां तीस प्रतिशत समर्पित सदस्य दोबारा जुड़ गए। चुनौतियां मनोवैज्ञानिक समर्थन की कमी से बढ़ती हैं, जहां एक लाख से अधिक केस अनसुलझे रहे। पुनर्वास से पुनरावृत्ति दर बीस प्रतिशत रही, जहां पांच सौ मामले दोहराए गए।

कुल रूप से, ये मुद्दे कार्यक्रमों को जटिल बनाते हैं, जो सुधार की मांग करते हैं। चुनौतियों में स्थानीय विरोध शामिल है, जहां तीन हजार से अधिक प्रदर्शन पुनर्वास केंद्रों के खिलाफ हुए। कार्यक्रमों में संसाधन वितरण की असमानता है, जहां पूर्वोत्तर राज्यों में पचास प्रतिशत कम फंड पहुंचा। चुनौतियां नौकरी अवसरों की कमी से हैं, जहां चार हजार प्रशिक्षित सदस्य बेरोजगार रहे। पुनर्वास में परिवार समर्थन की कमी है, जहां दो लाख से अधिक परिवार प्रभावित हुए। चुनौतियां मॉनिटरिंग की कमी से बढ़ती हैं, जहां पच्चीस प्रतिशत मामलों में फॉलो-अप नहीं हुआ। अंत में, ये अवरोध पुनर्वास की राह में रुकावटें हैं, जो निरंतर ध्यान मांगते हैं।

भविष्य की दिशा और सुधार सुझाव भविष्य की दिशा में डिजिटल प्लेटफार्मों का विस्तार प्रमुख है, जहां दो करोड़ से अधिक लोगों तक ऑनलाइन जागरूकता पहुंचेगी और आभासी मीटिंग्स से भागीदारी बढ़ेगी। सुधार सुझावों में फंडिंग बढ़ाना शामिल है, जहां सात हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य पुनर्वास के लिए रखा जाएगा। दिशाएं युवा केंद्रित होंगी, जहां पांच लाख से अधिक क्लब बनेंगे। भविष्य में मनोवैज्ञानिक सपोर्ट नेटवर्क विस्तार होगा, जहां तीन लाख सेशन सालाना होंगे। सुधार से सफलता दर साठ प्रतिशत पहुंच सकती है, जहां पांच हजार समर्पण लक्षित हैं। कुल रूप से, ये दिशाएं कार्यक्रमों को मजबूत बनाएंगी, जो लंबे समय तक प्रभाव डालेंगी। सुझावों में समुदाय संवाद बढ़ाना है, जहां एक लाख से अधिक मीटिंग्स से विश्वास निर्माण होगा। भविष्य की योजनाओं में शिक्षा एकीकरण शामिल है, जहां स्कूल पाठ्यक्रम में जागरूकता मॉड्यूल जोड़े जाएंगे। दिशाएं आर्थिक प्रोत्साहन पर हैं, जहां दो लाख लाभार्थियों को ऋण मिलेंगे। सुधार में मॉनिटरिंग ऐप्स का उपयोग है, जहां चार लाख यूजर्स ट्रेकिंग करेंगे। योजनाएं महिला-केंद्रित होंगी, जहां पचास प्रतिशत संसाधन महिलाओं के लिए होंगे। अंत में, ये प्रस्ताव भविष्य को आकार देंगे, जो चुनौतियों को कम करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय 47:

आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध और सदस्यता पर नियंत्रण

प्रतिबंध की प्रक्रिया और कानूनी सुधार

भारत में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 पर आधारित है, जहां गृह मंत्रालय सबूतों की समीक्षा के बाद संगठन को अवैध घोषित करता है और पैतालीस संगठनों पर यह लागू हो चुका है, मुख्य रूप से उन पर जो हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। प्रक्रिया में खुफिया रिपोर्ट्स और जांच निष्कर्ष शामिल होते हैं, जहां विशेष ट्रिब्यूनल तीस दिनों में अपील सुनता है और बीस से अधिक अपीलों को अस्वीकार किया गया। कानूनी आधार में संगठन की संपत्ति जब्ती और फंडिंग रोकने के प्रावधान हैं, जहां पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज की गई। प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए वार्षिक समीक्षा होती है, जहां दस प्रतिशत मामलों में संशोधन हुए। आधार में अंतरराष्ट्रीय दबाव भी शामिल है, जहां संयुक्त राष्ट्र सूची से पंद्रह संगठन प्रभावित हुए। कुल रूप से, ये कदम संगठनों को कमजोर बनाते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। कानूनी आधार का विकास 2008 के मुंबई हमलों के बाद तेज हुआ, जहां अधिनियम में संशोधन से सदस्यता मात्र से दस वर्ष की सजा का प्रावधान जोड़ा गया और तीन हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। प्रक्रिया में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका बढ़ी, जहां पांच सौ से अधिक जांचों से सबूत संग्रहीत हुए। विकास में डिजिटल ट्रैकिंग शामिल है, जहां सामाजिक मीडिया गतिविधियों से दो हजार से अधिक संगठन संबंधी पोस्ट ब्लॉक की गई। आधार में वित्तीय नियंत्रण है, जहां बैंक खातों को फ्रीज करने से चार हजार करोड़ रुपये रोके गए। प्रक्रिया से संगठनों की भर्ती पच्चीस प्रतिशत घटी, जहां एक हजार से कम नए सदस्य जुड़े। अंत में, ये बदलाव कानूनी ढांचे को मजबूत बनाते हैं, जो प्रतिबंध की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं।

प्रमुख प्रतिबंधित संगठन

प्रतिबंधित संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख है, जहां दो हजार से अधिक सदस्य गिरफ्तार हुए और मुंबई हमलों से जुड़े पांच सौ करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं, मुख्य रूप से पाकिस्तान आधारित गतिविधियों से। संगठनों में जैश-ए-मोहम्मद शामिल है, जहां पुलवामा हमले के बाद एक हजार से अधिक मामले दर्ज हुए और तीन सौ से ज्यादा स्लीपर सेल निष्क्रिय किए गए। प्रमुख में भारतीय मुजाहिदीन है, जहां शहरी हमलों से जुड़े चार सौ सदस्यों को सजा मिली। संगठनों में बम्बर खालसा अंतरराष्ट्रीय है, जहां खालिस्तान आंदोलन से पांच सौ करोड़ रुपये की फंडिंग रोक दी गई। प्रतिबंध से इनकी गतिविधियां चालीस प्रतिशत घटीं, जहां दो सौ से कम घटनाएं दर्ज हुईं। कुल रूप से, ये संगठन राष्ट्रीय खतरे हैं, जो प्रतिबंध से नियंत्रित हो रहे हैं। प्रतिबंधित में हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख है, जहां कश्मीर घाटी में तीन हजार से अधिक सदस्यों पर कार्रवाई हुई और एक हजार से ज्यादा हथियार जब्त किए गए। संगठनों में छात्र इस्लामी आंदोलन भारत शामिल है, जहां छात्र भर्ती से जुड़े दो हजार मामले दर्ज हुए और चार सौ से अधिक मदरसे बंद किए गए। प्रमुख में सीपीआई माओवादी है, जहां नक्सल क्षेत्रों में पांच हजार सदस्यों का समर्पण हुआ। संगठनों में आईएसआईएस खुरासान है, जहां ऑनलाइन प्रचार से एक हजार से अधिक युवा प्रभावित हुए। प्रतिबंध से भर्ती पैंतीस प्रतिशत कम हुई, जहां एक सौ पचास से कम नए मामले आए। अंत में, ये संगठन विविध खतरे पैदा करते हैं, जो प्रतिबंध से कमजोर हो रहे हैं।

सदस्यता नियंत्रण के तरीके

सदस्यता नियंत्रण में ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रमुख है, जहां पांच लाख से अधिक सामाजिक मीडिया खाते स्कैन हुए और दो हजार से ज्यादा भर्ती प्रयास रोक दिए गए, मुख्य रूप से युवाओं को लक्षित कर। तरीकों में खुफिया नेटवर्क शामिल हैं, जहां एक लाख से अधिक मुखबिरो से सूचनाएं एकत्र होती हैं और तीन हजार संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। नियंत्रण में शिक्षा अभियान हैं, जहां स्कूलों में चार लाख छात्रों को रेडिकलाइजेशन रोकने के पाठ सिखाए गए। ये तरीके वित्तीय ट्रेकिंग से जुड़े हैं, जहां एक हजार करोड़ रुपये की सहायता रोक दी गई। नियंत्रण से सदस्यता दर पच्चीस प्रतिशत घटी, जहां पांच सौ से कम नए सदस्य जुड़े। कुल रूप से, ये विधियां भर्ती को रोकती हैं, जो संगठनों को कमजोर बनाती हैं। नियंत्रण के तरीकों में पुनर्वास केंद्र प्रमुख हैं, जहां दो हजार पूर्व सदस्यों को कौशल ट्रेनिंग दी गई और सत्तर प्रतिशत मुख्यधारा

में लौटे। तरीकों में सीमा निगरानी शामिल है, जहां तीन हजार से अधिक घुसपैठ प्रयास रोके गए और विदेशी सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत कम हुई। नियंत्रण में कानूनी कार्रवाई है, जहां सदस्यता से जुड़े चार हजार मामलों में सजा दी गई। तरीकों में समुदाय सतर्कता है, जहां तीन हजार से अधिक गांवों में रिपोर्टिंग सिस्टम बने। नियंत्रण से संगठन शक्ति पैंतीस प्रतिशत घटी, जहां दो सौ से कम सक्रिय सदस्य बचे। अंत में, ये उपाय सदस्यता को सीमित करते हैं, जो आतंकवाद की जड़ें काटते हैं।

प्रवर्तन और कार्रवाई के उदाहरण प्रवर्तन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई प्रमुख है, जहां पांच हजार से अधिक छापे मारे गए और दो हजार संगठन सदस्य गिरफ्तार हुए, मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई में। कार्रवाई के उदाहरण में पुलवामा हमले के बाद एक हजार से अधिक जांचें शामिल हैं, जहां जैश-ए-मोहम्मद के तीन सौ सदस्यों पर आरोप तय हुए। प्रवर्तन में संपत्ति जब्ती है, जहां चार हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की गईं। उदाहरण में छात्र इस्लामी आंदोलन भारत पर छापे हैं, जहां पांच सौ मदरसे बंद किए गए। कार्रवाई से संगठन गतिविधियां पैंतालीस प्रतिशत कम हुईं, जहां एक सौ पचास से कम हमले हुए। कुल रूप से, ये उदाहरण प्रवर्तन की ताकत दिखाते हैं, जो संगठनों को दबाते हैं। कार्रवाई में विशेष अदालतों का उपयोग प्रमुख है, जहां तीन हजार मामलों की सुनवाई हुई और एक हजार दोषसिद्धियां दर्ज हुईं। उदाहरण में लश्कर-ए-तैयबा पर अभियान हैं, जहां चार सौ सदस्यों को सजा मिली और दो हजार करोड़ रुपये जब्त हुए। प्रवर्तन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, जहां दो सौ प्रत्यर्पण सफल हुए। उदाहरण में माओवादी संगठनों पर अभियान हैं, जहां पांच हजार सदस्यों का समर्पण हुआ। कार्रवाई से हिंसा चालीस प्रतिशत घटी, जहां एक सौ से कम मौतें हुईं। अंत में, ये मामले कार्रवाई की विविधता दिखाते हैं, जो नियंत्रण को प्रभावी बनाते हैं।

उपलब्धियां और आंकड़े

उपलब्धियों में संगठनों की संख्या में कमी प्रमुख है, जहां पैंतालीस संगठनों पर प्रतिबंध से उनकी सक्रियता पचास प्रतिशत घटी, मुख्य रूप से कश्मीर में जहां तीन सौ से कम घटनाएं दर्ज हुईं। आंकड़ों में सदस्यता में चालीस प्रतिशत गिरावट शामिल है, जहां पांच हजार से अधिक सदस्यों ने समर्पण किया। उपलब्धियां संपत्ति जब्ती में हैं, जहां छह हजार करोड़ रुपये फ्रीज हुए। आंकड़े हमलों में पैंतीस प्रतिशत कमी दिखाते हैं, जहां दो सौ से कम आतंकवादी घटनाएं हुईं। उपलब्धियां भर्ती रोकने में हैं, जहां चार हजार युवाओं को मुख्यधारा में लाया गया। कुल रूप से, ये परिणाम उपलब्धियों को

मापते हैं, जो प्रतिबंध की सफलता दिखाते हैं। आंकड़ों में गिरफ्तारियों में वृद्धि है, जहां दस हजार से अधिक सदस्य पकड़े गए और तीन हजार दोषसिद्धियां हुईं। उपलब्धियां फंडिंग रोकने में हैं, जहां चार हजार करोड़ रुपये की सहायता ब्लॉक की गई। आंकड़े संगठन शक्ति में पैतालीस प्रतिशत कमी दिखाते हैं, जहां एक हजार से कम सक्रिय सेल बचे। उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय सूचियों में हैं, जहां बीस संगठन वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित हुए। आंकड़े हिंसा में पच्चीस प्रतिशत गिरावट में हैं, जहां एक सौ पचास से कम मौतें दर्ज हुईं। अंत में, ये सांख्यिकी उपलब्धियों को प्रमाणित करते हैं, जो नियंत्रण की प्रभावकारिता दर्शाते हैं।

चुनौतियां और भविष्य के सुधार

चुनौतियों में संगठनों का पुनर्गठन प्रमुख है, जहां बीस प्रतिशत प्रतिबंधित गुट नए नामों से उभरे, मुख्य रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों से जहां दो हजार से अधिक नए खाते बने। सुधार सुझावों में कानूनी संशोधन शामिल है, जहां सदस्यता सजा को पंद्रह वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। चुनौतियां प्रवर्तन संसाधनों की कमी से हैं, जहां तीन हजार से अधिक लंबित मामले हैं। भविष्य में डिजिटल ट्रेकिंग बढ़ेगी, जहां पांच लाख खाते की निगरानी होगी। सुधार से प्रभाव चालीस प्रतिशत बढ़ सकता है, जहां दस नए प्रतिबंध लक्षित हैं। कुल रूप से, ये मुद्दे प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं, जो नवीन उपायों की मांग करते हैं। सुझावों में जांच एजेंसियों का विस्तार है, जहां दो हजार अतिरिक्त अधिकारी भर्ती होंगे और जांच समय पचास प्रतिशत कम होगा। चुनौतियों में अंतरराष्ट्रीय दबाव का अभाव शामिल है, जहां पंद्रह प्रतिशत संगठन विदेशी समर्थन से सक्रिय हैं। भविष्य में पुनर्वास एकीकरण होगा, जहां चार हजार पूर्व सदस्यों को रोजगार मिलेगा। सुधार में जन भागीदारी बढ़ाना है, जहां एक लाख समितियां बनेंगी। चुनौतियां कानूनी अपीलों से बढ़ती हैं, जहां पच्चीस प्रतिशत मामलों में छूट मिली। अंत में, ये प्रस्ताव भविष्य को मजबूत बनाते हैं, जो चुनौतियों को कम करने का प्रयास करते हैं।

अध्याय 48:

सैन्य प्रतिउत्तर और सीमा-पार सर्जिकल/एयर स्ट्राइक ऑपरेशन

सर्जिकल स्ट्राइक की अवधारणा और इतिहास

सर्जिकल स्ट्राइक की अवधारणा सीमित, सटीक और लक्षित हमलों पर आधारित है, जहां भारतीय सेना ने 2016 में उरी हमले के जवाब में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सात लॉन्च पैड्स को नष्ट किया, जिससे अड़तीस से अधिक आतंकवादी मारे गए और दो भारतीय जवान शहीद हुए। इतिहास में यह रणनीति 1965 के भारत-पाक युद्ध से विकसित हुई, लेकिन आधुनिक रूप 2016 में सामने आया जब ग्यारह दिन की योजना से पांच सौ से अधिक कमांडो ने तीन किलोमीटर अंदर घुसकर ऑपरेशन पूरा किया। अवधारणा में गोपनीयता और न्यूनतम नागरिक हानि पर जोर है, जहां ऐसे पांच प्रमुख ऑपरेशन दर्ज हुए और कुल दो सौ से अधिक आतंकवादी निष्क्रिय किए गए। इतिहास में म्यांमार सीमा पर 2015 का ऑपरेशन शामिल है, जहां राष्ट्रीय समाजवादी परिषद नागालैंड-खापलांग के शिविरों पर हमला कर अड़तीस उग्रवादी मारे गए। अवधारणा से सीमा पार खतरे पच्चीस प्रतिशत कम हुए, जहां एक सौ से कम घुसपैठ प्रयास सफल रहे। कुल रूप से, ये हमले प्रतिउत्तर की नीति को मजबूत बनाते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हैं। इतिहास का विकास 2019 के पुलवामा हमले के बाद तेज हुआ, जहां बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति परिष्कृत हुई और तीन सौ कमांडो ने प्रशिक्षण लिया। अवधारणा में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग बढ़ा, जहां पचास से अधिक मिशनों में इनकी भूमिका साठ प्रतिशत रही। विकास में अंतर-सेवा समन्वय है, जहां सेना, वायुसेना और नौसेना ने दो सौ से अधिक संयुक्त अभ्यास किए। इतिहास में पूर्वोत्तर राज्यों के ऑपरेशन शामिल हैं, जहां पंद्रह उग्रवादी शिविर नष्ट किए गए। विकास से ऑपरेशनल सफलता चालीस प्रतिशत बढ़ी, जहां अस्सी से अधिक लक्ष्य सटीकता से हिट हुए। अंत में, ये प्रगति सर्जिकल स्ट्राइक को आधुनिक बनाती हैं, जो सीमा सुरक्षा में नई ऊर्जा लाती हैं।

प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन

प्रमुख ऑपरेशन में 2016 का उरी सर्जिकल स्ट्राइक प्रमुख है, जहां उन्नीस भारतीय सैनिकों की शहादत के जवाब में चार घंटे के मिशन से चार लॉन्च पैड्स ध्वस्त किए गए और पैतालीस आतंकवादी मारे गए, मुख्य रूप से नियंत्रण रेखा पार कर। ऑपरेशन में पैराट्रूपर्स की भूमिका थी, जहां सत्तर कमांडो ने ग्रेनेड और मशीन गन्स से हमला किया। सर्जिकल स्ट्राइक में 2015 का म्यांमार ऑपरेशन शामिल है, जहां राष्ट्रीय समाजवादी परिषद नागालैंड-खापलांग के दो शिविरों पर हमला कर अड़तीस उग्रवादी निष्क्रिय किए गए। प्रमुख में कश्मीर ऑपरेशन है, जहां बीस आतंकवादी मारे गए और पांच शिविर नष्ट हुए। ऑपरेशन से घुसपैठ प्रयास पैंतीस प्रतिशत कम हुए, जहां एक सौ पचास से कम मामले दर्ज हुए। कुल रूप से, ये मिशन प्रतिउत्तर की क्षमता दिखाते हैं, जो दुश्मन को चेतावनी देते हैं। ऑपरेशन का विस्तार 2019 के बाद हुआ, जहां बालाकोट से पहले तीन सर्जिकल स्ट्राइक हुए और कुल एक सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए। प्रमुख में पूर्वोत्तर का ऑपरेशन है, जहां एकीकृत मुक्ति मोर्चा असम शिविरों पर हमला कर पच्चीस उग्रवादी पकड़े गए। विस्तार में वायु समर्थन शामिल है, जहां तीस जेट्स ने कवर प्रदान किया। ऑपरेशन में लद्दाख क्षेत्र का मिशन है, जहां चीनी सीमा पर दस संदिग्ध पोस्ट नष्ट किए गए। विस्तार से सफलता पैतालीस प्रतिशत बढ़ी, जहां नब्बे से अधिक लक्ष्य हासिल हुए। अंत में, ये उदाहरण ऑपरेशनों की विविधता दिखाते हैं, जो रणनीतिक गहराई लाते हैं।

एयर स्ट्राइक की रणनीति और तकनीक

एयर स्ट्राइक की रणनीति में सटीक बॉम्बिंग प्रमुख है, जहां 2019 बालाकोट ऑपरेशन में मिराज दो हजार जेट्स ने एक हजार किलोग्राम के बम गिराए और जैश-ए-मोहम्मद के तीन शिविर नष्ट किए, जिससे तीन सौ से अधिक आतंकवादी प्रभावित हुए। तकनीक में लेजर-निर्देशित मिसाइलें शामिल हैं, जहां दो सौ से अधिक मिशनों में इनकी सटीकता पांच नब्बे प्रतिशत रही। रणनीति में ड्रोन सर्विलांस है, जहां पांच सौ से अधिक मानवरहित हवाई वाहन ने लक्ष्य पहचाने। तकनीक में उपग्रह इमेजरी का उपयोग है, जहां दस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्कैन हुआ। रणनीति से हवाई हमलों की सफलता पचास प्रतिशत बढ़ी, जहां एक सौ से कम मिशन असफल रहे। कुल रूप से, ये तरीके एयर स्ट्राइक को प्रभावी बनाते हैं, जो दुश्मन आधारों को निशाना बनाते हैं। रणनीति का विकास 2020 के बाद तेज हुआ, जहां राफेल जेट्स

के शामिल होने से तीस प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। तकनीक में इंफ्रारेड ट्रेकिंग शामिल है, जहां रात के मिशनों में अस्सी प्रतिशत सफलता मिली। विकास में संयुक्त कमांड है, जहां वायुसेना और सेना ने एक सौ पचास अभ्यास किए। रणनीति में मिसाइल रक्षा बायपास है, जहां नब्बे प्रतिशत लक्ष्य हिट हुए। विकास से लागत तीस प्रतिशत कम हुई, जहां पांच सौ करोड़ रुपये खर्च हुए। अंत में, ये प्रगति रणनीति को उन्नत बनाती हैं, जो हवाई प्रतिउत्तर में नई क्षमता लाती हैं।

प्रतिउत्तर ऑपरेशनों के प्रभाव

प्रतिउत्तर के प्रभाव में आतंकवादी हमलों में कमी प्रमुख है, जहां 2016 स्ट्राइक के बाद चालीस प्रतिशत घटनाएं घटीं और कुल पांच सौ से कम हमले दर्ज हुए, मुख्य रूप से सीमा क्षेत्रों में। प्रभाव में दुश्मन मनोबल का हास है, जहां पाकिस्तान आधारित गुटों की भर्ती पैंतीस प्रतिशत कम हुई। ऑपरेशनों से राष्ट्रीय एकता बढ़ी, जहां अस्सी प्रतिशत जनता ने समर्थन दिया। प्रभाव में आर्थिक नुकसान रोकना है, जहां तीन हजार करोड़ रुपये की क्षति टली। प्रतिउत्तर से घुसपैठ पैंतालीस प्रतिशत घटी, जहां दो सौ से कम प्रयास सफल रहे। कुल रूप से, ये परिणाम ऑपरेशनों की उपयोगिता दिखाते हैं, जो दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑपरेशनों के प्रभाव में अंतरराष्ट्रीय मान्यता शामिल है, जहां पचास देशों ने भारत के कदमों का समर्थन किया और वैश्विक आतंकवाद चर्चा में तीस प्रतिशत योगदान बढ़ा। प्रभाव में सैन्य तैयारियां मजबूत हुईं, जहां एक लाख से अधिक सैनिकों को विशेष ट्रेनिंग मिली। ऑपरेशनों से खुफिया क्षमता पच्चीस प्रतिशत बढ़ी, जहां चार हजार से अधिक टिप्स एकत्र हुए। प्रभाव में नागरिक हानि न्यूनतम रही, जहां पांच नब्बे प्रतिशत मिशन बिना संपार्श्विक क्षति के पूरे हुए। ऑपरेशनों से मनोवैज्ञानिक लाभ हुआ, जहां दुश्मन गुटों की सक्रियता बीस प्रतिशत कम हुई। अंत में, ये प्रभाव प्रतिउत्तर की रणनीतिक महत्वपूर्णता दर्शाते हैं, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं।

ऑपरेशनों की चुनौतियां

ऑपरेशनों की चुनौतियों में मौसम संबंधी बाधाएं प्रमुख हैं, जहां तीस प्रतिशत मिशन बर्फबारी और बारिश से प्रभावित हुए, मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में जहां पचास से अधिक ऑपरेशन स्थगित हुए। चुनौतियां दुश्मन प्रतिरोध से हैं, जहां पाकिस्तान की वायु रक्षा से बीस प्रतिशत जोखिम बढ़ा। ऑपरेशनों में खुफिया सटीकता की कमी है,

जहां पंद्रह प्रतिशत मामलों में लक्ष्य चूक गए। चुनौतियां राजनीतिक दबाव से बढ़ती हैं, जहां दस प्रतिशत ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय आलोचना से रुके। ऑपरेशनों से मानव हानि का जोखिम है, जहां चालीस से अधिक सैनिक शहीद हुए। कुल रूप से, ये मुद्दे ऑपरेशनों को जोखिमपूर्ण बनाते हैं, जो सावधानी की मांग करते हैं। चुनौतियों में तकनीकी विफलता शामिल है, जहां पच्चीस प्रतिशत ड्रोन मिशन असफल रहे और एक सौ से अधिक यूनिट्स खोए गए। ऑपरेशनों में संचार ब्रेकडाउन है, जहां पैंतीस प्रतिशत मामलों में सिग्नल जैमिंग से समस्या हुई। चुनौतियां बजट सीमाओं से हैं, जहां दो हजार करोड़ रुपये की कमी से उपकरण अपडेट रुके। ऑपरेशनों में नागरिक सुरक्षा का मुद्दा है, जहां बीस प्रतिशत मिशन विवादास्पद रहे। चुनौतियां पोस्ट-ऑपरेशन प्रबंधन से बढ़ती हैं, जहां पंद्रह प्रतिशत मामलों में मीडिया लीक हुए। अंत में, ये अवरोध ऑपरेशनों की राह में रुकावटें हैं, जो निरंतर सुधार मांगते हैं।

भविष्य की रणनीतियां और सुधार

भविष्य की रणनीतियों में ड्रोन-आधारित स्ट्राइक का विस्तार प्रमुख है, जहां पांच सौ से अधिक मानवरहित हवाई वाहन तैनात होंगे और लक्ष्य सटीकता अट्ठानबे प्रतिशत पहुंचेगी। सुधार सुझावों में खुफिया एकीकरण बढ़ाना शामिल है, जहां एक लाख से अधिक स्रोतों से डेटा संग्रहीत होगा। रणनीतियां हाइब्रिड युद्ध पर फोकस करेंगी, जहां साइबर और एयर स्ट्राइक का संयोजन होगा। भविष्य में प्रशिक्षण सिमुलेटर बढ़ेंगे, जहां दो लाख सैनिकों को आभासी ट्रेनिंग मिलेगी। सुधार से जोखिम चालीस प्रतिशत कम हो सकता है, जहां पचास नए ऑपरेशन लक्षित हैं। कुल रूप से, ये दिशाएं रणनीतियों को नवीन बनाएंगी, जो चुनौतियों से निपटेंगी। सुझावों में अंतर-सेवा समन्वय मजबूत करना है, जहां तीन सौ संयुक्त अभ्यास होंगे और दक्षता पैंतीस प्रतिशत बढ़ेगी। भविष्य की योजनाओं में लेजर हथियार शामिल हैं, जहां एक सौ से अधिक यूनिट्स तैनात होंगी। रणनीतियां नागरिक सुरक्षा पर जोर देंगी, जहां नब्बे प्रतिशत मिशन बिना हानि के होंगे। सुधार में बजट वृद्धि है, जहां तीन हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटित होंगे। रणनीतियां वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होंगी, जहां बीस देशों के साथ समझौते होंगे। अंत में, ये प्रस्ताव भविष्य को मजबूत बनाते हैं, जो प्रतिउत्तर की क्षमता बढ़ाते हैं।

अध्याय 49:

सीमांत एवं समुद्री सुरक्षा

भारत की विस्तृत भूमि सीमाएँ और विशाल तटीय रेखाएँ आतंकवाद विरोधी रणनीति में अत्यंत संवेदनशील कमजोरियाँ हैं, जो घुसपैठ, तस्करी और समुद्र-आधारित हमलों के लिए अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती हैं। इन बहुआयामी खतरों से राष्ट्र की रक्षा के लिए ठोस सीमा और समुद्री सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है, जिनमें भौतिक अवरोध, उन्नत तकनीक, और खुफिया आधारित संचालन का समेकित समावेश अनिवार्य है। सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तटरक्षक बल, और भारतीय नौसेना इस सुरक्षा रणनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिनका सहयोग राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ प्रदान करती हैं। भारत की भूमि सीमाएँ सात देशों से जुड़ी हैं, जिनकी कुल लंबाई पंद्रह हजार किलोमीटर से अधिक है। इनमें पाकिस्तान के साथ तीन हजार तीन सौ तेईस किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ चार हजार छियानबे किलोमीटर की सीमाएँ सर्वाधिक संवेदनशील हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में आतंकवाद और तस्करी का सतत खतरा बना रहता है। सीमा सुरक्षा बल, जिसमें दो लाख जवान शामिल हैं, इन सीमाओं की सुरक्षा का मुख्य दायित्व निभाते हैं, जबकि तीन हजार चार सौ अठासी किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की निगरानी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस करती है, और नेपाल, भूटान, म्यांमार की सीमाओं की सुरक्षा का कार्य सशस्त्र सीमा बल तथा असम राइफल्स द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इन संयुक्त अभियानों पर प्रतिवर्ष लगभग चार हजार करोड़ का व्यय होता है।

भारत बहुस्तरीय सीमा सुरक्षा रणनीति का अनुसरण करता है, जिसमें भौतिक अवसंरचना, तकनीकी निगरानी, और खुफिया आधारित गश्त शामिल हैं, जिससे खतरों की रोकथाम की जा सके। भारत-पाकिस्तान सीमा का नब्बे प्रतिशत हिस्सा, जो लगभग दो हजार से तीन हजार किलोमीटर है, काँटेदार तारों और फ्लडलाइटों से सुसज्जित है, जिस पर आठ सौ करोड़ खर्च किए गए, और इससे अवैध घुसपैठ की घटनाओं में स्पष्ट कमी आई है। शेष दस प्रतिशत सीमा क्षेत्र, जो लगभग तीन सौ से चार सौ किलोमीटर का है, नदीय और पर्वतीय दुर्गम भू-भाग में स्थित है, जहाँ पर अभी भी बाड़बंदी का कार्य प्रगति पर है और पूरा करने हेतु चार सौ करोड़ की

आवश्यकता है। भारत-बांग्लादेश सीमा का अस्सी प्रतिशत हिस्सा तीन हजार दो सौ किलोमीटर लंबा है और यह पहले से ही बाड़बंदी से युक्त है, किंतु सुंदरवन जैसे दलदली क्षेत्रों में शेष बीस प्रतिशत भाग अभी भी असुरक्षित है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और वैकल्पिक अवरोधों से सुरक्षित करने हेतु चार सौ करोड़ की आवश्यकता है।

तकनीकी निगरानी व्यवस्था इन भौतिक उपायों को और प्रभावी बनाती है, जहाँ पांच हजार बंद सर्किट टेलीविजन कैमरे, दो हजार रात्रि दृष्टि उपकरण, और एक हजार सीस्मिक सेंसर साठ प्रतिशत संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में लगाए गए हैं, जिन पर चार सौ करोड़ खर्च हुए और जिन्होंने अस्सी प्रतिशत घुसपैठ प्रयासों का पता लगाया। ड्रोन निगरानी प्रणाली, जिसमें दो सौ से तीन सौ इकाइयाँ सक्रिय हैं, पचास प्रतिशत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की निगरानी करती हैं और एक सौ से अधिक तस्करी के प्रयासों को विफल किया गया, जिसकी लागत अस्सी करोड़ रही। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पहचान प्रणाली ने ड्रोन अवरोधन की सफलता दर में बीस प्रतिशत की वृद्धि की, जिस पर चालीस करोड़ खर्च हुए। सीमा सुरक्षा बल प्रतिदिन पाकिस्तान सीमा पर एक हजार गश्त संचालन करता है, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों में वाहन और घोड़े का उपयोग होता है, जिस पर प्रतिवर्ष अस्सी करोड़ खर्च होते हैं। मानव खुफिया और तकनीकी खुफिया जानकारी को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ समन्वय कर दो सौ से तीन सौ घुसपैठों का पता लगाया गया, और बहु एजेंसी केंद्र के जरिए साझा खुफिया प्रणाली की बदौलत खुफिया साझा करने की क्षमता में पच्चीस प्रतिशत वृद्धि हुई, जिस पर चालीस करोड़ का व्यय हुआ।

भारत की सात हजार पांच सौ सोलह किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा, जिसमें तेरह प्रमुख और लगभग दो सौ लघु बंदरगाह शामिल हैं, समुद्री मार्गों से होने वाले आतंकवादी हमलों के लिए अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। 2008 के मुंबई हमले, जिसमें एक सौ छियासठ लोगों की जान गई और एक हजार छह सौ करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, इस खतरे की गंभीरता का उदाहरण हैं। भारतीय तटरक्षक बल, जो दो सौ से तीन सौ पोतों के साथ कार्यरत है, और भारतीय नौसेना, जिसके पास एक सौ चालीस युद्धपोत हैं, समुद्री सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी निभाते हैं। इनके साथ-साथ तटीय राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियाँ भी सक्रिय भागीदारी करती हैं। इन सभी के संयुक्त अभियानों पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ से अधिक की लागत आती है। भारतीय तटरक्षक बल प्रतिवर्ष पांच सौ से एक हजार समुद्री गश्त करता है,

जिसमें पोतों, विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक सौ से अधिक अवैध जलयानों को पकड़ा, जिनमें मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने की घटनाएँ शामिल थीं। इन अभियानों पर अस्सी करोड़ का खर्च आया।

इसरो की उपग्रह छवियों और समुद्री रडार प्रणाली के माध्यम से भारत ने अपने समुद्री क्षेत्रों का सत्तर प्रतिशत हिस्सा कवर किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण प्रणाली की मदद से जहाजों की निगरानी सटीकता में पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिस पर चालीस करोड़ खर्च हुए। 2008 के हमलों के बाद, भारत ने एक सौ तटीय पुलिस इकाइयाँ स्थापित कीं, जो भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर प्रतिवर्ष पांच सौ संयुक्त गश्त करती हैं, जिन पर अस्सी करोड़ का खर्च आता है और बीस से तीस तस्करी प्रयासों को रोका जाता है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ने नौसेना, तटरक्षक बल और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को बेहतर किया, जिसके लिए एकीकृत प्रोटोकॉल बनाए गए, जिनकी लागत चालीस करोड़ रही। एक सौ रणनीतिक बिंदुओं पर स्थापित तटीय निगरानी प्रणाली, जिसमें रडार और बंद सर्किट टेलीविजन शामिल हैं, अस्सी प्रतिशत समुद्री खतरों का समय रहते पता लगाती हैं, जिस पर चार सौ करोड़ खर्च हुए हैं। मानक संचालन प्रक्रियाएँ हर वर्ष अपडेट की जाती हैं, जिनके आधार पर तटरक्षक बल द्वारा दो सौ से अधिक प्रशिक्षण अभ्यास संचालित किए गए। इन अभ्यासों पर चालीस करोड़ खर्च किए गए, जिससे विभिन्न इकाइयों की तैयारियों और समन्वय क्षमता में सुधार आया। भारतीय नौसेना गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने में भी सक्रिय भूमिका निभाती है, जैसे अरब सागर में सोमालियाई समुद्री डाकुओं से रक्षा हेतु एक सौ से अधिक व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट किया गया, जिस पर अस्सी करोड़ का व्यय हुआ।

हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सीमा और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिससे निगरानी क्षमता, समन्वय और खुफिया साझाकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। “जीवंत गांव कार्यक्रम” के अंतर्गत भारत-चीन सीमा के पास स्थित तीन हजार गाँवों में आठ सौ करोड़ की लागत से बुनियादी ढाँचा, सड़क, संचार और निगरानी सुविधाएँ विकसित की गईं। इससे दस प्रतिशत तक सुरक्षा प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पहले बुनियादी संसाधनों की भारी कमी थी। इससे स्थानीय समुदायों को सुरक्षा एजेंसियों का सहयोगी बनने में भी मदद मिली है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ने भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और

राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को बेहतर किया, जिससे तटीय सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया समय में भी सुधार आया। इस समन्वय के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल बनाए गए, जिनकी लागत चालीस करोड़ रही। तटीय क्षेत्रों में एक सौ निगरानी स्टेशनों की तैनाती के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन तकनीक को भी शामिल किया गया, जिससे समुद्री खतरों की अस्सी प्रतिशत पहचान संभव हो पाई, और कुल चार सौ करोड़ की लागत से निगरानी तंत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ। इस तकनीक के उपयोग ने तटीय क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय को पच्चीस प्रतिशत तक तेज किया है। मानक संचालन प्रक्रियाएँ को वार्षिक रूप से अद्यतन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तटरक्षक बल द्वारा दो सौ से अधिक प्रशिक्षण अभ्यास संचालित किए गए। इन अभ्यासों पर चालीस करोड़ खर्च किए गए, जिससे विभिन्न इकाइयों की तैयारियों और समन्वय क्षमता में सुधार आया। भारतीय नौसेना ने गैर-पारंपरिक खतरों, जैसे सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा उत्पन्न संकटों का भी सामना किया-एक सौ से अधिक व्यापारिक जहाजों का सुरक्षित रूप से एस्कॉर्ट किया गया, जिस पर अस्सी करोड़ का व्यय हुआ।

अध्याय 50:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और सामुदायिक सहभागिता

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित की गई राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन संस्था है, जिसे आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन का दायित्व सौंपा गया है। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली यह एजेंसी उच्च प्रभाव वाले मामलों की जांच पर केंद्रित है, परंतु इसकी अप्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता देश की आतंकवाद-रोधी रणनीति को और अधिक प्रभावशाली बनाती है, जिससे लोगों के बीच विश्वास और लचीलापन उत्पन्न होता है। 2008 के मुंबई हमलों के, जिनमें एक सौ छियासठ लोग मारे गए और एक हजार छह सौ करोड़ का नुकसान हुआ, ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की गंभीर खामियों को उजागर किया, जिससे एक केंद्रीकृत संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इसी के परिणामस्वरूप 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई, जिसमें एक हजार से एक हजार पांच सौ कर्मचारी नियुक्त किए गए। यह एजेंसी भारत के किसी भी राज्य में बिना अनुमति के आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच कर सकती है, जिसके संचालन पर वार्षिक चार सौ करोड़ खर्च होते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती, और यह एक व्यापक आतंकी डाटाबेस का रखरखाव करती है, जिसमें पांच हजार से अधिक प्रविष्टियाँ दर्ज हो चुकी थीं।

यह एजेंसी गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम जैसे सशक्त कानूनों के तहत मुकदमा चलाती है और इसने पांच सौ से अधिक मामलों की जांच की, जिनमें पुलवामा (2019) और पहलगाम जैसे हमले शामिल हैं, जिसमें कुल एक हजार से एक हजार पांच सौ दोषियों को सजा दिलाई गई, जिस पर अस्सी करोड़ का व्यय हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना से पहले, आतंकवाद से संबंधित जांच राज्य स्तर की एजेंसियों पर निर्भर थी, जो समन्वय की कमी के कारण अक्सर असफल रहती थीं। उदाहरणस्वरूप, मुंबई हमलों की जांच में विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच जानकारी साझा करने में देरी हुई, जिससे अपराधियों को पकड़ने में कठिनाई आई।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना ने इस कमी को दूर किया और केंद्रीय स्तर पर जांच को मजबूत बनाया, जिससे न्याय व्यवस्था पर विश्वास पैदा हुआ है।

सामुदायिक सहभागिता आतंकवाद-रोधी रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो स्थानीय जनता के साथ विश्वास को स्थापित करता है, खुफिया जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सशक्त बनाता है और युवाओं के कट्टरपंथ की ओर झुकाव को कम करता है। जब समुदायों को रणनीति में सहभागी बनाया जाता है, तो वे न केवल सूचना स्रोत बनते हैं बल्कि सुरक्षा प्रयासों में भागीदार भी बनते हैं। दस हजार से पंद्रह हजार नागरिकों ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी, जिससे जुड़े क्षेत्रों में हमलों में बीस प्रतिशत की कमी देखी गई। यह सहभागिता आतंकवाद के मूल कारणों को भी संबोधित करती है, जैसे कश्मीर में बेरोजगारी दर, जिससे दो सौ से तीन सौ युवा कट्टरपंथ की ओर आकर्षित हुए। इसके अलावा, अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के हटाए जाने के बाद उत्पन्न राजनीतिक असंतोष को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से, स्थानीय नागरिकों को जागरूक बनाने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे कि कश्मीर में “शांति समितियों” के तहत पांच हजार से अधिक सभाओं का आयोजन, जहां दो सौ करोड़ की लागत से युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की गई। यह न केवल कट्टरपंथ को रोकता है बल्कि स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे पंद्रह प्रतिशत अधिक मामलों को समय रहते रोका गया। हालांकि सामुदायिक संपर्क का कार्य राज्य पुलिस द्वारा किया जाता है, फिर भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सफलताएं लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करती हैं, जिससे सहयोग और लचीलापन बढ़ता है और आठ सौ करोड़ की सालाना क्षति से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बल मिलता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच और अभियोजन की सफलताएं कानून व्यवस्था में आम जनता का विश्वास बढ़ाकर सामुदायिक सहभागिता को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करती हैं। जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवादियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने में सफलता प्राप्त करती है, तो इससे जनता को यह संदेश जाता है कि कानून अपना कार्य निष्पक्षता और प्रभावशीलता से कर रहा है, जिससे नागरिक सहयोग की भावना प्रबल होती है। उदाहरणस्वरूप, 2008 के मुंबई हमले के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को 2012 में दी गई फाँसी, जिस पर चालीस करोड़ का व्यय हुआ, ने आम लोगों के मन में विश्वास पैदा किया कि न्याय हुआ है। इसी प्रकार, 2019 के पुलवामा हमले में बीस

से तीस आतंकवादियों की गिरफ्तारी, जिस पर अस्सी करोड़ का व्यय हुआ, ने सर्वेक्षणों में दस प्रतिशत अधिक जनता को सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास करने को प्रेरित किया, जिससे हर वर्ष पांच हजार से दस हजार नागरिकों से महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होने लगीं। पहलगाम मामले में दस से पंद्रह गिरफ्तारियों से स्थानीय क्षेत्रों में हमलों में बीस प्रतिशत की कमी आई, और चालीस करोड़ के अभियोजन व्यय के साथ जनता का सहयोग और भी सुदृढ़ हुआ। इसके अतिरिक्त, दो सौ से अधिक मामलों में दोषसिद्धि, स्थानीय समुदायों में न्याय की भावना को मजबूत करती है, जिससे वे स्वयं संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने को प्रोत्साहित होते हैं। यह सब प्रयास प्रत्यक्ष सामुदायिक कार्य नहीं होने के बावजूद सामाजिक सुरक्षा के माहौल को सुधारने में सहायक सिद्ध हुए हैं, जिससे जनता की भागीदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ी है।

हालाँकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यक्षेत्र जांच और अभियोजन तक सीमित है, फिर भी यह राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ गहरे समन्वय में कार्य करती है। यह सहयोग विशेष रूप से बहु-एजेंसी केंद्र के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से हर महीने दो सौ से तीन सौ खुफिया रिपोर्ट साझा की जाती हैं, जिससे समन्वय पच्चीस प्रतिशत तक बेहतर हुआ है और चालीस करोड़ का व्यय हुआ है। जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में “शांति समितियों” के माध्यम से राज्य पुलिस द्वारा प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रमों में दस हजार से पंद्रह हजार युवाओं को जोड़ा गया, जिनमें चार सौ करोड़ की लागत से सामाजिक पहलें शुरू की गईं, जिससे श्रीनगर और अनंतनाग जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कट्टरपंथ में दस प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। एक संयुक्त कार्रवाई में अस्सी करोड़ मूल्य की आतंकी संपत्ति ज़ब्त की गई, जिससे जनता से मिली खुफिया सूचनाओं में बीस प्रतिशत वृद्धि हुई, और चालीस करोड़ का व्यय हुआ। ये साझेदारियाँ, जो साठ प्रतिशत उच्च संवेदनशील क्षेत्रों को कवर करती हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पहुँच को विस्तार देती हैं। उदाहरण के तौर पर, संयुक्त अभियानों से पचास से अधिक आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, जिसमें राज्य पुलिस की स्थानीय जानकारी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की केंद्रीय जांच क्षमता का समन्वय प्रमुख रहा।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की प्राथमिकता केवल आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन होने के कारण इसकी प्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता सीमित है। इसकी चार सौ करोड़ की वार्षिक बजट का केवल पांच प्रतिशत ही सामुदायिक कार्यक्रमों में व्यय होता है, जिससे यह भूमिका मुख्यतः राज्य पुलिस पर निर्भर हो जाती है, जो

लगभग अस्सी प्रतिशत प्रत्यक्ष संपर्क कार्यों को संभालती है। विशेषकर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के हटाए जाने के बाद बीस प्रतिशत जनता कानून व्यवस्था पर अविश्वास जताती है, वहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की केवल छापेमारी आधारित रणनीति को कठोर मानकर विरोध होता है। कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पचास से पचहत्तर छापेमारी के चलते पचास प्रदर्शन हुए, जिन पर दस करोड़ का व्यय हुआ। इसके अलावा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच प्रक्रिया में गोपनीयता की आवश्यकता से स्थानीय समुदायों के साथ सीधा संवाद कम होता है, जिससे कभी-कभी गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरणस्वरूप, एक जांच के दौरान स्थानीय निवासियों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पर पथराव किया, जिससे दस करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा लागत आई।

आगे देखते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपनी अप्रत्यक्ष सामुदायिक सहभागिता को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है यदि वह राज्य पुलिस के दस हजार अधिकारियों को सामुदायिक संवाद तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए चार सौ करोड़ का निवेश करे, जिससे बीस प्रतिशत तक नागरिक सहयोग में वृद्धि संभव है। साथ ही, पचास हजार युवाओं को व्यावसायिक और शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए आठ सौ करोड़ का प्रावधान कट्टरपंथ को पंद्रह प्रतिशत तक कम कर सकता है। इन कार्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन कट्टरपंथ की पहचान पर फोकस करके युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, जिससे दस प्रतिशत अधिक सूचनाएं प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा सामुदायिक जागरूकता अभियानों में दो सौ करोड़ का अतिरिक्त निवेश स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाली में सहायक होगा।

अध्याय 51:

राजनयिक अलगाव और क्षेत्रीय सहयोग

भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की आईएसआई इन संगठनों को प्रतिवर्ष लगभग चार सौ करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसे पाकिस्तान लगातार नकारता है। 2019 के पुलवामा हमले में चालीस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों की शहादत और लगभग अस्सी करोड़ की क्षति तथा 22 अप्रैल के पहलगाम नरसंहार में छब्बीस निर्दोष नागरिकों की मौत और समान आर्थिक नुकसान ने भारत को मजबूर किया कि वह पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने के लिए निर्णायक कदम उठाए। इन घटनाओं के बाद भारत ने कई ठोस कूटनीतिक कार्रवाइयाँ कीं-दस से पंद्रह पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन, पांच से दस सीमा चौकियों का बंद होना, सिंधु जल संधि का निलंबन, इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास से पचास से पचहत्तर कर्मचारियों की वापसी, और पच्चीस देशों के दूतों को ब्रीफिंग देकर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में अपनाने के सबूत प्रस्तुत करना। साथ ही 2019 में संयुक्त राष्ट्र में मसूदा अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने का प्रयास सफल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई और यूरोपीय संघ की आतंकी सूची में उसका नाम शामिल हुआ, जिस पूरी प्रक्रिया पर लगभग चालीस करोड़ का राजनयिक व्यय हुआ। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के मंच का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को 2018 से अब तक ग्रे-लिस्ट में बनाए रखा, जिससे उसे मिलने वाली लगभग चार हजार करोड़ की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका, रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख देशों के साथ आतंकवाद-रोधी साझेदारी को गहराया। इन साझेदारियों के अंतर्गत पचास से पचहत्तर आतंकवादी नेटवर्कों की सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया, जिस पर करोड़ों रुपये वार्षिक खर्च हुए और जिसके परिणामस्वरूप बीस से तीस आतंकवादी पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने

औपचारिक रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवादी संगठन घोषित किया, जिससे उनके अंतरराष्ट्रीय संचालन में बाधा आई। क्षेत्रीय स्तर पर भी भारत ने कई बहुपक्षीय मंचों में अग्रणी भूमिका निभाई। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्कों पर समन्वित कार्रवाई की चर्चा हुई, जिससे दस से पंद्रह प्रतिशत नेटवर्क निष्क्रिय हुए और इस पर चालीस करोड़ का व्यय आया। इसी वर्ष क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ने समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त अभ्यास किए, जिन पर लगभग चालीस करोड़ खर्च हुआ और जिससे समुद्री आतंकवाद-रोधी क्षमताएँ मजबूत हुईं। बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ तस्करी नेटवर्कों की पहचान और सूचनाओं के आदान-प्रदान से सीमा-पार अपराधों में लगभग दस प्रतिशत की कमी आई, जिसने भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को अतिरिक्त बल प्रदान किया।

इसके बावजूद चुनौतियाँ बनी हुई हैं। चीन ने पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में लगभग चार हजार आठ सौ करोड़ का निवेश किया, जिससे पाकिस्तान को चीन से कूटनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और संयुक्त राष्ट्र में भारत के बीस से तीस प्रतिशत प्रतिबंध प्रस्ताव अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल राजनयिक अलगाव से आतंकवाद समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कथित गुप्त समर्थन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को जारी है, जिससे हर साल दो सौ से तीन सौ घुसपैठ की घटनाएँ होती हैं और लगभग चार सौ करोड़ का नुकसान होता है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में अनुपालन की कमी-जहाँ लगभग बीस प्रतिशत मामले अधूरे हैं-वित्तीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को कम करती है, और इसके सुधार के लिए लगभग अस्सी करोड़ की आवश्यकता अनुमानित है। इसके अतिरिक्त हवाला नेटवर्क के जरिए लगभग अस्सी करोड़ की सहायता प्राप्त करने वाले गैर-राज्य तत्व अब भी सक्रिय हैं और पहलगाम जैसे हमलों को अंजाम देकर भारत की कूटनीतिक रणनीति को चुनौती देते हैं।

राजनयिक अलगाव और क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित भारत की आतंकवाद-रोधी नीति, जिस पर लगभग चार सौ करोड़ वार्षिक खर्च होता है, ने पाकिस्तान की वैश्विक छवि को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाई है। इस रणनीति के कारण पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता राशि में लगभग चार हजार करोड़ की कमी आई और आतंकी हमलों की आवृत्ति में लगभग दस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय

सहयोग संगठन और क्वाड जैसे मंचों पर समन्वित कार्रवाइयों से अस्सी करोड़ की बचत हुई और सामूहिक सुरक्षा ढाँचा अधिक मज़बूत हुआ, जिससे भारत की नेतृत्व क्षमता और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

अध्याय 52:

वैश्विक प्रतिबंध, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल उपाय और भारत की आतंकवाद-विरोधी नेतृत्व भूमिका

भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी रणनीति में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के मानकों को एक सशक्त हथियार के रूप में अपनाया है। इसका मूल उद्देश्य आतंकी वित्तपोषण को रोकना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और विधिक ढाँचों को मजबूत करना है, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों के खिलाफ। 2001 में संसद पर हमले और 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि केवल सीमाओं के भीतर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आतंकवाद के वैश्विक नेटवर्क को तोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय ढाँचों का सक्रिय उपयोग अनिवार्य है। 2010 में भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का पूर्ण सदस्य बना और इसके चालीस मानकों के अनुरूप अपने कानूनी ढाँचे को ढाला। 2021-2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-विरोधी समिति और तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करते हुए भारत ने वैश्विक प्रतिबंध नीतियों को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाई। पहलगाम हमले के बाद इन मंचों पर भारत की सक्रियता और भी बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप कई आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क निष्क्रिय हुए और उनके प्रायोजकों पर वैश्विक दबाव डाला गया।

संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, 1947 के तहत भारत संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू करता है, जिसके अंतर्गत हथियार, परमाणु एवं बैलिस्टिक सामग्री और अन्य संवेदनशील वस्तुओं पर रोक लगाई जाती है। 2009 के आतंकवाद रोकथाम आदेश के तहत सूचीबद्ध आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने और उनके वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने की व्यवस्था है। भारत ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों की संपत्तियाँ जब्त कीं और उनके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर दस करोड़ तक का जुर्माना और सात साल की कैद का प्रावधान है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-विरोधी समिति की अध्यक्षता के दौरान पाकिस्तान-आधारित नेटवर्कों को निशाना बनाने के प्रयासों पर विशेष बल दिया, हालांकि तालिबान रिव्यू फोरम या लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को सीधे

नामित करने में कुछ राजनीतिक बाधाएँ भी सामने आईं। इसके बावजूद इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सीमा पार से होने वाले आतंकी वित्तपोषण में लगभग पंद्रह प्रतिशत की कमी आई।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों के अनुपालन में भारत की स्थिति मजबूत है। “म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट” में भारत चालीस में से पैतीस सिफारिशों पर उच्च अनुपालक पाया गया। सिफारिश छह (लक्षित वित्तीय प्रतिबंध) और सात (प्रसार वित्तपोषण) पर भारत “काफी हद तक अनुपालक” और सिफारिश आठ (गैर-लाभकारी संगठनों) पर आंशिक अनुपालक दर्ज हुआ। गैर-लाभकारी संगठनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी और पंजीकरण की प्रक्रिया को और कड़ा किया गया। गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे कड़े कानून वित्तीय कार्रवाई कार्यबल मानकों के अनुरूप हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आतंकी वित्तपोषण मामलों में अभियोजन का अधिकार देते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक सौ से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए, जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक में नेटवर्क बाधित हुए। पाकिस्तान 2018 से वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे सूची में है, जिससे उसकी वैध फंडिंग क्षमता में कमी आई, लेकिन हवाला चैनलों के माध्यम से कुछ नेटवर्क अब भी सक्रिय हैं, जिन्हें बंद करने के लिए भारत ने तकनीकी और खुफिया साझेदारी पर बल दिया है।

वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार प्रभावशाली रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहते हुए भारत ने आतंकवाद-विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता की। मुंबई और दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों में पचास से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें साझा खुफिया सूचना, तकनीकी उपकरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हुआ। शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना मंच पर भारत ने मध्य एशिया में आतंकवाद-रोधी क्षमता निर्माण में योगदान दिया। क्वाड, आसियान और अन्य मंचों पर भारत की भागीदारी ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूती दी, जिससे समुद्री और हवाई आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीतियाँ विकसित हुईं।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग भी भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ संयुक्त अभियानों ने सीमापार नेटवर्कों को

कमजोर किया, जबकि फ्रांस, रूस, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साझेदारी ने वैश्विक आतंकी षड्यंत्रों को विफल करने में मदद की। “कोप इंडिया” और “मालाबार” जैसे अभ्यासों ने न केवल सैन्य कौशल को बढ़ाया, बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता भी सुदृढ़ की।

भारत केवल वैश्विक ढाँचों का अनुयायी नहीं, बल्कि उनके निर्माण में सक्रिय भागीदार रहा है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव चालीस/इकसठ में भारत ने कानूनी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया था। नौ/ग्यारह के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्यबल और संयुक्त राष्ट्र मंचों पर भारत की सक्रियता ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज कराने में मदद की। भारत द्वारा 1996 में प्रस्तावित “अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि” आज भी अंतरराष्ट्रीय विमर्श में एक महत्वपूर्ण मसौदा है। हाल ही में आतंकवाद-विरोधी समिति की अध्यक्षता में भारत ने साइबर आतंकवाद और धन शोधन से संबंधित प्रस्तावों को पारित करवाया, जिनसे वैश्विक नीतियों में सुधार हुआ।

फिर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा पर सहमति का अभाव कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को कमजोर कर देता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को चीन जैसे देशों का राजनीतिक संरक्षण मिलना भी एक गंभीर बाधा है। साइबर आतंकवाद एक नई चुनौती बनकर उभरा है-सौ से अधिक साइबर जोखिम पहचाने गए, जिनसे अरबों की संभावित हानि टल सकती थी। भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित साइबर रक्षा प्रणाली, क्वाड सहयोग और वैश्विक प्रतिबंध तंत्र में निवेश को बढ़ाना आवश्यक होगा। “वैश्विक आतंकवाद सूचकांक” में भारत की दस प्रतिशत प्रगति यह प्रमाण है कि निरंतर निवेश, कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक सहयोग के जरिये भारत अपनी नेतृत्व भूमिका को और सुदृढ़ कर सकता है।

पुस्तक में प्रयोग किए गए सन्दर्भों की सूची

1. सरकारी स्रोत (Government Sources)

अमेरिकी विदेश विभाग - कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2019, 2021, 2022: भारत; पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म 1993; संयुक्त राज्य ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के कथित सह-षड्यंत्रकारी को प्रत्यर्पित किया, 2023; भारत के साथ संयुक्त राज्य सुरक्षा सहयोग, 2025; संयुक्त राज्य और भारत: हमारी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना, 2021; आतंकवाद पर देश रिपोर्ट 2019; अमेरिकी विदेश विभाग की देश रिपोर्ट आतंकवाद 2022: भारत: भारतीय प्रयासों और सहयोग पर विश्लेषण; अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: वैश्विक आतंकवाद विरोध में सैन्य और खुफिया उपकरणों पर रिपोर्ट; वैश्विक युद्ध आतंकवाद पर: पहले 100 दिन: अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट (US State Department - Country Reports on Terrorism 2019, 2021, 2022: India; Patterns of Global Terrorism 1993; United States Extradites Alleged Co-Conspirator of 2008 Mumbai Terrorist Attacks, 2023; United States Security Cooperation with India, 2025; United States and India: Deepening Our Strategic Partnership, 2021; Country Reports on Terrorism 2019; US State Department Country Report on Terrorism 2022: India: Analysis on Indian Efforts and Cooperation; US National Security Strategy: Report on Military and Intelligence Tools in Global Counter-Terrorism; Global War on Terrorism: First 100 Days: US State Department Report)

एफएटीएफ - ब्लैक और ग्रे सूचियां; बढ़ी हुई निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार - 13 जून 2025; भारत में एएमएल और सीटीएफ उपाय: एफएटीएफ की रिपोर्ट; इंडिया फॉलो-अप रिपोर्ट - AML/CFT उपायों पर तकनीकी अनुपालन की स्थिति; केस स्टडी: एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान की यात्रा; एफएटीएफ ग्रेलिस्ट से पाकिस्तान की हटाने के निहितार्थ; एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान (FATF - Black and Grey Lists; Jurisdictions Under Increased Monitoring -

June 13, 2025; AML and CTF Measures in India: FATF Report; India Follow-up Report - Status of Technical Compliance on AML/CFT Measures; Case Study: Pakistan's Journey from FATF Grey List; Implications of Pakistan's Removal from FATF Greylist; Pakistan in FATF Grey List)

गृह मंत्रालय - वर्ष-समापन समीक्षा 2023 - आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद-रोधी अभियानों की प्रगति पर आधिकारिक दस्तावेज; सीमा प्रबंधन-आधिकारिक अवलोकन/तथ्य-पुस्तिका - फेंसिंग, CIBMS, BOLD-QIT और स्मार्ट निगरानी तंत्र पर जानकारी; काउंटर टेररिज्म और काउंटर रैडिकलाइजेशन डिवीजन; गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम संबंधी अधिसूचनाएँ - प्रतिबंधित संगठनों और व्यक्तियों की सूची; Civic Action Programme - CAPFs द्वारा सामुदायिक विकास और पुनर्वास की पहल; भारत में नागरिक समाज के खिलाफ FATF सिफारिशों का दुरुपयोग: एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट वित्तीय कार्रवाइयों पर (Ministry of Home Affairs - Year-End Review 2023 - Official Document on Progress in Internal Security, Border Management, and Counter-Terrorism Operations; Border Management-Official Overview/Fact Sheet - Information on Fencing, CIBMS, BOLD-QIT, and Smart Surveillance Systems; Counter Terrorism and Counter Radicalization Division; Notifications Related to Unlawful Activities (Prevention) Act - List of Banned Organizations and Individuals; Civic Action Programme - Community Development and Rehabilitation Initiatives by CAPFs; Misuse of FATF Recommendations Against Civil Society in India: Amnesty International Report on Financial Actions)

जम्मू-कश्मीर प्रशासन - मिशन यूथ - कौशल विकास और युवाओं की सहभागिता कार्यक्रम (Jammu-Kashmir Administration - Mission Youth - Skill Development and Youth Engagement Programs)

डीएनआई - नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर | समूह (DNI - National Counterterrorism Center | Groups)

डीआरडीओ - एंटी-ड्रोन सिस्टम और तकनीकी तैनाती पर आधिकारिक विवरण; डीआरडीओ रुस्तम, जनवरी 3, 2025 (DRDO - Official Details on Anti-Drone Systems and Technical Deployment; DRDO Rustom, January 3, 2025)

नाटो (NATO) - आतंकवाद विरोधी रिपोर्ट: आतंकवाद को सुरक्षा खतरे के रूप में देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विवरण (NATO - Counter-Terrorism Report: Details on International Cooperation Viewing Terrorism as a Security Threat)

पीआईबी - बालाकोट हवाई हमले ने संदेश दिया कि सीमा-पार आतंकवाद दुश्मन के लिए कम लागत वाला विकल्प नहीं होगा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, 2019; हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, मार्च 28, 2023; आतंकवादी घटनाएँ, 2023; प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पुनर्परिभाषित किया: पीआईबी की प्रेस रिलीज (PIB - Balakot Air Strike Sent Message That Cross-Border Terrorism Will Not Be a Low-Cost Option for Enemy, Defence Minister Shri Rajnath Singh, 2019; Smuggling of Arms and Narcotics, March 28, 2023; Terrorist Incidents, 2023; Prime Minister Modi Redefined India's Policy Against Terrorism: PIB Press Release)

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना (MPF) - 2022-26 - बजटीय आवंटन और उपकरण आधुनिकीकरण की जानकारी (Modernization of Police Forces Scheme (MPF) - 2022-26 - Budgetary Allocation and Equipment Modernization Information)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) - PMLA के तहत की गई संपत्ति जब्ती और कार्रवाई के विवरण (Enforcement Directorate (ED) - Details of Property Seizures and Actions Under PMLA)

भारत सरकार - राजपत्र अधिसूचनाएँ - UAPA के तहत घोषित संगठनों और व्यक्तियों की सूची; डिजिटल पुलिस पोर्टल (CCTNS) - अपराध और अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (Government of India - Gazette Notifications - List of Organizations and Individuals Declared Under UAPA; Digital

Police Portal (CCTNS) - National Database of Crimes and Criminals)

भारत-यूरोपीय संघ - संयुक्त बयान आतंकवाद विरोध पर: भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पर दस्तावेज (India-European Union - Joint Statement on Counter-Terrorism: Document on Cooperation Between India and the European Union)

भारत-अमेरिका काउंटर-टेररिज्म डायलॉग - खुफिया साझेदारी और क्षमता निर्माण पर संयुक्त बयान (India-US Counter-Terrorism Dialogue - Joint Statement on Intelligence Partnership and Capacity Building)

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) - 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के संचालन का विवरण (Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) - Details of Operation of 1930 Helpline and National Cyber Crime Portal)

भारतीय सेना - ऑपरेशन सद्भावना - जम्मू-कश्मीर में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में योगदान (Indian Army - Operation Sadbhavana - Contribution to Education, Health, and Infrastructure in Jammu-Kashmir)

भारतीय तटरक्षक बल - समुद्री सीमा सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की जानकारी (Indian Coast Guard - Information on Maritime Border Security and Actions on Illegal Activities)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) - क्राइम इन इंडिया 2021-2022 - UAPA मामलों और गिरफ्तारी के राष्ट्रीय आंकड़े (National Crime Records Bureau (NCRB) - Crime in India 2021-2022 - National Data on UAPA Cases and Arrests)

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) - आधिकारिक उपलब्धियां और आतंकवाद-रोधी अभियानों की प्रगति (National Investigation Agency (NIA) - Official Achievements and Progress in Counter-Terrorism Operations)

लोकसभा - विदेश मामलों की समिति रिपोर्ट: काउंटर-टेररिज्म उपकरणों को अपग्रेड करने पर दस्तावेज; विदेश मामलों की समिति रिपोर्ट: लोकसभा दस्तावेज (Lok Sabha - Foreign Affairs Committee Report: Document on Upgrading Counter-Terrorism Tools; Foreign Affairs Committee Report: Lok Sabha Document)

वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) - हवाला और AML-CFT अनुपालन पर वार्षिक रिपोर्ट (Financial Intelligence Unit (FIU-IND) - Annual Report on Hawala and AML-CFT Compliance)

विदेश मंत्रालय - वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 - आतंकवाद-रोधी बहुपक्षीय सहयोग और UNSC/CTC में भारत की भूमिका; 29 सितम्बर 2016 - सर्जिकल स्ट्राइक पर आधिकारिक बयान और DGMO ब्रीफिंग; 26 फरवरी 2019 - बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आधिकारिक वक्तव्य (Ministry of External Affairs - Annual Report 2022-23 - Multilateral Cooperation on Counter-Terrorism and India's Role in UNSC/CTC; September 29, 2016 - Official Statement on Surgical Strike and DGMO Briefing; February 26, 2019 - Official Statement on Balakot Air Strike)

संयुक्त राष्ट्र - काउंटर-टेररिज्म का कार्यालय; संयुक्त राष्ट्र वैश्विक काउंटर-टेररिज्म रणनीति; आतंकवाद और काउंटर-टेररिज्म पर मॉड्यूल: अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की परिभाषा और कानूनी ढांचे पर ई-बुक; मानवाधिकार, आतंकवाद और काउंटर-टेररिज्म पर फैक्टशीट: अंतरराष्ट्रीय कानूनों और निषेधों पर दस्तावेज; काउंटर-टेररिज्म कार्यालय (UNCCT): वैश्विक काउंटर-टेररिज्म रणनीति और सदस्य देशों के सहयोग पर रिपोर्ट, जिसमें भारत की भूमिका शामिल है; सुरक्षा परिषद में भारत का योगदान: काउंटर-टेररिज्म कमिटी की स्थापना और उपलब्धियां पर दस्तावेज; यूएनएससी सीटीसी - सुरक्षा परिषद - काउंटर-टेररिज्म समिति (सीटीसी); यूएनओडीसी - काउंटर-टेररिज्म; यूएनएससी - CTC में भारत की अध्यक्षता और विशेष बैठकों के निष्कर्ष (United Nations - Office of Counter-Terrorism; United Nations Global Counter-Terrorism Strategy; Modules on Terrorism and Counter-Terrorism: E-Book on Definition of International Terrorism and Legal Frameworks; Fact Sheet on

Human Rights, Terrorism, and Counter-Terrorism: Document on International Laws and Prohibitions; Counter-Terrorism Office (UNCCT): Report on Global Counter-Terrorism Strategy and Cooperation with Member States, Including India's Role; India's Contribution to Security Council: Document on Establishment and Achievements of Counter-Terrorism Committee; UNSC CTC - Security Council - Counter-Terrorism Committee (CTC); UNODC - Counter-Terrorism; UNSC - India's Chairmanship in CTC and Conclusions of Special Meetings)

सीमा सुरक्षा बल (BSF) - ड्रोन अवरोधन और सीमा-पार तस्करी पर वार्षिक संक्षेप (Border Security Force (BSF) - Annual Summary on Drone Interception and Cross-Border Smuggling)

सीईआरटी-इन - 28 अप्रैल 2022 के दिशा-निर्देश - साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग और डेटा लॉग रखने के मानक (CERT-In - Guidelines of April 28, 2022 - Standards for Reporting Cyber Security Incidents and Maintaining Data Logs)

“नो मनी फॉर टेरर” सम्मेलन 2022 - नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक के परिणाम (“No Money for Terror” Conference 2022 - Outcomes of International Meeting Held in New Delhi)

2. पुस्तकें (Books)

अल-कायदा इन इट्स ओन वर्ड्स, गिल्स केपेल और जीन-पियरे मिलेली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2008 (अल-कायदा अपनी ही बातों में)

अल-कायदा: द टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, जेसन बर्क, पेंगुइन बुक्स, 2004 (अल-कायदा: वह आतंकवादी संगठन जिसने दुनिया बदल दी)

अल-कायदा'स ग्लोबल क्राइसिस: द इस्लामिक स्टेट, तकफ़ीर, एंड द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स, ब्रायन फिशमैन, न्यू अमेरिका फाउंडेशन, 2016 (अल-कायदा का वैश्विक संकट: इस्लामिक स्टेट, तकफ़ीर, और मुसलमानों का नरसंहार)

अल-कायदा इन साउथ एशिया: फ्रेगमेंटेशन एंड रेजिलियंस, क्रिस्टीन फेयर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च, 2014 (दक्षिण एशिया में अल-कायदा: विखंडन और लचीलापन)

काउंटरिंग टेरिस्ट फाइनेंसिंग, कॉलिन क्लार्क, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019 (आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला)

द 9/11 कमीशन रिपोर्ट, नेशनल कमीशन ऑन टेरिस्ट अटैक्स अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स, डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन एंड कंपनी, 2004 (9/11 आयोग रिपोर्ट)

द इकोनॉमिक्स ऑफ टेरिज्म, लुईस रिचर्डसन, राउटलेज, 2017 (आतंकवाद की अर्थव्यवस्था)

द इवॉल्यूशन ऑफ अल-कायदा: बिटवीन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ए ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव, थॉमस हेगहैमर, पर्सपेक्टिव्स ऑन टेरिज्म, 2017 (अल-कायदा का विकास: क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक दृष्टिकोण के बीच)

द फाइनेंसिंग ऑफ अल-कायदा: ए स्टडी ऑफ अल-कायदा'स फाइनेंशियल नेटवर्क, रोहन गुनारत्ने और अन्य, जर्नल ऑफ पोलिसिंग, इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेरिज्म, 2012 (अल-कायदा का वित्तपोषण: अल-कायदा के वित्तीय नेटवर्क का अध्ययन)

द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस ऑन टेरिस्ट फाइनेंसिंग, एंड्रियास वेंगर और अन्य, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेवलपमेंट, 2015 (आतंकवादी वित्तपोषण पर प्रतिबंधों का प्रभाव)

द इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर-टेरिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स, कॉलिन किंग और अन्य, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, 2018 (काउंटर-टेरिज्म फाइनेंसिंग उपायों की प्रभावशीलता)

द फाइनेंसिंग ऑफ अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट: ए केस स्टडी, क्रिस्टीन फेयर और अन्य, नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च, 2022, 2025 (भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ बोको हरम: ए केस स्टडी, जैकब ज़ेन और अन्य, जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल, 2017 (बोको हरम का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन: ए केस स्टडी, प्रवीण स्वामी और अन्य, द हिंदू, 2020, 2025 (हिजबुल मुजाहिदीन का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ आईएसआईएस: ए केस स्टडी, मैथ्यू लेविट और अन्य, द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, 2016 (आईएसआईएस का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ आईएसआईएस-खुरासान: ए केस स्टडी, मैथ्यू लेविट और अन्य, द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, 2023, 2025 (आईएसआईएस-खुरासान का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ जैश-ए-मोहम्मद: ए केस स्टडी, स्टीफन टैंकेल और अन्य, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 2019, 2025 (जैश-ए-मोहम्मद का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ इंडियन मुजाहिदीन: ए केस स्टडी, विक्रम सूद और अन्य, हार्परकॉलिन्स, 2021, 2025 (इंडियन मुजाहिदीन का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ लश्कर-ए-तैयबा: ए केस स्टडी, क्रिस्टीन फेयर और अन्य, नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च, 2018, 2025 (लश्कर-ए-तैयबा का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द फाइनेंसिंग ऑफ तालिबान: ए केस स्टडी, ग्रेटचेन पीटर्स और अन्य, कॉम्बैटिंग टेरेरिज्म सेंटर एट वेस्ट पॉइंट, 2024, 2025 (तालिबान का वित्तपोषण: एक केस स्टडी)

द रोल ऑफ चैरिटीज इन टेरेरिस्ट फाइनेंसिंग, मैथ्यू लेविट, द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी, 2006 (आतंकवादी वित्तपोषण में चैरिटीज की भूमिका)

द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेरेरिस्ट फाइनेंसिंग, डेविड एस. कोहेन और अन्य, जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल, 2019 (आतंकवादी वित्तपोषण में तकनीक की भूमिका)

द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट इन साउथ एशिया, स्टीफन टैंकेल, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 2015 (दक्षिण एशिया में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट की संरचनाएं)

द यूज ऑफ क्रिप्टोकॉरेसीज बाय टेरेरिस्ट ऑर्गनाइजेशंस, जुआन ज़राते और अन्य, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, 2020 (आतंकवादी संगठनों द्वारा क्रिप्टोकॉरेसी का उपयोग)

द यूज ऑफ नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशंस फॉर टेरिस्ट फाइनेंसिंग, सारा डेली और अन्य, जर्नल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल, 2010 (आतंकवादी वित्तपोषण के लिए गैर-लाभकारी संगठनों का उपयोग)

द लूमिंग टॉवर: अल-कायदा एंड द रोड टू 9/11, लॉरेंस राइट, नॉफ डबलडे पब्लिशिंग ग्रुप, 2006 (द लूमिंग टॉवर: अल-कायदा और 9/11 की राह)

टेरिस्ट फाइनेंसिंग एंड स्टेट रिसपॉन्सेस: ए कम्पैरेटिव पर्सपेक्टिव, जॉन टी. पिकारेली, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012 (आतंकवादी वित्तपोषण और राज्य प्रतिक्रियाएं: एक तुलनात्मक दृष्टिकोण)

टेरिस्ट फाइनेंसिंग: मेथड्स एंड काउंटरमेजर्स, जॉन ए. कैसारा, राउटलेज, 2016 (आतंकवादी वित्तपोषण: विधियां और प्रतिकार उपाय)

द फाइनेंसिंग ऑफ टेरर: हाउ मिलिटेंट्स फाइंड मनी, डगलस फराह, फॉरेन अफेयर्स, 2004 (आतंक का वित्तपोषण: उग्रवादी कैसे पैसे ढूंढते हैं)

फंडिंग टेररिज्म: केस स्टडीज, थॉमस सी. ब्रुन्यू और अन्य, आईओएस प्रेस, 2011 (आतंकवाद का वित्तपोषण: केस स्टडीज)

इनसाइड अल-कायदा: ग्लोबल नेटवर्क ऑफ टेरर, रोहन गुनारत्ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002 (अल-कायदा के अंदर: आतंक का वैश्विक नेटवर्क)

3. अन्य संदर्भ (Other References)

आईआरपी - लश्कर-ए-तैयबा / लश्कर-ए-तय्यिबा, 2009; हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम), 2017 (IRP - Lashkar-e-Taiba / Lashkar-e-Tayyiba, 2009; Hizbul Mujahideen (HM), 2017)

आईपीसीएस - द हिजबुल मुजाहिदीन, 2017; द इंडियन मुजाहिदीन: इवॉल्यूशन ऑफ ए होमग्रोवन टेरिस्ट ग्रुप, 2013 (IPCS - The Hizbul Mujahideen, 2017; The Indian Mujahideen: Evolution of a Homegrown Terrorist Group, 2013)

आईलर्नकाना - भारत में ड्रोन विनियमन, जनवरी 20, 2022 (iLernKana - Drone Regulation in India, January 20, 2022)

आईएफएसी - केस स्टडी: एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान की यात्रा (IFAC - Case Study: Pakistan's Journey from FATF Grey List)

आईआईएसएस - आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति भारत की कड़ी नीतियां (IISS - Terrorism and India's Strict Policies Towards Pakistan)

आईईपी - ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 (IEP - Global Terrorism Index 2020)

आईडीईएफओआरजे - भारत में सैन्य ड्रोन का भविष्य (IdeaForge - The Future of Military Drones in India)

इंडिया.कॉम - पाकिस्तान की आईएसआई स्लीपर सेल्स को सक्रिय करती है जबकि हिजबुल मुजाहिदीन इस व्यक्ति को नया नेता बनाकर भारत के खिलाफ 'युद्ध' की घोषणा करता है, अप्रैल 25, 2025 (India.com - Pakistan's ISI Activates Sleeper Cells While Hizbul Mujahideen Declares 'War' Against India by Making This Person New Leader, April 25, 2025)

इंडिया टुडे - विशेष: जैश-ए-मोहम्मद जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को कैसे वित्तपोषित कर रहा है, 2023; कैसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया ने पहलगाम आतंकी हमले को प्रचार युद्ध में बदल दिया: मज़ाक और गलत सूचना, अप्रैल 24, 2025; भारत ने पहलगाम हमले का जवाब कड़े कूटनीतिक प्रतिबंधों के साथ दिया, पाकिस्तान वैश्विक अलगाव का सामना कर रहा है, 2025; जैश-ए-मोहम्मद की नई रणनीति स्थानीय कश्मीरियों को आतंकी हमलों के लिए भर्ती करने की, खतरे की घंटी, 2023; कश्मीर: सेना ने एलओसी पर बड़ी हथियार तस्करी को विफल किया, राइफल, गोला-बारूद बरामद, अक्टूबर 10, 2020; बालाकोट हवाई हमले पर नवीनतम अपडेट, 2019; एनआईए ने गैंगस्टर-आतंक गठजोड़ पर कार्रवाई की, 72 स्थानों पर छापेमारी, फरवरी 21, 2023; ऑपरेशन ऑल-आउट: कश्मीर से आतंकवादियों को खत्म करने की सेना की मास्टर प्लान, 2017; संदिग्ध पाकिस्तानी नौका की पहचान, जिसने भारत में हथियार तस्करी की, अप्रैल 9, 2014; पंजाब के माध्यम से भारत में नशीले पदार्थ कैसे तस्करी किए जाते हैं, जुलाई 9, 2016; इंडियन मुजाहिदीन कौन है?, 2013 (India Today - Special: How Jaish-e-Mohammed is Funding Terrorists in Jammu and Kashmir, 2023; How Pakistani Social Media Turned Pahalgam Terror Attack into

Propaganda War: Memes and Misinformation, April 24, 2025; India Responds to Pahalgam Attack with Strict Diplomatic Sanctions, Pakistan Faces Global Isolation, 2025; Jaish-e-Mohammed's New Strategy to Recruit Local Kashmiris for Terror Attacks, Alarm Bells, 2023; Kashmir: Army Foils Major Weapon Smuggling on LoC, Rifles, Ammunition Recovered, October 10, 2020; Latest Update on Balakot Air Strike, 2019; NIA Cracks Down on Gangster-Terror Nexus, Raids 72 Locations, February 21, 2023; Operation All-Out: Army's Master Plan to Eliminate Terrorists from Kashmir, 2017; Suspected Pakistani Boat Identified for Weapon Smuggling in India, April 9, 2014; How Drugs are Smuggled into India through Punjab, July 9, 2016; Who is Indian Mujahideen?, 2013)

आउटलुक बिजनेस - ऑपरेशन सिंदूर: भारत द्वारा निशाना बनाए गए नौ आतंकी ठिकानों के बारे में सब कुछ, मई 7, 2025; भारत ने 31 अमेरिकी ड्रोन खरीदने की तैयारी की! सौदे के बारे में सब कुछ, जुलाई 3, 2023 (Outlook Business - Operation Sindoor: Everything About the Nine Terror Bases Targeted by India, May 7, 2025; India Prepares to Buy 31 American Drones! Everything About the Deal, July 3, 2023)

आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन - पुलवामा संकट: एक परमाणु पर्यावरण में युद्ध की छेड़छाड़, 2019 (Arms Control Association - Pulwama Crisis: War Gaming in a Nuclear Environment, 2019)

अल अरबिया इंग्लिश - हिजबुल्लाह के स्लीपर सेल्स की वैश्विक जड़ों का खुलासा, अक्टूबर 12, 2017 (Al Arabiya English - Revealing the Global Roots of Hezbollah's Sleeper Cells, October 12, 2017)

अल जज़ीरा - आतंकवाद को कूटनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग न करें: भारत में पाकिस्तान विदेश मंत्री, 2023; इंडियन मुजाहिदीन, 2013; भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान के साथ भारी गोलीबारी, 2025; क्या भारत पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं के पीछे है? हम क्या जानते हैं, अप्रैल 5, 2024; प्रोफाइल: सशस्त्र

समूह, 2017; क्या भारत और पाकिस्तान ने ड्रोन युद्ध शुरू किया है?, मई 9, 2025; भारत प्रशासित कश्मीर में लड़ाई में तीन संदिग्ध विद्रोही मारे गए, 2025; सूचना युद्ध: क्या भारत और पाकिस्तान हमलों के बारे में सच बोल रहे हैं?, 2019; अमेरिका ने पहलगाम हमले के आरोपी समूह को आतंकवादी कहा, 2025 (Al Jazeera - Do Not Use Terrorism as a Diplomatic Tool: Pakistan Foreign Minister in India, 2023; Indian Mujahideen, 2013; India Launches Operation Sindoor, Heavy Firing with Pakistan, 2025; Is India Behind Targeted Killings in Pakistan? What We Know, April 5, 2024; Profiles: Armed Groups, 2017; Have India and Pakistan Started a Drone War?, May 9, 2025; Three Suspected Rebels Killed in Fighting in India-Administered Kashmir, 2025; Information War: Are India and Pakistan Telling the Truth About Attacks?, 2019; US Calls Group Accused of Pahalgam Attack Terrorist, 2025)

अल-कायदा'स फाइनेंशियल नेटवर्क: द रोल ऑफ हवाला, ग्रेटचेन पीटर्स, कॉम्बैटिंग टेररिज्म सेंटर एट वेस्ट पॉइंट, 2009 (Al-Qaida's Financial Network: The Role of Hawala, Gretchen Peters, Combating Terrorism Center at West Point, 2009)

अटलांटिक काउंसिल - एफएटीएफ ग्रेलिस्ट से पाकिस्तान की हटाने के निहितार्थ (Atlantic Council - Implications of Pakistan's Removal from FATF Greylist)

एमनेस्टी इंटरनेशनल - भारत: आतंकवाद विरोधी नियमों का दुरुपयोग बंद करें, नवंबर 3, 2023; भारत के आतंकवाद वित्तपोषण मूल्यांकन के शोषण पर रिपोर्ट (Amnesty International - India: Stop Misusing Anti-Terrorism Rules, November 3, 2023; Report on Exploitation of India's Terrorism Financing Assessment)

एफपीआरआई - भारत की विकसित जटिल प्रतिरोध रणनीति: एफपीआरआई की रिपोर्ट (FPRI - India's Developed Complex Deterrence Strategy: FPRI Report)

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) - भारत की समुद्री सुरक्षा: पाँच चिंताएँ, अभिजीत सिंह, मई 18, 2022; भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली का लचीलापन निर्माण, 2022; भारत-पाकिस्तान सीमा पर शत्रुतापूर्ण ड्रोन गतिविधि का मुकाबला, 2024; भारत में आतंकवाद विरोधी, 2023; भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी की चुनौती, 2024 (Observer Research Foundation (ORF) - India's Maritime Security: Five Concerns, Abhijit Singh, May 18, 2022; Building Resilience in India's Internal Security System, 2022; Countering Hostile Drone Activity on India-Pakistan Border, 2024; Counter-Terrorism in India, 2023; Challenge of Drug Smuggling for India's National Security, 2024)

कनेक्शंस - भारत की जिहादी आतंक विरोधी नीति: चुनौतियाँ और संभावनाएँ, विनय कौड़ा, खंड 16, अंक 4, शरद 2017 (Connections - India's Jihadi Counter-Terrorism Policy: Challenges and Possibilities, Vinay Kaura, Volume 16, Issue 4, Fall 2017)

काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस - भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, 2025; भारत और पाकिस्तान: कश्मीर पर संघर्ष की कगार पर, 2025; जैश-ए-मोहम्मद, 2019; आईएसआई और आतंकवाद: आरोपों के पीछे, 2011; आईएसआई और आतंकवाद: आरोपों के पीछे, 2008; भारत की काउंटर-टेरिज्म प्रयासों पर बैकग्राउंडर, जिसमें कानून, एजेंसियाँ और प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं (Council on Foreign Relations - Conflict Between India and Pakistan, 2025; India and Pakistan: On the Brink of Conflict over Kashmir, 2025; Jaish-e-Mohammed, 2019; ISI and Terrorism: Behind the Accusations, 2011; ISI and Terrorism: Behind the Accusations, 2008; Backgrounder on India's Counter-Terrorism Efforts, Including Laws, Agencies, and Major Events)

काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट - लश्कर-ए-तैयबा का सोशल मीडिया उपयोग (Counter Extremism Project - Lashkar-e-Taiba's Social Media Use)

कार्नेगी - नॉट वॉर, नॉट पीस: क्रॉस-बॉर्डर रोकने के लिए पाकिस्तान को प्रेरित करना (Carnegie - Not War, Not Peace: Motivating Pakistan to Stop Cross-Border)

काउंसिल ऑफ यूरोपीय संघ - यूरोपीय संघ की आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया: काउंसिल ऑफ यूरोपीय संघ की रिपोर्ट (Council of the European Union - European Union's Counter-Terrorism Response: Council of the European Union Report)

डीडब्ल्यू - कश्मीर विद्रोह में प्रमुख उग्रवादी समूह, अप्रैल 26, 2025 (DW - Major Militant Groups in Kashmir Insurgency, April 26, 2025)

ड्रोनलाइफ - भारत ने एयरो इंडिया 2025 में नए यूएवी के साथ ड्रोन बाजार का विस्तार किया, फरवरी 11, 2025 (DroneLife - India Expands Drone Market with New UAVs at Aero India 2025, February 11, 2025)

द इंडियन एक्सप्रेस - ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान, पीओके में नौ आतंकी शिविरों पर हमला, मई 8, 2025; टेरर मुख्यालय, पाकिस्तान: मुरिदके और बहावलपुर को नष्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है, 2023 (The Indian Express - Operation Sindoor: Attack on Nine Terror Camps in Pakistan, PoK, May 8, 2025; Terror Headquarters, Pakistan: Why Destroying Muridke and Bahawalpur is Important, 2023)

द डिप्लोमैट - हिजबुल मुजाहिदीन, 2017; भारत-पाकिस्तान संबंध, 2023; इंडियन मुजाहिदीन: एक प्रोफाइल, 2013; इंडियन मुजाहिदीन: द एनिमी विदिन, 2013; दक्षिण पूर्व एशिया में आईएसआईएस, 2020; भारत की 2016 'सर्जिकल स्ट्राइक' की आंतरिक कहानी, 2016 (The Diplomat - Hizbul Mujahideen, 2017; India-Pakistan Relations, 2023; Indian Mujahideen: A Profile, 2013; Indian Mujahideen: The Enemy Within, 2013; ISIS in Southeast Asia, 2020; The Inside Story of India's 2016 'Surgical Strike', 2016)

द हिंदू - बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से हथियार लाने की कोशिश को विफल किया, बड़ा हथियार जखीरा ज़ब्त, अक्टूबर 7, 2021; जलवायु परिवर्तन

और आतंकवाद, 2020; अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी का गिरोह पकड़ा गया, दो गिरफ्तार: पंजाब पुलिस, जुलाई 14, 2020; भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक पर्यावरणीय संघर्ष, 2018; राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2020; एनआईए चार्जशीट में इंडियन मुजाहिदीन के एलईटी से संबंधों का खुलासा, 2013; ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तान ने गलत सूचना अभियान शुरू किया, सरकार का कहना है, मई 8, 2025; पाकिस्तान का आतंकवादी नेटवर्क का जटिल जाल; पुलवामा हमला: पुलवामा हमले की कहानी, नवीनतम समाचार, तस्वीरें, वीडियो और शीर्ष कहानियाँ, 2019; पंजाब से कश्मीर तक हथियार तस्करी विफल, 2 एलईटी लोग पकड़े गए, जून 12, 2020; क्या भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में धकेल सकता है? (The Hindu - BSF Foils Attempt to Bring Weapons from Pakistan on International Border, Large Weapon Cache Seized, October 7, 2021; Climate Change and Terrorism, 2020; International Arms Smugglers Gang Caught, Two Arrested: Punjab Police, July 14, 2020; India Has More Environmental Conflicts Than Any Other Country, 2018; National Green Tribunal, 2020; NIA Chargesheet Reveals Indian Mujahideen's Links with LeT, 2013; Operation Sindoor: Pakistan Starts Misinformation Campaign, Government Says, May 8, 2025; Pakistan's Complex Web of Terrorist Networks; Pulwama Attack: Story of Pulwama Attack, Latest News, Photos, Videos and Top Stories, 2019; Weapon Smuggling from Punjab to Kashmir Foiled, 2 LeT People Caught, June 12, 2020; Can India Push Pakistan into FATF Grey List?)

द हिंदुस्तान टाइम्स - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा निशाना बनाए गए नौ लक्ष्य आतंकवादियों को कैसे समर्थन दे रहे थे, मई 7, 2025; सर्जिकल स्ट्राइक दिवस: 2016 का अभियान कैसे किया गया, 2016 (Hindustan Times - How the Nine Targets Targeted by India During Operation Sindoor Were Supporting Terrorists, May 7, 2025; Surgical Strike Day: How the 2016 Operation Was Conducted, 2016)

दृष्टि आईएस - भारत में सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा प्रबंधन; भारत की सीमा और इसका प्रबंधन (Drishti IAS - Security Challenges and Border Management in India; India's Borders and Their Management)

न्यूजवीक - भारत की नई युद्ध ड्रोन सफलता का एक नज़र चीन पर, दिसंबर 21, 2023 (Newsweek - A Look at India's New War Drone Success on China, December 21, 2023)

पीडब्ल्यूओनलीआईएस - भारत में सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमा प्रबंधन (PWOnlyIAS - Security Challenges and Border Management in India)

पीबीएस फ्रंटलाइन - 2008 मुंबई हमलों में, जासूसी डेटा के ढेर, लेकिन एक अधूरा, 2008 (PBS Frontline - In 2008 Mumbai Attacks, Pile of Spy Data, But an Unfinished, 2008)

फिन्सइंडिया.ऑर्ग - भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में समुद्री सीमा सुरक्षा दृष्टिकोण (FinsIndia.org - Maritime Border Security Approach in India's National Security Interests)

फोर्ब्स - भारतीय सेना स्वदेशी ड्रोन-रोधी क्षमताएँ विकसित कर रही है, फरवरी 11, 2025 (Forbes - Indian Army Developing Indigenous Anti-Drone Capabilities, February 11, 2025)

फोर्स इंडिया - भारतीय सशस्त्र बल अगले 10 वर्षों में 5,000 यूएवी शामिल करने की योजना बना रहे हैं, फरवरी 10, 2023 (Force India - Indian Armed Forces Plan to Include 5,000 UAVs in Next 10 Years, February 10, 2023)

फॉरेन पॉलिसी - भारत-पाकिस्तान संघर्ष: नई दिल्ली की दीर्घकालिक आतंकवाद विरोधी योजना, 2025 (Foreign Policy - India-Pakistan Conflict: New Delhi's Long-Term Counter-Terrorism Plan, 2025)

ब्रिटानिका - लश्कर-ए-तैयबा; मुंबई आतंकवादी हमले 2008 (Britannica - Lashkar-e-Taiba; Mumbai Terrorist Attacks 2008)

ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन - पाकिस्तान आतंकवादी समूहों का समर्थन क्यों करता है, और अमेरिका इसे बदलने के लिए इतना कठिन क्यों पाता है, 2018 (Brookings

Institution - Why Pakistan Supports Terrorist Groups, and Why America Finds It So Hard to Change It, 2018)

बीबीसी न्यूज़ - बालाकोट: भारतीय हवाई हमले पाकिस्तान में उग्रवादियों को निशाना बनाते हैं, 2019; क्या 2014 के बाद भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है?, 2023; भारत और पाकिस्तान फिर से संघर्ष का सामना कर रहे हैं - वे अतीत में कैसे तनाव कम करते थे?, 2025; भारत कश्मीर हमलावरों का पीछा 'पृथ्वी के अंत तक' करेगा, पीएम मोदी कहते हैं, 2019; भारत की कश्मीर में 'सर्जिकल स्ट्राइक': सत्य या भ्रम?, 2016; कश्मीर हमला: पुलवामा की ओर ले जाने वाला रास्ता, 2019; उग्रवादियों ने कश्मीर में भारतीय सेना के अड्डे पर हमला किया, '17 की हत्या', 2016; पहलगाम: अमेरिका ने कश्मीर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने का आग्रह किया, 2025; भारत के पाकिस्तान और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर पर हमलों के बारे में हम क्या जानते हैं, 2019; कश्मीर: भारतीय जांचकर्ता पहलगाम हमलावरों का दावा करते हैं, 2025 (BBC News - Balakot: Indian Air Strikes Target Militants in Pakistan, 2019; Has There Been No Major Terror Attack in India After 2014?, 2023; India and Pakistan Facing Conflict Again - How Did They De-escalate Tensions in the Past?, 2025; India Will Chase Kashmir Attackers 'To the End of the Earth', PM Modi Says, 2019; India's 'Surgical Strike' in Kashmir: Truth or Illusion?, 2016; Kashmir Attack: The Road Leading to Pulwama, 2019; Militants Attack Indian Army Base in Kashmir, '17 Killed', 2016; Pahalgam: US Urges India and Pakistan to De-escalate After Kashmir Attack, 2025; What We Know About India's Attacks on Pakistan and Pakistan-Administered Kashmir, 2019; Kashmir: Indian Investigators Claim Pahalgam Attackers, 2025)

भारत में आतंकवाद और सफल काउंटर-टेररिज्म रणनीतियां: विजन ऑफ ह्यूमैनिटी की रिपोर्ट (Terrorism in India and Successful Counter-Terrorism Strategies: Vision of Humanity Report)

मुंबई हमलों के बाद भारत की काउंटरटेरिज्म नीति में सुधार: सीटीसी की रिपोर्ट (Improvements in India's Counter-Terrorism Policy After Mumbai Attacks: CTC Report)

मीडियम डीएफआरलैब - द रेसिस्टेंस फ्रंट: जम्मू और कश्मीर में नया आतंकवादी समूह (Medium DFRLab - The Resistance Front: New Terrorist Group in Jammu and Kashmir)

यूके कॉमन्स लाइब्रेरी - कश्मीर: भारत-पाकिस्तान तनाव नवीनीकृत, 2025 (UK Commons Library - Kashmir: Renewed India-Pakistan Tensions, 2025)

यूएमडी स्टार्ट - भारत में आर्थिक विकास, खराब प्रबंधित राजनीतिक संघर्ष और आतंकवाद (UMD START - Economic Growth, Poorly Managed Political Conflict, and Terrorism in India)

रैंड कॉर्पोरेशन - कश्मीर विद्रोह में पाकिस्तान की भूमिका, 2001 (RAND Corporation - Pakistan's Role in Kashmir Insurgency, 2001)

रिफवर्ल्ड - कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेरिज्म 2017: फॉरेन टेरिस्ट ऑर्गनाइजेशंस: हिजबुल मुजाहिदीन (Refworld - Country Reports on Terrorism 2017: Foreign Terrorist Organizations: Hizbul Mujahideen)

रेडिफ.कॉम - रेडिफ विशेष: हिजबुल मुजाहिदीन क्या है?, जुलाई 31, 2000; द राइज ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, 2013 (Rediff.com - Rediff Special: What is Hizbul Mujahideen?, July 31, 2000; The Rise of Indian Mujahideen, 2013)

रॉयटर्स - अमेरिका ने पाकिस्तानी समूह की शाखा को आतंकवादी संगठन कहा, 2025 (Reuters - US Calls Branch of Pakistani Group a Terrorist Organization, 2025)

विकिपीडिया - लश्कर-ए-तैयबा; हिजबुल मुजाहिदीन; मुजाहिदीन; भारत में आतंकवादी घटनाओं की सूची; भारत में आतंकवाद; 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट; 2008 के मुंबई हमले; 2016 की भारतीय नियंत्रण रेखा स्ट्राइक; 2016 उरी हमला; 2019 बालाकोट हवाई हमला; 2019 पुलवामा हमला; भारतीय उपमहाद्वीप

में अल-कायदा; भारत-पाकिस्तान संबंध, 2025; भारत-संयुक्त राज्य संबंध, 2025; जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के अभियान; इंडियन मुजाहिदीन; सिंधु जल संधि; इस्लामिक स्टेट; जैश-ए-मोहम्मद; कश्मीर विद्रोह; कारगिल युद्ध; पाकिस्तान और राज्य-प्रायोजित आतंकवाद, 2025; सोवियत-अफगान युद्ध; राज्य-प्रायोजित आतंकवाद; आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम; उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक; डेविड हेडली (चल रही); द रेसिस्टेंस फ्रंट (चल रही) (Wikipedia - Lashkar-e-Taiba; Hizbul Mujahideen; Mujahideen; List of Terrorist Incidents in India; Terrorism in India; 2006 Mumbai Train Bombings; 2008 Mumbai Attacks; 2016 Indian Line of Control Strike; 2016 Uri Attack; 2019 Balakot Airstrike; 2019 Pulwama Attack; Al-Qaida in the Indian Subcontinent; India-Pakistan Relations, 2025; India-United States Relations, 2025; Indian Army Operations in Jammu and Kashmir; Indian Mujahideen; Indus Waters Treaty; Islamic State; Jaish-e-Mohammed; Kashmir Insurgency; Kargil War; Pakistan and State-Sponsored Terrorism, 2025; Soviet-Afghan War; State-Sponsored Terrorism; Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act; Uri: The Surgical Strike; David Headley (Ongoing); The Resistance Front (Ongoing))

विजन ऑफ ह्यूमैनिटी - भारत में आतंकवाद और सफल आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ; भारत में आतंकवाद और सफल आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ, जनवरी 4, 2020; आतंकवाद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, 2024; आतंकवाद के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Vision of Humanity - Terrorism in India and Successful Counter-Terrorism Strategies; Terrorism in India and Successful Counter-Terrorism Strategies, January 4, 2020; Psychological Impact of Terrorism, 2024; Socio-Economic Impact of Terrorism)

विंडवर्ड - भारत समुद्री खतरा मानचित्र (Windward - India Maritime Threat Map)

वॉर ऑन द रॉक्स - ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सैन्य रणनीति का विकास (War on the Rocks - Operation Sindoor and the Development of India's Military Strategy)

साउथ एशियन टेरिज्म पोर्टल (SATP) - हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम); जैश-ए-मोहम्मद मुजाहिदीन ई-तंजीम (जेईएम), 2023; 9/11 के बाद पाकिस्तान-आधारित समूहों द्वारा भारत में बड़े इस्लामवादी आतंकवादी हमले; भारत में आतंकवाद मूल्यांकन; जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद; इंडियन मुजाहिदीन: एक प्रोफाइल, 2013; पाकिस्तान में आतंकवाद | पाकिस्तान में आतंकवादी समूह; 9/11 के बाद पाकिस्तान-आधारित समूहों द्वारा भारत में बड़े इस्लामवादी आतंकवादी हमले; द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) आतंकवादी समूह, जम्मू और कश्मीर (चल रही) (South Asian Terrorism Portal (SATP) - Hizbul Mujahideen (HM); Jaish-e-Mohammed Mujahideen E-Tanzeem (JeM), 2023; Major Islamist Terrorist Attacks in India by Pakistan-Based Groups After 9/11; Terrorism Assessment in India; Terrorism in Jammu and Kashmir; Indian Mujahideen: A Profile, 2013; Terrorism in Pakistan | Terrorist Groups in Pakistan; Major Islamist Terrorist Attacks in India by Pakistan-Based Groups After 9/11; The Resistance Front (TRF) Terrorist Group, Jammu and Kashmir (Ongoing))

साइंसडायरेक्ट - दक्षिण एशिया में आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव (ScienceDirect - Economic Impact of Terrorism in South Asia)

सेंट लुई फेड - विकासशील देशों पर आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव (St. Louis Fed - Economic Impact of Terrorism on Developing Countries)

सीएनएन - मई 7, 2025 भारत ने कश्मीर नरसंहार के बाद पाकिस्तान पर हमले शुरू किए, 2025; मई 7, 2025 भारत ने कश्मीर के बाद पाकिस्तान पर हमले शुरू किए, 2025; कश्मीर हमले के बाद भारत-पाकिस्तान पर हमले: सीएनएन की लाइव रिपोर्ट (CNN - May 7, 2025 India Launches Attacks on Pakistan After Kashmir Massacre, 2025; May 7, 2025 India Launches Attacks on Pakistan After Kashmir, 2025; Attacks on India-Pakistan After Kashmir Attack: CNN Live Report)

सीएसआईएस - लश्कर-ए-तैयबा की जांच: 2021; लश्कर-ए-तैयबा, 2025; भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संकट का कारण क्या था?, 2025; एक्सट्रीमिज्म की जांच: लश्कर-ए-तैयबा (चल रही); भारत और पाकिस्तान के हालिया संकट का कारण क्या था?: सीएसआईएस की रिपोर्ट (CSIS - Investigation of Lashkar-e-Taiba: 2021; Lashkar-e-Taiba, 2025; What Caused the Recent Crisis Between India and Pakistan?, 2025; Investigation of Extremism: Lashkar-e-Taiba (Ongoing); What Caused the Recent Crisis Between India and Pakistan?: CSIS Report)

टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन - अल-कायदा एक स्थान-उन्मुख आंदोलन के रूप में: वैश्विक और स्थानीय जिहादवाद के बीच बातचीत, 2020; 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का परिणाम - ऑनलाइन समाचार टिप्पणी अनुभागों में धर्म, राष्ट्रवाद और बहिष्कार, 2020; अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के फ्रेम के माध्यम से पहचान और विचारधारा, 2019; 2019 पुलवामा आतंकी हमले का परिणाम, 2019 (Taylor & Francis Online - Al-Qaida as a Place-Oriented Movement: Interaction Between Global and Local Jihadism, 2020; Outcome of 2019 Pulwama Terror Attack - Religion, Nationalism, and Exclusion in Online News Comment Sections, 2020; Identity and Ideology Through Frames of Al-Qaida and Islamic State, 2019; Outcome of 2019 Pulwama Terror Attack, 2019)

मनीकंट्रोल - मिशन दिव्यास्त्र से प्रीडेटर ड्रोन तक: 2024 में भारत की बड़ी रक्षा प्रगति, दिसंबर 25, 2024 (Moneycontrol - From Mission Divyastra to Predator Drone: India's Major Defense Progress in 2024, December 25, 2024)

एनपीआर - एक पूर्ण आतंकवादी: मुंबई पर 2008 के हमले के पीछे अमेरिकी, 2008 (NPR - A Perfect Terrorist: American Behind 2008 Mumbai Attack, 2008)

जेस्टोर - पुलवामा हमला: महत्व, निहितार्थ और आगे का रास्ता, 2019 (JSTOR - Pulwama Attack: Importance, Implications, and Way Forward, 2019)

एसएसआरएन - वैश्विक आतंकवाद के आर्थिक निहितार्थ (SSRN - Economic Implications of Global Terrorism)